

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

नि यो ज न : देश और विदेश में

ए० बी० भट्टाचार्या, एम० ए०

अर्थशास्त्र विभाग,

आगरा कॉलेज, आगरा

रतन प्रकाशन मन्दिर

पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता

आगरा : देहली : मेरठ : कानपुर : गोरखपुर : इन्दौर

सर्वाधिकार लेखक के आधीन हैं ।

प्रथम संस्करण, फरवरी, १९६१

मूल्य : ग्यारह रुपए पच्चीस नए पैसे मात्र

प्रकाशक :

रतन प्रकाशन मन्दिर,
राजामण्डी, आगरा ।

मुद्रक :

पद्म चन्द जैन
प्रेस इलेक्ट्रिक प्रेस,
घटिया आजमखाना, आगरा ।

पूजनीया माताजी को सादर समर्पित

प्राक्कथन

प्रस्तुत पुस्तक मुख्य रूप से मेरी Planning at Home and Abroad का अनुवाद है। कुछ अध्याय, अनुवाद-काल में बदल दिए गए हैं एवं कुछ को परिवर्तित किया गया है। कुछ अध्याय नए जोड़े गए हैं। इस प्रकार इस बात की पूरी चेष्टा की गई है कि यह विभिन्न वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये अधिक उपयुक्त सिद्ध हो सके। प्रतियोगिताभूलक परीक्षाओं के विद्यार्थी एवं साधारण पाठक भी इसे उपयोगी पायेंगे।

यह पुस्तक पूर्ण मौलिकता का दावा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने विभिन्न पुस्तकों, रिपोर्टों, पत्र-पत्रिकाओं, एवं लेखों से सहायता ली है। मेरी ओर से इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया गया है कि सभी जगह References दिये जायें, किन्तु मेरी भूल से या अनुवादकों की भूल से यदि रह गये हों, तो मुझे उसके लिए खेद है। मैं उन समस्त लेखकों एवं प्रकाशकों का आभारी हूँ जिनकी 'विषय वस्तु' का उपयोग इस पुस्तक में किया गया है।

भारत में सोवियत संघ, चीन गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका की Embassies एवं ग्रेट ब्रिटेन के High Commission के प्रति मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ—जिन्होंने अपने देशों की आर्थिक स्थिति के विषय में मुझे उपयोगी साहित्य भेजा एवं उनके प्रकाशन की आज्ञा प्रदान की।

इस पुस्तक का अनुवाद सर्व श्री सुखराम सिंह, एम० ए० (१२ अध्याय), जयवीर सिंह, चौहान, एम० ए० एवं लक्ष्मीकान्त चतुर्वेदी ने किया है। समस्त अध्यायों का ससोधन मेरे मित्र श्री रामभूति शर्मा, एम० ए०, 'साहित्यरत्न' द्वारा किया गया है। समस्त अनुवादकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। श्री लक्ष्मीकान्त चतुर्वेदी ने मेरे साथ धैर्यपूर्वक काम करके अ-अनुवादित अध्यायों के लिखने में सहायता की है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे मित्र, प्रो० पूर्णचन्द्र मित्रा (गवर्नमेंट हमीदिया कॉलेज, भोपाल) ने कुछ सुझाव भेजे थे जिनके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूँ। मेरे सबसे छोटे भाई प्रदीप कुमार भट्टाचार्य के प्रति "कुछ न करने के लिए" आभारी हूँ। समस्त पाण्डुलिपि को सशोधित करने, कहीं-कहीं फिर से अनुवाद करने एवं पुनः लिखने के लिए मैं अपने मित्र श्री रामभूति शर्मा के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ। वास्तविक बात तो यह है कि यदि वह पिछले ३-४ महीनों से अथक परिश्रम न करते होते तो यह पुस्तक कभी भी तैयार नहीं हो पाती।

श्री पदमचन्द जैन, रत्न प्रकाशन मन्दिर (प्रकाशक) एवं प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस के कर्मचारियों के प्रति मैं आभारी हूँ। उन्होंने बड़े परिश्रम से पुस्तक को छापा है। इस प्रेम के मैनेजर श्री बी० एन० मेहरा जी एवं समस्त प्रूफ रीडरों के सहयोग के लिये आभारी हूँ। मुद्रण में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।

मुझे आशा है कि अध्यापक-वन्द्य एवं छात्र-छात्राएँ इसे उपयोगी पायेंगे एवं अपनायेंगे। त्रुटियों के विषय में अवगत करा देने पर आगे मैं उन्हें दूर करने का यत्न करूँगा।

अर्थशास्त्र विभाग }
आगरा कॉलेज, आगरा }

—ए० बी० भट्टाचार्या

अनुक्रमणिका

प्रथम भाग

नियोजन के सिद्धान्त

१. विषय प्रवेश

१

आर्थिक नियोजन का अर्थ तथा परिभाषायें, १
अनियोजित आर्थिक अवस्था की बुराईयाँ, ८
आर्थिक नियोजन के सिद्धान्त का जन्म, ११
नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है ? १२
आर्थिक नियोजन से हानियाँ, १४
नियोजन की विशेषतायें, १७

२. आर्थिक नियोजन के उद्देश्य

२०

सामान्य सिद्धान्त, २०
नियोजन के विरोधी उद्देश्य, २२
समाज सेवा या उद्योग ? २४
केन्द्रीय लक्ष्य, २५
पारस्परिक सम्बन्धित उद्देश्य, २६
तृतीय योजना के मुख्य उद्देश्य, २७
असमानता की न्यूनता, २७
समानता की ओर, २८
समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना, २६
कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ३२
कल्याणकारी राज्य के स्थापनार्थ ग्रहण किए हुए उपाय, ३५

३. नियोजन और रोजगार

३७

विषय-प्रवेश, ३७

बेरोजगारी दूर करने के विभिन्न उपाय, ३८

समस्या का आकार तथा प्रकार, ४१

तृतीय योजना में रोजगार की सम्भावनाएँ, ४६

४. निम्नतम जीवन-स्तर की प्राप्ति

४६

विषय-प्रवेश, ४६

प्रथम योजना और राष्ट्रीय आय, ५३

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आय, ५५

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ५६

वृहत् औद्योगीकरण की ओर, ५७

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना : औद्योगीकरण के लिए एक बड़ा कदम, ५८

साक्ष्य-प्रबन्ध, ६०

वस्त्र, ६२

५. नियोजन तथा मूल्य-निर्धारण

६४

उद्योग का नियन्त्रण एवं मूल्य, ६४

स्वतन्त्र बनाम नियोजित उत्पादन तथा मूल्य, ६८

स्वतन्त्र वितरण बनाम राज्य का व्यापार एवं मूल्य, ६९

प्रतिस्पर्धी बनाम नियन्त्रित मूल्य, ७०

कर, द्रव्य का नियन्त्रण तथा मूल्य, ७४

बढ़ती हुई, गिरती हुई अथवा स्थायी

मूल्यों में कौन-सी सबसे अच्छी है ? ७५

६. आर्थिक नियोजन के पूर्व-प्रयोजन

तथा प्रभाव उत्पन्न करने के साधन

७८

सांख्यिकीय आंकड़े और सूचनाएँ, ७८

उद्देश्यों का निर्धारण, ८०

प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों का निर्धारण, ८३

योजना के लिये वित्त-अवस्था, ८४

सन्तुलन की समानता, ८१

७. नियोजनकर्ता कौन हो ?

८६

विषय-प्रवेश, ८६

व्यक्तिगत नियोजन के पक्ष में, ९०

केन्द्रीय आर्थिक नियोजन की आवश्यकता तथा महत्व, ९२

भारत में केन्द्रीय नियोजन, ९६

८. आर्थिक प्रणालियाँ : (१) पूँजीवाद

९६

पूँजीवाद का अर्थ और उसका विकास, ९६

पूँजीवाद के मुख्य लक्षण और दोष, १०१

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण, १०८

९. आर्थिक, प्रणालियाँ : (२)

समाजवाद, मार्क्सवाद एवं साम्यवाद

११३

समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा, ११३

सामूहिकवाद या राजकीय समाजवाद, ११७

अधिकवाद या मजदूर सववाद, ११७

वैज्ञानिक समाजवाद अथवा मार्क्सवाद, ११८

साम्यवाद, १२४

अन्य प्रकार की समाजवादी व्यवस्थाएँ, १२७

समाजवाद के गुण तथा दोष, १२८

१०. मिश्रित अर्थव्यवस्था

१३२

ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि, १३२

मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ, १३६

भारतवर्ष में मिश्रित अर्थव्यवस्था, १३८

सार्वजनिक क्षेत्र, १३९

निजी क्षेत्र का विकास १४६

११. राजकीय उद्योग

१५१

भूमिका, १५१

राजकीय उद्योग की विशेषतायें, १५२

भारत में राजकीय उद्योगों का विकास, १५३

राज्य-उद्योगों का प्रबन्ध, १५५

राज्य-उद्योगों का आलोचनात्मक विश्लेषण, १५६

१२. आर्थिक नियोजन के प्रकार एवं पद्धतियाँ

१६२

विषय प्रवेश, १६२

उद्देश्यपूर्ण नियोजन, १६३

भौतिक और वित्तीय योजना, १६३

दीर्घकालीन बनाम अल्पकालीन योजना, १६५

स्वतन्त्र नियोजन, १६६

नियोजन पद्धति : 'विनाश' बनाम 'निर्माण', १६७

नियोजन पद्धति : सन्तुलित बनाम अमन्तुलित विकास, १६८

नियोजन पद्धति : स्थिर बनाम अस्थिर, १६९

नियोजन पद्धति 'प्रोत्साहन मूलक' बनाम 'आज्ञा मूलक', १७०

नियोजन पद्धति : फासिज्म बनाम नाजीज्म, १७२

१३. अविकसित देशों की आर्थिक विशेषतायें

१७३

अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा, १७३

अविकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण कौन-कौन से हैं ?, १७५

अविकसित देशों का अस्तित्व क्यों होता है ?, १७७

अविकसित देशों की आर्थिक प्रगति में बाधाएँ, १७९

पूँजी निर्माण की कठिनाइयाँ, १८५

१४. अविकसित देशों में नियोजन-प्रणाली

१८०

अविकसित देशों में नियोजन-महत्त्व, १८०

उद्योग-प्रमुख नियोजन या कृषि-प्रमुख ? १८१

पूँजी-प्रमुख या श्रम-प्रमुख उत्पादन ? १८३

घाटे के बजट द्वारा नियोजन, १८४

- केन्द्रीय नियोजन या मिश्रित ग्रन्थव्यवस्था ?, १९५
 व्यक्तिगत आमदनी में वृद्धि या राष्ट्रीय आय में वृद्धि ?, १९६
 अधिक उत्पत्ति या अधिक उपभोग ?, १९७
 अव्यवस्थित या अर्द्ध-व्यवस्थित क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की जावे ? १९८
 योजना की रूपरेखा, १९९
 अविकसित देशों में नियोजन की कठिनाइयाँ, २००
 अविकसित देशों में नियोजन को सफल बनाने के तत्त्व, २०६

१५ विविध

२१०

- परिवार-नियोजन, २१०
 मूल्य नीति, २१७
 आर्थिक उन्नति के सिद्धान्त एवं विकास के नमूने, २२०
 Growth models, २२४
 (a) Harrod's views, २२४
 (b) Domar's views, २२५
 (c) Sweezy's theory (as analysed by Domar), २२६
 (d) Mahalanbis Model, २२९
 नियोजन की प्रवन्ध सम्बन्धी आवश्यकताएँ, २३०

द्वितीय भाग

भारतीय नियोजन

१६ भारत के प्रारम्भिक नियोजन

२४१

- संक्षिप्त इतिहास, २४१
 जन नियोजन, २४३
 गांधीवादी योजना, २४५
 सर्वोदयी योजना, २४६
 बम्बई योजना, २४८
 कोलम्बो योजना, २५५

१७. प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलताएँ तथा असफलताएँ

२६२

उद्देश्य और पहुँच, २६२
उत्पादन की प्रवृत्ति, २६५
विनियोग तथा उत्पत्ति, २७०
वित्तीय प्रकरण और कीमतें, २७२
रचनात्मक तथा नीति-सम्बन्धी पहलू, २७३
उपसंहार, २७५

१८. द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन एवं आशायें २७६

कृषि और सामुदायिक विकास, २७६
सामुदायिक विकास कार्यक्रम, २८२
कृषि-कार्यक्रम सम्बन्धी उपसम्भियाँ, २८२
सिंचाई एवं जल-विद्युत शक्ति, २८४
गाँव और कुटीर उद्योग-घरे, २८८
विशाल तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग, २८९
सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक कार्यक्रम, २९०
औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, २९८
खनिज साधनों का विकास, ३०४
यातायात और संचाहन, ३०६
'कोर' कार्यक्रम, ३१६
सामाजिक सेवाएँ, ३१७
गृह-निर्माण कार्य, ३२१
ग्राम्य सामाजिक सेवाएँ, ३२२

१९. द्वितीय पंचवर्षीय योजना : आलोचनात्मक अध्ययन ३२४

✓ २०. तृतीय पंचवर्षीय योजना

३५५

योजना की रूपरेखा, ३५५
योजना के लिए साधन, ३७२
प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं का
तुलनात्मक अध्ययन, ३८१

तृतीय पंचवर्षीय योजना की विवेकतायें, ४०८
तृतीय पंचवर्षीय योजना की आलोचना, ४१५

तृतीय भाग

विदेशों में नियोजन एवं आर्थिक व्यवस्था

२१. अमेरिका का पूँजीवाद	४२५
२२. ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था	४५१
२३. चीन गणराज्य में नियोजन	४६३
२४. आदर्श नियोजन : सोवियत संघ	४७६

Appendices

प्रथम भाग

नियोजन के सिद्धान्त : भारतीय नियोजन के सन्दर्भ में

विषय-प्रवेश (Introductory)

१—आर्थिक नियोजन का अर्थ तथा परिभाषाएँ

(Meaning and Definition of Economic Planning)

देश की आर्थिक व्यवस्था (Economic Order) में नियोजन के समावेश का मुख्य उद्देश्य राज्य के उत्पादन एवं वितरण पर नियंत्रण रखना, राष्ट्रीय आय की वृद्धि करना, रहन सहन के स्तर को ऊँचा करना, जनता को आर्थिक विकास के लिये अधिकतम सुअवसर प्रदान करना तथा राष्ट्र के साधनों एवं शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग करना है।

“यह आर्थिक संगठन की एक योजना है। इसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामूहिक योजनाओं का समावेश होता है। ये सब योजनाएँ एक ही आर्थिक संगठन की समानस्तरीय इकाई (Co ordinate units) मान ली जाती हैं, जिसमें सभी प्राप्त साधनों का उपयोग करके उत्पादन तथा राष्ट्र में अधिक कल्याण एवं सन्तुष्टि प्राप्त हो सके। ऐसा करने से कुछ व्यक्ति, संस्थायें एवं वर्ग असन्तुष्ट भी हो सकते हैं।”¹

राष्ट्रीय नियोजन समिति (The National Planning Committee) ने नियोजन की निम्नलिखित परिभाषा दी है :—

“लोकतन्त्रात्मक सरकार के नियोजन में एकीकरण (Co-ordination) होता है जिसमें राष्ट्र के प्रतिनिधि उपभोग, उत्पादन, अनुसन्धान, व्यापार एवं आय के वितरण के लिए कुछ मिद्वान्त निर्धारित करने हैं। ऐसी योजना केवल आर्थिक स्थिति तथा रहन सहन के स्तर को ऊँचा करने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि

1 “It is a scheme of economic organisation in which individual family and institutional plans are treated as subordinate and co-ordinate units of one single economic system for the purpose of utilising all the available resources to achieve maximum efficiency in production and increased welfare and satisfaction to the nation, even at the risk of dissatisfaction to some individuals, institutions and sections of the community.” (*Economic Planning in India*—C. B. Memoria, p 1.)

एच० लेवी (H. Levy) को पहुँच महत्वपूर्ण है। नियोजन, जैसा कि हम जानते हैं, मुख्यतः तीन उद्देश्यों को लेकर चलता है—देश के आर्थिक जीवन में स्वायत्त, उत्पादन तथा वितरण पर कुशलतापूर्वक नियन्त्रण तथा जनसमूह का उत्थान। एच० लेवी के मतानुसार योजना को मफनना के लिये उत्पादन तथा वितरण पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है, किन्तु उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इसको स्पष्ट करने में वह असफल रहे हैं। केवल 'स्वेच्छापूर्वक कार्य, अदृश्य तथा अनियन्त्रित' कह देना ही पर्याप्त नहीं है।

आर्थिक नियोजन को एच० डूमरी परिभाषा डा० डाल्टन (Dr. Dalton) ने इस तरह दी है—“आर्थिक नियोजन का एक व्यापक अर्थ है, इसके अधिकारियों का अपन चुने हुए उद्देश्यों को अपने विस्तृत साधनों द्वारा वा्यान्वित करना।”¹

जैसाकि परिभाषा से प्रतीत होता है, डाल्टन अपनी परिभाषा को बहुत स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। अधिक साधन सम्पन्न कोई भी समुदाय, राज्य एव वर्ग हो सकता है, लेकिन उनमें से योजना किसे बनानी है? कार्य तथा लक्ष्य इनके विभिन्न हैं, लेकिन यह कैसे जाना जाय कि कौनसा कार्य विशेष कार्य में लाना है तथा उसके क्या परिणाम हैं? क्या योजना कोई निश्चित लाभ प्राप्त करने के द्येय से बनाई जाती है? ये कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने में डाल्टन का परिभाषा असमर्थ है। इसलिये यह परिभाषा अपूर्ण है।

प्रो० रौबिन्स (Prof. Robbins) ने नियोजन को दो तरह से व्याख्या की है—

१—“वास्तव में देखा जाय तो सम्पूर्ण आर्थिक जीवन ही योजना से भरा रहता है, योजना बनाने का अर्थ वायदे और उद्देश्य से कार्य करना तथा पहुँच करना है। आर्थिक प्रकरण में चुनाव का अत्यधिक महत्त्व है।”

२—“आर्थिक नियोजन इस युग की अबूक औपध है। जन हितकारी राज्य के आदर्श को जानने का आर्थिक नियोजन ही एकमात्र साधन है।”

रौबिन्स की आर्थिक नियोजन की परिभाषा व्यावहारिक, पर्याप्त एव पूर्ण है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य के विषय में तो दो राय नहीं हो सकती। इसका तो एक

1 “Economic planning, in its widest sense, is deliberate direction, by persons in charge of large resources of economic activity towards chosen ends” (H Dalton—*Practical Socialism*, Britain, (1935) p 243)

2 (i) “Strictly speaking all economic life involves planning to plan is to act with a promise, a purpose to choose, and choice is the essence of economic activity”

(ii) “Economic planning is a grand pancea of our age Economic planning is only a means of realising the ideal of a Welfare State” (L Robbins—*Economic Planning and International Order*, (1938), p 3)

ही उद्देश्य है — 'आर्थिक नियोजन कल्याणकारी राज्य के आदर्श को जानने का साधन है।' नियोजन के क्षेत्र तथा अधिकार पर रॉबिन्स ने कोई प्रकाश नहीं डाला है। व्यक्ति तथा राज्य दोनों ही 'कल्याणकारी राज्य' के आदर्श को उद्देश्य बनाकर नियोजन कर सकते हैं। परन्तु दोनों की पहुँच (Approach) में बहुत भ्रंतर है। पूँजीवादी नियोजन का मुख्य उद्देश्य निजी लाभ होना है तथा जनता के कल्याण का ध्येय गौण रहता है। लेबिन समाजवादी नियोजन में रहन सहन के स्तर को ऊँचा करने का ही केवल एकमात्र ध्येय होना है। रॉबिन्स ने नियोजन के स्वरूप की ओर कोई संकेत नहीं किया।

इसके अतिरिक्त कुछ और भी अर्थशास्त्री हैं जो उपरोक्त परिभाषाओं से सहमत नहीं हैं। उन्होंने आर्थिक नियोजन की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की है—

(अ) "नियोजन बहुत सी समितियों का एक दूम्परे के सहयोग से एक निश्चित स्वीकृत लक्ष्य (Accepted end) के लिये कार्य करना है।"¹

(ब) "आर्थिक नियोजन का ध्येय समाज के सभी सदस्यों के स्तर को ऊँचा करना है।"²

(स) "उत्पादन तथा वितरण का एक ऐसा आदर्श रखा जिसमें माँग एवं पूर्ति में बहतर सन्तुलन स्थापित किया जा सके।"³

इनमें से एक भी आर्थिक नियोजन के मूल तत्व को तथा उसकी ठीक परिभाषा को स्पष्ट नहीं कर सका है। लेखक आर्थिक नियोजन के अर्थ एवं ध्येय के बीच में कुछ उद्भ्रान्त से प्रतीत होने हैं। उन्होंने आर्थिक नियोजन की आवश्यकता तथा ध्येय के माध्यम से उसकी परिभाषा दी है, जिसे पूर्णतः ठीक नहीं कहा जा सकता।

प्रो० जॉन जीविल्स (Prof. John Jewkes) के विचार में नियोजन का अर्थ है, "केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था इस बात को स्पष्ट करती है कि राज्य तथा उपभोक्ता किस व्यवसाय को करना चाहते हैं। यह व्यक्तिगत सम्पत्ति

1 "Planning may be defined as the working of a number of organizations in conjunction with one another for some consciously accepted end"

2 "The object of economic planning is the achievement and retention of a high standard of living for all the members of the society"

3 "The working of production and distribution on a pre conceived pattern and the rehabilitation of the existing system of such a plan with a view to secure a better adjustment between demand and supply conditions"

के विनाश द्वारा राष्ट्र को आत्म निर्भर होने को प्रेरित करती है।¹ इस परिभाषा की स्पष्टता के विषय में हमें कोई सन्देह नहीं, लेकिन यह नियोजन के सम्पूर्ण अर्थ को स्पष्ट करने में अममर्थ है, इसीलिए अपूर्ण है। एक अन्य स्थान पर प्रो० जीविल्स ने कहा है, “आर्थिक नियोजन का विचार राष्ट्रों के आर्थिक प्रयामों में उसी तीव्रता से फैल रहा है जिन तीव्रता में जंगल में आग फैल जाती है। ...” आज से ५० वर्ष बाद आर्थिक नियोजन का सिद्धान्त उसी प्रकार निरावार और आकस्मिक समझा जायगा जैसा कि कुछ काल पूर्व ब्रिटेन में खाद्य संकट के समय लाल मछलियों के समूह का पना लगना। इसी प्रकार जब सभी देश उन्नत हो जायेंगे तो नियोजन महत्वहीन हो जायगा।²

भिन्न भिन्न विद्वान् अर्थ जतान्दी से आर्थिक नियोजन की विभिन्न परिभाषायें देने आ रहे हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव बड़ा ही कठिन है। इनका वास्तविक कारण यह है कि जो कुछ भी आर्थिक प्रक्रिया कार्यान्वित की जाती है उसे योजना-बद्ध पहले किया जाता है।

“योजना रहित आर्थिक व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकती। हर आर्थिक व्यवस्था के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है।”

प्रो० विल्हेम केल्हेउ (Prof. Wilhelm Keilhau) ने आर्थिक नियोजन की निम्नलिखित परिभाषायें दी हैं :—

(अ) “आर्थिक व्यवस्था कुछ निश्चित प्रयोजनों की पूर्ति के लिये नियोजित प्रक्रिया है। हर आर्थिक कार्य में नियोजन आवश्यक है। आर्थिक नियोजन के सिद्धान्त केवल मानव के कुछ विशेष उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थशास्त्र के सभी सिद्धान्तों से सम्बन्धित हैं।”³

1 “The Centrally Planned Economy implies the state determination of investment and its distribution, of occupation, of consumers’ choice. It involves progressively the destruction of private property and it leads to national self-sufficiency.” J. Jewkes—*Ordeal by Planning*. (1948), p. X (Introduction)

2 “Fashions in economic thinking are notoriously infectious and fickle. They run through communities with the speed of forest-fires. The current mania for comprehensive economic planning by the state may well appear, half a century hence, as just another of the red herrings which fate throws across the forward march of free people.” (*Ibid*, pp. 1-2)

3. “Economy consists in a totality of planned efforts to realise certain purposes. Planning is essential in every activity of economic character. The theory of economic planning does not deal only with some special forms of human societies, but with a certain important part of every economy. It belongs to the general theory of economics.” (W. Keilhau—*Principles of Private and Public Planning*, pp. 16-17.)

(ब) "योजना सहायक ध्येयो तथा प्रस्तावनाओं (Suggestions) का एक संगठन है, जोकि एक दार्शनिक ढंग से एकत्रित होकर एक प्रधान लक्ष्य की ओर बढ़ती है। सभी दिशाओं में जहाँ कि प्रधान उद्देश्यों में आर्थिक लक्षणा एक ही क्यों न हो, हमें आर्थिक योजना में पूरा करना पड़ता है। इसीलिये आर्थिक योजना के सिद्धान्त के दो प्रमुख प्रयोजन हैं—एक, प्रधान उद्देश्यों की व्याख्या, तथा दूसरा, व्यक्ति और वर्ग इनको किस तरह मार्गान्वित करे।"¹

(न) "नियोजन पूर्व निर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।"²

(द) "आर्थिक नियोजन नियोजित प्रक्रियाएँ हैं, जिनसे भविष्य में उन्नति, प्राप्ति, वृद्धि तथा समृद्धि की सम्भावना के साथ-साथ मानव कुछ आर्थिक निष्पत्तियों में प्रेरित होता है अथवा पहले से अधिक अपने को अच्छा साधन सम्पन्न बनाने का प्रयत्न करता है और नियोजित प्रक्रिया ही अन्य आर्थिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा, सहायता तथा प्रोत्साहन देती है।"³

वि० केलहेड की ऊपर दी हुई परिभाषाओं में से केवल अन्तिम को छोड़कर बाकी सभी, कुछ हद तक, भ्रमात्मक हैं। नियोजन के अर्थ तथा उद्देश्य को स्पष्ट करने में वह सफल नहीं हुए। उन्होंने नियोजन के उद्देश्य तथा उनकी क्रूरता पर अनुचित ध्यान दिया है। फिर भी उनकी अन्तिम परिभाषा पर्याप्त सीमा तक उचित तथा ठीक है। उसमें वे नियोजन की परिभाषा तथा अर्थ को स्पष्ट कर पाए हैं। यह परिभाषा आर्थिक नियोजन के विस्तार पर प्रकाश डालती है।

किसी वर्णनात्मक विषय के अध्ययन में, वह भी विशेषकर अर्थशास्त्र में बहुत

1. 'A Plan is a totality of subordinate purpose resolutions and executive resolutions, all serving the same supreme purpose and being linked together in a systematical and rational way' In all cases, where the supreme purpose is of an economic character, we have to do with economic plans. A theory of economic planning has, therefore, two main objects to discuss the primary or supreme economic purposes and to describe how individuals or groups of individuals plan in order to realise these purposes" (*Ibid*, p 26)

2. 'Planning makes up one of the two main forms of economic thinking in pre time' (*Ibid*, p. 48)

3. 'Economics are planned activities which create, promote, acquire, preserve or secure future usefulness as well as planned activities which enable human beings to do economic work or to do it better than before, and planned activities which organise, protect support or assist other economic activities' (*Ibid*, p 42)

सी बाधाएँ हैं। यही कारण है कि नियोजन की परिभाषा के विषय में विद्वानों के मत एक नहीं हैं। ऊटन ने ठीक ही लिखा है “छः अर्थशास्त्रियों के मत मत होते हैं।”¹

आर्थिक नियोजन के विषय में भी यह कथन बिलकुल सत्य है क्योंकि वह अर्थशास्त्र का ही एक अंग है। अर्थशास्त्रियों के पास वाद-विवाद के लिये बहुत सामग्री है। “नियोजन के विषय में भी वाद-विवाद के लिये बहुत तथ्य हैं। बहुत द्वन्द्वात्मक विचारों के होने के कारण एक साधारण व्यक्ति तो इस द्वन्द्व के समूह में गोते लगाता रह जायगा तथा कभी भी उभर कर नहीं आसकेगा अर्थात् एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पायेगा।”²

विभिन्न विद्वानों के विचारों में भिन्नता और पारस्परिक मतभेद का यह कारण है कि नियोजन का कार्य मूढ़म और कठिन होना है। इसकी सफलता केवल प्रतिवादों के स्थायित्व तथा एकीकरण, जो कि विभिन्न क्षेत्रों के निर्माण के लिये एक दूसरे से सम्बन्धित है, पर ही निर्भर नहीं बल्कि स्थानीय आत्म बल तथा मस्तिष्क की उर्वरा शक्ति पर निर्भर है, जोकि जनता में ऐसी प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होगी। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि नियोजित कार्यों के विषय में अभी स्पष्ट स्वीकार नहीं किया जाना है कि अनियोजित प्रयास की तुलना में नियोजित व्यवस्था अधिक सफल होती है।

इस तरह आर्थिक नियोजन किसी व्यक्ति, समाज तथा राज्य की सुमंगलित तथा स्वतन्त्र और सुसम्बन्धित प्रक्रिया है, जो जन जीवन की उन्नति के लिए, रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने के लिए एवं राष्ट्र के साधनों और शक्तियों का समुचित उपयोग करके देशवासियों का आर्थिक स्थिति में उन्नति करने के लिए बनाया जाना है। इसमें ममन क तत्व का समावेश भी आवश्यक है।³

आर्थिक नियोजन के अर्थ तथा परिभाषा में मतभेद अब भी समाप्त नहीं हो पाया है। यह कथन, “नियोजन भी समाजवाद की तरह अधिक पारिभाषित विषय

1. “Wherever there are six economists, there are seven opinions” (Mrs B Woo tan—*Lament for economies*)

2. “There is a lot of glib talk about planning. So many conflicting views have been expressed and all of them seem to have so much validity that the ‘average man’ in this realm is bewildered and lost in trying to unravel the snarl of crossed lines and mixed motives”

3. Thus, Economic Planning may be defined as a co-ordinated, organised effort by an individual, society or state to attain the objectives of the amelioration of the masses, raising the standard of living and increasing national income per capita through maximum and most useful utilisation of nation's productive resources. It also contains a time element for its implementation (*Planning at Home & Abroad—A. B. Bhattacharya, p. 7.*)

है।¹ अब तक सब लगता है। लेकिन इससे निराश न होकर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर दृष्टि के साथ आगे बढ़ना चाहिये "अर्थशास्त्री प्रत्येक बात पर अतृप्त रहना है। अब लगता है कि वह अपने को पहचानने में भी असहमत है।"²

२—अनियोजित आर्थिक व्यवस्था की बुराईयाँ (Evils of an Unplanned Economy)

आर्थिक नियोजन न तो भारत के लिए और न मरार के लिए ही नया विषय है। लेकिन फिर भी इन समयों में नही मुठकाटा जा सकता है कि कुछ दशकों (Decades) पहले इसको इतनी प्रधानता नहीं दी गई थी, जितनी कि आज की जा रही है। वास्तव में राष्ट्रों के आर्थिक विकास में इनने एक नया मार्ग दिखाया है; विशेष कर कम की तथा हाल ही में चीन की योजनाओं की मरकत में इसको एक नया बल मिल गया है। नियोजन आर्थिक ढांचे की बुराईयों को दूर करने के लिए तथा राष्ट्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आजकल हमारे देश में बहुत-सी आर्थिक बुराईयाँ तथा विषमताएँ विद्यमान हैं। नियोजकों को सबसे पहले देश के वर्तमान आर्थिक ढांचे में जो बुराईयाँ तथा कुरीनियाँ व्याप्त हैं, उनका समाधान करना है।

यह बड़े पैमाने का विषय है कि "अधिकतर देशों में उत्पादन के साधनों पर समाज के एक वर्ग विशेष का एकाधिकार है—वर्जित श्रमिकों का शोषण करते हैं। ग्रामों की आत्म-निर्भरता, मृद की दर तथा लगान अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो चुकी है। बेरोजगारी के बढ़ जाने से मानव जाति पीड़ित है"³ इन्हीं कारणों ने जनता ने संघर्ष प्रारम्भ कर दिया है। "नियोजन, नियोजित मितप्रतिष्ठा तथा आर्थिक ढांचे जो कि उन्हें दलित के अवसर देंगे—वह सब शोषित जनता को

1. 'Planning like Socialism, is a much overworked expression.' (B. C. Ghosh—*Planning for India*, p. 2.)

2. "Economists disagree on everything. Now we hear that they even disagree on their own identity" (Wilhelm Keilhau—*Principles of Private and Public Planning*, (1951), p. 40.)

3. "Sources of production are being monopolized by one class of people—the capitalists, which exploit the others—the labourers. The old village-self-sufficiency has broken down and ryots suffer from increased rents and higher rates of interest. Unemployment prevails which means in terms of human suffering." (*Fundamentals of Economics*—J. K. Mehta and others)

नियोजन की माँग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अधिक उद्योगों में अपना भाग चाहता है, न कि सम्पूर्ण उद्योग का अपना बनाना चाहता है।¹

द्वितीय महायुद्ध के समय में जबकि अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की बुराईयों लोगो को दृष्टिगोचर हुई तथा उन्हें कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा, तभी से उनके मस्तिष्क में योजना का विचार घर कर गया। युद्ध के दिनों में तथा उसके पश्चात् लड़ाका देशों ने अपने उत्पादन के सम्पूर्ण साधनों को युद्ध विषयक सामग्री निर्माण करने में लगा दिया था—यह जानने हुए भी कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई हुई वस्तुएँ बहुत कम हैं। इन्हीं ने युद्ध कालीन नियंत्रण को जन्म दिया और साथ साथ राशनिय, वस्तुओं की दुर्लभता तथा चोरबाजारी को प्रोत्साहित करते हुए साधारण व्यक्तियों को सकट में डाल दिया। इसके साथ साथ मूल्यों का बढ़ जाना भी लोगों को योजना की ओर बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं ने, जिनके द्वारा देश की राष्ट्रीय अर्थिक व्यवस्था का तीव्रगति से हर क्षेत्र में विकास हुआ, इस सदेह को दूर कर दिया।

2 अर्थशास्त्रियों का कथन है कि नियोजन बेरोजगारी में फैली हुई व्याकुलता तथा आपत्ति को यदि पूरी तरह से दूर न कर सका तो बम अवश्य कर देगा। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि वह अनियोजित मितव्ययिता की, बढ़ी हुई कीमतों से सघर्ष कर उमकी कुरोनियों को बड़ में उखाड़ देगा तथा रहन सहन के स्तर को ऊँचा करने के लिये बढ़तों में एक सच बनायेगा, जिससे अधिक से अधिक उपभोग की वस्तुएँ उत्पन्न की जा सकें। इसमें देश का सामूहिक आर्थिक विकास शीघ्र से शीघ्र सम्भव हो सकेगा।

डा० कुरेशी (Dr. Qureshi) ने अपनी पुस्तक 'स्टेट एण्ड इकोनॉमिक लाइफ' (*State and Economic Life*) में विल्फुल ठीक कहा है, "आत्मनिर्भरता का सिद्धान्त अवांछनीय है क्योंकि एव हमारे की सहायता के बिना किसी का कार्य नहीं चल सकता। इस तरह हम किसी देश का अधिक भला तब ही कर सकेंगे जबकि हम सम्पूर्ण देश को ध्यान में रखकर योजना बनायें न कि केवल उद्योगों के लिए ही योजना बनायें और फिर धीरे धीरे सम्पूर्ण विश्व की योजना की जन्म दें।"²

1 "To cry out for Planning, for a planned economy and financial system that will give him the chance of getting on with his job. He demands planning even if it be somewhat dubious sort for his own industry is not for industry as a whole" (Ibid)

2 "The doctrine of self-sufficiency is unpracticable. And there is dependence of one upon another. Thus, we try to make the best out of a country we plan not only for this industry or that, but for the country as a whole, and gradually we plan for the entire world."

हमारा देश तो युगो से 'मादा जीवन उच्च विचार' अर्थात् अपनी 'आवश्यकताओं को अधिक से अधिक कम किया जाय' यह मन्देश देना चला आ रहा है। अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जाय यह पूछने हम डाक्टर के पास कभी नहीं जायेंगे जब तक कि बीमार न पड़ें और डाक्टर के पास जाने को विवश न हो जायें। यही दशा हमारे आर्थिक नियोजन की भी है। अब हम योजनार्थे इसलिए बना रह रहे हैं कि इसके बिना कार्य चसना बहुत ही कठिन हो गया है।

प्रो० आर० वी० राव (Prof. R. V. Rao) ने अपनी 'इकोनोमिक प्लानिंग इन इण्डिया' (*Economic Planning in India*) में सन् १९४५ में ही लिखा था कि "नियोजन के लिए हम उस समय ही मोचने हैं जबकि आर्थिक परिस्थितियाँ हमें इसके लिये विवश कर देती हैं। हमारे आर्थिक जीवन में जब कुछ अनुविधायें आती हैं तभी हम नियोजन की मोचते हैं, या जब शक्तियाँ तथा साधना की ध्यान में रखते हुए उत्पादन बहुत ही कम हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने प्रमत्त होकर अपने प्रसीम उपहार हमें दे डाले हैं, लेकिन मानव अपने आर्थिक विराम के लिए उनमें सम्भावित लाभ उठाने में असमर्थ है। इसीलिए भारत अपने नाशना में सम्पन्न होते हुए भी निवन है। अतः हमें कच्चा माल का निपात न करके अपने देश में ही उत्पादन की प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि हम कच्चा माल निर्यात करने हैं तो इसका अर्थ है हम रोजगार का निर्माण कर बेरोजगारी का प्रायान करते हैं। संक्षेप में हमारा ध्येय, अपने साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके जनता को खुशहाल बनाने, रहन सहन के स्तर को ऊँचा करने तथा उचित समय में आत्म निर्भर बनाने का होना चाहिए।

'इस देश के आर्थिक विकास पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति का यही कथन होगा कि आर्थिक नियोजन के विकास की नीति ही दोषपूर्ण थी। यह भी सत्य है कि देश में आर्थिक जीवन के भविष्य की योजना उद्योगों के स्थापनार्थ ही अधिक समझी जानी चाहिए जो कि केवल उपभोक्ताओं की भोजनादि की आवश्यकता को ही नहीं बल्कि आर्थिक सुविधा प्रदान करेंगे तथा अपनी राष्ट्रीय मितव्ययिता को पहले से भी विस्तृत आश्रय देंगे।'¹

अनियोजित मितव्ययिता की दूसरी दुबलता स्वतन्त्र जोलिम का अस्तित्व है। इससे उत्पादन तथा वितरण को ऐसे ढंग में मर्यादित या निबन्धित नहीं किया जाता

1 Considering the history of economic development in this country, one has to remark that there was lack of policy in regard to the economic development of our country. It has been truly said that the future planning of the economic life of the country must be directed to the establishment of industries which will not only cater to the demand for consumers' goods but also for capital goods and provide a broader basis for our National Economy "

जिससे समूचे समाज का उत्थान हो। 'बात साधारण है कि यह नियन्त्रण दृश्य तथा अदृश्य हो सकता है। अदृश्य नियन्त्रण जो बाजार में प्रचलित होता है, वह स्वतन्त्र जोखिम उठाने वाले योद्धाओं के हाथ का हथियार बन जाता है। दृष्टिगोचर होने वाला नियन्त्रण जिसे राज्य संचालित करता है वह नियोजन के विधायकों का विषय होता है।' इस तरह नियोजन जोखिम उठाने वाले ढंग को समाप्त कर देश की मितव्ययिता का हर तरह से—आर्थिक ढंगों या तरीकों से विकास सम्भव बनाता है।

३—आर्थिक नियोजन के सिद्धान्त का जन्म

(Growth of the Idea of Economic Planning)

अपने आदर्शों तथा विचारों में मानव सबसे अधिक परिवर्तनशील है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में सदैव विकास चाहता है। आदिम युग में उसका ज्ञान सीमित था। इस कारण वह किसी समाज की स्थापना नहीं कर सकता था। बाद में ज्ञान वृद्धि के साथ साथ समाज की उन्नति प्रारम्भ हुई तथा सम्यता का विकास हुआ। इतिहासकार तथा अन्य विद्वानों का कथन है कि पैलीओलिथिक (Palaeolithic), मीसोलिथिक (Mesolithic) आदि युग में सम्यता का थोड़ा प्रसार था। वास्तविक सम्यता का प्रसार नोलीथिक (Neolithic) युग के अन्तिम दिनों से शिशु रूप में प्रारम्भ हुआ था।

व्यक्तिगत उत्पादन तथा उपभोग के आदर्श सामूहिक प्रयासों तथा प्राप्तियों के द्वारा धीरे-धीरे एक दूसरे का स्थान लेने लगे। कालान्तर में मनुष्य ने अपने उपयोग तथा कल्याण के लिए अधिक में अधिक परिश्रम कर अधिक से अधिक उत्पादन किया। 'व्यक्तिवाद' के पश्चात् 'वर्गवाद' का जन्म हुआ। सम्यता के प्रसार से 'उद्योगवाद', 'स्वतन्त्र व्यापार' तथा 'पूँजीवाद' का जन्म हुआ। इस समय के पश्चात् ही औद्योगिक क्रांति हुई जिसमें व्यापारिक शिक्षाओं से प्रभावित होकर राज्य ने भी हस्तक्षेप किया। औद्योगिक क्रांति के आने से एकान्त्रित्व को आश्रय मिला तथा राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता कर स्वतन्त्र मितव्ययिता एवं जोखिम को बढ़ावा मिला। डेविड ह्यूम (David Hume) एवं एडम स्मिथ (Adam Smith) तथा बाद के उपयोगितावादियों ने भी इस विषय को प्रोत्साहित किया। प्रथम महायुद्ध के छिड़ जाने तक, व्यक्तिवाद का साम्राज्य था।

उन्नीसवीं सदी के पूँजीवाद की मुख्य विशेषतायें यह थी : व्यक्तिगत लाभ पर अधिक बल देना, स्पर्धा, 'गला-काट-स्पर्धा', क्रूरता, आर्थिक तथा अनार्थक प्रतिस्पर्धा, श्राप को कुछ साधोदारों में ही बाँटना, पारस्परिक मगठन ऐसे करना ताकि सदैव वे श्रमिक-वर्ग का शोषण कर सकें, व्यक्तिगत सम्पत्ति का होना एवं स्वतन्त्रतापूर्वक जोखिम को अपने हाथ में रखना। तत्पश्चात् पूँजीवाद में एक और

बुराई आगई—उन्होंने दुर्बलता तथा निर्धनता का शोषण करना प्रारम्भ कर दिया। इससे विभिन्न 'वर्गों' में द्वेष की भावना जागृत हो गई।

मजदूरों ने शोषण से बचन के लिए सघ बनाना आरम्भ कर दिया। जर्मनी तथा अन्य योरोपीय देशों में सघों की सफलता में उसके प्रवर्तक बड़े तथा उन्होंने उसके क्षेत्र को विस्तृत किया। दुर्बल तथा निर्धनों का पूँजीवादियों में अकेले सवर्ष करना नितान्त असम्भव था। कला तथा शिक्षा के तीव्र विकास द्वारा मानवीय शक्तियाँ तथा उत्पादन के साधना में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। सम्पूर्ण राष्ट्र मिलकर अनियन्त्रित शोषण का विरोध करने लगे। 'कनस्वरूप, बहुत से देशों में राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा। अतः निर्धनों को शोषण से बचाने, पूँजी पर नियन्त्रण रखने तथा पूँजीवाद के अवयवों को दूर करने के कार्यों को राज्य ने अपने हाथ में ले लिया।

पूँजीवाद के प्रवर्णण, आदर्शों के परिवर्तन, राज्य के हस्तक्षेप का लाभ तथा हस्त के केन्द्रीय नियोजन की अदम्य सफलता ने राज्य को नियोजन के लिए फिर प्रोत्साहित किया। विशेषकर, विच्छेद देशों में सोच लिया कि उनकी आर्थिक दशा को सुधारने का केवल एक ही रास्ता है और वह है केन्द्रीय नियोजन के सिद्धान्तों को अपनाना। इससे उनकी उन्नति सम्भव है। किसी अन्य प्रकार से नहीं। यही नवीन भावना बड़ी तीव्र गति से देश में केन्द्रीय नियोजन को फैला रही है। उन देशों में जो जहाँ राज्या ने केन्द्रीय योजना नहीं बनाई है, साधारण नियोजन उत्पादन, उपभोग तथा वितरण सभी क्षेत्रों में दृष्टिकोण होता है। राज्य का हस्तक्षेप तो आज का मुख्य नारा है। भारत में अग्रज के आगमन से पूर्व पूँजीवाद अस्तित्व में नहीं था। बाद में उद्योग धन्य विकास के साथ, भारत में पूँजीवाद अपने सभी अवयवों के साथ प्रविष्ट हुआ। युद्ध के पश्चात् देश की मितव्ययिता को आर्थिक नियोजन द्वारा संगठित करने के प्रयास किये गये। अब आर्थिक उन्नति के लिए केन्द्रीय योजनाएँ काम में लाई जा रही हैं।

४—नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है ?

(Why Planning ?)

यह आर्थिक नियोजन का युग है। हर देश में आर्थिक नियोजन किसी न किसी रूप में जन्म ले रहा है। इस सम्बन्ध में एच० मोरीसन (H. Morrison) ने ठीक ही कहा है, "व्यक्तिगत पूँजीवाद को पुराना पैतृक तथा अनियन्त्रित स्वर्द्धा पुराना पड़ चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति को नया आदर्श तथा दृष्टिकोण के अनुसार अपने को मोड़ना पड़ेगा।" यहाँ नहीं, आज के युग में आर्थिक नियोजन के सिद्धान्तों को अपनाने के अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

1. "The old paternal system of private capitalism and uncontrolled competition are out of date, and everyone has to adjust his outlook and ideal to the new outlook"—H Morrison

१—अनहस्तक्षेप (Laissez Faire) की पुरानी प्रणाली को दूर करना, जिसमें निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं :—

(अ) कुछ मनुष्यों के हाथों में पूँजी के संचित होने से धन के वितरण में विषमता होती है ।

(ब) धर्मिक, निर्धनो तथा दुर्बलों का शोषण होना ।

(स) अनाधिक स्पर्धा से धन का अपव्यय होना तथा एकाधिकार का जन्म ।

(द) मानव का तनिक भी ध्यान न कर लाभ के सिद्धान्त पर चल दिया जाना ।

(य) व्यवसाय-चक्र (Trade Cycle) प्रणाली को यह नहीं रोक सकती ।

२—अनियोजित अर्थव्यवस्था को दूर करना क्योंकि उसमें निम्नलिखित दोष हैं :—

(अ) अधिक-उत्पादन (Over-production) तथा कम-उत्पादन (Under-production) की सम्भावना ।

(ब) प्राकृतिक साधनों का नुटिपूर्ण शोषण तथा दुरुपयोग ।

(स) समाज में विभिन्न समस्याओं का जन्म तथा उपभोग की वस्तुओं का अभाव ।

३—“केवल नियोजन ही पूँजीवाद के अवशेषों को दूर करने की एक आशा है ।”^१ नियोजित अर्थव्यवस्था में जिम प्रकार वैज्ञानिक ढंग से उत्पत्ति होती है उसी प्रकार सुव्यवस्थित रूप से उसका वितरण भी होता है ।

४—नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वत्र विस्तृत तथा व्यापक होती है । नियोजित अर्थव्यवस्था में एक पक्षीय तथा असन्तुलित आर्थिक उन्नति की बिल्कुल भी सम्भावना नहीं होती है । ‘अनियोजित तथा स्पर्धापूर्ण प्रणाली में विनियोग बिना सोचे समझे किया जाता है तथा उत्पादन आवश्यकता से कम या अधिक होता है । प्रायः वे किसी एक वस्तु के उत्पादन के एक छोटे भाग को नियन्त्रित करते हैं । इसलिए सम्पूर्ण उत्पत्ति के विषय में ज्ञान की उनमें कमी रहती है, जिसमें सम्पूर्ण उत्पत्ति के आर्थिक परिणामों को वे नहीं जान सकते । केवल केन्द्रीय संगठन ही इसका अनुमान लगा सकता है, एक व्यक्ति नहीं । प्रतस्पर्धा में सलग्न उत्पादक समस्त उत्पत्ति का सही सही अनुमान नहीं लगा सकते ।’

५—डर्बिन (E. F. M. Durbin) के अनुसार केवल एक केन्द्रीय संस्था ही पहले में यह पता लगा सकती है कि कच्चे माल का निःशेष हो रहा है, प्राकृतिक

1. “Planning alone provides a hope and the means of remedying the ill-effects of capitalism.”—E. F. M. Durbin.

साधनों का अपव्यय हो रहा है, सौन्दर्य, स्वास्थ्य और मानव जीवन का विनाश हो रहा है—जिसके विषय में उन साहसियों द्वारा जानकारी सम्भव नहीं होती जो भविष्य के बारे में सोच व समझकर योजना नहीं बनाते।” (*Problems of Economic Planning*, pp. 50-51.) ।

६—नियोजन के अधिकारी अपना योजनाओं द्वारा सभी नागरिकों को, विशेषकर धर्मिका को पर्याप्त मात्रा में प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार के प्रोत्साहन अनियोजित राज्य में कभी प्राप्त नहीं किया जा सकते।

७—आर्थिक मंदी तथा दो महायुद्धों ने मनुष्य के विचारों को नियोजन के अनुकूल बना दिया है—जो सम्पूर्ण समाज के लाभ के लिए, धर्म तथा पूँजी दोनों के बाधों में परिवर्तन करते हैं। कुछ राष्ट्र सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र के कल्याण को सोच रहे हैं। उन्होंने सरकारी फर्मधारियों की एक सेना तैयार कर ली है, जो माधुर्य मानव जीवन को मुधारने की केला से परिचित हैं। उन्होंने सभी वर्गों को सिखा दिया है कि वग-विद्वेष को समाप्त कर दिया जाय—जिसमें उन्हें सफलता मिली है, और सफलता ही एकता की भावना को जन्म देती है।

८—संक्षेप में, नियोजन अनियोजित अर्थ-व्यवस्था के सभी अवनुष्ठानों को दूर करता है।

५—आर्थिक नियोजन से हानियाँ

(Disadvantages of Economic Planning)

१—स्वतन्त्रता का लोप—“व्यक्तिवादियों की दृष्टि में राज्य के हर कार्य का विस्तार व्यक्ति की स्वतन्त्रता में बाधक है और जो अपनी स्वतन्त्रता को तोकर अपनी आर्थिक उन्नति की आशा राज्य से करते हैं वे ऐसे ही मूर्ख हैं जैसे, कोई मारे जाने के डर में आत्महत्या कर ले। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा आर्थिक नियोजन अर्थ में विलग्नल भिन्न है क्योंकि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में बहुमुखी लाभ का गुण विद्यमान होता है तथा नियोजन का ध्येय ही व्यक्ति, वर्ग तथा समाज को अधिक से अधिक लाभ देना है।”^१

१ “Individualists say that every extension of state activity is a nail in the coffin of individual freedom. And those who wish the state to provide for their economic needs at the cost of their freedom are like fools who are so afraid of being murdered that they commit suicide. That individual freedom and economic planning are contradictions in terms because under a planned economy plurality of interests is evil and planning aims to eliminate the ‘interaction of all the numerous private interests’ of the individuals, groups or classes .. .”

२—केन्द्रीय नियोजन मानव को स्पर्द्धा तथा विभिन्न लाभो से वंचित रखता है। “राज्य को विभिन्न क्षेत्रो मे न्यायकर्ता न समझकर एकता को उत्पन्न करने वाला समझा जाना चाहिये, जिसमे विभिन्न प्रकार के लाभो की बात बिलकुल ही दूर रहगी। इसलिये विरोध को स्वतन्त्र राज्यों मे वैधानिक कार्य समझा जाता है तथा परतन्त्रो मे राजद्रोह।”

३—आर्थिक नियोजन के विरोध मे एक और आरोप है। “जब किसी नियोजक का पता लगाया जाय तो तानाशाह दिखाई देगा क्योंकि नियोजक योजना को व्यक्तियों पर लागू न करके व्यक्तियों को योजना पर लागू करता है।”

४—ग्रट्रूड विलियम्स (Gertrude Williams) ने लिखा है, “सरकार की इच्छानुसार कार्य करके स्वर्ग प्राप्ति की अपेक्षा—एक स्वतन्त्रता, जिसके लिये हममे से बहुत से मृत्यु का आलिङ्गन करना चाहेंगे या इच्छापूर्वक खार्ड मे राक्षस से मिलना ठीक समझेंगे।”^१ इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति राज्य नियन्त्रण का अधिक से अधिक लाभ कभी भी नहीं उठा सकता। इसलिये राज्य नियोजन स्वतन्त्र व्यापार से सदैव कम लाभदायक है।

५—नियोजन मे नियामक सरकारी कर्मचारी होते है, इसलिये वे कभी भी ऐसे उत्साह से, मन लगाकर तथा साहसपूर्वक कार्य नहीं करते जैसा कि व्यक्ति स्वतन्त्र-व्यापार प्रणाली मे करते है। परिणामस्वरूप, स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था से इसमे कम सफलता मिल पाती है।

६—केन्द्राय नियोजन के विरोध मे एक मुख्य आरोप यह है कि नियोजन के अधिकारी प्राकृतिक साधनों और शक्तियों के उत्पादन का अनुमान लगाने मे नितान्त भ्रमन्त रहते है। यह दोष स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था मे नहीं हाता।

७—राज्य नियोजित प्रणाली मे सशय तथा प्राप्तियों की ओर दृष्टि मे जनता सहयोग नहीं देती है।

८—राज्य अपने नियोजन मे दृढ नहीं रहता।

प्रोफेसर हेक (Prof Hayek) का नियोजन के अवगुणो के विषय मे मत^२।

(१) “सम्पूर्ण नियोजन उत्साह तथा स्वेच्छापूर्वक लागू करना चाहिये ताकि नाश का भय न रह जाय।”

1. “One of the freedoms for which most of us would be prepared to die in the last ditch is the right to go to the devil in our own way, rather than to paradise by government way.”

2. Road to Serfdom—Hayek., diff. chapters.

(11) “उपभोक्ता की सत्ता, व्यावसायिक स्वातन्त्र्य एवं स्वतन्त्र नैतिक न्याय से वंचित होंगे।”

(111) “सम्पत्ति का लोप होना—जाना-बूझा ही राजनैतिक सत्ता द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति का हनन होना है।”

(1V) “लोकतन्त्र के विरोध में की हुई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप दुरे से दुरे व्यक्ति सत्ताधारी बनने हैं, सत्ताधारी दल अपने विरोधियों को अपनी सत्ता के बल पर विभिन्न प्रकार की यातनायें देकर अपनी घोर मोहने के लिये विवश करता है। इस प्रकार समूहवाद का उत्थान मनुष्यों में दुरी भावनाओं को फैलाता है।”

(V) “योजना को कार्यान्वित करने से नागरिकों को नैतिक न्याय मिलने से वंचित होना पड़ता है, जिसके कारण विचार स्वातन्त्र्य तथा बाह्य बातें व्यर्थ पड़ सकती रह जाती हैं।”

(VI) “सत्ताधारियों की विजय से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की सम्भावना बिलकुल दूर भाग जाती है।”¹

प्रो० मिर्ज़ेन तथा वॉबर (Prof Mises and Max Waber) ने आर्थिक नियोजन का विरोध करने हुए लिखा है, “समाजवादी अर्थ-प्रवस्था में बाजार के नियन्त्रण एवं मूल्य के निर्धारण की कोई विधि नहीं है तथा उत्पादन के साधनों के महत्व का ठीक ठीक अनुमान लगाने की कोई सम्भावना नहीं है। विशेष तौर से उत्पादन के साधना का, जब तक वे बाजार में नहीं आ जायें, सही मूल्य

1 Prof Hayek's views (*Road to Serfdom*, diff. chapters) —

(i) “The all embracing plan must be enforced by arbitrary administrative decision so the rule of Law will disappear”

(ii) “Consumers' sovereignty, the free choice of occupation and right to independent moral judgment must all be sacrificed”

(iii) “The disappearance of property leads to the direct determination of the individual's wealth and status by the dictatorial political power”

(iv) “The reaction against democracy brings the worst people into power, with the concentration camp and the torture chamber as their favourite instruments of government, and the growth of collectivism releases the inflames of the evil passions of the people”

(v) “In order to make the plan work, all citizens must be coerced or deceived into making the same moral judgment, so that freedom of thought and objective science must be stamped out”

(vi) “With the conquest of authoritarian rule, the possibility of a moral life disappears”

निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि नियोजित अर्थ व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व ही नहीं होता है—तो उत्पत्ति के साधनों का सच्चा बाजार कैसे सम्भव हो सकता है ? कुछ भी हो, यह सब सिद्धान्त पक्षपातपूर्ण है । हम पूर्णतया इन मतों से सहमत नहीं हो सकते ।

६—नियोजन की विशेषतायें (Characteristics of Planning)

डरबिन (E F M. Durbin) की राय में नियोजन की प्रमुख विशेषता यह है, “नियोजन विभिन्न उद्योगों के स्वेच्छापूर्वक कार्य करने वाले दृष्टिकोण को तनिक भी प्रोत्साहित नहीं करता है । नियोजन सबिषय के विषय में कोई निश्चित दृष्ट सिद्धान्त नहीं बताता है न बनाने चाहिए । विस्तारपूर्वक भावी मानवीय इच्छाओं, कलात्मक आविष्कार, सुरक्षा तथा चुनहालों का वर्णन नहीं किया जा सकता । इसलिए ऐसी योजनाओं का बनाना मूर्खता है जो समाज की आवश्यकताओं को तथा परिवर्तनों को ध्यान में रखकर शीघ्र हो परिवर्तित नहीं की जा सकती । फिर नियोजन की वास्तविक विशेषता क्या है और कहाँ है ? सर्वसाधारण की नवीन योजनाओं पर विचार किया जाय तो कह सकते हैं कि नियोजन इकाइयों के विस्तार को विस्तृत करने का तथा उसके परिणामस्वरूप उनके क्षेत्र को व्यापक करने का प्रबन्ध है । यह धार्मिक निर्णय के समय पर ही किया जाता है ।”²

1. “Within a socialistic economy there is no provision for market control of the process of price formation and, therefore, no possibility of accurate evaluation of the force of production. Particularly, it is impossible to determine accurately the price of the means of production, since this can be worked out only in the market, whereas under a planned economy, with no private ownership of capital there is no market for the means of production.”

2. “Planning does not, in the least imply the existence of a plan in the sense of an arbitrary plan for different industries. Planning does not, and should not imply any dogmatism about the future. It is not possible to tell in detail what will happen to human tastes, to technical invention, to general standard of security and well being. It would, therefore, be foolish in the extreme to lay down plans which could not be amended quickly in the light of changing social requirements. Where then is the true characteristic of planning. The element common to all the forms of new control we regard as planning is the extension of the size of unit of management and the consequent enlargement of the field surveyed when economic decisions are made.”

योजना को सफल बनाने के लिए, उसमें अस्थिरता (Dynamism) तथा लचीलपन (Flexibility) के तत्वा का समावेश करना चाहिए। डॉ० वालकृष्ण ने नियोजन की प्रणाली (Planning Techniques) पर विचार करते हुए संकेत किया था, 'नियोजन एक अस्थिर सिद्धान्त है। केवल लक्ष्य एवं विनियोग के विषय में यह स्थिर (Static) है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उपायों के प्रयोग के साथ, नियोजन की अस्थिरताओं के सुदृढ़ अध्ययन को भी अपनाना चाहिए। नियोजन के अर्थ के साथ हीमन के तत्व में परिवर्तन होना आवश्यक है, तथा, क्रम के अभाव में, अर्थ व्यवस्था के विभिन्न खण्डों में, वे प्रसाधनों की मुसगठित रूप पर विचरित प्रभाव डालेंगे।'¹ श्री नेहरू ने भी राष्ट्रीय विकास समिति (National Development Council) में भाषण देने के अवसर पर इंगित किया था कि, 'नियोजन, वास्तव में, एक लगातार जारी रहने वाला सिद्धान्त है। नियोजन का अर्थ केवल वस्तुओं के उत्पादन में प्राथमिकता देना ही नहीं है। यह विस्तृत एवं गम्भीर विषय है—नियोजन की प्रथम बात यह है कि उसमें गत-व्यय अर्थात् मजिल की एक निश्चित रूपरेखा होती है। इस रूपरेखा की दृढ़ होने की आवश्यकता है।'²

नियोजन की व्यापक एवं पूर्ण बनाने के लिए दीर्घकालीन नियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें अल्पकालीन योजनाएँ भी सम्मिलित होनी चाहिए। नियोजन, यदि वह अनन्त इमारत नहीं है, तो उसे दीर्घकालीन सिद्धान्त होना चाहिए जिसे दीर्घकालीन नियोजन कहते हैं। मावियन संघ चीन, संयुक्त अरब गणराज्य, भारत एवं पाकिस्तान आदि सभी देशों में दीर्घकालीन नियोजन है। इसमें भी केवल एक मात्र योजना ही नहीं होनी चाहिए वास्तव में आर्थिक नियोजन की सम्पूर्ण प्रणाली को

1 'Planning is a dynamic process. To think merely in terms of targets and investments is purely a static approach. With the implementation of the measures to reach targets a concurrent study of the dynamics of planning should be undertaken. Factor prices are bound to undergo a change with the impact of planning and in the absence of regimentation, they would exert an adverse influence on the allocation of resources among different segments of economy' (Planning Technique and the Indian Plan frame Dr R. Balkrishna, Commerce, Annual Number, Dec 1955 P. A—28)

2 'Planning of course, is a continuous process. Planning does not mean merely giving priorities to things. It is something wider and deeper, the first thing about planning is to have a definite picture of where we are going. This picture need not to be very rigid' (Planning and Development—Speeches of Shri Nehru Speech delivered at the N D C Meeting on Nov 9, 1954 (Govt of India Publication, P. 15))

कई समय अथवा योजनाओं में विभक्त कर देना चाहिए । जैसे भारत की पंचवर्षीय योजना वार्षिक योजनाओं के आधार पर संचालित होती है । विस्तृत योजनायें विस्तृत दृष्टिकोणों एवं उद्देश्यों की ओर संकेत करती हैं, तथा अल्पकालीन योजनायें साधारण ढंग से संचालित की जाती हैं । हमारी योजनाओं में स्पष्टतः इस बात का संकेत है कि लम्बो-ध्रुवी (Long-range), छोटी-छोटी श्रेणियों के समुदाय से बनती है अर्थात् बड़ी योजना लघु योजनाओं (वार्षिक योजनाओं) का समूह मात्र होती है ।"



1. Second five year plan—Govt. of India, pp. 18-19.

नोट—'योजनाओं की विशेषतायें', अध्याय १३ में भी है ।

आर्थिक नियोजन के उद्देश्य

(Objectives of Economic Planning)

१—सामान्य सिद्धान्त

(General Theory)

आर्थिक नियोजन के उद्देश्य भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मुख्यतया, यह निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास करता है :—

- (१) आर्थिक जीवन में स्थायित्व।
- (२) उत्पादन में कुशलता।
- (३) वितरण में समानता।

इसके विपरीत कैलहेड (W. Kellham) का कहना है कि नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्न आठ बातों का समावेश होना चाहिए :—

- (क) भविष्य की आवश्यकताओं का स्वरूप जिनकी कि हम सन्तुष्ट करना चाहते हैं।
- (ख) समय, जबकि आवश्यकताएँ सन्तुष्ट करनी होंगी।
- (ग) वस्तु सामग्री तथा व्यक्तिगत सेवाएँ जो कि आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिये आवश्यक हैं।

- (a) "The nature of the future want which we wish to satisfy.
- (b) The time, when the want will have to be satisfied
- (c) The material goods and personal service required to satisfy the want
- (d) An appropriate method for producing, acquiring or securing the required goods and services
- (e) The probable sacrifices for the achievement of the intended results
- (f) The calculated balance, according to a personal or social standard, between intended results and probable sacrifice
- (g) The resolution to carry out the activities under consideration or to give them up.
- (h) If the resolution is positive, an appropriate plan for its execution." —W Kellham.

(घ) आवश्यक सामग्रों तथा सेवाओं को उत्पन्न करने, प्राप्त करने तथा लाभ उठाने की उचित प्रणाली ।

(ङ) वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए सम्भावित बलिदान ।

(च) वांछित परिणामों तथा सम्भावित बलिदानों के बीच व्यक्तिगत अथवा सामाजिक स्तर के अनुसार अनुमानित मन्तव्य ।

(छ) जिसे जाने वाले कार्यों या उनको छोड़ देने की सम्भावना पर विचार ।

(ज) यदि प्रस्तावना स्वीकृत हो जानी है तो उसको कार्यान्वित करने के लिए उचित योजना का निर्माण ।

बी०सी० घोष के बहमनुसार आर्थिक नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(१) "नियोजन सामाजिक उद्देश्य में उत्पादन तथा वितरण का अल्पकालीन ही नहीं बल्कि दीर्घकालीन माधन है ।

(२) "मनुष्यों के रहन सहन के स्तर की उन्नति के माध्यम्य पूर्णरूप में रोजगार मिलने का प्रवन्ध करता है ।

(३) देश का औद्योगीकरण करना है ।"

कुछ अन्य विद्वान् आर्थिक नियोजन के वर्तमान उद्देश्यों से मन्तव्य नहीं हैं । प्रॉ० बी० राव का मत है कि "पूर्ण नियोजन अर्थ-व्यवस्था का अर्थ है, आर्थिक क्रियाओं के पूर्ण क्षेत्र पर नियन्त्रण रखना अर्थात् उत्पाति, उपभोग, वितरण एवं वृद्धि आदि पर नियन्त्रण रखना ।"

प्रॉ० वाडिना तथा मर्चेंट के विचार में नियोजन का अर्थ है, "मनुष्यों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना, आर्थिक मायनों का समुचित उपयोग करके उनका बहुमुखी विकास करना, नुकी एवं समृद्ध जीवन की सम्भावना को बढ़ाना, देश में यान्त्रिकी के मायनों का समुचित प्रवन्ध करना, गृह उद्योग-व्यवसायों को विकसित

1. (a) 'Planning, as we shall understand it, means production and distribution with social purpose—not only for a short period, but also for a long period.

(b) "The attainment of full employment as well as the progressive improvement in the standard of living of the people.

(c) Industrialization of the country."—B. C. Ghosh

(2) "A full fledged planned economy would mean complete control over the entire field of economic activity—production, consumption, distribution, money etc."—R. V. Rao.

करना, ग्राम्य जीवन को समृद्ध बनाना तथा अधिक विस्तृत बाजारों का निर्माण करना।¹

प्रो० आर्देशीर दलाल ने भी लिखा है कि “नियोजन का उद्देश्य उत्पादन का अधिक में अधिक सम्भव सीमा तक विकास करना तथा सर्वसाधारण के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना।”

साधारणतया सभी प्रकार के नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं :—

(क) आर्थिक नियोजन, पूर्व-निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये, नियोजकों का पूर्ण निश्चित तथा सामूहिक प्रयास होता है। लक्ष्य तथा उद्देश्य नियोजन-कारियों द्वारा निश्चित किये जाते हैं। उनको निश्चित करते समय वे देश में फैली हुई कुरीतियों, आर्थिक बुराईयों, देश की आर्थिक दशा तथा विकास की आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हैं।

(ख) आर्थिक नियोजन का ध्येय उत्पत्ति ध्यय को सम्भावित सीमा तक कम करना है। यह एक अन्य उद्देश्य है जिसका लक्ष्य कम कीमत से अधिक उत्पादन करना तथा उपभोग को बढ़ाते हुए रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना है। उत्पादन की क्षमता के विषय में भी नियोजक द्वारा पहले ही निश्चित कर लिया जाता है।

(ग) सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा अवसरों की माँग एवं पूर्ति में पहले से अच्छा सन्तुलन करना। साथ ही साथ इसके द्वारा अनियोजित अर्थव्यवस्था के अवयवों को दूर कर दिया जाता है। जब तक माँग तथा पूर्ति में समुचित सन्तुलन स्थापित नहीं होता है तब तक नियोजन के अधिकारी माँग की असमानता का दूर करने में, रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में, तथा समुचित अवसर प्रदान करने में असफल रहेंगे।

२—नियोजन के विरोधी उद्देश्य

(Rival objectives in Planning)²

अधिक उत्पादन अथवा अधिक रोजगार (More output or more employment ?)

सर डेनिस रीवर्टसन (Sir Dennis Robertson) ने बिल्कुल ठीक कहा है, “आर्थिक उत्थान को प्राप्त करने की विशेष आवश्यकता उपभोग के त्याग से ही केवल

1 “To raise the standard of living of people, to bring to them by a many sided improvement of economic resources, the possibilities of a richer and fuller life, to provide improved transport facilities within the country, to develop our domestic industries, to provide amenities to rural life and to create larger home markets.”

2. Rival Objectives of Planning—Ashok Mehta (Facts of Planning, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, pp. 57—67.)

सम्बन्धित नहीं है बल्कि व्यवस्थित दिनचर्या में क्रियाशील रूप से कार्य करने का परामर्श है—जो अधिक कठिन है।¹ नियोजन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें इन सम्भव परिवर्तनों पर विचार करना होता है। उदाहरणार्थ, जब कभी हम बेकारी के पहलू, अथवा इससे भी अधिक, आर्थिक विकास पर रोजगार के दृष्टिकोण से विचार करते हैं, तो यह स्मरण रखना आवश्यक हो जाता है कि यह व्यवस्थित जीवन की लय तथा कार्य में पर्याप्त परिवर्तन लाता है। बेरोजगार अथवा अपूर्ण रोजगार वाले व्यक्तियों की शक्ति को विकास के लिये एकत्रित कर देना है। पंचवर्षीय योजनाओं का मौलिक रूप देखा जाय तो प्रतीत होगा कि उनमें लाखों ही हल्के कार्यों की वृद्धि की प्रस्तावना की गई है। यह अतिरिक्त रोजगार की प्रस्तावना है, स्थापना नहीं। परम्परागत दोष पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक स्वरूप के विद्यमान होने के कारण, छिपे हुए एवं पक्षपात से उत्पन्न बेरोजगारी के कारण तथा जनसंख्या में द्रुतगति से वृद्धि होने के कारण, योजना निम्नित अतिरिक्त कार्य बेरोजगारी की समस्या को मूल नष्ट करने के लिए कम पड़ गये हैं। इस प्रकार, हमारी योजनाओं में प्रस्तावित लाखों अतिरिक्त हल्के कार्यों के उत्पन्न होने के बावजूद भी ऐसी सम्भावना की जाती है कि सन् १९५६ से सन् १९६१ में बेरोजगारी और अधिक हो जायगी।

प्रो० सी० एन० वकील (Prof. C. N. Vakil) ने भी सकेत किया है—
 “छिपे हुए बेरोजगार की समस्या का मुख्य कारण यह है कि नियोजित अर्थव्यवस्था जनसंख्या की बढ़ती हुई गति को ध्यान में रखकर उसके अनुपात से व्यय अथवा लागत नहीं लगाती है।”² इस प्रकार योजना में जो लागत अथवा विनियोग रखा गया है, हमें उसमें दुगने के लिए सोचना चाहिए। यदि बड़े एवं भारी उद्योगों पर अधिक बल दिया जाता है तो उसमें उद्योगों में अभिनवीकरण की स्थापना से, उत्पत्ति में प्राचोर्गिक परिवर्तनों के कारण, एवं पूँजीवादी उत्पत्ति के सिद्धान्तों के ग्रहण करने से, अधिक बेरोजगारी उत्पन्न होना आवश्यक हो जाता है। इसके विपरीत, यदि छोटी माना के उद्योग एवं श्रमिक प्रमुख (labour intensive) उत्पत्ति के सिद्धान्त का समर्थन दिया जाता है तो वे देश की तीव्र आर्थिक उन्नति में बाधक ही भाविन होंगे। इसलिए, दोनों सिद्धान्तों का मिश्रण

1. “The sacrifice necessary to achieve economic growth consists not only in passive abstinence from consumption, but in something which is much harder—namely, consent to being disturbed in established routine of life and work”—Sir Dennis Robertson.

2. “The problem of disguised unemployment arises because the economy does not step up the rate of investment above that of population growth.”—Prof. C. N. Vakil.

ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें देश की आर्थिक उन्नति की प्रगति में बिना किसी बाधा के अधिक रोजगार की शक्तियों का विकास होना सम्भव हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि 'विकास स्वयं ही रोजगार को बढ़ावा देता है।' आर्थिक विकास के परिवर्तनों के साथ जैसे ही परम्परागत सामाजिक संगठन समाप्त होते हैं तो छिपा हुआ रोजगार स्पष्ट हो जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा पारिवारिक दृढ़ता का जैसे ही अलग अलग होना आरम्भ हो जाता है तो अधिन में अधिक ग्रामीण व्यक्ति रोजगार की खोज में निकल पड़ते हैं।

के० एन० राज—बी भी राय हैं कि, "बम विकसित अर्थव्यवस्था में रोजगार की समस्या क्रमशः बढ़ती ही रहती है। क्योंकि, आर्थिक विकास की प्रगति के साथ तथा इसके फलस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक वातावरण में परिवर्तनों के आने से, पुराने सामाजिक संगठन के शेष व्यक्तियों में आशा की जा सकती है कि वे अपने फालतू थम को कार्य में लगा दें।" इस प्रकार, सम्पूर्ण रोजगारी की समस्या को हल करने के लिए अधिक विनियोग की आवश्यकता होती है।

प्रो० आर० नर्सक (Prof Ragnes Nuiske) ने पूँजी निर्माण के लिए देहाती क्षेत्रों में प्रतिदिन देहाती थम के लिए अधिक अवसर प्रदान करने का दृढ़तापूर्वक प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा है, "फालतू समय पूँजी एकत्र करने का मौलिक साधन है। कृषि में अधिक मक्या में सलमन कृषक समुदाय के लिए फालतू समय से आमदनी करने का अवसर पहले से ही विद्यमान है। इस फालतू थम के द्वारा पूँजी के निर्माण के लिए वर्तमान कार्य पद्धति में विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, अपने समय के कुछ अंश को पूँजी वाले कार्य में प्रयुक्त करके ही प्राप्त किया जा सकता है।"

३—समाज सेवा या उद्योग ?

(Social Service or Industry ?)

अजोब मेहता ने ठीक ही कहा है, "यह सम्भव है कि सर्वाधिक लाभकारी लागत प्रणाती लोगों के हित का उत्थान करने के लिये उत्तम होयी। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मकानों की मुख्यवस्था का प्रबन्ध करने का तात्पर्य है उनको अच्छा नागरिक बनाना और इसलिए इसमें यह आशा की जा सकती है कि इस प्रकार अच्छे कर्मचारी उत्पन्न होंगे।" श्री नेहरू ने इस दशा का नाम 'व्यक्तियों की लागत' (Investment in masses) दिया है। प्रतिदिन की औसत Calories intake की साधारण व्याख्या से सिद्ध होगा कि अन्य कारणों के साथ साथ हमारे श्रमिकों में अकुशलता,

सुस्ती, अनुपस्थिता, रोग, शीघ्र थकान आने की भावना विशेषरूप से विद्यमान है।^१

प्रो० हैरो लैंबिस्टीन (Prof. Harrey Leibenstein) ने अपनी 'Economic Backwardness and Economic Growth' नामक पुस्तक के पृष्ठ ६५ पर लिखा है, "Calorie intake एवं उत्पत्ति में सम्बन्ध १९४२ तथा १९४५ के मध्य जर्मनी में Krant एवं Muller ने बहुत से अध्ययनों द्वारा बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया है।" जो बात अन्धे एवं मनुलिन भोजन के लिये सत्य है वही बहुत कुछ सामाजिक हित के अन्य विषयो—शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की सुविधाये, मकान आदि में भी बिलकुल सत्य है। लाश्ल डबल्पू० शैन्नन (Lashle w Shannon) के विचार में "आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए एवं आर्थिक दृष्टि में उन्नत देशों की आर्थिक प्रगति की भिन्न भिन्न दरें, कृषि-प्रधान राष्ट्रों को औद्योगिक राष्ट्रों में परिवर्तित करने के लिए साक्षरता तथा शिक्षा के प्रसार के महत्त्व की ओर संकेत करती है।"^२

४—केन्द्रीय लक्ष्य (Central Objective)

नियोजन आयोग ने पञ्चवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए योजना के निम्नलिखित केन्द्रीय उद्देश्य बतलाये हैं :—

नियोजन का केन्द्रीय उद्देश्य रहन सहन के स्तर को ऊँचा करना, सर्व-साधारण को अधिक सम्पन्न व समृद्ध बनाना, सबको सुखवमर प्रदान करके उन्हें अधिक धनी बनाना तथा जीवन के सभी पहलुओं को उत्तम बनाना है। इसलिए यह दोनों ही उद्देश्यों की ओर संकेत करता है।

१—देश में प्राप्त उत्पत्ति के भौतिक तथा मानवीय साधनों का संतुलित ढंग से कार्य में लगाना ताकि अधिक में अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो सके।

२—धन की असमानता को दूर किया जाय एवं सबको सुखवमर प्रदान किया जाय।

प्रारम्भिक अवस्था में अधिक उत्पादन के नियोजन पर अधिक धन दिया जाता है। प्रारम्भ में सामाजिक तथा आर्थिक स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देना उचित नहीं है। रचनात्मक कार्य स्वयं ही

1. Calorie intake (Average) in under-developed areas = 2100 per day.
Calorie intake (Average) in middle income Areas = 2200-2800 "
Calorie intake (Average) in advance countries = Above 3000 "
2. L. W. Shannon, 'Under Developed Area' P. 113.

यह सत्य है कि भारत के स्वाधीन होने के पश्चात् राजा तथा उनकी विशाल सम्पत्ति का वैभव अतीत की बात बनकर रह गये हैं और उनकी रियासत छीन ली गई हैं लेकिन आय तथा धन को असमानता आज भी हमारे देश में बड़े रूप से व्याप्त है ।

ग्राम्य तथा शहर के समाज, सम्यता तथा आर्थिक परिस्थितियों की पूर्ण व्यापक विपरीतताओं ने भी असमानता का जन्म दिया है । यह अन्तर हमारा आर्थिक प्रणाली के दोष से उत्पन्न हुआ है । कृषि तथा ग्रामीण शिक्षा पर अत्यन्त निर्भर रहना तथा उनसे आज के उद्योगों की अपेक्षा बहुत कम उत्पादन होना भी असमानता का मूल कारण है । इस असन्तुलन तथा हमारे आर्थिक म्बल के बढ़ने के लिए पञ्च-वर्षीय योजनाओं को जन्म दिया गया है । जैसे सविधान ने राजनैतिक तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करने के प्रयत्न किये हैं उसी भाँति आर्थिक नियोजन भी आय तथा धन की असमानताओं को दूर करेगा ।

आर्थिक असमानता को दूर करने में मुख्य बाधा स्वयं असमानता है । क्योंकि यदि असमानता का विनाश करने एवं सबको भाग्य मामलों में उचित भाग मिलने का आश्वासन देने वाली विधि अपनाई जाय तो रोटो छटा होती जायेगी । तात्पर्य यह है कि पूर्ण व्यापक असमानता को यदि किसी भी आवश्यक वस्तु के खण्ड करके दूर किया जाय तो एक दूसरी असमानता की समस्या और सम्मुख आयेगी तथा इससे तनिक भी लाभ नहीं होगा । इसलिए 'आश्वासन दिवाना आवश्यक है ।'

८—समानता की ओर (Towards Equality)

यदि 'धुराई के कारणों को नष्ट कर दिया जाय तो धुराई स्वयं नष्ट हो जानी है ।' इसलिए हमारे देश में आर्थिक असमानता ख़त्म करने एवं आर्थिक समानता की ओर अग्रसर होने के लिए निम्नलिखित उपाय बताए गये हैं तथा उनका अनुसरण किया गया है एवं किया जा रहा है :—

(क) कम्पनी कानून में सुधार करना एवं उद्योगों के स्वामित्व तथा नियन्त्रण के एकीकरण को समाप्त करना ।

(ख) इम्पेरियल बैंक और जीवन रीमा कम्पनियाँ का राष्ट्रीयकरण करना, जिनमें कि समाज की बहुत बड़ी वर्ग का भाग एकत्रित है ।

(ग) आर्थिक संघ की स्थापना, जिसमें उद्योगों—और विशेषकर नवीन व्यापारियों को भुविषा दिये जाने का इन सच में प्रबन्ध होना ।

(घ) उद्योगों का राष्ट्रीयकरण—समाजवादी अर्थ व्यवस्था की स्थापना के लिए यह परमावश्यक है कि राष्ट्र के समस्त प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया

जाय। देश की आर्थिक असमानता को दूर करने का और औद्योगिक उन्नति प्राप्त करने का केवल यही एक उपाय है। इस उद्देश्य की पूर्ति के प्रयास में भारत के समस्त उद्योगों को स्वामित्व और नियन्त्रण की दृष्टि से इन तीन भागों में विभाजित किया गया है—सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्र एवं निजीक्षेत्र। सरकार का लक्ष्य अन्तिम रूप में समस्त उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना है।

(ड) विकेन्द्रीकरण—सहकारी प्रथा के अन्तर्गत लघु और कुटीर उद्योगों का संगठन करके।

(च) कृषि और कृषि-सम्बन्धी उद्योग-धन्यो की उन्नति करना। कृषि-सम्बन्धी कानून में सुधार करके, सामुदायिक विकास कार्यों की उन्नति द्वारा और राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं में विस्तार करके।

(छ) आर्थिक असमानता को कम करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली को अपनाया गया है। स्वतन्त्रता से पहले की कर-नीति में सुधार के साथ साथ 'एस्टेट टैक्स' और 'कैपिटल गेन्स टैक्स' लगाए गए हैं।

(ज) अधिकतम आय की सीमा को कम करके और न्यूनतम आय की सीमा को बढाकर भी असमानता को दूर किया जा रहा है।

(झ) कृषि उत्पत्ति में वृद्धि, शिक्षा और रोजगार के अधिक सुभवसर और उद्योगों का विकास इस उद्देश्य से हो रहे हैं, जिससे आय की असमानता दूर हो सके।

९—समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना

(The Attainment of a Socialistic Pattern of Society)

समाज का समाजवादी रूप—इसका उद्गम तथा अर्थ :

सन् १९४६ में अवादी (Avaldi) में स्वीकृत हुए आर्थिक नीति के प्रस्ताव (Economic Policy Resolution) का उद्देश्य था—“देश के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विकास करना, देश में अधिक वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति करना, जीवन-स्तर को ऊँचा बनाना और रोजगार के सुभवसर उत्पन्न करना—जिससे दस साल की अवधि में सम्पूर्ण रोजगार का लक्ष्य पूरा हो सके।” प्रस्ताव में आगे कहा गया था कि “राष्ट्र का ध्येय हितकारी राज्य की स्थापना तथा समाजवादी आर्थिक समाज की स्थापना करना है। यह केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि और अधिक उत्पत्ति एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करके प्राप्त हो सकते हैं।”

प्रस्ताव में यह भी बताया गया था कि समाजवादी समाज की स्थापना में “राज्य, नियोजन तथा विकास के कार्य में आवश्यक रूप से एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा।” राज्य बड़े पैमाने पर योजनाएँ बनाने का प्रयत्न करेगा। इसके अन्तर्गत राज्य, शक्ति, यातायात के साधन और अन्य बातों के विकास में सहयोग प्रदान करेगा और देश की आर्थिक विपमताओं को दूर करेगा। समाजवादी ढंग के समाज की विशेषताएँ निम्न हैं:—

(क) समाजवादी समाज की प्रणाली का मूल उद्देश्य एक ऐसे सामाजिक तथा आर्थिक क्रम की स्थापना है, जिसके अन्तर्गत समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सुअवसर समान रूप में मिले।

(ख) इस प्रकार का समाज जाति पॉति, धर्म और स्त्री-पुरुष के भेदभाव तथा आर्थिक असमानता के अन्तर को दूर करे।

(ग) राज्य, राष्ट्रहित के उद्देश्य से उत्पत्ति के साधनों का नियन्त्रण अपने हाथ में ले।

(घ) समाज आर्थिक प्रणाली का एक ऐसे ढंग से संगठन करे जिससे, राष्ट्र की सम्पत्ति केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में एकत्रित न हो जाय। क्योंकि इससे देश की जनता को हानि होती है।

(ङ) देश की सम्पत्ति में वृद्धि करने के लिए और उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि करने के लिए मुख्यवस्थित प्रयास करना।

(च) राष्ट्रीय आय को समान रूप से वितरित करना और इसके द्वारा आर्थिक विपमताओं को दूर करना।

(छ) इस प्रकार का सामाजिक तथा आर्थिक निर्माण शान्तिपूर्वक एवं लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों के आधार पर हो।

समाजवादी ढंग के समाज के सात सिद्धान्त^१:

(१) प्रथम सिद्धान्त के अनुसार नागरिकों को पूर्ण रोजगार तथा कार्य करने का अधिकार मिलना है। समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना तभी सम्भव हो सकती है जबकि देश के कार्य के उपयुक्त सभी व्यक्तियों को कार्य करने का सुअवसर मिले।

(२) समाजवादी ढंग के समाज का दूसरा सिद्धान्त राष्ट्र की सम्पत्ति का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाना है। समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के योग्य

1. *Socialistic Pattern of Society*—Shriman Narayan, A I C C, New Delhi.

2. *Ibid.*

नागरिकों को योग्यतानुसार व्यवसाय और रोजगार दिलाना ही पर्याप्त नहीं है साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि आर्थिक जीवन को एक ऐसे ढंग से संगठित किया जाय जिससे उपभोक्ता की वस्तुप्राप्ति के उत्पादन में वृद्धि हो और रहन सहन का स्तर ऊँचा हो सके ।

(३) इसका तीसरा सिद्धान्त यह है कि राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर हो जाय ।

(४) समाजवादी ढंग के समाज का चौथा मौलिक उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त करना है । कोई समाज उस समय तक सही ढंग से समाजवादी नहीं कहा जा सकता है जब तक कि इसके संगठन में सामाजिक एकता तथा न्याय न हो । आर्थिक असमानता तथा अन्याय को दूर करने के साथ साथ भारतीय समाज में अधिक में अधिक समानता लाना भी बहुत आवश्यक है ।

(५) समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक और प्रजातन्त्रात्मक प्रणालियों को अपनाकर होनी चाहिए । संसार के समाजवादी और साम्यवादी राष्ट्रो ने समाजवाद की स्थापना बर्ग संघर्ष, हिंसात्मक प्रणाली और गृह-युद्ध की अपनाकर की है । पर भारत का ऐसा कोई विचार नहीं है कि वह इन समाजवादी या साम्यवादी राष्ट्रो की पद्धति का अनुकरण करे । प्रथम और द्वितीय योजनाएँ इन्हीं आधारों पर आधारित हैं ।

(६) इसका छठवाँ मूल उद्देश्य ग्राम पंचायतों तथा सहकारी उद्योगों की स्थापना करके आर्थिक तथा राजनैतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना है ।

(७) समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना का अंतिम लक्ष्य यह है कि देश के सबसे निर्धन वर्ग का सर्वाधिक लाभ या सुविधायें राज्य द्वारा प्रदान की जायें । भारत में समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना इसीलिए हो रही है जिससे देश की साधारण जनता जो अत्यधिक गरीब है—को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके ।

समाजवादी ढंग का समाज तथा भारतीय योजनाएँ ¹ (Socialistic Pattern and Indian Plans)

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माताओं ने वियोजन के अन्तर्गत समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना पर बल प्रदान किया है । मौलिक कल्याण में वृद्धि या जीवन स्तर में उन्नति ही नियोजन का एकमात्र ध्येय नहीं होना । यदि किसी समाज को अपने अधिकतर समय और कार्य के घण्टा को जीवन के लिए आवश्यक वस्तुप्राप्ति को उत्पन्न करने में ही व्यतीत करना पड़े तो वह जीवन के उच्च आदर्शों की प्राप्ति न कर सकगा ? आर्थिक विकास का साधन राष्ट्र की उत्पादन

शक्ति को विस्तृत करना तथा एक ऐसे वातावरण को उत्पन्न कर देना है, जिसमें उत्पादन और विकास के क्षेत्रों का विस्तार ही सके।

अविकसित देशों का सच्य केवल यही नहीं होना कि देश में आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाय, बल्कि उन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में इस प्रकार का परिवर्तन लाना होता है, जिससे देश की आर्थिक उन्नति द्रुतगति में हो एवं जीवन के उच्च आदर्श भी प्राप्त हो सकें।

इन महत्ताओं तथा मूल उद्देश्यों को 'समाजवादी ढंग के समाज' ढाँचों में समावेश किया गया है। विकास के मूल सिद्धान्त को निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका वास्तविक अर्थ व्यक्तिगत लाभ न होकर सामाजिक लाभ है। विकास को प्रणाली में सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्ध इस प्रकार नियोजित होने चाहिए जिसमें कि राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में केवल समुचित वृद्धि ही न हो, बल्कि विभिन्न वर्गों में आय तथा सम्पत्ति के वितरण में भी समानता आ जाय। उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा नियोजन के मूल सिद्धान्तों का निर्णय नियोजकों द्वारा सामाजिक उन्नति के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। नियोजन के द्वारा एक ओर दखि वर्ग को अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिए और दूसरी ओर, राष्ट्र में सम्पत्ति तथा आय का समान वितरण होना चाहिए।

कुछ मुख्य उद्योगों में, जिनमें बड़ी मात्रा में उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्ति की नवीनतम प्रणाली अपनाई जाती है, उत्पादन-कार्य पर नियन्त्रण होना चाहिए। इन क्षेत्रों में विकास का उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्य का होगा, तथा नवीनतम उद्देश्यों को भी राज्य संचालन के अन्तर्गत माना पड़ेगा। प्रबन्ध में जनता का पूर्ण या आंशिक स्वामित्व, नियन्त्रण अथवा सहयोग उन क्षेत्रों में विशेषतः जिनमें शिल्प सम्बन्धी उत्पत्ति प्रणाली, आर्थिक शक्ति तथा धन के एकीकरण पर आवश्यक है, बन देनी है। उन क्षेत्रों में जहाँ व्यक्तिगत उद्योग राज्य की सहायता के बिना उन्नति नहीं कर सकते, उन क्षेत्रों में सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक साधनों का उपभोग आवश्यक है। जेप आर्थिक क्षेत्रों में एक ऐसी आर्थिक प्रणाली को अपनाया चाहिए जिसमें साहसी एकाकी या सहकारिता के आधार पर वस्तु और सेवाओं की उत्पत्ति के लिए पूँजी का विनियोग कर सके।

१०—कल्याणकारी राज्य की स्थापना

(The Attainment of a Welfare State)

भारतीय योजना का एक अन्य उद्देश्य देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी है। कल्याणकारी राज्य राष्ट्र-निवासियों की जीवन की प्रारम्भिक

आवश्यकताओं, जैसे खाद्य पदार्थ, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं को प्रदान करने की क्षम्य ग्रहण करता है। कल्याणकारी राज्य द्वारा वृद्ध, अपाहिज, अनाथ और बेरोजगार मनुष्यों की सहायता की जाती है।

टी० डब्ल्यू केन्ट (T. W. Kent) ने इसकी परिभाषा इस तरह दी है, “वह राज्य जो अपने नागरिकों को अनेक सामाजिक सुविधाएँ प्रदान करता है। इनमें से प्रथम लक्ष्य नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना है। यदि वह अपनी साधारण आय में किसी प्रकार बचि रह जाता है तो राज्य उसकी सहायता करता है।”

डा० अब्राहम (Dr. Abraham) के अनुसार, “कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होता है, जिसमें सरकार आर्थिक शक्तियों को अपने हाथ में इसलिए ले लेती है ताकि वह देश के आर्थिक प्रयासों को नियन्त्रित कर सके और देश की सम्पत्ति और आय का देशवासियों में समान वितरण कर सके। इसी के साथ साथ उनका यह भी कार्य होना है कि वह जनता को वास्तविक आय को बढ़ाने का प्रयास करे।”

कल्याणकारी राज्य का मिश्रात भारत के लिए नवीन है। सन् १९४७ के बाद में भारत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की चेष्टा कर रहा है तथा दलितवर्ग की पुनःपुराणी बाधाओं को दूर करने, आय की असमानता को कम करने तथा राज्य की आय, सम्पत्ति और सामाजिक न्याय में समानता लाने का प्रयास कर रहा है। आर्थिक विषमतायें हमारे देश में सदियों से फैली हुई हैं। इसका मूल कारण अंग्रेजों की दोषपूर्ण आर्थिक नीति तथा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने की नीति (Laissez faire Policy) का अस्तित्व है। श्री अशोक मेहता ने अनुमान लगाया है कि भारत में ३० बड़े उद्योगपतियों ने अपने “सहयोगियों के सहयोग से भारत की आर्थिक स्थिति और उद्योगों पर अधिकार कर रखा है।”

लोकतन्त्र को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि आर्थिक असमानता और निर्धनों का शोषण शीघ्रातिशीघ्र रोक दिया जाय। क्योंकि देश की जनता कितनी भी अनिश्चित तथा दलित क्यों न हो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक शान्तिनाश को दोषकाल तक सहन नहीं करेगी। आइन्स्टाइन (Einstein) का कथन, “भूखा मनुष्य अच्छा राजनैतिक सलाहकार नहीं होता है” आज की तथा भविष्य की परिस्थितियाँ में भी बिल्कुल सत्य ही सिद्ध होगा। Ann Van Wynen Thomas का कथन इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है, “भूखे व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं होते हैं। जिस किसी ने कभी भी भूख का अनुभव किया है वही दूसरों की भी अपनी तरह विन्ता करता है। भूखे आदमियों में स्वतन्त्रता की या अथवा बात करना उचित नहीं है।

भूखे में सम्पर्क स्थापित करने का सबसे अच्छा तथा केवल एक ही ढंग है कि उसे भोजन कराये जायें । दूसरी ओर, स्वतन्त्रता की समानता भरे पेट पर भ्रम या इन्द्रजाल होगी ।”

नियोजन आयोग ने कल्याणकारी राज्य के लिए आधिक्य नियोजन के निम्न-लिखित उद्देश्य बताये हैं :—

“वर्तमान सामाजिक व आर्थिक निर्माण कार्य में आर्थिक क्रियाओं (Economic Activity) को पुनः व्यवस्थित करने की समस्या नहीं है, बल्कि निर्माण-कार्य को इस प्रकार सगठित करना है ताकि मूल आवश्यकताएँ (Fundamental Urges)—स्वतः ही कार्य करने का अधिकार, पर्याप्त आय का अधिकार, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार तथा वृद्धावस्था, बीमारों एवं अश्व-आपत्ति के विरुद्ध बीमा या सुरक्षित रहने का अधिकार आदि पूरी कर सकें ।”

हमारे संविधान में लोकतन्त्र के अन्तर्गत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का उल्लेख है । हमारे संविधान के तृतीय भाग की धाराओं से यह विस्तृत स्पष्ट हो जायगा कि—

१—“राज्य के अन्तर्गत किसी कार्यालय में नियुक्ति, रोजगार आदि के विषयों में सभी नागरिकों को समानता होगी ।”

२—“सभी नागरिकों को सम्पत्ति अर्जित करने, उसे रखने या उनकी देखभाल का पूर्ण अधिकार होगा ।”

३—“मानव व्यापार (Traffic in Human beings), शिशु व्यापार अथवा किसी में जबरदस्ती काम लेना निषिद्ध होगा ।”

(हमारे संविधान का चतुर्थ खण्ड) राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त (Directive Principles of State Policy) का उल्लेख करके कल्याणकारी राज्य का एक सुन्दर आदर्श प्रस्तुत करता है :—

(क) सभी नागरिकों—स्त्री तथा पुरुषों को अपनी पर्याप्त जीविका (Livelihood) अर्जन करने का समान अधिकार होगा ।

(ख) समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्व तथा नियंत्रण को इस प्रकार वितरण करना जिसमें सर्वसाधारण का कल्याण हो सके ।

(ग) आर्थिक प्रणाली की व्यवस्था इस प्रकार की जाय ताकि सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ ही व्यक्तियों में एकत्रित होकर सर्वसाधारण का अपकार न कर सकें ।

(घ) वृद्धों तथा नवयुवकों को शोषण से बचाया जायगा ।

(ड) स्त्री तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होगी ।

(च) स्त्री और पुरुष मजदूरों की शक्ति और स्वास्थ्य का क्षय न हो पाए और बच्चों का (जो मजदूरी करते हैं) शोषण न हो सके ।

११—कल्याणकारी राज्य की स्थापनार्थ ग्रहण किये हुए उपाय

(Measures adopted to Attain a Welfare State)

जब से राज्य ने समाजवादी ढंग की समाज-व्यवस्था तथा कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्तों को अपनाया है, तभी से राज्य ने इन्हें प्रयोग में लाने के लिए असह्य प्रभावशाली कदम उठाये हैं । राज्य न देश में फैली अराज्य की असमानता एवं सम्पत्ति की असमानता को दूर करने के लिए तथा द्रुत औद्योगीकरण को प्रभावित करने के लिए राज्य उद्योगों की स्थापना की है । समाज में उत्पादन, उपभोग तथा वितरण की समानता लाने के लिए राज्य द्वारा बहुत से कानून, प्रस्ताव तथा बिल प्रस्तुत किये गये हैं ।

सन् १९४८ में फौटरी कानून पारित किया गया (जिसमें बाद में कुछ सुधार भी हुए) । इसके अनुसार कारखानों में कार्य करने की पहले से अच्छी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना—काम के घण्टे कम करना, स्वच्छता का प्रबन्ध, प्रकाश, रोशनदान, विश्रामगृह, कैंटीन, मनोरंजन के साधन इत्यादि छुटाना । बहुत-से मालिकों की शोषण वाली नीति को रोकना । इसके अनुसार मजदूरों को कम से कम समय कार्य करना पड़ेगा किन्तु अधिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हो सकेगा, जिससे वे अपने रहन सहन के स्तर को ऊँचा कर सकें । उनके रहने के लिए आवास का प्रबन्ध भी धीरे धीरे किया जाना है ।

मजदूरों की राज्य बीमा योजना (Employees' State Insurance Scheme) भी देना में लागू कर दी गई है, जिससे मजदूरों को निम्नलिखित मुख्य लाभ प्राप्त होंगे—

१—स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायता । २—प्रवाहिज अवस्था में सहायता । ३—निर्भरता स्थिति में सहायता । ४—बीमारों की अवस्था में सहायता, और ५—प्रसूति सहायता (Maternity Benefit) ।

सामाजिक एकता एवं मानवजाति में समानता लाने के लिए भिन्न भिन्न कानून बनाये गये हैं, विशेषकर समाज की असमानता तथा लुभालुभा के द्वारा उत्पन्न बुराई में बचने के कानूनों का निर्माण हुआ है ।

इम्पीरियल बैंक और देशस्थित जीवन-बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया है कि उनमें पर्याप्त मात्रा में पूँजी प्राप्त हो सके—जिससे

सामाजिक लाभ के उद्देश्य से उद्योगों की स्थापना हो सके। इम्पोरियल बैंक और जीवन-बीमा कंपनियों में साधारण जनता को छोटी-छोटी बचतें एकत्रित थीं। इम्पोरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण इसलिए भी किया गया कि वह छोटी छोटी औद्योगिक संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान कर सके।

राज्य ने सदियों से चली आ रही देहातियों, विशेषकर कृषकों की आपत्तियों, कठिनाइयों तथा याननाओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय अपनाये हैं तथा कुछ कानून बनाये हैं, उनमें से मुख्य यह हैं :—मालगुजारी कानून, जमींदारों पर्या का अन्त, विखरी हुई भूमि की चक्कन्दो, सहकारी कृषि-प्रणाली का प्रारम्भ करना, सामुदायिक विकास यात्रनाओं की स्थापना, विकास खण्डों की स्थापना तथा अत्यधिक अनाज की दर को रोकने का कानून (Usurious Interest Act) आदि।

इनके अतिरिक्त न्यूनतम और अधिकतम आय की सीमा बांधना, कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax), एस्टेट ड्यूटी, भारी और प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, फाइनेंस और पोरेजन की स्थापना और बहुत से राज्य उद्योगों की स्थापना आदि कल्याणकारी राज्य के आदर्शों के अनुसार अपनाये गये हैं, ताकि राष्ट्र के समस्त नागरिकों को अधिकतम लाभ और मुक्त-सुविधा प्राप्त हो सके। भारत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाएँ इसी आदर्श को सामने रखकर बनाई गई हैं, और कार्यन्वित हो रही हैं। यह आशा की जाती है कि भविष्य में इस प्रकार के अन्य और भी बहुत-से कदम उठाए जायेंगे, जिनमें भारत में एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी।

निगोजन और रोजगार

(Planning and Employment)

१—विषय-प्रवेश

(Introductory)

नभी आर्थिक नियोजनो का आदर्श पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना है। गैलन (Gallen) ने गायद सबसे पहले इस सत्य की व्याख्या की थी, "रोजगार की प्राप्ति प्राकृतिक औपध है जो मानवीय प्रयत्न के लिए आवश्यक है।"¹ यह कथन शत प्रतिशत सत्य है।

पूर्ण रोजगार के सिद्धान्त का वर्णन और उसको परिभाषा विभिन्न प्रकार से की गई है। पूर्ण रोजगार, "वह परिस्थिति होती है जिनमें रिक्त स्थानों की सख्या बेकार मनुष्यों की सख्या से देखने में कम न हो ताकि यदि एक व्यक्ति किसी भी समय एक काम को छोड़कर दूसरे काम को प्राप्त करने का प्रयास करे तो उन्नत वह सफल हो जाय।" सर विलियम बेवरेज (Sir William Beveridge) ने पूर्ण रोजगार को परिभाषा इस प्रकार की है, "वह दशा जिसमें रिक्त स्थानों की सख्या बेकार आदमियों से अधिक हो।" उमने लिखा था कि इसका यह भी अर्थ है, "ठीक मजदूरी की दर पर कार्यों की सख्या इस प्रकार हो कि बेकार व्यक्ति सरलता से उन्हें प्राप्त कर ले। परिणामस्वरूप, एक काम के छूटने में और दूसरे को पाने में कम से कम समय लगे।"²

पूर्ण रोजगार के सिद्धान्त में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। पूर्ण रोजगार का अर्थ है कि 'बेकार परन्तु कार्य के योग्य व्यक्तियों को रोजगार का अवसर इस शर्त पर प्रदान करना कि वह भिन्न परिस्थितियाँ में कार्य करने को सहमत हो।' लीग ऑफ नेशन्स (League of Nations Committee) ने सन् १९१६ में ही कहा था, "बेकार व्यक्ति वह है जो मजदूरी के लिए काम को तलाश में हो तथा अपनी समता एवं योग्यतानुसार काम पाने में असफल रहा हो।" यह विचार बहुत सीमा तक पीगू (Prof. A. G. P. gou) के विचारों से मिलता जुलता है—'दिये हुए कार्य

1 'Employment is Nature's Physician and essential to human happiness' —Gallen

2. "Full employment in a free society." —Sir W Beveridge.

की परिस्थिति, कार्यों के घंटे और मजदूरी की दर पर किसी उद्योग में कार्य के इच्छुको और जिनको इस उद्योग में कार्य मिलना है, उनके अन्तर को उम उद्योग में फैली हुई बेरोजगारी कहते हैं।¹

बेकारी की समस्या को विभिन्न विद्वानों और अर्थशास्त्रियों ने अनेक ढंग में वर्गीकरण किया है। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं :—

१—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बेरोजगारी। २—मौसमी बेरोजगारी। ३—आवर्तक बेरोजगारी। ४—माघारण बेरोजगारी। ५—प्रौद्योगिक पद्धति के परिवर्तनस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी। ६—अपूर्ण रोजगार। ७—कृषि-मन्वन्वी बेरोजगारी, और ८—शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी।

बेरोजगारी के भी बहुत-से कारण होने हैं। यह विभिन्न राशियों, नमाज, चातावरण तथा मनुष्यों में भिन्न प्रकार की होती है। विभिन्न विद्वानों के बताये हुए बेरोजगारी के निदानों को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है :—

(अ) किसी उद्योग में निर्मित वस्तुओं की बहुत काल तक माँग में कमी रहना।

(ब) दुर्निर्देशित माँग (Misdirected demand)।

(स) 'श्रम-बाजार' का श्रमरुल सगठन या काम का कम होना तथा रोजगार (Labour market) की खोज में आदमिया का अधिक होना।

(द) कृषि मन्वन्वी घन्धा पर अधिक दबाव।

(म) उत्पादन में अन्वेषणों का न होना और उत्पत्ति की प्रणालियों में परिवर्तन न होना।

(न) यातायात, सहायताहन तथा बिक्री के कार्यों की सुविधाओं में कमी।

(ल) व्यापार चक्र को रोकने में असफलता।

(व) दोषपूर्ण शिक्षा तथा प्रशासन प्रणाली का होना।

(श) कृषि तथा उद्योगों के उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना।

२—बेरोजगारी दूर करने के विभिन्न उपाय

(अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन)

समय-समय पर विभिन्न विद्वानों ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अवधि को ध्यान में रखकर इनके भिन्न भिन्न उपाय बताये हैं। उनमें से कुछ केवल सैद्धान्तिक और आदर्श रूप से ही ठीक हैं जबकि अन्य विद्वानों ने एक निश्चित कार्यक्रम का उल्लेख किया है। वृजगोपात गुप्ता ने "A Treatise on Employment" में बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्नलिखित आठ सुझाव दिये हैं² :—

1 Prof A C Pigou, 'Unemployment,' (1916)

2 Brij Gopal Gupta—A Treatise on Employment.
(Ch. IX, P. 34)

(१) सूचना तथा निर्णय के लिए नियोजन ।

(२) पूर्ण रोजगार की नीति अपनाने के लिये जनता का सहयोग ।

(३) पर्याप्त मात्रा का विनियोग—जिसमें जनता को विनियोग करने का सुअवसर मिले ।

(४) निजी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना ।

(५) उपभोग को प्रोत्साहन देना ।

(६) मूल्य में एकाधिकार की स्थापना का विरोध ।

(७) विदेशी व्यापार में वृद्धि तथा विदेशी विनियोग-नीति को बढ़ावा देना ।

(८) बेरोजगारी को दूर करने के लिये ऐसा ही प्रयास करना जैसा कि युद्ध-सकट को दूर करने के लिये किया जाता है ।

नियोजन आयोग ने बेकारी से मुक्ति पाने के लिए निम्नलिखित ११ सिफारिशें की हैं^१ :—

(१) व्यक्तियों तथा छोटे छोटे वर्गों को छोटे छोटे उद्योग तथा व्यापार स्थापित करने के लिए राज्य के महायन्त्रा-कानून के अन्तर्गत सहायता प्रदान करना ।

(२) जिन क्षेत्रों में मानव शक्ति की कमी अभी विद्यमान है उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण मुविधाओं को विस्तृत करना । बहुत सी ऐसी दिशाएँ हैं, जिनमें अभी प्रशिक्षण की कमी विद्यमान है—जो पञ्चवर्षीय योजनाओं की सफलता में बाधा डालती हैं । प्रशिक्षण मुविधाओं के विस्तार से योजना का कार्य सरल हो जायगा और अशिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिल जायगा ।

(३) कुटीर उद्योग धन्यों एवं छोटी मात्रा के उद्योग धन्यों के उत्पादित माल को राज्य, सरकारी सस्थाओं और अन्य सस्थाओं द्वारा खरीदा जाना, जिससे इन उत्पादकों को प्रोत्साहन मिले ।

(४) स्वायत्त शासन (नगरपालिका आदि) के अधिकारियों का व्यक्तिगत शिक्षण सस्थाओं तथा स्वेच्छापूर्वक स्थापित सस्थाओं की स्थापना में तथा नगरों में वयस्क शिक्षा केन्द्र (Adult Education Centre) खोलने में सहायता करनी चाहिए । देहात में 'एक अध्यापक स्कूल' खोलकर रोजगार बढ़ाने में प्रोत्साहन देना चाहिए ।

(५) राष्ट्रीय विस्तार सेवा (National Extension Service) के कार्य को स्वयं इसके उत्पादन के लिये साहस पूर्वक चलाना चाहिए ताकि यह देहाती अर्थ-व्यवस्था की उन्नति में तथा शिक्षित वर्गों को बेकारी की समस्या को दूर करने में अधिक में अधिक मौलिक तथा तत्कालीन सहायता कर सके ।

1. Recommendations made by the Planning Commission,
Govt. of India.

(६) सड़कों के यातायात का विकास होना चाहिए । वर्तमान अनुज्ञप्ति नीति (Licensing Policies) का पुनः परीक्षण इस दृष्टि से किया जाय कि सड़क यातायात का विकास हो, वह भी विशेषकर गैरसरकारी क्षेत्र में हो ।

(७) नगरों में स्थित गंदी वस्तियों को हटाकर कम आय वाले वर्ग के लिए निवास स्थान के निर्माण की योजना बनाना—अर्थात् उनके लिए नये मकानों का बनाना ।

(८) व्यक्तिगत रूप से मकान बनाने के कार्य को प्रोत्साहन देना ।

(९) शरणार्थियों की नगर बसाने वाली योजना में नियोजित सहायता देना ।

(१०) शक्ति की विकास योजनाएँ जो व्यक्तिगत पूँजी से प्रारम्भ की जायें उनको प्रोत्साहन देना । आज भी बहुत स उत्तम नगरों में शक्ति की कमी है जोकि व्यवसाय एवं रोजगार तथा उद्योगों के विकास में बहुत ही बाधक है । राज्यों की सरकार शक्ति की दशा का अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों में कर सकती है । पंचवर्षीय योजनाओं में शक्ति की कमी को दूर करने वाले उपाय सम्मिलित नहीं किये गए हैं । आगे के लिए भी यह आवश्यक है कि ऐसे प्रस्ताव भेजे जायें, जिनमें स्पष्टतः इस धान का उल्लेख किया जाय कि उनमें व्यक्तिगत पूँजी की भाषा कितनी होगी ।

(११) नियोजन आयोग का अन्तिम मुद्दा यह है, “उन स्थानों पर शिक्षण-शिविर खोले जायें जहाँ सरकार के प्रयत्न के लिए कार्य के सुप्रवसर विद्यमान हैं ।” उदाहरणार्थ, विकास योजनाएँ, सड़क निर्माण-कार्यक्रम, भूमि सुधारक तथा वन लगाने और भूमि-अभरण को रोकने के कार्य और सहकारी आधार पर भूमि का पुनर्संयोजन व विकास इत्यादि ।

प्रथम योजना में रोजगार के सुप्रवसर (Employment Opportunities in the First Plan)¹ .

प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी था कि रोजगार को विस्तृत किया जाय तथा जनता के रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाया जाय । उसमें देहाती क्षेत्र पर अधिक बल दिया जाय । इसका कारण यह था कि वहाँ की बेरोजगारी की समस्या बड़ी गम्भीर तथा भयङ्कर थी । नियोजन आयोग ने प्रथम योजना में देहाती बेरोजगार की समस्या कम करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावित मुद्दा दिए थे—छोटे-बड़े मिर्चाई के कार्यों का विकास करना । नियोजन आयोग ने शहरी क्षेत्र के लिए द्रुत औद्योगीकरण, नवीन रोजगारों का निर्माण और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने के मुद्दा दिए थे ।

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत सरकार ।

प्रथम योजना में नियोजन के समय (१९५१-५६) में सम्भावित अतिरिक्त रोजगार के निम्नलिखित अनुमानित आँकड़ों का विवरण था :—

श्रेणी	रोजगार में अतिरिक्त वृद्धि ।
(१) उद्योग (बहुत उद्योग समेत)	४ लाख प्रतिवर्ष
(२) मिर्चाई तथा शक्ति की बड़ी योजनायें	७½ लाख प्रतिवर्ष
(३) कृषि	२३ लाख प्रतिवर्ष
(क) अतिरिक्त सींचे हुए क्षेत्र के कारण	१४ लाख प्रतिवर्ष
(ख) लालावो इत्यादि की मरम्मत आदि से	१½ लाख प्रतिवर्ष
(ग) भूमि को पुनः कृषि-योग्य बनाने से	७½ लाख प्रतिवर्ष
(४) मकान तथा निर्माण कार्य	१ लाख प्रतिवर्ष
(५) सड़क (सुरक्षित रखना तथा विकास करना)	२ लाख प्रतिवर्ष
(६) कुटीर उद्योग घन्घे	२० लाख प्रतिवर्ष
इसके अतिरिक्त ३६ लाख को पूर्ण रोजगार मिलेगा ।	
(७) अन्य तथा स्थानीय कार्य	इसमें रोजगार बढ़ेगा लेकिन उसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।
(८) शिक्षितों के लिए रोजगार	इस पर उचित बल नहीं दिया गया ।

द्वितीय और तृतीय योजनाओं में रोजगार-सम्भावनाएँ^१ :

आर्थिक विकास की योजना का ध्येय प्राप्त साधनों का उपयोग इतने प्रकार करना होता है जिससे उत्पादन की उन्नति की दर अधिक से अधिक हो जाय । वास्तव में यह एक लम्बी अवधि का कार्य (Long term task) है । दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की नीति से आर्थिक विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती । अब यह मान लिया जाता है कि बेरोजगारी की समस्या विशेषकर हमारी सी अविकसित आर्थिक व्यवस्था में बड़ी मात्रा के विकास से ही दूर हो सकती है ।

३—समस्या का आकार तथा प्रकार

(Size & Nature of the Problem)

रोजगार के निर्माण की सुविधाओं के क्षेत्र में आशामी वर्षों में जिन तथ्यों का ध्यान रखना है वे तीन प्रकार के हैं :—

(१) नगरी तथा ग्रामी में जो वर्तमान बेकार लोग हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना ।

(२) भ्रम क्षेत्र में जो नये भूमिक प्रविष्ट होंगे उनके लिए रोजगार की

१. द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनायें—भारत सरकार ।

व्यवस्था करना। यह अनुमान किया गया है कि प्रतिवर्ष २ मिलियन अनिच्छित श्रमिक इन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे।

(३) कृषि तथा घरेलू व्यवसायों, जिनमें अर्द्ध-बेकारी है, उनके लिए पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बेरोजगारी की समस्या का अन्वयन सामूहिक रूप में ही नहीं होगा चाहिए बल्कि शहरी और देहाती क्षेत्रों में जो स्थिति विद्यमान है उसके विस्तेषण किए हुए रूप में होना चाहिए। इसलिए देश के विभिन्न प्रदेशों में इसके परिमाण (Magnitude) का लेखा (Account) नगरो तथा देहाती क्षेत्रों में रखना आवश्यक है। शिक्षितों में फैला हुआ बेरोजगारी का साधारण बेरोजगारी से अलग कर देना चाहिए।

बेरोजगारी को दूर करने में बहुत-सी कठिनायियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ इन सम्बन्ध में हैं कि बेरोजगारी के आकार प्रकार और कारणों का ज्ञानता कठिन होता है। कुछ इन कारण में कि भारत में किसी भी विषय पर पूर्ण एवं सही आँकड़े प्राप्त नहीं हो पाते। इनके अतिरिक्त इन कारण से भी कि रोजगार-दफ्तरो में ठीक प्रकार से कार्य नहीं होना।

योजना के प्रारम्भिक काल में ही, नये कार्यों का विस्तार होने पर भी, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोजगार-दफ्तर के आँकड़ों के अनुसार सन् १९५१ में ३०२३ लाख बेरोजगार उनके रजिस्ट्रो में दर्ज थे। यह मात्रा १९५३ में ५०२२ लाख हो गई और सन् १९५६ तक ७०५ लाख तक पहुँच गई। इस परिस्थिति में अपनी सुधार नहीं हो पाया है। नेशनल सैम्पल सर्वे (National Sample Survey) ने सन् १९५४ में यह अनुमान लगाया था कि शहरी क्षेत्रों में २०२४ मिलियन बेरोजगार थे। टी० एन० कृष्णन् ने अनुमान लगाया था कि सन् १९५३ में १५७ मिलियन एवं १९५५ में २०५८ मिलियन बेरोजगार थे। नियोजन आयोग ने सन् १९५६ में बेरोजगारों की संख्या २०५४ मिलियन बताई थी। उसी साल विलफ्रेड मालेन्बोम (W. Malenbaum) ने यह संख्या २०५ मिलियन बताई थी, और उसी वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (I. L. O) ने भारत में बेरोजगारों की संख्या ३ से लेकर ३०५ मिलियन बताई थी।

देहान में पूर्ण रोजगार और अर्द्ध-रोजगार में अन्तर करना बड़ा कठिन है। इन क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए केवल काम की मात्रा को बढ़ाने तथा बहुत-से अर्द्ध-रोजगार वालों की आय में वृद्धि करना नहीं है बल्कि पूर्ण समय के रोजगार की सुविधाओं की एक निश्चित मर्यादा का निर्माण करना है। इन विषय में कृषि में लगे हुए मूनिहीन मजदूरों के विषय में विशेष रूप से विचार करना चाहिए।

द्वितीय योजनाकाल में श्रम के क्षेत्र में १० मिलियन नवीन श्रमिकों के प्रवेश का अनुमान लगाया गया है। इस संख्या में से शहरी श्रमिकों की अनुमानित संख्या ३८ मिलियन को निकाल दिया जाय तो देहाती नवीन प्रविष्ट श्रमिकों की अनुमानित संक्ति १६५६-६१ में लगभग ६२ मिलियन के होगी।

निम्नलिखित तालिका यह प्रकट करती है कि इस काल में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कार्यों की संख्या में किस प्रकार वृद्धि होनी चाहिए :

	(मिलियन)		
	नगरो में	देहात में	योग
१—श्रम-क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नये श्रमिकों के लिए	३.८	६.२	१०.०
२—पुराने रोजगारवालों को	२.५	२.८	५.३
योग	<u>६.३</u>	<u>९.०</u>	<u>१५.३</u>

यदि रोजगार की सुविधाओं का निर्माण उपर्युक्त क्रम में सम्भव भी बना दिया जाय तो भी अर्द्ध-रोजगार की समस्या का हल पूरा नहीं हो सकेगा।

प्रणाली का चुनाव (Choice of Technique) :

वर्तमान बेरोजगारी के परिमाण पर विचार करते हुए और श्रमिकों की संख्या की वृद्धि की दर को देखते हुए यह ध्याता रखना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूर्ण रोजगार मिल जायगा, गलत होगा। यह लक्ष्य एक नियोजित प्रयासों के क्रम द्वारा जो कि द्वितीय योजना के पश्चात् समाप्त हो जायगा, पूरा हो सकेगा। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए और लम्बे समय तक की योजनाओं को सफल बनाने के लिए योजना में उन प्रयासों को सम्मिलित करना पड़ेगा जिनसे नये रोजगारों की स्थापना हो।

आवश्यकता से अधिक माना में प्राप्त श्रमिकों की संख्या से सम्बन्धित अर्थ-व्यवस्था में श्रम-प्रमुख उत्पत्ति प्रणाली को साधारण रूप से प्रोत्साहन देना स्वाभाविक तथा वाञ्छनीय है। किसी किसी मामले में चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता है। उदाहरणार्थ, भारी उद्योगों में चुनाव का प्रश्न नहीं होता है या उन उद्योगों की प्रारम्भिक अवस्था में जिनमें आगे चलकर अधिक रोजगार की सम्भावना होगी। कृषि-क्षेत्र में यन्त्रीकरण (Mechanisation) केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही होगा। इन पाँच वर्षों में रोजगार प्रणाली को सड़क-निर्माण, गृह-निर्माण और रेलवे के क्षेत्रों में ऐसा ही बनाए रखना होगा जैसा कि अब है। पूँजी प्रमुख उत्पत्ति-प्रणाली के प्रयोग में दुष्टों की हानि निम्न रूप में उत्पन्न हो सकती है :—

(प्र) श्रमिकों का कार्य से हटाया जाना—जो हर हालत में रोकना है।

(ब) पूँजी प्रमुख उत्पत्ति में श्रमिकों का स्थान पूँजी द्वारा ले लिया जाता है, श्रमिकों को हर हालत में रोकना है।

द्वितीय योजना में रोजगार-वृद्धि का अनुमान (Employment Potentiality in Second Plan) :

अनुमानित अतिरिक्त रोजगार

	(सह्या लाखों में)
(१) निर्माण	२१'००
(अ) कृषि तथा सामुदायिक विकास	२'६६
(ब) सिंचाई तथा शक्ति	३'७२
(स) उद्योग तथा खनिज पदार्थ (कुटीर तथा लघु उद्योगों समेत)	४'०३
(द) यातायात तथा संचालन (रेलवे सहित)	१'२७
(य) सामाजिक सेवाएँ	६'६८
(२) अन्य (सरकारी नौकरियों सहित)	२'३४
(३) सिंचाई तथा शक्ति	५'१
(४) रेलवे	२'५३
(५) अन्य यातायात तथा संचालन के साधन	१'८०
(६) उद्योग तथा खनिज पदार्थ	७'५०
(७) लघु तथा कुटीर उद्योग-धंधे	४'५०
(८) अन्न-विभाग, मछली पकड़ने का व्यवसाय, राष्ट्रीय विकास सेवा तथा सहायक योजनाएँ	४'१३
(९) शिक्षा	३'१०
(१०) स्वास्थ्य	१'१६
(११) अन्य सामाजिक सेवाएँ	१'४२
(१२) सरकारी नौकरियाँ	४'३४
१ से १२ तक का योग =	५१'६६
(१३) अन्य व्यापार, वाणिज्य आदि समेत योग का ५२%	२७'०४
कुल योग	७८'०३

या ८०'०० लाख

प्रत्येक क्षेत्र में योजना की रोजगार-शक्ति का अ-दाज लगाना ही पर्याप्त नहीं है। रोजगार के क्षेत्रीय वितरण को जानने का भी प्रयास किया जाएगा। विशेष रूप से उस क्षेत्र का ध्यान रखा जायगा जहाँ पूर्ण-वैरोजगारी और अर्द्ध-वैरोजगारी

अधिक मात्रा में है। सरकार निम्नलिखित प्रणालियों को अपनाकर रोजगार में वृद्धि कर सकती है :—

(१) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अधिकतम मात्रा में बेरोजगार वाले क्षेत्र में स्थापित करना।

(२) स्थानीय (बेरोजगार वाले क्षेत्र के) व्यवसायों और उद्योगपतियों को कम से कम ध्याज की दर पर सरकार की ओर से ऋण प्रदान करना।

(३) सार्वजनिक ठेके के कुछ प्रतिशत कार्यों को इन बेरोजगार वाले मनुष्यों के लिए सुरक्षित रखना।

(४) सरकार की ओर से अन्य ऐसी आर्थिक प्रणालियों को अपनाना जिनसे अधिक बेरोजगार वाले क्षेत्रों में निजी पूँजीवाले उद्योगों की अधिक स्थापना हो।

शिक्षितों में बेरोजगारी (Educated Unemployed) :

रोजगार दफ्तर में लिखे शिक्षितों का प्रतिशत वितरण^१

वर्ष	मैट्रिक	इण्टर	ग्रेजुएट	याग	घरेलू तथा अनुसूचित नौकरी की खोज में समस्त योग का प्रतिशत
१	२	३	४	५	६
१९५३	७६.७	१०.६	१२.७	१००	५२.२६
१९५४	७६.६	११.६	११.८	१००	५१.४३
१९५५	७६.८	१०.८	१२.३	१००	५२.८६

शिक्षितों की बेरोजगारी देश की साधारण बेरोजगारी का एक अंग है। भारतवर्ष में साधारण और शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी के कारण यह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया गया है एवं देश का आर्थिक विकास इस तीव्रता से नहीं हुआ जिस तीव्रता से श्रमिक वर्ग की वृद्धि हुई। फिर भी, साधारण बेरोजगारी से शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी के निम्नलिखित कारणों से भिन्नता है :—

(१) जनता का ऐसा विश्वास है कि शिक्षा पर किए गए विनियोग के बदले में उनको अच्छी नौकरी मिल जानी चाहिए।

^१ Statistics relating to the National Employment Service (Unpublished), Directorate General of Resettlement and Employment, Government of India, 1957.

(२) शिक्षित स्वाभाविक रूप से ही अपनी शिक्षानुसार नौकरी की तलाश करता है—जिसके कारण विभिन्न प्रकार के रोजगारों और उनके लिए प्रार्थियों की पूर्ति में असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है ।

(३) शिक्षितों में 'सफेद पोश' नौकरी ढूँढने का रोग सा लग गया है । वे चाहते हैं कि उन्हें शारीरिक परिश्रम न करना पड़े ।

योजना का लक्ष्य शिक्षितों में बेरोजगारों को कम करना है । इसीलिए, १९५५ में एक अध्ययन समिति (Study Group) भी बनाई गई थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आगामी पांच वर्षों में १४५ लाख शिक्षित व्यक्ति श्रम क्षेत्र (Labour Force) में प्रवेश करेंगे । समिति ने शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ५५ लाख रखी थी । समिति के अनुसार आगामी ५ वर्षों में जिन समस्याओं को हल करना है वह यह है कि इस वर्ग के लिए कम से कम दो मिलियन कार्यों (Job) का निर्माण करना । समिति ने यह भी अनुमान लगाया था कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की योजनाएँ जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हैं, केवल एक मिलियन कार्य ही निर्माण कर सकेंगी । अन्य २४ लाख शिक्षित व्यक्ति इन पाँच वर्षों में अवकाश ग्रहण करने वाले लोगों के स्थानों पर रोजगार प्राप्त करेंगे । इनके अतिरिक्त दो लाख व्यक्तियों को इस काल में निजी क्षेत्रों के उद्योगों में कार्य मिल सकेगा । बाकी बेरोजगारों की अवस्था में द्वितीय योजना काल में किसी प्रकार के सुधार की सम्भावना नहीं है ।

४—तृतीय योजना में रोजगार की सम्भावनाएँ

(Employment Potentiality in the Third Plan)

तृतीय योजना में होने वाले विनियोग के आकार तथा आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, हम इस समय यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसके द्वारा ३५ मिलियन अतिरिक्त रोजगार कृषि क्षेत्र में तथा १०५ मिलियन अतिरिक्त रोजगार अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न होगा । साथ ही साथ कृषि, छोटे उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में जिनको अर्द्ध-रोजगार प्राप्त है, उनको पूर्ण रोजगार प्राप्त हो सकेगा । कुछ भी हो, जिस भीमा तक यह रोजगार उत्पन्न होगा, उसका परिमाण अभी से नहीं बताया जा सकता है । इस प्रकार, तृतीय योजना काल में रोजगार की परिस्थितियाँ और अधिक खराब न हो जायें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगभग एक मिलियन अधिक रोजगार उत्पन्न करना होगा ।

इसलिए ऐसे उद्योगों में, जिनके लिए कि कम मात्रा में प्राप्त वस्तुओं, विशिष्ट कुशल मजदूरों अथवा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी, उत्पादक-अतिरिक्त-

रोजगार उत्पन्न करने के लिए आगामी कार्यक्रम पर विचार कर लेना आवश्यक है। इसके लिए अनेक दिशाओं में कार्य करने की आवश्यकता होगी, जिनमें से कुछ यह है :—

(१) द्वितीय योजना के पूरे हो जाने पर लगभग १६,००० कम्पा तथा गाँवों में विद्युत् पहुँच जायगी और आशा है कि तृतीय योजना के पूरे हो जाने पर यह मर्यादा १४,००० से भी अधिक बढ़ जायगी। उस समय तक ५,००० से २०,००० तक की जनसंख्या वाले सभी छोटे कम्पा में विद्युत् पहुँच जाने की आशा है। विद्युत् का प्रयोग होने में, छोटे उद्योगों का विस्तार करने का यह जो लाभप्रद अवसर प्राप्त होगा, उनका पूरा पूरा लाभ उठाना होगा। यदि सिन्पकारों तथा आत्म नियोजित मजदूरों को प्राविधिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ यथाभवमर (शीघ्र ही) तथा काफी मात्रा में मिल जायें तो यह कार्य बहुत सरल हो जायगा।

(२) तृतीय योजना के कार्यक्रमों में इस बात का ध्यानपूर्वक विचार लगाने का प्रस्ताव रखा गया है कि बड़े उद्योगों के उत्पादन का किस प्रकार विकेंद्रीकरण किया जाय ताकि उत्पादन का काफी भाग छोटे या घरेलू उद्योगों को प्राप्त हो जाय।

(३) ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ तक सम्भव हो, उपयुक्त एवं प्रगतिशील उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे गाँव अपने निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

(४) योजनाओं में मशीनों के उपयोग की सीमा तय करके शारीरिक परिश्रम के क्षेत्र का बढ़ाया जाना सम्भव है। यह उस सीमा तक होना चाहिए जहाँ तक कि निर्माण के समय और कीमत की दृष्टि से काफी मात्रा में लाभ होता हो। अलग-अलग योजनाओं पर विचार करते समय इस ओर पूरा पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है।

(५) बेरोजगारी की समस्या पर पूरे देश अथवा बड़े खण्ड—जैसे प्रदेश (राज्य)—के रूप में विचार किया जाना है। बेरोजगारी की समस्या का क्षेत्रीय अथवा जिला स्तरीय ध्यान पर, निकट में अध्ययन करने का (सम्पन्न बनाने का) प्रयत्न नहीं किया गया है। प्रत्येक जिले में कृषि, सिंचाई, शक्ति, ग्रामीण तथा छोटे उद्योग, मानवगत तथा समाज सेवाओं में सम्बन्धित विकास के कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि जिले की आर्थिक क्रियाओं का स्तर उत्थान हो और उत्पादन में सामान्यतः वृद्धि हो। इनके द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार तो मिलेगा ही साथ ही साथ अनेक कार्यक्रमों का उद्देश्य यह भी है कि हर एक किसान या शिल्पी अथवा छोटे साहसियों और सहकारी संस्थाओं तथा ऐसे ही अन्य संगठनों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। इन कार्यक्रमों का यदि पूरा पूरा लाभ उठाया गया तो जिला

एक क्षेत्रीय स्तर पर कार्य के लिए अधिक सम्भावनाएँ बढ़ सकती हैं। यह सब स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यों में उचित सुधार और विकास करके हो, हो सकेगा। प्रादेशिक सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि बेरोजगारी की समस्या की, जिलों के अनुसार विभाजित कर लेना चाहिए और जहाँ तक सम्भव हो जिले तथा क्षेत्रों की योजनाएँ बनाकर इनको प्रत्यक्ष रूप से हल कर लेना चाहिए।

उत्पादन कार्यों के लिए अभी बहुत क्षेत्र है जैसे (जातीय)। स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये कार्य किये जा सकते हैं :—सिंचाई के साधनों को उत्तम बनाना, भूमि का साफ करना, भूमिश्ररण को रोकने के लिए खेतों के चारों ओर ऊँची भेड़ बनाना, वृक्षों का अधिक सङ्ग्रह में लगाया जाना, गाँवों में नयी सड़कों का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का सुधार करना और सारी बस्ती के लिये भोपडियाँ तथा गोदाम बनाना, आदि ऐसे काम हैं जिन्हें करके लाभ उठाया जा सकता है। इन स्थानीय कामों को कम खर्च में बाजार दर से भी कम, गुजारे मान को मजदूरी देकर कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि ३ मिलियन नये मजदूरों का प्रबन्ध करना है तो इस ढंग से अतिरिक्त कीमत १२-५ करोड़ ६० प्रतिवर्ष की हो सकती है। इस प्रकार के कार्य योजना की अवधि में उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं और योजना की आर्थिक दृष्टि से मदद भी की जा सकती है। यदि यह स्कीम (ध्वस्त) सफल हो गई तो उत्पादन-कार्यों को उत्तम बनाने के लिए सुविधाएँ प्रदान करना सम्भव होगा, जिनकी कि तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति बहुत बड़ी सख्या में हैं।^१

निम्नतम जीवन-स्तर की प्राप्ति (Implementation of Minimum Standard)

१—विषय-प्रवेश (Introductory)

“रहन सहन के स्तर में किसी प्रकार की उन्नति राष्ट्रीय आय पर निर्भर होनी है। राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का मुख्य उपाय द्रुत ढंग में औद्योगीकरण करना है।”^१ हमारे देश में औद्योगीकरण बेरोजगारी के शोघ्र विनाश के लिए तथा कृषि सम्बन्धी उद्योगों के दबाव को हटाने के लिए और भी अधिक आवश्यक है।

भारत के विषय में यह अति दुःख तथा खेद का विषय है कि यद्यपि भारत एक धनी देश है किन्तु भारतीय निर्धन हैं। भारत में पर्याप्त मात्रा में साधन, शक्ति के स्रोत, मानव शक्ति, कच्चा माल, विस्तृत कृषि-योग्य भूमि, वन, खनिज-पदार्थ तथा जल विद्युत शक्ति के होने के बावजूद भी भारत निर्धन है। इस कारण, निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि देश में समुचित आर्थिक तथा सामाजिक संगठन की कमी है। केवल समुचित सामाजिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक संगठन ही हमें वर्तमान भयानक निर्धनता से मुक्ति प्रदान कर सकता है।

सर्वमम्मति से यह स्वीकार कर लिया गया है कि हमारी निर्धनता केवल आर्थिक ही नहीं—बल्कि नैतिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक भी है। यदि इसको अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाय तो हम यह पायेंगे कि जीवन के उच्च आदर्श, जैसे, सदाचार (Virtue), ईमानदारी (Honesty), नैतिकता (Morality) आदि गुण, जब पेट खाली होता है तो रखे रह जाते हैं।

निर्धनता के पापी घेरे में, जिसमें अनुरूप भोजन, मानसिक अव्यवस्था, शारीरिक दुर्बलता, रोग और रोग को रोकने के प्रबन्ध का अभाव, अधिका, साधारण तथा व्यावसायिक शिक्षा की कमी, अकुशलता, कम उत्पादन, कम पारिवारिक आदि बातों का अस्तित्व ही निर्धनता की ओर ले जाता है तथा रहन सहन के स्तर को नीचा करता है। आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या कम उत्पादन (Under-production) है। राष्ट्रीय लाभार्थ की वृद्धि के बिना श्रमिकों, उपभोक्ताओं, समस्त जनता एवं पूँजी की बड़ी हुई माँग पूरी नहीं हो सकती।

1. Planning for India—B. C. Ghosh, Chapter III, P. 26.

०.३५; सन् १८९५ में ०.४५; सन् १९२१-२२ में ०.७१ सन् १९२५-२६ में ०.८३ सन् १९४४-४५ में ०.९४; सन् १९२५-२६ में अमरीकी डॉलर का भारतीय मुद्रा में जो मूल्य था उसी को अन्तर्राष्ट्रीय इकाई कहा गया था। इन आंकड़ों से प्रकट होता है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय बहुत कम है। इसमें भी अधिक खेद का विषय यह है कि यह तीव्र गति से नहीं बढ़ रही है। कुछ सीमा तक यह स्थिर है। राष्ट्रीय आय की स्थिरता के कारण देश का आर्थिक विकास भी स्थिर हो गया है।

राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee), १९५१-५४, के निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय हैं :—

१—देश की राष्ट्रीय आय १९४८-५१ में निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन में)	१९४८-४९ की कीमतों के अनुसार (करोड़)	राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमत (करोड़)	१९४८-४९ के कीमतों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय	वर्तमान कीमत के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आय
१९४८-४९	३५०.३८	८६५०	९६५०	२४६.९	२४६.९
१९४९-५०	३५४.८२	८८२०	९०१०	२४८.६	२५३.९
१९५०-५१	३५६.३३	८८५०	९५३०	२४६.३	२६५.२

२—(क) कृषि, जिसमें कि कार्य करने वाली संख्या का ७२.४ प्रतिशत भाग समाहित था, समस्त राष्ट्रीय आय का ५१.३ प्रतिशत भाग प्राप्त होता था।

(ख) कार्य करने वाली संख्या का १०.६% भाग जोकि खानों में, उद्योगों में तथा लघु उद्योगों में सलग्न था, उसको समस्त राष्ट्रीय आय का १६.१ प्रतिशत भाग प्राप्त होता था।

(ग) व्यापार, यातायात एवं संचादवाहन के साधनों में कार्य करने वाली संख्या का ७.७ भाग व्यस्त था जिसको कि समस्त राष्ट्रीय आय का १७.७ भाग प्राप्त होता था।

(घ) अन्य नौकरियों में, जिनमें कार्य करने वाली संख्या का ६.३ प्रतिशत भाग था, इसको समस्त राष्ट्रीय आय का १५.१ प्रतिशत भाग प्राप्त होता था।

३—राष्ट्रीय आय का उत्पत्ति के आकार द्वारा साहस का इस प्रकार वर्गीकरण किया गया था—

(i) लघु उद्योग—जिनमें कृषि और गृह उद्योग भी सम्मिलित थे—में ६२६० करोड़ रु० लगे हुए थे ।

(ii) बड़ी माना की उत्पत्ति में १०२० करोड़ रु० लगे थे ।

(iii) अन्य में लगी पूँजी—महत्त्वहीन (Non-significant)

४—इस समिति ने कार्य करने वाली सस्या का कुल योग १४३,२२१,००० अथवा कुल जनसस्या का ४० प्रतिशत के लगभग रक्खा । इस जनसस्या का सन् १९५१ में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में प्रतिशत वितरण निम्न प्रकार था :—

(क) कृषि, पशु पालन, तथा तत्सम्बन्धी क्रियायें ७१.८, (ख) वन विभाग ०.२, (ग) मत्स्य-विभाग ०.४, (घ) खनिज ०.५, (ङ) कारखाने २.१, (च) छोटे साहस ८.०, (छ) सगठित बैंक तथा बीमा ०.१ (ज) सवादवाहन ०.१ (झ) रेलवे ८.०, (ञ) व्यापार तथा यातायात ६.७, (ट) व्यवसाय तथा स्वतन्त्र कला ४.५, (ठ) सरकारी नौकरियाँ २.७, (ड) घरेलू नौकरियाँ २.१ ।

राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए राज्य तथा देशवासियों दोनों को अग्रणी कदम उठाने हैं । विभिन्न प्रतिनिधियों में परस्पर समुचित एकीकरण (Co-ordination) तथा सहयोग (Co-operation) अपेक्षित है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न लिखित कदम उठाने हैं .—

१—देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित तथा सन्तुलित उपयोग । प्राकृतिक साधनों का अनुचित तथा असन्तुलित उपयोग देश की अर्थव्यवस्था में विपरीत परिणाम उत्पन्न करेगा । प्राकृतिक साधनों का बिना विचारे तथा निर्दयता पूर्ण शोषण करने से यह साधन सर्व के लिए नुस्त हो जायेंगे और राष्ट्र को बहुत समय तक कोई लाभ प्राप्त न हो सकेगा । इसके विपरीत, अनुचित तथा अपर्याप्त उपयोग राष्ट्रीय आय को चरम सीमा तक पहुँचाने में असमर्थ रहेगा । इस प्रकार प्राकृतिक साधनों के उपयोग का सबसे अच्छा व एकमात्र ठग देश की आवश्यकताओं तथा सम्भावनाओं की दृष्टि में रखते हुए उनका नियोजित, नियन्त्रित, सन्तुलित तथा एकीकृत (Co-ordinated) रूप से उपयोग करना है ।

२—राष्ट्रीय वृद्धि का नियोजित विकास, राष्ट्रीय आय की वृद्धि का दूसरा पूर्व प्रयोजनीय (Pre-requisite) साधन है । राष्ट्रीय आय की वृद्धि तथा विस्तार का नियोजन, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों तथा व्यक्तिगत साहसियों तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य द्वारा निर्मित होता है । नियोजनाधिकारी कोई भी हो लेकिन ध्येय, राष्ट्रीय आय की प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वृद्धि होनी चाहिए । अव्यवस्थित अथवा अनियोजित आर्थिक व्यवस्था पुरानी बान हो चुकी है, इसलिए

देश में रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए ।

३—देश के विभिन्न आय प्रयास (Income Pursuits) में समुचित एकीकरण (Co-ordination) स्थापित होना चाहिए । देश में वर्तमान अति 'वृषिकरण' (Over Agriculturisation) की नीति को त्याग देना चाहिए तथा उसके स्थान पर विभिन्न प्रकार के कार्यों तथा नौकरियों में सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए ।

४—राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए अन्य कदम यह उठाना है जिससे कि सभी नवीन प्रकार के उद्योगों का प्रारम्भ तथा वर्तमान उद्योगों के आकार में विस्तार हो । इन क्षेत्र में हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि बेरोजगारी तथा देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्याओं का सामना करने के लिए हम भ्रममर्थ हैं । इसके लिए देश में उत्पत्ति की धर्म प्रमुख प्रणाली (Labour-Intensive Methods) के द्वारा तथा वर्तमान परिस्थितियों पर विचार कर देश में औद्योगीकरण करना होगा । यह देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को भी हल कर सकेगा ।

५—जनसंख्या की तीव्र तथा असन्तुलित वृद्धि पर प्रतिबन्ध । यह एक उलझी हुई तथा जटिल समस्या है, जिसे बड़ी दृढ़ता एवं साहस में हल करना है । इन सम्बन्ध में नियोजन आयोग के दिये हुए प्रस्ताव प्रशंसनीय तथा व्यावहारिक दोनों ही हैं ।

६—उत्पत्ति के साधनों में औद्योगिक एवं आकार सम्बन्धी परिवर्तनों का समावेश ।

७—आय के उन नवीन साधनों को प्रयोग में लाना, जो बहुत दिनों से उपेक्षित थे ।

२—प्रथम योजना और राष्ट्रीय आय ^१

(First Plan & The National Income)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि भारत की राष्ट्रीय आय जो १९५०-५१ में ६५३० करोड़ थी वह १९६७-६८ में अतत प्रयासों (Continuity of efforts) द्वारा दूनी हो जायगी । उन्होंने योजनाकाल (१९५१-५६) में राष्ट्रीय आय की १२ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था । यह बड़ी प्रशंसा तथा प्रसन्नता की बात है कि यह लक्ष्य पूरा हो गया । वास्तव में प्रथम योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में १७.५ प्रतिशत वृद्धि हुई ।

1. Review of the First Five Year Plan—Planning Commission (1957), Ch., 1, pp. 7-8

निम्नलिखित तालिका में उपरोक्त परिणाम प्रतिशत के रूप में और विविष्ट खण्डों में प्राप्ति के रूप में प्रदर्शित किये गये हैं :—

५५]

वास्तविक राष्ट्रीय-उत्पादन (१९४८-४९ की कीमतों में)

मदे/धेणो	१	२	३	४	५	६	७	किसिम दो पर कालिम ७ में प्रतिशत वृद्धि
१—छपि, पशुपालन तथा तरसम्बन्धी क्रियायें (२० सौ करोड)	४३४	१६४०-४१	१६४१-४२	१६४२-४३	१६४३-४४	१६४४-४५	१६४५-४६	१५.७
२—खाने, कारखाने—बड़े तथा छोटे एव मृदु उद्योग (२० सौ करोड)	१४८	१४६५	१४६६	१४६७	१४६८	१४६९	१४७०	१५.२
३—ग्रामपार, यातायात एव सहाय वाहन के साधन (२० सौ करोड)	१६६	१७३	१७३	१७३	१७३	१७३	१७३	१५.६
४—अन्य मोकिया (२० सौ करोड)	१३६	१३६	१३६	१३६	१३६	१३६	१३६	२३.७
५—राष्ट्र की वास्तविक उत्पत्ति-धन्य के आधार पर (Net Domestic Product at Factor Cost) (")	८८७	६१२	६१२	६१२	६१२	६१२	६१२	१७.५
६—प्रति-व्यक्ति प्रति वर्ष आय (२०)	२४६.३	२४०.१	२४०.१	२४०.१	२४०.१	२४०.१	२४०.१	१०.५
७—जनसंख्या (करोडों में)	३५.६३२	३६.३३५	३६.३३५	३६.३३५	३६.३३५	३६.३३५	३६.३३५	६.६

1. Provisional.

[नियोजन : देश और विदेश में]

योजना के ५ वर्ष समाप्त होने पर राष्ट्रीय आय में लगभग १७.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। योजनाकाल में सभी प्रयासों में वृद्धि होने से महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। यद्यपि राष्ट्रीय आय की दर में सन्तोषजनक वृद्धि हुई है किन्तु भी राष्ट्रीय आय में समान रूप से वृद्धि नहीं हो रही है।

३—द्वितीय पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आय^१

(National Income and the Second Plan)

प्रथम योजनाकाल में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय की वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति के फलस्वरूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विधायकों (Drafters) ने प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय की और अधिक वृद्धि के लिए बल दिया। राष्ट्रीय आय की वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों के कुल विकास में प्रतिबिम्बित होती है। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की सम्भावना निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित की गई है—

उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय उत्पत्ति
(National Product by Industrial Origin)

विषय/श्रेणी	१९५२ ५३ के मूल्यों पर आधारित सं. करोड़ रु० में (Rs Crores at 1952 53 Prices)			प्रतिशत वृद्धि % Increase during	
	१९५० ५१	१९५५ ५६	१९६०-६१	१९५१ ५६	१९५६ ६१
१—कृषि एवं सम्बन्धित अन्य प्रयास	४४५०	५२३०	६१७०	१८	१८
२—खनिज	८०	६५	१५०	१६	५६
३—कारखाने	५६०	८४०	१३८०	४३	६४
४—निर्माण	१८०	२२०	२६५	२२	३४
५—छाटे उद्योग	७४०	८४०	१०८५	१४	३०
६—व्यापार, यातायात एवं सत्रादिकार	१६५०	१८५५	२२५०	१०	२३
७—व्यवसाय एवं नौकरियाँ	१४२०	१७००	२१००	२०	२३
८—कुल राष्ट्रीय उत्पादन	६११०	१०८००	१३४८०	१८	२५
९—प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय रु० में	२५३	२८१	३३१	११	१८

नियोजन आयोग ने आगे यह भी कहा है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास द्वारा सन् १९६७-६८ तक दुगुनी हो जायगी और प्रति-व्यक्ति प्रति-वर्ष आय १९७३-७४ तक दुगुनी हो जायगी ।

राष्ट्रीय आय और विनियोग में वृद्धि (१९५१-७६)

(१९५२-५३ के मूल्यो पर आधारित)

विषय	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	चतुर्थ योजना	पाँचवी योजना
	१९५१-५६	१९५६-६१	१९६१-६६	१९६६-७१	१९७१-७६
१	२	३	४	५	६
१-राष्ट्रीय आय अवधि के अन्त में (करोड़ रु० में)।	१०,८००	१३,४८०	१७,२६०	२१,६८०	२७,२७०
२-कुल वास्तविक विनियोग (करोड़ रु० में)	३,१००	६,२००	६,६००	१४,८००	२०,७००
३-अवधि के अन्त में विनियोग राष्ट्रीय आय के प्रतिशत रूप में।	७.३	१०.७	१३.७	१६.०	१७.०
४-अवधि के अन्त में जन-संख्या (मिलियन में)।	३८४	४०८	४३४	४६५	५००
५-पूँजी उत्पत्ति में वृद्धि।	१.८ : १	२.३ : १	२.६ : १	३.४ : १	३.७ : १
६-अवधि के अन्त में प्रति व्यक्ति प्रति-वर्ष आय।	२८१	३३१	३९६	४६६	५४६

४-तृतीय पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि

(Third Plan and the National Income)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में देश की राष्ट्रीय आय में ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि होगी और ५ प्रतिशत से कम तो यह किसी भी दशा में नहीं होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बिना जनता की निम्नलिखित समस्याओं का सामना नहीं हो सकता। क्योंकि देश की जनसंख्या में १.८% प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है इसलिए राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि लगभग ४% प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से होगी। यह साधारण लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए विनियोग में ११% से अधिक वृद्धि की आज्ञा करेगा। (ओकि हाल ही में विदेशों को सहायता से तथा अपनी विदेशी मुद्रा के वापस होने से १४ से १५ प्रतिशत तक पहुँच गया है।)

इस विषय में यह आवश्यक है कि योजना एक लम्बे समय के लिए बनाई जाय । चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि का लक्ष्य ८ प्रतिशत प्रतिवर्ष होना चाहिए जिससे कि प्रति व्यक्ति की प्रतिवर्ष आय, १५ वर्षों में लगभग दुगुनी हो जाय । समाज की वृद्धि को केवल इस दर पर स्थिर करके ही देश विनियोग के लक्ष्य को पूरा कर सकता है ।^१

५—बृहत् औद्योगीकरण की ओर *

(Towards Greater Industrialisation)

औद्योगिक क्रांति के बहुत समय पूर्व ही भारत सवार की औद्योगिक कर्मशाला (Industrial Workshop) माना जाता था । कुशल दस्तकारों का हाथ का बना हुआ देशी वस्त्र, छीट, मलमल, पत्थर, लकड़ी, तथा हाथी दाँत की शिल्पकारी सम्पूर्ण सवार में प्रसिद्ध थी ।

अंग्रेजों के भारत आने से इनका विनाश हुआ । इसके पश्चात् उपभोग की वस्तुएँ तथा भारी उद्योग कुछ सीमा तक देश में पतने ।

अंग्रेजों के समय में औद्योगीकरण की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं थी और न राष्ट्रीय आधार पर उद्योगों के विकास के लिए कोई प्रयास ही किया गया था । परिणामस्वरूप द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् मुख्यस्थित और मुट्ठ उद्योगों में भी पतन के चिह्न दिखाई देने लगे । इसका कारण यह था कि सन् १९३९-४५ में औद्योगिक औजारों से अत्यधिक काम लिया गया था जिसके कारण वे नष्ट प्राप्त हो चुके थे । केवल यही नहीं था बल्कि सन् १९४७ में देश की बदली हुई परिस्थिति के कारण आर्थिक एकता समाप्त हो गयी । इस प्रकार सन् १९४७ में, जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तो हमारे उद्योगों को एक विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा । कच्चा माल कम था इसलिए उत्पादन की मात्रा बड़ी मन्द गति में बढ़ सकी । आवश्यक वस्तुओं का मूल्य भी अन्य वस्तुओं की भाँति बहुत ऊँचा हो गया था ।

उस समय की पुकार 'अधिक उत्पादन' की थी । उत्पादन के सभी क्षेत्रों में संगठन में कार्य करने के लिए उद्योगों के विकास की एक निश्चिन नीति आवश्यक थी । फलतः सन् १९४८ में, सरकार ने, 'अन्तरी, औद्योगिक नीति' की 'घोषणा' की जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया । इस नीति के अनुसार उद्योगों का विभाजन तीन श्रेणियों में—विनियोग, स्वामित्व तथा नियन्त्रण की दृष्टि से—किया गया ।

1. Report of the Congress Planning Sub-committee

2. Towards Greater Industrialisation, Govt of India, Feb. 1957, से सहायता ली गई है ।

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ।

(ख) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग ।

(ग) निजी क्षेत्र के उद्योग ।

यह भी निर्णय किया गया था कि कुछ क्षेत्रों में राज्य केवल नवीन उद्योगों को ही स्थापना करे तथा १० वर्षों तक स्थापित वर्तमान उद्योगों को ऐसे ही बना रहने दे । क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया । औद्योगिक नीति की सभी दिशाओं के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, सरकार ने एक उचित प्रणाली का प्रचलन किया और सन् १९५१ में इस उद्देश्य से इण्डस्ट्रीज डवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन एक्ट, १९५१ (Industries Development and Regulation Act, 1951) पास किया, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक शक्ति उपार्जन कर ली ।

देश में औद्योगीकरण की गति को तीव्र करने की आवश्यकता को व्यापक रूप से अनुभव किया गया । लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय, दुर्भाग्यवश हमारे समक्ष इसने अधिक आवश्यक कुछ और समस्याएँ थी । इसलिए उद्योगों के विकास के लिए तथा खनिज पदार्थों का सही उपयोग करने के लिए कुल विनियोग का केवल ७% प्रदान किया जा सका । इस प्रकार औद्योगिक विकास की महत्वाकांक्षा पूरी न हो सकी । प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्पादन का लक्ष्य निजी क्षेत्र में ४१% उद्योगों की वृद्धि थी तथा बहुत बड़ी संख्या की वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र में होनी थी । योजनाकाल में औद्योगिक वृद्धि ६१% के लगभग हो सकी ।

६—द्वितीय पंचवर्षीय योजना : औद्योगीकरण के लिए एक बड़ा कदम

(Second Five Year Plan : A great step towards Industrialisation)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों, खनिज पदार्थों तथा यातायात के विकास पर विशेष बल दिया गया । सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनियोग द्वितीय योजना में १८% प्रतिशत बढ़ गया । मौलिक उद्योगों (Basic Industries) के विकास के लिए उद्योगों तथा खनिज साधनों पर किया जाने वाला प्रस्तावित कुल विनियोग ६६० करोड़ रु० था । व्यक्तिगत उद्योगों के विकासार्थ निजी क्षेत्र में (कुल ७२० करोड़ रु० का विनियोग होना था) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को विस्तृत करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के ५० प्रतिशत विनियोग के स्थान पर द्वितीय योजना में ६१ प्रतिशत विनियोग होगा । द्वितीय योजना का लक्ष्य भारी तथा मौलिक, उपयोग उद्योग, छोटी मात्रा तथा कुटीर उद्योगों में

सन्तुलित विकास करना है जिससे कम से कम उत्पादक एवं बिना कठिनाई के समाजवादी समाज की स्थापना की जा सके। इससे स्पष्ट है कि उत्पादक तथा पूँजी निर्माण करने वाली वस्तुएँ बड़ी मात्रा के उद्योगों द्वारा बनाई जानी चाहिए एवं उपभोक्ता की वस्तुएँ अधिकतर लघु तथा कुटीर उद्योगों में बनानी चाहिए।

क्या हमारे देश के औद्योगिक विकास एवं हमें प्राप्य वस्तुओं तथा सेवाओं पर द्वितीय योजना के प्रभाव को ज्ञात करना आसान है ? निम्नलिखित कुछ तथ्यों से द्वितीय योजना की विशालता का स्वरूप ज्ञात हो सकता है। औद्योगिक उत्पादन (सम्पूर्ण) सन् १९५१ की तुलना में ६४% बढ़ेगा। उत्पादक वस्तुओं (Producer goods) में ७३% की वृद्धि होगी और कारखानों में बनाई हुई उपभोग की वस्तुओं (Factory Produced Consumers goods) में १८% वृद्धि होगी। इस योजना के परिणामस्वरूप हम कृत्रिम खाद और रेल के इंजिन की उत्पत्ति में स्वावलम्बी बन सकेंगे और मोटर स्प्रिट तथा फर्नेस (Furnace) के लिए तेल की उत्पत्ति में अपनी आवश्यकता की मात्रा को पार कर जायेंगे। अब से ३ मिलियन टन अधिक फौलाद २२ मिलियन टन अधिक कोयला और प्रायः ६ मिलियन टन सीमेन्ट अधिक उत्पन्न हो सकेगा। चार आधुनिक जहाज, १८०० रेल के डिब्बे, एल्कोहोल के ६ मिलियन गैलन अधिक उत्पत्ति और मिट्टी के तेल का ४ मिलियन टन शोध कार्य होगा।

उपभोग की वस्तुओं के उद्योगों में सूती कारखानों के उत्पादन में २५% की वृद्धि होगी। चीनी के उत्पादन में ३५ प्रतिशत, बनस्पति तेल में ३१ प्रतिशत तथा कागज और पट्टे में १०० प्रतिशत वृद्धि होगी। इस प्रकार हम योजनाकाल में पर्याप्त मात्रा में सूती वस्त्र, चीनी, कागज, सीमेन्ट, कृषि-सम्बन्धी वस्तुएँ और सबक बनाने वाली मशीन उत्पन्न करने में समर्थ हो सकेंगे। मोटर गाड़ियों के उद्योग में कार तथा ट्रक की उत्पत्ति में ८०% वृद्धि होगी। रासायनिक उद्योग का विकास होगा। सोडा का उत्पादन तिगुना तथा कास्टिक सोडा का १०० प्रतिशत होगा। खनिज पदार्थों के उत्पादन में ५८ प्रतिशत की वृद्धि होगी। देश के लिए आवश्यक कीटाणु नाशक वस्तुएँ पूर्ण मात्रा में उत्पन्न होगी। उद्योगों के विकास में बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे उद्योगों तथा गृह उद्योगों के विकास पर भी समान महत्व प्रदान किया जायगा।

द्वितीय और तृतीय योजना के अन्त तक भी हम इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा रूस जैसे उन देशों के बराबर औद्योगिक विकास नहीं कर सकेंगे। यह सर्वविदित है कि इन देशों ने आधुनिक स्तर तक पहुँचने तथा उत्पादन को बढ़ाने में काफी समय लिया है। इसलिए आगामी पाँच वर्षों में ही पूर्ण नवीन भारत बनने की आशा

करना व्यर्थ है और न औद्योगिक ढाँचे को सम्पूर्ण बुराइयों को दूर करने की ही आशा की जा सकती है। द्वितीय और तृतीय योजनायें सही रास्ते की ओर केवल एक कदम हैं। वास्तव में कुछ योजनाओं के पश्चात् ही हम पूर्ण सन्तुलित तथा परिवर्तनशील औद्योगिक ढाँचे के स्थापनार्थ आगे बढ़ सकते हैं। सतत प्रयासों से हम नवीन और खुशहाली के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

७—खाद्य प्रवन्ध (Provision for food)

सभी मानवोद्योग आवश्यकताओं में भोजन की आवश्यकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समुचित एवं सन्तुलित विकास के लिए मानव को अच्छा तथा शक्तिदायक भोजन आवश्यक है। यह हमारी आर्थिक व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि आवश्यकता से अधिक कृषि होने के बावजूद भी हम भोजन को न्यूनतम आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। डा० राधाकमल मुखर्जी ने सन् १९३५ में लिखा था, “भारत की समस्त जनसंख्या, जो ४८ मिलियन है, उसके लिए भोजन की कमी है। प्रत्येक मनुष्य की प्रतिदिन की खुराक औसत ४२३ कैलरी (Calories) की कमी है।”^१ जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की तुलना में भोजन की पूर्ति की दर में प्रतिवर्ष ह्रास हो रहा है। यदि इसे रोकने के विशेष उपाय नहीं किये गये तो आगामी वर्षों में इसमें और ह्रास होने की पूरी सम्भावना है।

डा० बी० सी० गुहा (Dr. B. C. Guha)^२ ने एक हिसाब तैयार करके यह बताया है कि औसत रूप से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन के भोजन से २८०० कैलरी प्राप्त होनी चाहिए जिसके लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थ का उपभोग प्रतिदिन होना चाहिए :—

चावल (Unmilled or lightly milled Rice)—	१० औंस
गेहूँ	६ ”
दाल	४ ”
अण्डे	१ या दो
पीनी	२ औंस
दूध तथा दूध की बनी वस्तुएँ	१० ”
मछली और गोشت	४ ”
बिना पत्तीदार सब्जी	५ ”

1. “India has now fallen short of food for 48 millions of her average men. The average deficit is 423 calories in each man's daily ration”—Dr. Radha Kamal Mukharjee

2. *Planning for Nutrition*—Science & Culture, March, 1944.

हरी पत्तीदार सब्जी

५ औंस

चर्बी तथा तेल

२ "

फल

३ "

इस धुराक का साधारणतौर से व्यय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ३ रु० है। इस प्रकार यह व्यय ६० रु० प्रतिमास होता है, जो कि औसत परिवार के लिए प्राप्त करना असम्भव है। इसलिए यह कथन सत्य है कि "भ्रष्ट के विषय में भी हम पिछड़े हुए हैं," जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जायगा :—

कुछ देशों में भोजन से प्रति-व्यक्ति शक्ति और कैलोरी की वार्षिक प्राप्ति
Statement showing Annual per-capita energy and food contents in some countries
(Source *Eastern Economist*, Annual Number, 1950)

देश	कैलोरीज (Calories)			कुल प्रोटीन (Total protein)			पशु प्रोटीन (Animal protein)		
	युद्ध से पूर्व	१९४८-४९	१९४९-५०	युद्ध से पूर्व	१९४८-४९	१९४९-५०	युद्ध से पूर्व	१९४८-४९	१९४९-५०
फ्रान्स	२,८३०	२,६६०	२,६६०	६८	८३	८७	३३	३३	४१
पश्चिमी जर्मनी	२,६६०	२,४३०	२,६६०	८३	८१	७८	४०	२७	३३
इटली	२,४१०	२,३५०	२,३७०	८२	७५	७५	२०	१८	२०
	३,२२०	२,६७०	३,१३०	८१	१०१	१०२	४५	५२	५६
	३,१२०	३,०७०	३,२००	८५	८५	८५	५३	५३	६०
इंग्लैंड	३,१००	३,०४०	३,०८०	८२	८३	८१	४५	४३	४६
कनाडा	३,०७०	३,०६०	३,१३०	८५	८२	८३	४८	५६	५८
संयुक्त राज्य अमेरिका	३,१५०	३,१३०	३,१७०	८८	८०	८१	५०	६०	६०
ऑस्ट्रेलिया	३,०००	३,२१०	३,२१०	१०३	८७	८८	६७	६६	६७
न्यूजीलैंड	३,२६०	३,१३०	३,४००	८६	८४	१०१	६४	६३	६६
संका	२,१६०	१,६७०	२,०१०	५५	४३	४४	१६	११	११
चीन	२,२३०	२,१७०	२,०२०	७१	६६	६२	६	५	५
भारत	१,६७०	१,६२०	१,७००	५६	४२	४३	८	६	६
हिन्द चीन	१,८६०	१,४६०	१,५६०	४५	३५	३७	८	५	५
इंडोनेशिया	२,०४०	१,७६०	१,८८०	४६	४१	४२	५	५	५
जापान	२,१८०	२,०५०	२,१००	६४	५०	५३	१०	८	८
मिथ	२,४५०	२,४६०	२,३६०	७४	७२	७०	८	१०	१०
टर्की	२,५६०	२,५५०	२,३४०	७८	८०	७४	१२	१८	१७

“अमेरिका में औसत व्यक्ति के कॅलरीज के उपभोग का परिमाण, ३१७० एव इंग्लैंड में ३०८० है; लेकिन भारत में यह केवल १७०० है। प्रोटीन के उपभोग की हालत और भी खराब है। इस प्रकार हम अपनी खाद्य की आवश्यकताओं की सतुष्टि में बहुत ही पीछे हैं। यही कारण है कि भारतीय नागरिक सामान्य रूप से दुर्बल, श्रुक्षल, अवसादग्रस्त और प्रेरणाहीन होते हैं। खाद्य की कमी के कारण ही औसत रूप से भारतीयों को जीविन रहने की दर नीची है।^१

पञ्चवर्षीय योजनाओं में यह उल्लेख किया गया है कि कृषि की योजना बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त भोजन तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्था को आवश्यक कच्चा माल प्रदान कर सकेगी। सन् १९६०-६१ में आधुनिक उपभोग की दर से अन्न की ७०.५ मिलियन टन की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। सन् १९६१ तक के उपभोग की दर में वृद्धि का अनुमान प्रति वयस्क १८.३ औंस है जिसके फलस्वरूप सन् १९६१ तक कुल आवश्यकता का अनुमान ७५ लाख टन होगा। आगामी योजना के पाँच वर्षों में अन्न के उत्पादन में १० लाख टन की वृद्धि होगी। कॅलरीज में प्रति वयस्क का प्रतिदिन का उपभोग आजकल २२०० है जिसकी कि १९६०-६१ तक २४५० होने की आशा की जाती है। जब कि यह मात्रा कम से कम ३००० कॅलरीज होनी चाहिए।^२

८.—वस्त्र

(Clothing)

भोजन के पश्चात् हमारी अगली आवश्यक आवश्यकता वस्त्र है।^३ हम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उपभोग किये हुए वस्त्र के परिमाण से प्रति व्यक्ति की कपड़े की सतुष्टि को माप सकते हैं। प्रति व्यक्ति का वार्षिक कपड़े के उपभोग का अनुमान ६.७ गज आता है। औसत में इस देश के एक व्यक्ति को एक वर्ष में भी दो धोती प्राप्त नहीं होती और बहुत से इससे भी बुरी दशा में हैं। वस्त्रों के उपभोग के विषय में भारत की स्थिति सुधरने की अपेक्षा गिरती जा रही है। युद्ध से पूर्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कपड़े का उपभोग १६ गज था, जो सन् १९४८ ई० में १४.५ गज, सन् १९४९ में १२.६ गज और सन् १९५० में केवल ६.७ गज ही रह गया। इंग्लैंड में कपड़े

1. *Economic Basis of Higher Standard of Living*—T. P. Khaitan Lecture of Calcutta University, delivered by B. T. Thakur, Aug. 1952, p. 7.

2. *Second Five Year Plan*—pp. 259-60.

3. *Economic Basis of Higher Standard of Living*—T. P. Khaitan Lecture of Calcutta University, delivered by B. T. Thakur, Aug. '52, pp. 7-8.

की प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति उपभोग की औसत ४० गज से भी अधिक है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की ६४ गज से भी अधिक है, यानी हमारे देश से ६ गुनी अधिक है। इसके अतिरिक्त इन देशों के निवासी सूती कपड़ों के साथ साथ गर्म, रेशमी तथा रेघन आदि कपड़ों का भी बहुत मात्रा में उपभोग करते हैं।

कुछ देशों का प्रति-व्यक्ति प्रति-वर्ष सूती कपड़े के उपभोग का साधारण अनुमान

वर्ष	सं० राज्य अमेरिका ^१ (गज)	इंग्लैंड ^१ (गज)	भारत ^२ (गज)
सन् १९४८	६५.४	३७.६	१४.५
सन् १९४९	५६.३	३६.८	१२.६
सन् १९५०	६४.८	४१.५	६.७

हमारे देश के प्रति व्यक्ति कपड़े के उपभोग को बढ़ाने के लिये एवं कम से कम आवश्यकता की पूर्ति के लिए, हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

रहन सहन के स्तर को ऊँचा करने तथा जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, आवास, आमोद प्रमोद, सामाजिक सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छे प्रयत्न होने चाहिए। यह सन्तोष की बात है कि जब से हमने राष्ट्रीय नियोजन प्रारम्भ किया है, जनता को उपयुक्त बातों में बहुत सी सुविधाएँ दी जा रही हैं। सरकार, विभिन्न वर्ग एवं साधारण जनता द्वारा सामूहिक रूप से इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि देशवासियों को जीवन की अधिकतम सुविधायें मरलता से प्राप्त हो सकें और उनका साधारण जीवन स्तर ऊँचा हो सके।

1. Commerce, Annual Number, 1951, p 1151.

2. Monthly Statistics of the U. N for Nov, 1951.

नियोजन तथा मूल्य-निर्धारण

(Planning And the Price Mechanism)

१—उद्योग का नियन्त्रण एवं मूल्य (Control of Industry and Price)

बाजार पर नियन्त्रण तथा मूल्य-निर्धारण केन्द्रीय नियोजन के आवश्यक पहलू है। स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में ये इतने सत्य नहीं होते। स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में हर उद्योग को, उसकी सामर्थ्य के अनुसार उत्पादन का अधिकार होता है तथा बाजार की स्थिति के अनुसार अथवा माँग और पूर्ति के हिमाव से मूल्य-निर्धारण करने का अधिकार होता है। केन्द्रीय नियोजन मूल्य-निर्धारण के मौलिक सिद्धान्तों में विश्वास नहीं रखता। अगर नियोजनाधिकारी आवश्यक समझें तो नियन्त्रण को कई प्रकार में लागू कर सकते हैं। स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था के नियोजक तथा उसके समर्थक हर बात में अमहमत हो सकते हैं लेकिन यह इस बात पर महमत है कि देश को धनी औद्योगिक एवं कुशल बनाने के लिए पूर्ण आर्थिक स्थायित्व होना चाहिए।

राष्ट्र की आर्थिक मुक्ति के लिए योजना हो या न हो? प्रतिदिन के जीवन के विभिन्न पहलुओं का यदि वर्गीकृत अध्ययन किया जाय तो प्रतीत होगा कि हमारे जीवन में नियोजन अत्यन्त अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र विद्यमान है। यदि एक पदार्थ लगाना हो तो हम सोचते हैं कि वह किस प्रकार का, किस रंग का तथा कितना बड़ा एवं किस कीमत का हो? यही नियोजन है। यदि भोजन बनाना हो तो यह सोचा जाता है कि कैसा खाना बनाया जाय, कितने परिमाण में तथा कितने व्यक्तियों के लिए हो? यह भी नियोजन की बात है। तो हम इस बात को क्यों मानें कि स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में नियोजन नहीं हो सकता? जब कोई साहसी कोई उद्योग प्रारम्भ करता है तो उसे (अथवा उसके कर्मचारियों को) स्थिति, लगने वाली पूँजी, यानायात एवं बाजार की सुविधाएँ, कच्चे माल और श्रम की प्राप्ति तथा लाभ की संभावनाओं आदि के विषय में विचार करना पड़ता है। यह नियोजन है।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय नियोजनाधिकारियों का यह दावा कि केवल वे ही आर्थिक स्थायित्व (Economic Stability) को परवाह करते हैं, पूर्णतः सत्य नहीं है। यदि राज्य इस ओर पूर्ण रूप से सतर्क रह कि स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था से नागरिकों की कोई हानि न हो पाए तो स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।

१९वीं सदी के प्रारम्भ में संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप न करने की नीति के समर्थन में निम्नलिखित वक्तव्य दिया था, “इन सभी आशीर्वादों के अतिरिक्त हमें सुखी और खुशहाल बनाने के लिये और क्या आवश्यक है ? एक बान की ओर आवश्यकता है वह है बुद्धिमान तथा मितव्ययी सरकार, जोकि मनुष्यों को एक दूसरे से हानि पहुंचाने से बचाती है तथा उन्हें अपने निजी उद्योगों की उन्नति तथा मजदूरों के परिश्रम को उनकी इच्छानुसार संचालित करने के लिए स्वतन्त्र करती है।” अमरीका में दीर्घकाल से स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था का प्रचलन है लेकिन क्या इससे अमरीका के निवासियों का रहन सहन का स्तर उन देशों के नागरिकों से निम्न है जहाँ कि केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था विद्यमान है ? इसका मुख्य कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार इस ओर सतर्क दृष्टि रखती है।

स्वतन्त्र वचन में बधनहीन (Unfettered) स्पर्धा (Competition) होती है। स्पर्धा दुर्बल तथा अनुपलब्ध उत्पादकों को बाजार से हटाने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह उद्योगों को तीव्रगति से उत्पादन करने के लिए एक कम कीमत पर उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित करती है। ‘योग्य ही जीवित रहे’ (Survival of the fittest) का सिद्धान्त यहाँ भी लागू होता है। केन्द्रीय नियोजन तथा नियंत्रण में ऐसा सदैव नहीं होता है। वहाँ स्पर्धा के लिये कोई स्थान नहीं होता। स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में इस बात का भय सदैव बना रहता है कि स्पर्धा कभी ‘प्रतियोगी’ (Competitive) के स्थान पर ‘गला काट’ (Cut-throat) न बन जाए। उन परिस्थिति में इस बात का भय घना रहता है कि शक्तिशाली इकाइयाँ दुर्बलों को समूल नष्ट करके एक प्रकार का समूल एकाधिकार (Monopoly), द्वि अधिकार (Duopoly) तथा कुछो का अधिकार (Oligopoly) या सब आदि का निर्माण न कर, जिससे वे आगे चलकर कीमतों में वृद्धि कर सकें। इसमें उपभोक्ताओं को लाभ के स्थान पर हानि अधिक होती है। केवल ऐसी ही परिस्थिति में राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह आर्थिक स्थायित्व को बनाय रखने के लिए नियन्त्रण-पद्धति को अपनाये।

क्या राज्य हस्तक्षेप करता है ? यदि करता है तो क्या वह राज्य के नियोजन का एक अंग नहीं है ? प्रारम्भिक मध्य इस बात का है कि राज्य को उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं ? यदि करना चाहिए तो किस प्रकार ? यह दो प्रकार से हो सकता है - 'कीमत पर नियन्त्रण की स्थापना करके, तथा प्रतियोगी बाजार की स्थापना करके'—जिसमें एकाधिकार आदि की कठिनाइयाँ दूर हो सकें। परन्तु यह भी राज्य नियोजन के प्रभावशाली कदम हैं।¹

स्वतन्त्र माहम केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था पर एक और श्रेष्ठता का दावा करता है। यह औद्योगिक इकाइयों के आर्थिक ध्येयों तथा नियन्त्रण की कुशलता के विषय में होता है। हर माहमों को राज्य की तुलना में घन सम्बन्धी आपत्तियों का अधिक भामना करना पड़ता है। पूँजी का अभाव उनको अपने आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों को मन्तुलित रूप से विनियोग करने को विवश कर देता है। इस प्रकार उनका लक्ष्य पूँजी का कम विनियोग करके अधिक उत्पादन करना होता है। उनको विनियोग करने में मितव्ययी बनना पड़ता है तथा विनियोग करने के लिए अच्छे में अच्छा तरीका एवं उद्योग चुनना पड़ता है।

इस उद्देश्य तथा लाभ प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए वे अपने उद्योगों को कुशल तथा प्रभावशाली ढंग से व्यवस्थित करने के लिए अत्यधिक मचेष्ट रहते हैं। वे कठिन प्रतियोगिता, पूँजी का अभाव, उँची दरों पर कर्ज लगना, श्रमिक सघों द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों आदि का सामना करते हुए भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। इन सब कामों के लिए उन्हें अधिक शक्ति, समय, धन और पूँजी की कुशलता पर सघन एकाग्रता, पहले से सघ बनाना और उद्योगों का कुशल प्रबन्ध करना पड़ता है।

राज्य उद्योगों में स्वभावन इस बचत का अभाव होता है। इसका मूल कारण यह है कि वे लाभ की दृष्टि से नहीं चलाये जाते। उन्हें स्पर्द्धा का सामना नहीं करना पड़ता है और यदि वे उत्पत्ति भी करें तो कर्मचारीगण को कोई लाभ नहीं होता है। यह बात आर्थिक रूप से सत्य है, लेकिन पूर्णतया ठीक नहीं। केन्द्रीय

1 "These are doubted when the Government is 'Capitalist' in nature and principles. As the government, in that case, has to take the side of the capitalists, it becomes very difficult to check monopolistic tendencies in the methods mentioned above. Indirect efforts at increasing the purchasing power artificially and raising the standards—are adhered to in that case with some degree of success."

नियोजित उद्योगों वाले देशों के विश्लेषण में प्रतीत होता है कि यह दावा सत्य नहीं है। इस क्षेत्र में उद्योग से प्राप्त करने का दृष्टिकोण मूल्यों को नीचा बनाने रखने के लिए सहायक है। फिर भी पूँजीपतियों का यह दावा कि इस क्षेत्र के मुकाबले स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था अच्छी है, अभी तक स्थिरमान है।

सभी देशों के सविधान अपने नागरिकों को आर्थिक स्वातंत्र्य, व्यापार की स्वतन्त्रता, रोजगार तथा व्यवसायों की स्वतन्त्रता प्रदान करने हैं। यहाँ फिर यह प्रश्न उठता है कि जब राज्य ने व्यापार की स्वतन्त्रता, उद्योग एवं व्यवसायों की स्वतन्त्रता प्रदान की है तो वह उद्योगों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करके इस अधिकार का अपहरण क्यों करता है? नागरिक अपनी आजीविका के साधनों में स्वतन्त्र होना चाहिए। इस क्षेत्र में राज्य का 'अनाधिकार प्रवेश' व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर 'अनाधिकार हस्तक्षेप' होगा। इस क्षेत्र में राज्य केवल प्रतिरक्षा उद्योगों पर नियन्त्रण अपना सकता है क्योंकि इनमें व्यक्तिगत पूँजी नहीं लगी होती है।

उद्योगों के क्षेत्र में, पूँजीवाद पर नियन्त्रण रखने के लिए नियोजन को अपनाना पड़ता है। निम्नलिखित कारणों का अस्तित्व पूँजीवाद पर नियन्त्रण रखने के लिए आवश्यक होता है :—

(क) आय तथा वितरण में समानता बनाए रखना।

(ख) श्रमिकों को शारीरिक परिश्रम के लिए अच्छी मजदूरी देना।

(ग) उद्योगों के अनुचित विस्तार को रोकना जो कभी अधिक उत्पादन, धन के एकीकरण तथा एकाधिकार की स्थापना करता है।

(घ) लाभ का लक्ष्य एवं जनता के शोषण पर प्रतिबन्ध।

(ङ) रहन सहन के स्तर को ऊँचा करने के उपायों को अपनाना।

(च) मूल्यों पर नियन्त्रण रखना।

पूँजीवाद के विरुद्ध ये सभी आरोप सत्य नहीं हैं और न ये किसी देश की आर्थिक शक्तियों पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण के आधार हैं। आज भी सनार के बहुन-से उन्नति के दिखार पर पहुँचे हुए देशों ने नागरिकों के स्तर को बिना गिराये ही पूँजीवाद को अपने देशों में बनाया रखा है। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया और पश्चिमी जर्मनी अदि कुछ इसके उदाहरण हैं।

इसका यह अर्थ नहीं है कि पूँजीवाद पूर्णतया लाभकारी है। उग्र टग के पूँजीवाद और अधिक से अधिक शोषण वाले पूँजीवाद का सभी देशों में समूल नाश या उसका पूर्ण विरोध होना चाहिए। लेकिन जब यह देशों के लिए लाभदायक हो तो इसको बने ही नहीं रहने देना चाहिए बल्कि राज्य की उमकी समुचित सहायता भी करनी चाहिए। पूँजीवाद के दोष 'पूँजीवाद' से अलग किये जा सकते हैं। इसलिए केवल उससे दोष ही दूर करने चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन सभी देशों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन यह कहना कि यह हमेशा केन्द्रीय नियोजन ही हो, गलत है। प्रत्येक देश में आर्थिक नियोजन चाहे वह किसी भी प्रकार का हो आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति तथा स्थिरता लाने के लिए आवश्यक होता है। इस नियोजन का स्वरूप देश की आर्थिक स्थिति और देश में विद्यमान आर्थिक प्रणाली पर निर्भर होता है। प्रत्येक देश के लिए चाहे वहाँ केन्द्रीय नियोजन हो अथवा स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था उद्योगों पर नियन्त्रण, मुद्रा-प्रसार और मुद्रा सकुचन पर नियन्त्रण, मूल्यों का सही निर्धारण, एकाधिकार का स्थापित न होना, आय और सम्पत्ति का समान वितरण और देश में एक ढंगपूर्ण वित्तीय-नीति का अपनाना आवश्यक होता है।

२—‘स्वतन्त्र बनाम नियोजित उत्पादन तथा मूल्य’

(Free Vs. Planned Production and Price)

इस बात को हर आदमी मानना है कि मनुष्यविरहित आर्थिक विकास तथा बाजार-बला के स्थायित्व (Stability of market-mechanism) के लिए मूल्यों पर नियन्त्रण होना चाहिए। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि मूल्यों पर नियन्त्रण कौन रखे ? उत्पादक, वितरक, उपभोक्ता अथवा राज्य ?

उत्पादक के दो मुख्य ध्येय इस प्रकार हैं—अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना एवं अधिकतम उत्पत्ति। इससे अति उत्पादन का भय मदा बना रहता है। यदि साहसों के अनुमान तथा हिसाब गलत हो जायें तो माँग तथा पूर्ति के पारस्परिक सम्बन्ध में असन्तुलन हो जाना है। जिसके फलस्वरूप कम उत्पादन अथवा अति उत्पादन हो सकता है। कम उत्पादन या अति उत्पादन दोनों में कुछ दोष होने हैं। अधिक में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादक दूसरे उत्पादकों से स्पर्धा करेगा और अन्त में एकाधिकार स्थापित कर लेगा। यदि वह एकाधिकार स्थापित कर लेता है तो उसकी वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण न तो माँग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होगा, न वस्तुओं के उत्पादन व्यय से और न बाजार की स्पर्धा से बल्कि ऐसे समय में वह अपनी वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा—जिसे प्रायः उपभोक्तृओं को नष्ट होता है।

इस प्रणाली में ‘बनावटी अभाव की उत्पत्ति’ एक दूसरा भय और होता है। यह उत्पादक अथवा वितरक द्वारा एक असंश्लेषित अवधि तक मूल्यों को बढ़ाने के उद्देश्य से होता है, जिसे उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब तक इन बुराइयों को दूर नहीं किया जाता तब तक सामाजिक तथा आर्थिक समानता नहीं आ सकती।

नियोजित अर्थव्यवस्था के समर्थको^१ का कहना है कि पूँजीवादी व्यापार-जगत में हर चीज व्यापारिक गोपनीयता के आवरण में छिपी रहती है ।

नियोजित अर्थव्यवस्था के समर्थको का कहना है कि “पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के अस्तित्व में देश का आर्थिक ढाँचा अस्त-व्यस्त हो जाता है और देश में एक आर्थिक विषमता उत्पन्न हो जाती है । उत्पादको और वितरको के सामने केवल एक ही मार्ग प्रदर्शक होना है—वस्तुओं का मूल्य । यदि मूल्य में वृद्धि होती है तो सभी उत्पादक लाभ के लालच से अधिकतम उत्पत्ति करने लगते हैं, जिनमें अति उत्पत्ति की स्थिति आ जाती है । “ फिर मन्दी आने के कारण उत्पत्ति कम हो जाती है, बेरोजगारी फैलती है, लोगों को वस्तुएँ प्राप्त करने में कठिनाई होती है । इस प्रकार इन दोषों में व्यवसाय चक्र तीव्रता में चलता रहता है “ बाजार मूल्य में स्थिरता या सन्तुलन आने के साहसिया के समस्त प्रयास अमफल हो जाते हैं । ” (*Planning in the Soviet Union—S. G. Strumilin, 1957 p. 3.*)

रूस का दावा है कि उनकी राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा जो नियोजन-प्रणाली बनाई और अपनाई गई है उसने रूस में एक ऐसी अर्थव्यवस्था को नफल रूप दिया है जिसमें व्यापारिक चक्र, मन्दी, आर्थिक सकट, मूल्यों का भीषण उतार-चढ़ाव समाप्त हो गया है । (*Ibid, p. 3*)

३—स्वतन्त्र वितरण बनाम राज्य का व्यापार एवं मूल्य (Free Distribution Vs State Trading and Prices)

स्वतन्त्र वितरण को अर्थव्यवस्था में भी सभी वस्तुओं का वितरण का कार्य उत्पादको, थोक व्यापारियों तथा खेरीज में बेचने वालों द्वारा पूरा किया जाता है । वे विक्री की विभिन्न प्रकार की रीतियों का प्रयोग करते हैं । स्वतन्त्र वितरण में ये वितरक ही समान तथा अन्धे वितरण के लिए उत्तरदायी होते हैं ।

सभी वस्तुओं की कीमत, एक सख्त सीमा तक, वितरण की प्रकृति पर निर्भर होती है । यदि वितरण पूर्ण तथा सन्तुलित है तो कीमते सामान्य तथा स्थिर होती हैं । इसके अभाव में कीमते असाधारण और असन्तुलित होती हैं तथा कीमतों में तनिक भी स्थायित्व नहीं होता है । इसलिए वितरण सुव्यवस्थित होना चाहिए ।

1. *Planning in the Soviet Union*, Academician S. G. Strumilin, pp. 2-3.

वितरकों के मुख्य उद्देश्य दो होते हैं—अधिकतम विक्री और अधिकतम लाभ। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वितरक कभी कभी असाधु उपाय अपनाते हैं, जैसे कृत्रिम उपाय से वस्तुओं की कमी उत्पन्न करना, चोरी से वस्तुओं का अपने पाम बड़ी मात्रा में संचय करना या वस्तु के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि करना। यदि उन्हीं वस्तुओं की पूर्ण इन वितरकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा समभव होनी है तो इनके बेईमानी के सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। परन्तु, यदि इनकी पूर्ति अन्य धर्मों द्वारा सम्भव नहीं होती तो उपभोक्ता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यावहारिक जीवन में उपभोक्ताओं को इन परिस्थितियों में तब तक कठिनाइयों उठानी पड़नी हैं जब तक कि इन परिस्थितियों में राज्य का हस्तक्षेप न हो।

जो कुछ देदी वस्तुओं के विषय में मत्त है, वही आयात निर्यात की हुई वस्तुओं के विषय में मत्त है, यदि वितरक चाहे तो आयात निर्यात की वस्तुओं में चोरवाजारी की अधिक सम्भावना है—क्योंकि इस क्षेत्र में, बढ़ती कीमतों को रोकने, कीमतों के अस्थायित्व को रोकने अथवा उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने में राज्य की बड़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में राज्य के लिए केवल एक ही मार्ग शेष रहता है—वस्तुओं के आयात निर्यात में राज्य का नियन्त्रण।

कुछ भी हो, हम इस मत्त को नहीं भुल सकते कि स्वतन्त्र वितरण के कार्य (राज्य की तुलना में) अधिक कुशल होते हैं अर्थात् राज्य वितरण कार्यों के स्वतन्त्र वितरण में कम कुशलतापूर्वक निर्वाह कर पाता है। स्वतन्त्र वितरण में लोग अधिक लगन से, उत्साह से, अनुभव से, तथा लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। ऐसा राज्य नियन्त्रित व्यापार से नहीं हो पाता है। अनुभव तथा अन्तर्दृष्टि के कारण वितरक व्यापार की भली भाँति व्यवस्था कर सकते हैं तथा कीमतों में अधिक स्थायित्व एवं वितरण में अधिक समानता ला सकते हैं।

स्वतन्त्र वितरण का एक बड़ा लाभ और है। स्पर्धा के होने तथा 'सीमान्त वितरक' के अस्तित्व के कारण वितरक माल जमा करने, माल रखने, बनाबंदी अभाव की उत्पत्ति करने एवं वस्तुओं की मनमानों कीमतों को बढ़ाने के बहुत कम अवसर प्राप्ति हैं। ऐसे समय में उपभोक्ता को दो तरह में लाभ होता है—वस्तुयें शीघ्र मिल जाती हैं और कम कीमत देनी पड़ती है।

४—प्रतिस्पर्धीय धनाम नियन्त्रित कीमत

(Competitive Vs Controlled Price)

प्रतिस्पर्धीय कीमत का अर्थ है कि माँग एवं पूर्ण की शक्तियों के प्रभाव से

कीमत का निर्धारण अर्थात् प्रतिस्पर्द्धीय शक्तियों (माँग और पूर्ति) में जहाँ मन्तुलन स्थापित हो जाय वही कीमतों का निर्धारण होगा । यह कीमतों के निर्धारण का आर्थिक सिद्धान्त है । अधिकतर परिस्थितियों में कीमते इसी प्रकार निर्धारित की जाती हैं । इसमें बहुत-से लाभ होने हैं—जैसे, प्रतिस्पर्द्धा के परिणामस्वरूप कीमतों का कम हो जाना, औद्योगिक इकाइयों का अपनी उत्पत्ति की प्रणालियों को उन्नत करने को इच्छुक तथा मनक रहना । इस प्रणाली में कीमत, उत्पत्ति की सीमान्त कीमत के बराबर होती है, बाजार में केवल एक ही कीमत का प्रसार होता है, कीमतों में कोई अन्तर नहीं हो सकता है एवं इन माधारण परिस्थितियों में एकाधिकार की स्थापना नहीं हो सकती ।

कीमतों का निर्धारण जब माँग और पूर्ति की शक्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया से नहीं होता तभी उस मूल्य को नियन्त्रित करने के लिए उद्देश्य या राज्य की कदम उठाना पड़ता है । प्रतिस्पर्द्धा के फलस्वरूप छोटी इकाइयाँ यदि बाजार में हट जायँ और बड़े उद्योगपति एकाधिकार की स्थापना करके कीमतों को एक अनुचित सीमा तक बढ़ा दें तो नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है । दूसरे, यदि उत्पत्ति केवल एक संगठन या व्यक्ति के अधीन होती है, और वह कीमतों में स्वेच्छा से अन्तर लाने रहे तो नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है । तीसरे, यदि अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के व्यय से, कृत्रिम अभाव उत्पन्न करके कीमतें बढ़ा दी जायँ तो नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है । चौथे, वस्तुओं—विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की कमी या अभाव हो तो उपभोक्ताओं के समक्ष अधिक मूल्य देने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं होता है । इसलिए भी नियन्त्रण अधिकारियों के लिए, कीमत कम करने और मन्तुलित वितरण करने के लिए नियन्त्रण करना आवश्यक हो जाना है । पाँचवे, अमान की हुई वस्तु में व्यापारियों को अनुचित कीमत बढ़ाने के लिए बहुत अवसर मिलते हैं, जिसमें नियन्त्रण करने या व्यापार को प्रारम्भ करने के लिए राज्य विवश हो जाता है । छुटे, कभी कभी मुद्रा प्रसार के कारण अनुचित बढ़ी हुई कीमतों को रोकने के उद्देश्य से नियन्त्रण करना आवश्यक होता है ।

प्रतिस्पर्द्धीय (Competitive) कीमत कला (Price Mechanism) के समर्थकों का कहना है :—

(१) प्रत्यक्ष नियन्त्रण लागू करना (Imposition of direct control) सर्विधान की धाराओं के प्रतिकूल है । हमारे सर्विधान ने स्वतन्त्र व्यापार की स्वतन्त्रता प्रदान की है । जिसमें स्वतन्त्र रूप से मूल्य निर्धारण करना भी सम्मिलित है । प्रत्यक्ष नियन्त्रण इस धारा के प्रतिकूल है । जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह बात याद रखनी चाहिए कि नियन्त्रण कीमतों में स्थायित्व लाने के लिए किया

जाता है न कि व्यापारियों के व्यापार सम्बन्धी अधिकारों को समान करने के लिए। नियन्त्रण, उपभोक्ताओं को छोपण से बचाने के दृष्टिकोण से जब आवश्यक समझे जाते हैं लागू किये जाते हैं।

(२) यदि नियन्त्रण पूर्ण नहीं होते हैं तो उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा श्रमिकों को इससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उत्पादक लाभ प्राप्त करने के ध्येय में कार्य करते हैं। यदि यह लाभ प्रत्यक्ष नियन्त्रण से कम कर दिया जाय या समाप्त कर दिया जाता है तो वे अपनी पूँजों का विनियोग किन्हीं अन्य उद्योगों में करते हैं। इससे कुछ कठिनाइयाँ तथा उलझने उत्पन्न होती हैं। उपभोक्ताओं को, अपनी आवश्यकताओं को सतुष्ट करने के लिए, स्थायी कीमतों पर वस्तुओं तथा सेवाओं की सदैव आवश्यकता होती है। यदि उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन होने लगे तो पूर्ण और कीमतों में कोई स्थिरता नहीं रह पाती है। ऐसी परिस्थिति में श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने के कारण कठिनाइयाँ होंगी।

लेकिन यह बहुत दिन तक नहीं चल सकता। उत्पादक वर्ग को उत्पत्ति प्रारम्भ करने से पूर्व, बड़ा भारी विनियोग करना पड़ता है। इसलिए उनके लिए यह आमान नहीं है कि अपनी पूँजी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक उद्योग से दूसरे उद्योग में बदल सके। उत्पत्ति के प्रारम्भिक काल में कुछ मात्रा में परिवर्तन करने के पश्चात्, उत्पादन का स्थायित्व सामान्य पूर्ति के स्तर में प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को अधिक समय तक हानि नहीं उठानी पड़ती है। श्रमिकों की गतिशीलता में कुछ लाभ होता है, विशेषकर यह उनको कम मजदूरी के कार्यों को छोड़कर अधिक वेतन वाले मजदूरों के कार्य प्रदान करने में सहायक होते हैं।

(३) नियन्त्रण लागू करने से समय, शक्ति तथा धन व्यर्थ जाता है, जिसकी स्वतन्त्र बाजार में आवश्यकता नहीं होती है। राज्य को, नियन्त्रण लागू करने तथा उसे प्रभावशाली ढंग से संचालित करने के लिए एक मुख्यव्यय और सुसंगठित शासन की व्यवस्था करनी पड़ती है।

नियन्त्रण-प्रणाली के अधिक खर्च को जानते हुए भी, आवश्यकता पड़ने पर, प्रत्येक देश में इसे लागू किया जाता है। राज्य का कार्य केवल 'एक व्यक्ति समूह' को ही उन्नति के अवसर प्रदान करना नहीं है बल्कि जनता को अधिकतम सुविधायें और लाभ प्रदान करना है। इस प्रकार नियन्त्रण आवश्यक रूप से "कीमत-प्रणाली के स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की तुलना में बेढगा (Clumsy) अकुशल तथा बर्बाद वाला (Wasteful) नहीं होता है।" यदि नियन्त्रण उचित ढंग से व्यवस्थित,

सुसंचालित तथा सुसासित हो एवं उभे जनता के कल्याण तथा लाभ की दृष्टि से प्रारम्भ किया जाय तो यह अच्छा होता है। इनके अतिरिक्त नियन्त्रण इसलिए भी स्थापित किया जाना है कि आयात को मात्रा में कमी हो, निर्यात की मात्रा में वृद्धि हो और विदेशी मुद्रा की वृद्धि हो सके।

योजना आयोग के अनुसार^१ योजना के सदन में वित्तीय साधनों को एकत्र और संगठित करके आर्थिक नीति की इतिथी नहीं हो जानी बल्कि नीति का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि वह योजना की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग को प्रोत्साहित करे और वास्तविक साधनों का उपयोग करे। योजना केवल उन कार्यों को सूची नहीं है, जो हमें करने हैं, बल्कि योजना में एक नीति होती है जिसके अनुसार ये कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। मोटे तौर पर दो कार्य पद्धतियाँ हैं और उन दोनों का इस्तमाल किया जाना चाहिए। प्रथम आर्थिक क्रिया की वित्तीय नीति के माध्यम से पूरी तरह नियन्त्रित करना और द्वितीय, आयात और निर्यात नियन्त्रण, उद्योगों और व्यवसायों को लाइसेंस देना, मूल्य नियन्त्रण और नियमन आदि उपाय जो अर्थव्यवस्था के किन्हीं विधेय क्षेत्र की या उप क्षेत्र की आर्थिक क्रिया को प्रभावित और नियमित करने हैं। व्यापक योजना में जिसका उद्देश्य विनियोग में प्रत्येक वृद्धि करना और प्राथमिकता की योजना पर अमल करना होता है, इन दोनों तरह के नियन्त्रणों की जरूरत पड़ती है।

विकासशील अर्थव्यवस्था में वित्त और अर्थ के क्षेत्र में सरकार की बुनियादी प्रवृत्ति अनिवार्यतः प्रसारणात्मक होती है। अतएव मुद्रास्फीय की प्रवृत्ति को नियमित करने की मुख्य समस्या सामने आती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में साधन कम होने हैं जिनसे बहुत सी आवश्यक और आन्तरिक जरूरतों की पूर्ति करनी होती है। हमें सकता है कि कृषि उत्पादन क्षेत्र में कम हो या इस तरह की दूसरी कठिनाइयाँ पैदा हो जायें। लेकिन ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि जरा सी दिक्कत पड़ते ही विकास कार्यक्रम को रोक दिया जाय या धीमा कर दिया जाय। किन्ती हद तक जोखिम उठाना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मौका पड़ते ही आवश्यकतानुसार वस्तुओं पर नियन्त्रण लगाने के लिए तैयार रहा जाय। इन उपायों की मरुतता के लिए पहले से ही अनुकूल वातावरण तैयार किया जाना चाहिए।

१. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, (संक्षिप्त) १९५६ योजना आयोग, भारत सरकार, पृष्ठ—१८।

५—कर, द्रव्य का नियन्त्रण तथा कीमते

(Taxation, Control of Money and Prices)

कर मुख्य रूप से सरकारों राजस्व में वृद्धि करने, देश की आर्थिक अममानता को दूर करने, मुद्रा-प्रसार को कठिनाइयों को दूर करने एवं दरिद्रवर्गों को अधिक सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। कर-प्रणाली द्वारा देश की आर्थिक विषमताओं को दूर करने के साथ साथ देश की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य भी नियन्त्रित होता है। कर विभिन्न प्रकार से लगाए जा सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, मूल्य पर या माना पर। इसी प्रकार, कर विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं जैसे निश्चित दर कर, ऊर्ध्वगामी कर, प्रगतिशील कर, प्रयोगात्मक कर आदि। प्रत्येक देश में इन बातों की चेष्टा की जाती है कि कर प्रणाली को एक ऐसा सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया जाय जिससे देश में मुद्रा प्रसार एक जगह और मूल्यों में स्वतः नियन्त्रण स्थापित हो जाय। भारत में भी इन बातों का प्रयत्न किया गया है कि कर-प्रणाली में सुधार करके मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जाय।

नियोजन आयोग¹ के अनुसार भारत में टैक्सों के वर्तमान ढाँचे की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उनके द्वारा आबादी का अपेक्षाकृत बहुत कम भाग प्रभावित होता है। टैक्स द्वारा होने वाली कुल आमदनी का लगभग २८% प्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त होता है जिसका प्रभाव श्रमिकों की आबादी के एक प्रतिशत के लगभग भाग पर ही प्रत्यक्ष रूप में पड़ता है। लगभग १७% आमदनी आयात करों द्वारा होती है ... दूसरी ओर लगान से ... टैक्सों की कुल आमदनी का लगभग ८% वसूल होता है।

टैक्सों की यह सीमित दर राष्ट्रीय आमदनी में सरकार को टैक्स से प्राप्त आमदनी के छोटे अनुपात के लिये जिम्मेदार है। इसी के कारण टैक्सों की वर्तमान दर अधिक प्रतीत होती है। इसमें दोनों ही तरह सार्वजनिक बचतों की सीमा में बाधा पहुँचती है। ... परन्तु आयोजन की आरम्भिक अवस्थाओं में प्रोग्राम के आकार और वित्त के साधनों का निश्चय हम बातों को देखते हुए करना होगा कि आमन और राजस्व-कर मन्त्रालयों वर्तमान यन्त्र के द्वारा तथा वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक ढाँचे की सीमाओं के अन्दर क्या करना व्यावहारिक होगा। इसलिए जबकि भारत में टैक्स-नीति का उद्देश्य यह होता चाहिये कि टैक्स की आमदनी के स्तर को इस प्रकार से बढ़ाया जाय कि विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके,

1. पहली पंचवर्षीय योजना (जनता मस्करण), योजना आयोग, भारत सरकार, पृष्ठ, २८-२९।

हमें उन सामाजिक और आर्थिक ढाँचों के अनुकूल भी इस नीति को बनाये रखना होगा जिनके अन्तर्गत विकास का आरम्भ हुआ है ।

हमारे नियोजकों ने इस बात पर भी बल दिया है कि योजना में जिस सन्तुलन को प्राप्त करना है, वह वास्तविक और वित्तीय दोनों ही रूपों में होना चाहिए । उत्पादन के क्रम में मुद्रा के रूप में आय का जन्म होता है, और मुद्रा की माँग पर सम्भरित वस्तुओं की खपत होती है । अतः यह बात महत्वपूर्ण है कि मुद्रा के रूप में प्राप्त आय के व्यय को इस प्रकार नियमित किया जावे जिससे उपभोग्य वस्तुओं की माँग और पूर्ति के बीच, बचतों और विनियोग के बीच तथा वैदेशिक अर्जन और भुगतान के बीच सन्तुलन बना रहे । माँग और पूर्ति का सामंजस्य ऐसा हो जिससे भौतिक साधना का पूरा लाभ तो उठाया जा सके, पर मूल्य के ढाँचे में कोई बड़ा या असन्तुलित परिवर्तन न हो ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कीमतों को नियन्त्रित रखने के लिये यह आवश्यक है कि वित्तीय-व्यवस्था सुव्यवस्थित हो और कर प्रणाली भी देश में उन्नत प्रकार की हो ।

६—बढ़ती हुई, गिरती हुई अथवा स्थायी कीमतों में कौनसी सब से अच्छी है ?

(Are Rising, Falling or Steady Prices the Best ?)

बढ़ती हुई, गिरती हुई तथा स्थायी कीमतों के समर्थक विद्यमान हैं । कुछ यह कहते हैं कि,

१—बढ़ती हुई कीमतें—यदि उनमें वृद्धि धीरे-धीरे हो—देश के लिए बहुत लाभदायक होती हैं क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में उत्पादकों को लाभ होने के कारण देश में नये-नये उद्योगों की स्थापना होती है, कच्चे माल की अधिक खपत होती है, राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों का समुचित शोषण होता है, श्रमिकों को रोजगार मिलने में सुविधा होती है, सरकार को करों के रूप में अधिक राजस्व प्राप्त होता है और देश के औद्योगिक विकास द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है ।

२—कुछ अन्य व्यक्तियों का यह कहना है कि जब देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें धीरे-धीरे गिरती हैं तो देश को लाभ प्राप्त होता है क्योंकि

1. द्वितीय पंचवर्षीय योजना (सक्षित), योजना आयोग, भारत सरकार, पृष्ठ-७ ।

2. *Outlines of Economics*, M. Sen, Vol II, (1933), pp. 51-53.

ऐसी परिस्थितियों में उत्पादकों को अपनी उत्पत्ति की मात्रा को निश्चित करने के लिए काफी समय मिल जाता है और वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में कमी आ जाने के कारण जनता का उपभोग का स्तर ऊँचा हो जाता है ।

३—अधिकतर अर्थशास्त्री (जिनमें कैंसेल, कीन्स, हीट्रे आदि प्रमुख हैं) यह मानते हैं कि किसी भी देश के लिए न तो बढ़ती हुई कीमतें अच्छी होती हैं और न गिरती हुई कीमतें । वास्तव में यदि किसी देश को सुध्ववस्थित रूप से आर्थिक विकास करना हो तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्थिरता बनाए रखे । कीमतों में स्थिरता रहने में बाजार, उत्पत्ति और वितरण की अनिश्चितता सदा के लिए सुप्त हो जाती है और देश में व्यापार और विनिमय सुचारु रूप से चलता है—न किसी वर्ग को अत्यधिक हानि हो पाती है और न किसी वर्ग को लाभ । इस प्रकार हम दृढ़ता से यह कह सकते हैं कि कीमतों में स्थिरता रहने से उत्पादकों, उपभोक्तारों, सरकार, व्यापारी वर्ग आदि सभी को लाभ रहता है ।

प्रो० रीबर्टसन (Prof. Robertson) का मत है, “यदि हमारे सामने चुनाव करने की मुविधा हो तो आवश्यक रूप से हम ‘मूल्य में स्थिरता’ को ही चुनेंगे ... ”

प्रो० सैलिगमैन (Prof. Seligman) का मत है, “बढ़ती तथा घटती हुई कीमतों के कारण कीमतों में असन्तुलन उत्पन्न होता है जिससे उत्पादक, व्यापारी और नागरिकों को कठिनाई होती है । इसके कारण किसी एक वर्ग को अत्यधिक लाभ या हानि हो सकती है । वास्तव में बढ़ी हुई कीमत या कम कीमतें हानिकारक नहीं होनी बल्कि बढ़ती हुई कीमत और घटती हुई कीमत हानिकारक होती हैं । ... देश के मूल्य-स्तर में स्थिरता होनी चाहिए ।”

कीन्स (Keynes) के विचार इस विषय में इस प्रकार हैं,—“कीमतों में स्थिरता ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ (Gold Standard) से लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए बल्कि नियन्त्रित ‘पेपर स्टैंडर्ड’ (Paper Standard) द्वारा देश की केन्द्रीय बैंक और सरकार द्वारा इस मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण होना चाहिए ताकि कीमतों में, उत्पत्ति की मात्रा में, व्यापार और रोजगार की मात्रा में स्थिरता बनी रहे ।”

1. Robertson. —‘Money’ p. 140

2. Seligman—Principles. (Re-quoted from “Outlines of Economics.”—M. Sen Vol. II, P. 52)

3. Keynes.—General Theory.

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि देश के आर्थिक विकास के लिए या योजना को सफल बनाने के लिए यह परमावश्यक है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्थिरता बनी रहे क्योंकि ऐसी परिस्थिति में राज्य के समस्त नागरिकों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। सरकार, उत्पादक, उपभोक्ता, व्यापारी, श्रमिक, साहसी और यहाँ तक कि देश की साधारण जनता द्वारा भी इस बात की चेष्टा होनी चाहिए कि देश में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य-स्तर में स्थिरता बनी रहे।

आर्थिक नियोजन के पूर्व-प्रयोजन तथा

प्रभाव उत्पन्न करने के साधन

(Pre Requisites and Levers of Economic Planning)

विशेष रूप से भारतीय योजना के संदर्भ में

(With Special reference to Indian plans)

१—सांख्यिकीय आँकड़े और सूचनायें

(Statistical Data and Informations)

सफल आर्थिक नियोजन के लिए सांख्यिकी सम्बन्धी स्वीकृत आँकड़ों तथा सूचनाओं का प्रयोजन बहुत ही आवश्यक है। “आर्थिक नियोजन एक जटिल कार्य है, जिसमें आधार, सिद्धान्त, प्राथमिकताएँ, लक्ष्य, तत्त्व, आर्थिक पहलुओं की व्याख्या की जाय * * * नियोजकों को मौलिक सिद्धान्त को व्यवस्थित करना पड़ता है जिसे पर कि नियोजन का रूप और आकार आधारित होता है।¹ उसे उद्देश्यों, रोजगार, प्राथमिकताओं, विनियोग, व्यय प्रणाली एवं उत्पत्ति-लक्ष्य आदि से सम्बन्धित बहुत सी बातों पर नियोजन की रूपरेखा बनाने के लिए विचार करना पड़ता है। नियोजन को एक अच्छे रहस्य सहन के स्तर को प्राप्त करने का उपाय बताना होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने की प्रणाली का उपाय बताना होता है, एवं एक प्रगतिशील कर को अमल में लाने का प्रयत्न करना पड़ता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति में उन्हें सांख्यिकीय एवं सूचना की आवश्यकता पड़ती है। यदि ठीक तथा पर्याप्त स्वीकृत आँकड़े प्राप्त हैं तो आर्थिक नियोजक का कार्य अधिक आसान हो जाता है। इसके अभाव में नियोजक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्रथम योजना के निर्माण काल² में सांख्यिकीय एवं आँकड़ों सम्बन्धी बहुत-सी कठिनाइयाँ थीं। इनमें से कुछ निम्नलिखित थीं :—”

१—सांख्यिकीय संस्थाओं का अभाव।

२—विभिन्न विषयों पर क्षेत्रीय अनुसन्धान का अभाव।

1. *Statistics Papers* — A. B. Bhattacharya

2. *Second Five Year Plan*, Govt. of India, (1956) Chapter

३—विशिष्ट क्षेत्रों में वृद्धि, विनियोग, आय, उद्योग सम्बन्धी एवं प्रादेशिक विकास सम्बन्धी आकड़ों की कमी ।

इनके अतिरिक्त देश में जो सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध थे, वे ठीक और संशोधित नहीं थे । सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रकाशन एवं व्यवहार का प्रबंध भी आवश्यकानुसार एवं समयानुक्रम नहीं था, जिससे प्रथम पंचवर्षीय योजना के विश्लेषण को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में, सांख्यिकीय सामग्री एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने वाले संगठन और संस्थाओं को काफी सुदृढ़ किया गया है । १९४६ में केन्द्रीय सांख्यिकीय एकक और राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना, १९५० में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का प्रारम्भ और १९५१ में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना और भारतीय सांख्यिकीय संस्था का कार्य सांख्यिकीय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है । भारतीय सांख्यिकीय संस्था के कार्यों का भी विस्तार हुआ है । औद्योगिक मामलों में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन का राज्य सांख्यिकीय मण्डलों से निवृत्त सम्पर्क रहता है और वह समन्वयात्मक संस्था के रूप में कार्य करता है ।

सांख्यिकीय कार्य पद्धति के क्रमशः व्यापक रूप में विकास से दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में सहायता मिली है । १९५४ में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में योजना सम्बन्धी सांख्यिकीय कार्य में सम्बन्धित एक विशेष शाखा खोली गई है । भारतीय सांख्यिकीय संस्था और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने संयुक्त रूप में योजना सम्बन्धी औद्योगिक अध्ययन का कार्य हाथ में लिया और अनेक विषयों पर अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया । इसके बाद ही मार्च, १९५५ में योजना की एक रूपरेखा तैयार की गयी जिसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए सुझावों का संसिद्धा था ।

योजना निर्माण के साथ साथ मशीनों, सामग्री और श्रम की माँग और पूर्ति का लगानार सुगुलित रखने का अनिवार्य कार्य करना होगा । चान्द और प्रागामी योजनाओं के निर्माण के लिए सांख्यिकीय सूचना की और अधिक आवश्यकता होगी । साथ ही वित्तीय और भौतिक दृष्टि से योजना के संचालन का मूल्यांकन करते रहने की आवश्यकता पड़ेगी और आवश्यक समायोजन के लिए इस सूचना का प्रयोग करना होगा । इसलिए सांख्यिकीय पद्धति से निरन्तर अनिवार्य रूप से सूचना मिलनी चाहिए । इसका उद्देश्य केन्द्र और राज्यों के कार्यों को समन्वित करना है । केन्द्र के केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में योजना सम्बन्धी कार्यों के निरीक्षण के लिए एक योजना विभाग की स्थापना की गई है । योजना आयोग ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे राज्य के सांख्यिकीय मंडलों को राज्य के योजना सम्बन्धी सांख्यिकीय कार्यों

का उत्तरदायित्व लें। केन्द्रीय और राज्यीय सांख्यिकीय सस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। जिले के लिए जिला सांख्यिकीय एजेंसियाँ भी स्थापित की गई हैं। योजना आयोग का विचार है कि वह माँग और पूर्ति के भौतिक सम्बन्धों पर होने वाले औद्योगिक और सांख्यिकीय कार्यों को मजबूत और व्यापक बना देगा। दूसरे शब्दों में योजना से सम्बन्धित विनियोग, रोजी रोजगार और आय, पण्यों और जनशक्ति के सतुलन और योजना संचालन विषयक शोध सम्बन्धी अध्ययन कार्यों को बढ़ाया जायगा। भारतीय सांख्यिकीय सस्था में होने वाले सम्बन्धित कार्यों और भविष्य की योजना रचना को और विशेष ध्यान दिया जायगा। इस क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि योजना आयोग, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन और भारतीय सांख्यिकीय सस्था के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाई जाय।

२—उद्देश्यों का निर्धारण

(Determination of Objectives)

भारत में आयोजना का केन्द्रीय उद्देश्य जनता के जीवन के स्तर को ऊँचा उठाना और उनके लिए एक अधिक समृद्धशाली और विविधतापूर्ण जीवन के लिए अवसर प्रदान करना है। इसलिए आयोजन का लक्ष्य एक और तो यह होना चाहिए कि समाज में प्राप्त जन और सम्पत्ति के साधनों का और अधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जाय जिससे उन साधनों के द्वारा सामग्री और सेवा की अधिक से अधिक प्राप्ति हो और दूसरी ओर आमदनी, धन और अवसर में असमानताएँ कम हों। अगर किसी प्रोग्राम का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना होया तो उसका परिणाम यह हो सकता है कि कुछ छोटे से लोगों के हाथों में ज्यादा धन पड़ जाय और जनता अपनी गरीबी की वर्तमान दशा में ही बनी रहे और इस प्रकार उस प्रोग्राम को अधिक बड़े सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में असफलता मिले। दूसरी ओर, अगर वर्तमान धन की दुबारा बाँट ही की जाती है तो उसमें समाज के कुछ वर्गों के हितों की हानि होगी और शेष वर्गों की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं होगा। इसलिए हमारा प्रोग्राम दूसरा होना चाहिए, जिसमें कि उत्पादन बढ़ाने और असमानताएँ कम हों। प्रोग्राम के दोनों पक्ष एक दूसरे पर असर डालते हैं। यह निश्चय करना कि किम हद तक किसी एक दिशा में आगे बढ़ना, दूसरी दिशा में आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ कर सकता है, एक बड़े ही नाजुक निर्णय का सामना है। जबकि हमें आरम्भिक अवस्थाओं

1. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, (सक्षिप्त) १९५६, योजना आयोग, भारत सरकार, पृष्ठ, ६५-६६।

मे अधिक उत्पादन सम्बन्धी कोशिशों पर जोर देना होगा, क्योंकि इसके बिना किसी प्रकार की उन्नति सम्भव ही नहीं है। हमारा आयोजन आरम्भिक व्यवस्थाओं में मौजूदा सामाजिक और आर्थिक ठाँचे के अन्दर आर्थिक क्रियाशीलता को बढ़ावा देने तक ही सीमित न रहना चाहिए। हमें तो उस ढाँचे को फिर से ऐसा बनाना है जिसमें कि समाज के सभी लोगों के लिये क्रमशः रोजी-रोजगार, शिक्षा, बीमारी तथा अन्य असमर्थताओं के विरुद्ध सुरक्षा और सम्बन्धित आयदनी का पूरा-पूरा प्रवन्ध किया जा सके।¹

हमारे समाज के मूल उद्देश्य क्या है, इसका सार इसर 'समाजवादी ढंग की समाज व्यवस्था' के वाक्यांश द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मोटे तौर पर इसके माने यह है कि हमें बढ़ने का रास्ता चुनते समय सारे समाज की बात सोधेंगे किसी वर्ग या व्यक्ति के लाभ की नहीं, और विकास-पद्धति और सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धों का विधान कुछ इस तरह निर्धारित करेंगे कि न सिर्फ राष्ट्रीय आय और सम्पत्ति की विपन्नता घटती ही चली जाये, बल्कि आर्थिक उन्नति में समाज के वह वर्ग विशेष रूप से लाभान्वित हो जो अपेक्षाकृत कम सम्पन्न है। धारो और सुख और शान्ति का साम्राज्य हो और गरीब से गरीब मनुष्य को भी अपनी जिन्दगी सफल बनाने का पर्याप्त अवसर मिले।

ऐसी परिस्थितियों की स्थापना के लिए राज्य को भी अपने ऊपर भारी जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ती हैं। उद्योगों के सार्वजनिक क्षेत्र को तेजी से बढ़ाना होता है। सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में पूँजी कहाँ, कितनी और किस तरह लगे, इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी बहुत हद तक राज्य को अपनी होती है, और विकास के ऐसे काम उठाने होते हैं, जिन्हें निजी क्षेत्र या तो उठा नहीं सकता या उठाना नहीं चाहता। कुछ बड़े-बड़े नये उद्योग धंधों की, जिनके लिए आधुनिक शिल्पविधि का ज्ञान, बड़े पैमाने पर उत्पादन और साधनों के आवंटन और नियन्त्रण का एकाधिकार अपेक्षित हो, जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य को ही उठानी होगी। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ औद्योगिक कारणों से आर्थिक सत्ता और सम्पदा का संचयन एक विशेष व्यक्ति या वर्ग के हाथ में हो जाने की सम्भावना हो, आर्थिक या पूर्ण रूप से सार्वजनिक स्वामित्व और प्रवन्ध पर सार्वजनिक नियन्त्रण या हिस्से-दारी ज़रूर तैयार हो जाना चाहती है। निजी क्षेत्र को भी 'सुदृढ़-कर्म' करना होगा, लेकिन समूची योजना के दायरे में रहकर। विकासशील अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्रों को साथ-साथ उन्नति करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन स्पष्ट है, अगर आर्थिक उन्नति निश्चित गति से की जानी है और उसमें व्यापक सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना है तो सार्वजनिक

1 पहली पंच वर्षीय योजना, (भारत सरकार), जनता सस्तरण, योजना समीक्षण, पृष्ठ ७३।

क्षेत्र न सिर्फ बढ़ाना होगा बल्कि निजी क्षेत्र से ज्यादा तेजी से और ज्यादा आगे तक बढ़ाना होगा ।¹

द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं का उद्देश्य :

लोकतन्त्र और समानता के आधार पर प्रगति करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है ।

इन व्यापक दृष्टि को ध्यान में रखकर निम्न उद्देश्य प्राप्त करने के लिए द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई गई हैं —

(१) राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि करना जिससे देश के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो ,

(२) मूल और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देते हुए देश का तेजी से औद्योगीकरण ,

(३) रोजगार के अवसरों का अधिक विस्तार और ,

(४) आय और सम्पत्ति की विषमताओं का निराकरण और आर्थिक शक्ति का पहले से अधिक समान वितरण ।

ये उद्देश्य परस्पर सम्बद्ध हैं और उन्हें सन्तुलित ढंग से चल कर ही प्राप्त किया जा सकता है ।

रहन-सहन का निम्न या स्थिर स्तर बेरोजगारी और कम-रोजगारी, कुछ हद तक श्रमशून्य और अधिकतम आय का अन्तर, यह सब उस आधारभूत अल्पविश्वास के ही लक्षण हैं जो मुख्यतः संती पर आधारित अर्थव्यवस्था की विशेषता है । इस प्रकार द्रुत औद्योगीकरण और आर्थिक व्यवस्था का विविधतापूर्ण होना विकास का प्रगल्भ माप है । पर यदि हमें काफी तेजी से औद्योगीकरण करना है, तो लोहा और इस्पात, सोहेतर धातुएँ, कीयला, मीमेन्ट जैसे मूल उद्योगों और मशीन तैयार करने वाले उद्योगों का द्रुत विकास करना पड़ेगा । साधनों के विनियोग के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उनमें न केवल तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहे ।²

देश में औद्योगीकरण

हमारी योजना में औद्योगीकरण को, विशेषतः भारी और मूल उद्योगों के विकास को, उच्च प्राथमिकता दी गई है । औद्योगिक और खनिज पदार्थों के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को व्यापक बनाने की व्यवस्था की गई है । इन कार्यक्रमों को पूरा करने का मुख्य उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार पर है । इन कार्यक्रमों के लिए

1 (संक्षिप्त) द्वितीय पंचवर्षीय योजना, १९५६, योजना आयोग, भारत सरकार, पृष्ठ ११-१२

2 (संक्षिप्त) द्वितीय पंचवर्षीय योजना, १९५६, योजना आयोग, भारत सरकार, पृष्ठ ११-१२

अपार धन की आवश्यकता होगी । इसके अलावा सरकार के वर्तमान संगठन सम्बन्धी तथा प्रशासक कर्मचारी वर्ग को मजबूत किया जाना चाहिए और छीघ निर्णय करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उचित ढंग अपनाये जाने चाहिए । सम्भव है कि भारी उद्योग, तेल की खोज और कोयले के विकास कार्यक्रमों का आकार और बढ़ाना पड़े । आणविक शक्ति के विकास के साथ अन्य कार्यक्रम भी शुरू किये जायेंगे । आणविक शक्ति के विकास के लिए उत्पादन के साधनों में तेजी से वृद्धि करना और ईंधन एवं शक्ति के साधन उपलब्ध करना परमावश्यक है । दूसरी योजना के लक्ष्य प्रभावोत्पादक है, लेकिन यह याद रखना होगा कि उन्हें सिद्ध करने के लिए अपेक्षा-कृत बहुत अधिक धन और समुचित संगठन की आवश्यकता पड़ेगी ।

योजनाकाल में सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों को विकसित करके सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जायगा । दोनों क्षेत्रों को एक साथ मिल जुल कर काम करना होगा । दोनों क्षेत्र एक सम्पूर्ण व्यवस्था के अंग समझे जायेंगे क्योंकि योजना की प्रगति दोनों क्षेत्रों के समान और समुचित विकास पर निर्भर है । निजी क्षेत्र के विकास की प्रवृत्तियों पर सरकार समुचित नियमों के द्वारा अकुश रख सकती है और उसे ऐसा करना ही होगा ।¹

३—प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों का निर्धारण

(Fixation of Priorities and Targets)

नियोजन का सार सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होना है । जब कि किसी समाज के मधीन साधन (विशेषकर, भारत जैसी अविकसित आर्थिक व्यवस्था में) सीमित हैं तो नियोजनाधिकारियों के लिए प्राथमिकताओं के अनुसार चलना आवश्यक हो जाता है । सबसे आवश्यक वस्तु को पहले से तथा हर क्षेत्र में साधनों से अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए ।

किसी योजना-विशेष में प्राथमिकताओं के सिद्धान्त को इस प्रकार अपनाया जाता है कि अर्थव्यवस्था की परमावश्यकताओं को पहले हाथ में लिया जाता है । लेकिन कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के दीर्घकालीन परिवर्तनों की वाछनीयता (Desirability) पर भी पहले विचार करना होता है । विकास के कार्य में कार्यक्रम इस प्रकार का होता है कि सबसे अधिक आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति का प्रयास सबसे पहले होता है और इसी प्रकार अन्य आवश्यकताओं की प्राप्ति का प्रयास उनकी तीव्रता के अनुसार होता है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के विषय में उल्लेख किया गया था कि 'तात्कालिक पाँच वर्षों में सबसे ऊँची प्राथमिकता हमें खेतीबाड़ी को, जिसके अतर्गत विचार्य और विजली भी आ जाते हैं, देनी होगी । हम जिन योजनाओं को हाथ

1 (संज्ञिप्ति द्वितीय पंचवर्षीय योजना, १९५६, योजना आयोग, भारत सरकार, पृष्ठ—१३)

मे ले चुके हैं उनकी पूर्ति पर जोर देना कुछ हद तक इसी बात की ओर संकेत करता है। लेकिन इसके अलावा भी यह जाहिर है कि अनाज और उद्योगों के लिए जरूरी कच्चे माल का उत्पादन काफी बढ़ाए बिना अन्य क्षेत्रों में विकास की गति को तेज रखना अमभव होगा। और अधिक विकास के लिए खाद्य और कच्चे माल का होना बहुत जरूरी है, इसलिए इन वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भरता और बहुतायत की दशाओं का निर्माण होना बुनियादी बात है।¹

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगीकरण को सबसे अधिक प्राथमिकता प्रदान की गई थी। इसमें इसके साथ यह भी उल्लेख किया गया था कि "...हमें सिर्फ यह नहीं करना है कि लोगों के रहन सहन के स्तर का अध्ययन करें। हमारी जिम्मेदारी यह है कि देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी शक्ति, ऐसी गति पैदा करें कि वह आप ही आप उत्तरोत्तर उन्नति करती जाय, देश समृद्ध होता जाय और बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आगे बढ़े। लोगों की आर्थिक अवस्था सुधारना ही हमारा साध्य नहीं, मूलन वह तो लोगों का जीवन भर-पूरा और खुशहाल बनाने का साधन मात्र है।"²

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और औद्योगीकरण दोनों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। कृषि के क्षेत्र में गहरी खेती पद्धति को अपनाकर देश को खाद्य के विषय में आत्मनिर्भर बना देना, देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना करना—विशेषतौर पर भारी, इस्पात और 'उत्पादक उद्योगों' की स्थापना पर अधिक बल दिया गया है। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने पर भी बल दिया गया है।

आर्थिक योजना के निर्माण में लक्ष्यों का निर्धारण करना भी होता है। उचित लक्ष्यों का निर्धारण किए बिना हर क्षेत्र में आर्थिक उन्नति सम्भव नहीं हो सकती और न नियोजनाधिकारी विभिन्न आर्थिक प्रयासों के विकास पर घबड़ी तरह से दृष्टिपात ही कर सकते हैं। इसके लिए उत्पत्ति के लक्ष्यों को सभी क्षेत्रों में निर्धारित करना होता है। लक्ष्य-निर्धारण का एक दूसरा लाभ यह है कि उत्पादक तथा विनियोगी के समक्ष हर समय एक आदर्श उपस्थित रहता है। नियोजन को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उद्देश्यों, प्राथमिकताओं, सुविधाओं एवं उत्पादन कार्य के लिए लक्ष्य पहले से ही निर्धारित हो।

४— योजना के लिए वित्त-व्यवस्था

(Financing the Plan)

वित्त व्यवस्था आर्थिक नियोजन की एक पूर्व-प्रावश्यकता है। योजना का आकार तथा स्वरूप बहुत सीमा तक धन की प्राप्ति—ग्रान्तरिक तथा बाह्य-पर निर्भर

1. पहली पंचवर्षीय योजना, (जनता संस्करण), पृष्ठ—१७

2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, (संक्षिप्त), पृष्ठ, १०

होती है। बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि धन कम है तो योजना में बड़े कार्यों का होना सम्भव नहीं हो पाएगा। आर्थिक विकास के लिए सभी पहलुओं जैसे, कृषि, विद्युतशक्ति एवं सिंचाई शक्ति, प्राकृतिक साधनों का उपयोग, उद्योग, यातायात एवं सवादवाहन के साधन इत्यादि के विषय में योजनाओं का होना आवश्यक है। ये सभी धन की प्राप्ति पर निर्भर है। इसलिए आर्थिक नियोजन में धन की प्राप्ति की बड़ी महत्ता है।

योजना को सफल बनाने के लिये वित्त और विदेशी विनिमय के विषय में पहले से ही पूर्ण जानकारी विधायकों के लिए बहुत आवश्यक होती है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजना (रूपरेखा) के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायगा कि योजना-आयोग ने इन पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने से पहले वित्त और विदेशी विनिमय के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयोग ने उल्लेख किया है, “योजना के लिये साधन सग्रह की समस्या पर विचार सार्वजनिक और निजी दोनों विभागों की दृष्टि से करना उचित है क्योंकि एकत्रित साधनों का उपभोग यह दोनों विभाग करेंगे। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वदेश के वित्तीय साधनों का सग्रह करने के साथ-साथ विदेशी विनिमय की उपेक्षा न की जाय, दोनों के पर्याप्त होने पर ही योजना सफल हो सकेगी। इस समस्या का मूल रूप यह है कि स्वदेश में ही आवश्यक साधन एकत्रित किये जा सकते हैं या नहीं, और यदि किये जा सकते हैं तो कैसे? इसमें सफलता तब हो सकती है जब कि यह ध्यान रखा जाय कि वह एक निर्धारित सोमा से आगे न बढ़ने पाये और अपने पास वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक ढाँचे के भीतर रहते हुए जिन साधनों, अथवा तकनीकों का प्रयोग किया जाय वे इष्ट प्रयोजन के लिये उपयुक्त हों। इसके साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो देश औद्योगिक उन्नति के मार्ग पर पग बढाने लगता है उसे आरम्भ में आवश्यक यन्त्रादि सामग्री विदेशों से मँगानी ही पड़ती है और इसी कारण उसे विदेशी विनिमय की समस्या का सामना करना, और उसे विशेष प्रयत्नों से सुव्यवस्था पड़ता है।”¹

५.—सन्तुलन की समानता

(Maintaining Equality Of Balance)

आर्थिक नियोजन विभिन्न-भिन्न देशों में विभिन्न-भिन्न उद्देश्यों से लागू किया जाता है। आर्थिक विकास के अनुसार ससार के देशों को आसानी से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—उन्नत देश एवं पिछड़े देश। औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नत देशों में नियोजन लागू करने का मुख्य उद्देश्य “आर्थिक वैभव प्राप्त करने तथा उसको बनाए रखना होता है।” लेकिन पिछड़े देशों में, जोकि आर्थिक

अवनति तथा दारिद्र्य की विषमता से पीड़ित हैं, आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य 'रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना, प्रति-व्यक्ति प्रति-वर्ष आय को बढ़ाना तथा हर क्षेत्र में आर्थिक उत्थान प्राप्त करना होता है।' हमारा देश निर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से अनुन्नत होने के कारण नियोजन द्वारा आर्थिक विस्तार चाहता है।

आर्थिक विकास किस गति से होना चाहिये ? यदि हम अति-तीव्रता (Too rapid) वाली आर्थिक उत्थान की पद्धति को अपनायें, तो हमें पूँजी-प्रमुख उत्पत्ति के तरीके अपनाने पड़ेगे तथा आर्थिक उन्नति के तीव्र लक्ष्य को बनाये रखने की आवश्यकता होगी। इस प्रथा में यह कठिनाइयाँ हैं - (अ) पूँजी की कमी, (ब) विशिष्ट शिक्षा प्राप्त कुशल कर्मचारियों की कमी, (स) मशीनों द्वारा उत्पादन के कारण बेरोजगार में वृद्धि। क्या हम इन कठिनाइयों को सरलता से दूर कर सकेंगे ? प्रत्येक व्यक्ति हमारी पूँजी की कमी, कुशल एवं विशिष्ट-शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों की कमी, साधनों की कमी तथा देश में बढ़ते हुए बेरोजगार की स्थिति से परिचित हैं। इसलिये नियोजनाधिकारियों के लिए इस प्रकार के तीव्र गति की आर्थिक उन्नति के आदर्श को मानना केवल अनुचित ही न होगा बल्कि अवांछनीय भी होगा।

दूसरा उपाय जो दोष रहता है वह है 'मन्द आर्थिक उन्नति' (Slow Economic Growth)। जनसंख्या की वृद्धि की दर को जानते हुए यह पद्धति हमारे देश के लिए अवांछनीय है। यदि आर्थिक उन्नति की गति बहुत धीमी है तो वह देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की तीव्र गति से पराजित हो जायगी। अर्थात् बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह पद्धति पूर्ण साधन नहीं जुटा पायेगी। इसलिए जहाँ तक आर्थिक उन्नति की गति का सम्बन्ध है, न यह अधिक तीव्र होनी चाहिए—जिससे हम उसके साथ-साथ कदम न बढ़ा सकें, और न अधिक मन्द होनी चाहिए, जिसमें हम तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा न कर सकें। आर्थिक विकास औसत गति से होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, हर क्षेत्र के आर्थिक उत्थान एवं नियोजन समय के दृष्टिकोण से सन्तुलित तथा "आर्थिक उत्थान तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के नियन्त्रण में" समतुलित होनी चाहिये।

दूसरा सन्तुलन जो नियोजनाधिकारियों को ध्यान में रखना है वह यह है कि उत्पत्ति के थम-प्रमुख सिद्धान्त में अधिक रोजगार उत्पन्न करने का बहुत बड़ा गुण है। पूँजी-प्रमुख सिद्धान्त में कम कीमत पर बड़ी मात्रा में उत्पादन का गुण है। अपने-अपने क्षेत्रों में दोनों ही लाभदायक हैं। हमारी दृष्टि से (अधिक रोजगार के अवसरों के साथ आर्थिक उन्नति) थम-प्रमुख सिद्धान्त (Labour intensive methods) सबसे अच्छा है। इस प्रणाली का दोष यह है कि यह विनियोग और उत्पादन में वह अनुपात कमी नहीं ला पाता जो कि पूँजी-प्रमुख

उत्पत्ति में सम्भव होता है। इस पर प्रो० डोमर (Domar), हैरोड (Harrod), रोबिन्सन (Robinson) आदि के भिन्न-भिन्न मत हैं।¹

एक अन्य समानता (Equity) जो कि योजना की रूपरेखा बनाते समय योजनाधिकारियों को अपनानी चाहिए,—है पूँजी के संचय (Capital accumulation) एवं आर्थिक उन्नति में सन्तुलन। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस समस्या का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से वर्णन किया है। कुछ विद्वानों की राय है कि आर्थिक उन्नति के लिए (तीव्र हो या धीमी) 'तरल पूँजी' (Liquid Capital) अधिक आवश्यक है तथा विस्तृत रूप से पूँजी के संचय की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मत के समर्थन में वे कहते हैं, "यदि पूँजी की अधिकता है, तो वह धर्म की पूर्ति से अधिक हो सकती है और इस परिस्थिति में विनियोग को पूँजी के संचय से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। क्योंकि धर्मिकों की कमी के कारण उद्योग स्थापित नहीं हो पायेंगे।" यह केवल औद्योगिक तथा कम जनसंख्या वाले देशों में ही सत्य हो सकता है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि देश में जितना हो सके उतना पूँजी का संचय होना चाहिए जिससे अधिक उत्पादन हो सके, रोजगार मिल सके और द्रुत आर्थिक उन्नति सम्भव हो सके। हमारे नियोजनाधिकारियों ने हमारे नियोजनों में, इसी सिद्धान्त पर अधिक बल दिया है। इस पर विभिन्न विद्वानों का अलग-अलग मत है।²

"अल्पधिक पूँजी के संचय" के समर्थकों का यह कहना है कि अविकसित देशों में द्रुत एवं सन्तुलित आर्थिक विकास और सम्पत्ति-आधिक्य प्राप्त करने के लिये यह पद्धति कार्यान्वित नहीं हो सकती। अपने दृष्टिकोण के समर्थन में वह यह कहते हैं कि क्योंकि अविकसित देशों में 'क्रियाशील पूँजी' (Working Capital) की कमी होती है इसलिए इन देशों में पूँजी का संचय अधिक मात्रा में सम्भव नहीं होता है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने भारतीय योजनाओं की तीव्र आलोचना की है।

उनका दृष्टिकोण सैद्धान्तिक रूप से या अन्य अविकसित देशों के लिए ठीक हो सकता है—परन्तु भारत के लिए नहीं। इसका कारण यह है कि भारत प्राकृतिक सम्पत्ति और अन्य साधनों में धनी है। भारत के आर्थिक विकास के लिए केवल इस बात की आवश्यकता है कि उसकी आर्थिक सम्पत्ति का सन्तुलित रूप से सदुपयोग हो।

हमारे नियोजन के विधायकों ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि नियोजनकाल में देश में पर्याप्त मात्रा में पूँजी का संचय हो सके ताकि आर्थिक विकास का कार्य बिना किसी रुकावट के एवं द्रुति गति से अग्रसर हो सके। इस विषय में जो प्रश्न सामने उपस्थित होता है वह यह है कि क्या सार्वजनिक कोष के

1. Please see Ch 15, (Theory of Growth).

2. Please see Chapter 15

लिए एव विनियोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक धन निजी बचत से प्राप्त हो सकेगा ? इस प्रश्न का उत्तर लोगों के अनेक प्रकार के निजी निश्चयों पर निर्भर करता है । उनमें से एक यह भी है कि जनता कितनी मात्रा में बचत करती है या कर सकती है ? यदि इस प्रकार सार्वजनिक बचत और निजी बचत अधिक मात्रा में हो सके, तो पूँजी के निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी । वास्तव में इन नियोजनों के द्वारा सरकार जनता की धाँय को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिससे वे अधिक मात्रा में बचत कर सकें, जो आगे चलकर पूँजी का रूप ग्रहण कर पाएँ ।

घाटे के बजट द्वारा भी सरकार देश स्थित पूँजी की कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है । अविकसित देशों के लिए आर्थिक उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त करने का यह एक सरल उपाय है । इस घाटे के बजट द्वारा मौजूदा कठिनाइयाँ सरलता से दूर की जा सकती हैं परन्तु इस ओर सतर्क दृष्टि होनी चाहिए कि घाटे के बजट के कारण देश में अत्यधिक मुद्रा-प्रसार न हो जाय ।

कर-नीति में सन्तुलित रूप से सुधार करने पर भी सरकार देश में एक ऐसी आदर्श स्थिति उत्पन्न कर सकती है जिससे जनता अधिक मात्रा में बचत कर सके और उनका प्रयोग विनियोग कार्य में सरलता से हो सके—परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रत्येक देश में नियोजन के प्रारम्भिक काल में कर की दर अधिक होती है ।

इनके अतिरिक्त नियोजक का लक्ष्य यह भी होता है कि प्राकृतिक सम्पत्ति का शोषण सन्तुलित रूप से एव आवश्यकतानुसार हो । उद्योग धंधों की उन्नति हो, अधिक रोजगार के अवसर साधारण जनता को प्राप्त हो सकें । व्यापार—आन्तरिक एव अन्तर्राष्ट्रीय—में वृद्धि हो और इस प्रकार जनता की प्रति-व्यक्ति प्रतिवर्ष धाँय प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष खर्च से अधिक हो ताकि इन दोनों का अन्तर बचत का रूप ग्रहण कर सके ।

देश के औद्योगिक, वित्तीय एव वर सम्बन्धी नीति और वैश्विक-प्रथा सुव्यवस्थित हो जिससे सभी व्यक्तियों को बचत करने में एव बचत की पूँजी का रूप प्रदान करने में कोई कठिनाई न रहे ।

सोचिएत तब में जब नियोजन व्यवस्था प्रारम्भ की गई थी तो उसकी आर्थिक स्थिति हमारे देश से भी भिरी हुई थी । उसने पूँजी निर्माण के लिए उप-युक्त सभी उपाय अपनाये थे—लेकिन, जैसे-जैसे उनके देश में आर्थिक उन्नति होती गई और बचत के एव पूँजी निर्माण के प्राकृतिक सुयोग प्राप्त होते गये, वैसे ही वैसे इन प्रणालियों में ढील प्रदान की जाती रही । यह आशा की जाती है कि प्रारम्भिक कठिनाइयों के पश्चात् भारत में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जायगी और 'पूँजी निर्माण की समस्या' फिर 'समस्या' नहीं रह जायगी ।

नियोजनकर्ता कौन हो ?

(Who is to plan ?)

१—विषय-प्रवेश

(Introductory)

कुछ दशब्दी पूर्व अर्थशास्त्रियों के सामने प्रायः यह प्रश्न आता था कि नियोजन होना चाहिए या नहीं ? हम की नियोजन सम्बन्धी सफलताओं ने इस प्रश्न का उत्तर सदा के लिये दे दिया है—नियोजन आवश्यक है। इस सिद्धान्त के निश्चय हो जाने के पश्चात् एक अन्य प्रश्न हम लोगों के सामने आता है—नियोजन किसके द्वारा हो, अर्थात्, नियोजनकर्ता कौन हो ? इस अध्याय में हम इसी प्रश्न का हल ढूँढने का प्रयास करेंगे।

किसी भी देश में आर्थिक विकास का कार्य बड़ी मात्रा की या छोटी मात्रा की उत्पत्ति द्वारा सम्भव हो सकता है। प्रायः आर्थिक विकास के लिए छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के उद्योगों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार देश के उद्योग धन्य निजी क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में हो सकते हैं—वास्तव में, समाजवादी राष्ट्रों को छोड़ कर अन्य राष्ट्रों में प्रायः निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र होते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि विभिन्न देशों में प्रतिरक्षा, प्रमुख (Key) एवं भारी उद्योग साधारणतः सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं और बाकी निजी क्षेत्र में। भारत में भी ऐसी ही स्थिति विद्यमान है।

देश का आर्थिक स्तर कैंसा भी हो, उत्पत्ति की प्रणाली किसी भी प्रकार की हो, देश के उद्योग धन्यो का स्वामित्व और संचालन का भार किमी पर भी हो, देश के बहुमुखी आर्थिक विकास के लिए एक सुव्यवस्थित, सुपरिकल्पित और सन्तुलित नियोजन की आवश्यकता होती है। आर्थिक नियोजन का मध्य हमारे देशवासियों का आर्थिक उत्थान एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना होता है। नियोजन व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय हो सकता है।

अविकसित देशों के लिए आर्थिक उन्नति प्राप्त करना या देश को समृद्ध-शाली बनाने का एकमात्र साधन आर्थिक नियोजन ही है। नियोजन द्वारा ही देश के प्राकृतिक साधनों का सन्तुलित शोषण और व्यवहार हो पाता है, उद्योग धन्यो की

स्थापना और विस्तार सम्भव होता है, रोजगार की सुविधायें उत्पन्न की जा सकती हैं और देश की उत्पादन शक्तियों को समेट कर आर्थिक विकास के कार्य में जुटाया जा सकता है। नियोजन का यह कार्य व्यक्ति द्वारा, समाज द्वारा, कुछ पूँजीपतियों द्वारा या राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। जो भी नियोजन का कार्य इस रूप में करे, उसी को नियोजनकर्ता कहा जायगा। विभिन्न देशों में भी नियोजनकर्ता अलग अलग होते हैं, जैसे, पूँजीवादी देशों में पूँजीपति और साहसी एव समाजवादी या साम्यवादी देशों में राष्ट्र। कुछ देशों में इस कार्य में राष्ट्र और साहसी दोनों ही शामिल होते हैं। इसके अनुसार राष्ट्र नियोजन बनाता है और साहसी उसके लिए निर्दिष्ट कार्य-भार संभालते हैं।

२—व्यक्तिगत नियोजन के पक्ष में (Case for Private Planning)

“केन्द्रीय नियोजन व्यक्तिगत अधिकार को छीन कर मनुष्य को ‘शून्य’ बना देता है एव आर्थिक निर्णयों को बिना सोचे समझे ग्रहण करता है—आर्थिक विकास को उत्साहित नहीं करता एव केवल कुछ व्यक्तियों की इच्छानुसार ही कार्य होता है—जो कि अपनी स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से समस्त शक्तियों को अपने हाथ में समेट लेते हैं। यही कारण है कि केन्द्रीय नियोजन में आर्थिक समता एव न्याय दृष्टिगोचर नहीं होते।” “जो केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के निर्माण को मान्यता प्रदान करते हैं अथवा उसके निर्माण कराने के लिए कष्ट उठाते हैं, उन्हें कठिनाई तथा व्यर्थ प्रतीक्षा के सिवाय और कुछ नहीं मिल सकता।”

केन्द्रीय नियोजन के समर्थकों पर व्यक्तिगत योजना के समर्थक और भी कड़े शब्दों में धोखारे करते हैं। उनका कहना है, “आर्थिक और राजनैतिक स्वतन्त्रता भिन्न भिन्न नहीं है। कानून द्वारा ही आर्थिक स्वतन्त्रता को स्थापित किया जाता है, बनाये रखा जाता है अथवा उसको शक्ति प्रदान की जाती है।”¹ या “पूँजीवादी साहस को स्वाभाविक रूप से आर्थिक उन्नति की प्राप्ति में इतनी अधिक सफलता मिली है कि इसमें कुछ और मुधार करने की श्रेय नहीं है।”² इस सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि स्वतन्त्र साहस तथा केन्द्रीय नियोजन दोनों ही में अपने-अपने कुछ गुण तथा अकृण विद्यमान हैं।

कुछ मौलिक निश्चयान्तों (Basic decisions) का निर्णय प्रत्येक समाज को करना पड़ता है—जैसे, देश में अधिकतम माना में किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होना चाहिए, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार की जाय और उनके वितरण का स्वरूप क्या हो? ‘स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था’ में इसका निर्णय विभिन्न साहसियों द्वारा

1. *American capitalism*—Massimo Salvadori, p 11.

2. *Ordeal by Planning*—J. Jewkes, 1948, Ch. II, pp. 18-19.

स्वतन्त्र रूप से किया जाता है। स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत इनका निर्णय कीमत, माँग और लाभ को सामने रख कर किया जाता है।

प्रत्येक साहसी अपने उद्योग का विस्तार एवं अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नियोजन करता है। इस कार्य में वह निमित्त वस्तु की माँग, उत्पत्ति की मात्रा, वस्तु के गुण, श्रमिकों की मजदूरी की दर, कच्ची सामग्री की दर एवं बदलती हुई उत्पादन प्रणाली को अपने सामने रखता है। इस प्रकार के नियोजन-कार्य में उसका पिछले वर्षों का अनुभव और उद्योग सम्बन्धी ज्ञान अत्यधिक सहायक होता है। बड़ी मात्रा के विनियोग से पहले प्रत्येक साहसी के लिए एक सन्तुलित नियोजन का निर्माण आवश्यक होता है।

पूँजीवादी देशों में (जैसे, अमेरिका) साहसी विभिन्न उद्योगों में उस समय तक विनियोग करते रहते हैं, जब तक कि उनसे लाभ प्राप्त होता रहता है। प्रतिस्पर्द्धा द्वारा इन देशों में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की श्रेष्ठता तथा कीमत का निर्धारण होता है। स्वतन्त्र स्पर्द्धा में उपभोक्ता-वर्ग कीमत को प्रभावित कर सकते हैं—जो केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सम्भव नहीं होना।

पूँजीवादी राष्ट्र विभिन्न साहसियों के नियोजनों को कर-नीति, कर्जों की प्रथा और साख व्यवस्था द्वारा एक सूत्र में सश्रम कर सकते हैं। समय समय पर इन राष्ट्रों द्वारा प्रमुख (Key), भारी (Heavy) और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सलग्न बड़े उद्योगों के विषय में जानकारी के उद्देश्य से कमीशन (Commission) नियुक्त करते हैं जो राज्य को इन सस्याओं के विषय में रिपोर्ट (Report) देते हैं और आवश्यक सुधार के लिए सुझाव भी देते हैं। प्रायः केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की सुविधायें प्राप्त नहीं हो पाती हैं।

प्रावश्मकता पड़ने पर पूँजीवादी देश साहसियों को विभिन्न प्रकार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करते हैं ताकि विभिन्न उद्योग द्रुत गति से उन्नति कर सकें और इसके द्वारा देश का आर्थिक विकास भी द्रुत गति से हो सके। इन सहायताओं में कम व्याज की दर पर ऋण की व्यवस्था, आयात निर्यात सम्बन्धी नीति में परिवर्तन, व्यापार-चक्र का दमन, आर्थिक क्षेत्र में अत्यन्त परिवर्तनशीलता को रोकना, बेईमानी करने वाले उद्योगों को बन्द कर देना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना एवं आवश्यक उद्योगों को संरक्षण देना प्रमुख हैं। केन्द्रीय नियोजित देशों में प्रायः राष्ट्र की ओर से आर्थिक विकास में इतने क्रियाशील रूप से कार्य नहीं किया जाता।

समाजवादी और साम्यवादियों का यह कहना, “पूँजीवादी देशों की आर्थिक विषमता का एकमात्र कारण नियोजन का अभाव है” सर्वथा भ्रमात्मक है। इसका कारण यह है कि पूँजीवादी देशों में भी किसी उद्योग या व्यापार की स्थापना से पूर्व साहसी द्वारा नियोजन होता है। पूँजीवादी देशों और समाजवादी या

साम्यवादी देशों के आर्थिक नियोजन में यह अन्तर होता है कि पूर्वोक्त कार्य में यह कार्य व्यक्तिगत साहसी से होता है और केन्द्रीय नियोजित देशों में नियोजन का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है ।

केन्द्रीय नियोजन के समर्थकों का यह कहना कि “पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत साहसी का एकमात्र लक्ष्य लाभ कमाना होता है” अतःप्रतिभूत सत्य नहीं है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि साहसी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है, परन्तु यह कहना कि केवल यही उद्देश्य होता है, गलत है । लाभ कमाने के अतिरिक्त भी पूँजी को प्रयोग में लाना, देश के उद्योग-धंधों को विकसित करना, देश से बेरोजगारी दूर करना, परीक्षण करना (Experimentation) आदि भी उद्देश्य होते हैं ।

विभिन्न देशों का सविधान भी अपने नागरिकों को स्वतन्त्र व्यापार का अधिकार प्रदान करता है । केन्द्रीय-नियोजन पद्धति को अपनाने का अर्थ इस अधिकार को छीनना होता है—जो अवांछनीय है । इस क्षेत्र में पूँजीवादी देश गर्व से दावा कर सकता है कि वह नागरिकों को सविधान के अनुसार ही व्यापार और आर्थिक प्रयत्नों में स्वतन्त्रता प्रदान कर रहा है । केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में उस गुण का अभाव होता है ।

समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थकों का यह कहना, “पूँजीवादी देशों में बड़े उत्पादक एकाधिकार की स्थापना करके वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि कर देते हैं—और इस प्रकार नागरिकों का शोषण करते हैं” भी पूर्णतया सत्य नहीं है । पूँजीवादी देशों में प्रतिस्पर्धा के आधार पर ही वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निर्धारित होती हैं । प्रत्येक उद्योग में एकाधिकार की स्थापना भी सम्भव नहीं होती । इसके विपरीत, केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा न होने के कारण प्रायः वस्तुएँ या सेवाएँ अधिक मूल्य पर बिकती हैं ।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत निजी सहस्रियों द्वारा व्यवसाय और उद्योगों की स्थापना और विस्तार में और भी बहुत से लाभ केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की तुलना में प्राप्त हैं । इनमें से सबसे अधिक उल्लेखनीय शायद यह है कि साहसी व्यक्तिगत अनुभव, उद्यम, कठोर परिश्रम एवं एकाग्र रूप से व्यवसाय का संचालन करता है, जिसके फलस्वरूप व्यावसायिक संगठन राज्य-संगठित व्यवसायों से कहीं अच्छा होता है । संगठन की कुशलता पर ही साहसी का भविष्य निर्भर होता है ।

३—केन्द्रीय आर्थिक नियोजन की आवश्यकता तथा महत्त्व

(Need and Significance of Centralised Economic Planning)

केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है, “राष्ट्र के समस्त प्राकृतिक साधनों का केन्द्रीय नियोजन । संक्षेप में, केन्द्रीय नियोजन और स्वतन्त्र व्यापार

प्रणाली में क्षेत्र (scope) सम्बन्धी अन्तर होता है—यह अन्तर भौतिक मिद्धान्त के अतिरिक्त मात्रा (degree) के रूप में होता है। इस प्रणाली के लिए न तो यह आवश्यक होता है कि वह स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली को समाप्त कर दे और न यह होता है कि राष्ट्र के समस्त उत्पत्ति और वितरण के अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथों में हों। फिर भी, इस प्रथा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि साहसी निजी लाभ के उद्देश्य से जनता का शोषण करे। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा विविध प्रकार के नियन्त्रण एवं पाबन्दी साहसियों पर लगाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में स्वतन्त्र व्यापार के सभी गुण विद्यमान होते हैं जबकि उनके सभी दोष केन्द्रीय नियोजन द्वारा दूर कर दिए जाते हैं।¹

पूँजीवादी प्रथा में व्यापारी और उद्योगपति किसी भी प्रकार के नियन्त्रण और पाबन्दी के बिना कार्य करते हैं। इस प्रकार वे अपने निजी लाभ के लिए दरिद्र वर्ग का शोषण करते हैं, जिससे समस्त समाज को हानि होती है। पूँजीवाद से उत्पन्न इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही राज्य को नियन्त्रण करना पड़ता है—और कभी-कभी राज्य को व्यापार या उद्योग के क्षेत्र में भी अवतीर्ण होना पड़ता है। पूँजीपतियों द्वारा मजदूरों को कम मजदूरी देना एवं उनका शोषण किया जाना उतना ही पुराना है जितना कि पूँजीवाद, यही कारण था कि बहुत काल पूर्व—१५ वीं शताब्दी में—यह कहा गया था, “दरिद्र वर्ग परिश्रम करता है और धनी बग़ उस परिश्रम का फल प्राप्त करता है।”²

पूँजीवाद के अन्तर्गत रोजगार की अनिश्चितता एवं कार्य की दुर्दशा एक प्रधान कारण है जिसके लिए संसार के विभिन्न राष्ट्रीय के निवासी केन्द्रीय नियोजन की स्थापना चाहते हैं। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में ‘अति-उत्पादन’ एवं ‘कम उत्पादन’ का भय सदा बना रहता है जिससे देश की आर्थिक स्थिति में स्थिरता नहीं आ पाती एवं आर्थिक मंदी और तेजी का भय बना रहता है। ‘व्यवसाय-चक्र’ के कारण रोजगार की स्थिति में भी समता नहीं आ पाती। केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में यह कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं—जिनके कारण प्रायः सभी देशों में अब केन्द्रीय नियोजन की प्राथमिकता दी जा रही है।

पूँजीवादी प्रथा में प्रतिस्पर्धा का अस्तित्व होता है, जो प्रायः ‘अनाधिक प्रतिस्पर्धा’ का रूप ग्रहण करती है। इस ‘अनाधिक प्रतिस्पर्धा’ के कारण दुर्बल उत्पादक शक्तिशाली उत्पादकों के सामने नहीं ठहर पाते एवं बड़ी मात्रा के उत्पादक एकाधिकार की स्थापना कर लेते हैं। इसके पश्चात् वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य

1 *A Planned Economy or Free Enterprise*—E. Lipson, (1946), Appendix I, Page—314

2 *On England's Commercial Policy, (15th century)*

बढ़ा देते हैं तथा उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। कभी-कभी इस प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप देश में विषमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कच्ची सामग्री एवं निर्मित वस्तुएँ बढ़ाई होती हैं एवं देश का आर्थिक उत्पादन नियन्त्रण के अभाव में असम्भव सा प्रतीत होता है। केन्द्रीय नियोजन की स्थिति में यह सब कठिनाइयाँ प्रायः सामने नहीं आती—इसीलिए केन्द्रीय नियोजन पर बल दिया जाता है।

उद्योगों का एकीकरण एवं सम्मिश्रण (Combination) ऐसे तत्व हैं जिन्हें उपेक्षा राज्य द्वारा नहीं की जा सकती। सम्मिश्रण चाहे किसी भी प्रकार का हो—इसका उद्देश्य एक ही होता है, छोटे उद्योगों को समाप्त करके 'प्रायः एकाधिकार' की स्थापना करना जिससे वह उपभोक्ताओं का अधिकतम शोषण कर सके। इस परिस्थिति में राज्य निष्क्रिय नहीं रह सकता, उसकी क्रियाशील रूप में जनता और समाज के हित से इन औद्योगिक सम्मिश्रणों पर नियन्त्रण करना आवश्यक हो जाता है।

पूँजीवाद के अन्तर्गत नियोजन का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि इसमें विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा बनाये गये सैकड़ों और हजारों 'नियोजन' होते हैं। इनके प्रकार, प्रकार, क्षेत्र, स्वभाव, उद्देश्य, लक्ष्य, प्राथमिकता आदि सभी भिन्न भिन्न होते हैं—और प्रायः एक दूसरे के प्रतिगामी, इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत नियोजित रूप से अधिक उन्नति सम्भव नहीं हो पाती है। केन्द्रीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था में यह सभी अवगुण स्वतः ही लुप्त हो जाते हैं।

सोवियत संघ और चीन में अल्पकाल में ही जो द्रुत आर्थिक विकास हुआ है उसका केवल एक ही कारण है—समाज के हित को सामने रखकर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोजन किया जाना। केन्द्रीय नियोजन का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि उसके द्वारा राष्ट्र का आर्थिक विकास हो, राष्ट्र के समस्त नागरिकों की प्रति व्यक्ति ग्रामदानी में वृद्धि हो और इस प्रकार नागरिकों का जीवन स्तर ऊँचा हो जाय। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार एक सन्तुलित, सुव्यवस्थित, सुवर्धित एवं विशाल नियोजन तैयार करता है। इस नियोजन की सफलता पर राष्ट्र की सफलता, नागरिकों का जीवन स्तर, उनकी सुख-सुविधा एवं मावी जीवन निर्भर करता है। यह सभी बातें पूँजीवाद की प्रथा में सम्भव नहीं होती।

एम० जी० स्ट्रुमिलिन (S. G. Strumilin) ने ठीक ही कहा है, "पूँजीवाद की जो कुछ भी सफलतापदक हैं उनको अगर पलट कर देखा जाय तो उन पर 'औद्योगिक विषमता' लिखा पाया जायगा। (इसका अर्थ यह है कि स्वतन्त्र-व्यापार द्वारा आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है।) ... क्या यह सच नहीं है कि पूँजीवाद के पुजारी अपनी स्वार्थ-मिद्धि के लालच में 'प्रति उत्पादन' करके आर्थिक वृद्धि

एव मदी को जन्म नहीं देते ?.....जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं उन्हें आर्थिक विपमता के लिए सदा तैयार रहना चाहिए.....।'¹

प्रो० कीन्स (Prof. Keynes) का कथन, जो उन्होंने पूँजीवाद के विषय में कहा है, अलङ्घनीय है। उनके अनुसार, "आर्थिक मदी एव आर्थिक विपमता अनियमित अर्थव्यवस्था का परिणाम है।" सन्तुलित उत्पादन एव न्यायपूर्ण वितरण केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में ही सम्भव हो सकता है, क्योंकि केन्द्रीय नियोजन में ही राष्ट्र के समस्त साधनों को शामिल किया जाता है एव राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के आर्थिक उत्थान का आदर्श रखा जाता है। इसी के आधार पर केन्द्रीय नियोजन का निर्माण होता है, प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं। यही कारण है कि केन्द्रीय नियोजन में असन्तुलन की कोई सम्भावना नहीं होती।

उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त और भी बहुत से कारण हैं जिनके लिए केन्द्रीय नियोजन नागरिकों के लिए अधिक उपयुक्त है। केन्द्रीय नियोजन के अन्तर्गत ही आयात-निर्यात नीति का सन्तुलित व्यवहार सम्भव होता है। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भी केन्द्रीय हस्तक्षेप या कार्यवाही अधिक वाञ्छनीय है। उद्योगों की स्थापना और विकास का कार्य जब केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है तो उसमें 'मितव्ययिता' (Economy) का होना अधिक सम्भव होता है।

राष्ट्र को ही अपने समस्त नागरिकों की आर्थिक दशा एव आवश्यकताओं का अधिक ज्ञान हो सकता है। इसी प्रकार, देश में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक साधनों, शक्ति के साधनों, आदि का ज्ञान भी राष्ट्र को ही अधिक होता है। द्रव्य और वित्त सम्बन्धी आवश्यकताएँ, उद्योग और व्यापार सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा अन्य सभी प्रकार की आवश्यकताओं का ज्ञान भी सरकार को अधिक होना है। राज्य सरकार द्वारा नियोजन के निर्माण में यह सभी बातें सम्मुख रखी जाती हैं जिससे केन्द्रीय नियोजन केवल एक विशाल नियोजन ही न हो बल्कि वास्तविक और आदर्श भी हो। राज्य ही समस्त राष्ट्र की भलाई चाहता है इसलिए राज्य द्वारा जिस नियोजन का निर्माण होता है वह राष्ट्र के समस्त नागरिकों की भलाई के लिए होता है।

केन्द्रीय नियोजन की सफलता राष्ट्र के नागरिकों पर निर्भर होती है। राष्ट्र के समस्त नागरिक यदि सरकार को विभिन्न रूप से सहयोग प्रदान न करें तो नियोजन कभी भी सफल नहीं हो सकता। केन्द्रीय नियोजन का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक का आर्थिक विकास करना होता है। इसीलिए देश की जनता, साधारणतया, नियोजन को सफल बनाने में प्रयत्नशील होती है। नियोजन की सफलता से उसको लाभ होता है और नियोजन की असफलता से उसे हानि।

साधारण जनता की तरह थमिक भी केन्द्रीय योजना को सफल बनाने में भरसक प्रयास करता है क्योंकि वह केवल एक थमिक ही नहीं होता बल्कि एक उपभोक्ता, एक नागरिक और नियोजित क्षेत्र का एक सदस्य भी। केन्द्रीय

नियोजन में व्यक्तिगत लाभ का प्रश्न नहीं रहता इसीलिए श्रमिक-मालिक सघर्ष की सम्भावना भी नहीं रहती । उत्पादन का कार्य सरलता से, बिना किसी हड़ताल या कठिनाई के होता है ।

केन्द्रीय नियोजन में प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि नियोजन के कार्य में वह जो कुछ भी सहयोग दे रहा है वह 'राष्ट्रीय सेवा' है । इससे सभी के मन में कुछ 'गर्व' और 'देश-प्रेम' की भावना जागृत हो जाती है । पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई सम्भावना कभी नहीं हो सकती । केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में समाज और राष्ट्र की आर्थिक उन्नति सापूँर्ण्य रूप से होती है— पूँजीवाद की तरह व्यक्तिगत रूप से नहीं ।

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के मुकाबले समूचे केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था अच्छी है । क्योंकि इसके अन्तर्गत समूचे राष्ट्र की उन्नति होती है । श्रमिक-मालिक देशों में, विशेषतः पर, केन्द्रीय नियोजन केवल वाञ्छनीय ही नहीं बल्कि परमावश्यक भी है । यही कारण है कि भारतवर्ष ने अपनी आर्थिक स्थिति में द्रुत और सतृप्त सुधार करने के उद्देश्य से केन्द्रीय नियोजन की प्रणाली को अपनाया है ।

४—भारत में केन्द्रीय नियोजन (Central Planning in India)

भारत में प्राप्य विशाल मानवीय और भौतिक साधनों के होते हुए भी आर्थिक दृष्टिकोण से यह एक अशक्त देश है । आर्य तथा साधन के इस असन्तुलन का मुख्य कारण यह है कि वस्तुतः भारतवर्ष का आर्थिक विकास अनियोजित रहा है । प्राचीन युगों में व्यक्ति की आवश्यकताएँ अत्यधिक सीमित थीं जबकि प्राप्त साधनों की मात्रा उतनी ही अधिक थी । अतः तरकालीन मानव ने नियोजन के विषय में कभी चिन्ता ही नहीं की । आगे चलकर मुगल काल में भी देश के आर्थिक विकास के नियोजन तथा सन्तुलन के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया ।

समस्त ब्रिटिश शासकों के सम्मुख निर्धन भारतीय जनता का शोषण करना ही एकमात्र 'नियोजन' था । उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि वे हमारे प्राकृतिक साधनों का अधिक से अधिक शोषण करें, हमारे यहाँ के वस्त्र माल को अपने देश ले जायें तथा अपने यहाँ की निर्मित वस्तुओं का भारत में आयात करें । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वे हमारे यहाँ की पूँजी, व्यवसाय तथा गाम को तो अपने देश में ले गए और बदले में उन्होंने भारतवर्ष को बेरोजगारी, आर्थिक अवनति तथा निर्धनता ही प्रदान की । उन्होंने हमारे यहाँ के गृह-उद्योगों को भी एक प्रकार से समाप्त सा ही कर दिया ।

विश्व युद्ध तथा सन् १९२८ की आर्थिक मंदी के पश्चात् देश में पुनर्निर्माण के लिए केवल मिद्वान रूप में आर्थिक नियोजन अवश्य किया गया, जिसके

परिणामस्वरूप नियोजन के क्षेत्र में हमारे देश में सुव्यवस्थित रूप में प्रथम पंचवर्षीय योजना का समारम्भ हुआ। राष्ट्रीय आय, सामान्य जनता का जीवन स्तर तथा कृषि-उत्पादन के स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से सन् १९५१ में यह प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यरूप में परिणत की गई। जनता के सामान्य जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए इस योजना ने एक नया क्षेत्र प्रदान किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश की भावी आर्थिक स्थिति को और भी अधिक ऊँचा उठाने के लिए मुख्य रूप से औद्योगिक विकास पर बल प्रदान किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों के सामूहिक विकास पर सन्तुलन, सुव्यवस्थित और सुकल्पित रूप से बल दिया गया है।

विभिन्न देशों में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए नियोजन का होना नितान्त आवश्यक है :—

(१) देश की सामान्य जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना एवं उनके आर्थिकमान का विस्तार।

(११) आर्थिक समृद्धि की स्थापना और उसका विस्तार तथा आर्थिक संकट को रोकना। आर्थिक समृद्धि की स्थापना और उसका विस्तार करने का उद्देश्य अविकसित देशों में होता है। जबकि आर्थिक संकट का निवारण करने की समस्या विकसित देशों में उठती है। भारतवर्ष एक अविकसित देश है, अतः उसमें जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए राज्य-नियोजन का सिद्धान्त अपनाया जा रहा है। सारांश यह है कि राज्य-नियोजन भारत के लिए नितान्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।

भारतवर्ष एक निर्धन देश है, अतः यहाँ की व्यक्तिगत आय पर्याप्त वचन के लिए नाकाफी है। इसके लिए विनियोग भी अल्पमात्रा में है। यदि हम अन्य देशों की समकक्षता करने के लिये इच्छुक हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने देश में विशाल योजनाओं का प्रवर्तन करें ताकि आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों की प्रगति में हम पीछे न रह पायें। विशाल योजनाओं की स्थापना तथा परिचालन के लिए केवल राज्य ही पूँजी लगाने में समर्थ हो सकता है। अतः भारतवर्ष के लिये राज्य-नियोजन अत्यन्त आवश्यक है। यद्यपि राज्य-नियोजन प्रत्येक देश के लिये हितकर है, तथापि वह अविकसित राष्ट्रों के लिये तो एक अस्त्र कहें जा सकता है। "रूम तथा चीन में अत्यधिक द्रुत गति से जो आर्थिक विकास हुआ है उसका एकमात्र कारण केन्द्रीय नियोजन रहा है। हमारे देश में गणवर्षों में जो भी विशाल योजनाएँ पूर्णता को प्राप्त हुई हैं उनका प्रमुख आधार केन्द्रीय-नियोजन ही रहा है।

अविकसित देशों को समृद्धि तथा सम्पूर्ण बनाने के लिये केन्द्रीय नियोजन ही एकाग्र उपयुक्त माधन है। केन्द्र-नियोजित देशों ने इस बात को असंदिग्ध रूप से निश्चय कर दिया है कि, "राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के द्वारा ही

आर्थिक सफटो पर विजय प्राप्त की जा सकती है तथा किसी को भी यह कहने का अधिकार नहीं है कि ये सघर्ष प्राकृतिक तथा अनिवारणीय है”¹ अथवा “एक सफल राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के लिये किसी वास्तविक प्रजातन्त्रीय सरकार के हेतु राजनैतिक वातावरण का होना एक अनिवार्य शर्त है” तथा “केन्द्रीय नियोजन में जनता का सहयोग सहज उपलब्ध होता है।”

संक्षेप में, इस विषय में, हमारे निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रत्येक देश में नागरिकों के सामान्य जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिये नियोजन होना चाहिये।

(ii) व्यक्तिगत औद्योगिक नियोजन पूँजीवादी राष्ट्रों में ही सम्भव है—जहाँ कि सदियों से पूँजीवादी अर्थव्यवस्था विद्यमान है एवं पूँजी की कोई कमी नहीं है।

(iii) शेष राष्ट्रों—विशेषतः अशक्त राष्ट्रों में, केन्द्रीय नियोजन का होना आवश्यक है।

अन्ततोगत्वा ससार में केवल एक ही प्रकार का आर्थिक नियोजन स्थापित हो जायगा—और वह होगा केन्द्रीय आर्थिक नियोजन। ऐसा सिद्ध हो चुका है—तथा हो भी रहा है कि यह पद्धति सर्वोत्तम है तथा आर्थिक नियोजन का अधिकार भी इसके अनुसार राज्य में ही निहित हो जायगा।

आर्थिक प्रणालियाँ : (१) : (पूँजीवाद) (Economic Systems : (I) : Capitalism)

१—पूँजीवाद का अर्थ और उसका विकास (Meaning and Growth of Capitalism)

औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) ने पहले वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति प्रायः छोटी मात्रा में होती थी। यह कारण था कि उन उत्पादन कार्यों में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग कम मात्रा में होता था जो साधारण मनुष्यों की शक्ति से बाहर नहीं था। इसी कारण से उस काल में विभिन्न देशों में वस्तुओं की उत्पत्ति प्रायः एकाकी-उत्पादन के रूप में होती थी। परन्तु औद्योगिक क्रांति के बाद, जबसे उत्पत्ति के कार्य में शक्ति (Power) और मशीनों का प्रयोग होने लगा तथा उत्पत्ति बड़ी मात्रा में होने लगी तो उत्पत्ति के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए अधिक धन, पूँजी और उत्पत्ति के अन्य साधनों की आवश्यकता होने लगी जो सबके लिए इकट्ठा करना आसान नहीं था। इस प्रकार धीरे धीरे सम्पत्ति और पूँजी केवल कुछ ही हाथों में एकत्रित होती रही और देश के धन का वितरण असमान होता गया। ऐसी प्रथा को, जिसमें उत्पादन कार्य में, एक या कुछ ही व्यक्तियों की पूँजी प्रयुक्त होती है और जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है पूँजीवादी प्रथा कहते हैं। इस प्रथा के विकास में स्वतन्त्र व्यापार (free trade) और हस्तक्षेप न करने की नीति (Laissez faire Policy) का काफी महत्त्व रहा है।

पूँजीवाद के विषय में विभिन्न समयों में और विभिन्न देशों में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत रहते आए हैं। उनके मतों में जो भिन्नता है वह पूँजीवाद के अर्थ या परिभाषा, उसका स्वरूप या प्रकृति और उसकी विशेषताओं के सम्बन्ध में है। यद्यपि इन सभी विद्वानों ने पूँजीवाद की कुछ बातों का समान रूप से ही ध्यान दिया है फिर भी उनके दृष्टिकोणों में अन्तर रहा है।

पूँजीवाद की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न ढंग से की है। प्रोफेसर पीगू (A C Pigou) ने पूँजीवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है, "पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के मौलिक साधनों का अधिकार अथवा व्यवहार का अधिकार व्यक्तियों के पास होता है और इन साधनों का उपयोग इन अधिकारियों की आज्ञानुसार ही होता है। उनका उद्देश्य यह होता है कि इनकी सहायता में जो वस्तुएँ अथवा सेवाएँ उत्पन्न हो उनके द्वारा लाभ कमाया जाय। पूँजीवादी

अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पादक-साधनों का प्रमुख भाग पूँजीवादी उद्योगों में लगा हुआ हो।^१

प्रोफेसर बेंहम (Benham) के अनुसार 'पूँजीवादी अर्थव्यवस्था' 'आधिक तानाशाही की प्रतिविरोधी है'। पूरे उत्पादन का कोई केन्द्रीय नियोजन नहीं होता है। राज्य द्वारा लगाये हुए प्रतिबन्धों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए समय-समय स्वतन्त्र होता है। समाजवादी आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण विभिन्न प्रकार के दल से व्यक्तियों एवं व्यक्ति समूहों के समुच्चय रहित निर्णयों द्वारा होता है। क्योंकि प्रत्येक उत्पत्ति के साधन का स्वामी (जिसमें दाम-प्रथा के न होने के कारण श्रमिक भी शामिल है) उस साधन को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है और अपनी आय का मनचाही गति से व्यय कर सकता है।^२ (अनुवाद—विजेन्द्रपालसिंह, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, पृष्ठ—३७३)

प्रोफेसर सिडनी और बी बेंब (Sidney and Beatrice Webb) ने पूँजीवाद की परिभाषा इस प्रकार की है, "पूँजीवाद या पूँजीवादी प्रणाली अथवा यदि हम चाहे तो पूँजीवादी सभ्यता से हमारा अभिप्राय औद्योगिक और वैज्ञानिक संस्थाओं के विकास की उस अवस्था से है जिसमें अधिकांश श्रमिकों के पास उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व इस प्रकार नहीं होता है कि वे मजदूर वर्ग में गिने जाते हैं और जिनका जीवनवाद, जिनकी सुरक्षा और जिनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता राष्ट्र के छोटे से ही जनमूह की इच्छा पर निर्भर होते हैं, अर्थात् उन लोगों पर जो अपने वैधानिक स्वामित्व द्वारा भूमि, मशीनरी और मजदूर की श्रमशक्ति के मालिक होते हैं और

1 'A Capitalist industry is one in which the material instruments of production are owned or hired by private persons and are operated at their orders with a view to selling at a profit the goods and services that they help to produce. A Capitalist economy or Capitalist System is engaged in Capitalist industry'—A C Pigou *Socialism Vs Capitalism*

2 "A Capitalist economy is the antithesis of an economic dictatorship. There is no central planning of production as a whole. Subject to the limitations imposed by the state every body is more or less free to do what he likes. The Economic activities of the Community are determined by the apparently uncoordinated decisions of a multitude of different persons since each owner of a factor of production (including workers, who in the absence of slavery—own their own labour) is free to use it as he pleases, and to dispose of its earnings as he wishes" Benham

उसके संगठन पर नियन्त्रण रखते हैं तथा ऐसा करने में उनका उद्देश्य निजी तथा व्यक्तिगत लाभ कमाना होता है ।^१

(अनुवाद—निजयेन्द्रपालसिंह, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, पृष्ठ—३७४)

इसके अतिरिक्त भी पूँजीवाद की और बहुत-सी परिभाषायें विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं, जिनमें से कुछ अनुवादित रूप में (B. Tandon तथा M. D. Tandon, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, भाग १, पृष्ठ—२३६) इस प्रकार हैं

कुछ विद्वानों के अनुसार, “पूँजीवाद उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें वैयक्तिक सम्पत्ति पाई जाती है और मनुष्य कृत पूँजी तथा प्राकृतिक साधनों की निजी लाभ में उपयोगिता है ।” इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों का कहना है कि, “पूँजीवाद का अर्थ उद्योग के विवास में उस स्थिति से है जिसमें कि काम करने वाली का समुदाय उत्पादन के यन्त्रों के स्वामित्व से इस प्रकार परे हो जाता है कि वे हम प्रकार के श्रमिक बन जाते हैं कि उनका निर्वाह तथा निजी-स्वतन्त्रता उस राष्ट्र के उन थोड़े से व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर रहता है जो भूमि, पूँजी और श्रम-शक्ति के स्वामी हैं और उनके प्रबन्ध का नियन्त्रण अपने निजी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं ।” कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों का कहना है कि, “पूँजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें माल का उत्पादन तथा वितरण व्यक्तियों या समूहों द्वारा होता है जो अपने संग्रहित धन के भण्डार का उपयोग अपने लिए अधिक धन कमाने के हेतु करते हैं ।”

२—पूँजीवाद के मुख्य लक्षण और दोष

पूँजीवादी प्रथा में कुछ विशेषताएँ होती हैं जो साधारणतया अन्य आर्थिक प्रणाली में नहीं पाई जाती हैं । सामान्यतया पूँजीवाद की पहचान इन्हीं विशेषताओं, लक्षणों या दोषों द्वारा होती है । यह निम्नलिखित है —

१—निजी सम्पत्ति पर स्वामित्व का अधिकार (Right of private property and the system of Inheritance)—यह पूँजीवादी प्रथा की शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है । इसके द्वारा पूँजीवादी प्रथा के अन्तर्गत इस बात की स्वीकार कर लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति और इच्छा

1 “By the term Capitalism or the Capitalistic System or as we prefer the ‘Capitalist Civilization’ we mean the particular stage in the development of industry and legal institutions in which the bulk of the workers find themselves divorced from the ownership of the instruments of production in such a way as to pass into the position of wage earners whose subsistence, security and personal freedom seem dependent on the will of a relatively small proportion of the nation, namely those who own and through their legal ownership, Control the organisation of the Land, the machinery and the labour force of the Community and do so with the object of making for themselves individual and private gains”—
Sidney and Beatrice Webb

नुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति की स्थापना कर सकता है जो वंश-परम्परानुसार चल सकती है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में धन या पूँजी हो तो वह उसका व्यवहार स्वतन्त्र रूप से और अधिक धन कमाने के लिये, सम्पत्ति बढ़ाने के लिए या उत्पत्ति कार्य के लिए कर सकता है। उसके इस कार्य में (जब तक कि वह देश के अहित में न हो) सरकार, समाज या अन्य व्यक्तियों द्वारा बाधा नहीं डाली जा सकती। पूँजीवादी प्रथा में प्रत्येक मनुष्य को इस बात का पूरा अधिकार होता है कि वह अपने को अधिक खुशहाल बनाने के लिये, अधिक मात्रा में धन कमाये या सम्पत्ति का निर्माण करे।

वास्तव में निर्बाध-व्यापार और हस्तक्षेप न करने की नीति (*laissez faire system*) के द्वारा ही इस विशेषता की उत्पत्ति हुई है। निर्बाध व्यापार और हस्तक्षेप न करने का हमेशा यह परिणाम होता है कि समाज में रहने वाले विभिन्न स्तर के मनुष्यों में, और विशेषकर विभिन्न उत्पादकों में अपनी-अपनी उन्नति के लिए पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है और इस प्रकार पूँजीवादी प्रथा में सम्पत्ति केवल उन थोड़े से व्यक्तियों के पास ही एकत्रित हो जाती है, जो अधिक धन कमाने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार पूँजीवादी प्रथा में, निजी सम्पत्ति पर स्वामित्व और उसके वंश-परम्परा के अनुसार चले आते रहने का परिणाम यह होता है कि देश में धन, सम्पत्ति और पूँजी का वितरण असमान हो जाता है। धनिक वर्ग, इस प्रथा के अस्तित्व के कारण, और अधिक धनवान होते जाते हैं तथा निर्धन और अधिक दरिद्र।

२—प्रायः सभी विद्वानों के अनुसार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें त्रिनिमोग अथवा व्यवसाय की पूर्ण स्वतन्त्रता (*freedom of enterprise*) होती है। अर्थात् प्रत्येक उत्पादक को इस बात की स्वतन्त्रता होती है कि वह किसी भी वस्तु या सेवा की कितनी ही मात्रा में उत्पत्ति करे। उत्पत्ति की मात्रा का स्वरूप क्या होगा इसका निर्णय राज्य द्वारा न होकर उत्पादक की इच्छानुसार होता है। इस प्रकार साहसी वर्ग को इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है कि वह किसी भी वस्तु या सेवा की उत्पत्ति अपनी इच्छानुसार करे। उत्पादक अपनी शक्ति और वस्तुओं की भाँग के अनुसार उत्पादन की मात्रा का निर्णय करता है। उसके उस कार्य में दो मुख्य उद्देश्य होते हैं—अधिकतम उत्पत्ति और अधिकतम लाभ—और इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही वह वस्तु या सेवा की उत्पत्ति अपनी इच्छानुसार करता है। इसका प्रायः यह परिणाम होता है कि जिस वस्तु के उत्पादन से अधिकतम लाभ हो सकता है, सभी उत्पादक उस ओर झुकते हैं और राज्य द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप न होने के कारण, अन्त तक कुछ बड़े उद्योगपति ही उस क्षेत्र में शेष रह जाते हैं और इस प्रकार प्रायः एकाधिकार की स्थापना होती है, जिससे उपभोक्ताओं को हानि होती है।

३—आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic freedom) :

'इसके अन्तर्गत (अ) व्यवसायिक स्वतन्त्रता (ब) प्रसविदे करने की स्वतन्त्रता (freedom of contract) एवं (स) चुनाव की स्वतन्त्रता होती है। उपभोक्ताओं के चुनाव की स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि राज्य के नियमों का पालन करते हुए उसे अपनी आयको किसी भी प्रकार व्यय करने की स्वतन्त्रता होती है। उसे यह भी स्वतन्त्रता होती है कि वह आय के कुछ भाग को बचा ले तथा उसका (और अधिक आय प्राप्त करने के लिए) निवियोग (Investment) करे।' इस कथन का तात्पर्य यह है कि पूँजीवादी प्रथा में सरकार की ओर से व्यय, निवियोग या उत्पत्ति पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता है। देश में रहने वाले समस्त नागरिक इस बात के लिये स्वतन्त्र होते हैं कि वे अपने धन का प्रयोग किसी भी रूप में करें। प्रायः इसका परिणाम यह होता है कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में जिस मनुष्यों के पास अधिक धन होता है वह और अधिक धन प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी बचत के बड़े भाग को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति करने के लिए निवियोग करते हैं। इस प्रकार उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता है जो उनके पास पूँजी के रूप में इकट्ठा होता जाता है। इसका अन्तिम परिणाम यह होता है कि देश में धन का वितरण असमान हो जाता है।

४—वर्ग संघर्ष (Class conflict)—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की एक और विशेषता वर्ग-संघर्ष की है। पूँजीवादी प्रथा में निवियोग, उत्पत्ति या उपभोग पर किसी प्रकार का बन्धन न होने के कारण जिनके पास धन होता है वह अपने निजी लाभ के लिए उस धन का अधिकतम भाग 'अधिक उत्पत्ति' के लिये निवियोग करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि देश के धन या सम्पत्ति का एक बड़ा भाग केवल कुछ ही व्यक्तिओं के हाथ में जिसको पूँजीपति वर्ग कहते हैं इकट्ठा हो जाता है। पूँजीपतियों के पास अधिक धन होने के कारण वह मजदूरों का सरसत्ता से शोषण कर पाते हैं। इससे देश में दो वर्ग स्थापित हो जाते हैं—पूँजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि समाज का एक भाग 'सम्पन्न' (have) और दूसरा भाग 'असम्पन्न' (have not) हो जाता है।

इन दोनों वर्गों में एक दूसरे के प्रति मद्भावना का अभाव हो जाता है। सम्पन्न वर्ग असम्पन्न वर्ग से दूर रहना चाहता है और उनकी यह धारणा होती है कि मजदूर वर्ग उनका जन्मजात शत्रु है। इसके विपरीत, मजदूर वर्ग यह मानता है कि पूँजीपतियों के पास जो धन है वह वास्तव में उनका या उनके पूर्वजों का धन है, क्योंकि पूँजीपति के पास धन केवल निधनों के शोषण द्वारा ही इकट्ठा होता है। इस प्रकार पूँजीवादी प्रथा में देश में वर्ग-संघर्ष उत्पन्न होता है, जो राष्ट्र के लिये हानिकारक है।

५—श्रमिकों की दुर्दशा (Sad plight of the labourers)—मजदूरों के निर्धारण में, जहाँ पूँजीपति और श्रमिकों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है तो पूँजीपति की शक्ति अधिक होने के कारण तथा श्रम की विशेषताओं के कारण

श्रमिकों को ही भुक्ता पड़ता है और मजदूरी की दर प्रायः मजदूर की सीमान्त उत्पादन शक्ति से कम दर पर तय होती है। पूँजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण होता है।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में (पूँजीपतियों की प्रमुखता और अधिक क्षमता के कारण) उत्पत्ति में श्रमिकों की अपेक्षा साहसी का महत्त्व अधिक होता है (अधिक बनाया जाता है)। उसका परिणाम यह होता है कि उत्पत्ति में जब कि उत्पत्ति का कार्य पूँजीवादी प्रथा के अनुसार हो रहा हो, तो श्रमिकों का महत्त्व कम होता है। यह भी एक प्रकार का शोषण है, जिससे श्रमिकों की दुर्दशा में और वृद्धि होती है।

६—स्वार्थ-नीति (Self Interest)—पूँजीवादी प्रथा में उत्पत्ति, विनि-योग और वितरण पर किसी प्रकार का नियन्त्रण न होने के कारण पूँजीपति वस्तु या सेवाओं की उत्पत्ति स्वार्थ-सिद्धि और अधिकतम लाभ के उद्देश्य से करता है। इस कार्य में यदि उसे अन्य उत्पादकों के साथ 'गलाकाट प्रतिस्पर्धा' (Cut throat Competition) भी करने पड़े, तब भी वह न झिझकेगा। उसके सामने सिर्फ एक उद्देश्य है—निजी लाभ, जिसको वह किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहता है।

इस प्रथा के अन्तर्गत नियन्त्रण के अभाव से कभी-कभी वस्तुओं की उत्पत्ति आवश्यकता से अधिक मात्रा में भी होती है जिससे सैकड़ों कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादक कभी-कभी निजी लाभ के उद्देश्य से ऐसी वस्तुओं की उत्पत्ति या उनका वितरण भी करता है जो देश के लिये हानिकारक हैं।

७—अनियन्त्रित अर्थव्यवस्था (Uncontrolled Economic System)—इसके अन्तर्गत उत्पादक अधिकतर माँग की वस्तुओं का ही उत्पादन करना चाहता है। इस परिस्थिति में उसके लिए यह सम्भव होगा कि वह उत्पत्ति की मात्रा को बढ़ा कर वस्तु के उत्पत्ति व्यय को कम से कम कर सके। इसका कारण यह होता है कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को इस बात की पूर्ण आजादी (Consumers' Sovereignty) होती है कि वह जिस वस्तु को चाहे उसका उपभोग करे। सामान्य रूप से, उपभोक्ता वस्तु को कम से कम कीमत पर प्राप्त करना चाहता है। इस कारण उत्पादक की यही चेष्टा रहती है कि वह वस्तुओं की उत्पत्ति कम से कम उत्पत्ति-व्यय पर करे। इस प्रतिस्पर्धा में उत्पत्ति की छोटी-छोटी इकाइयाँ समाप्त हो जाती हैं और देश में केवल कुछ ही बड़े कारखाने शेष रह जाते हैं। इस प्रकार भी वस्तुओं का वितरण केवल कुछ ही हाथों में रह जाता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रथा में उत्पत्ति और वितरण के अनियन्त्रित होने के कारण 'अति-उत्पादन' (Over Production) या 'कम उत्पादन' (Under Production) की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो अवांछनीय है।

८—प्रतिस्पर्धा (Competetion)—पूँजीवाद की एक विशेषता प्रतिस्पर्धा भी है। पूँजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी लाभ के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं की उत्पत्ति करता है, इसलिये इसके उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आवश्यक

हो जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है; किन्तु पूँजीवाद का यह एक आवश्यक अङ्ग है। इससे लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है। लाभ यह होता है कि वस्तु की कीमत बाजार में कम हो जाती है, और हानि यह होती है कि यदि वस्तु की उत्पत्ति केवल एक या कुछ मिले हुए उत्पादकों द्वारा होती है तो एकाधिकार या प्रायः एकाधिकार की स्थापना हो जाती है जिसके फलस्वरूप आगे चल कर उपभोक्ताओं को हानि हो सकती है।

६—समन्वय का अभाव (Lack of Coordination)—पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली में न तो केन्द्रीय निर्देशन का कोई महत्त्व होता है और न उत्पत्ति नियन्त्रित रूप से ही होती है। वास्तव में, इस प्रकार की उत्पत्ति में क्रेता या उपभोक्ता का महत्त्व प्रबल होता है। उत्पादक उन्हीं वस्तु या सेवाओं की उत्पत्ति करना चाहता है जिनकी माँग अधिक होती है। वस्तुओं की माँग उपभोक्ताओं की आवश्यकता, रुचि, आय और स्वभाव पर निर्भर करती है। इस प्रकार उत्पत्ति का अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कीमत प्रणाली (Price mechanism) द्वारा होता है। इस प्रणाली में आदर्श सामंजस्य (Ideal Order) को बनाये रखना सम्भव नहीं होता और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पूँजीवादी उत्पत्ति व्यवस्था में समन्वय का अभाव होता है, जो कि अवांछनीय है।

१०—प्रतियोगिता और सगठन का सह-अस्तित्व (Co-existence of competition and combination)—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की यह एक विचित्र विशेषता है। प्रतिस्पर्धा और सगठन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं फिर भी इन आर्थिक प्रणाली में इन दोनों का एक सह-अस्तित्व (co-existence) है। बाजार में प्रभुत्व स्थापित करने के लिये प्रत्येक उत्पादक प्रयत्नशील होता है। इसके लिए वह उत्पत्ति की आधुनिकतम प्रणालियों को अपना कर उत्पत्ति-व्यय को कम करना चाहता है ताकि वह दूसरों के मुकाबिले में अपनी वस्तुओं की सस्ते दामों पर बेच सके और इस प्रकार दूसरे उत्पादकों को बाजार से खदेड़ कर अपना प्रभुत्व जमा सके। अतः उमें प्रारम्भिक स्थिति में दूमरे उत्पादकों से तीव्र प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। बड़ी मात्रा में उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप छोटी मात्रा के उत्पादक बाजार में हट जाते हैं। अन्त में उस वस्तु के एक या थोड़े से बड़ी मात्रा के उत्पादक रह जाते हैं। जब यह उत्पादक यह अनुभव करते हैं कि पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से वह एक दूसरे को हटा नहीं सकते और स्वयं हानि उठा सकते हैं, तो वे आपस में सगठन (combination) करते हैं। यह औद्योगिक सगठन (Industrial Combination) विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, किन्तु उनके उद्देश्य एक ही रहते हैं—अधिक लाभ कमाना।

११—आत्मघाती प्रकृति (Self destructive nature)—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था आत्मघाती होती है। अर्थात् इसका विनाश इसी के द्वारा होता है। पूँजीवादी प्रणाली में लाभ का उद्देश्य मुख्य होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति लाभ कामने

के उद्देश्य से हो, पूँजी का अधिकतम विनियोग (Investment) करता है और सदा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है कि वह बड़ी से बड़ी मात्रा में वस्तुओं की उत्पत्ति कम से कम उत्पत्ति-व्यय पर करे। प्रायः इसका परिणाम अति-उत्पादन (over-production) होता है जिससे देश में मन्दी आ जाती है और प्रायः सभी वर्ग के व्यक्तियों को हानि उठानी पड़ती है। पूँजीवन्दी अर्थव्यवस्था में नियन्त्रण का अभाव भी जनता को इस प्रणाली के खिलाफ कर देता है। किसी देश में जैसे-जैसे पूँजीवादी प्रथा का विकास होता जाता है, वैसे ही वैसे देश का धन कुछ ही हाथों में एकत्र हो जाता है और उनके द्वारा दरिद्र वर्ग का शोषण होने लगता है। अनियन्त्रित पूँजीवाद जब चरम सीमा पर पहुँच जाता है तो वर्ग-संघर्ष और अधिक बढ़ जाता है, एव उसको समाप्त करने के लिए इन देशों में समाजवाद, मार्क्सवाद या साम्यवाद की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार पूँजीवाद की 'समाप्ति' का कारण पूँजीवाद ही है।

१२—व्यापार-चक्र (Trade Cycle)—

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापार-चक्र अधिक तीव्रता से दृष्टिगोचर होता है। जब उत्पादकवर्ग यह अनुभव करता है कि किसी वस्तु या सेवा की माँग अधिक है या उसके उत्पादन से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है तो वह अपनी अधिकतम पूँजी का विनियोग उस वस्तु या सेवा की उत्पत्ति में करता है। इस प्रकार विभिन्न उत्पादकों द्वारा जब उस वस्तु या सेवा की उत्पत्ति अधिकतम मात्रा में होने लगता है तो उसकी पूर्ति उसकी माँग से अधिक हो जाती है जिससे 'अति-उत्पादन' (Over production) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पादकों को "मन्दी" का सामना करना पड़ता है।

इसके विपरीत यदि कम उत्पादन (under-production) होता है तो उपभोक्ताओं को वस्तुएँ कठिनाई से प्राप्त होती हैं और उनके लिए उन्हें ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। इस प्रकार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में 'अधिक उत्पादन' और 'कम उत्पादन', 'तेजी' और 'मन्दी' (Boom and depression) का व्यापार चक्र चलता रहता है जिसका कि देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

१३—सामाजिक परजीविता (Social Parasitism)—

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में 'सामाजिक परजीवियों' (Social Parasites) का अस्तित्व होता है। इसका अर्थ यह है कि पूँजीवादी समाज में बहुत से धनवान् ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार का कार्य किये बिना ही अपना जीवन सम्पन्नता और भोगविलास में व्यतीत करते हैं। उनके पूर्वजों ने या तो उद्योग-धन्धे स्थापित कर गये हैं जिनकी देखभाल और व्यवस्था के लिए उन्होंने व्यवस्थापक की नियुक्ति कर रखी है और इस प्रकार बिना कुछ किये ही बहुत धन पाते रहते हैं, जिससे वह विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते रहते हैं, या वशवरम्परानुसार उनके पास काफी भूमि

चली आ रही है जिसका लपान मिलता है या वह अपने नौकरो द्वारा उस भूमि पर खेती कराते हैं और उससे धन कमाते हैं, या उनकी कुछ भचल सम्पत्ति, मकान-दुकान आदि है जिसका किराया उनको बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाता है । उसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों के अधिकार में खाने है जिनसे उन्हें निरन्तर आमदनी होती रहनी है । यह सब बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में बिना कमाये भी बहुत धन प्राप्त हो सकता है । फलतः इस प्रकार के व्यक्ति भोग-विलास का जीवन व्यतीत कर सकते हैं । समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन बातों का अस्तित्व नहीं होता क्योंकि उसमें बिना कार्य किए धन की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

१४—धन की बर्बादी (Wastage of money)—

प्रतिस्पर्धा में और अन्य उत्पादकों को बाजार में हटाने के प्रयास में बहुत धन बर्बाद होता है । इस प्रतिस्पर्धा के कारण (बाजार पर कब्जा करने के लिए) उत्पादकों को कभी कभी उत्पत्ति-व्यय से भी कम कीमत पर वस्तुओं या सेवाओं को बेचना पड़ता है जिससे उन्हें हानि होती है और धन बर्बाद होता है । प्रचार और विज्ञापन पर उत्पादकों को अत्यधिक खर्च करना पड़ता है, इससे भी धन की बर्बादी होती है । अत्यधिक विशिष्टीकरण (Specialization), उत्पात्तिकी मात्रा की अत्यधिक वृद्धि, पूँजी प्रमुख-उत्पादन (Capital-intensive production) एवं अभिनवीकरण (Rationalization) की पद्धतियों के अपनाते के कारण भी धन की बर्बादी होती है । यदि यह सब धन खोज, गवेषणा, अन्वेषण और श्रमिकों के सामाजिक विकास के लिए व्यय किया जाय तो उससे सभी को लाभ होगा । कभी-कभी उद्योग-पतियों द्वारा एक ही प्रकार की वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिए देश में बहुत से कारखाने खोल दिए जाते हैं, जिनमें से बहुत से अनावश्यक होते हैं । इससे भी धन की बर्बादी होती है । समाजवादी अर्थ व्यवस्था में ऐसा कभी नहीं होता ।

१५—सामाजिक कल्याण का अभाव (Absence of Social welfare)—

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति केवल निजी लाभ के उद्देश्य से होती है—समाज की भलाई या श्रमिकों के कल्याण की दृष्टि से नहीं । उत्पादक उन वस्तुओं की उत्पत्ति में भी पीछे नहीं हटते जिनके उत्पादन से उन्हें तो लाभ है—परन्तु समाज को हानि है—जैसे, मादक द्रव्यों की उत्पत्ति । साहसी को श्रमिकों से कोई सहानुभूति नहीं होती । अतः वह कार्य करने के वातावरण में, कार्य के घंटों में, कार्य की परिस्थितियों आदि में कोई सुधार नहीं करता । उसी प्रकार श्रमिकों के मनोरंजन, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और निवास स्थानों के प्रबन्ध आदि पर उसे जितना ध्यान रखना चाहिए (एक मनुष्य और मालिक की हैसियत से) उतना ध्यान नहीं रखता । इससे श्रमिकों का आर्थिक और सामाजिक कल्याण नहीं हो पाता एवं उनका जीवन स्तर भी उन्नत नहीं हो पाता ।

१६—पूँजीवाद का सामाजिक मूल्य (Social Costs of Capitalism)—

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था समाज को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। उद्योगों के स्थानीयकरण से उसके आसपास का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर हो जाता है। वर्ग-संघर्ष के कारण देश की स्थिति में निरन्तर भ्रमन होती जाती है—देश की शान्ति हमेशा 'हड़ताल' और 'तालाबन्दी' (lock-out) से भग्न होती रहती है। व्यापार चक्र, 'मालाकाट प्रतिस्पर्धा' और तेजी-मन्दी के कारण देश के धन का अपव्यय होता है तथा बेरोजगारी बढ़ती है। सामाजिक परजीवियों (Parasites) के अस्तित्व से देश में भोगविलास की मात्रा बढ़ती जाती है। धनी वर्ग और धनी होकर दरिद्र वर्ग का शोषण करता है। समाज के एक बड़े भाग का—जो कि अर्थिक होता है, जीवन-स्तर गिरता जाता है। प्रायः उपभोक्ताओं को अधिक दाम देना पड़ता है क्योंकि इस प्रथा के अन्तर्गत एकाधिकार और व्यवसायिक समूहों के साथ ही साथ उद्योगपतियों द्वारा जानबूझ कर के कम उत्पादन भी किया जाता है, जिससे कि कीमत में कमी न हो।

३—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण (Merits of Capitalistic Economy)

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के बहुत से गुण तथा लाभ हैं जिनके कारण यह प्रथा अभी तक बहुत से देशों में विद्यमान है तथा ससार के कुछ प्रमुख राष्ट्र, जो ससार भर में बहुत खुशहाल समझे जाते हैं, इसी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं, जैसे, अमरीका ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रान्स आदि। यह सब देश इस बात को सिद्ध करते हैं कि किसी भी देश की उन्नति केवल केन्द्रीय नियन्त्रण या नियोजन पर ही आधारित नहीं होती बल्कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत भी अधिक विकास सम्भव है। पूँजीवाद के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं —

१ स्वयं संचालित (Automatic)—

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से कार्य करता है। इस प्रकार, कार्य में उन्हें उत्साह दिलाने का प्रयत्न सरकार की ओर से आवश्यक नहीं होता। इसी प्रकार किस समय किस कार्य को करें, उत्पत्ति का संगठन किस रूप में हो, उत्पत्ति की मात्रा क्या हो, उत्पत्ति कार्य के लिए पूँजी कहाँ से इकट्ठी की जाय या देश की आर्थिक अवस्था को उन्नत बनाने के लिए किन लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता प्रदान की जाय, यह सब कुछ ऐसे तथ्य हैं जो नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा निश्चित किये जाते हैं। परन्तु पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में यह सब स्वयं संचालित होते हैं। इस प्रकार एक ओर इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार का कार्य सरल हो जाता है, और दूसरी ओर, व्यक्तियों को भी अधिक स्वतन्त्रता रहती है। इस

प्रथा के अन्तर्गत उत्पादक और उपभोक्ता स्वयं अपना भविष्य और कार्य-पद्धति निश्चित करते हैं ।

२—बड़ी मात्रा की उत्पत्ति और प्रतिस्पर्धा का अस्तित्व—

इसमें उत्पादकों को पग-पग पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, इसलिए वह हमेशा इस बात के लिए सचेष्ट रहते हैं कि उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि हो । इससे उत्पादकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से लाभ होता है । प्रत्यक्ष रूप में तो यह लाभ होता है कि वह उत्पत्ति व्यय को कम करके बाजार को अपने अधिकार में कर सकता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके । अप्रत्यक्ष रूप में उसे यह लाभ होता है कि छोटे-छोटे और सीमान्त उत्पादक, जिनके पास पूँजी की कमी होती है, बाजार से हट जाते हैं और इस प्रकार उन्हें कम प्रतिद्वन्द्वियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है । इस प्रकार बड़ी मात्रा में उत्पत्ति होने से बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं और उपभोक्तानों को वस्तुएँ प्रायः सस्ती कीमत पर मिल जाती हैं ।

प्रतिस्पर्धा का अस्तित्व एकाधिकार या एकाधिकार की सी स्थिति को दूर कर देता है । निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में जबकि अधिकांश वस्तुओं की उत्पत्ति सरकार द्वारा होती है तो उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है । अतः उपभोक्तानों का महत्त्व कम हो जाता है । पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रायः उपभोक्तानों का महत्त्व अधिक होता है क्योंकि उत्पादक उन्हीं की इच्छा, रुचि और माग के अनुसार वस्तुओं की उत्पत्ति और उनका वितरण करते हैं ।

३—नमनीयता (flexibility) —

इसके अन्तर्गत उत्पत्ति निजी लाभ के उद्देश्य से की जाती है । इसलिए इस उत्पत्ति प्रणाली में परिवर्तनशीलता अधिक होती है । उत्पत्ति के प्रायः सभी साधनों की विक्षेपता यह होती है कि आवश्यकता पड़ने पर उनमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है या उन्हें एक उद्योग से हटा कर दूसरे उद्योग में भी प्रयुक्त किया जा सकता है । अर्थात् उनमें प्रतिस्थापन (Substitution) सम्भव होता है । समाजवादी या साम्यवादी राष्ट्रों में—जिनमें उत्पत्ति के समस्त साधन और उनका संगठन पूर्ण रूप से सरकार, पर, निर्भर होता है—यह प्रतिस्थापनशीलता, प्रायः काम में नहीं आती, क्योंकि वहाँ उत्पत्ति लाभ के उद्देश्य से नहीं होती । राष्ट्रीय उद्योगों में हानि होने पर भी वे बँस ही बने रहते हैं । परन्तु पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में पूँजीपति अपने पूँजी का प्रयोग किसी एक व्यवसाय या कारखाने में तब तक करता रहेगा जब तक उसे लाभ प्राप्त होता रहे । जब उसे लाभ प्राप्त न होगा या वह अनुभव करें कि उस पूँजी के दूसरे उद्योग में विनियोग से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है तो वह ऐसा ही करेगा । इस प्रकार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता बट जाती है और उनमें प्रतिस्थापन भी अधिक मात्रा में होता है । इसी कारण यह

कहा जाता है कि, “पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा गुण यह है कि उसमें अधिक लोचकता होती है।”

४—जोखिम उठाना (Risk taking) —

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में पूँजीपति ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है। जिन वस्तुओं या सेवाओं की अधिक माग होती है उनके उत्पादन क्षेत्र में पहले से ही बहुत से उत्पादक होते हैं। जिस क्षेत्र में अभी और उत्पादक नहीं हैं या कम हैं उस क्षेत्र में वह अधिक जोखिम उठा कर उन वस्तुओं की उत्पत्ति में अपनी पूँजी का विनियोग करता है। इस प्रकार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक जोखिम उठाया जाता है, नये नये प्रयोग, खोज और अन्वेषण किये जाते हैं जिससे कि पूँजीपति अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। राष्ट्र-नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रायः इस प्रकार का जोखिम नहीं उठाया जाता, जिसके कारण समाजवादी देशों में ऐसी वस्तुओं की उत्पत्ति सदा सम्भव नहीं होती। पूँजीपति इस बात को मान कर चलते हैं कि ‘बिना जोखिम उठाए लाभ नहीं हो सकता’ (No risk, no gain) इसलिए भी वे जोखिम उठाते हैं, और इस प्रकार उपभोक्ताओं को वे वस्तुएँ भी प्राप्त हो जाती हैं जो जोखिम उठाने के अभाव में प्राप्त नहीं हो सकती थी।

५—उत्पत्ति की प्रणालियों में उन्नति (Technological progress) —

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक जोखिम उठाया जाता है, अधिक प्रतिस्पर्धा होती है और उपभोक्ताओं का प्रभुत्व अधिक होता है। इन सबका परिणाम यह होता है कि उत्पादक हमेशा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि वह अपने कारखानों में अन्वेषण और गवेषणा करायें, उसके आधार पर उत्पत्ति के नये-नये तरीके मालूम करें तथा उनको अपनायें। यदि उत्पादक इस कार्य में सफल न हो सके तो उन्हें बाजार से हटना पड़ेगा। इस प्रकार इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप उन्हें उत्पत्ति के नये-नये तरीकों को अपनाना पड़ता है जिससे वह अधिक सुन्दर, टिकाऊ और अच्छी वस्तुएँ कम से कम कीमत पर उत्पन्न कर सकें।

६—पूर्ण रूप से साधनों का उपयोग (Full utilization of resources)—

अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये पूँजीपति उत्पादन के नये तरीकों को अपनाने के साथ ही साथ इस बात के लिए भी सचेष्ट रहना है कि ‘अवशिष्ट पदार्थ’ (Waste material) का भी उपयोग पूर्ण रूप से हो। इससे उसके लाभ की मात्रा में वृद्धि होती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के ‘अवशिष्ट’ पदार्थ का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होता जिससे राष्ट्र को हानि होती है, परन्तु पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अवशिष्ट पदार्थों का पूर्ण रूप से उपयोग होता है।

७—उत्पत्ति का कार्य और उद्योगों का प्रबंध विशेषज्ञों (Specialists) द्वारा होता है—

इसमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति केवल उनके विशेषज्ञों द्वारा ही होती है। प्रतिस्पर्धा के अस्तित्व के कारण उत्पत्ति के क्षेत्र में केवल वही टिक सकते हैं जो उस वस्तु या सेवा की उत्पत्ति में सबसे अधिक कुशल हैं। इस प्रकार जब वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति केवल कुशल व्यक्तियों के द्वारा ही होती है तो प्रायः उपभोक्ताओं को अच्छी और टिकाऊ वस्तुएँ कम से कम कीमत पर प्राप्त होती हैं। पूँजीपति, साहसी और प्रबन्धक अधिक काल तक एक ही कार्य को करते करते कुशल हो जाते हैं।

८—उत्पादन में प्रोत्साहन (Incentive to Production)

पूँजीवाद के अन्तर्गत उत्पत्ति के क्रियाशील (active) साधनों को दृष्टेय उत्साह प्रदान किया जाता है। लाभ की सम्भावना साहसी को उत्साह प्रदान करती है, जिसमें वह अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करके उस वस्तु या सेवा की उत्पत्ति से अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। केन्द्रीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था का यह सबसे बड़ा दोष होता है कि उसमें उत्पत्ति के संचालकों को किसी प्रकार का उत्साह प्राप्त नहीं होता जिसके कारण वह कभी भी उतने उद्यम और धैर्य से कठिन परिश्रम नहीं करते जितना कि पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में साहसी करना है। जो बात साहसी के लिए मत्व है वही बात प्रबन्धक और कुशल श्रमिकों के लिए भी। अच्छा फल दिखाने पर प्रबन्धक और श्रमिक दोनों के वेतन और भजदूरी की दर में वृद्धि मालिक की ओर से कर दी जाती है जिससे उत्पत्ति कार्य में सलग्न प्रत्येक व्यक्ति हमेशा अपनी पूर्ण शक्ति से कार्य करने के लिए इच्छुक रहता है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में वगण परम्परानुसार संपत्ति के अधिकार के अस्तित्व के कारण उत्पादक अधिकतम धन कमाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं ताकि वे सम्पत्ति की मात्रा में वृद्धि कर सकें और अपने बच्चों के लिए उसे छोड़ सकें।

९—योग्यतम की विजय (Survival of the fittest)—

पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। प्रतिस्पर्धा में वही विजयी हो सकता है जो कि योग्यतम हो या सबसे अधिक बलशाली हो। सामान्य रूप से, उत्पत्ति और वितरण का कार्य जब सबसे अधिक कुशल, योग्य और बलवान व्यक्तियों के हाथ में होता है तो उससे राष्ट्र और समाज को अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। समाजवादी और केन्द्र-नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था में इसका अभाव होता है।

१०—व्यक्तिगत देखभाल (Personal care)—

पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादक निजी लाभ के उद्देश्य से उद्योगों को स्थापित करता है और उनका संचालन करता है। इस प्रकार इस अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन का कार्य व्यक्तिगत देखभाल, उत्तरदायित्व, बुद्धिमानी एवं कुशल संचालन

के अन्तर्गत हो पाता है—जो केन्द्रीय नियोजन में सम्भव नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि उत्पत्ति का कार्य सुचारु रूप से होता है और बड़ी मात्रा में उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप वस्तुएँ प्रायः कम कीमत पर उपभोक्ताओं को प्राप्त हो जाती हैं।

११.—प्रजातन्त्रात्मक रूप (Democratic Character)—

पूँजीवाद की प्रकृति और उसका स्वभाव प्रजातन्त्रात्मक होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था या केन्द्रीय नियोजन की अर्थव्यवस्था की तरह यह पूर्णरूप से सरकार द्वारा आयोजित और नियोजित नहीं होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतन्त्रता के कारण इस प्रथा के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति और उत्पादक अपनी इच्छानुसार उत्पत्ति और वितरण कर सकता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है और उसका स्थान ऐसा होता है जैसा कि 'किसी राज्य में राजा का'। जिस प्रकार राजा की इच्छानुसार कार्य होते हैं, उसी प्रकार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की इच्छा, माँग और रचि के अनुसार ही उत्पत्ति होती है।

आर्थिक प्रणालियाँ (२)

(Economic Systems (2)

समाजवाद, मार्क्सवाद एवं साम्यवाद

(Socialism, Marxism and Communism)

१—समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा

(Meaning and definition of Socialistic Economy)

समाजवादी अर्थव्यवस्था पूँजीवाद के मुकाबले में बहुत ही प्राधुनिक है। वास्तव में पूँजीवाद के विरोध में ही समाजवाद की स्थापना हुई है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की समस्त वृत्तियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। पूँजीवाद में लाभ केवल उत्पादक और वितरक को ही प्राप्त होता है, इसके विपरीत, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त राष्ट्र की उत्पत्ति होती है जिससे प्रत्येक नागरिक लाभान्वित होता है। मजदूरसंघवाद से लेकर साम्यवाद तक समाजवाद के अनेक रूपों का बहुत विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा समय समय पर किया गया है। उनमें से कुछ विद्वानों का तो यह भी कहना है कि, "यदि २५ वर्ष की अवस्था तक कोई समाजवादी विचारों को न मानता हो तो यह कहा जायगा कि वह हृदयहीन है, परन्तु इस आयु के प्राप्त होने के पश्चात् भी यदि वह समाजवाद को प्रच्छा समझता रहे तो यह कहा जायगा कि उसमें विचार शक्ति ही नहीं है।"¹ समाजवाद के विभिन्न अर्थ जो कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा समय समय पर दिये गये हैं किस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न करते हैं उसके विषय में उल्लेख करते हुए (Shadwell) ने कहा है, "यह (समाजवाद) सैद्धान्तिक और रचनात्मक, भौतिक और अभौतिक, विचारात्मक, अति प्राचीन और बहुत ही आधुनिक दोनों एक ही साथ है इसका अस्तित्व एक कोरी भावना से लेकर एक ठोस रचनात्मक कार्यक्रम तक

1 'If one is not a socialist upto the age of twenty five, it shows that he has no heart; but if he continues to be a socialist after the age of 25, he has no head' Remark of a Swedish king, quoted by K. K. Dewett in *Modern Economic Theory*, p 613

फैला हुआ है, इसके विभिन्न समर्थक इसे एक ही जीवन दर्शन, एक प्रकार का धर्म, एक नैतिक नियम, एक आर्थिक प्रणाली, एक ऐतिहासिक पद्धति और एक वैज्ञानिक सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यह एक लोकप्रिय आन्दोलन तथा एक वैज्ञानिक विवेचना है, यह भूतकाल की एक टिप्पणी और भविष्य का एक दिग्दर्शन है, यह युद्ध का नारा है और युद्ध को रोकना चाहता है, यह एक हिंसात्मक क्रान्ति तथा रक्तहीन क्रान्ति है, यह प्रेम और सत्यता का महाग्रथ है और घृणा तथा लालच के विरुद्ध आन्दोलन है, यह मनुष्य की भावी आशा है और सम्पत्ता का अन्त है, यह एक अति आकर्षक भविष्य का आरम्भ है और भयपूर्ण सकट की चेतावनी है।¹ (परिभाषा का अनुवाद—बी पी सिंह, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, पृष्ठ—३८४)।

समाजवाद की एक और परिभाषा वेब्स (Webbs) ने दी है, जो इस प्रकार है—‘आरम्भ में इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर आतिथ्य स्वामित्व और नियन्त्रण के स्थान पर सारे समाज का स्वामित्व और नियन्त्रण होता है।’²

उपरोक्त परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि समाजवाद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज तथा राष्ट्र की उन्नति करना होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देश की उत्पत्ति और वितरण का अधिकार समाज या राष्ट्र द्वारा नियन्त्रित होता है। ऐसा केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवाद में ही संभव होता है।

डॉक्टर तुगन बरानोवस्की (Tugan-Baranowsky) के अनुसार “समाजवाद का सार यह है कि उसके अंतर्गत समाज के किसी व्यक्ति का शोषण नहीं हो सकता है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था लाभ की प्रेरणा के आधार पर चल रही है। परन्तु

1 “It is both abstract and concrete, theoretical and practical, idealist and materialist, very old and entirely modern it ranges from a mere sentiment to a precise programme of action. Different advocates present it as a philosophy of life, a sort of religion, an ethical code, an economic system, a historical category, a juridical principle, it is a popular movement and a scientific analysis, an interpretation of the past and a vision of the future, a war cry and a negation of war, a violent and a gentle revolution, a gospel of love and altruism, and a campaign of hate and greed, the hope of mankind and the end of civilisation, the dawn of the millennium and a fightful catastrophe” Shadwell

2 “The only essential feature in socialisation is that industries and services with the instrument of production which they require should not be owned by individuals and that industrial and social administration should not be organised for the purpose of obtaining private profit” Webbs

समाजवाद के अन्तर्गत उसका उद्देश्य अधिकतम कल्याण प्राप्त करना होता है।¹ (अनुवाद अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, बी पी सिंह, पृष्ठ—३८४) इसके अनिश्चित वेब्स (Webbs) ने समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवाद की परिभाषा एक अन्य स्थान पर इस प्रकार की है, “एक समाजवादी उद्योग वह होता है जिसमें उत्पत्ति के राष्ट्रीय साधनों पर सार्वजनिक सत्ता अथवा एन्ड्रिक सच का स्वामित्व होता है और जिसका संचालन उपज के दूसरे व्यक्तियों को बेचकर लाभ कमाने के लिए नहीं होता है बल्कि उन व्यक्तियों की प्रत्यक्ष सेवा के लिए होता है जिनका वह सत्ता अथवा वह सच प्रतिनिधित्व करता है।”²

एच डी डिक्सेन्सन (H D Dickenson) ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा एक अन्य ढंग से दी है। उनके अनुसार, “समाजवाद समाज का एक संगठन है। जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर सारे समाज का स्वामित्व होता है और उनका संचालन ऐसी संस्थानों द्वारा एक निश्चित योजना क्रम के अनुसार किया जाता है जो कि सारे समाज का प्रतिनिधित्व करती है और सारे समाज के प्रति उत्तरदायी होती है। समाज के सभी सदस्य समान अधिकारों के आधार पर ऐसे समाज द्वारा आयोजित उत्पादन के परिणामों के फलों के अधिकारी होते हैं।”³

लुक्स (Louks) और (Hoot) के अनुसार “समाजवाद वह आन्दोलन है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार की प्राकृतिक और मनुष्यकृत उत्पत्ति की वस्तुओं का जो कि बड़े पैमाने के उत्पादन में उपयोग की जाती हैं स्वामित्व और प्रदत्त व्यक्तियों को नहीं बल्कि सारे समाज के हाथ में देना होता है और उद्देश्य यह होता है कि बड़ी हुई राष्ट्रीय आय का इस प्रकार समान वितरण हो जाय कि व्यक्ति के आर्थिक

1 ‘The essence of socialism lies in the absence of exploitation of any individual in the society. The present economic system is based on the profit motive. But under socialism it aims at the maximum welfare of all. The production of commodities is on the basis of their utility to the community’ Tugan Baranowsky

2 ‘A socialised industry is one in which the national instruments of production are owned by public authority or voluntary associations and operated not with a view to profiting by sale to other people, but for the direct service of those whom the authority of association represents’ Webbs

3 ‘Socialism is an economic organisation of society in which the material means of production are owned by the community and operated by organs representative of, and responsible to, the community according to a general plan all members of the community being entitled to benefits from the results of such socialised planned production on the basis of equal rights’ H D Dickenson, *Economics of Socialism*, p 11

उत्साह और उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता तथा उपभोग के चुनाव मे कोई विशेष हानि न होने पाये।^{११}

मोरिस (Morris) का मत भी इन ग्रंथशास्त्रियों से, समाजवाद के ग्रंथ के विषय मे मिलता है। मोरिस ने समाजवाद की परिभाषा निम्नलिखित रूप से की है, “समाजवाद की प्रमुख विशेषता यह है कि सभी बड़े उद्योग और सभी भूमि पर सार्वजनिक अथवा सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए और उनका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सार्वजनिक हित मे होना चाहिए।”^{१२} (उपरोक्त सभी अनुवाद प्रोफेसर विजेन्द्रपालसिंह द्वारा किया गया है ग्रंथशास्त्र के सिद्धान्त, बी ए प्रथम वर्ष के लिए, पृष्ठ ३८३—३८६)।

उपरोक्त परिभाषाओं और समाजवाद की विशेषताओं के विषय मे अध्ययन के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्री इन विषयों के बारे मे एकमत नहीं है। परन्तु इन परिभाषाओं से समाजवाद की विशेषताओं ने कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जो निम्न प्रकार हैं —

१—देश की भूमि तथा मौलिक और भारी उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व होता है।

२—विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति साहसी के निजी लाभ के उद्देश्यों से नहीं होती, बल्कि समाज कल्याण और राष्ट्रहित के उद्देश्य से होती है।

३—समाजवादी अर्थव्यवस्था मे केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और उतनी ही मात्रा मे जो देश के लिए आवश्यक हैं।

४—उत्पत्ति केवल उतनी ही होती है जो देश को स्वावलम्बी बना सके।

५—समाजवाद की स्थापना, वगैरह संघर्ष को दूर करने तथा अनियमित आर्थिक विषमता को नियन्त्रण रखने के लिए हुई है।

६—इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय आय मे द्रुत वृद्धि होती है, धन का वितरण समान होता है और नागरिकों का जीवन स्तर ऊँचा उठता है।

७—इस अर्थव्यवस्था मे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा न होने के कारण आर्थिक वरबादी कम होती है।

1 “Socialism refers to that movement which aims at vesting in society as a whole rather than in individuals, the ownership and management of all nature made and man made producers’ goods used in large scale production to the end that an increased national income may be more equally distributed without materially destroying the individual’s economic motivations or his freedoms of occupational and consumption choices” —*Louks and Hoot*

2 “The important essentials of Socialism are that all the great industries and the land should be publicly or collectively owned, and that they should be conducted for the public good instead of for private profits” —*Morris*

८—समाजवाद का 'स्वाभाविक' आधार आर्थिक नियोजन होता है ।'

समाजवादी अर्थव्यवस्था के अनेक रूप हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं—सामूहिकवाद या राजकीय समाजवाद, श्रमिकवाद, वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद, एवं कारीगर संघवाद अथवा साम्यवाद ।

२—सामूहिकवाद या राजकीय समाजवाद

(Collectivism or State Socialism)

इस प्रकार की समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक विशेष गुण यह होता है कि, "उत्पत्ति के समस्त साधनों का राष्ट्रीयकरण होता है । राज्य द्वारा ही धन की उत्पत्ति और उसका वितरण होता है ।" इस प्रकार की समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी व्यक्ति विशेष को इस बात का अधिकार नहीं होता कि वह अपने निजी लाभ के उद्देश्य से किसी वस्तु या सेवा की उत्पत्ति करे । इस प्रकार सामूहिक या सरकारी प्रयास के द्वारा की गई उत्पत्ति या वितरण से जो कुछ लाभ प्राप्त होता है वह राष्ट्र द्वारा जन कल्याण और राष्ट्रहित में व्यय किया जाता है । इससे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में उन्नति शीघ्रता से सम्भव हो सकती है । राज्य तथा सामूहिक प्रयास के फलस्वरूप वस्तु या सेवा के उत्पादन से पारस्परिक प्रतिस्पर्धा या माधनों की दुर्वादी समाप्त हो जाती है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है । यद्यपि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में भी राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है किन्तु उस प्रथा में और राजकीय समाजवादी प्रथा में यह अन्तर होता है कि पहली प्रणाली में धन का वितरण असमान होता है जबकि दूसरी प्रणाली में धन का समान वितरण होता है, जिसमें देश के अधिकतम नागरिकों को लाभ प्राप्त होता है ।

सामूहिक समाजवाद और मार्क्सवाद के समर्थकों में समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप और प्रकृति के विषय में मतभेद है । दोनों का उद्देश्य प्रायः एक होता है, यद्यपि उनकी प्रणालियों में अन्तर है, जिसको इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है—
"जहाँ मार्क्सवादी-समाजवादी क्रान्ति व विद्रोह द्वारा समाजवादी-व्यवस्था की स्थापना में विश्वास करता है वहीं राजकीय समाजवाद वैधानिक तथा संसदीय ढंगों द्वारा राज्य सत्ता प्राप्त करना चाहता है ।"

३—श्रमिकवाद या मजदूर संघवाद

(Syndicalism)

श्रमिकवादी समाजवाद, पूँजीवाद के प्रत्यक्ष विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न होता है । श्रमिक और पूँजीपतियों में पारस्परिक सहयोग न होने के कारण और उनमें एक-दूसरे के प्रति विरोधी भावना रहने के कारण एक वर्ग दूसरे वर्ग को सदा दबा देने की चेष्टा करता है । उत्पत्ति कार्यों में अधिक सहभाग्य होने के कारण मज-

दूरो का महत्त्व बढ़ता चला जाता है जो पूँजीपतियों के शोषण को समाप्त करके अधिकार और नियन्त्रण की शक्तियों को अपने हाथ में कर लेना चाहते हैं। इस प्रकार पूँजीपतियों के विरोध में वे हमेशा हड़ताल आदि करते हैं और साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप से 'हिंसात्मक' या 'तोड़ फोड़' की प्रणाली को भी अपनाते हैं। इस प्रकार निरन्तर संघर्ष द्वारा पूँजीपतियों के अधिकार को समाप्त करके अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं—या करते हैं।

श्रमिकवाद के समर्थक इसके भी विरोधी होते हैं कि पूँजीपतियों से सत्ता छीनकर देश में एक 'साधारण समाजवाद' की स्थापना हो। इनका यह कहना है कि इस रूप में एक सही समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना सम्भव नहीं हो सकती। इसका कारण वह यह बताते हैं कि इस प्रकार के शासन में नौकरशाही का महत्त्व बढ़ता जाता है। शासन प्रवन्ध, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण आदि कार्यों से इन व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप से लाभ या हानि नहीं होती, इसलिए वे उत्साहपूर्वक काम नहीं करते हैं। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्र को उतना लाभ नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए।

श्रमिकवाद आधुनिक काल में बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं है क्योंकि जिस प्रणाली को अपना कर वह समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं वह हिंसात्मक है। हिंसात्मक प्रणालियों को अपनाने से शुरू में पूँजीपतियों को हानि होती है किन्तु इस प्रवृत्ति के बढ़ने से आगे चल कर देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को बटिनाई का सामना करना पड़ता है, जो अवैध है। इसके प्रतिरिक्त यदि देश का शासन, उत्पत्ति और वितरण का कार्य केवल श्रमिकों के हाथ में ही हो तो भी यह समस्त कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता—क्योंकि श्रमिक न तो इतने अधिक विद्वान् होते हैं कि वह शासन प्रणाली को ठीक प्रकार से चलायें न उन्हें उस कार्य के लिए कोई विशेष शिक्षा ही दी जाती है। फिर, श्रमिकवाद की स्थापना के पश्चात् कुछ श्रमिकों या श्रमिक नेताओं को देश का शासन कार्य संभालने के लिए कहा जाय तो उनमें भी कुछ समय बाद वही बातें पैदा हो जाती हैं जो नौकरशाही में होती हैं, अर्थात् व्यक्तिगत रूप से उत्पत्ति या वितरण से उन्हें लाभ न होने के कारण वे उन कार्यों को उत्साहपूर्वक नहीं करते।

४—वैज्ञानिक समाजवाद अथवा मार्क्सवाद^१

(Scientific Socialism or Marxism)

मार्क्सवाद उस ससार का, जिसमें हम रहते हैं और उस मानव समाज का, जो इस ससार का एक अंग है, एक सामान्य सिद्धान्त है। मार्क्सवाद का नाम कार्ल मार्क्स (Karl Marx) के नाम पर पड़ा है। कार्ल मार्क्स (१८१८-१८८३) ने

१ मार्क्सवाद क्या है ? एमिल बर्न्स (अनुवाद, ओमप्रकाश सगल) 'Peoples' Pub House Ltd, Bombay, पर आवारित।

फ्रेड्रिक ऐंगल्स (Friedrich Engels, १८२०-९५) के साथ मिल कर पिछली शताब्दी के मध्य और अन्तिम भाग में इस सिद्धान्त को विकसित किया था। इसी सिद्धान्त का एक अन्य नाम वैज्ञानिक समाजवाद भी है। इन दोनों विद्वानों ने इस बात की खोज की थी कि मानव समाज का आज जो रूप पाया जाता है वह ऐसा क्यों है ? उसमें परिवर्तन क्यों होते हैं ? तथा आगे चल कर मनुष्य जाति को और क्या-क्या परिवर्तन देखने पड़ेंगे ? अपने अध्ययन से वे इस परिणाम पर पहुँचे, कि “यह परिवर्तन-वाह्य प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों की भाँति अकस्मात् नहीं हो जाते बल्कि कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार होते हैं। इस सत्य की खोज के बाद यह सम्भव हो जाता है कि मानव समाज के बारे में एक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धान्त (Scientific theory) का निरूपण किया जाय जो मनुष्य जाति के वास्तविक अनुभव पर आधारित हो, जो धार्मिक विश्वासों, वंशपरम्पानुसार ग्रहण और वीर पूजाओं, व्यक्तिगत भावनाओं या काल्पनिक स्वप्नों के आधार पर बनी हुई, समाज के बारे में पहले की अस्पष्ट धारणाओं (और जो आज भी हैं) से भिन्न हो।”

मार्क्स ने अपने इस सिद्धान्त की जाँच ब्रिटेन के उस समय के पूँजीवादी समाज पर प्रयोग करके की थी। इस प्रयोग के द्वारा उन्हें यह पता लग गया कि उनका मत और उनकी खोज सही है। इसी प्रयोग के द्वारा वह इस बात को ज्ञात करने में भी सफल हो गये कि पूँजीवाद की जड़ क्या है ? कार्ल मार्क्स को इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के कारण बहुत ख्याति प्राप्त हुई। इस खोज के पश्चात् कार्ल मार्क्स ने एक अन्य सिद्धान्त की स्थापना की, वह यह था कि आर्थिक प्रगतियों का अध्ययन सही रूप से तभी हो सकता है जबकि उनका अध्ययन ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर किया जाय। कार्ल मार्क्स के यह सिद्धान्त पहले से अपने में सम्पूर्ण और सोलज्ज भावने तैयार कोई सिद्धान्त नहीं है। जैसे-जैसे इतिहास की नई-नई पंक्तें खुलती जा रही हैं, जैसे-जैसे मनुष्य और आधुनिक अनुभव प्राप्त करता जा रहा है वैसे ही वैसे मार्क्सवाद का भी विकास होता जा रहा है। मार्क्स और ऐंगल्स की मृत्यु के उपरान्त इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण योग देने का श्रेय लेनिन (V. I. Lenin) को (१८७०-१९२४) और स्तालिन (Joseph Stalin) १८७९-१९५३, को है।

“जिस तरह हर प्रकार के विज्ञान की खोज बाह्य प्रकृति को बदलने के काम आ सकती है, उसी तरह समाज के अध्ययन से प्राप्त हुई वैज्ञानिक खोज भी समाजको बदलने के काम में लाई जा सकती है। परन्तु, साथ ही साथ इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समाज की गति निर्धारित करने वाले सामान्य नियम भी उसी प्रकार के नियम होते हैं जिनसे बाह्य प्रकृति का संचालन होता है। हमारे शब्दों में, इन्हीं सामान्य नियमों की जिनकी सत्ता सार्वभौमिक है, और जो इन्सान तथा वस्तुओं

दोनों ही का निर्देशन करते हैं मार्क्सवादी दर्शन अथवा ससार का मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहा जा सकता है।¹

“मार्क्सवाद इतिहास का अध्ययन इस दृष्टिकोण से करता है ताकि उन प्राकृतिक नियमों का पता लग सके जो सारे मानव के इतिहास का संचालन करते हैं और इसके लिए वह व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि समूची जनता पर ध्यान देता है। जब वह आदिम समाज के युग के बाद बनने वाले जन समूहों पर नजर दौड़ाता है तो हर जन समूहों को कुछ ऐसे भागों में बाँटा पाता है जो समाज को विभिन्न दिशाओं में खींच रहे हैं, और यह कि वे ऐसा अपने व्यक्तिगत रूप में नहीं, बल्कि वर्गों के रूप में कर रहे हैं।”²

इस प्रकार हम यह पाते हैं कि प्रत्येक देश में विभिन्न समय में भिन्न भिन्न वर्ग रहते चले आ रहे हैं। मार्क्सवाद की स्थापना काल में विशेषरूप से यह वर्ग विद्यमान थे-श्रमिक वर्ग, दास वर्ग, भ्रष्ट दास वर्ग, पूँजीपति वर्ग, सामन्ती वर्ग, शासक वर्ग आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः किसान वर्ग और भू-स्वामी वर्ग में वर्ग संघर्ष बना रहता था जिसमें दास और भ्रष्ट दास वर्ग भी प्रायः सम्मिलित हो जाता था। वर्ग संघर्ष का कारण यह था कि भू-स्वामी वर्ग अपने से नीचे के वर्ग के लोगों का शोषण करते थे; उनसे अमानुषिक व्यवहार द्वारा काम कराते थे, जिसके एवज में उन्हें प्रायः कुछ भी नहीं देते थे।

इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी विभिन्न वर्गों में निरन्तर संघर्ष बना रहता था। इसमें सबसे अधिक उल्लेखनीय वर्ग-संघर्ष पूँजीपति और श्रमिकों के बीच था। पूँजीपतियों की शोषण नीति से सभी परिचित हैं। पूँजीपति वर्ग श्रमिकों से अत्यधिक काम लेते थे। कभी कभी तो श्रमिकों को एक दिन में १५-१६ घण्टे तक काम करना पड़ता था। जिसके एवज में पूँजीपति वर्ग उन्हें ‘जीवित रहने मात्र-मजदूरी’ प्रदान करता था और उस समय एक काल्पनिक सिद्धान्त ‘मजदूरी का लोह सिद्धान्त’ (Iron Law of wages) प्रचलित था। यह काल्पनिक सिद्धान्त उन्होंने अपने लाभ के उद्देश्य से बनाया था। इसी प्रकार स्त्रियों और बच्चों से भी वह १२-१३ घण्टे तक अत्यन्त प्रतिकूल वातावरण में दुर्व्यवहार के साथ काम लेते थे। जिसके बदले में उन्हें नाममात्र की मजदूरी प्रदान करते थे। इस कारण सभी वर्ग पूँजीपति वर्ग का विरोध करते थे।

वैज्ञानिक समाजवाद (Scientific Socialism) या मार्क्सवाद का एक मुख्य भाग मूल्य का सिद्धान्त (Theory of value) और ‘मूल्य का श्रम-सिद्धान्त’ (Labour theory of value) या ‘अतिरिक्त श्रम’ (Surplus labour) का सिद्धान्त

1 मार्क्सवाद क्या है ? एमिल बर्न (अनुवाद—ओमप्रकाश के संग्रह), पृष्ठ २

2 Ibid : pp 45

हैं। मानस की जनप्रियता और प्राधान्यता, कुछ हद तक, इन सिद्धान्तों के कारण ही प्राप्त हुई। मार्क्स का विचार था कि "मूल्य का आदि कारण श्रम है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में लगे हुए श्रम की मात्रा द्वारा निर्दिष्ट होता है। इस सिद्धान्त को समाज के लिए आवश्यक श्रम कहा जा सकता है। मूल्य समाज के लिए आवश्यक श्रम की समय-अवधि की इकाइयों में नापा जाता है। श्रम अवधि वह है जो किसी वस्तु को उत्पत्ति की सामान्य दशाओं के अन्तर्गत उत्पन्न करने के लिए उस समय में प्रचलित, निपुणता और परिश्रम के साधारण अंश के अनुसार आवश्यक होती है।"

पूँजी क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग प्रकार से दिया है। परन्तु पूँजी के विषय में मार्क्स का अपना ही एक अलग सिद्धान्त है। उनके अनुसार "पूँजी के शारीरिक रूप अनेक हैं। मशीन, मकान, कच्चा माल, ईंधन और उत्पादन के लिए आवश्यक दूसरी वस्तुएँ—ये सभी पूँजी में शामिल हैं। उत्पादन के वास्ते मजूरी देने में जो रकम लगती है वह भी पूँजी का ही भाग है। " " किन्तु मर्चण्टाइज में पूँजी उसी को कहते हैं जिसका उपयोग अतिरिक्त मूल्य पैदा करने में किया जाता है ।"¹

ऐसी पूँजी कैसे उत्पन्न हुई ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मार्क्स ने उस सिद्धान्त का स्पष्टन किया है जिसके अनुसार यह बताया जाता है कि 'पूँजी की उत्पत्ति कुछ मितव्ययी व्यवसायों द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपने खर्चों में हर प्रकार की कमी करके, थोड़ा-थोड़ा धन बचा कर उसको इकट्ठा किया था, जोजिम उठा कर उसका विनियोग उत्पत्ति कार्य के लिए किया था, उससे जो लाभ हुये वे उनको भी पहली रकम के साथ जोड़कर उत्पत्ति काम में विनियोग किया था और इसी प्रकार पूँजी उत्पन्न हुई थी।' कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने इतिहास का सहारा लेकर यह बताया है कि उपरोक्त धारणा बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि, "पुराने इतिहास पर नजर डाली जाय तो पता चलता है कि सुरु में पूँजी जिस तरह जमा हुई वह प्रायः छुनी सूट मार का तरीका था। कुछ दुसाहमी व्यापारियों ने अमरीका, हिन्दुस्तान और अफ्रीका से सोना आदि बहुमूल्य वस्तुएँ सूट वर बड़े पैमाने में पूँजी जमा की थी। " सार्वजनिक स्थानों को छीन कर उन्हें पूँजीवादी फर्मों के मालिकों को दिलाने के लिए 'हृदयन्दी कानून' बनाये गये थे। ऐसा करके किसानों से उनकी जीविका का साधन छीन लिया गया..... एिबाय इसके कि वे किसान अपनी छोटी गई जमीन पर नये मालिक के लिए काम करें, उनके पास जिन्दा रहने का कोई तरीका बाकी नहीं रह गया था। पूँजी का 'प्रारम्भिक एवजीकरण' इसी तरह से हुआ।"²

1 मार्क्सवाद क्या है एमिल बर्न, अनुवादक ओम प्रकाश सक्ल, पृष्ठ २४

2. Ibid pp. 25—26

कार्ल मार्क्स ने आगे चलकर यह बताया कि, “पूँजी प्रारम्भिक एक्कीकरण के स्तर पर ठहरी नहीं रहती,” उस परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य के सामने एक ही प्रश्न आता है, वह यह कि अगर इस बात को मान भी लिया जाय कि पूँजी का प्रारम्भिक एक्कीकरण इन झूट-मार और बेईमानों के तरीकों से हुआ, तो फिर उसमें निरन्तर वृद्धि किस प्रकार सम्भव हो रही है ? इस प्रश्न के उत्तर में कार्ल मार्क्स ने कहा कि प्रारम्भिक एक्कीकरण के बाद पूँजी का विकास और विस्तार ‘अतिरिक्त मूल्य’ (Surplus value) इकट्ठा होकर हुआ है। उनके अनुसार “मजदूर के जीवन निर्वाह के लिये जितना आवश्यक है उससे ज्यादा काम लेना, और बाकी शेष में वह जो कुछ तैयार करता है उसका मूल्य अपनी जेब में रखना, यानी, ‘अतिरिक्त मूल्य’ हथियाना—यह है पूँजी को बढ़ाने का तरीका। इस अतिरिक्त मूल्य का एक भाग पूँजीपति अपने जीवन निर्वाह पर खर्च करता है, बचा हुआ भाग नई पूँजी के रूप में स्तंभाल होता है। यानी, उसे वह अपनी पुरानी पूँजी में जोड़ देता है और उसकी मदद से पहले से ज्यादा मजदूरों को नौकर रखता है, और आगे उत्पादन में पड़ने से अधिक ‘अतिरिक्त मूल्य’ हथियाने में सफल हो जाता है। इससे फिर नई पूँजी तैयार हो जाती है और इसी प्रकार यह कभी न खत्म होने वाला क्रम चलता रहता है। “या कहना यह चाहिए कि यह क्रम कभी खत्म न होता यदि कुछ दूसरे आर्थिक एवं सामाजिक नियम काम न करने लगते। अन्त में जाकर, सबसे बड़ी रकावट वर्ग संघर्ष से ही पैदा होती है जो यदाकदा पूरी क्रिया को रोक देता है और अन्त में पूँजीवादी उत्पादन को बिटा कर उसका अन्त ही कर देता है।”¹

पूँजीवाद की चरम अवस्था का उल्लेख करते हुए, जिसके कारण साम्यवादी क्रान्ति हुई—लेनिन ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये थे —

(१) “उत्पादन एवं पूँजी का केन्द्रीयकरण इतना बढ़ चुका था कि एकाधिकार या हाज़रे स्थापित हो गये थे, जिन्होंने आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया था...।”

(२) ‘वैको की पूँजी कल कारखानों की पूँजी में घुल मिल गई थी, और उससे महाजनी पूँजी के स्वामियों का एक छोटा सा वर्ग पैदा हो गया था। प्रत्येक देश में इसी वर्ग का बोलबाला था.....।”

(३) “विभिन्न प्रकार के माल के निर्यात के अलावा, और उससे भिन्न पूँजी के निर्यात-महत्व का बहुत बढ़ जाना . . .।”

(४) ‘पूँजीपतियों के अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारी गुट बन गये थे। उन्होंने दुनिया को अपने बीच बाँट लिया था” ...।”

(५) "सबसे बड़ी ताकतों के बीच दुनियाँ का बंटवारा लगभग पूरा हो गया था (१८७६ में अफ्रीका का ११ प्रतिशत भाग यूरोपियन शक्तियों के कब्जे में था, और १९०० तक ६० प्रतिशत उनके अधिकार में चला गया था)।" १^१

इन सब तथ्यों के आधार पर लेनिन ने यह निष्कर्ष निकाला था, "साम्राज्यवाद का विस्तार केवल विभिन्न साम्राज्यों द्वारा स्थापित उपनिवेशों में ही नहीं होता बल्कि उसके लिए संपार के अन्य भागों में भी प्रयास किया जाता है।" जर्मनी के नात्सी शासनकाल का तथा ब्रिटेन, अमरीका, फ्रान्स आदि पूँजीवादी देशों का उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि पूँजीपति देश अपने साम्राज्यवाद के विस्तार में सदा प्रयत्नशील रहते हैं।

मार्क्स ने नये समाज के निर्माण के बारे में यह बताया था कि "नये समाज का संगठन एकदम नई जमीन पर नहीं होगा। अतः ऐसे किसी समाज की बात सोचना व्यर्थ है जो स्वयं अपनी नींव पर उठा हो ... इसके विपरीत एक सचमुच का समाजवादी समाज भी पहले की सभी सामाजिक व्यवस्थाओं की भाँति ही अपने से पहले की व्यवस्था के आधार पर ही उठेगा ... सत्य बात तो यह है कि पूँजीवादी समाज के भग्दर होने वाला विकास ही समाजवाद का रास्ता तैयार करता है और इस बात की सूचना देता है कि परिवर्तन किस प्रकार का होगा। लेनिन ने भी, कार्ल मार्क्स के निम्नलिखित सिद्धान्त को अपनाया था, जिसमें कार्ल मार्क्स ने यह बतलाया था कि "हमारा काम सबसे पहले यह होगा कि व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत स्वामित्व को सहयोगी उत्पादन और सहयोगी स्वामित्व में बदल दे। यह काम जोर-जबरदस्ती से नहीं, बल्कि मिसाल पेश करके, और इस उद्देश्य के लिये सामाजिक सहायता पहुँचा कर ही होगा।" १२

समाजवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की हो? इसके विषय में उल्लेख करते हुए मार्क्स ने आगे बतलाया कि जब उत्पत्ति एक योजना के अनुसार होती है—जिसमें उत्पत्ति की सभी बातें राष्ट्र द्वारा और समाजहित के लिये नियन्त्रित की जाती हैं—तो देश में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को लाभ होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स की दृष्टि में, "समाजवाद का मतलब आर्थिक क्षेत्र में उत्पादनों के साधनों पर पूरे समाज का स्वामित्व स्थापित होना, उत्पादन शक्तियों का तेजी से उन्नति करना और उत्पादन का एक योजना के अनुसार संगठित किया जाना है। इस व्यवस्था में अति उत्पादन या कम उत्पादन कभी नहीं हो सकता ... जैसे जैसे सुनियोजित उत्पादन बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उनका सुनियोजित वितरण भी बढ़ता जाता है।" १३

1 Ibid, page, 32-35

2. लेनिन द्वारा कार्ल मार्क्स और उनके सिद्धान्त में उद्धृत जिम्को एमिल बर्न्स ने मार्क्सवाद क्या है? में पृष्ठ-२६ पर पुनः उद्धृत किया है।

3 Ibid, page, 59

समाजवाद किस सीमा के पश्चात् साम्यवाद (Communism) में परिणत हो जाता है, उसका उल्लेख करते हुए मार्क्स ने कहा था कि जब समाजवादी समाज में उत्पादन इस हद तक बढ़ जाता है कि सभी नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं और किसी के लिए कोई चीज कम नहीं पड़ती तब भ्रलग-भ्रलग व्यक्ति कितना लेते हैं, इसे नापने, तौलने और सीमित करने में जरा भी तथ्य नहीं रहता। जब यह अवस्था आजाती है तब उत्पादन और वितरण इस सिद्धान्त के आधार पर होता है "कि हर कोई अपनी योग्यता के मुताबिक काम करे, और अपनी जरूरत के मुताबिक ले और जब यह सम्भव हो जाता है, तभी समाजवाद साम्यवाद में बदल जाता है।"¹

५—साम्यवाद (Communism)²

वैज्ञानिक समाजवाद का उन्नत रूप साम्यवाद है। मार्क्स के अनुसार "समाजवाद वह पहली मजिल है जब उत्पादन के साधनों पर जनता का अधिकार होता है और इसलिये मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण मिट जाता है, लेकिन सुनियोजित समाजवादी उत्पादन के द्वारा देश की पैदावार इतनी नहीं बढ़ पाती है कि हर एक को उसकी जरूरत के अनुसार मिल सके। परन्तु साम्यवाद की मजिल का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि भौतिक वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में मिलने लगती हैं। जिस समय मजदूर वर्ग शक्ति पर अधिकार करता है और समाजवाद की ओर बढ़ना शुरू करता है उसी समय से लोगों के दृष्टिकोण में भी एक परिवर्तन शुरू हो जाता है। तरह-तरह के बन्धन जो पूँजीवाद में नागपाश जैसे हथकड़ी होते हैं तब ढीले पड़ने लगते हैं और अन्त में भंग हो जाते हैं। शिक्षा और विकास के सब अवसर सब बच्चों के लिये समान रूप से खुल जाते हैं... .. जाति-पाति का फर्क जाता रहता है और शारीरिक तथा मानसिक श्रम की यह बढती हुई समानता धीरे-धीरे पूरी आजादी में फैल जाती है। हर आदमी 'बुद्धि-जीवी' बन जाता है और 'बुद्धिजीवी' शारीरिक श्रम से भागना बन्द कर देते हैं... ..।"³

कार्ल मार्क्स ने जब अपने यह विचार वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में प्रकट किये थे तो उससे पहले उन्होंने उन समाजवादी दृष्टिकोणों की आलोचना की थी जो उनसे पहले प्रचलित थे। उन समाजवादी विचारों को कार्ल मार्क्स ने 'केवल एक कल्पना' कह कर पुकारा था और उनका यह कहना था कि समाजवादी समाज की स्थापना उन प्रणालियों को अपनाकर कभी भी सम्भव नहीं हो सकती। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कार्ल मार्क्स अपने विचारों में ठीक थे। वास्तव में उस समय जिस समाजवाद का रूप हम हस्त में देखते हैं या चीन में जिसका प्रचार हो रहा है उसका आधार काफी हद तक कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों पर ही आधारित है।

¹ Ibid, page 62

² Communist manifesto (साम्यवादी घोषणा) के अनुसार

3. मार्क्सवाद क्या है ? 'एमलि बर्न्स, अनुवाद, ओमप्रकाश संगल, पृष्ठ ६२-६३

मार्क्स और एन्जिल्स (Engels) का विचार था कि 'साम्यवाद का पहला काम श्रमिकों को संगठन द्वारा ऊपर उठा कर उन्हें शासकों में परिवर्तित करना है'। साम्यवादी घोषणा (Communist manifesto) में उन्होंने साम्यवाद की स्थापना की निम्नलिखित मुख्य विधियाँ बताई थी ¹

१—“भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति का उन्मूलन और भूमि के सभी लगानों को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये उपयोग करना।

२—‘एक बहुत ही प्रगतिशील (Progressive) मजदूरी क्रम बढ्द शील ग्रामदानी कर का लगाना।

३—“राष्ट्र में जितने भी प्रकार के ‘उत्तराधिकार’ हो सकते हैं उनको समाप्त कर देना।

४—‘देश को छोड़ जाने वाले सभी व्यक्तियों, देश के विरुद्ध कार्य करने वाले देशद्रोहियों और विद्रोहियों की सम्पत्ति को जब्त (confiscation) कर लेना।

५—“साख (Credit) का राज्य के हाथों में केन्द्रीयकरण (centralization)। इसके लिए एक राष्ट्रीय बैंक (National Bank) की स्थापना करना जो साख सम्बन्धी सभी व्यवस्थाओं और तथ्यों पर अधिकार रखे तथा उसका नियन्त्रण करे।

६—“राष्ट्र में स्थित विभिन्न प्रकार के सवाद-वाहन और यातायात के साधनों का केन्द्रीयकरण।

७—‘राज्य में स्थित समस्त उत्पत्ति के साधनों को अपने कब्जे में कर लेना और उनका तथा उन कारखानों और उद्योगों का जिनकी स्थापना राज्य द्वारा हो, विकास और नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा होना। बजूर भूमि को खेती योग्य बनाना और एक निश्चित सामूहिक योजना के अनुसार भूमि से सबधित सभी बातों में समान रूप से सुधार करना।

८—“बच्चों, श्रमिकों और राज्य के अन्य व्यक्तियों को नि शुल्क विभिन्न प्रकार की और आवश्यक शिक्का का प्रबन्ध करना ताकि वे आगे चल कर कुशल नागरिक, कुशल श्रमिक और सुयोग्य प्रबन्धक बन सकें। ग्रामदानी की असमानता उनकी शिक्षा में बाधक न हो।

९—‘सभी प्रकार के श्रम का समान उत्तरदायित्व और ‘श्रम सेना (Labour Army) की स्थापना।’

मार्क्स ने, उस विषय पर प्रकाश डालते हुए कि वग-सवग किस प्रकार सम्पूर्णरूप से दूर हो सकती है और साम्यवाद की स्थापना की नींव किस प्रकार मजबूत हो सकती है कहा, “जब विकास के अन्तर्गत भेद समाप्त हो जायेंगे और सारा उत्पादन सारे राष्ट्र के एक विशाल सघ के हाथ में केन्द्रित हो जायगा, सार्वजनिक शक्ति की राजनैतिक प्रकृति का अन्त हो जायेगा। राजनैतिक शक्ति हाती

वास्तव में एक वर्ग की दूसरे वर्गों को दमन करने की समर्थित शक्ति होती है। यदि श्रमिक संगठित रूप में वर्ग-युद्ध में भाग लेते हैं और विजयी होकर उत्पत्ति की पुरानी दशाओं को समाप्त कर देते हैं तो वे साथ में वर्ग विरोध की दशाओं को भी समाप्त कर देंगे। और इस प्रकार एक वर्ग के रूप में स्वयं अपने भी प्रभुत्व को समाप्त कर दये।”¹

साम्यवाद की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए मार्क्स, एंजिल्स, लेनिन आदि ने निम्नलिखित मत प्रकट किए हैं —

१—“जब साम्यवादी संगठन शक्तिशाली हो जायेगा तो पूँजीपतियों को समाप्त करके शासन के अधिकार को छीना जाएगा और इस प्रकार श्रमजीवियों (Proletariat) का राज्य स्थापित किया जायेगा। आरम्भ में श्रमिकों की तानाशाही (Dictatorship of the proletariat) स्थापित होगी और इस तानाशाही का उद्देश्य सभी विरोधियों एवं पूँजीपतियों को समाप्त करना होगा। अन्त में एक वर्गहीन समाज (Classless society) का निर्माण किया जायेगा। इसके पश्चात् राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी और राज्य स्वयं ही समाप्त हो जावेगा।”²

२—“साम्यवाद का आचार अन्तर्राष्ट्रीय है तथा यह जाति, धर्म, रंग और राष्ट्रीयता के भेदों को स्वीकार नहीं करता है।”

३—“साम्यवाद का साधारण उद्देश्य सामान्य रूप से सम्पत्ति को समाप्त करना नहीं है, बल्कि इसके विपरीत पूँजीपति की सम्पत्ति को समाप्त करना है जो कि वर्ग संघर्ष पर आधारित है और मुठ्ठी भर मनुष्यों को इस बात की शक्ति प्रदान करता है कि वह राष्ट्र के अन्य व्यक्तियों का शोषण कर सकें।”³

४—“साम्यवाद किसी भी व्यक्ति द्वारा समाज की उत्पत्ति का उपयोग करने के अधिकार को छीनना नहीं चाहता। यह केवल उस शक्ति को छीनना चाहता है जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे के श्रम का उपयोग करता है।”

५—“साम्यवाद में समाजीकृत उत्पादन की एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसी उत्पात्ति का विकास समाज के विभिन्न वर्गों के भेद को स्वयं मिटा देगा।”⁴

६—“साम्यवाद में स्त्रियों को नीची दृष्टि से नहीं देखा जाता। न यह समझा जाता है कि वे समाज के प्रत्यक्ष क्षेत्र में योग नहीं दे सकती। इस बात की विशेष व्यवस्था की जाती है कि वे बिना किसी कठिनाई के कार्य कर सकें।”⁵

1. Karl Marx & F. Engels, 'Manifesto of the Communist Party'—

Marx Engels Selected Works, Vol I, p 51

2 (हिन्दी में अनुवाद—वा० पा० मिह, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, भाग १, पृष्ठ ३६१)

3 Marx Engels Selected Works, Vol I, p 45

4 Ibid p 47

5 F Engels 'Socialism—Utopian and Scientific'

७ - "साम्यवाद के अन्तर्गत जातियों के बीच खड़ी हुई दीवारें गिर जाती हैं। समाजवादी समाज में कोई 'पराधीन जाति' नहीं होती।"^१

८ - 'इस प्रथा के अन्तर्गत जनतंत्र का केवल यह अर्थ नहीं रहता कि पार्लियामेंट में कौन प्रतिनिधि बन कर जाय और उसके लिए लोगों से वोट मागे जायें। जनतंत्र का अर्थ अब यह हो जाता है कि प्रत्येक कारखाने में, प्रत्येक मुहल्ले में, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नर-नारी स्वयं अपने देश के भविष्य का निर्माण करते हैं।'^२

९ - "शहर और देश का फर्क मिटने लगता है।"^३

१० - साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था की सबसे बड़ी बात यह होती है कि "पूँजीवाद से उत्पन्न स्वार्थपरता और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के बदले लोगों में एक सच्चा सामाजिक दृष्टिकोण और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है... .. इस समाज में स्त्री-पुरुषों का सिवा इसके और कोई दृष्टिकोण नहीं होता कि समाज के विकास में वे अधिक से अधिक योग दें।"^४

साम्यवाद के आलोचकों ने इस प्रथा की अत्यन्त निन्दा की है। उनके अनुसार साम्यवाद की निम्नलिखित त्रुटियाँ हैं :—

१ - साम्यवाद के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लोप हो जाता है।

२ - साम्यवाद के अन्तर्गत मनुष्यों को अपनी इच्छानुसार आजीविका के साधन को चुनने की इजाजत नहीं होती। राष्ट्र जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की शिक्षा या कार्य प्रदान करना चाहे उसमें व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता नहीं होती कि वह उसकी व्यवहलना कर सके।

३ - साम्यवाद के आलोचकों का यह भी कहना है कि साम्यवाद की स्थापना से तानाशाही (dictatorship) की स्थापना हो जाती है।

४ - साम्यवादी प्रथा के विरोध में यह भी कहा जाता है कि इस प्रथा में सैनिकीकरण (Regimentation) हो जाता है जिससे मानव जीवन को उच्चतम मूल्य (Higher ends of life) की समाप्ति हो जाती है।

५ - साम्यवाद में एक दोष यह भी बताया जाता है कि इसके चरम-स्थिति पर पहुँच जाने पर परिवार का बन्धन और धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

६ - अन्य प्रकार की समाजवादी व्यवस्थाएँ (Other Types of Socialistic Order)

(अ) रूसी साम्यवाद अथवा बोल्शेविज्म (Russian Socialism or Bolshovism) सन् १९१७ में जार (Czar) के विरुद्ध रूस में क्रान्ति हुई थी उसके

१. मार्क्सवाद क्या है-एमिल बर्न्स, अनुवाद-ओमप्रकाश संगल, पृष्ठ ६२.

२. Ibid, 63.

३. Ibid

४. Ibid, 64

पश्चात् वहाँ पर एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी समाज की स्थापना हुई जिम्मेवो बोल्शेविज्म कहते हैं। इस क्रान्ति के पश्चात् जब देश की शासन सत्ता जार के हाथ से हट कर श्रमजीवियों (Proletariat) के हाथ में आई तो उन्होंने सबसे पहले भूमि का राष्ट्रीयकरण किया। इसके अन्तर्गत भूमि किसानों के पास ही बनी रही और वह उसी पर फल करते रहे परन्तु उसका स्वामित्व राष्ट्र के हाथ में हो गया। उस समय उन्हें अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त समस्त उपज को राष्ट्र को बेचना पड़ता था। मन् १९१६ तक इस में, साम्यवादी प्रथा के अन्तर्गत समस्त खानो, कारखानो, उद्योग धंधो, सहको, यातायात तथा सवादावादन के साधनो, बैंक, बीमा वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि का राष्ट्रीयकरण हो गया था। इस प्रकार धीरे-धीरे इस प्रगति करना रहा और साम्यवादी सिद्धान्तों को अपने राष्ट्र में लागू करता रहा। इसी के अनुसार समार में सबसे पहले रूस ने आर्थिक नियोजन की नींव डाली। इन आर्थिक नियोजनों के आधार पर रूस ने इतनी प्रगति की है कि उसका स्थान सभार के उन्नत देशों में शिखर श्रेणी में है।

(ब) अराजकतावाद (Anarchism)—इस आर्थिक प्रणाली की उत्पत्ति साम्यवाद से ही हुई। सबसे पहले इस सिद्धान्त को ग्रिम क्रोपोटकिन (Kropotkin) ने प्रतिपादित किया था, “अराजकतावाद का साधारण अर्थ व्यवस्थाहीनता (disorder) अथवा सत्ताहीनता (Lack of authority) होता है। परन्तु, आर्थिक दर्शन के रूप में अराजकतावाद बिल्कुल ही भ्रमलगी चीज है। इसके अनुसार अराजकतावाद केवल समाजवाद में राज्य अथवा शासन के प्रभाव को सूचित करता है।” इसकी स्थापना का आधार क्रान्ति है। इस प्रथा को मानने वाले व्यक्तियों का यह कहना है कि इसके द्वारा एक वर्गहीन और सघर्ष-रहित समाज की स्थापना हो जाती है क्योंकि “क्रान्ति मानव समाज का संगठन कर देती है।”

इसके अतिरिक्त समाजवाद के कुछ अन्य रूप भी हैं

- (स) फैबियन समाजवाद (Fabian Socialism),
- (द) राष्ट्रीय समाजवाद (National Socialism),
- (च) नात्सीवाद (Nazism)
- (ज) फासिज्म (Facism)

७—समाजवाद के गुण तथा दोष (Merits and Demerits of Socialism)

समाजवाद के गुण

१—वर्ग सघर्ष की समाप्ति—समाजवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता या इसका लाभ यह है कि इसके अन्तर्गत वर्ग सघर्ष की समाप्ति हो जाती है।

२—राष्ट्रीयकरण—समाजवादी अर्थव्यवस्था में राष्ट्र की समस्त भूमि, प्राकृतिक साधन, कलकारखाने, वाणिज्य और व्यापार, यातायात और संचार-वाहन के साधन आदि सभी विषयों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है ।

३—अनुत्पाजित आय (Unearned Income) की समाप्ति—समाजवादी अर्थव्यवस्था में वंश-परंपरानुसार स्वामित्व समाप्त हो जाता है । इस प्रकार पूँजीवादी प्रथा के अंतर्गत भूमि के अधिकारियों को भूमि के स्वामित्व से जो अनुत्पाजित आय प्राप्त होती है वह समाप्त हो जाती है । इसी प्रकार कल कारखानों से, बिना किसी परिश्रम के उत्तराधिकारी सूत्र में जो अनुत्पाजित आय प्राप्त होती है उसकी भी समाप्ति हो जाती है । समाजवादी अर्थव्यवस्था में कार्यानुसार ही प्रतिफल प्राप्त होता है ।

४—राज्य का महत्व बढ़ जाता है—समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य के महत्व का अत्यंत विस्तार होता है क्योंकि देश के शासन प्रबंध, न्याय, शान्ति और सुरक्षा के कार्यों के प्रतिरिक्त भी इस प्रथा के अंतर्गत उत्पत्ति के समस्त साधनों का नियंत्रण और प्रबंध, उसकी उत्पत्ति और वितरण का कार्य राज्य द्वारा ही होता है ।

५—आर्थिक नियोजन—समाजवादी अर्थव्यवस्था का आधार आर्थिक नियोजन है । इन आर्थिक नियोजनों के द्वारा ही देश की आर्थिक स्थिति में निरंतर उन्नति प्राप्त करने की कोशिश की जाती है और इसी के द्वारा ही इस बात की भी चेष्टा की जाती है कि देश में रहने वाले समस्त नागरिकों का जीवन-स्तर क्रमशः उन्नत हो सके ।

६—आर्थिक असमानताओं की समाप्ति—समाजवादी अर्थव्यवस्था में मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं रह पाता । पूँजीवाद में आमदनी के आधार पर वर्गों की स्थापना होती है क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों की आमदनी में बड़ा अंतर होता है । देश का धन केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो जाता है । धनिक अधिक धनी होते जाते हैं, निर्धन और अधिक गरीब । इस प्रकार की आर्थिक असमानता समाजवाद में संभव नहीं होती ।

७—समाज कल्याण (Social welfare)—समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है जिसका पूँजीवाद में अभाव रहता है । समाज कल्याण पर अधिक बल देने से राष्ट्र के समस्त नागरिकों को पहले से अधिक सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं ।

८—नवीन पद्धतियों का अपनाना जाना—समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना प्रायः पूँजीवाद के विरोध में ही होती है । इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में उस प्राचीन समाज को नष्ट कर दिया जाता है जिसके अंतर्गत मनुष्यों का शोषण मनुष्यों द्वारा होता है । और एक ऐसी “नई सामाजिक, राजनैतिक और

आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है जिससे द्वारा मानव जाति के सम्मान और उसकी अधिकतम विकास की दशाएँ बनी रह सके ।”

६. कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना—कल्याणकारी राज्य की स्थापना—जिसके अन्तर्गत राष्ट्र में रहने वाले समस्त नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सामान्य सुविधायें समान रूप से प्रदान की जाती है ताकि वे अधिकतम उन्नति कर सकें—समाजवादी अर्थव्यवस्था में ही सम्भव है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को जीवित रहने, शान्ति और सुरक्षा से रहने, शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार प्राप्त करने, वृद्धावस्था में पेन्शन पाने और बीमारी में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त करने के पूरे अधिकारों का आश्वासन राज्य द्वारा दिया जाता है।

समाजवाद के दोष

१—समाजवाद के आलोचकों का कहना है कि समाजवाद तानाशाही को जन्म देता है।

२—असफल औद्योगिक प्रबन्ध—दूजीपतियों का यह कहना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उद्योगों का प्रबन्ध प्रायः गैरजिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों के हाथ में छोड़ दिया जाता है। इन कर्मचारियों को इस प्रबन्ध के कार्य से कोई निजी लाभ नहीं हो पाता। इसलिए वे इस कार्य को पूरा मन लगाकर नहीं करते। यह दोषारोपण आशिक रूप से ही सत्य है।

३—स्वतन्त्रता की कमी—समाजवाद में कीमतों का निर्धारण राष्ट्र द्वारा ही होता है; साधारण सिद्धान्त के अनुसार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा नहीं, इसलिए इस प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्तृओं का महत्त्व लुप्त हो जाता है।

४—उत्पादन कार्य में प्रेरणा का अभाव (Absence of Incentive to Production)—प्रायः यह कहा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति और वितरण के कार्य निजी लाभ के उद्देश्य से नहीं होते। इसलिए उत्पत्ति और वितरण में सलग्न व्यक्तियों में इस प्रथा के अन्दर कार्य करने की प्रेरणाओं का अभाव रहता है। यह विचार भ्रमात्मक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीयता की भावनाएँ अधिक जागृत होती हैं और प्रत्येक मनुष्य इस बात में गर्व अनुभव करता है कि वह राष्ट्र की भलाई में (जिसमें अपनी भलाई भी सम्मिलित है) सहयोग प्रदान कर रहा है।

५—निर्णयों का अभाव (Absence of Decision making)—समाजवाद के विरोध में यह भी कहा जाता है कि इसमें द्रुत और सही निर्णय नहीं होने पाते। व्यवस्थापक वर्ग को शीघ्र या सही निर्णय करने से व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। यह बात सैद्धान्तिक रूप से ठीक हो सकती है किन्तु व्यवहारिक रूप से यह भ्रम है। प्रायः यह देखा जाता है कि समाजवादी राष्ट्र तीव्रता से उन्नति करते हैं जो केवल तभी संभव हो सकता है जबकि सभी व्यक्ति सही प्रकार से, ठीक समय पर, मन लगाकर, राष्ट्रहित के उद्देश्य से कार्य करें।

उपरोक्त सभी तथ्यों के अध्ययन के पश्चात् हम केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं और वह यह कि समाजवादी अर्थव्यवस्था राष्ट्र-उन्नति के लिए और राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान सुयोग और सुविधायें प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी है। रूस और चीन ने समस्त संसार को इस बात का सबूत दिया है कि राष्ट्र-उन्नति के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था से बढ़कर अन्य कोई प्रणाली नहीं है। यही कारण है कि भारतवर्ष में भी समाजवाद की स्थापना होने जा रही है। भारत समाजवादी ढंग के समाज (*Socialistic Pattern of Society*) की स्थापना के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए यहाँ केन्द्रीय नियोजन की पद्धति को अपनाया जा रहा है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था^१ (Mixed Economy)

१—ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

‘मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतवर्ष तथा सारे ससार के लिए एक नया विचार है’। प्राचीन काल में आर्थिक क्षेत्र में सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति और आर्थिक संस्थाओं को पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। ऐडम स्मिथ का विचार था कि ‘आर्थिक स्वतन्त्रता’ ही सारी आर्थिक उन्नति का आधार है। उनका कहना था कि: “राष्ट्र को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्वतन्त्रता पाना आवश्यक है। राष्ट्र इन आर्थिक क्रियाओं को सही ढङ्ग से मितव्ययता से चलाने में असमर्थ है।” यह मत करीब करीब सभी अर्थशास्त्रियों को मान्य था। राज्य भी इस मिश्रित अर्थ व्यवस्था की ओर से उदासीन थे क्योंकि उस समय कोई आर्थिक कठिनाई उनके सामने नहीं थी। आर्थिक स्वतन्त्रता के बारे में स्मिथ के विचार इतने सुन्दर थे कि वे आने वाले अर्थशास्त्रियों के लिए उद्धरण योग्य बन गये थे। स्मिथ का कहना था, “जितनी असम्बद्धता एक व्यापारी और राजा के चरित्र में पाई जाती है उतनी किन्हीं में नहीं। राजा प्रायः धन की बबिदी करने वाले होते हैं।” इसका तात्पर्य यह है कि सरकार किसी भी प्रकार की मितव्ययिता करने में असमर्थ होता है। साहसी कुशलता तथा मितव्ययिता से उद्योग को बचाते हैं, उनमें उद्योग की उन्नति के लिए उत्साह होता है जो कि राज्य व्यवस्था में नहीं पाया जाता। जहाँ साहसी स्वयं अपनी पूँजी लगा कर उद्योग चलाता है, वहाँ सरकार जनता का धन लगाती है। अतः राज्य-उद्योग में बुद्धिमानी से धन व्यय करने का अभाव होता है। साहसी अपने प्रति स्वयं जिम्मेदार होता है क्योंकि वह स्वयं अपनी पूँजी से उद्योग चलाता है। जहाँ उद्योग राज्य द्वारा प्रचलित है वहाँ इस जिम्मेदारी का विकेंद्रीकरण हो जाता

^१ इसमें विशेषरूप से भारतीय स्थिति का अध्ययन किया गया है।

है और कोई भी व्यक्तिगत रूप से उद्योग के प्रति जिम्मेदार नहीं होता, साहसी की अपनी पूँजी सीमित होती है।

एडम स्मिथ ने पाया इस बात का उल्लेख अपने लेखों में सभी जगह किया है, "आर्थिक विकास के लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। (Il mondo Va Da Se) वर्तमान संसार की आर्थिक अवस्था लाखों मनुष्यों की सयुक्त प्रयासों का फल है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखते कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात का कि आर्थिक विकास के प्राप्त करने का उद्देश्य कैसे सफल हो ?"¹

आर्थिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें राज्य का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होता है तथा स्वतन्त्र व्यापार का अर्थ यह नहीं कि देश में कोई राजकीय संगठन न हो। यह कोरा 'भाष्यवादी' सिद्धान्त नहीं होता है। स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत प्रत्येक साहसी के लिए क्षेत्र व्यापक होता है, और वह निर्भीकता पूर्वक अपने मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इस प्रणाली में सरकार के पास उद्योग-सम्बन्धी कोई खास कार्य करने को नहीं होता। प्राचीन अर्थशास्त्रियों में जे. बी. मे, डेविड रिकार्डों, मिल आदि इस सिद्धान्त के कटु पक्षपाती थे और उन्होंने इस विचार का काफी प्रचार किया।

'स्वतन्त्र-व्यापार' (free trade) की नीति कुछ काल तक तो मान्य रहा पर बाद में इस सिद्धान्त की आलोचना होने लगी। इसकी आलोचना के मुख्य आधार इसमें पाये जाने वाले दोष थे। इस प्रथा में गलाकाट प्रतिस्पर्धा, 'स्वार्थान्धता', पारस्परिक शोषण, व्यापार-चक्र, तथा आर्थिक उतार चढ़ाव, और आर्थिक-संकटों के विद्यमान होने के कारण मनुष्यों का विश्वास इस पद्धति पर से उठ गया। मुख्य रूप से पूँजीवाद की कठिनाइयों तथा मदी के अस्तित्व ने लोगों के विचारों को स्वतन्त्र व्यापार की पद्धति की ओर से हटा कर समाजवाद की ओर आकर्षित किया। इसकी प्रमुख आलोचना कीन्स और पीगू ने की। एल. रोबिन्स के विचार यद्यपि इससे मिलते जुलते हैं पर उन्होंने समाजवाद का समर्थन नहीं किया।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही अर्थशास्त्रियों को इस बात का ज्ञान हो गया कि स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था पूर्णरूपेण ठीक नहीं है क्योंकि यह प्रथा स्वयं में पूर्ण नहीं थी, और इसमें भाग और पूँजी की शक्तियाँ उस रूप में कार्य नहीं कर पा रही थी जिस रूप में कि वास्तव में होना चाहिए। 'स्वतन्त्र-व्यापार' की नीति का पतन प्रथम महायुद्ध के समय तक काफी हो चुका था। इसी समय कीन्स (Keynes) की पुस्तक '*End of laissez faire*' (1926) प्रकाशित हुई जिसमें

उन्होंने 'स्वतन्त्र-व्यापार-नीति' के दोषों को सार के सामने रखा। कीन्स के विचारों को उस समय के अर्थशास्त्रियों ने बड़ा महत्त्व दिया। उस समय जो मन्दो और आर्थिक सकट उत्पन्न हुए उन्होंने भी कीन्स के विचारों को सही सिद्ध किया। इन्हीं सब कारणों से उस समय के सभी अर्थशास्त्री जो 'स्वतन्त्र व्यापार-नीति' के विरुद्ध थे, कीन्स के समर्थक हो गये।

धीरे-धीरे 'स्वतन्त्र व्यापार-नीति' का स्थान 'समाजवाद' ने ले लिया। अब यह बात मानी जाने लगी कि केवल 'पूर्ण-समाजवाद' ही 'स्वतन्त्र व्यापार नीति' की बुराइयों को दूर कर सकता है। 'समाजवाद' के अन्तर्गत देश के उद्योग धंधों, व्यापार, विनिमय, उत्पत्ति और वितरण पर सरकार का आधिपत्य हो जाता है। इस विचार की पूर्णता के कारण सभी अर्थशास्त्री इसके समर्थक हो गये। पीगू (Pigou) ने अपनी पुस्तक (*Socialism Versus Capitalism*) में लिखा है, "आर्थिक शान्ति के लिए उत्पत्ति का समाजीकृत होना बहुत आवश्यक है। अतः यह जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। इन्होंने प्रागे लिखा है कि 'केन्द्रीय नियोजन प्रणाली' वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था से कहीं अच्छी है।"¹

प्रो. कीन्स (Keynes) पूर्ण सामाजीकरण के विरुद्ध थे—विशेष रूप से उत्पत्ति के सामाजीकरण के। वे उद्योगों पर सरकार के पूर्ण आधिपत्य के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि राज्य साहसी के सहस्र जिम्मेदारी और कुशलता से उद्योग नहीं चला सकता। इसका कारण यह है कि राज्य को साहसी की तरह लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होता है। उनके विचार से समाजवाद और व्यक्तिवाद में विरोध बिल्कुल तथ्यहीन है। उनके विचार में देश की सर्वोत्तम अर्थव्यवस्था वह है जिसमें स्वतन्त्र व्यापार राज्य की देखभाल में हो। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य के आर्थिक विकास में यदि राज्य और साहसी दोनों मिल कर प्रयास करें तो बहुत अच्छा हो। 'स्वतन्त्र व्यापार' पद्धति का अन्त सबसे पहले इस में हुआ और उसके स्थान पर सार्वजनिक अर्थव्यवस्था की अपनाया गया।

इस में आर्थिक नियोजन का संयोजन आर्थिक उन्नति और नियोजन की पूर्व आवश्यकताओं (Pre-requisites) के साथ पिछली कई दशकियों (Decades) से बढ़ता चला जा रहा है। वास्तव में किसी देश में आर्थिक नियोजन को सफलता सभी प्राप्त हो सकती है जब कि नियोजन बनाने के लिए जिन तथ्यों (Facts & Figures) की आवश्यकता होती है, वह उस देश में पाये जायें। अक्टूबर, सन् १९१७ की क्रान्ति (October Revolution of 1917) के पश्चात् जब रूस में नई सरकार की स्थापना लेनिन के अधीन हुई, तो वह न तो देश के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने और न देश में सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रणयने में शीघ्रता करना

चाहती थी। इसका कारण यह था कि उनके मतानुसार जब तक देश के समस्त श्रमिक शिक्षित होकर नियोजन और देश के शासन को पूर्ण रूप से सभालने योग्य न हों तब तक न तो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो और न सार्वजनिक अर्थव्यवस्था की स्थापना हो।¹ इसके पश्चात् श्रमिकों को आर्थिक नियोजन के विषय में उत्साह प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें कुछ कारखानों को नियंत्रित करने का अधिकार दे दिया गया था। तब तक वहाँ न तो राज्य के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था न व्यविवनन सम्पत्ति का विनाश किया गया और न साहसियों के व्यक्तिगत लाभ को समाप्त किया गया था।

लेनिन का, द्रुत आर्थिक विकास करने के विषय में यह मत था कि देश के समस्त प्राकृतिक साधनों और उत्पात्ति सत्त्वामों का राष्ट्रीयकरण हो।² इस प्रकार धीरे धीरे हम में उत्पात्ति और वितरण का समस्त दायित्व और स्वामित्व सरकार के हाथों में आ गया और केन्द्रीय नियोजन की पद्धति को अपनाया गया। इस में यह कार्य GOSPLAN द्वारा किया गया।

पूँजीवाद के कट्टर समर्थक भी अब इस बात को मानते हैं कि सभार के सभी देशों के नागरिकों में पूँजीवाद के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना जाग्रत हो गई है—विशेष तौर पर जब से रूस और चीन में आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप द्रुत आर्थिक विकास हुआ है। एम० सैल्वेडरी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है, 'सभार के प्राय सभी देशों के निवासी अब इस बात को मानने और समझने लगे हैं कि पूँजीवाद एक निष्कण्ट आर्थिक प्रणाली है। समाजवादी राष्ट्रों में जिनमें समस्त सभार के एक तिहाई मनुष्य रहते हैं—पूँजीवाद की समाप्ति हो गई है। योहप और लैटिन अमरीका के कुछ यक्षतन्त्र देशों में—जहाँ पूँजीवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है—पूँजीवाद की दशा अत्यन्त दयनीय है योहप के देशों में

प्राय भाषी जनता यह चाहती है कि तुरन्त या धीरे धीरे देश में सामुहिक (Collectivism) की स्थापना हो प्राय एक तिहाई इस बात की माग करने हैं कि देश में अप्रत्यक्ष रूप से क्रमशः समाजवाद की स्थापना हो कुछ अर्थ राष्ट्र के निवासियों का ध्येय यह है कि सामाजिक उद्यम पुष्प के द्वारा समाजवाद की स्थापना हो कुछ लोगों की धारणा यह है कि यदि देश में आर्थिक उत्पत्ति करनी है तो वह समाजवादी प्रथा द्वारा ही सम्भव हो सकती है खेद का विषय यह है कि सभार के प्राय सभी व्यक्ति अब यह मानने लगे हैं कि देश के आर्थिक विकास के पथ पर पूँजीवाद बाधक के रूप में खड़ा होता है।'³ यह सब धारणायें

1 V I Lenin Coll Works Russian, III Ed, Vol XXIII, p 251 (Underscored by S G Strumilin)

2 Ibid

3 American Capitalism—Massimo Salvadori (American Reporter Book Supplement, Feb, 27, 1957, p 1)

अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन आदि पूँजीवादी देशों के आर्थिक विकास को देखते हुये भी फँस रही है। वास्तव में संसार के प्रायः सभी पूँजीवादी देश अब पूँजीवाद में ही सुधार करने की चेष्टा कर रहे हैं।

चीन दूसरा देश है जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था को सफलता के साथ सामाजिकरण हो गया है। चीन में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करने का केवल एक ही ध्येय था—समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना। इसके द्वारा वे पूँजीपतियों के शोषण और जमींदारी तथा अन्य इसी प्रकार की प्रथाओं को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते थे। आज चीन में उत्पाति और वितरण के समस्त साधनों का स्वामित्व, नियन्त्रण और प्रवन्ध राष्ट्र के हाथ में है..... चीन में जन क्रान्ति के बाद जब नई सरकार की स्थापना हुई थी तभी इस बात का निश्चय कर लिया गया था कि देश के समस्त उद्योग-वधों का राष्ट्रीयकरण पूँजीपतियों को कोई मुआवजा दिए बिना ही कर दिया जायगा। परन्तु बाद में चीन के नेताओं ने ऐसा करने से चीन की जनता को रोका और वहाँ भी समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना धीरे-धीरे हुई। चीन में जो प्रथम और द्वितीय योजनाएँ बनाई गई हैं उनका उद्देश्य यही है कि देश का आर्थिक विकास हो, व्यक्तिगत आय में वृद्धि हो, एवं देश के समस्त उत्पाति के साधनों और वितरण का क्रमशः राष्ट्रीयकरण हो जाय।

२—मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ

(Characteristics of Mixed Economy)

मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत सार्वजनिक उद्योग तथा व्यक्तिगत उद्योग साथ-साथ कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था दो असंगत प्रमाण विचारों के अर्थशास्त्रियों के सामञ्जस्य का फल है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार देश के समस्त उत्पादन साधनों, और आर्थिक क्रियाओं का एक साथ (en masse) राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक है। जबकि अन्य कुछ अर्थशास्त्रियों ने स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन किया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पाति तथा वितरण की जिम्मेदारी राज्य तथा साहसियों—दोनों पर होती है।

ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, फ्रांस आदि देशों में—जहाँ स्वतंत्र व्यापार है—बहुत तीव्रता से औद्योगिक विकास हो रहा है तथा दूसरी ओर राज्य द्वारा संचालित आर्थिक नियोजनों ने रूस, चीन आदि देशों में बड़ा चमत्कार दिखाया है। स्वतंत्र व्यापार नीति तथा केन्द्रीय नियोजन दोनों में ही कुछ गुण तथा दोष हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का विभाजन सार्वजनिक उद्योग तथा व्यक्तिगत उद्योग में होता है। दोनों ही, व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित के उद्देश्य

से कार्य करते हैं। 'मिश्रित अर्थव्यवस्था में साहसी बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य करता है' पर जहाँ साहसी देश की आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण कार्य करता है, वहाँ इसके ऊपर राज्य का अकुश रहना है जिसके सामने सारे देश की उन्नति का ध्यान रहता है। इसी विचार को लेकर राज्य साहसी के उन कार्यों को नियंत्रित करता है जिनके द्वारा देश की आर्थिक प्रगति होती है।¹

मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाये जाने के कारण

१—व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक दोनों ही उद्योगों के पास पूँजी का अभाव—प्रविकसित देशों में साहसी तथा राज्य दोनों ही के पास पूँजी का अभाव होता है। अतः दोनों में से कोई भी अकेला उतनी पूँजी का विनियोग नहीं कर सकता जितनी कि आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। दोनों ही एकाकीरूप में बड़ी बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने में असमर्थ होते हैं। अतः ऐसी अवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था बन जाती है।

२—कुशल व्यक्तियों का अभाव—मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का यह एक कारण है। प्रायः यह देखा जाता है कि देश में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव होता है। यदि देश के समस्त आर्थिक प्रयासों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया जाता है तो विशेष प्रकार के शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की कमी का अनुभव होता है।

३—देश की आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र का विभाजन—व्यक्तिगत और सार्वजनिक उद्योग में अन्तर कर देने से कार्य-संचालन अधिक सुगमता से तथा प्रभावशाली रूप से किया जा सकता है। यह काम 'स्वतंत्र व्यापार' या पूर्ण राष्ट्रीयकरण में प्राप्त नहीं हो सकता।

४—मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूँजीवाद के सारे गुण तो पाये जाते हैं पर उसके दोष नहीं आने पाते क्योंकि इस नीति में पूँजीवाद को एक निश्चित सीमाओं में पनपने दिया जाता है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में तीन आर्थिक क्षेत्र होने हैं, यथा

१ सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector)—इस क्षेत्र के अन्तर्गत देश की उन्नति और वितरण का प्रबन्ध, स्वामित्व, संगठन और आर्थिक संचालन राज्य द्वारा होता है। व्यक्तिगत साहसियों को इस क्षेत्र में कोई स्थान नहीं होता। प्रतिरक्षा तथा सामरिक महत्त्व के उद्योग इसके उदाहरण हैं।

२ सार्वजनिक-व्यक्तिगत क्षेत्र (Public-cum-Private Sector)—इस क्षेत्र के अन्तर्गत देश के उद्योगों का प्रबन्ध और स्वामित्व सरकारी तथा गैर सर-

कारी क्षेत्रों में विभाजित होता है। इसमें सरकार अपना प्रभुत्व स्थापित रखने तथा प्रबंध में अपना स्वामित्व कायम रखने के लिए पूरी पूँजी का ५१ प्रतिशत विनियोग करती है और विनियोग का बाकी ४९ प्रतिशत भाग गैरसरकारी क्षेत्र के लिये छोड़ देती है। मध्यम माना की उत्पत्ति संस्थायें तथा उपभोग की वस्तु के उद्योग इस श्रेणी में आते हैं।

३. निजी क्षेत्र (Private Sector)—इस क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योगों का प्रबंध, आदिक-मंचालन, तथा संगठन पूर्णरूपेण व्यक्तिगत साहसियों के हाथ में होता है। इसके अन्तर्गत कुछ उपभोग की वस्तुएँ बनाने के उद्योग तथा कम महत्व वाले उद्योग आते हैं।

यह विभाजन बिल्कुल अपरिवर्तनीय नहीं है। इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।

३—भारतवर्ष में मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy in India)

भारतीय सरकार द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा नागरिकों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए अपनाया गया है। देश की द्रुत आर्थिक उन्नति के लिये कृषि, उद्योग, यातायात और संचारवाहन के साधनों आदि का उत्तम होना और देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्णरूपेण उपयोग होना अति आवश्यक है। इन सब बातों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है तथा नियोजन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए और सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ी मर्यादा में प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। उचित रूप से उत्पादन और वितरण के कार्य को चलाने के लिए भी पूँजी की आवश्यकता होती है। वर्तमान काल में समस्त आवश्यक पूँजी का विनियोग न तो केवल सरकार द्वारा और न एकाकी रूप में हो सकता है। यही कारण है कि सरकार ने मिश्रित-अर्थव्यवस्था पद्धति को अपनाया ताकि सरकार और साहसियों के सम्मिलित प्रयास द्वारा देश की द्रुत आर्थिक उन्नति सम्भव हो सके।

प्रधानमंत्री ने भी कहा कि “देश में राजकीय और व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था के आपसी विरोध की बड़ी चर्चा है” उन्होंने कहा कि “इसमें कोई विरोध नहीं है। कुछ लोगो का मत है कि निजी उद्योग को पूर्ण और निर्बाध अवसर मिलना चाहिए। पर इस प्रकार का निर्बाध निजी उद्योग असम्भव है और राज्य को बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करना पड़ता है। हम अपने सीमित साधनों को देखते हुए स्वतंत्र व्यापार नीति को नहीं अपना सकते। हमें हर उद्योग में, चाहे वह राजकीय हो या निजी, एक नियोजित व्यवस्था का निर्माण करना है। निजी उद्योग को विस्तार के लिए काफी क्षेत्र मिलना चाहिए पर उसे राजकीय नियोजन के अन्तर्गत ही चलना पड़ेगा। ऐसा नियोजन बिल्कुल बेकार होगा जिसमें देश की भारी क्रियायें सम्मिलित

न हो चाहे वह राजकीय हो या निजी। सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक विस्तृत और सुव्यवस्थित होना पड़ेगा।¹

मिश्रित ग्रन्थव्यवस्था पश्चिमी देशों में तो पहले से ही विद्यमान थी पर भारतवर्ष में इसका प्रादुर्भाव हाल ही में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हुआ है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले देश में राजकीय उद्योग इतनी उन्नति पर नहीं था। केवल कुछ विभाग ही जैसे, रेल यातायात, डाक-तार विभाग, रिजर्व बैंक, प्रतिरक्षा विभाग आदि राजकीय उद्योगों के अंतर्गत थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार ने कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में उन्नति करके देश के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास शुरू कर दिया। इन सब बातों के लिए, तथा अन्य उन्नत देशों के मुकाबले में आने के लिए, एक ऐसी व्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता हुई जिसके द्वारा कम से कम कठिनाई से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। कुछ समय तक हमारी राष्ट्रीय सरकार एक ऐसी पद्धति की खोज करती रही जिससे देश के उद्योगों का सन्तुलित विकास हो सके। उस समय न तो सरकार ही इस स्थिति में थी कि वह समस्त उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सके और न चाहती बग ही देश का औद्योगीकरण करने में समर्थ था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही मिश्रित ग्रन्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत की प्रथम, द्वितीय और तृतीय पञ्चवर्षीय योजनाएँ इसी आधार पर निर्मित की गई हैं।

(४) सार्वजनिक क्षेत्र (The Public Sector)

‘सार्वजनिक क्षेत्र’ का विचार भारतवर्ष के लिए नया ही है, पर पश्चिमी देशों में इसका विकास पिछले कई वर्षों से हो रहा है। समाजवादी देशों में तो यह प्रथा काफी उन्नति पर है। भारतवर्ष में ‘सार्वजनिक क्षेत्र’ की स्थापना सन् १९४८ के औद्योगिक प्रस्ताव के कारण हुई। राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त ने (तथा इस विचार ने कि जो उद्योग निजी क्षेत्र द्वारा चलाये जायेंगे उनका भी राष्ट्रीयकरण हो सकता है तथा उनका संचालन राज्य द्वारा बनाए कानून के अन्तर्गत ही हो सकेगा) देश के तत्कालीन सारे आर्थिक ढाँचे को बदल दिया तभी से सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी तेजी के साथ उन्नति हो रही है।

सन् १९४८ के औद्योगिक प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित पाँच बग के उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में रखे गये —

- (१) प्रतिरक्षा तथा सामरिक महत्व के उद्योग (Defence Industries)
- (२) लोकोपयोगी सेवाएँ (Public utility Services)
- (३) भारी उद्योग (Heavy Industries)
- (४) जहाज बनाने का उद्योग तथा (५) अन्य योजनाएँ।

1 *Planning and Development*, Speeches of Jawahar Lal Nehru (1952 56), Publications Division, Govt of India p 24

प्रथम योजना में सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक योजनायें :¹

(अ) केन्द्रीय सरकार

लोहा और इस्पात योजना, ३००० लाख रुपया, जहाज निर्माण, १४०८ लाख रुपया, मशीन यन्त्र कारखाना, ६६३८ लाख रुपया, चिन्दरी का रासायनिक कारखाना, ६०३ लाख रुपया, रेल के इंजिन का कारखाना, ४७३ लाख रुपया, रेल-डिब्बा कारखाना, ४०० लाख रुपया, पेंसिलीन कारखाना, २०६६ लाख रुपया, राष्ट्रीय यन्त्र कारखाना, १८२ लाख रुपया, भारतीय टेलीफोन उद्योग, १३० लाख रुपया, हिन्दुस्तान केमिस्ट लि०, १२६७ लाख रुपया, मन्डो का नमक कारखाना, १०० लाख रुपया, दुधन मिट्टी कारखाना, ५४ लाख रुपया, डि० डि० टि० कारखाना, ३६१ लाख (डाँतर), नमक के चालू कारखाने, ५० लाख रुपया, आवात कारखाना, ११८ लाख रुपया, अन्य योजनायें, २०२१ लाख रुपया।

(ब) राज्य सरकारें

मैसूर लोहा और इस्पात कारखाना, २८३ लाख रुपया, उत्तर प्रदेश सरकार का सोमेट कारखाना, २३०५ लाख रुपया, नेपा मिल, २०० लाख रुपया, सरिसक लि०, २०० लाख रुपया, सीनूर फागज मिल, ६० लाख रुपया, उत्तर प्रदेश सूदम (Precision) यन्त्र कारखाना ५०२ लाख रुपया, बिहार सरकार का सुपर फाउण्टेन कारखाना, ४११ लाख रुपया, अन्य योजनायें, ६५ लाख रुपया। (प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, जनता वक्ता, भारत सरकार, पृष्ठ २६५-२६६)।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र :²

बड़ी कार्गिड्यो, लोहे तथा इस्पात बनाने के कारखाने तथा औद्योगिक मशीनें :

चितरजन कारखाना की १२० से ३०० तक इन्जन प्रतिवर्ष बनाने की योजना है, जिससे रेल के लिये बड़े बड़े इन्जनों के काम इन्वेष्ट में ही किए जा सकें। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निषम की यह भी योजना है कि बड़ी फाउन्ड्रियो, लोहे की मशीनो और बड़े बड़े डॉबो के बनाने का काम शुरू किया जावे, जो बड़ी बड़ी मशीनो, उनके पुराने और रिजली के भारी सामान आदि के निर्माण के लिए आवश्यक है।

सार्वजनिक क्षेत्र में जिन भारी मशीन उद्योगों के लिये व्यवस्था की गई है, वे हैं—बिजली का भारी सामान निर्माण करना (लगत २० करोड़ रु०) हिन्दुस्तान पब्लिक औद्योगिक कारखाने का विस्तार और नेशनल इन्स्टिट्यूट डेवेलपमेंट कारपोरेशन के मातृ भारी औद्योगिक मशीनें और उनके पुर्जे निर्माण करना। इससे भारी औद्योगिक मशीनरी का विकास करना सुगम हो जायगा।

दक्षिण धारकाट लिफ्टाइट योजना—दक्षिण भारत में कोयले की खानों

१ प्रथम पञ्चवर्षीय योजना—भारत सरकार

२ द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना (संक्षिप्त)—भारत सरकार।

की कमी के कारण दक्षिण आरकाड की नेवली की बहुमूत्री लिंगनाइट योजना को उच्चतम प्राथमिकता दी गई । योजना यह है कि ३५ लाख टन लिंगनाइट की प्रतिवर्ष खुदाई की जाये, (अ) जिससे २,११,००० किलोवाट विजली पैदा की जायेगी, (घा) प्रतिवर्ष ३,८०,००० टन कार्बोनाइट ब्रिकेट तैयार किये जायेंगे, और (३) यूरिया और सल्फेट नाइट्रेट के रूप में ५०,००० टन निश्चित नत्रजन पैदा किया जायगा । योजना पर आरम्भ में ५२ करोड़ रु० खर्च किया जायगा और बाद में आवश्यकतानुसार अधिक रकम लगाई जायेगी । इस योजना पर कुल खर्च का प्रारम्भिक अनुमान ६८ करोड़ रुपया लगाया गया है ।

उबरंक का उत्पादन—नत्रजन के उत्पादन में ४७,००० टन की वृद्धि करने के लिए निश्चित कदम उठाए जा चुके हैं । इसके लिए सिन्धी खाद फैक्टरी का विस्तार किया गया है, जिससे उसके कोक की भट्टी का गैस का उपयोग किया जा सकेगा । दक्षिण आरकाड की लिंगनाइट योजना की ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है । इसके अलावा दो नए कारखाने कायम किए जायेंगे । एक नगल में जो प्रतिवर्ष ७०,००० टन नत्रजन पैदा करेगा और दूसरा कुरकेला में जो ८०,००० टन नत्रजन पैदा करेगा । नगल के कारखाने के लिये २२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । कुरकेला के सयन के लिये फिलहाल ८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और आवश्यकता के अनुसार अधिक रकम भी खर्च की जा सकेगी ।

इन्जीनियरी के बड़े उद्योग—हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार करने के कारण विशाखापटनम् में जहाजों के उत्पादन में पहले तो पुरानी किस्म के ६ और नई किस्म के चार जहाज बनाये जायेंगे । जहाजों के निर्माण के उद्योग का विकास करने के लिये अन्य योजनाओं में एक योजना विशाखापटनम् में एक नया शिपयार्ड बनाने की है और ७५ लाख रुपये की व्यवस्था इसलिए की गई है कि उसके लिए प्रारम्भिक कार्य शुरू किया जा सके और साथ ही बड़े जहाज डीजल इंजन के बनाने की भी योजना है जिनके लिए यथा समय आवश्यकतानुसार धन राशि की व्यवस्था की जायेगी ।

चित्तरंजन इंजन कारखाने के विस्तार के अलावा रेल सामग्री सम्बन्धी योजनाओं में निम्न योजनाएँ सम्मिलित हैं जिनमें रेल के डिब्बे तैयार किए जायेंगे ।

१—देराबूर में जोड़हीन डिब्बे बनाने के कारखाने का निर्माण पूरा करना,

२—छोटी लाइन के डिब्बों के निर्माण के लिए नया कारखाना कायम करना, और

३—फालतू पुर्जों बनाने के लिए दो छोटे इन्जीनियरी कारखाने खोलना । इन सारी योजनाओं के लिए १७ करोड़ रु० रखा गया है ।

केन्द्रीय सरकार की दूसरी कम खर्च की योजनाएँ निम्नलिखित हैं—

१—वर्तमान डी० डी० टी० और एटिवायोटिक कारखानों का विस्तार ।

२—निवाकूर कोचीन में दूसरे डी० डी० टी० कारखाने का निर्माण ।

३—हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स फैक्टरी और इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज का विस्तार, तथा

४—सिवयुरिटियो और बाडो के लिए कागज बनाने की सिवयुरिटी पेपर मिल की स्थापना ।

विभिन्न राज्यों की औद्योगिक योजना कार्यों में निम्न उद्योगों का उल्लेख किया जा सकता है—मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स का विस्तार, दुर्गापुर में कोक भट्टी का निर्माण, मैसूर और बिहार में बिजली के पोर्सलीन इन्सुलेटरो का निर्माण, हैदराबाद की आगा टूल कारखाने का पुनर्गठन और उत्तर प्रदेश की सीमेट फैक्टरी तथा सुपरफास्फेट कारखाने का विस्तार ।

नये इस्पात कारखानों के साथ कोक की भट्टियों के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर की कोक भट्टी की योजना के और दक्षिण भारकाडु की लिगनाइट योजना का प्रारम्भ होने पर आर्गेनिक रासायनिक पदार्थ बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे घरेलू खपत के लिए रासायनिक पदार्थों प्लास्टिक और रंग के उद्योग पनप सकेंगे ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक योजना कार्यों पर जिसमें नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए नियत की गई धन राशि शामिल नहीं है, मोटे तौर पर ५ अरब २ करोड़ रुपया खर्च किया जावेगा । विभिन्न राज्यों का खर्च अपनी योजनाओं पर ३२ करोड़ रुपया कूता गया है । इसमें वह ५ करोड़ रुपया भी शामिल है जो सहकारिता के आधार पर विभिन्न राज्यों में चीनी के कारखाने कायम करने में लगाया जायगा । आसाम तथा पाण्डेचैरी सरीखे राज्यों में कुछ विशेष उद्योगों के विकास के लिए बतौर सहायता के दी जाने वाली रकम भी इसमें सम्मिलित है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम—वाणिज्य उद्योग मन्त्रालय के लिए निर्दिष्ट की गई ७० करोड़ रुपये की रकम के अलावा ५५ करोड़ रुपये की रकम राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के लिए रखी गई है । इन साधनों का एक हिस्सा (मोटे तौर पर २४ से २५ करोड़ रुपए) कपड़े और पटसन के उद्योगों के प्राधुनिकीकरण पर खर्च किया जायेगा, शेष रकम जो ३५ करोड़ रुपये के लगभग कूती गई है, नये मूल-भूत और बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उपलब्ध की जायेगी । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने जिन औद्योगिक योजनाओं के सम्बन्ध में जाँच पड़ताल करनी शुरू की है उनमें फाउड्रियाँ, लोहे की भट्टियाँ, बड़े-बड़े ढाँचों के निर्माण तथा रिफ़ैक्टरियो, नक्ली रेशम के लिए रासायनिक सुगदी, अखबारी नागज आदि, रंगों और दवाओं के बनाने वाले पदार्थ, कार्बन, अल्यूमिनियम, भारी सामान को इधर से उधर ले जाने वाले बड़े बड़े साधनों का निर्माण, खदानों की खुदाई आदि, लोहा तथा लोहेतर उद्योगों के लिये रोल और रोलिंग मिल के समान का

निर्माण शामिल है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए निगम को भविष्य में अधिक धनराशि की आवश्यकता हो सकती है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र¹

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में उसी प्रणाली पर कार्य होगा जैसा कि सन् १९५६ के Industrial Policy Resolution में बताया गया है या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है। भारी उद्योग, सामरिक महत्व के उद्योग और अन्य भारी उद्योग अब भी सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहेंगे। इसी के साथ-साथ तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह भी बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत और अधिक कारखाने तथा उद्योग बन्दे स्थापित किये जायेंगे। अधिकतर नये उद्योगों की स्थापना भी इसी क्षेत्र में होगी। इसके अतिरिक्त जब और जैसा आवश्यक समझा जायेगा उसी तरह से उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके इस क्षेत्र का विकास किया जायेगा। जिन उद्योगों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में शुरू की जायेगी परन्तु ममत्त न हो सकेगी—उनको तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में पूरा किया जायेगा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उन्नति की निम्नलिखित प्राथमिकताओं को स्वीकृत किया गया है

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में जो कार्य शुरू किये गये हैं या किये जायेंगे उनको समाप्त करना।

(२) भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन बनाने के कारखाने, यंत्र और कल पुर्जों के कारखाने, लौह और इस्पात बनाने के कारखाने और रासायनिक खाद बनाने के कारखानों को स्थापित करना और जो पहले से ही हैं उनका विकास करना।

(३) 'उत्पादक वस्तुओं' (Producer goods) की उत्पत्ति में भारी वृद्धि करना।

(४) जिन उद्योगों की स्थापना की गई है उनमें पूर्ण शक्ति से काम किया जाना।

(५) धोपध, कागज, यस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल और मकान बनाने की विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का अधिकतम मात्रा में देश में ही उत्पत्ति किया जाना।

औद्योगिक विकास के लिए पूर्णरूप से २,५०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसका विभाजन इस प्रकार किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर १,५०० करोड़ रुपये खर्च हों और निजी क्षेत्र में १,००० करोड़

1. तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर आधारित।

रुपया । सार्वजनिक क्षेत्र के खर्चों में १० करोड़ रुपये ऐसे भी हैं जो शायद बाद में निजी क्षेत्र को विकास कार्यों के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त हो सकें ।

उपरोक्त २,५०० करोड़ रुपये का विभिन्न उद्योग और खनिज पदार्थों के उपयोग पर निम्नलिखित रूप से बँटवारे का ध्येय बनाया गया है—

व्यय का विभाजन

(करोड़ रु०)

औद्योगिक वर्ग	१९६१-६६ में पूँजी-वित्तियोग
धातु-कर्म और इंजीनियरी उद्योग	१२००
रासायनिक और सम्बद्ध उद्योग (भारी रसायन, उर्वरक, औषध, प्लास्टिक-पदार्थ, रज्जक, सीमेंट, कागज आदि)	६५०
कपड़ा उद्योग	१२५
खाद्य-उद्योग	७५
खनिज पदार्थ	४०५
विविध (इसमें सरकारी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए छोटे नगर और आवास-बस्तियाँ भी शामिल हैं)	४५
योग	२५००

तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों का मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है —

(क) वे परियोजनाएँ, जिन पर अमल हो रहा है, और जो दूसरी योजना पार करके तीसरी योजना की परिधि में आई हैं,

(ख) नई परियोजनाएँ, जिनके लिए विदेशों से ऋण का आश्वासन मिल चुका है ।

(ग) नई परियोजनाएँ, जिन्हें फिलहाल योजना में माना जा सकता है । इसमें से अधिकतर तैयारी के काफी आगे के दौर में हैं किन्तु इनके लिए विदेशों से ऋण का अभी कोई इन्तजाम नहीं किया गया ।

(घ) अन्य नई परियोजनाएँ, जिन पर आरम्भिक काम कुछ खास आगे नहीं बढ़ा और जिनके लिए अभी विदेशों से ऋण का भी कोई इन्तजाम नहीं किया गया ।

(ङ) अनुपांगक ढंग की परियोजनाएँ, जिनकी क्रियान्विति ऐसी कुछ बातों पर निर्भर होगी, जिनके सम्बन्ध में अभी से कोई निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता ।^१

सार्वजनिक क्षेत्र की कठिनाइयाँ तथा दोष :

१—संगठन सम्बन्धी—सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास और उन्नति में सबसे बड़ी बाधा प्रबन्ध सम्बन्धी होती है। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के प्रबन्धों का प्रचलन विभिन्न समयों में किया गया। परन्तु प्रत्येक प्रकार के व्यवसायिक संगठन में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ पाई गईं। मैनेजिंग एजेंट्स (Managing Agents) द्वारा प्रबन्धित व्यवसायों में भी बहुत सी बाधाएँ हैं, जिनके कारण इस प्रथा को सर्वोत्तम नहीं समझा जाता है। इसी प्रकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रबन्धित व्यवसायों में भी संगठन सम्बन्धी कठिनाइयाँ हैं। संगठन के विषय में समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किये जाने के पश्चात् अब अधिकतर संस्थाओं में प्रायः अर्ध-स्वतन्त्र संगठन प्रणाली अपनाई जाती है। सार्वजनिक उद्योगों का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि निजी लाभ की सम्भावना न होने के कारण संगठनकर्ता उतने उत्साह, उद्यम और कुशलता से प्रबन्ध का कार्य नहीं करते, जितना निजी क्षेत्र में करते हैं।

२—मूल्य-निर्धारण और उपभोक्ता—सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन से प्रायः उन्हें प्रतिस्पर्द्धा का सामना नहीं करना पड़ता है जिससे कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी एकाधिकार की स्थापना हो जाती है। इस परिस्थिति में उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को उभी कीमत पर खरीदना पड़ता है जिस पर सरकार उन्हें बेचना चाहती है। यह कीमत प्रायः प्रतिस्पर्द्धात्मक दर से अधिक होती है। यदि हम प्रकार की अवस्था सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के पश्चात् भी विद्यमान रहे तो इसका अर्थ यह होगा कि सरकार अपने उद्देश्य में सफल रही, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना का एक प्रमुख कारण उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तुओं को दिलाना होता है।

३—अधिको की मांग—सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पत्ति होने में कारखानों की संख्या कम हो जाती है, पूँजी-प्रमुख-प्रणाली से उत्पत्ति होती है एवं उद्योगों के क्षेत्र में अभिनर्वाकरण की वृद्धि आनाई जाती है। इससे देश में बेरोजगारी फैल जाती है और नियोजन के प्रमुख उद्देश्य—जीवन स्तर को ऊँचा उठाना एवं रोजगार दिवाना अपूर्ण रह जाने है।

४—सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और विकास यदि निरन्तर बढ़ता रहे तो देश में एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि इन उद्योगों में सलग राज्य कर्मचारियों के हाथ में अत्यधिक शक्ति आ जाये और वे उस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दें। इससे देश की आर्थिक अवस्था में सुधार न हो कर अवनति होगी और देश की जनता में सरकार के प्रति विद्वेष उत्पन्न हो जायेगा—जो अवांछनीय है।

५—यदि सार्वजनिक क्षेत्र का विकास निरन्तर और तीव्र गति से होता ही रहे तो उससे एक कठिनाई यह भी उत्पन्न हो सकती है कि सरकार को कर और

मालगुजारी के रूप में जो धन प्राप्त होता है वह मिलना बन्द हो जाये, क्योंकि जब अन्य उत्पादक ही न रहेगे तो उनसे कर आदि कैसे मिल सकेगा। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

६—सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में प्रायः यह भी देखा जाता है कि महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति भी होती है जिन्हें उद्योग सम्बन्धी विषयों का कोई ज्ञान नहीं होता।

७—इस क्षेत्र के विकास पर सरकार को बहुत धन खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण जनहिन और जन कल्याण के कार्यों के विस्तार के लिए सरकार के पास काफी धन नहीं बच पाता जिससे जन कल्याण के कार्य उपेक्षित रह जाते हैं।

उपयुक्त बातों से यह न समझ लेना चाहिये कि उद्योग धन्धों के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना और विकास से केवल हानियाँ ही हैं। सच तो यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगधन्धों की स्थापना से देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ होता है। पूँजीपतियों का शोषण समाप्त हो जाता है, वस्तुएँ सरलता से तथा सस्ते दामों पर प्राप्त होती हैं। अति उत्पादन और कम उत्पादन की सम्भावना नहीं रहती एवं आर्थिक तेजी और मन्दी भी समाप्त हो जाती है। उद्योग धन्धों का संतुलित विस्तार होता है। देश के प्राकृतिक साधनों का सही शोषण सम्भव होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। धन का वितरण समान होता है।

५—निजी क्षेत्र का विकास

(Private Sector)

द्वितीय योजना में ।¹

सार्वजनिक क्षेत्र के समान निजी क्षेत्र में भी लोहे और इस्पात के उद्योगों के लिए विशेष महत्त्व है। १ अरब १५ करोड़ रुपये के इस क्षेत्र में विनियोग होना की कल्पना की गई है। निजी क्षेत्र में इस्पात के उद्योगों का वर्तमान उत्पादन २३ लाख टन हो जाना की आशा है जबकि इस समय वह १२॥ लाख टन ही है।

अन्य धातु सम्बन्धी उत्पादन के लक्ष्य, जैसे कि अल्युमिनियम और फेर्रोमैंगनीज के क्रमशः ३० ००० और १,७२,००० टन स्थिर किए गए हैं।

सीमेंट तथा रिफ़ाइनरी उद्योगों का वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः १ करोड़ ६० लाख टन और १० लाख टन १९६०-६१ तक के लिए स्थिर किया गया है, जब कि १९५५-५६ में उत्पादन क्रमशः ४६ लाख ३० हजार टन और ४,४४,००० टन था।

छोटे और बड़े इंजीनियरी कारखानों के लिए विकास का जो कार्यक्रम निश्चित किया गया है, वह विशेष महत्वपूर्ण है। ढाँचों के निर्माण, मोटर गाड़ियाँ,

1 द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना—भारत सरकार।

रेल के इ जन व डिब्बे, ढलाई व पिटाई के काम, औद्योगिक मशीनों, वाइसकिल, सीने की मशीनें, मोटरों और ट्रान्सफार्मर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए लैंचे पैमाने के उत्पादन की कल्पना की गई है। टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा प्रतिवर्ष जो १०० इ जन तैयार किए जाते हैं, उनका उत्पादन दुगुना करने के लिए १ करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था करने का अनुमान है। मोटर गाड़ियों के उद्योगों के विकास के कार्यक्रम से, देशी उद्योग इस धन्दे की ८० प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति करेगे। ट्रकों के उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया है। १९६०-६१ तक जो ५७,००० गाड़ियां तैयार की जाएंगी, उनमें ट्रकों की संख्या ४०,००० होगी।

निजी क्षेत्र के लिए बनाई गई योजना में औद्योगिक मशीनों के उत्पादन का विस्तार सम्मिलित किया गया है, और मूली कपड़ा मिल मशीनों, पटसन मिल मशीनों, चीनी मिल मशीनों, कागज मिल मशीनों, सीमेंट मिल मशीनों, हलै-कट्रिक मोटरों और विजलों के ट्रान्सफार्मर (३३ के वी ए से कम) के उत्पादन लक्ष्यों की सिफारिश की गई है। अधिकांश इंजीनियरी उद्योगों के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता अपेक्षित है, और उसके लिए आवश्यक कार्रवाही की जा रही है। सोडाऐश, कास्टिक सोडा, फास्फेटिक खादों, औद्योगिक विस्फोटक पदार्थों, रंग और तत्सम्बन्धी पदार्थों आदि के रासायनिक उद्योगों के विकास को निजी क्षेत्र के कार्यक्रम में विशेष महत्त्व दिया गया है। विकास के कार्यक्रम में उत्पादन की मात्रा का बढ़ाना और क्रमानुसार उत्पादन में रद्दोबदल करते रहना सम्मिलित है। रंगों से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों में जिनके उत्पादन को विशेष महत्त्व दिया गया है वलेरो वैनजीन, नाइट्रोबैनजीन, टोल्यून, नैफ्थलीन और ऐन्थाक्विनाइन पदार्थों को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। गन्धक के तेजाब का उत्पादन उस माँग पर निर्भर करता है जो सोडा व इस्पात, रासायनिक खाद, नकली रेधम और सूती उद्योग के लिए की जाएगी।

विद्यालयापट्टनम में कालटेक्स के शोध कार्य के लिए बनाये जाने वाले कारखाने के १९५७ तक तैयार हो आने की आशा है और दूसरी योजना में उसके लिए १० करोड़ ६० की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक और शक्ति सुरासार के उत्पादन को विशेष रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इस समय के २ करोड़ ७० लाख गैलन के उत्पादन को ३ करोड़ ६० लाख गैलन तक पहुँचाया जाएगा। डी०डी०टी० के उत्पादन में विस्तार और पोलिविनल क्लोराइड और बुटेडाइन के उत्पादन की व्यवस्था कुछ ऐसी दिशा में है, जिससे औद्योगिक सुरासार का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जा सकता है। प्लास्टिक उत्पादन के क्षेत्र में हाल ही में जो योजना स्वीकार की गई है, उनमें सैल्यूलोज एमीटेट, पोलिथाइलीन, पोलिविनल क्लोराइड एण्ड क्लोरिया फॉर्मलडिहाइड (Klonde and Una Formaldehyde) के उत्पादन को सम्मिलित किया गया है, और यह आशा की गई है कि ऐसा होने पर मोल्डिंग

पाउडरों का जो उत्पादन १९५५-५६ में १,१८० टन है, वह दूसरी योजना के अंत तक ११,४०० टन तक पहुँच जायेगा।

उपभोग्य पदार्थों में उत्पादन शत-प्रतिशत बढ़ाने की कल्पना की गई है, जैसे चांगज तथा पुट्टे के उत्पादन में। चीनी के उत्पादन को जो १९५५-५६ में १६ लाख ७० हजार टन है, १९६०-६१ तक २२ लाख ५० हजार टन तक बढ़ाने की प्राप्ति है। इसमें सहकारी आधार पर कायम की जाने वाली चीनी मिलों के उत्पादन का हिस्सा ३५ हजार टन सालाना होगा। जनस्पति तेलों के उत्पादन १७ लाख टन से २१ लाख टन तक बढ़ जाने की आशा है। विकास कार्यक्रम में विनोद के तेल और विशेष प्रक्रिया से खनी से तेल के उत्पादन को विशेष महत्त्व दिया गया है। कपड़े और सूत के उत्पादन को क्रमशः ८५ अरब गज और १ अरब ९५ करोड़ पौंड तक बढ़ाना निश्चित किया गया है। मिल्स और विकेंद्रित उत्पादन में इस उत्पादन को बाँटा जाना अभी छेप है। इस समय तक जितने तकुए तंगे हुए हैं, और जिनके लाइसेंस दिए जा चुके हैं, वे १८ अरब ५ करोड़ पौंड सूत पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं। रामायनिक उद्योग को उस कार्यक्रम से विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, जो रंगों के मध्यवर्ती पदार्थों के, जिसके लिए विशाल कच्चे माल की आवश्यकता होगी, उत्पादन के लिए बनाया गया है। विटामिन पैदा करने के क्षेत्र में, विटामिन 'ए' के कच्चे पदार्थों से पैदा करने की संभावनाओं और लेमन ग्रास तेल के उत्पादन की योजना की परीक्षा की जा रही है। आया है कि रामायनिक क्षेत्र में वर्तमान कारखाने, विशेष विकास कर सकेंगे। इस समय जो प्रक्रिया चल रही है, उसका उद्देश्य वास्तविक उत्पादन करना है। यह प्राप्ति की जाती है कि निजी क्षेत्र में रासायनिक उद्योगों पर ३ करोड़ रु० लगाया जाएगा।¹

तृतीय पंचवर्षीय योजना और निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्र के विषय में एक पूर्ण सिद्धान्त बनाने के लिए योजना आयोग काफी दिनों से देशी और विदेशी साहसियों से बातचीत करता चला आ रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत इस बात को पूर्ण मान्यता प्रदान की जा रही है कि देश की मर्यादीत उन्नति और औद्योगिक विकास के लिए यह परमावश्यक है कि देश में उद्योगों का विकास सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में हो। इसी के माध्यम से इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि उद्योग विकास के कार्य में भारी उद्योग, मध्यममान के उद्योग, छोटे उद्योग और गृह उद्योग सभी को महत्त्व मिले।

सन् १९५६ की औद्योगिक नीति के अनुसार यह निश्चित किया गया है कि उपभोक्ताओं के महत्त्व की प्राप्ति सभी वस्तुओं और अन्य साधारण महत्त्व की वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति निजी क्षेत्र में होगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना

1. द्वितीय पंचवर्षीय योजना—भारत सरकार।

2. तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा—भारत सरकार।

में इस नीति का पूर्ण रूप से अनुकरण किया गया है और तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि निजी क्षेत्र का विकास इसी नीति के अनुसार ही होगा। उद्योगों की स्थापना के लिए जिन २,५०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है उनमें से १००० करोड़ रुपये का विनियोग निजी क्षेत्र में होगा।

निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और विकास कार्यों के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएँ निश्चित की गई हैं —

१—द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रारम्भ होने वाले उद्योगों को पूरा करना।

२—निजी क्षेत्र में उन उद्योगों की स्थापना जिनके लिए विदेशी साहसी इच्छुक हैं तथा विदेशी पूँजी प्रादि की व्यवस्था हो चुकी है।

३—उपभोक्ताओं के महत्त्व के उद्योगों को स्थापित करना और उनमें लक्ष्य (Target) के अनुसार उत्पत्ति करना।

४—विभिन्न उद्योगों के लिए सरकार की ओर से जो अधिकतम उत्पत्ति का लक्ष्य निश्चित किया गया है उनको प्राप्त करना।

५—मध्यम आकार के इजीनियरिंग, अलौह (non ferrous) और अन्य रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना।

६—मध्यम और छोटे आकार के उद्योगों की स्थापना और उनका विकास करना।

निजी उद्योग क्षेत्र को विस्तार का काफी अवसर मिलेगा।

भारतव्य के उप-राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने १७ मार्च, सन् १९५५ को बम्बई में वर्मा सैल के उद्घाटन समारोह के अवसर पर कहा था, "भविष्य में होने वाली आर्थिक उन्नति हमारे बीते युग पर निर्भर है। यद्यपि हमारे सामने समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है, पर अभी हमें इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था के यह माने नहीं हैं कि हम देश में प्रचलित सारे उद्योगों का एकदम राष्ट्रीयकरण कर दें और एक नये औद्योगिक युग का निर्माण करें। व्यक्तिगत उद्योग क्षेत्रों को देश के उद्योगों की उन्नति के लिए पूरा अवसर मिलेगा—अगर वे ईमानदारी से राष्ट्रहित के दृष्टिकोण को अपना कर चले।"

निजी क्षेत्र के विकास में सरकारी प्रोत्साहन का अभाव।

टाटा आयरन और स्टील कंपनी के संचालक श्री जहाँगीर गांधी के मतानुसार "इसमें कोई संशय नहीं है कि निजी उद्योग क्षेत्र का देश की आर्थिक व्यवस्था में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या यह अन्त तक बना

रह सकता है ? उत्तर अवश्य ही नकारात्मक होगा क्योंकि निजी उद्योग क्षेत्र में सरकारी प्रोत्साहन का अभाव है। मगर सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कठिनाई है सरकार द्वारा उद्योग नीति में परिवर्तन किया जाना तथा औद्योगीकरण या... मैनेजिंग एजेंसी प्रथा का देश से उन्मूलन, उद्योगों के विकास में मदद गति, कर की भारी दर आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण निजी क्षेत्र के विस्तार की कोई सम्भावना नहीं रह पाती।”

निजी उद्योग क्षेत्र को अधिक सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता है .

इंडियन चैम्बरस ऑफ कामर्स और इंडस्ट्रीज के फ़ेडरेशन (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries) के २८ वें वार्षिक अधिवेशन में एक नई आर्थिक-नीति को अपनाने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें निजी उद्योग क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन देने की चर्चा की गई। इस प्रस्ताव में उक्त नीति को अपनाने के लिए निम्न कारण दिये गये —

१—मैनेजिंग एजेंसी प्रथा तथा निजी उद्योग क्षेत्र में अधिक कार्य कुशल साहसी पाये जाते हैं।

२—निजी उद्योग क्षेत्र देश के उत्पादन की वृद्धि में काफी मदद कर सकता है।

३—निजी उद्योग क्षेत्र में तथा सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र में सहयोग सम्भव है, जिससे देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सारे प्राकृतिक तथा उत्पत्ति के साधनों का सन्तुलित उपयोग सरलता से हो सकता है।

४—राज्य कुछ शर्तें लगा कर देश के औद्योगीकरण का प्रश्न निजी उद्योग क्षेत्र पर छोड़ कर अन्य क्षेत्रों के विकास करने में सलग्न हो सकता है।

५—देश के विधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य (Welfare State) में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय एवं समान अवसर प्राप्त होता है। अतः ‘साहसी तथा राज्य’ औद्योगिक क्षेत्र में समान हैं। इसलिए उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में होने का समान रूप से अवसर प्राप्त होना चाहिए।

राजकीय उद्योग

(State Enterprises)

१—भूमिका (Introductory)

राजकीय उद्योग में सभी उद्योग सम्मिलित होने हैं जो सरकार द्वारा स्थापित किये जाते हैं तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के अपनाने के पदचातु जिनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इसका कारण यह है कि ससार के किसी भी देश में समाजवादी अर्थ व्यवस्था शुरू से ही नहीं थी बल्कि उसकी स्थापना तथा विस्तार पूँजीवादी घोषण को समाप्त करने के लिए ही हुआ। इस प्रकार यह आशा करना कि किसी भी देश में प्राचीन काल से ही उत्पत्ति, विनिमय और वितरण पर सरकार का अधिकार रहा हो, गलत होगा।

औद्योगिक क्रांति के पश्चात् कुछ देशों में पूँजीवाद की स्थापना हो जाने पर धीरे-धीरे पूँजीपतियों का शोषण बढ़ता गया। इसमें वर्ग संघर्ष का जन्म हुआ। इस वर्ग संघर्ष ने समाजवाद की विचारधारा को जन्म दिया। रूस की श्रमिक क्रांति के पश्चात् जब वहाँ पर श्रमिकराज्य की स्थापना हुई (जो वास्तव में साम्यवाद है) समाजवाद के लाभ की जानकारी के पश्चात् कुछ अन्य देशों ने भी इस विचार को अपनाया कि 'देश की उत्पत्ति और वितरण पर राज्य का पूर्ण अधिकार हो।' अब राजकीय उद्योग (State Enterprise) की विचारधारा अनेक देशों में फैल रही है।

यह कहना कि भारतवर्ष में राजकीय उद्योगों की स्थापना केवल स्वाधीनता प्राप्ति और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के पश्चात् हुई, ऐतद्प्रतिपाद नहीं है। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष में भी काफी दिनों से कुछ क्षेत्रों में राजकीय उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद था। उदाहरणार्थ, यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन काल से ही, विशेषतौर पर सन् १८५७ के विद्रोह के पश्चात्, राजकीय उद्योगों की स्थापना सरकार द्वारा हुई थी। मुख्य रूप से डाक तार विभाग (Post & Telegraph Dept.), रेलवे (Railways), प्रतिरक्षा उद्योग (Defence Industries) आदि का उल्लेख कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ और उद्योगों का नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता था।

२—राजकीय उद्योग की विशेषतायें

(Characteristics of State Undertakings)

राजकीय उद्योगों में निम्नलिखित कुछ विशेषतायें हैं, जिनके कारण इसका विस्तार विभिन्न देशों में तीव्रता से हो रहा है —

१. समाजवादी विचारों का विस्तार — आधुनिक काल में सत्तार के प्रायः सभी देशों में वर्ग संघर्ष का दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि सत्तार के विभिन्न देशों में समाजवादी मत का विस्तार होता जा रहा है। हम और चीन जैसे समाजवादी राष्ट्रों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि इस मत का समान वितरण और अधिक उन्नति समाजवादी अर्थव्यवस्था के अवनान पर भरसकता से प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी नोटा जान गया है कि समाज-कल्याण सभी सम्भव हो सकता है जबकि ऐसा स्थान समस्त उद्योग और उत्पत्ति का नियंत्रण, तथा उनका वितरण सरकार के हाथ में हो।

२—राज्य प्रबन्ध — राजकीय उद्योगों की स्थापना में एक और विशेषता यह होती है कि उनका प्रबन्ध भी सरकार द्वारा होता है। सरकार के पास साधनों की कमी नहीं होती और इसीलिए सरकारी उद्योगों में अच्छे और कुशल प्रबन्धकों की कमी कमी नहीं होती। सरकार कुशल प्रबन्धकों को अधिक वेतन और सरकारी नौकरी का प्रलोभन देकर आकर्षित कर सकती है।

३—राजकीय उद्योग के अन्तर्गत उन उद्योगों की स्थापना भी सरलता से सम्भव होती है, जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है। साहसी द्वारा बहुत बड़ी रकम आम इकट्ठी नहीं हो पाती जिसके कारण आवश्यकताओं और सम्भावना रहते हुए भी कभी कभी बहुत बड़े बड़े कार्य साहसी अपने हाथ में नहीं ले पाता है। सरकार के पास विनियोग करने के लिए बहुत पूँजी होती है जिससे वह उन उद्योगों की स्थापना भी राजकीय उद्योग के रूप में कर लेती है जो अन्यथा स्थापित नहीं हो सकते थे।

४—इसी प्रकार उन उद्योगों की स्थापना, जिनमें प्रारम्भिक काल में हानि की सम्भावना होती है और जिसे साहसी स्थापित करना नहीं चाहता, (परन्तु उनका स्थापित होना आवश्यक है) वे केवल राजकीय उद्योग के रूप में ही स्थापित हो सकते हैं।

५—राजकीय उद्योगों की स्थापना में विदेशी सहायता, (घन या तकनीकी कुशलता Technical skill) के रूप में सरलता से प्राप्त हो सकती है जो निजी उद्योगों में प्रायः सम्भव नहीं हो पाती। राजकीय उद्योग के अन्तर्गत विभिन्न देशों से जो यन्त्रादि आयाते हैं उसके साथ यह शर्त सभी होती है कि उसके विषय में पूर्ण यान्त्रिक तथ्य (Mechanical Know-how) उस देश की सरकार से प्राप्त होमे।

६—सरकारी उद्योगों की स्थापना से, पूँजीपतियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से जो धन की बरबादी होती है, वह समाप्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि जब देश के प्रत्येक कर्म-कारखानों पर राज्य का अधिकार होता है तो राज्य द्वारा इन कारखानों से उतनी ही वस्तुये या सेवामें उत्पन्न की जाती हैं जितनी कि आवश्यक हैं। सरकार द्वारा वस्तु या सेवा के विषय में प्रचार सरलता से हो जाता है जिससे उन्हें बेचने में अधिक कठिनाई नहीं होती।

३—भारत में राजकीय उद्योगों का विकास

(Evolution and Growth of State Undertakings in India)

भारत में राजकीय उद्योग काफी दिनों से चला आ रहा है। यह बात ठीक है कि राजकीय उद्योग का क्षेत्र अब बहुत बढ गया है, परन्तु पहले भी राजकीय उद्योग इस देश में विद्यमान था। उदाहरणार्थ, हम टंकसाल (Mint) और पोस्ट-ग्रामिन (Postal System) का उल्लेख कर सकते हैं। भारतीय रेल व्यवस्था (Indian Railways System) इसका एक अन्य उदाहरण है। भारत के अंग्रेज अधिकारी कभी भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के पक्ष में नहीं थे, किन्तु उन्होंने टंक-साल, रेल, तार विभाग, अस्त्र-शास्त्र का निर्माण आदि कुछ कार्य अपने अधिकार में रखे थे ताकि उसके द्वारा राजकीय धन में वृद्धि हो और देश की सुरक्षा के लिये किसी पर आश्रित न रहना पड़े।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश के नेताओं का ध्यान देश की शीघ्रता से समृद्धिशीली बनाने की ओर गया। उन्होंने अनुभव किया कि देश के विकास के लिये देश में अधिक उद्योग घड़े स्थापित हो। एव देश के प्राकृतिक साधनों का सन्तुलित शोषण हो। इसी प्रकार उनका यह भी विचार था कि देश में बड़े उद्योगों की स्थापना और उनका प्रबंध, बड़ी-बड़ी योजनाओं का बनाना और उनको कार्यान्वित करना, देश की पूँजी की कमी को दूर करना और विदेशी सहायता प्राप्त करके देश का औद्योगीकरण तभी सम्भव हो सकता है जब कि यह सब कार्य 'राज्य-उद्योग' के रूप में हो।

सन् १९४२ में कांग्रेस के अवादी सम्मेलन में इस बात का निश्चय किया गया कि देश के आर्थिक ढाँचे को बदल कर समाजवादी ढंग के समाज (Socialistic Pattern of Society) की स्थापना की जाय। तभी में राज्य उद्योगों पर अधिक जोर दिया जाने लगा। समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना का उद्देश्य ही यह है कि धीरे-धीरे राष्ट्रस्थित उत्पत्ति और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाय और जो नई समस्याएँ या उद्योग घड़े खोले जायें वे सभी 'सार्वजनिक उद्योग' के रूप में हो, और इस प्रकार गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र (Private Sector) धीरे धीरे सार्वजनिक उद्योग-क्षेत्र (Public Sector) में परिवर्तित हो जाय।

साध्य पदार्थ की कमी स्वाधीनता के पश्चात् भी भारतवर्ष में बनी रही। इससे सरकार को इस बात के लिए सचेष्ट होना पड़ा कि साध्य-पदार्थों के वितरण

का समस्त दायित्व वह अपने ऊपर ले ले । इसके दो मुख्य कारण थे, पहला यह कि खाद्य-सामग्री विदेशों से मगाना आवश्यक था जो केवल सरकार द्वारा ही सरसता से संभव हो सकता था और दूसरा यह कि खाद्य-सामग्रियों का उचित और ठीक वितरण केवल राज्य द्वारा ही संभव हो सकता है । इस प्रकार खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करने और उसको वितरण करने का कार्य सरकार ने अपने हाथों में ले लिया । स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् से ही देश की कृषि और मिर्चाई में उन्नति करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है । कृषि की उन्नति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि खेतों में अच्छे प्रकार के साद का प्रयोग हो । भारत में रासायनिक खाद (Chemical fertiliser) की उत्पत्ति पहले नहीं होती थी, जिसमें सरकार को इसका आयात करना पड़ता था । इसकी कमी को दूर करने के लिए सरकारी उद्योग के रूप में रासायनिक खाद निर्माण करने के कारखाने खोले गए, जो ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं ।

सन् १९५४ के बिल द्वारा इसी बात की चेष्टा की गई कि जो उद्योग निजी उद्योग क्षेत्र में हैं वे सरकार के निर्देशानुसार कार्य करें ।

इसके पश्चात् जब कुछ उद्योग सार्वजनिक उद्योग-क्षेत्र में खुल गए और लोगों को इस बात की शका होने लगी कि शायद यह सार्वजनिक उद्योग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं तो जनता की भाँग पर एक बिल सन् १९५४ में पास किया गया जिसका शीर्षक था "The Public Financed Industries Control Bill 1954," इसके पश्चात् Estimates Committee ने तथा Public Accounts Committee ने भी सार्वजनिक-उद्योग संबंधी तथ्यों पर समय-समय पर प्रकाश डाला है । इनके सुझावों तथा अन्य सुझावों के अनुसार सार्वजनिक उद्योगों का नियन्त्रण और प्रबंध सरकारी कमचारियों द्वारा होता है ।

जीवन-बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Life Insurance Com) करने में, इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण और उसको स्टेट बैंक में परिवर्तित करने से तथा एयर-इंडिया इन्टरनेशनल (A. I. I.) के राष्ट्रीयकरण से सार्वजनिक उद्योग के क्षेत्र का और विकास हो गया । इनके राष्ट्रीयकरण करने के तीन मुख्य कारण थे । पहला तो यह कि इम्पीरियल बैंक और जीवन-बीमा कम्पनियों में देश के अधिकतर व्यक्तियों की पूँजी, धर्मानत या बचत इकट्ठी थी, जिसका सदुपयोग राष्ट्र उन्नति के हित में नहीं हो रहा था । दूसरा कारण यह था कि एयर इंडिया-इन्टरनेशनल का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसके लिए जितनी पूँजा की आवश्यकता थी वह गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा इकट्ठा करना कठिन था, तथा उन्हें बड़ी बड़ी विदेशी मस्यामों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी, जिससे उनके समाप्त हो जाने की सम्भावना थी, तीसरा कारण यह था कि राष्ट्र की बहुमुखी उन्नति के लिए इनका राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया था ।

सन् १९५१ में ए०जी० गोरवाला ने राजकीय उद्योग के विषय में जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था कि "भारतवर्ष के लिए राजकीय उद्योग की स्थापना और उसका विस्तार बहुत आवश्यक है।" खास तौर पर उन्होंने यह सिफारिश की थी कि साधन पदार्थों का व्यापार और नियन्त्रण, रासायनिक खाद और अन्य प्रकार की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति—जो सरलता से गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हो सकती—सार्वजनिक उद्योग-क्षेत्र में उत्पन्न होनी चाहिए। उन्होंने इस बात की भी सिफारिश की थी कि राज्य उद्योगों का प्रबन्ध, उनका संचालन और विस्तार सरकारी कर्मचारियों द्वारा, राष्ट्रहित के उद्देश्य से हो। इस प्रकार उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि उद्योगों का स्वामित्व, प्रबन्ध और संचालन जनहित के उद्देश्य से सरकार के ही हाथ में हो। उसमें लाभ कमाने का कोई उद्देश्य न रहे। राज्य उद्योगों के लाभ उनसे प्राप्त सुविधाएँ और उनका द्रुत विस्तार इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने जनता के विश्वास की अवहेलना नहीं की है। यही कारण है कि भारत में सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र का विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

४—राज्य-उद्योगों का प्रबन्ध

(Management of State Undertakings)

राज्य-उद्योग या राज्य-संचालित व्यवसाय का प्रबन्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही होता है। उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद मैनेजर या मैनेजिंग-डाइरेक्टर का होता है। इसकी सहायता करने के लिए तथा उसके कार्य को सरल बनाने के लिए डाइरेक्टरों की एक समिति (Board of Directors) होती है। ये मैनेजर को समय-समय पर विभिन्न प्रकार के विषयों पर सलाह देते हैं। मैनेजर प्रायः इनकी सलाहों को मान कर काम करता है, परन्तु उनके लिए यह हमेशा आवश्यक नहीं होता कि उन सलाहों को शत प्रतिशत रूप में माने। बोर्ड के सदस्य प्रायः मैनेजर को समापति मान कर बाय करते हैं और हमें इस बात की चेष्टा करते हैं कि वह सभी पारस्परिक सहयोग और सहभावना से काम करे। उद्योग की स्थिति और उसके आकार के हिसाब से डाइरेक्टरों की संख्या निश्चित की जाती है। मध्यम और बड़ी मात्रा के उद्योग में प्रायः ५ से लेकर ६ तक डाइरेक्टर होते हैं। इनमें से प्रत्येक को एक विभाग सौंप दिया जाता है—जैसे, किसी को श्रम सम्बन्धी, किसी को धन सम्बन्धी, किसी को प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकारी बना दिया जाता है। मध्यम रूप की उत्पत्ति संस्थाओं में प्रायः प्रत्येक डाइरेक्टर को एक से अधिक विषयों का भार ग्रहण करना पड़ता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, मैनेजर या डाइरेक्टरों के समापति को, जहाँ तक हमें इन डाइरेक्टरों के मतों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए; किन्तु उसे इस बात का अधिकार है कि अगर वह आवश्यक समझे तो डाइरेक्टरों के मत की अवहेलना करे। उस हालत में उसे सम्बन्धित मन्त्री को इस

बात की सूचना देनी पड़ती है कि उसने डाइरेक्टरों के मतों के अनुसार काम नहीं किया है।

मैनेजर और डाइरेक्टरों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। यदि किसी पूर्वस्थित उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया हो तो इस बात का भरसक प्रयास किया जाता है कि उसमें जो पहले मैनेजर, सहकारी मैनेजर आदि थे, उनकी ही नियुक्ति डाइरेक्टरों के रूप में हो। इस विषय में शिक्षा आदि के विषय में कोई पाबन्दी नहीं होती। उसकी शिक्षा जो पहले से है, उसका अनुभव, काय कुशलता, जिम्मेदारी और सद्भावना से कार्य करने की प्रवृत्ति तथा उसकी उस उद्योग के प्रति वफादारी आदि ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर उसकी नियुक्ति डाइरेक्टर के रूप में होती है। जाति-पाति या वेतन का कोई आधार इस नियुक्ति में नहीं होता। इन डाइरेक्टरों की उम्र प्रायः तीस से पचास वर्ष तक की होती है। उनके वेतन और अन्य सुविधाओं के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है—काय के स्वरूप, उत्पत्ति की मात्रा, योग्यता, शिक्षा, अनुभव और पहले के वेतन आदि बातों के द्वारा ही उनका वेतन निश्चित किया जाता है।

मैनेजर और डाइरेक्टरों की नियुक्ति किसी विशेष भ्रष्टाचार के लिए नहीं होती। यह वास्तव में 'प्रेसीडेन्ट' की भर्ती पर है कि वह कितने दिन तक मैनेजर या डाइरेक्टर की नियुक्ति करता है। डाइरेक्टरों की पदच्युति कई कारणों से हो सकती है, जिनमें से प्रमुख है—पागलपन, शारीरिक अस्वस्थता, अयोग्यता, जानबूझ कर कार्य न करना, उच्च अधिकारियों की आज्ञा की अवहेलना करना, चारित्रिक दोष आदि। आवश्यकता पड़ने पर मैनेजर सम्बन्धित व्यक्ति से स्तीफा माग सकता है जिस वह सम्बन्धित मन्त्री के पास भेज देता है।

मैनेजर और डाइरेक्टरों की नियुक्ति से पहले यह आवश्यक है कि वे अपनी आमदनी और अपनी सम्पत्ति के विषय में सम्बन्धित मन्त्री को सूचित कर दें। इसी के साथ-साथ उनको यह भी बताना पड़ता है कि उनकी रुचि या योग्यता किस ओर है? क्या उनका कोई सम्बन्धी या निकट सम्बन्धी उसी प्रकार के व्यवसाय में सलग्न है? क्या उनका कोई सम्बन्धी किसी देशी या विदेशी फर्म में कार्य कर रहा है? जो 'सार्वजनिक-शासन' (Civil Service) विभाग से आते हैं, कुछ हद तक उनकी भी इन विषयों की सूचना देनी पड़ती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उद्योगों के कार्य के साथ साथ 'सार्वजनिक शासन' का कार्य भी करना पड़ता है।

राज्य उद्योगों की व्यवस्था प्रणाली

१—विभागीय व्यवस्था (The Departmental Pattern)—इस व्यवस्था के अन्तर्गत राजकीय-उद्योग का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मन्त्री पर होता है, जो उस कार्य को सुचारूप से चलाने के लिए एक मैनेजर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) की नियुक्ति करता है, जो इस प्रकार की राज्य व्यवस्था का

प्रबन्ध करते हैं। इसके अन्तर्गत मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (Administrative Service) के समकक्ष होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें उद्योगों के विषय में पर्याप्त जानकारी और अनुभव होता है। इस प्रकार की राज्य व्यवस्था का उत्तरदायित्व मन्त्री पर होने के कारण वह पार्लियामेंट के प्रति इसके विषय में उत्तरदायी होता है।

भारतवर्ष में यह प्रथा विद्यमान है, जिसमें उल्लेखनीय उद्योग यह हैं : रेलवे, डाक और तार विभाग, प्रतिरक्षा व्यवसाय, खाद्य पदार्थ और रासायनिक खाद का व्यवसाय; हीराकुण्ड और भाखड़ा नांगल बांध, चितरजन लोकोमोटिव फैक्टरी, पैनिमिलीन फैक्टरी, नेशनल इनस्ट्रूमेंट फैक्टरी (National Instrument Factory), सरकारी नमक उत्पत्ति उद्योग (Govt Salt Works) इत्यादि। इनमें कुछ अन्य उद्योग भी क्रमशः शामिल किये जा रहे हैं।

इस प्रकार के प्रबन्धित राज्य व्यवसायों में विशेष गुण यह होता है कि सम्बन्धित मन्त्री और कुशल व्यवस्थापकों के हाथ में यह कार्य होता है, जिससे इनकी विकास की सम्भावना और शक्ति में वृद्धि होती है। परन्तु इनका सबसे बड़ा दोष यह होता है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य होने के फलस्वरूप प्रत्येक कार्य देर से, और अकुशलता से और कभी-कभी गलत नीतियों में होते हैं।

२—प्रद्व-सरकारी व्यवस्था (The Operating-Contract System)—

इस प्रथा के अन्तर्गत स्थापित किये गये उद्योगों का स्वामित्व सरकार का होता है, परन्तु उसकी व्यवस्था का कार्य साहसी द्वारा होता है। इस प्रकार साहसी और सरकार में यह समझौता हो जाता है कि सरकार उस उद्योग की स्थापना के लिए सब प्रकार की सुविधायें प्रदान करेगी और साहसी का कार्य यह होना है कि उस उद्योग में सम्बन्धित सभी प्रकार की व्यवस्था और योजना का कार्य करे। सामान का प्रतिशत या उसका स्वरूप भी इस समझौते के द्वारा निश्चित किया जाता है। इनके अन्तर्गत कुछ और सामान्य शर्तें सरकार की ओर से रखी जाती हैं—जैसे, सरकार उस व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर सकती है, उत्पत्ति की मात्रा और वस्तु के गुण (Quality) को नियन्त्रित कर सकती है, आवश्यकता पड़ने पर साहसी को इस बात का भी प्रबन्ध करना पड़ेगा कि उस उद्योग में लगे कर्मचारियों की साधारण और वित्तिष्ठ शिक्षा का प्रबन्ध करे।

यह प्रथा प्रायः अवि विकसित देशों (Under-developed Countries) में पायी जाती है। इन देशों की सरकारों का आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नत देशों के साहसियों के साथ समझौता होता है, जिसके अनुसार वे साहसी इन देशों में भारी कारखाने स्थापित करते हैं। इसका कारण यह होता है कि इन पिछड़े देशों के पास ऐसे उद्योगों के स्थापित करने के लिए साधन और सुविधायें प्राप्त नहीं होती।

इस प्रथा का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि राष्ट्र के पास साधन न होते हुए भी वह देशी और विदेशी साहसियों की सहायता से (और दोनों पक्षों के लाभ

की सम्भावना से) इन देशों में नये-नये और भारी उद्योगों की स्थापना हो जाती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। इस प्रथा से एक अन्य लाभ यह भी होता है कि इनकी व्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता और इनकी व्यवस्था कार्य-कुशल तथा अनुभवी साहसियों द्वारा होने के कारण यह द्रुत गति में उन्नति कर सकते हैं। इस प्रथा में हानि केवल यह होती है कि यदि समझौता ठीक प्रकार से न किया जाय या कुछ वर्षों के पश्चात् इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण सरकार द्वारा सम्भव न हो सके तो राष्ट्र को सदा हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उसका लाभ साहसी ही उठाते रहते हैं।

भारतवर्ष में इस प्रकार के भी कुछ राज्य-उद्योग हैं, जैसे, हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी, राजरकेला, सिन्ध्री फर्टीलाइजर्स (Sindri fertilizers), ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन (Eastern Shipping Corporation), हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (Hindustan Shipyard Ltd.) इत्यादि। इस प्रथा में एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि यह आवश्यक नहीं है कि सरकार केवल विदेशी साहसियों के साथ ही समझौता करे, देशी साहसियों के साथ भी वह समझौता कर सकती है।

३—सहकारी प्रथा (The Co-operative Type)—इस प्रथा के अन्तर्गत उद्योग के क्षेत्र में पूंजीपतियों और राज्य में पारस्परिक सहयोग की स्थापना होती है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसको सहकारी प्रथा कहते हैं। इसमें उद्योगों की स्थापना, पूंजी का प्रबन्ध, स्वामित्व और प्रबन्ध सरकार तथा साहसी दोनों के बीच में बँटा होता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयास से यह उद्योग स्थापित होते हैं। इन उद्योगों में सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि सरकारी नीति और नियन्त्रण का सम्मिश्रण साहसी की योग्यता और व्यवस्था-शक्ति के साथ होता है, जिसके फलस्वरूप इन उद्योगों में हानि की सम्भावना कम हो जाती है। अवादी अधिवेशन (१९४८) के आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में जो सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र की स्थापना का संकेत किया गया था, यह प्रथा प्रायः उसी रूप में है। इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (Indian Telephone Industries Limited), हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लि० (Hindustan Housing Factory Ltd.), हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० (Hindustan Machine Tools Ltd.), हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० (Hindustan Shipyard Ltd.), आदि इसके उदाहरण हैं। धीरे-धीरे इस प्रथा के द्वारा भी, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके, देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना सम्भव हो सकती है।

४—स्वयं व्यवस्थित प्रथा (Autonomous Management Patterns)—इस प्रथा के अन्तर्गत पार्लियामेंट द्वारा कानून बना कर इन संस्थाओं की स्थापना की जाती है, जिससे वह अपने नाम से और अपने प्रबन्ध द्वारा

सरकारी उद्योगों की स्थापना और उनका प्रवन्ध कर सकें। इन पर स्वामित्व सरकार का होता है किन्तु इनका कार्य प्रवन्ध निजी क्षेत्र के उद्योगों की व्यवस्था के अनुरूप होता है। सरकारी उद्योग के सभी लाभ और हानियाँ इसमें भी विद्यमान होती हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन (Damodar Valley Corporation), जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) आदि इसके उदाहरण हैं।

५—राज्य-उद्योगों का आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis of State Undertakings)

राज्य उद्योगों की स्थापना और उसके विस्तार से राष्ट्र को कुछ लाभ प्राप्त होते हैं जो निम्नलिखित हैं —

१—राज्य उद्योगों की स्थापना और उनके विस्तार से समाजवादी भ्रष्ट-व्यवस्था की स्थापना सरल और सम्भव हो जाती है।

२—राज्य उद्योगों की स्थापना लाभ न कमाने और जनता को अधिकतम सुविधाय प्रदान करने के लिए होती है। इस प्रकार राज्य उद्योगों की स्थापना से जनता का पूँजीपतियों द्वारा शोषण समाप्त हो जाता है।

३—राज्य उद्योगों की स्थापना से देश में औद्योगीकरण तीव्रता से और एक नीति के अनुसार सम्भव हो सकता है जो पिछड़े हुए देशों में गैर सरकारी उद्योगों के रूप में सम्भव नहीं हो पाता। सरकार इस बात की ओर भी सचेष्ट रहती है कि उद्योगों की स्थापना देश के विभिन्न भागों में इस ढंग से की जाय कि देश स्थिति कच्ची सामग्री और प्राकृतिक साधनों का अधिकतम प्रयोग सम्भव हो सके और उद्योगों के विस्तार से स्थानीयकरण को बढ़ावा न मिले।

४—राष्ट्र उद्योगों द्वारा सकट का सामना सरलता से हो सकता है, जैसे पिछले कई वर्षों में सरकार ने खाद्य पदार्थों में व्यापार करके राष्ट्र को भ्रष्ट सकट से बचा लिया है।

५—बड़े बड़े उद्योगों और योजनाओं की स्थापना और उनका विस्तार (विशेषतः पर अविकसित देशों में) केवल सरकार द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

६—उद्योग और आमदनी के क्षेत्र में असमानता को दूर करने के लिए, तथा राज्य में अधिकतम प्रतिरक्षा सामग्री की उत्पत्ति के लिए और देश को आर्थिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए राज्य उद्योगों की स्थापना या उद्योगों का राष्ट्रीयकरण या मार्गजनिक क्षेत्र में नये नये कारखानों की स्थापना आवश्यक होती है।

उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त कुछ और भी गुण राज्य-उद्योगों में पाये जाते हैं। परन्तु यह सोचना कि इन राज्य-उद्योगों में केवल लाभ ही लाभ हैं, कोई हानि नहीं, भ्रमात्मक होगा। वास्तव में इनमें बहुत से दोष हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

१—राज्य उद्योगों की व्यवस्था के कार्य को चलाने के लिए जो नियुक्तियाँ होती हैं वे हमेशा ठीक नहीं होतीं। इसमें प्रायः ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होती है जिनकी साधारण कार्य कुशलता और दक्षता पर किसी को कोई सन्देह नहीं हो सकता परन्तु उन्हें व्यवसाय चलाने या उद्योगों के प्रबन्ध का कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए वह इन कार्यों को उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते जिन तरह से निजी क्षेत्र के साहसी या व्यवस्थापक कर सकते हैं।

२—राज्य-उद्योगों के व्यवस्थापकों पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उद्योग से लाभ प्राप्त हो रहा है या हानि। इसलिए यह इन उद्योगों की उन्नति के लिए उतना प्रयास कभी भी नहीं कर पाते जितना कि साहसी करता है।

३—प्रायः यह कहा जाता है कि राज्य-उद्योगों की स्थापना वर्ग-सघर्ष को समाप्त करने के लिए की जाती है। खेद का विषय है कि भारत सरकार अपने राज्य-उद्योगों द्वारा अभी तक इस वर्ग-सघर्ष को समाप्त नहीं कर पायी है।

४—जिन वस्तुओं या सेवाओं की राज्य-उद्योगों द्वारा उत्पत्ति होती है उनका निर्माण राष्ट्र में अन्य किसी कारखाने में नहीं होता। इसका अर्थ यह होता है कि इन वस्तुओं की उत्पत्ति और वितरण का पूरा अधिकार सरकार को प्राप्त हो जाता है जिसमें एकाधिकार (Monopoly) की स्थापना हो जाती है।

५—सरकारी उद्योगों की स्थापना से उपभोक्ताओं का महत्त्व समाप्त हो जाता है क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा का अन्त हो जाता है। जब बाजार में कीमत का निर्धारण प्रतिस्पर्धा के आधार पर होता है तो प्रत्येक उत्पादक कम से कम उत्पत्ति-व्यय पर वस्तुएँ उत्पन्न करता है एवं उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को खरीदता है। इस प्रकार उस परिस्थिति में उत्पादक का उपभोक्ताओं की इच्छानुसार वस्तुएँ उत्पन्न करनी होती है परन्तु सरकारी उद्योग की स्थापना से प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और इसलिए उपभोक्ता का महत्त्व भी समाप्त हो जाता है।

६—राज्य व्यापार में प्रायः वस्तुओं की कीमतें ऊँची होती हैं जिससे देश की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, भारत सरकार द्वारा जब से खाद्य पदार्थ (food grains) का व्यापार हो रहा है उसी से इनकी कीमतों में वृद्धि हो गई है।

७—यह कहना कि राज्य उद्योगों की स्थापना से ही देश में समाजवादी अर्थ व्यवस्था की स्थापना सम्भव हो सकती है, पूर्णतः ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना केवल मात्र राज्य-उद्योगों की स्थापना द्वारा नहीं होती—इसके और भी बहुत से तरीके हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की पूर्णरूपेण स्थापना में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का भेद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि उसमें उत्पत्ति और वितरण का स्वामित्व केवल सरकार के हाथ में होता है।

८—राज्य-उद्योगों की स्थापना से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत प्रायः अधिक होती है क्योंकि सार्वजनिक उद्योगों में व्यय अधिक होता है ।

९—राज्य उद्योगों में श्रमिकों की शिक्षा और उनके कल्याण पर प्रायः उतना धन अभी नहीं दिया जा रहा है जितना कि दिया जाना चाहिये । विशेषतौर पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितना महत्व श्रम कल्याण पर होना चाहिये । उतना महत्व श्रम कल्याण पर अभी भारत में नहीं दिया जा रहा है ।

१०—राज्य-उद्योग की स्थापना से या राज्य व्यवसाय के प्रवर्तन से कभी-कभी विभिन्न वस्तुओं और-सेवाओं पर नियन्त्रण स्थापित हो जाना है । आवश्यकता पड़ने पर राशनिंग (Rationing) प्रथा भी जारी की जाती है, जिससे जनता को कठिनाईयाँ होती हैं ।

११—उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़ते हैं, जो स्थितशील उद्योग नीति के विरुद्ध है ।

१२—राज्य-उद्योगों के प्रबन्ध में आवश्यकतानुसार परिवर्तन उतनी सरलता से नहीं हो पाता जितना कि निजी-उद्योगों में ।

१३—राज्य-उद्योगों की स्थापना में प्रायः अभिनवीकरण (Rationalisation) की पद्धति को अपनाया जाता है, जिससे उत्पात्ति का ढग श्रम-प्रमुख (Labour intensive) के स्थान पर पूँजी-प्रमुख (Capital intensive) हो जाती है और देश में बेरोजगारी फैल जाती है ।

१४—सरकार द्वारा नियन्त्रित और प्रबन्धित उद्योग हमेशा मन्दगति से कार्य करते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में 'लाल फीता' (Red tape) की कठिनाईयाँ विद्यमान रहती हैं ।

१५—राज्य-उद्योगों की स्थापना कभी कभी विदेशी साहसियों के सहयोग से भी होती है, जिससे, प्रायः चल कर राष्ट्र को हानि भी हो सकती है ।¹

आर्थिक नियोजन के प्रकार एवं पद्धतियाँ^१

(Kinds And Techniques of Economic Planning)

१—विषय प्रवेश

(Introductory)

आर्थिक नियोजन के व्यापक एवं आलोचनात्मक अध्ययन के लिए, नियोजन के प्रकार तथा पद्धतियों का अध्ययन आवश्यक और महत्वपूर्ण है। योजना के संदर्भ में वित्तीय साधनों को एकत्र और संगठित करके आर्थिक नीति की इतिथी नहीं हो जाती, बल्कि नीति का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि वह योजना की आवश्यकताओं के अनुसार उपभोग को उत्साहित करे और वास्तविक साधना का प्रयोग करे। योजना केवल उन कार्यों की सूची नहीं है जो हमें करने हैं बल्कि योजना में एक नीति होती है जिसके अनुसार ये कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। छोटे तौर पर दो कार्य पद्धतियाँ हैं, और उन दोनों का स्तंभाल किया जाना चाहिए। प्रथम, आर्थिक क्रिया को धन और वित्त नीति के माध्यम से पूरी तरह नियन्त्रित करना और द्वितीय, आयात और निर्यात नियन्त्रण, उद्योगों और व्यवसायों को लाइसेंस देना, मूल्य-नियन्त्रण और नियमन आदि उपाय जो अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र की या उप-क्षेत्र की आर्थिक क्रिया को प्रभावित और नियमित करते हैं। व्यापक योजना में, जिसका उद्देश्य विनियोग में यथेष्ट वृद्धि करना और प्राथमिकता की योजना पर अमल करना होता है, इन दोनों तरह के नियन्त्रणों की जरूरत पड़ती है।^२ सत्तार के सभी देशों में, जहाँ केन्द्रीय नियोजन की पद्धति को अपनाया जाता है, इन दोनों ही प्रणालियों को व्यवहार में लाया जाता है। इसका कारण यह है कि यह एक-दूसरे के पूरक है। किन्तु यह सोचना कि नियोजन की केवल यही दो प्रणालियाँ एवं पद्धतियाँ हैं, गलत होगा। नियोजन की कुछ प्रमुख पद्धतियाँ और प्रणालियाँ निम्न लिखित हैं :

1. With special reference to India

२ | द्वितीय पंचवर्षीय योजना (संक्षिप्त), पृष्ठ २८

२—उद्देश्यपूर्ण नियोजन (Planning with a Purpose)

यदि कोई व्यक्ति शब्दकोश के अर्थानुसार 'उद्देश्यपूर्ण नियोजन' शब्द का अध्ययन करे तो वह भ्रम में पड़ जायगा। क्या बिना किसी उद्देश्य के भी योजना का अस्तित्व हो सकता है ? इसका स्पष्ट उत्तर होगा 'नहीं।' फिर इस शब्द का क्या आशय है ? नियोजन अच्छी तरह से निश्चित लक्ष्यो तथा उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लक्ष्यो की प्राप्ति पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप में हो सकती है। यदि ये पूर्णरूपेण प्राप्त किये जायें तो वह 'उद्देश्यपूर्ण नियोजन' कहलायेगा, अन्यथा नहीं। स्टालिन के अनुसार, "पूँजीवाद के समर्थक भी यह मानते हैं कि उत्पत्ति कार्य में 'किसी' प्रकार का नियन्त्रण आवश्यक होता है परन्तु पूँजीवादियों की योजना काल्पनिक और अव्यावहारिक होती है जो किसी के लिए भी वाध्य मूलक नहीं होती, यही कारण है कि उन्हें योजना से सफलता नहीं मिलती।"¹ वस्तुनियों के नियोजको ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा था, "पहले नियोजन का एक आधार बना लेना चाहिए, फिर उसका धारण पूर्ण शक्ति से करना चाहिए।"²

जैसा कि ऊपर बताया गया है, 'उद्देश्यपूर्ण नियोजन' नियोजन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उद्देश्य एवं आधार निश्चित तथा स्थिर होते हैं। इस प्रणाली में आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्यो और उद्देश्यो में परिवर्तन संभव नहीं होता है। जब इस प्रकार का नियन्त्रण बना लिया जाता है तो राज्य, सरकार एवं जनता उसको कार्यान्वित करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। भारत की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में से कोई सी भी इस प्रकार की नहीं है। इसका मुख्य कारण यह रहा कि भारतीय योजनाओं को आवश्यकतानुसार एवं वित्तीय-स्थिति (आन्तरिक एवं विदेशी) के अनुसार समय-समय पर बदलने की आवश्यकता पड़ती रहती है।

३—भौतिक और वित्तीय योजना³ (Physical and Financial Planning)

समाज की जनशक्ति के प्रयोग में विकास के साथ साथ जो परिवर्तन आता है, वह इस बात का सूचक है कि अन्य साधनों के उपयोग की दिशाओं में भी परि-

1 Speech of Stalin, incorporated in 'Soviet Economic System' By Baykov, p 424

2 Sir Stafford Cripps, Speech delivered in House of Commons, Feb. 28, 1946

3 (संक्षिप्त) द्वितीय पंचवर्षीय योजना, १९५६, योजना आयोग, भारत सरकार, पृष्ठ ७६ ७१

वर्तन आया है। अथवा यो कहा जाय कि यह सभी परिवर्तन परस्परालम्बी है। वास्तविक साधनों को लगातार सतुलित ढंग से उन्नत होना और आगे बढ़ना है। विकास के लिए आयोजन में यह बात निहित है कि वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत वास्तविक साधनों के उपयोग में कैसे परिवर्तन लाये जायें। समस्या के प्रति यह दृष्टि रखना, अर्थात् वास्तविक साधनों अथवा भौतिक योजना के रूप में विकास की समस्या को देखना, वैसा ही है जैसे, आवश्यक या प्रस्तावित विकास प्रयत्नों के अन्तर्गत इस प्रकार साधनों का आवंटन और उत्पादन, जिससे आय और रोजगार की अधिक से अधिक वृद्धि हो। दूसरे शब्दों में, विकास के कार्यक्रम को संचालित करते हुए यह जरूरी है कि हम मुद्रा और वित्त के अर्थ-गुठन के पीछे भाग सकें और यह अनुमान लगा सकें कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत और विशेषतः सामरिक महत्त्व के क्षेत्रों में मांग और पूर्ति पर उन कार्यक्रमों की क्या प्रतिक्रिया होगी। इसके साथ ही वास्तविक साधनों को जुटाते हुए हमें केवल अलग-अलग योजना-कार्यों पर दृष्टि नहीं रखनी है बल्कि सम्पूर्ण कार्यक्रमों को एक साथ ध्यान में रखना है। इस उद्देश्य से हमें यह अध्ययन करना है कि किसी विशेष बिन्दु पर उत्पादन में आयोजित वृद्धि के फलस्वरूप किस प्रकार विभिन्न दिशाओं में पूर्ण-विनियोग की मांग बढ़ती है।

दूसरे शब्दों में, वास्तविक साधनों के रूप में योजना में कुछ सन्तुलन होने चाहिए। जब किसी योजना का प्रारम्भ होता है तो वह पहले-पहल एक स्थापित सन्तुलन को ढिगा देता है और तब उच्चतर स्तर पर एक नया सन्तुलन स्थापित करता है। समस्या यह है कि आवश्यक वास्तविक साधनों, जैसे मशीनें, धन, व्यवस्था और साज-सज्जा आदि की पूर्ति उचित मात्रा में होती रहें। कुछ हद तक विनियोग के किस स्वरूप को अपनाया जाता है, इसमें आवश्यक सन्तुलन स्थापित हो सकेगा। जहाँ ऐसा नहीं किया जा सकता वहाँ अवरोध के उन बिन्दुओं की स्पष्टतः बताया जा सकता है जिनका सामना करना है और जिन्हें दूर करना है।

इस बात पर बल देना आवश्यक है कि योजना में जिस सन्तुलन को प्राप्त करना है, वह वास्तविक और वित्तीय दोनों ही रूपों में होना चाहिए। उत्पादन के क्रम में मुद्रा के रूप में आय का जन्म होता है, और मुद्रा की मांग पर सम्भरित वस्तुओं की सपत्त होती है। अतः यह बात महत्वपूर्ण है कि मुद्रा के रूप में प्राप्त आय के व्यय को इस प्रकार नियमित किया जाये जिसमें उपभोग्य वस्तुओं की मांग और पूर्ति के बीच, वस्तु और विनियोग के बीच और बंदिशक अर्जन और भुगतान के बीच सन्तुलन बना रहे। इसके साथ ही प्रत्येक महत्वपूर्ण पक्ष की मांग और पूर्ति के बीच सन्तुलन भी आवश्यक है।

— वित्तीय योजना निर्माण का सार यह है कि मांग और पूर्ति का सामंजस्य ऐसा हो जिससे भौतिक साधनों का पूरा लाभ तो उठाया जा सके, पर मूल्य के

टाँचे में कोई बड़ा या असन्तुलित परिवर्तन न हो। वित्त अथवा धरेलू वित्त विकास के मार्ग में कोई विशेष बाधा नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि उसे हमेशा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन केवल इसी बात से कि किसी के पास भुगतान के यथेष्ट साधन हैं, यह सिद्ध नहीं हो जाता कि आवश्यक वास्तविक साधन जुट जायेंगे। अगर वास्तविक साधन नहीं जुट पाते, तो भुगतान के साधनों में वृद्धि के फलस्वरूप व्यवस्था में और गड़बड़ी ही होगी। अतः वित्तीय साधनों पर बल देने का अर्थ है ठोस आयोजन और प्रबन्ध। चाहे कोई भौतिक आयोजन की बात सोचे, चाहे वित्तीय आयोजन की, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर उच्चतर स्तरों पर विभिन्न प्रकार के सन्तुलन स्थापित करें।

४—दीर्घकालीन बनाम अल्पकालीन योजना (Long-term Vs Short-term Planning)

आर्थिक विकास में वास्तविक साधनों के उपयोग में बड़े परिवर्तन निहिन रहते हैं। जब हम दूरगामी या भविष्य की योजना बनायें तो ऐसे परिवर्तनों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कुछ खास उद्देश्यों के लिए केवल पाँच साल की योजना पर विचार करना ही यथेष्ट हो सकता है। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि और अधिक लम्बे समय के विकास पर दृष्टि रखी जाये। प्रत्येक पञ्चवर्षीय अवधि में होने वाले विकास के बीच पूर्ण सन्तुलन स्थापित हो ही जाये, यह आवश्यक नहीं है। कुछ हद तक छोटे बहुत असन्तुलन से किसी एक समयवर्ष में विकास की गति अधिक तीव्र हो सकती है और सन्तुलन श्रेष्ठकर। बिजली, परिवहन और बुनियादी उद्योगों के क्षेत्र में यह बात सही हो सकती है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में विनियोग का रूप पिण्डित (Lumpy) होता है। ऐसे विनियोगों की जल्दतरती को समझने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि तत्कालिक या वर्तमान माँगों की बजाय आगामी दस या पन्द्रह वर्षों में किन-किन दिशाओं में विकास की परिवर्तना की गई है। इस प्रकार निकट भविष्य के लिये जो कार्यक्रम बनाये या चालू किये जायें उन्हें व्यापक परिप्रेक्षित में बनाना चाहिए।

ऊपर जिन बातों को बताया है उनके अनुसार दीर्घकालीन कार्यक्रमों की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत अल्पकालिक कार्यक्रमों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए पञ्चवर्षीय योजना को वार्षिक योजनाओं या कार्यक्रमों में बाँटना होगा और सफलताओं को वार्षिक आधार पर आकना होगा। इस पद्धति में केन्द्र और राज्य सरकारें वार्षिक बजट बनाकर कार्य करती हैं। और इससे वर्ष के बाद आने वाले वर्ष में पञ्चवर्षीय कार्यक्रम को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों पर पुनर्विचार और उनका समायोजन करने का मौका रहता है।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं का ढाँचा इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे उनके अन्तर्गत इस प्रकार की वार्षिक योजनाएँ तैयार की जायेंगी। पाँच साल तक चालू योजना की नमूनीय रूप से कल्पना करनी चाहिए। योजना निर्माण कोई ऐसा अभ्यास नहीं है जो एक ही बार में पाँच वर्ष के लिए कर लिया जावे। उसके अन्तर्गत चालू और भविष्य की प्रवृत्तियों पर जब तक निगाह रखना, तकनीकों, आर्थिक और सामाजिक सूचनाओं और घाकड़ों पर व्यवस्थित रूप से विचार करते रहना और नयी जरूरतों के अनुसार कार्यक्रमों को समायोजित करते रहना आवश्यक है।

दीर्घ योजना का एक और भी अंग है जिसकी चर्चा करना आवश्यक है। एशिया और अफ्रीका के समस्त अल्प विकसित अचलों की कुछ विकास सम्बन्धी समस्याएँ हैं। यह अचल कुछ राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से अभी तक अधिकांशतः अल्प विकसित रहा है, और उनमें से कुछ देशों की अर्थव्यवस्था उन योत्पीय देशों की अर्थव्यवस्था से सम्बद्ध है, जिनके साथ उनके राजनीतिक सम्बन्ध रहे हैं। इसके फलस्वरूप ऐसे अचलों में उद्योग व्यवसाय का थोड़ा-बहुत विकास नहीं हुआ है और न इस बात की खोजबीन पूरी तरह हो पाई है कि इन अचलों के देशों में पारस्परिक सहायता और पूरक प्रयत्नों की कितनी गुंजाइश है। लेकिन जैसे-जैसे इन अचलों में विकासात्मक योजना आगे बढ़ती है, उत्पादन के विभिन्न कार्यक्रमों और पारस्परिक हित की दृष्टि से होने वाले वाणिज्य तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान की समस्या अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जायेगी। यह स्वाभाविक है कि इन अचलों का प्रत्येक देश अपनी जरूरतों और अपनी पद्धतियों के अनुसार अपने साधनों का विकास करेगा। फिर भी यह जरूरी है कि विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्पादन और तकनीकी जानकारी के पारस्परिक विनिमय की व्यवस्था हो। इसी व्यापकतर प्राचलिक परप्रेक्षित में भारत में योजना को आगे बढ़ना है। इस बात का ध्यान में रखना है कि गरीबी, जीवन के निम्न मानदण्ड और आर्थिक पिछड़ेपन की समस्याएँ सभी जगह एक समान हैं, और प्रत्येक देश के प्रयत्न और अनुभव इस अचल के अन्य देशों के लिए मूल्यवान सिद्ध होंगे।

५—स्वतन्त्र नियोजन

(Free Planning)

स्वतन्त्र नियोजन प्रणाली में राज्य और साहसी दोनों ही को अपने-अपने क्षेत्र में नियोजन करने का अधिकार होता है। प्रकृति में यह 'निश्चित नियोजन, प्रणाली के विपरीत होता है। इस प्रकार के नियोजन की प्रारम्भिक स्थिति में सरकार और माहमी दोनों मिल कर आदर्श उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। इसके पश्चात् उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजन के आधार, तकनीक, प्राथमिकताएँ एवं लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। इन सब कार्यों में दोनों का सहयोग होता है। इस

प्रकार, स्वतन्त्र नियोजन प्रणाली में सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्र होते हैं। स्वतन्त्र नियोजन प्रणाली में नियोजन काल में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जा सकते हैं। इस प्रकार, यह नियोजन की आवश्यकतानुसार परिवर्तनशील प्रणाली है।

स्वतन्त्र नियोजन प्रणाली में कुछ दोष एवं कुछ गुण हैं। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि राज्य तथा साहसी विभिन्न सिद्धान्तों पर सहमत नहीं हो पाते, जिसके फलस्वरूप उन्नति की दर में तीव्रता से वृद्धि नहीं हो पाती। इसका एक और दोष यह है कि इस प्रकार के नियोजन में प्रायः परिवर्तन होते रहते हैं जिससे नियोजन का अन्तिम रूप निश्चित करना कठिन होगा। इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें परिवर्तित परिस्थित, साधन एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जा सकते हैं। नियोजन-रचना-काल में नियोजक के पास आवश्यक आंकड़े पूर्णमात्रा में नहीं होते, जिससे उनके लिए नियोजन को अन्तिम रूप प्रदान करना कठिन होता है। किन्तु इस प्रकार के नियोजन में नियोजन-काल में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जा सकते हैं। हमारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाएँ इस प्रणाली के अन्तर्गत आती हैं। साधनों की कमी हमारे नियोजकों को इसके लिए बाध्य करती है कि वे नियोजन की परिवर्तनशील पद्धति को अपनायें।

६—नियोजन-पद्धति 'विनाश' बनाम 'निर्माण' (Planning Through Dislocation Vs Construction)

नियोजन के समर्थकों में प्रायः इस बात पर द्वन्द्व होता है कि नियोजन का मिडान्त क्या हो? एक वर्ग के मतानुसार, 'नियोजन का कार्य विनाश पद्धति को अपनाकर होना चाहिए।' अर्थात्, उनके अनुसार, नियोजन का कार्य तभी सफल हो सकता है जबकि उपभोग, उत्पत्ति एवं वितरण पद्धति को पूर्णरूप से बदल दिया जाय। उत्पत्ति प्रणाली में परिवर्तन लाने से समाज के सभी नागरिक—विशेषरूप से श्रमिक—प्रभावित हो जाते हैं। श्रम-प्रमुख उत्पत्ति के स्थान पर पूँजी-प्रमुख उत्पत्ति की प्रणाली के अपनाने से देश में बेरोजगारी फैल जाती है, जिससे प्रारम्भिक स्थिति में दरिद्र एवं श्रमिक वर्ग को बहुत कठिनाई होती है। किन्तु जब यह प्रथा कुछ काल में स्थितिशील हो जाती है तो इसके गुण नजर आने लगते हैं—अधिक उत्पत्ति, कम उत्पत्ति व्यय, कीमत में कमी, 'अवशिष्ट पदार्थ' का उपयोग, समान वितरण, नये उद्योगों की स्थापना आदि। इस प्रथा के विरोधियों का कहना है कि नियोजन का उद्देश्य नागरिकों का जीवन-स्तर ऊँचा करना एवं रोजगार दिलाना होता है—जो कि इस प्रणाली की प्रारम्भिक स्थिति में प्राप्त नहीं हो पाते। उनका यह भी कहना है कि अवकसित देशों के लिए यह प्रणाली और भी हानिकारक है।

इसके विपरीत एक अन्य वर्ग के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि नियोजन की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे काम में लगे हुए कोई भी व्यक्ति नियोजन के कारण विस्थापित न हो जायें । इसके लिये वह यह सलाह देते हैं कि उत्पत्ति और वितरण के क्षेत्र में नई पद्धतियों को न अपनाया जाय बल्कि पुराने काल से चला आ रही पद्धति को अपनाकर ही नियोजन के अन्तर्गत इस बात की चेष्टा की जाय कि उत्पत्ति और वितरण का क्षेत्र बढ जाय एवं देश की उत्पादन की दर में क्रमशः वृद्धि हो । प्रथम प्रणाली में शुरू में नागरिकों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है किन्तु देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से सम्भव होता है । दूसरी प्रणाली में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती किन्तु विकास की दर बहुत मन्द रहती है ।

७—नियोजन पद्धति : सन्तुलित बनाम असन्तुलित विकास (Planning with Balanced Vs Unbalanced Growth)

नियोजन का वास्तविक सैद्धान्तिक रूप 'सन्तुलित विकास-पद्धति' के अन्तर्गत ही होता है । सन्तुलित विकास का अर्थ यह होता है कि नियोजन में एव नियोजन काल में उपभोग, विनियोग एव आमदनी में समान रूप से विकास तथा वृद्धि होनी चाहिए । वास्तव में ये तीनों ही आपस में प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होते हैं, जिसके फलस्वरूप किसी एक में उन्नति अथवा अवनति होने से दूसरे भी प्रभावित हो जाते हैं । आमदनी में वृद्धि होने से उपभोग की मात्रा में भी वृद्धि हो सकती है तथा विनियोग हेतु बचत की मात्रा में भी वृद्धि सम्भव होती है । इसके विपरीत, यदि विनियोग की मात्रा में भी कमी हो जाय तो आमदनी कम हो जायगी, जिससे उपभोग की मात्रा में भी कमी आ जायगी । नियोजन की यह एक सही और वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसके कारण सभी देशों के नियोजनाधिकारी इस पद्धति की प्रशंसा करते हैं एव नियोजन कार्य में इसको अपनाते हैं ।

इसके विपरीत, 'असन्तुलित विकास' नियोजन प्रणाली में इस बात की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि उपभोग, विनियोग एव आमदनी में एक ही साथ (एक एक ही दर पर) विकास या वृद्धि हो । इसका मुख्य कारण यह होता है कि विभिन्न देशों में आमदनी का वितरण समान रूप से नहीं होता है । धनी वर्ग द्वारा ही विनियोग किया जाता है—एव उनकी ही आमदनी में वृद्धि होती है । देश के समस्त नागरिकों की व्यक्तिगत आमदनी में विशेष परिवर्तन नहीं होता है । अवि-कसित देशों के लिए तो सन्तुलित विकास पद्धति का अपनाना प्रायः असन्तुलित विकास पद्धति को अपनाकर ही किया जाता है ।

सोवियत संघ ने जब अपने देश में नियोजन पद्धति को अपनाया था तो उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी । उन्होंने उस समय असन्तुलित विकास की नियोजन प्रणाली को ही अपनाया था । भारतवर्ष में भी नियोजकों ने योजनाओं के

निर्माण में असन्तुलित विकास पद्धति को अपनाया है। इस पद्धति को अपनाकर जब देश की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो जाता है तभी सन्तुलित विकास प्रणाली को अपनाया जाता है। यद्यपि सन्तुलित विकास योजना पद्धति सही एवं वैज्ञानिक प्रणाली है, किन्तु अविकसित देशों के लिए असन्तुलित विकास योजना प्रणाली वरदान है।

८—नियोजन पद्धति : स्थिर बनाम अस्थिर (Dynamic Planning Vs Static Planning)

नियोजन पद्धति का विभाजन अस्थिर एवं स्थिर रूप में भी सम्भव हो सकता है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मत यह है कि नियोजन एक अस्थिर पद्धति है। इसका कारण यह यह बताते हैं कि दीर्घकालीन नियोजन में नियोजन के सभी तत्वों में परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे सम्पूर्ण 'योजना-काल' के लिए एक निश्चित एवं अपरिवर्तनशील नियोजन का निर्माण कठिन हो जाता है। प्रारम्भ होने के पश्चात् योजना-कार्यक्रम जैसे जैसे अग्रसर होता है वैसे ही वैसे नई-नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। नियोजन द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि 'बदली हुई परिस्थिति' के अनुसार ही नियोजन का कार्य चलाया जाय। उसी दशा में देश योजनाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार नियोजन की 'अस्थिर प्रणाली' में इस बात की सुविधा रहती है कि आवश्यकता और समयानुसार नियोजन की रीति, स्वरूप, लक्ष्य, और उद्देश्यों में परिवर्तन किया जा सके। इस प्रणाली में वित्तीय स्थिति के अनुसार नियोजन का कार्य मन्द या तीव्र गति से अग्रसर हो सकता है।

नियोजन की 'स्थिर प्रणाली' के अन्तर्गत योजना का निर्माण (एक विशेष अवधि के लिए) किया जाता है और उसके पश्चात् उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता। इस प्रकार के नियोजन के निर्माण से पहले जनता और विभिन्न समुदायों को इस बात का पूरा अधिकार होता है कि वह सरकार को अपने सुझाव पेश करे। सरकार या नियोजनाधिकारी इस बात की पूरी चेष्टा करते हैं कि जहाँ तक सम्भव हो सके इन सुझावों को नियोजन में सम्मिलित कर लें—परन्तु इस कार्य को करने के लिए वह बाध्य नहीं होती। व्यावहारिक रूप से नियोजनाधिकारी अच्छे और तथ्यपूर्ण सुझावों को मान लेते हैं। इस प्रकार के नियोजन का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि इन 'नियोजनों' में निरन्तर परिवर्तनों की कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। नियोजन में यदि निरन्तर परिवर्तन करने की आवश्यकता बनी रहे तो उद्देश्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। इसके विपरीत, इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि नियोजन काल में आवश्यकतानुसार परिवर्तन इस प्रकार के नियोजन में सम्भव नहीं होता है। नियोजन में 'अविध्य—तत्त्व' सदा विद्यमान रहता है। इस प्रकार, नियोजन-काल में यदि वित्तीय, साधन सम्बन्धी, प्रादर्श या

उद्देश्य सम्बन्धी अथवा नीति सम्बन्धी कोई परिवर्तन देश में हो और नियोजन के स्वरूप या आकार में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े तो—यदि आवश्यकतानुसार नियोजन में परिवर्तन सम्भव न हो सके आवश्यक रूप से कठिनाई उपस्थित होगी। विभिन्न देशों (जैसे, चीन, रूस, भारत आदि) की नियोजन पद्धति का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रायः सभी देशों में नियोजन की पद्धति काफी हद तक, अस्थिर प्रणाली पर आधारित होती है।

६—नियोजन पद्धति : 'प्रोत्साहन मूलक' बनाम 'आज्ञा मूलक' (Planning by Inducements Vs Planning by Direction)

पूँजीवादी देशों में हस्तक्षेप न करने की आर्थिक नीति होती है। हमारे शब्दों में, साहसी अपन उद्योग एवं व्यापार के विषय में योजना का कार्य स्वयं करते हैं। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस परिस्थिति में 'आज्ञा द्वारा' नियोजन सम्भव नहीं होता। जिन देशों में केवल व्यक्तिगत साहस या निजी क्षेत्र का ही अस्तित्व होता है, वहाँ 'प्रोत्साहन द्वारा' नियोजन की पद्धति को अपनाया जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोजन का पूर्ण भार उठाना कभी भी सम्भव नहीं हो सकता—इसलिये, 'आज्ञा द्वारा' नियोजन कभी भी पूर्ण-नियोजन का रूप धारण नहीं कर सकता। इस मत के समर्थकों का कहना है कि निम्नलिखित कारणों से 'आज्ञा मूलक' नियोजन सफल नहीं हो पाता।

१—उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग की स्वतन्त्रता चाहता है।

२—साहसी अपनी इच्छा तथा शक्ति के अनुसार उद्योगों और व्यवसायों में लागू होना चाहता है तथा विनियोग करना चाहता है।

३—यमिक की हार्दिक इच्छा यही रहती है कि वह अपनी शक्ति, इच्छा, कुशलता एवं अभिरुचि के अनुसार कार्य प्राप्त कर सके।

४—केन्द्रीय नियोजन की सफलताएँ सीमित हैं—वास्तव में, केन्द्रीय नियोजन के विषय में प्रायः यह कहा जाता है कि "केन्द्रीय नियोजन से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का लोप हो जाता है और आर्थिक विकास का उद्देश्य भी सफल नहीं हो पाता।"

उपरोक्त बातों के अध्ययन से हम साधारणतया इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जहाँ निजी क्षेत्र का आधिपत्य हो वहाँ 'आज्ञामूलक' नियोजन पद्धति असफल रहती है। किन्तु, यह बात उन क्षेत्रों के लिये सही नहीं है जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का आधिपत्य है या केन्द्रीय नियोजन के अन्तर्गत राष्ट्र की समस्त उत्पाति संस्थाओं पर राष्ट्र का अधिकार है।

'प्रोत्साहनमूलक' नियोजन पद्धति पूँजीवादी राष्ट्रों में या मिश्रित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में अधिक प्रभावशील होता है। इस प्रथा के अन्तर्गत सरकार

द्वारा साहसियों और उद्योगपतियों को आर्थिक विकास के कार्य को द्रुत गति से कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं। इस कार्य में सरकार इस बात की ओर सचेष्ट रहती है कि साहसी और उद्योगपति एक निश्चित आदर्श की प्राप्ति के लिये एकाकी या सामूहिक रूप से प्रयास करे। इस प्रयास में यदि उन्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो सरकार उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करती है।

इस 'प्रोत्साहनमूलक' नियोजन में नियोजन का कार्य सरकार और साहसी दोनों के सम्मिलित प्रयास से होता है। सरकार द्वारा आदर्श, उद्देश्य और लक्ष्य का निर्धारण होता है एवं 'कठिनाइयों' को दूर करने का प्रयास किया जाता है तथा प्रोत्साहन दिया जाता है। इस प्रकार के नियोजन का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि आर्थिक विकास का कार्य द्रुत गति में होता है—क्योंकि साहसी निजी लाभ के उद्देश्य में उद्यम के साथ कार्य करता है। इसके विपरीत, इस प्रणाली का दोष यह होता है कि सरकारी नियन्त्रण के अभाव में पूँजीवादी प्रथा के समस्त अवगुण इसमें आ जाते हैं।

'आज्ञामूलक' नियोजन प्रणाली के समर्थकों का कहना है कि "नियोजन का उद्देश्य ही निजी क्षेत्र की कठिनाइयों को दूर करना होता है।" उद्योग-पतियों, और पूँजीपतियों के शोषण को समाप्त करने तथा द्रुत एवं सन्तुलित आर्थिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही 'नियोजन' को अपनाते हैं। इसका केवल एक ही अर्थ होता है—नियोजन केवल 'आज्ञामूलक' ही होना चाहिये।

सोवियतसंघ में जब GOSPLAN द्वारा इस की प्रथम योजना का निर्माण किया गया था तो उसमें 'आज्ञामूलक नियोजन के साथ-साथ 'प्रोत्साहनमूलक' पद्धति को भी अपनाया गया था। इसका कारण यह था कि उस समय तक वहाँ उत्पत्ति और वितरण के समस्त साधनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया था। इसके पश्चात् जब वहाँ केन्द्रीयकरण हो गया तो नियोजन कार्य के लिए एक ही प्रणाली अपनाई गई—'आज्ञामूलक प्रणाली'। चीन में भी अपनी पहली योजना में, थोड़ी मात्रा में, 'प्रोत्साहनमूलक प्रणाली' को नियोजन में स्थान दिया था। किन्तु द्वितीय योजना में केवल 'आज्ञामूलक प्रणाली' को ही अपनाया। भारतवर्ष में प्रथम पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र के आधिपत्य के कारण 'प्रोत्साहन द्वारा नियोजन' पर अधिक बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज को स्थापना पर अधिक बल दिया गया। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ एवं 'आज्ञामूलक' नियोजन प्रणाली का क्षेत्र भी इस योजना-काल में बढ़ गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का और विस्तार किया जा रहा है, इसलिये, साधारण रूप से 'आज्ञामूलक प्रणाली' का महत्त्व और बढ़ गया है। क्योंकि भारतवर्ष में अभी तक निजी क्षेत्र का भी सह अस्तित्व

है इसलिये प्रोत्साहन द्वारा नियोजन पद्धति भी, अभी तक यहाँ विद्यमान है। इन दोनों प्रणालियों में 'आज्ञामूलक' अधिक अच्छी समझी जाती है।

१०—नियोजन पद्धति : फासिज्म बनाम नाजीज्म^१

(Planning Concepts : Fascism Vs Nazism)

माजीज्म एवं फासिज्म दोनों ही निरकुसतावादी (Estatist) विचारधाराएँ हैं। फाजीज्म के अनुसार समाज में राज्य का स्थान सर्वोच्च है। म्यूसोलिनी का कथन था, "हर वस्तु तथा व्यक्ति राज्य के अन्तर्गत एवं राज्य के लिए है, राज्य के बाहर या विरुद्ध कोई या कुछ नहीं हो सकता... परन्तु नाजीवादी राज्य के स्थान पर राष्ट्र को सर्वोच्च मानते हैं।" नाजीज्म एवं फासिज्म दोनों ही प्रणालियों में यह पाया जाता है कि राज्य नागरिकों की जीवन सम्बन्धी सभी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास करता है। "इन प्रणालियों के द्वारा वे पूँजीवाद तथा समाजवाद दोनों के समर्थक होने का दावा कर सकते हैं। इटली में यह ढंग था निगमात्मक राज्य (Corporate State) की योजना और जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद की कल्पना। वास्तव में दोनों का ही मूल उद्देश्य राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर नियन्त्रण स्थापित करना था।"^२

"मिन्हीकेटो, उनके सभों (Federations) तथा महासभों (Confederations) और निगमों (Corporations) द्वारा फासिस्ट राज्य का इटली में पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर नियन्त्रण हो गया था। इसी प्रकार की व्यवस्था जर्मनी में भी की गई थी। वहाँ उसको राष्ट्रीय समाजवाद के नाम से पुकारा जाता था।"^३
"फासिज्म और नाजीज्म दोनों के अन्तर्गत देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं पर सरकार द्वारा नियन्त्रण एवं योजना नियोजन होता है।"^४

१. पूँजीवाद नियोजन के लिए अध्याय ८ देखिए।

२. समाजवादी, मार्क्सवादी तथा साम्यवादी नियोजन के लिए अध्याय ९ देखिए।

३. मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत नियोजन के लिए अध्याय १० देखिए।

४. राजनीति शास्त्र के आधार, द्वितीय भाग, अम्बादत्त पन्त आदि, पृष्ठ ३०१।

५. Ibid, p 302.

६. For further details, please see Appendix iv.

अविकसित देशों की आर्थिक विशेषतायें^१

(Characteristics of an Under-developed Economy)

१—अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा

(Meaning and Definition of an Under-developed)

अविकसित अर्थव्यवस्था का अध्ययन पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है और तभी से ससार के विभिन्न अर्थशास्त्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। विशेष तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास के साथ-साथ विद्वानों का ध्यान इस ओर भी गया कि ससार के सभी राष्ट्र धीरे-धीरे आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति करें ताकि उन्हें दूसरे देशों के भरोसे पर न रहना पड़े और उन्नत देश इन राष्ट्रों का आर्थिक दृष्टि से शोषण न कर सकें। समाजवादी अर्थव्यवस्था का कुछ देशों में अपनाया जाना और उन देशों में आर्थिक नियोजन के द्वारा अल्प समय में द्रुत आर्थिक उन्नति का होना अविकसित देशों के लिए एक आदर्श बन गया।

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अविकसित अर्थव्यवस्था की भिन्न-भिन्न रूप से व्याख्या की है। कुछ का कहना है कि “अविकसित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें प्राकृतिक सम्पत्तियों का सन्तुलित और ढगपूर्ण शोषण नहीं होना है।” इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि “अविकसित देशों में कुछ कठिनाइयों के अस्तित्व के कारण साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है।” इसी प्रकार एक अन्य वर्ग के अर्थशास्त्री यह समझते हैं कि साधनों के उपलब्ध होने पर भी जिन देशों की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आमदनी कम है वे अविकसित देश कहे जा सकते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जिन देशों में उत्पत्ति के साधन कम हैं, या जिन देशों में उत्पत्ति के विभिन्न प्रयासों में (खेती, व्यवसाय, उद्योग आदि) असमानता है, या जिस देश में राष्ट्रीय आय कम है, या जिस देश में उत्पत्ति के साधनों की कमी है, या जिस देश में साधनों का सम्पूर्ण और ढगपूर्ण प्रयोग नहीं होता है, या जिस देश में समस्त प्राकृतिक सम्पत्तियों का समान शोषण नहीं होता वह देश अविकसित कहलाता है।

१. इसमें विशेष तौर पर भारतीय स्थिति का अध्ययन किया गया है।

है इसलिये प्रोत्साहन द्वारा नियोजन पद्धति भी, अभी तक यहाँ विद्यमान है। इन दोनों प्रणालियों में 'आज्ञाभूतक' अधिक अच्छी समझी जाती हैं।

१०—नियोजन पद्धति : फासिज्म बनाम नाजीज्म^१ (Planning Concepts : Fascism Vs Nazism)

नाजीज्म एवं फासिज्म दोनों ही निरंकुशतावादी (Estatist) विचारधारार्थ हैं। फाजीज्म के अनुसार समाज में राज्य का स्थान सर्वोच्च है। मुसोलिनी का कथन था, "हर वस्तु तथा व्यक्ति राज्य के अन्तर्गत एवं राज्य के लिए है, राज्य के बाहर या विरुद्ध कोई या कुछ नहीं हो सकता परन्तु नाजीवादी राज्य के स्थान पर राष्ट्र को सर्वोच्च मानते हैं।" नाजीज्म एवं फासिज्म दोनों ही प्रणालियों में यह पाया जाता है कि राज्य नागरिकों की जीवन सम्बन्धी सभी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास करता है। "इन प्रणालियों के द्वारा वे पूँजीवाद तथा समाजवाद दोनों के समर्थक होने का दावा कर सकते हैं। इटली में यह दृग या निगमात्मक राज्य (Corporate State) की योजना और जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद की कल्पना। वास्तव में दोनों का ही मूल उद्देश्य राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर नियन्त्रण स्थापित करना था।"^२

'सिन्डीकेटो, उनके सघो (Federations) तथा महासघो (Confederations) और निगमो (Corporations) द्वारा फासिस्ट राज्य का इटली में पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर नियन्त्रण हो गया था। इसी प्रकार की व्यवस्था जर्मनी में भी की गई थी। वहाँ उसको राष्ट्रीय समाजवाद के नाम से पुकारा जाता था।'^३

• फासिज्म और नाजीज्म दोनों के अन्तर्गत देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं पर सरकार द्वारा नियन्त्रण एवं योजना नियोजन होता है।^४

१ १—पूँजीवाद नियोजन के लिए अध्याय ८ देखिए।

२—समाजवाद, मार्क्सवाद तथा साम्यवाद नियोजन के लिए अध्याय, १ देखिए।

३—मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत नियोजन के लिए अध्याय १० देखिए।

४ राचनाति शास्त्र के आधार, द्वितीय भाग, अम्बादत्त पन्त आदि, पृष्ठ ३०१।

३ Ibid, p 302

4. For farther details, please see Appendix IV.

अविकसित देशों की आर्थिक विशेषतायें¹

(Characteristics of an Under-developed Economy)

१—अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा

(Meaning and Definition of an Under-developed)

अविकसित अर्थव्यवस्था का अध्ययन पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है और तभी से ससार के विभिन्न अर्थशास्त्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। विशेष तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास के साथ-साथ विद्वानों का ध्यान इस ओर भी गया कि ससार के सभी राष्ट्र धीरे-धीरे आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति करें ताकि उन्हें दूसरे देशों के भरोसे पर न रहना पड़े और उन्नत देश इन राष्ट्रों का आर्थिक दृष्टि से शोषण न कर सकें। समाजवादी अर्थव्यवस्था का कुछ देशों में अपनाया जाना और उन देशों में आर्थिक नियोजन के द्वारा अल्प समय में द्रुत आर्थिक उन्नति का होना अविकसित देशों के लिए एक आदर्श बन गया।

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अविकसित अर्थव्यवस्था की भिन्न-भिन्न रूप से व्याख्या की है। कुछ का कहना है कि “अविकसित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें प्राकृतिक सम्पत्तियों का सन्तुलित और ढगपूर्ण शोषण नहीं होना है।” इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि “अविकसित देशों में कुछ कठिनाइयों के अस्तित्व के कारण साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है।” इसी प्रकार एक अन्य वर्ग के अर्थशास्त्री यह समझते हैं कि साधनों के उपलब्ध होने पर भी जिन देशों की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आमदनी कम है वे अविकसित देश कहे जा सकते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जिन देशों में उत्पत्ति के साधन कम हैं, या जिन देशों में उत्पत्ति के विभिन्न प्रयासों में (खेती, व्यवसाय, उद्योग आदि) असमानता है, या जिस देश में राष्ट्रीय आय कम है, या जिस देश में उत्पत्ति के साधनों की कमी है, या जिस देश में साधनों का सम्पूर्ण और ढङ्गपूर्ण प्रयोग नहीं होता है, या जिस देश में समस्त प्राकृतिक सम्पत्तियों का समान शोषण नहीं होता वह देश अविकसित कहलाता है।

1. इसमें विशेष तौर पर भारतीय स्थिति का अध्ययन किया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकसित देश वह है जो या तो (अ) उत्पत्ति के साधनों, सुविधाओं और प्राकृतिक सम्पदा से वंचित है, या (ब) वह देश, जिनके पास साधन, शक्ति, प्राकृतिक सम्पत्ति और सुगवसर प्राप्त है (जिससे वह देश के आर्थिक ढांचे में सुधार करके देश को उन्नत बना सकें), परन्तु किसी कठिनाई या कठिनाइयों के अस्तित्व के कारण इस प्रयास में सफल नहीं हो रहा है। भारतवर्ष भी इसी वर्ग में आता है।

भारतवर्ष पिछली कई सदियों से पराधीन रहा है। इसके फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था का विकास उस रूप में न हो सका, जिस रूप में होना चाहिये था, बल्कि उस रूप में हुआ जिस रूप में अंग्रेज अपने लाभ के लिए करना चाहते थे। अर्थात् भारतवर्ष का आर्थिक विकास उसकी स्थिति, जलवायु, जनसंख्या, प्राकृतिक सम्पत्ति, शक्ति के साधन, और प्राकृतिक साधनों की दृष्टिकोण में रखकर नहीं किया गया। बल्कि इस रूप में किया गया कि ब्रिटेन के उद्योगों को कम से कम मूल्य पर अच्छी से अच्छी काफी सामग्रियाँ प्राप्त हो सकें। देश की कृषि दिनो दिन अधनति की ओर जाती रही और उपज में वृद्धि के लिये खेती में नवीनतम पद्धतियों का प्रयोग या सिंचाई का सुचारु रूप से प्रबन्ध नहीं किया गया। इसी के साथ-साथ जनसंख्या की वृद्धि ने और देश के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों ने खेतों के और छोटे-छोटे टुकड़े बना दिये। जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत की प्रायः सभी भूमि पर उत्पत्ति-ह्रास-नियम लागू होने लगा। भारत में पूर्व स्थित गृह-उद्योग और छोटे माना के उद्योगों के अंग्रेजों द्वारा नष्ट किये जाने के फलस्वरूप और अधिक व्यक्ति—जो वास्तव में अनावश्यक थे—कृषि कार्य में मजबूरी से जुट गये। इन सब बातों के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आमदनी बहुत कम हो गई। साथ ही साथ इन दरिद्र किसानों की वह शक्ति भी समाप्त हो गई जिससे वे अधिक उत्पत्ति के लिए कृषि पद्धति में सुधार कर सकते थे। इस प्रकार भारत के किसान जो प्रायः समस्त आबादी के—७०-७५ प्रतिशत हैं, और अधिक गरीब हो गये।

भारत में बड़ी मात्रा के जो बोरे से उद्योग खोले गये उनमें से प्रायः सभी विदेशी साहसी द्वारा और विदेशी पूँजी से, खोले गये। इससे एक ओर तो देशी उद्योग घनघे नष्ट हो गये और दूसरी ओर देश का सारा धन इन विदेशियों के हाथ पहुँच गया।

इसके अतिरिक्त भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति के विकास का कोई प्रयास नहीं किया गया और वास्तव में इन प्राकृतिक साधनों का अग्रमान, प्रसन्नतुलित और अन्यायपूर्ण शोषण हुआ। इसका एकमात्र उद्देश्य ब्रिटेन के उद्योगों का विस्तार करना था। उसका भी परिणाम यह हुआ कि भारतीय नागरिकों की आमदनी कम से कम होनी चली गई और देश की प्राकृतिक सम्पदा भी निश्चेष्ट होती गई।

देश में जनसंख्या की अनियन्त्रित वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, बेरोजगारी का बढ़ना, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का देश में स्थापित होना सभी इस बात में सहायक थे कि देश की आर्थिक स्थिति में और तीव्रता से अवनति आये। इस प्रकार अविकसित अर्थ व्यवस्था की स्थिति भारतवर्ष में बनी। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् से राष्ट्रीय सरकार इस ओर सचेष्ट है कि इस अवस्था में सुधार लाये और देश की आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाए।

२—अविकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण कौन कौन से हैं ?

(Symptoms of an Underdeveloped Economy)

इसका यदि हम विश्लेषण करें तो अविकसित अर्थव्यवस्था के कुछ लक्षण हमारे सामने आ जावेंगे। उनमें से कुछ ये हैं—

१—देश की आबादी में तीव्रता से वृद्धि—इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है—विशेषतः पर यदि वह देश पहले से ही घनी आबादी का हो। भारतवर्ष में अधिक जनसंख्या के विद्यमान होते हुए भी देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। लेकिन देश की कृषि-उत्पत्ति, व्यवसाय और उद्योग और प्राकृतिक साधनों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसलिए प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आमदनी में वृद्धि कठिनाई से हो रही है और देश में भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ती आ रही है।

२—उद्योग धंधों का असन्तुलित और भ्रष्ट विकास—अविकसित देशों का दूसरा लक्षण यह होता है कि उन देशों में उद्योग धंधों का विकास कम और असन्तुलित रूप से होता है जिससे उत्पत्ति के बहुत से साधन बेकार पड़े रहते हैं। भारत में भी उद्योग धंधों के वितरण का जितना अवसर और साधन प्राप्त है उस अनुपात में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है और न हो पा रहा है।

३—शासन और प्रबन्ध की अक्षमता—देशों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रबन्ध और शासन ठीक प्रकार से नहीं चल पाते जिससे देश के किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विस्तार उस रूप में और उस तीव्रता से नहीं हो पाता जैसा कि होना चाहिए। देश की आर्थिक नीति, ऋण प्रणाली, मुद्रा स्थिति, व्यवसाय नीति और उस प्रकार के अन्य विषयों का प्रबन्ध जब तक पूर्ण दक्षता से नहीं किया जाता तब तक उन राष्ट्रों का आर्थिक विकास कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव हो जाता है। दुर्भाग्यवश भारत में उपरोक्त विषयों का प्रबन्ध और शासन अकुशल है।

४—देश में पूँजी की कमी—प्रायः यह देखा जाता है कि अविकसित देशों में जहाँ एक ओर उत्पत्ति के साधनों की (पूँजी के अतिरिक्त) कमी नहीं होती, वहाँ दूसरी ओर देश में उपलब्ध पूँजी की मात्रा में कमी होती है, जिसके कारण देश के उद्योग धंधों का ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता। पूँजी की कमी इन देशों में मुख्य रूप से इसलिए होती है कि लोगों की आमदनी बहुत कम होती है जिसके

फलस्वरूप वे वचत नहीं कर सकते और जब वचत नहीं हो पाती तो पूँजी का निर्माण नहीं हो पाता ।

५—उत्पत्ति के विभिन्न प्रवासों में असन्तुलन—अविकसित देशों का एक लक्षण यह भी होना है कि इन देशों में असन्तुलित प्रयास होते हैं, अर्थात् उत्पत्ति के विभिन्न क्षेत्रों को (जैसे-कृषि उद्योग धन्यो आदि) समान महत्त्व प्रदान नहीं किया जाता । प्रायः ऐसा होता है कि या तो कृषि पर आवश्यकता से अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है या उद्योग धन्यो पर या कभी कभी केवल एक ही उद्योग के विकास पर । इसी प्रकार इन क्षेत्रों में उत्पत्ति की जो मात्रा होनी है (जैसे, बड़ी मात्रा की उत्पत्ति, गृह उद्योग आदि उनमें भी सन्तुलन नहीं होता है । उत्पत्ति की इन मात्राओं में जो अंतरांग अनुपात होना चाहिए वह नहीं होता । इन सब बातों का प्रभाव यही होता है कि देश की आर्थिक स्थिति में उन्नति उस रूप से नहीं हो पाती जैसी कि होनी चाहिये ।

भारतवर्ष के विषय में यह बातें सत्य हैं । भारतवर्ष में कृषि पर अत्यधिक जोर दिया जाता है जब कि उद्योग धन्यो के विकास पर उतना महत्त्व प्रदान नहीं किया जाना जितना कि देना चाहिए । इसके फलस्वरूप कृषि में आवश्यकता से अधिक मनुष्य जुटे हुए हैं, और उद्योग क्षेत्र में विकास की सम्भावना होती हुए भी माधनों का सम्पूर्ण प्रयोग नहीं हो पा रहा है । इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में बड़ी मात्रा की उत्पत्ति पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है, जबकि देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार इन बड़े उद्योगों के साथ साथ मध्यमाकार की उत्पत्ति संस्थाओं, छोटी मात्रा की उत्पत्ति संस्थाओं और गृह उद्योगों के विकास पर अधिक बल देना चाहिए ताकि देश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ बेरोजगार की दशा में भी सुधार हो सके ।

६—विदेशी राज्य—प्रायः यह देखा जाता है कि उन देशों की आर्थिक स्थिति अविकसित रह जाती है जो दूसरे देशों के द्वारा शासित होते हैं । इसके दो कारण होते हैं । प्रथम तो यह कि विदेशी शासक स्वयं यह नहीं चाहता कि उस देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाय क्योंकि उस स्थिति में उस देश के स्वतन्त्र हो जाने की सम्भावना होती है । और दूसरा कारण यह कि विदेशी शासक अपने देश में उत्पन्न वस्तुओं को इन देशों में बेचना चाहता है—जो तभी सम्भव हो सकता है जब कि यह देश पिछला हुआ हो ।

भारतवर्ष में भी, जब तक ब्रिटिश शासन बना रहा, ऐसी ही स्थिति बनी रही । सन् १९४७ के बाद से, जब देश की स्वतन्त्रता मिली, तभी से भारतवर्ष के उद्योग धन्यो में उन्नति हुई है और सरकार की ओर से इस बात का भरसक प्रयास किया जा रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति में निरन्तर उन्नति हो ।

परन्तु हमेशा यह आवश्यक नहीं होना कि अविकसित देशों में विदेशी शासन ही हो ।

(७) देश में साधनों की कमी—कुछ राष्ट्रों की आर्थिक दशा इसलिए भी बिगड़ी रहती है कि उन देशों में साधनों की कमी होती है। इन साधनों में सभी बातें सम्मिलित होती हैं—जैसे प्राकृतिक सम्पत्ति, ऋषि योग्य भूमि, शिक्षित और कुशल कारीगर, चल और अचल पूँजी, उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री, उद्योगधंधों की स्थापना के लिए साहसियों का अभाव, अच्छे प्रबंधकों की कमी आदि। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि इस प्रकार के देशों में इच्छा होते हुए भी आर्थिक स्थिति में सुधार संभव नहीं हो पाता है और उन देशों की आर्थिक स्थिति हमेशा ही अविकसित रहती है।

३—अविकसित देशों का अस्तित्व क्यों होता है ?

प्रायः यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि अविकसित देशों का अस्तित्व क्यों होना है जब कि ससार की सभी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और उन्नत तथा अनुन्नत देश इस ओर सचेष्ट हैं कि ससार में कोई देश अविकसित न रह जाय। इन देशों के अविकसित रहने के निम्नलिखित चार मुख्य कारण हैं—

(१) प्राकृतिक कारण, (२) राजनैतिक कारण, (३) सामाजिक कारण, और (४) आर्थिक कारण।

प्राकृतिक कारण—विभिन्न राष्ट्रों की भयंकरवस्था के अविकसित रहने का प्राकृतिक कारण प्रायः यह होता है कि उन देशों में प्राकृतिक सम्पत्ति बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। इसी के साथ एक कारण उस देश में प्राप्त प्राकृतिक वातावरण और जलवायु भी हो सकती है। जिन देशों में प्राकृतिक सम्पत्ति कम, निकुण्ड और अनुपयोगी होती है या प्राकृतिक सम्पत्ति बहुत कम प्राप्त होती है, उन देशों का आर्थिक विकास बहुत कठिनाई में हो पाता है। इसी प्रकार जिस देश का प्राकृतिक वातावरण और जलवायु प्रतिकूल होता है वहाँ रहने वाले मनुष्यों की कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं हो पाती। अतः देश की आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो पाता।

राजनैतिक कारण—ये कारण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे, यदि किसी देश पर विदेशी शासन हो तो प्रायः उस देश की आर्थिक प्रगति सन्तोषजनक रूप से नहीं हो पाती। इसी प्रकार देश में जो राजनैतिक दल सत्ताधारी होता है उसकी औद्योगिक और आर्थिक नीति यदि त्रुटिपूर्ण होती है तो भी उन राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति में प्रायः सुधार नहीं हो पाता। राजनैतिक नीति के कुप्रभाव में यदि किसी राष्ट्र का किसी विदेशी राष्ट्र या राष्ट्रों के साथ सदा मनमुटाव और युद्ध की आशंका बनी रहती है तो भी उस देश की आर्थिक स्थिति में उस रूप से सुधार नहीं हो पाता जैसा कि होना चाहिए। देश का शासन अगर बहुत ही ढीला और दोषपूर्ण हो और देश में शान्ति तथा सुरक्षा का अभाव हो तो भी आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती।

सामाजिक कारण—ये कारण बहुत से हो सकते हैं। विभिन्न वर्ग और स्तरों में अन्तर, एक दूसरे के विपरीत सामाजिक नियमों का अस्तित्व और सामाजिक नियमों का अत्यधिक रूप से धर्मों द्वारा प्रभावित होना आदि कुछ ऐसे सामाजिक कारण हैं जो आर्थिक विकास के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

भारतवर्ष में विभिन्न जातियों या अस्तित्व, जाति-पाँति का भेद-भाव, छुआ-छूत, संयुक्त परिवार की प्रथा का अस्तित्व, विभिन्न प्रकार के सामाजिक स्तर और उनके अलग-अलग सामाजिक नियमों का अस्तित्व, विभिन्न प्रतिरोधी धर्मों तथा धार्मिक-भावनाओं का अस्तित्व और उनका सामाजिक प्रभाव, परिवार नियोजन की भावनाओं को अधार्मिक और प्रकृति विरोधी माना जाना, जिसमें जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, आदि कुछ ऐसे सामाजिक कारण भारत में विद्यमान हैं जो आर्थिक प्रगति के पथ को रोक देते हैं। अविकसित देशों का यह एक मुख्य लक्षण भी है।

आर्थिक कारण—इन कारणों में सबसे प्रथम देश में प्राप्त प्राकृतिक सम्पत्ति का उल्लेख हाता है। प्राकृतिक सम्पत्ति यदि विभिन्न प्रकार की और अधिक होती है तो प्रायः आर्थिक उन्नति सरलता से सम्भव होती है। परन्तु यदि प्राकृतिक सम्पत्ति कम हो और उसका शोषण भी उचित ढंग से न हो तो आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। उत्पत्ति के प्रयासों में से किसी एक प्रयास पर अत्यधिक बल प्रदान करना और दूसरे प्रयासों की व्यवहेलना करना भी राष्ट्रों के आर्थिक दृष्टिकोण से अविकसित रहने के कारण होते हैं। इसी प्रकार आमदनी में कमी, उपभोग की मात्रा में कमी जीवन स्तर का अवनत होना शिक्षा और काम कुशलता में कमी, उत्पत्ति के साधनों का उपयोग न हो पाना, पूँजी की कमी, विनियोग की सुविधायें प्राप्त न होना, योग्य साहसियों और प्रबन्धकों की कमी, देश की भ्रष्टपूर्ण औद्योगिक, आर्थिक, राजनैतिक और वित्तीय नीति, देश में शांति और सुरक्षा का अभाव और सबसे ऊपर, देश में एक ऐसे वातावरण का अभाव जिससे आर्थिक विकास शीघ्रता से और सरलता से हो सके। ये कुछ अन्य आर्थिक कारण हैं जिनसे कुछ राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति अविकसित रह जाती है।

अविकसित देशों के आर्थिक विस्तार के प्रयासों में बहुत सी कठिनाइयाँ भी आती हैं, जिनका सहो हल हो जाने पर आर्थिक विकास का मार्ग खुल जाता है। जैसे हम इस प्रश्न का उत्तर ढूँढना पड़ता है कि आर्थिक विकास का प्रयास समाज के उच्चतम स्तर से शुरू कर या निम्नतम स्तर से? उच्चतम स्तर में कम संख्या होने के कारण उसका नियोजन और प्रबन्ध सरलता से हो सकता है किन्तु यह स्तर तो पहले से ही उन्नत है। इसको और उन्नत बनाने में धन का असमान वितरण हो सकता है। यदि निम्नतम स्तर को उन्नत बनाने की योजना बनाई जाय तो अत्यधिक पूँजी, प्रयास और साधनों की आवश्यकता होती है, जो अविकसित देशों में

प्राप्त नहीं हो सकती । इसलिए उन देशों की आर्थिक उन्नति के लिए इस प्रकार का नियोजन करना पड़ता है जिससे वर्ग भेद मिट जाय और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार सम्भव हो सके ।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अविकसित देशों के उन्नति के पथ पर राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जो कारण हैं उनको सामूहिक प्रयास से यदि दूर कर दिया जाय तथा साथ ही साथ देश में विभिन्न प्रकार की उत्पत्ति संस्थाओं में सुधार किये जायें और नियोजन के आधार पर देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जाये, तो आर्थिक दृष्टिकोण से अविकसित राष्ट्र धीरे-धीरे विकसित राष्ट्रों में परिणत हो सकते हैं ।

४—अविकसित देशों की आर्थिक प्रगति में बाधाएँ

विभिन्न अर्थशास्त्रियों में प्रायः इस बात पर वाद-विवाद होता है कि अविकसित देशों की आर्थिक उन्नति ठीक रूप से और शीघ्रता से क्यों नहीं होती ? एक वर्ग के अर्थशास्त्रियों का जिनका दृष्टिकोण निराशावादी (Pessimistic) है—यह कहना है कि इन देशों में आर्थिक उन्नति कभी नहीं होगी, यह सर्वथा अमपूर्ण है । दूसरे वर्ग के अर्थशास्त्रियों का यह कहना है (जिसमें अधिकतर विद्वान हैं) कि अविकसित देशों के सामने कुछ कठिनाइयाँ होती हैं जिनके कारण इन देशों में आर्थिक विकास नहीं हो पाता । यदि यह कठिनाइयाँ दूर कर दी जायें तो इन देशों में आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा । अविकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के पथ में निम्नलिखित मुख्य बाधाएँ आती हैं —

१—अति जनसंख्या (Over population)—अविकसित देशों की आर्थिक अविति का एक कारण तीव्रता से जनसंख्या का बढ़ना होता है । जिन देशों में पहले से ही जनसंख्या अधिक होती है, उनमें यदि निरन्तर वृद्धि होती रहे तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब कि देश का सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचा ही अव्यवस्थित हो जाता है । जनसंख्या अधिक होने से देश में अकाल, भुखमरी, बीमारियाँ, प्राकृतिक प्रकोप आदि में वृद्धि होती है । इसी प्रकार देश में बेरोजगारी फैलती है, राष्ट्रीय आय में कमी आ जाती है, प्रति व्यक्ति आमदनी कम हो जाती है, जीवन स्तर गिर जाता है, कार्य कुशलता में वृद्धि नहीं हो पाती, आर्थिक विकास की सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पाती । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जनसंख्या का आधिक्य होने से मनुष्यों का दृष्टिकोण निराशापूर्ण हो जाता है, कृषि पर अत्यधिक बल प्रदान किया जाता है, जिससे आगे चल कर खेतों में उत्पत्ति-ह्रास-नियम लागू हो जाता है और उत्पत्ति की मात्रा कम होनी जाती है । इस प्रकार हम यह देखते हैं कि किसी देश में जनसंख्या का आधिक्य होने से उसका सामाजिक, राजनैतिक, चारित्रिक और आर्थिक पतन-होता है । भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य देशों में सतुलित रूप के आर्थिक विकास न होने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है । समाज और राष्ट्र

के समुक्त प्रयास द्वारा जब तक इन देशों की जनसंख्या की वृद्धि पर पूरा नियन्त्रण न हो और परिवार नियोजन की भावना का विस्तार न हो तब तक अधिक जनसंख्या की कठिनाइयों का दूर होना कठिन प्रतीत होता है ।

२—बाजार की कठिनाइयाँ (Marketing Imperfections)—आर्थिक विकास के लिए दो बातें बहुत आवश्यक समझी जाती हैं । एक तो यह कि सम्पूर्ण बाजार पर प्रभुत्व तथा नियन्त्रण सरकार द्वारा हो जिससे विभिन्न वर्गों का शोषण समाप्त हो जाये, और दूसरा बाजार में विनिमय का कार्य पूरा प्रतिযোগिता के अन्तर्गत तथा बाजार के नियमों के अनुसार हो ।

अविकसित देशों में इन दोनों बातों में से कोई भी एक बात पूर्णरूप से लागू नहीं होती । इन देशों में जब तक उत्पत्ति और वितरण के समस्त साधनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण नहीं होता है तब तक उत्पत्ति और वितरण के अधिकतर साधन कुछ पूँजीपतियों के हाथों में होते हैं । जिसके फलस्वरूप इन देशों के बाजारों में बाजार के नियम सही रूप से लागू नहीं हो पाते और पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के सभी अवगुण दिखाई पड़ते हैं । व्यापार चक्र का प्रभाव, अति उत्पादन और अल्प उत्पादन के कुप्रभाव, गलाकाट प्रतिस्पर्धा का अस्तित्व, विभिन्न उत्पादकों में एक-ऐसा संघर्ष और 'अनार्थिक' प्रतिस्पर्धा (जिससे राष्ट्र के निवासियों को विभिन्न प्रकार की हानि उठानी पड़ती है,) अत्यधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति और देश में धन का असमान वितरण कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका जन्म और विस्तार बाजार की त्रुटियों के अस्तित्व में ही होता है । इन त्रुटियों के रहने के कारण ही एकाधिकार की स्थापना होती है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है जिससे नागरिकों का जीवन स्तर नीचा हो जाता है, उद्योग धंधों का ठीक विस्तार नहीं हो पाता और कभी-कभी देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग नहीं हो पाता । यह सब तथ्य ऐसे हैं जो किसी भी राष्ट्र को आर्थिक दृष्टिकोण से पीछे की ओर धकेलते हैं और उन प्रयासों के आगे दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं जो आर्थिक विकास के लिए किये जाते हैं । अविकसित देश आर्थिक उन्नति तभी कर सकते हैं जब वे इन कठिनाइयों को दूर करके सरकार और जनता के सामूहिक प्रयास से एक ऐसी आदर्श परिस्थिति की स्थापना कर सकें जो उन्हें आर्थिक प्रगति की ओर ले जा सके ।

३—विदेशी विनियोग से उत्पन्न कठिनाइयाँ (Repercussions of Foreign Investments)—अविकसित देशों को आर्थिक विकास की एक और बाधा देश स्थित विदेशी विनियोग से होता है । आर्थिक दृष्टिकोण से पीछड़े हुए देशों में प्रायः पूँजी का विनियोग उन विदेशी राष्ट्रों द्वारा होता है जो आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि में उन्नत हैं । इसके कारण दो होते हैं । पहला, इन पीछड़े हुए देशों के पास विनियोग योग्य पूँजी का अभाव होता है और दूसरा कारण यह कि उन्नत देश उस और प्रयत्नशील रहते हैं कि उन्हें दूसरे देशों में विनियोग करने की

सुविधा के अवसर प्राप्त हो । इन दोनों ही कारणों या किसी एक कारणवश पिछड़े हुए देशों में विदेशी विनियोग होता है । उसका परिणाम हमेशा घातक होता है । विदेशी साहसी केवल निजी लाभ के उद्देश्य से या अपने राष्ट्र-हित के उद्देश्य से इन पिछड़े हुए देशों में उत्पात्ति और वितरण का कार्य करते हैं । वास्तव में, इन विदेशी साहसियों द्वारा इन पिछड़े हुए राष्ट्रों का आर्थिक शोषण होता है और वे उनके आर्थिक विकास में हमेशा के लिए बाधक रहते हैं । इन देशों के साहसी जब कभी भी उद्योगों की स्थापना का प्रयास करते हैं तो वे विदेशी साहसी अपनी सत्ता और शक्ति के द्वारा उन प्रयास को व्यर्थ कर देते हैं, जिससे उन राष्ट्रों का आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो पाता । विदेशी साहसी मनमानी करते हैं और पिछड़े हुए राष्ट्रों का शोषण करके उनकी सम्पत्ति अपने राष्ट्र को पहुँचा देते हैं । जिससे अविकसित देश की दशा और विगड़ जाती है । इस कमी को दूर करने के उपाय यह हैं कि या तो उत्पात्ति और वितरण का समस्त स्वामित्व शायित्व और अधिकार सरकार अपने हाथ में ले ले और इस प्रकार राष्ट्रीय और विदेशी समस्त उत्पात्ति सत्ताओं का राष्ट्रीयकरण हो जाय या सरकार की ओर से इन विदेशी साहसियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाय ताकि वे अपनी इच्छानुसार कार्य न कर सकें या राष्ट्र की सहायता से धीरे-धीरे विभिन्न उद्योगों की स्थापना राष्ट्र निवासियों द्वारा हो ।

४—सरक्षण का अभाव, घाटे की वित्तीय व्यवस्था और अरक्षित अर्थ व्यवस्था से उत्पन्न कठिनाइयाँ (Failures of 'Protection', 'Deficit financing' and threat to 'Exposed Economy')—अविकसित देशों की आर्थिक कठिनाइयाँ कई अन्य कारणों से भी उत्पन्न होती हैं, जैसे शिशु उद्योगों को राष्ट्र द्वारा सरक्षण न मिलना या राष्ट्रीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से सरक्षण न मिलना । घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अनियन्त्रित रूप से अपनाना और राष्ट्र में अरक्षित अर्थव्यवस्था का अस्तित्व आदि ।

पिछड़े हुए देशों के लिए यह बहुत आवश्यक होता है कि वह आर्थिक उत्पत्ति प्राप्त करने के लिए राष्ट्र के उद्योगों और साहसियों को सब प्रकार की सुविधायें प्रदान करे । इन सुविधाओं में पूँजी प्राप्त करना, देश में उद्योगों की स्थापना करना और उनका सफल संचालन, विदेशी आयात को रोकना, सरक्षण कर लगाना आदि सम्मिलित हैं । यदि पिछड़ा हुआ देश इन कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके तो कुछ समय के पश्चात् राष्ट्रीय आमदनी में आवश्यक रूप से वृद्धि होगी । परन्तु विदेशी प्रभाव के कारण और अपनी कमजोरियों के फलस्वरूप अविकसित देश इस सरक्षण-नीति का ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर सकता जिसके फलस्वरूप अविकसित देशों का आर्थिक विकास मन्द पड़ जाता है ।

अविकसित देशों में राष्ट्रोन्नति के उद्देश्य से घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अपनाया जाता है । घाटे की वित्तीय व्यवस्था तभी तक उचित समझी जा सकती है जब तक उसका पूर्ण नियन्त्रण सरकार द्वारा राष्ट्र हित के उद्देश्य से ठीक प्रकार

से सम्भव है। परन्तु प्रायः यह देखा जाता है कि अविकसित देश घाटे की वित्तीय व्यवस्था में निरन्तर वृद्धि करते जाते हैं। और एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का प्रसार इतना अधिक हो जाता है कि उसका नियन्त्रण बहुत कठिन हो जाता है। इससे देश में मुद्रा प्रसार हो जाता है, और वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। उसका परिणाम यह होता है कि जनता का उपभोग का स्तर और नीचा हो जाता है, जिससे जीवन स्तर भी गिर जाता है और अविकसित देश की आर्थिक स्थिति में और अधिक भ्रष्टावृत्ति आ जाती है।

इसी प्रकार 'अरक्षित भ्रष्टावृत्ति' का अस्तित्व अविकसित देशों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसमें देश की भ्रष्टावृत्ति पर सरकार का नियन्त्रण नहीं होता। कोई भी व्यक्ति (चाहे वह राष्ट्रीय हो या विदेशी) जिस रूप में भी चाहे धन या पूँजी का उपयोग कर सकता है, पूँजी का विनियोग कर सकता है, उत्पत्ति की मात्रा में विस्तार या संकुचन अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, आयात और निर्यात पर कोई विशेष नियन्त्रण नहीं होता। इस प्रकार अरक्षित भ्रष्टावृत्ति में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका अधिकतम लाभ विदेशी विनियोगी उठावे हैं। ये सब बातें अविकसित राष्ट्रों के आर्थिक विसास में बाधक होती हैं। हृष्ट की बात यह है कि अब प्रायः सभी अविकसित देश उपरोक्त बातों को सम्पूर्ण रूप से अपने अधीन करने का प्रयास कर रहे हैं और इन देशों की सरकारें इस ओर सचेष्ट हैं कि देश की औद्योगिक, व्यावसायिक, वित्तीय और अन्य आर्थिक प्रयास सम्बन्धी तत्त्व सम्पूर्ण रूप से उनके अधिकार और नियन्त्रण में हों।

५—औद्योगीकरण की कठिनाइयाँ (Problems of Industrialization) —विभिन्न राष्ट्रों के आर्थिक विकास में उद्योगों का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। औद्योगिक विकास का अर्थ होता है—देश स्थित प्राकृतिक सम्पत्तियों का सन्तुलित शोषण, वस्तु और सेवाओं की अधिकतम उत्पत्ति, अधिक आमदनी और जीवन स्तर में उन्नति, रोजगार की अधिक सुविधायें और राष्ट्र का आर्थिक विकास। अविकसित देशों में प्रायः औद्योगीकरण की सुविधायें उपलब्ध नहीं होती। पूँजी और विनियोग की सुविधाओं का अभाव, उद्योग धन्यो का स्थापित न होना, विदेशी प्रतिस्पर्धा से राष्ट्रीय उद्योगों की हानि और देशी उद्योगों द्वारा उत्पन्न वस्तु और सेवाओं को बाजार की अप्राप्ति, देश में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, शक्ति के साधनों में कमी या उत्पत्ति की अप्राप्तिक्रम प्रणालियों को अपना देने की असमर्थता, देश के औद्योगीकरण में बाधाएँ हैं। जब तक अविकसित देश इन बाधाओं को दूर करके देश में नये नये उद्योग धन्यो की स्थापना नहीं कर पायेंगे तब तक उनका आर्थिक विकास सम्भव न हो सकेगा। आर्थिक विकास के लिए उद्योग धन्यो, व्यवसाय और वित्त सम्बन्धी नीति में आवश्यक परिवर्तन करना आवश्यक होता है।

६—खाद्य पदार्थों की कमी (Food insufficiency)—अविकसित देशों में हमेशा खाद्य की कमी या अन्न सकट बना रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि राष्ट्र को सदा इस ओर सचेष्ट रहना पड़ता है कि विदेशों से खाद्य पदार्थों का आयात करके देशवासियों को भुखमरी से बचाये। इस प्रयास में सरकार का समय, शक्ति और बहुत सा धन नष्ट हो जाता है—जिनका प्रयोग यदि अन्य रूप से किया जाय तो देश की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो सकता है। इस प्रकार अविकसित देशों के लिए यह परमावश्यक समझा जाता है कि वह खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाय ताकि वह अपने साधन और शक्ति का प्रयोग देश के आर्थिक विकास के कार्यों में कर सके। भारतवर्ष और दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रायः सभी देशों में खाद्य पदार्थों की कमी बनी रहती है जिसके कारण उनकी आर्थिक विकास की योजनायें पूरे उद्यम से कार्य नहीं कर पाती।

७—दोषपूर्ण शासन प्रबन्ध (Faulty Public Administration) अविकसित देशों में प्रायः यह देखा जाता है कि वहाँ शासन प्रबन्ध उतना स्वतन्त्र और कुशल रूप से नहीं हो पाता जैसा कि होना चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे, प्रबन्ध-शिक्षा की कमी, देश में नैतिकता के सिद्धान्तों को कम अपनाया जाना, कमजोर सरकार का अस्तित्व या देश भक्ति का अभाव आदि। कभी-कभी तो शासन प्रबन्ध इसलिए भी ढीला होता है कि सरकार की नीति ही ढीली होती है।

प्रबन्ध और शासन ढीला तथा नृतिपूर्ण होने का प्रभाव देश के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पड़ता है। राजनैतिक क्षेत्र में यह प्रभाव होता है कि राज्य-मत्ता जिन हाथों में होती है उनकी अपनी स्वतन्त्र और मजबूत नीति न होने से वे अपने राजनैतिक सिद्धान्त ठीक प्रकार से नहीं बना पाते जिससे राष्ट्र की अन्य राजनैतिक पार्टियाँ भी शक्तिशाली हो जाती हैं और वे आगे चल कर कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती हैं। इसको दूर करना केवल एक ही रूप में सम्भव है—राजनैतिक क्षेत्र में कड़े शासन प्रबन्ध का होना, ताकि उसमें किसी प्रकार का भेद भाव या अष्टाचार न हो सके। सामाजिक क्षेत्र में शासन प्रबन्ध का कुशल होना और भी अधिक आवश्यक है। शासन प्रबन्ध यदि सुदृढ़ नहीं होता तो समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ प्रवेश करती हैं जो धीरे-धीरे समाज को खोखला बना देती हैं। राष्ट्र का विकास समाज के विकास पर निर्भर होता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि समाज को नीचे गिरने से रोका जाय और इस बात का भरसक प्रयास नागरिकों, समाज सुधारकों और सरकार द्वारा होना चाहिए जिससे सामाजिक उन्नति बराबर होती रहे। राजनैतिक और सामाजिक उन्नति पर काफी हद तक राष्ट्र की आर्थिक उन्नति निर्भर करती है। क्योंकि राष्ट्रों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास होता है (और विशेषतः पर अविकसित देशों का) इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस बात का पूर्ण प्रयास होना चाहिए कि शासन प्रबन्ध अच्छे से अच्छा

हो। आर्थिक विकास के साधारण कार्य, नियोजन के कार्य, वस्तु और सेवाओं का नियन्त्रण, कीमतों का नियन्त्रण, उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय और वितरण कार्यों में समय-समय पर विभिन्न प्रकार की सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है जो उचित रूप से तभी सम्भव हो सकता है जबकि देश का शासन-प्रबन्ध कुशल हो। इसी प्रकार देश की वित्तीय-व्यवस्था, उद्योग, व्यवसाय, यातायात और सम्वादवाहन के साधन, कर नीति, राज्य उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में कुशल प्रबन्ध और सुदृढ शासन प्रबन्ध का होना बहुत आवश्यक है। राष्ट्र की आर्थिक उन्नति प्रत्यक्ष रूप से इसी पर निर्भर होती है। भारत का मन्दगति से आर्थिक विकास होने का एक कारण देश में कुशल शासन प्रबन्ध का अभाव है।

८—प्रजातन्त्रवाद से उत्पन्न कठिनाइयाँ (Problems of Democracy)—कभी-कभी यह देखा जाता है कि अविक्वित देशों का शासन-प्रबन्ध प्रजातन्त्रवाद के आधार पर होता है। प्रजातन्त्रवाद प्रायः तभी सफल होता है जबकि देश के प्रायः सभी नागरिक शिक्षित हो किन्तु यदि उन क्षेत्रों में प्रजातन्त्रवाद की स्थापना हो—जहाँ शिक्षा का अभाव है तो प्रायः वहाँ प्रजातन्त्रवाद की सफलता कठिन हो जाती है। प्रजातन्त्रवाद के अन्तर्गत आर्थिक विकास के उद्देश्य से जो प्रयोग (Experimentation) किये जाते हैं उनसे बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिससे आर्थिक विकास का कार्य और कठिन हो जाता है। भारतवर्ष में भी प्रजातन्त्रवाद का अस्तित्व है और क्योंकि यहाँ के अधिकतर मनुष्य अशिक्षित हैं इसलिए बहुत से आर्थिक प्रयास बेकार हो जाते हैं। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के लक्ष्य से जो प्रयोग देश में किये गये हैं उनमें से बहुत से (बहुत रुपया खर्च होने के बावजूद भी) असफल रहे हैं। अविक्वित देशों में आर्थिक विकास एक ऐसे ढंग से होना चाहिए जिसमें प्रायः सरकार का हाथ शतप्रतिशत हो।

९—नियोजन के तरीकों में भिन्नता से उत्पन्न कठिनाइयाँ (Problems due to diversities of Planning Techniques)—जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं नियोजन के बहुत से तरीके और प्रणालियाँ हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न प्रकार के नियोजन के उद्देश्य से अपनाये जाते हैं। यद्यपि इन तरीकों और प्रणालियों में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख होता है कि उनकी विशेषतायें कौन सी हैं या उनका व्यवहार किस रूप में और किस क्षेत्र में होना चाहिये, फिर भी प्रजातन्त्रात्मक देशों में जब नियोजन के विषय में विभिन्न प्रयोग होते हैं तो कभी-कभी नियोजन सम्बन्धी वे तरीके और प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं जो एक दूसरे के प्रतिबल होती हैं। इससे राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है और आर्थिक उन्नति के स्थान पर—काफी रुपया खर्च होने पर भी—आर्थिक अवनति हो दिखाई पड़ती है। इस विषय में इस बात का उल्लेख भी निराधार न होगा कि कभी-कभी एक ही राष्ट्र में एक ही सरकार द्वारा विभिन्न समय पर नियोजन के

विरोधी तरीकों और प्रणालियों को भी अपनाया जाता है जिससे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता। वास्तव में तरीका यह होना चाहिए कि नियोजन के तरीके और प्रणाली के विषय में पहले सोच विचार कर लिया जाय और उसके बाद जब किसी एक तरीके या प्रणाली को अपनाया जाय तो उसमें आगे चल कर फिर कोई परिवर्तन न किया जाय।

१०—प्रारम्भिक सुविधाओं का अभाव (Absence of basic facilities)—अविकसित देशों का आर्थिक विकास का एक मात्र उपाय आर्थिक नियोजन का अपनाया होना है। आर्थिक नियोजनों के निर्माण के लिए कुछ प्रारम्भिक सहूलियत आवश्यक होती है। जैसे, देश की जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त होना, प्राकृतिक साधनों की जानकारी, देश की आर्थिक स्थिति के विषय में आँकड़े प्राप्त होना आदि। अर्थात्, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय आँकड़े, प्रशिक्षित कर्मचारी, उत्पत्ति के विभिन्न साधन, विनिर्भय और वितरण की सहूलियतें और नियोजन की पक्षपाती सरकार की आवश्यकता होती है। इन सबके ऊपर राष्ट्र के निवासियों का नियोजन द्वारा आर्थिक विकास प्राप्त करने का प्रबल उत्साह होना चाहिए। यह सब सुविधाएँ नियोजन कार्य के लिए प्रारम्भिक आवश्यकताएँ समझी जा सकती हैं। जिन अविकसित देशों में इन तथ्यों की बहुलता है वहाँ पर नियोजन द्वारा आर्थिक विकास सरलता से सम्भव होता है। लेकिन यदि किसी देश में इन तथ्यों का अभाव हो तो उस राष्ट्र के लिए आर्थिक उन्नति प्राप्त करना कठिन हो जायेगा।

५—पूँजी-निर्माण की कठिनाइयाँ (Problems of Capital formation)¹

अविकसित देशों के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा पूँजी-निर्माण के सम्बन्ध में होती है। पूँजी का निर्माण जब तक किसी देश में नहीं हो पाता है तब तक राष्ट्र का आर्थिक विकास प्रायः सम्भव नहीं होता, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए नये-नये उद्योगों की स्थापना, देश स्थित प्राकृतिक सम्पत्तियों का सन्तुलित शोषण और व्यापार में वृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के विनिर्धनों की आवश्यकता होती है। यह सभी कार्य ऐसे हैं जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है। पूँजी के अभाव में इच्छा और अन्य साधनों के मौजूद होने पर भी आर्थिक विकास कठिन हो जाता है।

कुछ विद्वानों का कहना है कि यदि राष्ट्र में पूँजी की कमी हो तो विदेशों से पूँजी मँगाकर देश के उद्योगों का विस्तार सरलता से किया जा सकता है। यह एक

1. For mathematical implications, please also refer to chapter 15 (Theory of Growth)

ऐसा मत है जिस पर कोई राय देने से पहले अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पक्षों का अध्ययन स्पष्ट रूप से कर लेना चाहिए। इसके पक्ष में यह कहा जाता है कि आर्थिक विकास के प्रारम्भिक काल में विदेशी पूँजी की सहायता लेने से उद्देश्य की प्राप्ति सरलता से और शीघ्रता से सम्भव हो जाती है। पूँजी का कुछ काल तक विदेशों से अपने देश में विनियोग हो सकता है। कुछ सुविधाय प्रदान करके अविकसित देश विदेशी साहसियों को अपने देश में उद्योग धन्धों की स्थापना के लिए आमन्त्रित कर सकते हैं, इससे अविकसित देशों में वह उद्योग भी सरलता से स्थापित किये जा सकते हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है और जो इन अविकसित देशों के पास नहीं होती। इस प्रकार देश में नये उद्योग धन्धों की स्थापना से देश की कच्ची सामग्री का सरलता से और सुव्यवस्थित रूप से व्यवहार सम्भव हो जाता है, देश में रोजगार की स्थिति में सुधार हो जाता है, श्रमिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं। इन उद्योग धन्धों की स्थापना से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति बड़ी मात्रा में होने लगती है, जिससे उनके दामों में ह्रास होता है और उसका उपभोग तथा व्यवहार साधारण जनता के लिए भी सम्भव हो जाता है जिससे मनुष्यों का जीवन-स्तर ऊँचा हो जाता है। इस प्रकार व्यस्तित्व रूप से घामदनी में वृद्धि होने से और जीवन-स्तर के उन्नत हो जाने से मनुष्यों को अधिक मात्रा में वचन करने की सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं, जिसमें आगे चलकर देश में अधिक पूँजी का निर्माण सम्भव हो जाता है। जब देश में पूँजी का निर्माण इतना होने लगे कि देश की विदेशी पूँजी की आवश्यकता न रहे और वह उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाये, तो सरकार धीरे-धीरे विदेशी साहसियों का बहिष्कार कर सकती है या विदेशी सस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। इस प्रकार अविकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के प्रथम पहलू में विदेशी पूँजी और साहसी बहुत योग दे सकते हैं।

इसके विपक्ष में यह कहा जाता है कि 'विदेशी व्यापार के साथ विदेशी झूठा भी आता है।' अर्थात् विदेशी साहसियों को यदि राष्ट्र के उद्योग धन्धों की सत्ता सौंप दी जाय तो इस बात का हमेशा डर बना रहता है कि विदेशी निजी लाभ के उद्देश्य से और अपनी स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से क्रमशः सरकार के प्रवन्ध और शासन क्षेत्र में भी प्रभाव डालने लगते हैं और यदि राष्ट्रीय सरकार कमजोर हो तो उस राष्ट्र की भी प्रशंसा कर सकते हैं कि समस्त राष्ट्र को ही हडप ले—जैसा भारत में ब्रिटिश शासन काल के स्थायित्व काल में हुआ था।

इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि जब विदेशी साहसी अपनी पूँजी लगाकर अविकसित राष्ट्रों में उद्योग धन्धों की स्थापना करते हैं तो सदा इस बात की चेष्टा करते हैं कि उनका निजी लाभ अधिकतम मात्रा में हो इस कार्य में यदि उस राष्ट्र को हानि भी होती हो तो भी विदेशी साहसी अपने उद्देश्य की पूर्ति से निरस्त नहीं होते। इनके द्वारा इन अविकसित राष्ट्रों को प्राकृतिक सम्पत्तियों का

शोषण अत्यन्त असंतुलित और घृणित रूप से होता है। इसी प्रकार, श्रमिकों, राष्ट्रीय उद्योगपतियों और साधारण जनता का शोषण भी इन विदेशी साहसियों द्वारा होता है। यह विदेशी साहसी इस ओर भी सचेष्ट रहते हैं कि उनके कारखानों में कोई भी 'देशी श्रमिक' किसी प्रकार की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त न कर सके और जब कभी भी किसी देशी उद्योगपति द्वारा उस वस्तु के निर्माण की चेष्टा होती है (जिसकी उत्पत्ति विदेशी साहसी कर रहे हैं) तो उस चेष्टा को यह किशोरावस्था में ही कुचल देते हैं, जिससे उस राष्ट्र में देशी साहसियों द्वारा आर्थिक विकास के प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं और राष्ट्र के आर्थिक विकास की सम्भावना सदा के लिए लुप्त हो जाती है। विदेशी साहसी एकाधिकार की स्थापना करके बाजार का सम्पूर्ण नियन्त्रण अपने हाथ में ले लेते हैं और वस्तुओं तथा सेवाओं की मनमानी दर निश्चित करके उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। इन सब बातों के अतिरिक्त विदेशी साहसी प्रायः इस ओर भी प्रयत्नशील होते हैं कि वे जो कुछ भी आमदनी करें उसे अपने देश में भेज दें। इससे इन अविकसित राष्ट्रों के मूल्य पर इन साहसियों के देशों का आर्थिक विकास होना है।

अविकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण की जो बहुत सी कठिनाइयाँ हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई यह है कि राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आमदनी बहुत कम होती है। आमदनी कम होने का परिणाम यह होता है कि मनुष्यों के लिए जीवन-निर्वाह करना ही कठिन हो जाता है। वे इच्छा होते हुए भी किसी भी प्रकार से बचत नहीं कर पाते हैं। जब बचत की सम्भावना ही नहीं होती तो यह आशा करना कि उस राष्ट्र में पूँजी का निर्माण सरलता से और अधिक मात्रा में हो मज्जा कल्पना मान है। भारतवर्ष और दक्षिण पूर्व एशिया के अविकसित राष्ट्रों में जो पूँजी निर्माण नहीं हो पाता है, उसका खास कारण यही है कि इन राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आमदनी बहुत कम है, जिससे इच्छा रहने पर भी पूँजी-निर्माण सम्भव नहीं हो पाता है।

पूँजी-निर्माण के मार्ग में अति-जनसंख्या और जनसंख्या का अधिक घनत्व भी एक प्रमुख बाधा होती है। जनसंख्या आधिक्य होने से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा और कार्यक्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है। देश में बेरोजगारी फैली होती है और रोजगार प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रतिस्पर्धा और मरीबी के कारण साधारण जनता को कम उम्र से ही किसी न किसी प्रयास में जुट जाना पड़ता है, जिससे व्यक्तिगत आमदनी कम हो जाती है। श्रमिकों की पूर्ति मार्ग के मुकाबले में बहुत अधिक होती है जिससे मजदूरी की दर कम हो जाती है, इस प्रकार विभिन्न राष्ट्रों में जनसंख्या आधिक्य होने से प्रायः व्यक्तिगत आमदनी बहुत कम हो जाती है, जिससे बचत और पूँजी-निर्माण प्रायः संभव नहीं हो पाता।

प्रयासों में असन्तुलन भी पूँजी-निर्माण को हतोत्साहित करता है। इसके अनुसार किसी एक विशेष प्रयास पर अत्यधिक बल प्रदान किया जाता है जबकि

दूसरे प्रयास उपेक्षित रह जाते हैं। इससे भी राष्ट्रीय आय में कमी हो जाती है। उदाहरणार्थ, भारत का दृष्टान्त दिया जा सकता है जहाँ कृषि पर आवश्यकता से अधिक बल प्रदान किया जाता है जिससे कृषि प्रयास में बहुत से व्यक्ति 'अतिरेक' के रूप में होते हैं और बाकी लोगों को भी कृषि क्षेत्र में साल भर काम नहीं रहता है। इसके विपरीत, गृह-उद्योग और उद्योग-धन्यो—जहाँ और अधिक मनुष्य प्रयुक्त होने चाहिए—उनकी कमी है। इसका भी प्रभाव यह होता है कि प्रति व्यक्ति आम-दनी कम हो जाती है और सचय तथा पूँजी-निर्माण सम्भव नहीं हो पाता।

राष्ट्रप्रति और विभिन्न सकटों को दूर करने के उद्देश्य से जब अविकसित देशों में घाटे की खजट-नीति को अपनाया जाता है और देश में मुद्रा प्रसार हो जाता है तो प्रायः यह देखा जाता है कि देश की साधारण जनता को अपनी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है किन्तु इस काल में उनकी आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में मुद्रा-प्रसार के फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है। इसका भी परिणाम यह होता है कि बचत नहीं हो पाती और बचत के अभाव से पूँजी निर्माण भी नहीं हो पाता।

नियोजन काल में प्रायः करो में वृद्धि की जाती है। यह कर केवल उत्पत्ति तक ही सीमित नहीं होते बल्कि उपभोग की सभी वस्तुओं पर विक्री कर और आय कर के रूप में होते हैं। इस प्रकार जनता से विभिन्न प्रकार के भारी कर वसूल करने का परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपनी आमदनी में से एक बड़े भाग को बचत के रूप में नहीं रख पाता है, जो प्रायः चल कर पूँजी का रूप ग्रहण कर सके।

अविकसित राष्ट्रों में बैंक और साख सम्बन्धी सुविधाओं की कमी होने के कारण साधारण जनता की छोटी छोटी बचतें एकत्रित नहीं हो पाती ताकि बैंक द्वारा इन छोटी-छोटी बचतों को एकत्रित करके विशाल पूँजी का रूप प्रदान किया जा सके। प्राथमिक अर्थव्यवस्था में उद्योग और व्यवसाय का विकास मुख्य रूप से साख की सुविधाओं पर निर्भर करता है और जो राष्ट्र इन सुविधाओं को प्रदान करने में असमर्थ होता है वहाँ पूँजी का निर्माण या उद्योग धन्यो तथा व्यवसाय का विकास प्रायः सम्भव नहीं हो पाता।

अविकसित राष्ट्रों में 'पूँजी की कमी' भी पूँजी के निर्माण में एक विशेष बाधा उत्पन्न करती है। 'पूँजी' के अभाव से देश की प्राकृतिक सम्पत्तियों का शोषण उद्योग धन्यो की स्थापना, व्यावसायिक उन्नति और आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो पाता है। और जब तक इन क्षेत्रों में विकास सम्भव नहीं हो पाता तब तक राष्ट्रीय आय में विशेष उन्नति होना सम्भव नहीं होता जिसके फलस्वरूप बचत करना और पूँजी का निर्माण कठिन हो जाता है।

अविकसित राष्ट्रों को परिवर्तनशील, अस्थायी और अशक्त व्यावसायिक, उद्योग सम्बन्धी और वित्तीय नीति भी पूँजी-निर्माण के पथ पर विघ्न उत्पन्न करती है। इन श्रुतिपूर्ण नीतियों का अस्तित्व अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक उन्नति प्राप्त करने से दूर रखते हैं। इन नीतियों का स्पष्ट और शक्तिशाली न होने के कारण साहसी, उद्योगपति, विनियोगी और व्यवसायी नये-नये प्रयासों को अपनाने से डरते हैं जिससे राष्ट्रीय विकास और पूँजी का निर्माण सम्भव नहीं हो पाता।

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि भारतवर्ष और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य अविकसित राष्ट्रों में पूँजी का निर्माण बहुत-सी प्राकृतिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक कठिनाइयों के कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है यद्यपि सभी सरकारें इस ओर सक्रिय रूप से सचेष्ट हैं और यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में यह बाधाएँ दूर हो जावेंगी और आवश्यकतानुसार पूँजी का निर्माण इन राष्ट्रों में सम्भव हो सकेगा।

अविकसित देशों में नियोजन-प्रणाली

(Planning Techniques for Under-developed Countries)

१—अविकसित देशों में नियोजन-महत्व

(Importance of Planning in Under developed Countries)

अविकसित देशों में प्रायः यह देखा जाता है कि उनके साधनों का शोषण पूर्ण एवं सन्तुलित रूप से नहीं हो पाता। इसका परिणाम प्रायः यह होता है कि विदेश में आर्थिक उन्नति के पर्याप्त साधन विद्यमान होने पर भी देश का आर्थिक उत्थान नहीं हो पाता। आधुनिक काल में प्रत्येक सरकार इस ओर सचेष्ट रहती है कि जहाँ तक हो सके राष्ट्र के समस्त सम्पत्ति और साधनों का व्यवहार राष्ट्र के अधिकतम कल्याण के उद्देश्य से हो सके। यही कारण है कि पिछड़े हुये, अर्द्ध विकसित और अविकसित देशों में भी अब आर्थिक विकास पर बल दिया जा रहा है ताकि देश का आर्थिक उत्थान द्रुतगति से सम्भव हो सके, और यह राष्ट्र कुछ काल में ही आर्थिक रूप में उन्नत राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्द्धा में अवतीर्ण हो सके।

प्रायः सभी विकसित राष्ट्रों में विदेशी शासन या तो अभी तक बना हुआ है या कुछ काल पहिले तक बना हुआ था। यह भी एक मुख्य कारण है जिसके फलस्वरूप इन राष्ट्रों का आर्थिक विकास व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाया है। विदेशी शासकों का यह आदर्श और उद्देश्य रहा है कि वह शामिल देश को शोषण करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि इन अविकसित देशों में आर्थिक उन्नति न हो पाये। भारतवर्ष में अंग्रेजों ने सदा इस बात की चेष्टा की कि भारत के खनिज पदार्थ और कच्ची सामग्री अधिकतम मात्रा में ब्रिटेन भेजी जाय और वहाँ से निर्मित वस्तुएँ भारत में मगाई जायें। इसका परिणाम यह होता था कि भारत को हानि होती थी और साथ ही साथ उसके उन्नति करने के मार्ग में सदा के लिये कठिनाई उत्पन्न होती थी। देश की कच्ची सामग्री निर्यात के रूप में बाहर चली जाती थी और निर्मित वस्तु के रूप में आयात होती थी इससे राष्ट्र का आर्थिक ढाँचा कमजोर होता चला गया।

अविकसित देशों में पूँजी का सदा अभाव रहता है। उसका कारण यह है कि नागरिकों की आमदनी कम रहने की वजह से वे बचत नहीं कर पाते और जब तक बचत नहीं हो पाती है तो विनियोग कार्य के लिये पूँजी का निर्माण भी नहीं हो पाता। यह भी एक कारण है जिसके लिये इन अविकसित देशों में नियोजन का अत्यन्त महत्त्व है। इन देशों में नियोजन का कार्य प्रायः सरकार द्वारा होता है एवं विनियोग के लिये पूँजी की व्यवस्था भी प्रायः सरकार और साहसी दोनों के सहयोग से होती है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन पद्धति के अपनाने पर ही इन राष्ट्रों का आर्थिक उत्थान सम्भव हो पाता है।

अविकसित देशों में शिक्षित और प्रशिक्षित (Technical) श्रमिकों की कमी रहती है। नियोजन के अभाव में इन देशों में न तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था ही उगपूरण रीति से हो सकती है और न उद्योग, कृषि, व्यवस्था एवं अन्य क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार योग्य व्यक्ति ही प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार यदि इन देशों में नियोजन पद्धति न अपनाई जावे तो उत्पत्ति-व्यवस्था एवं वितरण व्यवस्था में कमी भी परिवर्तन या सुधार सम्भव नहीं हो सकेगा। इससे भी देश का आर्थिक विकास सदा के लिये रुक जावेगा।

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि अविकसित राष्ट्रों के लिये आर्थिक उत्थान एवं राष्ट्र का पुनः संगठन (आर्थिक रूप से) नियोजन द्वारा ही सम्भव हो सकता है। नियोजन का स्वरूप अलग अलग प्रकार का हो सकता है, किन्तु नियोजन-पद्धति का अपनाया जाना आवश्यक है।

२—उद्योग-प्रमुख नियोजन या कृषि-प्रमुख ?

(More Industry or Agriculture ?)

अविकसित राष्ट्रों के नियोजकों के सामने सदा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे राष्ट्र के आर्थिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उद्योग पर अधिक बल दें या कृषि पर ? साधारण रूप से कुछ यह प्रश्न कर सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र पर अधिक बल देने की क्या आवश्यकता है। कृषि और उद्योग दोनों पर समान बल दिया जा सकता है और दोनों में एक ही साथ उन्नति प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में, यह चारखा गलत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अविकसित राष्ट्रों के पास साधन और पूँजी की अत्यन्त कमी रहती है। उस सीमित साधन और पूँजी के अपनाने से, विशेष रूप से एक ही क्षेत्र पर अधिक बल प्रदान किया जा सकता है, समस्त क्षेत्रों पर नहीं। अविकसित देश अधिकतर कृषि-प्रधान हैं। यही कारण है कि इन देशों में जब नियोजन का कार्य शुरू किया जाता है तो प्रायः कृषि की उन्नति एवं पुनर्संगठन पर अधिक बल प्रदान किया जाता है। इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं :-

(१) कृषि प्रधान देशों में अधिक सख्यक जनता का भाग्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर होता है। इसीलिये उनके भाग्य को समालने की पहिले चेष्टा की जाती है। देश की अधिक सख्या जनसख्या यदि खुशहाल हो जावे तो बाकी भाग भी धीरे-धीरे खुशहाल हो जावेगा।

(२) उद्योग के मुकाबले में कृषि के पुनरुत्थान में कम पूँजी की आवश्यकता होती है। अविकसित देशों में पूँजी की हमेशा कमी बनी रहती है इसलिये इस बात की चेष्टा की जाती है कि पहिले उन क्षेत्रों को उन्नत बनाने का प्रयास किया जावे जो कम पूँजी द्वारा सम्पन्न हो सके।

सोवियत संघ, चीन, आदि देशों में जब प्रारम्भिक रूप से योजना का कार्य शुरू किया गया तो वहाँ पर भी पहिले कृषि को उन्नत बनाने की ही चेष्टा की गई थी। भारतीय प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि “भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिये कृषि उन्नति पर सबसे अधिक महत्व और प्राथमिकता प्रदान की गई है।”

नियोजन के प्रारम्भिक काल में कृषि को उन्नत बनाने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि खाद्य पदार्थ एवं कुछ कच्ची सामग्रियों के विषय में देश आत्मनिर्भर हो जाता है। इसके प्रतिरिक्त क्योंकि अधिक सख्यक जनसख्या कृषि पर आधारित होती है इसलिये उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने से देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है एवं अन्य क्षेत्रों में उन्नति करने के लिये राष्ट्र को सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं। किन्तु इसमें दोष भी है। कृषि प्रायः असंगठित रहती है एवं कृषक वर्ग सुधारों को मानने से प्रायः इन्कार करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि नियोजन-काल ही में द्रुत आर्थिक विकास की उपलब्धि अत्यन्त कठिन हो जाती है। एक और कठिनाई यह है कि राष्ट्र की व्यक्तिगत आमदनी तीव्रगति से तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि देश में उद्योग और व्यवसायों का विकास सन्तुलित एवं द्रुतगति से न हो।

प्रायः सभी देशों में, जहाँ नियोजन-पद्धति अपनाई जाती है, इस बात की चेष्टा की जाती है कि नियोजन की प्रारम्भिक स्थिति में कृषि में आवश्यकीय सुधार किया जावे तथा कृषि क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जाय। इससे भविष्य में किये जाने वाले अन्य नियोजनों के लिये सुदृढ आधार तैयार हो सके। इसके पश्चात् अन्य योजनाओं में प्रायः उद्योगों के विकास पर प्राथमिकता प्रदान की जाती है—साथ ही साथ इस बात की भी चेष्टा होती है कि देश किसी भी उन्नति को और अग्रसर हो सके। भारतवर्ष में प्रथम योजना में कृषि आदि के विकास पर अत्यधिक बल प्रदान किया गया था, किन्तु द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग एवं व्यवसायों की उन्नति पर अधिक बल प्रदान किया गया है।

३—पूँजी-प्रमुख या श्रम-प्रमुख उत्पादन ?

(Capital Intensive or Labour Intensive Production ?)

अविकसित देशों में नियोजन पद्धति के निर्णय करते समय नियोजकों के सामने एक प्रश्न यह आता है कि नियोजन के अन्तर्गत वस्तु और सेवाओं की उत्पत्ति का स्वरूप क्या हो ? अर्थात् श्रम-प्रमुख प्रणाली द्वारा उत्पादन का कार्य करना चाहिये या पूँजी-प्रमुख प्रणाली द्वारा । श्रम-प्रमुख उत्पत्ति में सबसे बड़ा गुण यह होता है कि अधिकतम मात्रा में नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सकता है । यही कारण है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों में, और विशेष तौर से उन देशों में, जहाँ रोजगार की कमी है श्रम-प्रमुख उत्पत्ति प्रणाली अपनाई जाती है ताकि देश में जो बेरोजगारी या अर्द्धबेरोजगारी विद्यमान है वह समाप्त हो जाय या उसकी मात्रा कम से कम रह जाय । भारतवर्ष भी एक ऐसा ही देश है जहाँ जनसंख्या अधिक है एवं पर्याप्त मात्रा में बेरोजगारी है । यही कारण है कि भारतीय नियोजन में इस बात की चेष्टा की गई है कि जहाँ तक हो सके श्रम-प्रमुख उत्पत्ति प्रणाली को ही अपनाया जाय । इस प्रणाली में सबसे बड़ा दोष यह है कि इस प्रणाली के अपनाये जाने पर आर्थिक विकास का कार्य मन्द गति प्राप्त करता है । इस प्रकार योजना काल में व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में विशेष वृद्धि नहीं हो पाती । साथ ही साथ योजना काल में जनसंख्या में क्रमागत वृद्धि होने से देश का आर्थिक विकास प्रायः स्थिर हो जाता है ।

पूँजी प्रमुख उत्पत्ति के माधनों में सबसे अधिक प्रमुखता पूँजी को प्राप्त होती है । अधिक पूँजी के विनियोग में, बड़ी मात्रा में शक्ति और मशीनों के प्रयोग से, अभिनवीकरण (Rationalisation) की पद्धति को अपनाकर उत्पत्ति प्रणाली में परिवर्तन करके एवं अधिकतम साधनों का प्रयोग करके उत्पत्ति का कार्य किया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति अधिकतम मात्रा में एवं कम से कम उत्पत्ति व्यय पर उत्पन्न हो जाता है एवं देश में आर्थिक प्रगति द्रुतगति से सम्भव हो जाती है । इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि अत्यधिक पूँजी के विनियोग से एवं मशीनों के प्रयोग के कारण श्रमिकों को काम मिलना कठिन हो जाता है तथा देश में बेरोजगारी फैल जाती है । अर्द्धविकसित या अविकसित देशों के लिए इससे लाभ के स्थान पर और कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं । इन देशों में इस प्रणाली को नियोजन के अन्तर्गत सम्मिलित न करने का एक और कारण यह है कि इन देशों में पूँजी की कमी बनी रहती है जिससे विशाल मात्रा में पूँजी का विनियोग सम्भव नहीं हो पाता है । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अविकसित देशों में बड़ी मात्रा की उत्पत्ति या पूँजी-प्रमुख उत्पत्ति प्रणाली अपनाई ही नहीं जाती । वास्तव में अविकसित राष्ट्रीयों के नियोजक इस ओर सदा सचेष्ट रहते हैं कि नियोजन में श्रम-प्रमुख और पूँजी

प्रमुख दोनों ही प्रकार की उत्पत्ति प्रणाली को अलग-अलग क्षेत्रों में अपनायें। भारतवर्ष में भी नियोजकों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में इस और स्पष्ट संकेत किया है कि कृषि, छोटे उद्योग एवं गृह उद्योगों के क्षेत्र में धर्म प्रमुख उत्पत्ति प्रणाली अपनाई जायगी जबकि बड़ी मात्रा की उत्पत्ति और व्यवसायों में पूँजी-प्रमुख प्रणाली। इस प्रकार हम इस निष्पत्ति पर पहुँचते हैं कि अविक्सित राष्ट्रों के लिए केवल मात्र पूँजी-प्रमुख प्रणाली का अपनाता घातक सिद्ध होगा।

४—घाटे के बजट द्वारा नियोजन

(Planning Through Deficit Financing)

अविक्सित राष्ट्रों में पूँजी की हमेशा कमी रहती है। यही कारण है कि नियोजकों को योजना बनाते समय इस बात का पता पूरी तरह से लगाना पड़ता है कि नियोजन कार्य के लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था किस प्रकार होगी। अर्थात् कितना रुपया, नियोजन काल में, कबो द्वारा, रैबैन्कू से, उधार माँग कर (देश या विदेश से) सहायता प्राप्त कर आदि इकट्ठा हो सकेगा। इसी के आधार पर उन्हें नियोजन के उद्देश्य, आधार, एवं आकार का निर्धारण करना पड़ता है। व्यावहारिक रूप से यह देखा जाता है कि अविक्सित देशों में नियोजन कार्य को सफल और प्रगतिशील बनाने के लिए जितने वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है उतना साधन इन सरकारों के पास प्रायः नहीं होता। इस कमी को दूर करने के लिए करों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, विदेशों से सहायता और ऋण प्राप्त किये जाते हैं। देश की जनता से भी रुपया माँगा जाता है। इन सब पद्धतियों को अपनाने के पश्चात् भी जो कमी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए घाट की बजट योजना को अपनाना आवश्यक हो जाता है। नियोजन के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रति वर्ष घाट का बजट बनाया जाता है। किन्तु इस प्रणाली में एक बहुत बड़ा दोष होता है। वह यह कि इस प्रणाली से देश में अत्यधिक मात्रा में मुद्रा प्रसार हो जाता है। मुद्रा प्रसार के साथ ही साथ इसकी समस्त कठिनाइयाँ, जिसमें कीमतों का अत्यधिक बढ़ना सबसे अधिक प्रमुख है, देश में उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार अधिक समय तक और अधिक मात्रा में घाटे की बजट पद्धति के अपनाये जाने पर लाभ के स्थान पर हानि ही होती है।

अविक्सित देशों के लिए क्योंकि घाटे की बजट योजना प्रायः अपरिहार्य होती है इसलिए इन सरकारों द्वारा इस बात की भी चेष्टा साथ ही साथ करनी चाहिये कि देश में अत्यधिक मुद्रा प्रसार न हो सके। अत्यधिक मुद्रा प्रसार होने से योजना के समस्त लाभ समाप्त हो जाते हैं और जनता के लिए वही कठिनाइयाँ बनी रह जाती हैं जिनको कि दूर करने के लिए नियोजन पद्धति अपनाई जाती है।

अत्यधिक मुद्रा प्रसार को दूर करने के कई उपाय होते हैं—जैसे, कीमत पर नियन्त्रण, राशनिंग प्रणाली को अपनाना, साख नियन्त्रण, मुद्रा प्रचलन पर नियन्त्रण आदि। प्रायः सभी अविकसित देशों में योजनाधिकारी घाटे की बजट योजना को अपनाते हैं और उसमें उत्पन्न मुद्रा प्रसार की समस्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपरोक्त उपाय अपनाते हैं। इस प्रकार देश की पूँजी की कमी की कठिनाई भी दूर हो जाती है और जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ता है। एक बात उस विषय में ध्यान रखने योग्य है—वह यह कि अविकसित देशों में प्रारम्भिक नियोजन काल में आवश्यक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है जिसमें जनता को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है—यह स्थिति अवाञ्छनीय होते हुए भी अवश्यभावी होती है। नियोजन अधिकारी को इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करना चाहिये, किन्तु इस कठिनाई से भयभीत होकर नियोजन के कार्य में ढीस प्रदान नहीं करनी चाहिये या नियोजन के कार्य को स्थगित नहीं कर देना चाहिये। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अविकसित देशों में घाटे की बजट योजना—कुछ कठिनाइयाँ होते हुए भी—परम आवश्यक है।

५—केन्द्रीय नियोजन या मिश्रित अर्थ-व्यवस्था ? (Centralised Planning or Mixed Economy ?)

अर्द्धविकसित या अविकसित राष्ट्रों के सामने साधन और पूँजी की कमी बनी रहती है इसीलिये उसके सामने यह प्रश्न भी सदा बना रहता है कि नियोजन का स्वरूप पूर्णरूपेण केन्द्रीय हो या सार्वजनिक प्रयास के साथ-साथ निजी प्रयास का भी सह-अस्तित्व हो ? केन्द्रीय नियोजन यदि पूर्णरूप से हो—तो उसका अर्थ यह होगा कि नियोजन का कार्य, उसका प्रबन्ध, प्राथमिकता एवं उद्देश्य का निर्णय तथा पूँजी की व्यवस्था केन्द्रीय 'सरकार' द्वारा ही होगी। अविकसित राष्ट्रों की सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में साधन और पूँजी नहीं होती इसलिये यह सरकार नियोजन की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले पाती। यदि यह सरकार यह चाह कि नियोजन का शतप्रतिशत कार्य अपने ही हाथ में ले तो आवश्यक रूप से नियोजन कार्य में कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी और उद्देश्य की पूर्ति में भी बाधाएँ आवेंगी। यही कारण है कि अविकसित राष्ट्र नियोजन के प्रारम्भिक काल में समस्त दायित्व अपने ही ऊपर नहीं लेते और नियोजन के कार्य में केन्द्रीय सरकार के प्रयासों के साथ-साथ व्यक्तिगत प्रयास का भी सह-अस्तित्व होती है।

भारतवर्ष की प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं का यदि विश्लेषण किया जाय तो भी यह पाया जायगा कि ये योजनाएँ मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ही आधारित हैं। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि न तो सरकार के पास इतनी विशाल पूँजी है कि वे नियोजन के समस्त खर्चों को उठा सकें, न साहसियों के पास

ही इतना घन है कि वे सरकार की सहायता के बिना ही देश में औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास सम्बन्धी समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस प्रकार यदि मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रणाली न अपनाई जाती तो नियोजन का कार्य सफलतापूर्वक अप्रसर नहीं हो पाता।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अविकसित देशों के नियोजनाधिकारियों को नियोजन बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्र की द्रुत आर्थिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पूँजी की कठिनाई को मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपना कर दूर कर दें। भारतवर्ष में यही प्रणाली अपनाई जा रही है, अब चीन व रूस में प्रारम्भिक नियोजन काल में इसी पद्धति को अपनाया गया था। अविकसित राष्ट्रों के लिये नियोजन द्वारा आर्थिक विकास प्राप्त करने का यही सही रास्ता है।

६—व्यक्तिगत आमदनी में वृद्धि या राष्ट्रीय आय में वृद्धि ?

(Increase in par-capita Income or in National Income ?)

साधारण रूप से तो यही कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आमदनी में भी वृद्धि हो जाती है—और यह सही भी है। किन्तु, यदि आय के स्तर में अत्यन्त विज्ञान अन्तर हो या वितरण की पद्धति त्रुटिपूर्ण हो तो यह भी हो सकता है कि राष्ट्रीय आय में द्रुतगति से वृद्धि होने पर भी साधारण जनता की प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आमदनी में विशेष उन्नति न हो। इसका कारण यह रह सकता है कि देश के कुछ ही धनी व्यवसायी औद्योगिक-विकास द्वारा बहुत अधिक मात्रा में धन कमायें, और इस प्रकार राष्ट्र की सम्पत्ति केवल कुछ ही हाथों में एकत्रित हो जावे। ऐसी अवस्था में साधारण जनता की प्रतिवर्ष आमदनी में विशेष उन्नति नहीं होगी जबकि धनी वर्ग की आमदनी में अत्यधिक वृद्धि से राष्ट्रीय आय में वृद्धि सम्भव है।

अविकसित राष्ट्रों में साधारण जनता की आमदनी बहुत कम रहती है। इस आमदनी में वृद्धि करने के उद्देश्य से ही नियोजन का कार्य हाथ में लिया जाता है। नियोजन के पश्चात् भी यदि वितरण की त्रुटि की वजह से साधारण जनता की प्रति व्यक्ति आमदनी में विशेष अन्तर (उन्नति) न हो पाये तो इसका अर्थ यह होगा कि नियोजन का उद्देश्य असफल रहा। अधिकतर नियोजनाधिकारी इस बात की चेष्टा करते हैं कि नियोजन द्वारा साधारण जनता की प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आमदनी के स्तर को ऊँचा बनायें, और इस प्रकार प्रति व्यक्ति आमदनी एवं राष्ट्रीय आय दोनों में सन्तुलित रूप से वृद्धि होती है।

उपरोक्त विषय के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अविकसित राष्ट्रों के नियोजन भरसक इस बात का प्रयास करते हैं कि नियोजन काल में एवं नियोजन द्वारा राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की आमदनी में उन्नति प्राप्त हो। इससे

राष्ट्र के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक भी खुशहाल हो जाता है और उनका जीवन स्तर ऊँचा हो जाता है—जो नियोजन का उद्देश्य भी है। भारतीय योजनाओं के विस्तार करने पर भी हम इसी सत्य को पाते हैं।

७—अधिक उत्पत्ति या अधिक उपभोग ?

(More Production or More Consumption ?)

योजना के उद्देश्यों में अधिक उत्पत्ति और अधिक उपभोग दोनों होते हैं। परन्तु योजना के निर्माताओं को इस बात का फैसला करना पड़ता है कि उत्पत्ति और उपभोगों में से वह किस को अधिक प्राथमिकता प्रदान करें ? साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि उत्पत्ति और उपभोग आपस में प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं। एक में कमी आने से दूसरे में भी कमी आ जाती है और एक के बढ़ जाने से दूसरे में भी वृद्धि आ जाती है।

अविकसित राष्ट्रों के सामने उत्पत्ति और उपभोग दोनों की समस्याएँ होती हैं। आमदनी कम रहने की वजह से उपभोग का स्तर भी नीचा रहता है। इसी कारण वचन भी नहीं हो पाती और न पूँजी का निर्माण हो पाता है। पूँजी के अभाव में उत्पत्ति का कार्य भी अग्रसर नहीं हो पाता। नियोजनाधिकारी के सामने उपभोग के स्तर को ऊँचा करने तथा उद्योग धंधों के विकास का प्रश्न रहता है। नियोजन काल में प्रति व्यक्ति आमदनी में वृद्धि होती है जिससे साधारणतया मनुष्यों का जीवन स्तर कुछ ऊँचा होता है। इससे स्वतः ही उपभोग का स्तर थोड़ा ऊँचा हो जाता है। आमदनी में वृद्धि होने से सचय की मात्रा में भी वृद्धि होती है जिससे पूँजी का निर्माण सरल हो जाता है और उत्पत्ति पहिले से अधिक मात्रा में होने लगती है।

अविकसित राष्ट्रों के प्रारम्भिक नियोजन काल में उत्पत्ति पर अधिक वल दिया जाता है। ('उत्पत्ति' में सभी प्रकार और सभी स्तर की उत्पत्ति सम्मिलित रहती है।) उत्पत्ति कार्य में सरकार और साहसिक दोनों ही एक दूसरे से सहयोग करते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे राष्ट्र में औद्योगीकरण का उद्देश्य पूरा हो जाता है और वस्तुएँ सस्ती बनने के कारण और आमदनी की वृद्धि से उपभोग का स्तर भी ऊँचा हो जाता है।

इस विषय में दो बातें विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य हैं। प्रथम, उत्पत्ति के समस्त प्रयास केवल साहसिकों के हाथ में ही नहीं होने चाहिये, क्योंकि उस हालत में देश में धन का वितरण अग्रमान हो जायगा—जो नियोजन सिद्धान्त के विरुद्ध और अवांछनीय है। द्वितीय, इस अवस्था में इस बात का भी भय बना रहेगा कि साधारण मनुष्य की आमदनी स्तर की विशेष उन्नति में रुकावट न होने पावे। राष्ट्र की ओर से इस बात का पूरा प्रयास होना चाहिये कि नियोजन के लाभ समस्त जनता को प्राप्त हों—केवल धनी वर्ग को ही नहीं। भारतीय योजना

में समाजीकरण, केन्द्रीयकरण, कल्याणकारी राज्य की स्थापना और समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के प्रयास आदि उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सम्मिलित किये गये हैं।

इस प्रकार हमारा निष्कर्ष यह है कि अविकसित राष्ट्रों की योजनाओं में उत्पत्ति पर उपभोग के मुकाबले में अधिक प्राथमिकता प्रदान की जाती है। नियोजन द्वारा जब इन राष्ट्रों का आर्थिक विकास काफी ऊँचे स्तर पर पहुँच जाता है तो फिर इस बात का अधिक प्रयास किया जाता है कि उपभोग के स्तर में वृद्धि हो— यो तो उत्पत्ति और आमदनी बढ़ने से साधारण उपभोग के स्तर में उन्नति स्वतः ही हो जाती है।

८—अव्यवस्थित या अर्द्ध-व्यवस्थित क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की जावे ?

(Priority for Unorganised or Semi organised Sector ?)

अविकसित देशों के नियोजकों के सामने एक प्रश्न सदा यह बना रहता है कि नियोजन द्वारा वह किम क्षेत्र को पहले विकसित करने का प्रयास करें? क्षेत्रों को सामान्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—अव्यवस्थित एवं अर्द्ध-व्यवस्थित। अव्यवस्थित क्षेत्र के विकास पर सामान्यरूप से नियोजन में अधिनतम प्राथमिकता प्रदान किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब तक किसी देश के अव्यवस्थित क्षेत्र की उन्नति न हो, तब तक उस देश के लिये द्रुत आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त न हो सकेगा। इसके विपरीत, यदि नियोजक अर्द्ध-विकसित क्षेत्र को उन्नत बनाना चाहे तो उस कार्य में उसे विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि कम माधन के व्यय से एवं कम कठिनाई से ही अर्द्ध-विकसित क्षेत्र को व्यवस्थित किया जा सकता है।

अर्द्ध-व्यवस्थित क्षेत्रों को सन्तुलित रूप से व्यवस्थित करने में कम साधनों एवं प्रयासों की आवश्यकता होती है। अविकसित देशों के पास साधनों की सदा कमी बनी रहती है। इसी कारण इन देशों के नियोजक इस बात की चेष्टा करते हैं कि पहले अर्द्ध-व्यवस्थित क्षेत्रों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित बनाले। इस कार्य में उन्हें विशेष कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। जब तक यह क्षेत्र पूर्णरूप से व्यवस्थित हो पाते हैं तब तक अव्यवस्थित क्षेत्र उस पर्याय पर पहुँचते हैं जिसको कि हम अर्द्ध-व्यवस्थित क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार नियोजन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को उन्नत तथा व्यवस्थित करने का क्रम चलता रहता है।

भारतवर्ष में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ था तभी से इस बात की बराबर चेष्टा की जा रही है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों की उन्नति एक क्रम से हो। द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी इस बात का स्पष्ट

सकेत मिलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास का कार्यक्रम समानान्तर रूप से चले। फिर भी, इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में कुछ प्राथमिकता का प्रदान किया जाना आवश्यक होता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में कहा गया है, "तीसरी योजना के समान विद्यालय और विस्तृत योजना का विकास करते समय उसकी विभिन्न परियोजनाओं और व्ययों को ठीक ठीक सोपानों में बाँट लेना निहायत जरूरी है। इसके बिना यह सम्भव नहीं है कि योजना पर धुस्ती से अमल हो, पूँजी-विनियोग का हर वर्ष मिलते वाले स्वदेशी और विदेशी साधनों के साथ मेल बैठता रहे और इस बात का निश्चय हो कि योजना के हर सोपान में कुछ परियोजनाओं पर अमल हो रहा है और योजना निरन्तर आगे बढ़ रही है और फायदा पहुँचा रही है।" वास्तव में, योजना के प्रारम्भिक काल में अर्द्ध-व्यवस्थित क्षेत्र को पूर्ण व्यवस्थित बना देने के कार्य को अधिक प्राथमिकता की आवश्यकता होती है क्योंकि इस कार्य में कम साधनों की आवश्यकता होती है एवं समय की दृष्टि में भी यह कार्य शीघ्र सम्भव होता है।

६—योजना की रूपरेखा¹

(Plan-frame)

किसी योजना के पूँजी-विनियोग के रूप से पता चल सकता है कि योजना काल में उसकी प्राथमिकताएँ क्या रहनी चाहिए और उसके विभिन्न भागों में से किस पर कितना जोर दिया जायगा। इसके अतिरिक्त, इनका निश्चय, उस समय विद्यमान आर्थिक परिस्थिति और सम्भावित प्रवृत्तियों का विचार करके, देश की बुनियादी, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करके, और दीर्घकालीन लक्ष्यों को देख कर भी किया जाता है। इसलिये इनका निश्चय करते समय अनेक विचारों में समुलन रखने की होशियारी भी बरतनी पड़ती है।

विकास के नक्शे में स्वभावतः सबसे प्रथम स्थान कृषि का है। देश के अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देना और उद्योगों तथा निर्यात की आवश्यकताएँ पूरी कर देना इसलिये कृषि के उत्पादन को यथामुम्भव उच्चतम स्तर तक उठाना होगा, ताकि ग्रामीण लोगों की आमदनी और रहन-सहन का स्तर भी अन्य क्षेत्रों के लोगों के साथ साथ ऊँचा उठे। कृषि-उत्पादन का स्तर देख कर यह भी पता लगता है कि समस्त अर्थव्यवस्था की तरक्की किस रूप-रंग में हो रही है। यों भी, कृषि-अर्थव्यवस्था का विस्तार और ग्रामीण जन-शक्ति तथा अन्य साधनों का उपयोग करने में परस्पर गहरा सम्बन्ध है। . . .

सामान्य विचारों के द्वितीय वर्ग का सम्बन्ध योजना में उद्योग, बिजली और परिवहन के क्षेत्र को प्रदान की गई प्राथमिकता से है। अर्थव्यवस्था को

1 तीसरी पंचवर्षीय योजना (रूपरेखा) — भारत सरकार, पृष्ठ २३—२४
(प्रायः सभी अविकसित देशों के नियोजन की रूपरेखा इसी ढंग की होती हैं)

उच्चतर स्तर पर ले जाने और उसकी गति को तीव्र करने के लिये इन क्षेत्रों का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। यह मानी हुई बात है कि आगे बढ़ने के क्रम में एक मजिल ऐसी आ जाती है कि उससे आगे कृषि की उन्नति और जनशक्ति का विकास, उद्योगों की प्रगति पर ही निर्भर करने लगते हैं। इसलिये, कृषि और उद्योगों को सदा विकास की एक ही प्रक्रिया का समबाय अंग मान कर चलना चाहिए। जब तक अर्थव्यवस्था स्वावलम्बी गति की दशा में नहीं पहुँच जाती, तब तक औद्योगिक विकास के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बड़ी मात्रा में पड़ती ही रहेगी।

चूँकि बड़ी परियोजनाओं में लगाई हुई पूँजी से, उत्पादन-वृद्धि-रूपी फल की प्राप्ति, बहुधा बहुत समय के पश्चात् होती है, इसलिए उसकी योजना काफी पहले से बना लेनी चाहिए, और दीर्घकाल पश्चात् तथा अपेक्षाकृत कम समय में फल देने वाली परियोजनाओं में एक उचित अनुपात रख लेना चाहिए।

उद्योग, विजली और परिवहन आदि प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकताओं का निश्चय सावधानीपूर्वक कर देना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनमें तुरन्त ह्रां हेर फेर किया जा सके। ...इन क्षेत्रों के कार्यक्रमों का संचालन समन्वयपूर्वक होना चाहिए।

औद्योगिक क्षेत्र की योजना, ममस्त अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनाई (जाती) है, और बँसा करते समय योजना के सरकारी और निजी क्षेत्रों की एक मान (लिया जाता है)। उपलब्ध प्राकृतिक साधनों और देश की बटनी हुई आवश्यकताओं का तकाजा (होता) है कि बुनियादी उद्योगों पर—विशेषकर इस्पात, यन्त्र-निर्माण, ईंधन और विजली पर—ज्यादा जोर दिया जाय। “समाज सेवाओं, विकरम-क्षेत्रों,” वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा, आदि पर भी प्राथमिकता प्रदान की जाती है। नियोजन की रूपरेखा बनाते समय लक्ष्य, उद्देश्य, साधन आदि विषयों का पूर्णरूप से ध्यान रखा जाना चाहिए।

१०—अविकसित देशों में नियोजन की कठिनाइयाँ

(Problems of Planning in Under-developed Countries)

अविकसित देशों के नियोजकों को नियोजन के निर्माण में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विशेषरूप से, नियोजन को प्रारम्भिक अवस्था में यह कठिनाइयाँ स्पष्टरूप से दिखाई देती हैं तथा नियोजकों को जटिल परिस्थिति में डाल देती हैं। किन्तु, नियोजन का कार्य जब सुचारु रूप से चल पड़ता है तो

यह कठिनाइयाँ क्रमशः निस्तेज होने लगती हैं, और अन्तिम रूप से यह समाप्त हो जाते हैं। नियोजन के प्रारम्भिक काल में निम्नलिखित कठिनाइयाँ विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती हैं :—

(१) आँकड़ों सम्बन्धी कठिनाइयाँ—नियोजन के निर्माण के लिये एवं उसे सुव्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त मात्रा में एवं सही आँकड़ों की आवश्यकता होती है। सही आँकड़ों के अभाव में विभिन्न आवश्यकताओं की सही मात्रा का ज्ञान नहीं हो पाता। नियोजन के उद्देश्य, लक्ष्य, प्राथमिकता, साधन एवं ग्रन्थ विषयों के निर्धारण के लिये पर्याप्त मात्रा में एवं सही प्रकार के आँकड़ों (data) की आवश्यकता होती है। इनके अभाव में नियोजन का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। अविकसित देशों में प्रायः सही आँकड़े इकट्ठे करने की समस्याएँ नहीं होती—जिससे नियोजन कार्य में बाधा पड़ती है। भारतवर्ष में भी, प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में आँकड़ों का अभाव स्पष्टरूप से अनुभव हुआ था। अब इस कार्य पर अधिक दल प्रदान किया जा रहा है।

(२) जनसंख्या के अनुमान की कठिनाइयाँ—अविकसित देशों में से अधिकतर या तो जनसंख्या-आधिक्य के शिकार हैं या जनसंख्या की कमी के। इससे कमी-कमी नियोजन-कार्य में कठिनाई हो जाती है। परन्तु, जनसंख्या की सही मात्रा के विषय में अज्ञानता अत्यन्त हानिकारक है। इन देशों में प्रायः यह पाया जाता है कि देश की जनसंख्या को निरन्तर जानने का प्रयास नहीं होता। भारतवर्ष में जन-गणना प्रत्येक १० वर्ष बाद होती है। इस बीच जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसके बारे में जानकारी केवल अनुमान द्वारा ही ज्ञात की जाती है—जो सैद्धान्तिक रूप से गलत है। जनसंख्या की वृद्धि किसी विशेष गति से नहीं होती है, अर्थात् किसी वर्ष जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है और कभी मंद गति से। इस प्रकार नियोजक जब नियोजन का खाका बनाते हैं तो वे जनसंख्या के अनुमानित अंक को ही ध्यान में रखते हैं, और उसी के अनुसार नियोजन करते हैं जिससे नियोजन कार्य में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। भारतवर्ष की प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सफलता की कमी होने का एक कारण यह भी रहा कि जनसंख्या में वृद्धि (नियोजन काल में) अनुमान से अधिक तीव्रता से हुई।

(३) प्राकृतिक साधनों के अनुमान संबंधी कठिनाई—नियोजन कार्य को सतुलित एवं सुव्यवस्थित रूप से करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक होता है कि देश की प्राकृतिक संपत्ति के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। इसी के आधार पर उत्पत्ति के लक्ष्य, उद्देश्य एवं नियोजन पद्धति का निर्धारण निर्भर करता है। देश में यदि प्राकृतिक साधनों की भरमार हो तो ऐसे नियोजन को कार्यान्वित किया जा सकता है जिसमें इन साधनों का उपयोग अधिक मात्रा में तथा ठीक प्रकार से किया जाय। इसके विपरीत, यदि देश में प्राकृतिक साधनों की कमी होती

छोटे प्रकार के नियोजन का निर्माण प्रवृत्तमाननी होया। नियोजकों के सामने प्राकृतिक सम्पत्तों सम्बन्धी धाकड़े तथा तथ्यों का होता बहुत बहुरी है। विन्तु, सेद का प्रियम है कि प्रायः सभी अधिकसित देशों में दस प्रकार के प्रामाणिक तथ्यों की हमेशा कमी रहती है जिससे नियोजन का कार्य जटिल हो जाता है। भारतवर्ष में अब विभिन्न साधारण और सरकारी सस्थाओं द्वारा—सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों से—इस प्रकार के धाकड़े सब इकट्ठे किए जा रहे हैं जिससे नियोजन का कार्य कमश सरल होता जा रहा है।

(४) राष्ट्रीय धाय के विषय में अज्ञानता—यह एक और कमी है जो अधिकसित राष्ट्रों के नियोजनाधिकारियों के सामने नियोजन-निर्माण में कठिनाई पैदा करती है। राष्ट्रीय धाय के विषय में जब तक पूर्ण ज्ञान न हो तब तक नियोजन के उद्देश्य और लक्ष्यों के निर्धारण में सुविधा नहीं होती। राष्ट्रीय धाय यदि बहुत कम हो तो अनुपयोग में खर्च करने की शक्ति भी कम होगी एवं पूँजी का निर्माण भी प्रयत्न मंद गति से होगा। इसका प्रभाव यह होगा कि प्रामाणिक विकास का कार्य बहुत गति से सम्भव नहीं हो सकेगा। इसके अविरुद्ध भी, राष्ट्रीय धाय के विषय में अज्ञानता रहने पर नियोजन का सम्पूर्ण आधार भी खलत हो सकेगा। माधुनिक काल में प्रायः प्रत्येक सरकार द्वारा इस बात को जानन की चेष्टा की जाती है कि यहाँ की राष्ट्रीय धाय प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी है? अब इस बात का निर्धारण होता है कि नियोजन के लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय धाम में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये? भारत में विभिन्न सरसामों द्वारा राष्ट्रीय धाय को आसने का प्रयास होता आ रहा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष, प्रतिव्यक्ति की आयदनी में वर्धमान वृद्धि का लक्ष्य रखना गया है।

(५) कर-बहुल शक्ति के विषय में अज्ञानता—नियोजन कार्य की सफल बनाने के लिए उस पर निश्चित माया में धर्च करना पड़ता है। सरकार के पास इस धर्च को ठठाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से कर द्वारा जवता से दरमा प्राप्त करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कर लगाने के निश्चान्तों में यह भी बताया जाता है कि अधिकतम कर लगना ही लगना चाहिए जितना कि साधारण जनता सरसता से वहन कर सके। इसके लिए यह आवश्यक होता कि समय-समय पर दस बात की मोन होती रहे कि देशवासियों की कर-बहुल-शक्ति कितनी है? अधिकतर देशों में इस बात की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है जिसके कारणसे कर की रूप से एवं ठीक मात्रा में कर लही छप जाता। अधिकसित देशों के नियोजकों के सामने यह भी एक समस्या होती है।

(६) विनियोग शक्ति की अनुमान सम्बन्धी कठिनाई—अधिकसित देशों में प्रायः इस बारे में लक्ष्य और धाकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते कि देश में विभिन्न उस्तसित-प्रयासों में कितनी मात्रा में विनियोग हो सकता है। अर्थात् इन राष्ट्रों के

नियोजनाधिकारियों को इस बात की अज्ञानता होती है कि विभिन्न क्षेत्रों में, नियोजन काल में, कितनी मात्रा में एवं किस रूप से विनियोग संभव है ? इस अज्ञानता के कारण नियोजन के उद्देश्य, तरीके, आकार, प्रणाली, लक्ष्य एवं साधनों के निर्धारण में कठिनाई होती है। भारत में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ था तो यह कठिनाई भयानक रूप से नियोजकों के सामने उपस्थित हुई थी। अब यह समस्या इतनी भयानक नहीं रह गई है, क्योंकि विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा अब इस विषय में जानकारी होती है।

(७) पूँजी उत्पादन-अनुपात (Capital Output-Ratio) संबंधी आंकड़ों का अभाव—अविकसित देशों में पूँजी-उत्पादन अनुपात के विषय में विशेष जानकारी नहीं होती है। इसका एक कारण तो यह है कि इन देशों में उद्योग धंधे अधिक उन्नत दशा में नहीं होते हैं, और दूसरा कारण यह है कि इसके अध्ययन के समस्त लाभों के विषय में इन देशों के निवासी प्रायः अनभिज्ञ हैं। नियोजन के निर्माण में इस विषय में तथ्यों की उपलब्ध अत्यंत आवश्यक है। इसी के आधार पर नियोजक उद्योग संबंधी नीति का निर्माण करता है। भारत में नियोजन के प्रारम्भिक काल में इस विषय पर अधिक ध्यान प्रदान नहीं किया गया था, किन्तु अब इस बारे में पूर्ण जानकारी का प्रयास होना है। जब इस विषय पर पूरे तथ्य और आंकड़े प्राप्त होने लगेंगे तो नियोजन का कार्य और सुगम हो जायगा।

(८) नियोजनकाल संबंधी कठिनाई—अविकसित राष्ट्रों के सामने एक यह भी कठिनाई होती है कि वह इस बात को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें कि नियोजन की अवधि अल्पकाल की होगी या दीर्घकाल के लिए ? दीर्घकालीन नियोजन के लिए विशाल साधन की आवश्यकता होती है—जो प्रायः सभी अविकसित देशों के लिए जुटाना कठिन होता है। दूसरी ओर, यदि योजना काल अत्यंत छोटा हो तो नियोजन के सभी उद्देश्य प्राप्त न हो सकेंगे। यही कारण है कि प्रायः सभी अविकसित देशों में नियोजन प्रणाली इस प्रकार की होती है कि एक 'नियोजन' दीर्घकाल के लिए प्रायः ५ से ७ वर्ष तक होता है जबकि उसी अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिए भी एक छोटी-छोटी योजना बनाई जाती है। इससे दीर्घकालीन योजना के समस्त लाभ प्राप्त हो जाते हैं और उसके निर्माण तथा कार्यान्वित होने की कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं।

(९) द्रव्य सम्बन्धी कठिनाई—अविकसित देशों के सामने नियोजन कार्य में सबसे बड़ी बाधा या कठिनाई द्रव्य सम्बन्धी होती है। इन देशों के पास विशाल योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए साधनों की कमी रहती है। इसी कारण नियोजकों को सबसे अधिक प्रयास इस बात का करना पड़ता है कि नियोजन कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए द्रव्य की व्यवस्था किस प्रकार हो ? साधारणतया

वे इस बात की चेष्टा करते हैं कि नियोजन कार्य के लिए अधिकतम धन सरकारी आमदनी से प्राप्त किया जाये। परन्तु प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नियोजन-कार्य को चलाने के लिए उन देशों की सरकार की आमदनी कम रहती है। इसलिए इन राष्ट्रों द्वारा आमदनी में वृद्धि करने के लिए करो में वृद्धि की जाती है। जब कर में वृद्धि द्वारा भी समस्त आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो देश की जनता से ऋण लिया जाता है। यदि इससे भी आवश्यकता की पूर्ति न हो तो विदेशों से ऋण मांगा जाता है तथा घाटे की बजट-योजना का निर्माण किया जाता है। व्यावहारिक रूप से यह देखा जाता है कि इन राष्ट्रों की नियोजन सम्बन्धी द्रव्य की आवश्यकता इन समस्त उपायों को अपनाने के पदचातु भी पूरी नहीं हो पाती और नियोजकों की नियोजन का निर्माण करते समय द्रव्य सम्बन्धी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(१०) घाटे के बजट योजना से उत्पन्न कठिनाइयाँ—जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, अविकसित राष्ट्रों द्वारा घाटे का बजट बना कर नियोजन कार्य सम्बन्धी द्रव्य और वित्तीय साधन की पूर्ति करने का प्रयास होता है। इससे यह कठिनाई तो काफी सीमा तक दूर हो जाती है, परन्तु और अन्य कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं—जैसे, देश में मुद्रा प्रसार उत्पन्न होने के फलस्वरूप सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं। उसका परिणाम यह होता है कि उपभोग का स्तर तथा जीवन-स्तर दोनों ही नीचे गिरन लगते हैं, और नियोजन का उद्देश्य, जो कि जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने का होता है, वह पूरा नहीं हो पाता है। अविकसित राष्ट्रों की सरकार और नियोजनाधिकारियों को सदा इस ओर मचेष्ट रहना पड़ता है कि घाटे के बजट के निर्माण से देश में अत्यधिक मुद्रा-प्रसार और कीमतों में वृद्धि न होने पावे। इसके लिए उन्हें नियन्त्रण और राशनिंग आदि प्रणालियों को अपनाना पड़ता है।

(११) श्रम और उत्पत्ति के अन्य साधनों की गतिशीलता में कमी—अविकसित राष्ट्रों के नियोजकों को एक और भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन देशों में प्रायः यह देखा जाता है कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में उतनी गतिशीलता नहीं होती जितनी उन्नत देशों में होती है। इस कारण भी नियोजक औद्योगीकरण के कार्य में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते जितनी कि वह प्राप्त करना चाहते हैं।

(१२) तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव—अविकसित राष्ट्रों में नियोजन कार्य में तथा उद्योग धन्धों और व्यवसायों में उन्नति प्राप्त होने में इस कारण भी कठिनाई उत्पन्न होती है कि तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव होना है। उत्पत्ति के क्षेत्र में उत्पादन प्रणाली में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है एवं शक्ति के नये साधनों और मशीनों का अधिकतम प्रयोग उद्योगों में होता है। उद्योगों को उन्नतिशील बनाने के लिए विशिष्ट शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता

होती है—इनके अभाव में औद्योगीकरण का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पाता । उन्नत देशों को इस प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है ।

(१३) विदेशी मुद्रा की कमी एवं पूँजी निर्माण का अभाव—कम प्रामदनी वाले देशों में पूँजी निर्माण का कार्य मरलता से नहीं हो पाता । नियोजन-कार्य को मरलता में प्रचलित करने एवं अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अधिकतम मात्रा में मशीनों और यन्त्रों का व्यवहार हो । परन्तु इन देशों में न तो अधिकतर मशीन और यन्त्रों का निर्माण ही होता है और न इनके पास इतने साधन होते हैं कि वे अपनी पूर्ण आवश्यकतानुसार मशीनों को विदेशों से ही खरीदें । यह कार्य सभी सम्भव हो सकेगा जब इन देशों में विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध बड़ी मात्रा में सम्भव हो सके । प्रायः अविकसित देशों में विदेशी मुद्रा की अत्यन्त कमी बनी रहती है जिससे नियोजन के कार्य में बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है ।

(१४) शासन-सम्बन्धी तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी कठिनाइयाँ—इन देशों के नियोजनाधिकारियों को शासक तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है । शासन-प्रबन्ध प्रायः प्रभावशाली नहीं होता जिससे नियोजन-कार्य की सफलता में बाधा उत्पन्न होती है । नियोजन के प्रारम्भिक काल में प्रत्येक क्षेत्र में स्वतः ही कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जिनको दूर करने के लिए शासन-प्रबन्ध का प्रभावशाली होना आवश्यक है ।

राज्य-उद्योगों में प्रबन्ध और प्रशासन-सम्बन्धी कठिनाइयाँ विद्यमान होती हैं—जिससे इन क्षेत्रों में नियोजनाधिकारियों को सफलता प्राप्त नहीं होती । राज्य उद्योगों का प्रशासन एवं संचालन ठीक रूप से होना चाहिए नहीं तो आशानुरूप फल इन उद्योगों से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

(१५) जनता के सहयोग का अभाव—राज्य नियन्त्रित और केन्द्रीय-संचालित नियोजनों की सफलता जनता के सहयोग पर निर्भर होती है । अविकसित देशों की जनता प्रायः अशिक्षित होती है जिसके कारण नियोजन के सभी लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होते—जिससे वे सरकार को नियोजन की सफलता में उतना सहयोग नहीं दे पाते जितना सहयोग कि उन्हें देना चाहिए । इन देशों की जनता प्रायः अत्यन्त निर्धन होती है जिसके कारण नियोजन काल में जब उन्हें अधिक कर देना पड़ता है तो वे नियोजन का विरोध करने लगते हैं । इन देशों के नियोजनाधिकारियों को विभिन्न प्रकारों द्वारा जनता को इस बात का विश्वास दिलाना पड़ता है कि नियोजन उन्हीं के लिए है और मौजूदा परिस्थिति में उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वे आगे नहीं रहूँगी, तथा उनकी सन्तानें नियोजन के पूरे लाभ उठा पायेंगे ।

इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त भी, अविकसित देशों के नियोजनाधिकारियों को कुछ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे, अति जनसंख्या सम्बन्धी समस्या, देश में फैली हुई शिक्षा, स्वास्थ्य हीनता, निवास स्थान सम्बन्धी और बेरोजगार सम्बन्धी समस्याएँ, नियोजन के निर्माण करते समय प्राथमिकता, उद्देश्य, लक्ष्य एवं साधन के निर्धारण सम्बन्धी-कठिनाइयाँ, केन्द्रीय नियोजन की सामान्य कठिनाइयाँ एवं केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्यों के नियोजनों में असन्तुलन की कठिनाइयाँ आदि।

११—अविकसित देशों में नियोजन को सफल बनाने के तत्त्व

(Factors governing the success of Planning in Under-developed Countries)

अविकसित राष्ट्रों में नियोजन कार्य को सफल बनाने के तत्त्वों को सरलता से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(अ) आन्तरिक तत्त्व एवं (ब) बाहरी तत्त्व

आन्तरिक तत्त्व (Internal factors)

आन्तरिक तत्त्व, जिन पर अविकसित राष्ट्रों में नियोजन की सफलता निर्भर करती है बहुत से होने हैं। इससे पहले अविकसित राष्ट्रों में नियोजन की कठिनाइयाँ जिन क्षेत्रों में एष जिस रूप में बताई गई हैं उनको ही यदि दूर कर दिया जाये तो नियोजन कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकेगी।

इनके अतिरिक्त यह भी आवश्यक होता है कि नियोजनकाल में देश में पूर्णरूप से शान्ति और सुरक्षा बनी रहे। यदि देश में शान्ति और सुरक्षा का अभाव हो तो उद्योग-धन्धों, व्यवसायों एवं अन्य प्रयासों के क्षेत्रों में क्षिप्तता आजावेगी जिससे नियोजन की सफलता में बाधा आवेगी। किन्तु, इसके विपरीत, यदि देश में पूर्ण शान्ति और सुरक्षा हो तो इस बात की आशा होगी कि नियोजन कार्य सफलतापूर्वक एवं द्रुत गति से अग्रसर होगा।

इसी प्रकार यदि राष्ट्रीय सरकार देश की जनता में यह विश्वास पूर्णरूप से छरान कर सके कि नियोजन की सफलता से उनकी समृद्धि में वृद्धि होगी और उसे जन-सहयोग प्राप्त हो सके, तो भी नियोजन के कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्ति की आशा बनी रहती है। भाग्यवश में पहली योजना के शुरू से ही राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने पर बड़ा जोर दिया जाता रहा है। यह भी अनुभव किया जा रहा है कि जिन कार्यों का सम्बन्ध स्थानीय लोगों के कल्याण से हो, उनमें लोगों के सगठन विशेष योग दे सकते हैं। यह आशा एक बड़ी मात्रा में पूरी भी हुई है। अनेक स्वयंसेवकों ने, विशेषकर स्त्रियों ने, स्वयं प्राणों बढ़ कर नई जिम्मेदारियाँ उठाई हैं। केन्द्र और राज्यों की सरकारों को भी कई बार कुछ सामंजस्यपूर्ण सगठनों की सहायता करने का अवसर मिला

है। इससे सरकार को मौका मिला कि वह विभिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षित और पूरा समय लगा कर काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं को पेश कर सके। सरकार ने कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय-स्मारक-न्यास, हरिजन-सेवक-संघ, गांधी-स्मारक निधी, भारत-सेवक-समाज, भारतीय समाजकार्य-सम्मेलन, भारतीय-शिशु-कल्याण-परिषद, आदि प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर 'राष्ट्रीय जन-सहयोग-परामर्शदात्री समिति' स्थापित की है, जो जनता का सहयोग प्राप्त करने के क्षेत्र में सरकार का मार्ग-प्रदर्शन करती है। विकास के कार्यक्रमों में जनता का सहयोग प्राप्त करने से सम्बद्ध समस्याओं पर भी इस समिति में विचार-विमर्श होता रहता है। इस समिति की सिफारिशों से जो योजनाएँ चल रही हैं अथवा भविष्य में चलाई जायेंगी, उनकी पूर्ति के लिए १० करोड़ रु० की राशि रख दी गई है। एक विचार यह भी है कि विकास-कार्यों में जनता का सहयोग बढ़ाने की नई नई विधियाँ निकालने और उनका प्रदर्शन करने के लिए कुछ योजनाएँ चलाकर देखी जायें और इस प्रश्न का अनुसंधान करने के लिए अध्ययन आरम्भ किया जाए।¹

देश की प्रशासन की कुशलता और उपलब्ध जन-सहयोग पर नियोजन की सफलता एक बड़ी सीमा तक निर्भर होती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के विवेक को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है² प्रशासन के सभी काम कुशलता और शीघ्रता से करने की आवश्यकता और जहाँ कहीं जनता से वास्ता पड़े, वहाँ प्रशासन में उसका अधिक से अधिक विश्वास प्राप्त करना ऐसी समस्याएँ हैं, जिनका अधिक विकास के क्षेत्र में गम्भीर महत्त्व होना है। विकास कार्यों की गति और सरकार के कर्तव्य बढ जाने के कारण, प्रशासन में सुधार के इन पहलुओं को और भी जल्दगी समझा जाने लगा है। प्रशासन के सुधार में प्राप्तिव्य प्रधान लक्ष्य ये हैं :

- (१) सरकार अपनी नीतियों का निर्धारण स्पष्ट शब्दों में कर दे और उनका निरन्तर पालन होते रहने का ध्यान रखे।
- (२) नीतियों के पालन करने में - किसकी जिम्मेदारी क्या है, इसे स्पष्टतः निर्धारित कर दिया जाय।
- (३) कार्य ठीक प्रकार से और शीघ्रता से होना चाहिए।
- (४) इसका पता रखा जाय कि बड़ी योजनाओं से कितना लाभ हो रहा है।
- (५) जनता के साथ सम्पर्क और सहयोग ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं और सब नागरिकों के साथ शिष्टता और नम्रता का वर्तव्य किया जाता है या नहीं।

1. तृतीय पंचवर्षीय योजना (रूपरेखा), भारत सरकार, पृष्ठ ६८।

2. तृतीय पंचवर्षीय योजना (रूप रेखा)—भारत सरकार, पृष्ठ ६०।

इसके साथ-साथ इस बात की भी आवश्यकता होती है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच में पूर्ण समन्वयता हो। यदि केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेद बने रहें तो नियोजन द्वारा आवश्यक एवं इच्छित सफलता प्राप्ति में बाधाएँ उत्पन्न हो जाने का डर बना रहेगा।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त भी, नियोजन को सफल बनाने के लिये देश में कुछ आधारभूत तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है जैसे द्रव्य और साधन की व्यवस्था करना, सही आँकड़े एवं तथ्यों की प्राप्ति की व्यवस्था, मुद्रा प्रसार को रोकने का भरसक प्रयास, कीमतों को बढ़ने से रोकने के उपाय सोचना, साथ-साथ-साथ सस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण, व्याप-सामग्री एवं उद्योगों के लिए कच्ची सामग्रियों के क्षेत्र में घातमित्रीकरण की स्थिति उत्पन्न करना, विदेशी ऋण और तकनीकी सहायता की व्यवस्था करना आदि।

बाह्य ताव (External Factors)

नियोजन की सफलता के लिये बाह्य तत्त्वों का अनुकूल होना भी बाह्यनीय होता है। बाह्य तत्त्वों में विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विद्यमान राजनैतिक वातावरण होता है। यदि वातावरण ठीक है तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सुख और धान्ति का अस्तित्व होना स्वाभाविक है। उस परिस्थिति में ससार के उन्नत देश अधिकसिद्ध देशों को नियोजन द्वारा आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिये भरसक प्रयास करते हैं। निम्न यदि वातावरण उनाब का या दूषित है (जिसमें युद्ध का भय बना रहता है) तो सभी देश युद्ध-सामग्री के निर्माण में एवं अपनी सुरक्षा के लक्ष्यों में व्यस्त होगे। परिणाम स्वरूप, अधिकसिद्ध देशों को इन देशों से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त न हो सकेगी।

राजनैतिक मतभेद के कारण भी एक देश दूसरे देश की सहायता प्रदान करने से हाथ खींच लेता है। जैसे इस समय ससार में दो बात चलचल हैं—पूँजीवादी विचारों का देश, एवं समाजवादी और साम्यवादी विचारों वाले देश। यदि एक देश पूँजीवादी सिद्धान्त को मानने वाला है तो उसे कोई सहायता साम्यवादी देशों में प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार, यदि वह साम्यवादी विचारधारा में विश्वास करे तो उसे पूँजीवादी राष्ट्रों से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी।

यदि अधिकसिद्ध देश किसी उन्नत देश द्वारा धासित है, तो जब तक आर्थिक दृष्टि से उन्नत देश इस अधिकसिद्ध देश की ऊँचाई न उठाना चाहें तब तक न तो वह ठीक प्रकार से नियोजन का कार्य ही कर पायेगा, और न नियोजन द्वारा अपने देश को आर्थिक दृष्टि से उन्नत ही कर पायेगा। अर्थात्, जब कोई देश दूसरे पर धासित होता है तो वहाँ 'नियोजन' का सफल होना बहुत ही कठिन होता है।

अधिकसिद्ध देशों के नियोजन की सफलता काफी हद तक आर्थिक दृष्टि से उन्नत देशों की आर्थिक और तकनीकी सहायता पर निर्भर करती है। प्रायः इन देशों

के पास पूँजी की कमी रहती है। इसी कारण, योजना को सफल बनाने के लिये, उन्हें विदेशों से सहायता एवं ऋण लेनी पड़ती है। इसके अभाव में, इन देशों में नियोजन का कार्य असम्पूर्ण रह जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अविकसित देशों के सामने नियोजन कार्य में बहुत सी बाधाएँ उपस्थित होती हैं। इसके अतिरिक्त, इन देशों में नियोजन कार्य की सफलता विदेशी सहायता पर भी निर्भर होती है। किन्तु इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि इन राष्ट्रों को नियोजन प्रयास छोड़ देना चाहिए। इसके विपरीत, अधिक उत्साह और उद्यम से कार्य में लग जाना चाहिए। यह हर्ष की बात है कि भारतवर्ष समस्त कठिनाइयों को दूर करके एक नियोजन की पहली बाधाओं से निराश न होकर उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहा है।

विविध

(Miscellaneous)

१—परिवार नियोजन^१ (Family Planning)

परिवार नियोजन का लक्ष्य है परिवार के स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिये उपयुक्त वातावरण बनाना। परिवार के जीव-विज्ञान सम्बन्धी, आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं और परिवार के महत्व पर विचार करने से परिवार के बहुत से दुख मिट सकते हैं। यह काम और भी सरल हो जाए यदि परिवार की क्रमिक उन्नति लिए और दाम्पत्य सम्बन्ध के मानव प्रजनन का विज्ञान तथा वैवाहिक जीवन की साम्यता एवं विषमता के कारणों अथवा पारिवारिक जीवन की अथ समस्याओं का अध्ययन किया जावे।

यह स्पष्ट है कि परिवार नियोजन जीवन का उत्तरदायित्वहीन ढंग नहीं है। परिवार की सीमाबन्दी तक ही इसका ध्येय समाप्त नहीं होना। परिवार नियोजन के कार्य में केवल कम बच्चे पैदा करना और उनके जन्म में समयान्तर देना ही नहीं है परन्तु और भी ऐसे कार्य हैं जो परिवार के कल्याण के लिये आवश्यक हैं, जैसे युवक युवतियों को विवाह तथा पितृत्व के दायित्व योग्य बनाना, बांझपन, सन्तानोत्पत्ति, काम सम्बन्धी शिक्षा, विवाह सम्बन्धी सलाह मसवरा आदि देना भी है, जिनसे परिवार की वृद्धि और उन्नति हो और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सामूहिक कल्याण के लिये आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण हो।

परिवार समाज का प्राथमिक अंग है और इसकी धीरे धीरे पुनर्प्राप्ति होना जारी है। समाज की उत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने परिवार को सीमित रखें और इसका सामूहिक स्तर तथा आय परिवार के प्रकार के अनुकूल हो। मा बाप तथा बच्चा की सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामाजिक वातावरण तैयार करने में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

१ परिवार नियोजन क्यों ? (Produced by the Directorate of Advertising & Visual Publicity, Ministry of I & B for Ministry of Health, Govt of India)

मुख्य लक्ष्य

जनसंख्या सबधी ऐसी नीति अपनाने का मुख्य लक्ष्य है परिवार के सुख एवं स्वास्थ्य की रक्षा, अनिच्छित बच्चों की संख्या में कमी तथा आवश्यक और इच्छित बच्चों की संख्या में वृद्धि की जाय। इच्छित बच्चे का स्वागत होता है और वह प्यार एवं ममता भरे वातावरण में पलता है।

भारत में परिवार परिसीमन एक बड़ी समस्या है। इसी कारण से परिवार के आकार पर अधिक बल दिया जाता है और परिवार परिसीमन तथा परिवार नियोजन को समानार्थक माना गया है। परिवारसीमन कार्यक्रम (जो कि आवश्यक है) को यत्नपूर्वक चलाते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि "परिवार नियोजन" सीमित अर्थों में न लिया जाए, क्योंकि इसमें वे समस्त उपाय हैं जो परिवार और समुदाय के सुख और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

बहुमुखी समस्या

जनसंख्या सबधी समस्याएँ बहुमुखी हैं यानी संख्या सबधी तथा जीव विज्ञान पर आधारित, व्यक्ति से संबंधित तथा समुदाय से संबंधित। जनसंख्या और परिवार की संख्या में वृद्धि सरल तथ्यों पर आधारित है। जिनका ज्ञान आवश्यक है। फेयरचाइल्ड¹ के शब्दों में मानव भी धरती पर एक पशु है और आत्मिक एवं बौद्धिक विकास के फलस्वरूप अन्य पशुओं के समान ही आवश्यकताओं और सीमाओं में स्वयं भी बंधा हुआ है। इस धरती के आकार प्रकार भी सीमित है और इसी के अन्दर मानव को अपनी विश्व यापी रहने और खान की मांगों की पूर्ति करना पड़ती है और दोनों हालतों में सभावनाय सीमित होती है। अपने जीवन चक्र में प्रत्येक जीव भूख तथा काम प्रेरणा की दो मौलिक शक्तियों द्वारा परिचालित होता है। परंतु असीमित प्रजनन क्षमता तथा सीमित खाद्य सामग्री सभावनाओं के कारण ये दोनों मूल शक्तियाँ सीधे एक दूसरे के विमुख होती हैं।

आर्थिक कारण

यह स्पष्ट है कि आर्थिक कारणों के आधार पर जन्मानुपात में कमी होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब प्रत्येक दम्पति परिवार नियोजन द्वारा अपने बच्चों की संख्या कम करने का प्रयत्न करे। बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना-कपड़ा और अन्य सुविधाएँ प्रदान करने कीलिय यह आवश्यक है कि परिवार के आकार पर नियन्त्रण रखा जाए। उचित समय के अन्दर अन्दर उस ध्येय की पूर्ति के लिए सभी परिवारों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। कठिन प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलगी।

1 हैनरी फेयरचाइल्ड : "पापुलेशन एण्ड पीस" विरजीनियरलिंग आफ प्लेण्ड प्रेग्नहुड।

नैतिक कारण

परिवार नियोजन को अपनाने में नैतिक कारण भी क्वाबट नहीं होने चाहिए। पिछली सदियों में विश्व के विभिन्न भागों में लोग जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए शिशु हत्या और नवजात बच्चों की लापरवाही किया करते थे। परन्तु सन्तति नियंत्रण के लिए आधुनिक तरीकों में ऐसी कोई वृत्ति नहीं है। उनका प्रयोग तो एसी वृत्तियों को रोकने के लिए किया जाता है। गर्भ रोकने से किसी की हत्या नहीं होती। अतः परिवार नियोजन को अपनाने में कोई अनैतिकता नहीं है।

स्वास्थ्य

परिवार नियोजन के बारे में डाक्टरों दृष्टिकोण इतना स्पष्ट है कि उसके ब्योरे की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी घटनाओं का प्रत्येक डाक्टर को पता है जहाँ पर गर्भ से माँ अथवा बच्चे के जीवन को खतरा पैदा हो गया हो या उसके बाद उनका जीवन दुःखमय बन गया हो। यदि माँ दुर्बल हो या किसी भयानक रोग से पीड़ित हो तो उसके लिए गर्भ धारण बहुत खतरनाक है। दिल, केंफड़े, गुर्दे के किसी रोग, खून की कमी, पागलपन और गर्भ में रक्त दूषित रोग वाली स्त्री को गर्भवती बनने देना उसके और बच्चे दोनों के साथ घोर अन्याय करना है।

लोगों में यह विश्वास है कि पाँच छह बच्चों वाली माँ का गर्भवती बनना कम खतरनाक होता है। परन्तु असलियत यह है कि चौथी गर्भावस्था से खतरा बढ़ जाता है। छठी के बाद खतरा दुगुना हो जाता है और दसवीं के बाद पाँच गुना हो जाता है।

स्वस्थ स्त्रियों के लिए गर्भ धारण करना स्वाभाविक शारीरिक कर्म है। परन्तु ऐसा उचित परिस्थितियों में करना चाहिए और प्रसूतिपूर्व पर्याप्त अन्तर के साथ तथा थोड़ी सक्रियता में होनी चाहिए। उचित आहार की कमी और रोगों के कारण प्रसव-कष्ट बढ़ जाते हैं। माँ मानसिक को गर्भावस्था और प्रसव सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्रसव में पूर्व और उसके पश्चात् यदि माता, सेवा में कमी और प्रसव के समय थकती तरह देखभाल न होने से, तथा गरीबी, गन्दगी अथवा चिकित्सा की कमी जैसी दूसरे कारणों से स्त्री की गर्भ धारण की शक्ति कम होती जाती है तो बाद में गर्भावस्था और भी कष्टप्रद और स्वास्थ्य की दुश्मन बन जाती है। यथोचित समयान्तर वाली प्रसूतियों से माँ का स्वास्थ्य ठीक रहता है।

खतरनाक

ऐसी भी घटनाएँ हो सकती हैं जहाँ अस्वस्थ होने पर भी बच्चे पैदा करने की तीव्र इच्छा होती है। परन्तु प्रत्येक स्त्री की अवस्था भिन्न-भिन्न होती है। अतः डाक्टर का यह कर्तव्य है कि वह सभाव्य माना-पिनायों को खतरों से परिचित करा दें।

यदि गर्भ के कारण बार-बार माँ का रक्त दूषित हो जाता हो तो उसे और गर्भ धारण करने की सलाह नहीं देनी चाहिए। सबकी यही राय है कि एक बार बीमार होने पर तब तक गर्भ धारण नहीं करने देना चाहिए जब तक कि रोग के सभी लक्षण समाप्त नहीं हो जाते। रोग के तीसरी बार होने पर गर्भ धारण किसी भी अवस्था में नहीं होने देना चाहिए।

तपेदिक होने पर बच्चा माँ से अलग रहना चाहिए और उसके पालन-पोषण का प्रबन्ध घर से बाहर करना चाहिए। अतः ऐसे रोगियों को कम से कम बच्चे और परिवार के हित के लिए ही गर्भावस्था का परिहार करना चाहिए।

जिस स्त्री को गुर्दे सम्बन्धी रोग हो जाएँ उसे इस रोग से छुटकारा पाने के कम से कम दो वर्ष तक जब तक मूत्र भाग से पस और जीवाणु साफ न हो जायें, गर्भ नहीं होना चाहिए। गठिया और दिल के रोगों से पीड़ित स्त्रियों को गर्भवती बनने के खतरे से बचना चाहिए।

डायबटीज (मूत्र रोग) के रोगियों को सावधानी और परिवार परीक्षामन की आवश्यकता होती है। विशेषतया जब माता-पिता दोनों ही इस रोग के शिकारी हो।

रति रोग से पीड़ित व्यक्तियों को गर्भ धारण की सलाह देना उनके साथ अन्याय करना है। जब दोनों इस रोग से मुक्त हो तो गर्भ धारण करना चाहिये। शारीरिक दोषों अथवा अन्य किन्हीं कारणों से जिन स्त्रियों के बच्चे बार-बार आपरेशन द्वारा हुए हों अथवा बहुत बार गर्भ धारण कर चुकी हो, उन्हें गर्भ-निरोध के उपाय अवश्य करने चाहिए।

परिवार का आकार

अपने लिए उचित रहन-सहन का स्तर बनाए रखने और बच्चों को अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान करने की इच्छा ही मुख्य रूप से परिवार नियोजन को स्वैच्छया स्वीकार करने की प्रेरक शक्ति है।

माँ बाप सामाजिक और आर्थिक वातावरण को, जिनमें वे स्वयं रहते हैं, ध्यान में रखकर परिवार के आकार का निर्णय कर सकते हैं।

प्रत्येक परिवार के लिये बच्चों की संख्या निर्धारित करना बहुत कठिन है। भूतपूर्व रजिस्ट्रार-जनरल श्री आर० ए० गोपालस्वामी ने १९५१ की जनगणना की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक दम्पति के अधिक से अधिक तीन बच्चे होने चाहिए।

अकेला बच्चा प्रायः सूनापन महसूस करता है। बच्चों की आयु में भी इतना अन्तर नहीं होना चाहिए कि उसे घर में किसी दूसरे बच्चे की संगति का अभाव लगे।

बच्चे केवल दो होने की दशा में भी वे प्रायः मानसिक असन्तोष से मुक्त नहीं होते और एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। (उदाहरणार्थ भाई का अपनी बहन से

ईर्ष्या करना) । यह स्मरणीय है कि शायु के साथ-साथ बच्चे पैदा होने की सम्भावनाएं कम हो जाती हैं । पहली गर्भविस्था को बहुत समय तक टालना अच्छा नहीं है । जब माँ बाप पूर्ण यौवन में हो तो उस समय पहले बच्चे के पैदा करने की इच्छा हो जानी चाहिए । ताकि माता-पिता के प्रौढ़ अवस्था के पहुँचने तक बच्चे बड़े हो जाएँ और अपनी देखभाल करने योग्य बन जाएँ । यह माँ और बच्चे दोनों के हित में है कि बच्चों में कम से कम दो से तीन वर्ष का अन्तर हो ।

उचित उपाय

कुछ लोगों को डर है कि परिवार को सीमित करना प्रकृति के विरुद्ध है । सभ्यता की प्रगति मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर है । वह धीरे-धीरे अपने आप-आप के वातावरण पर काबू पा रहा है । मनुष्य ने मृत्यु के कई कारणों पर नियन्त्रण कर लिया है । उसी प्रकार उसे जन्म पर भी नियन्त्रण प्राप्त करना चाहिए । प्राचीन काल में जब कभी भी जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक हो जाती थी तो अकाल, महामारी, अनावृष्टि, बाढ़ अथवा युद्ध आदि द्वारा संतुलन कायम हो जाता था । परन्तु आज मनुष्य इस समस्या का हल आपदाओं की बजाएँ समुचित उपायों द्वारा चाहता है ।

सभ्यता के बारे में बताते हुए डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णण^१ ने कहा था "यह धीरे-धीरे मनुष्य द्वारा प्रकृति पर नियन्त्रण प्राप्त करना है । जबकि जानवरों की दुनियाँ में पशु-योनियों में जीवन अथवा मरण प्रकृति अथवा वातावरण पर निर्भर है, मनुष्य की इनकी बुद्धि दी गई है कि वह अपने आपको वातावरण के अनुकूल बनाए । प्रत्येक मानव का यह कर्तव्य है कि वह इस ज्ञात का पता लगाए कि सामाजिक, शारीरिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएँ कौन-कौन सी हैं और उनको पूरा करने का प्रयत्न करे । ईश्वर हमसे भिन्न नहीं है । वह हमारे अन्दर रह रहा है और सदा इस ज्ञात की प्रेरणा देता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सच्चे तरीके से तथा न्यायपूर्वक मनुष्य जाति के भले के लिए करें ।"

यह कहना है ?

इस बात का कोई समाधान नहीं है कि गर्भ निरोधक उपाय करना हानिकारक, अनैतिक, अप्राकृतिक अथवा दोष-बर्धक है । बल्कि इससे माँ के स्वास्थ्य की रक्षा होती है, अनिच्छित गर्भविस्था का भय दूर होता है, आप और अनिश्चित गर्भ से उमंगी रक्षा होती है और प्रत्येक दम्पति एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के योग्य बनते हैं । इससे माँ बाप को अधिक विश्वास है, सहस्रानुसृत मिलती है तथा बच्चे मरोग से नहीं बल्कि इच्छा से पैदा करने, बच्चों के स्वास्थ्य और सुख की रक्षा तथा अपने साधनों के अनुसार परिवार का आकार स्थिर करने में आसानी रहती है । इस तरह बच्चे व प्रति अपना कर्तव्य निभाने में मदद मिलती है ।

१. राधाकृष्णण, एम (१९५२) तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में अवसर पर उद्घाटन भाषण ।

इससे देश के साधनों के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता आती है और प्रत्येक दम्पति को एक सुखी, प्रबल एवं समृद्ध राष्ट्र बनाने में सहयोग देने का अवसर मिलता है । विश्व में बहुत कम देश हैं जिनको भारत की तरह जटिल जनसंख्या के संकट का सामना करना पड़ रहा है । देश तथा प्रत्येक परिवार को सुखी तथा समृद्ध बनाने के लिये यह आवश्यक है कि सब साधनों को विकसित और जनसंख्या को नियन्त्रित किया जाये ।

गुण

जीव विज्ञान सम्बन्धी हमारी जानकारी बहुत सीमित है । फिर भी तीन प्रकार के जैविक गुण हम जानते हैं । अर्थात् शुद्ध वंशागत, वंशागत एवं वातावरण-नुकूल, तथा शुद्ध वातावरणानुकूल । वातावरण द्वारा बहुत से वंशागत दोषों को दबाया और वाछनीय वंशागत गुणों को बढ़ाया जा सकता है । वातावरण पर मानव नियन्त्रण दिन प्रति दिन बढ़ रहा है ।

हम यह भी जानते हैं कि कुछ समय पहले इस बात के निर्णय में बहुत बड़ा हाथ मृत्यु का होता था कि किस व्यक्ति अथवा वर्ग के प्राणियों को जीवित रहना चाहिए । मृत्यु के कई कारणों पर नियन्त्रण कर देने के पश्चात् अब उत्पत्ति को भी दृष्ट्याधीन करने की भावना विभिन्न गतियों से विकसित हो रही है । परिवार परिसी-मन का प्रचलन शिक्षा सम्बन्धी, आर्थिक और व्यावसायिक कारणों से विभिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न है । इसलिये यह विचार करने की बात है कि विभिन्न वर्गों में जन्मानुपात क्यों भिन्न है । यह बहुत दुःख की बात होगी यदि परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा परिजनन क्षमता विशेष वाले लोगों की क्षमता का नाश कर दिया जाए । अस्टेन में जनसंख्या के सम्बन्ध में बैठायें गये रायल कमीशन ने कहा था कि नियोजन के जो लाभ हैं वे हमारे समाज में दिखाई पड़ते हैं । यह भी देखा गया है कि उन वर्गों के परिवार, जिनकी आय बहुत अधिक है और उन भ्राता पितामहों के जो अच्छे शिक्षित और बुद्धिमान हैं, दूसरों की अपेक्षा छोटे हैं । हमारे सामने जो विशेषज्ञों ने मत प्रकट किया है कि परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या को कम करने से देश की बुद्धि का स्तर गिर जाएगा, इस बात का हम पूरा अनुमान नहीं लगा सकते । इस प्रश्न पर काफी मौखिक विचार करने की आवश्यकता है ।

विभिन्न क्षेत्रों में प्रयत्न

यह भी कहा जाता है कि विश्व के ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ काफी अन्न होता है और दूसरों को दिया जा सकता है । वहाँ वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का भी भण्डार है । इसमें शक नहीं कि विश्व के साधनों को इकट्ठा करने, पर्याप्त पूर्णीकरण और तकनीकी उन्नति से स्थिति पर काबू पाया जा सकता है । समन्वित आयोजन, सभी क्षेत्रों में उन्नति और खोज तथा विश्व के साधनों को बराबर बाँटने से, हमारी बहुत सी कठिनाइयाँ हल हो सकती हैं, विश्व का सहयोग मिलने से उत्पादक सभार की समस्या, जो कि अविश्वसित और बहुत जनसंख्या वाले देशों की उन्नति में बहुत बड़ी बाधा है, किसी हद तक हल हो सकती है ।

इन कारणों के महत्त्व को कम नहीं समझा जा सकता। वस्तुतः रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने के लिए इस क्षेत्र में बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। संतति निग्रह में विद्वानों रखने वाले जनसंख्या के हल के लिए परिवार परिसीमन की सबसे अच्छी तरीका मानते हैं। उनमें से कुछ परिवार परिसीमन के लिए सामाजिक, प्राथमिक और सांस्कृतिक कारणों को ध्यान में नहीं रखते। बहुत से परिवार नियोजन और संतति निग्रह में कोई अन्तर नहीं मानते और जनसंख्या के गुणात्मक पहलू तथा परिवार नियोजन की अन्य समस्याओं की भी उपेक्षा कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो संतति निग्रह की निन्दा करते हैं और सभी कठिनाइयों का हल औद्योगीकरण बताते हैं।

दृढ़ रूप से सामाजिक, प्राथमिक तथा सांस्कृतिक वातावरण को सुधारने और विस्तीर्ण तथा प्रशस्त रूप में परिवार परिसीमन के संदेश का प्रचार करने से सफलता मिल सकती है। पहला कार्य करने से दूसरे के लिए अपने आप प्रोत्साहन बन जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य जनता के स्वास्थ्य, सुख और रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना है। बढ़ती हुई जनसंख्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक होती है। जनसंख्या की समस्या बहुत जटिल है और इसके हल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, औद्योगिक, कृषि और रोगाणु क्षेत्रों में प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

हमारे सामने एक जटिल समस्या है। यह ठीक है कि इसे हल करना आसान नहीं परन्तु निराश होने की कोई वजह नहीं है। सम्भवतः रोगाणु विकास अन्तिम छोर पर पहुँच गया है। मनुष्य उसकी महान् उत्पत्ति है परन्तु विकास अभी हो रहा है। मनुष्य के साथ ही साइकोसोशल विकास प्रारम्भ हो गया है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वह परिवर्तनों से गुजर चुका है और धीरे-धीरे वातावरण पर नियन्त्रण पा रहा है। यदि वह मृत्यु पर काबू पा सकता है तो जन्म पर भी नियन्त्रण कर सकता है। प्रश्न यह है कि क्या वह भाग्यवादी ही बना रहेगा या अनुभव से कुछ सीखेगा और जटिल समस्या को जिसका उसने स्वयं निर्माण किया है, दबलेगा। यदि वह समस्या के बारे में केवल तर्क ही करता रहा तो भ्रम, रोग, युद्ध और गरीबी अपना अपना प्रकोप दिखायेंगे। यदि उसने सबकुछ को डालने का निश्चय कर लिया तो उसे सफलता मिलेगी।

तीसरी योजना में परिवार-नियोजन¹

तीसरी और चौथी योजनाओं में परिवार-नियोजन कार्यक्रम को एक प्रमुख कार्यक्रम मानकर चलाया जाएगा। परन्तु साथ ही, इस कार्यक्रम में कई उलझन की बातें भी हैं, और इसका पल कुछ समय पश्चात् ही भाजूम हो सकता है। पहली योजना में इसका प्रारम्भ तो अल्प परिमाण में हुआ था, परन्तु अब इसका

विस्तार काफी हो चुका है—यहाँ तक कि १९६१ तक परिवार नियोजन के कार्य में सलग्न शहरी केन्द्रों की संख्या ६७६ और ग्रामीण केन्द्रों की संख्या १,१२१ हो जाएगी। स्वास्थ्य-मन्त्रालय ने तीसरी योजना के लिए सुझाव देने को एक विशेष समिति नियुक्त की थी। उसने इसके कार्यक्रम पर विचार करके कुछ सुझाव दिए हैं। उनका सम्बन्ध बहुत बड़े क्षेत्र से है और उनमें कार्यक्रम का विवरण, उसे पूरे करने के साधन, आर्थिक पहलू, स्त्री प्रथवा पुरुष का वन्द्याकरण, स्वेच्छिक सगठनों की भूमिका, गर्भ-निरोधक साधनों का उत्पादन, आदि अनेक विषय सम्मिलित हैं। इन सुझावों पर अभी विचार किया जा रहा है। अभी परिवार-नियोजन के लिए तीसरी योजना में २५ करोड़ ६० लाख दिए गए हैं, परन्तु विस्तृत कार्यक्रम बन जाने पर इस राशि के विषय में फिर विचार किया जाएगा। मोटी बात यह है कि इस कार्यक्रम को और फैलाया और घना किया जाएगा, परन्तु प्राधिकार जोर इन कामों पर दिया जाएगा।

- (१) परिवार-नियोजन के कार्यक्रम के अनुकूल सामाजिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए लोगों को समझाना बुझाना और प्रचार करना;
- (२) परिवार-नियोजन के कार्यों का साधारण स्वास्थ्य-सेवाओं के साथ मेल बैठाना,
- (३) चिकित्सा और स्वास्थ्य केन्द्रों की मार्फत परिवार नियोजन को वन्द्याकरण, आदि सेवाएँ उपलब्ध कराना और गर्भ-निरोधक उपकरण बाँटना,
- (४) मेडिकल कालेजों और अन्य शिक्षा-मन्त्रालयों में प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का विकास करना, और
- (५) परिवार-नियोजन के आन्दोलन में स्थानीय नेताओं का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना।

२—मूल्य-नीति (Price-Policy)

नियोजन को सफल बनाने के लिये प्रत्येक नियोजक को इस ओर सतर्क दृष्टि रखनी पड़ती है कि नियोजन-काल में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अत्यन्त वृद्धि न हो पाये। क्योंकि ऐसा होने से नियोजन का लक्ष्य (जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना) असफल हो जाता है। प्रथम और द्वितीय योजना काल में करोड़ों में वृद्धि के साथ साथ साधारण जनता की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बहुत से कारण थे, परन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह था कि घाटे की बजट योजना एवं वित्त तथा द्रव्य संचयी नीतियों के कारण देश में मुद्रा प्रसार द्रुत गति से हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण काल से ही

इस और सतर्क दृष्टि रखी गई है कि जहाँ तक सम्भव हो सके कीमतों में विशेष वृद्धि न हो पाये ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में मूल्य-नीति¹

तीसरी योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू, मूल्य-नीति है । इस पर इन दिनों विशेष ध्यान दिया जा रहा है । यह स्पष्ट है कि योजना-पूँजी-विनियोग जिस प्रकार क्रमशः बढ़ाते जाने की बात सोची जा रही है, उसके परिणामस्वरूप साधारणतया मूल्यों के और ऊँचा उठने की सम्भावना है । इसलिए, योजना नीति का प्रयत्न यह होना चाहिए कि मूल्य—खास कर अत्यावश्यक उपभोक्ता पदार्थों के मूल्य—अधिक न बढ़ें, अपेक्षाकृत स्थिर रहें ।

मूल्यों का उतार-चढ़ाव कई बातों पर निर्भर करता है । उनमें से कुछ तो बाजार की तमाम माँग से सम्बद्ध होती हैं और कुछ अलग-अलग वस्तु की माँग और पूर्ति से । इसलिए, मूल्य नीति को भी कई क्षेत्रों में सक्रिय होना पड़ता है—वित्तीय उपाय, द्रव्य-नीति, और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ नियन्त्रण अथवा माल सीधा पहुँचाने की व्यवस्था । विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपायों का समुक्त प्रयोग करके ही मूल्यों को अपेक्षाकृत स्थिर रखते हुए विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है ।

योजना में खाद्यान्न, वस्त्र, चीनी, आदि के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने की बात सोची जा रही है । जहाँ तक सम्भव हो सका है, पूँजी विनियोग व रूप का निश्चय करने समय आवश्यक उपभोग्य पदार्थों की आवश्यकता का भी ध्यान रखा गया । फिर भी, कभी कभी माँग और पूर्ति में असन्तुलन हो जाने की सम्भावना रहती ही है, और इस कारण अनिष्टकारी प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए समय पर ही प्रभावशाली कारवाई कर देना आवश्यक होता है । खाद्यान्न के सम्बन्ध में यह बात विशेषरूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका प्रतिकूल प्रभाव न केवल जनता के अधिक निर्बल वर्गों पर पड़ना है, बल्कि मूल्य और लागत की समस्त व्यवस्था पर भी उसकी प्रतिक्रिया होती है ।

जब नव खाद्यान्न-उत्पादन देश में ही आवश्यक मात्रा में नहीं होने लगता, तब तब की अवधि को पार करने के लिए विदेशों से खाद्यान्न मगाने की आवश्यकता रहेगी ही । हाल में अमेरिका के साथ जो 'पी० एन० ४८०' समझौता हुआ है, उसमें इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ध्यात करने के अतिरिक्त, मरुत काल के लिए भी पर्याप्त मात्रा में गेहूँ प्राप्त करने की व्यवस्था है । इसमें मूल्यों की स्थिर रखने में काफी मदद मिलेगी ।

1. तृतीय पंचवर्षीय योजना (कार्रवाई), भारत सरकार, पृष्ठ १३-१४.

- मरन्तु मूल्य-नीति के कई व्यापक पहलू हैं। विकास में सलग्न किसी अर्थ-व्यवस्था के लिए यह जरूरी होता है कि मूल्य-वृद्धि का सामना करने के लिए वह अपनी आन्तरिक रक्षा व्यवस्था दृढ़ रखे। गेहूँ की कमी तो विदेशों से माल मंगा कर पूरी कर ली जाएगी, चावल की शायद कमी रहे जाए। हो सकता है कि किसी वर्ष, किसी कारणवश, कुछ फसलें मारी जाएं, और यह भी हो सकता है कि कभी मुत्ताफाखोर लोग माल दबा लें। हास के वर्षों में एक नई समस्या सामने आई है—देश के विभिन्न भागों में मूल्यों में भारी अंतर होने की। इन नव परिस्थितियों का ठीक ढंग से सामना करना हो, तो उचित सरकारी कार्यवाही-द्वारा मूल्यों के नियन्त्रण, सरकारी व्यापार और सहकारी समितियों की मार्फत माल की विक्री तथा वितरण करवाने का सहारा लेना अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त, खाद्य-पदार्थों की मूल्य नीति का निश्चय करते समय यह भी देखना पड़ता है कि देश की अर्थव्यवस्था में अन्य पदार्थों के मूल्यों का क्या रज़ है। विभिन्न पदार्थों के मूल्यों में उचित सम्बन्ध भी स्थिर रखना पड़ता है। यह बात भी सावधानीपूर्वक सोचनी पड़ती है कि मूल्य-नियन्त्रण, प्रादेशिक व-दोषस्त, न्यूनतम और अधिक मूल्यों का निर्धारण और सरकारी व्यापार, आदि को मिलाकर ऐसी क्या व्यवस्था की जाए कि अधिकतम उद्देश्य-सिद्धि हो। इन सब समस्याओं पर इन दिनों राष्ट्रीय विकास-परिषद् की एक समिति विचार कर रही है।

योजना में वर बढ़ाने का सुझाव भी रखा गया है। खपत को काबू में रखने के लिए न्यायसंगत कर लगाना योजना का एक आवश्यक अंग है। सरकारी उद्योग-व्यवसायों में भी अधिकतम बचत करनी होगी—जहाँ उचित जान पड़े, वहाँ यह काम मूल्यों में हेर-फेर करके भी करना होगा। मूल्यों में अकस्मान् अथवा बिना किसी क्रम की वृद्धि रोकना निहायत जरूरी होगा। कभी-कभी मूल्य और मूल्य नियन्त्रण की जो विधियाँ अपनाई जाती हैं, उनके कारण कई पेचीदा मयाल लड़े हो जाते हैं। उन्हें हल करते समय परस्पर-विरोधी भावों में सन्तुलन कायम रखना पड़ता है। मूल्यों, आय और लाभों में निश्चय सम्बन्ध होता है। इस कारण, इस बात का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक होता है कि नियन्त्रण के जो भी उपाय किए जाएं, वे प्रभावशाली और परस्पर-संगत हों। जो उपाय अपनाए जाएँ, उनमें हेर फेर करने की गुंजायश रहे, ताकि यदि विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में पारस्परिक सम्बन्ध ठीक रखने की जरूरत पड़े, तो वैसा किया जा सके। परन्तु इसके साथ ही, सरकार की स्थिति ऐसी रहनी चाहिए कि यदि जरूरत पड़े, तो सभी जगहों पर वह प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित कर सके।¹

1. क़ीमतों की वृद्धि रोकने के लिये साख पर नियन्त्रण, अधिक निर्यात, मुद्रा-प्रसार में कमी, योजना के आकार में कमी आदि का सुझाव भी विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया है।

३—आर्थिक उन्नति के सिद्धान्त एवं विकास के 'नमूने'

(Theory of Economic Growth and Growth Models)

पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक उन्नति के सिद्धान्तों के विषय में काफी अध्ययन हुआ है। आधुनिक अर्थशास्त्री अब इस बात को स्पष्ट रूप से मानते सगे हैं कि "उन्नति के सिद्धान्त" केवल एक काल्पनिक तथ्य नहीं है। इसके विपरीत, विभिन्न सिद्धान्तों द्वारा उन्होंने इस बात की प्रतिपादित किया है कि यह सिद्धान्त सत्य एवं व्यवहारिक है। यों तो सभी विद्वानों में काफी मतभेद है, पर वे सभी इस बात को मानते हैं कि "आर्थिक विकास" कोई लक्ष्यहीन तथ्य नहीं है। बहुत सी "बातें" ऐसी हैं जिनके बारे में व्यवहारिक सत्यता के प्रमाण का कोई अभाव नहीं है। जैसे, "पूँजी विनियोग सम्बन्ध," "पूँजी-उत्पादन सम्बन्ध," "आमदनी-व्यय (संघय) सम्बन्ध," "पूँजी-निर्माण एवं आर्थिक विकास सम्बन्ध" आदि। इसी प्रकार, सभी अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि विभिन्न "क्षेत्रों" के "आर्थिक विकास" के लिये अलग अलग "विकास सिद्धान्त" की अपनाने की आवश्यकता होती है। वे इस बात पर भी सहमत हैं कि "आर्थिक विकास" के तथ्य परिवर्तनशील होते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में "आर्थिक उन्नति के सिद्धान्तों" पर निम्नलिखित विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकाश किया है तथा उन्होंने 'आर्थिक विकास' की प्राप्ति के लिये विभिन्न प्रकार के Growth Models को अपनाने की भी सिफारिश की है

- (१) Prof R F Harrod.
- (२) Mrs J Robinson
- (३) Prof R M Solow
- (४) Prof T W Swan.
- (५) Prof J Tobin
- (६) Prof W Fellner
- (७) Mr N Kaldor
- (८) Mr R Eisner.
- (९) Mr D G Champernowne
- (१०) Mr W W Rostow
- (११) Mr. H A John Green
- (१२) Mr. Von Neumann
- (१३) Mr Leontief
- (१४) Prof P. C Mahalanobis

उपरोक्त सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि प्रत्येक देश में साहसों और राज्य की ओर से "आर्थिक उन्नति" के लिये पर्याप्त प्रयास होना चाहिए, क्योंकि देश का आर्थिक विकास तब तक नहीं होता जब तक कि देश के साधारण

नागरिकों का उपभोग का स्तर एवं जीवन-स्तर ऊँचा न हो पाये। वे सभी इसी बात को मान्यता प्रदान करते हैं कि उन सिद्धान्तों को ही केवल अपनाना चाहिए जो स्पष्ट, सत्य, उपयुक्त एवं व्यवहारिक हों।

कुछ बातों पर मतएवम होने पर भी, Growth Models के विचार में उनके मतों में बहुत भिन्नता है। कुछ विद्वानों ने वचन की मात्रा में वृद्धि करके “आर्थिक विकास” करने के बारे में सुझाव दिये हैं, जबकि इसके विरुद्ध, कुछ अन्य विद्वानों ने अधिक “लैबोरी विनियोग” द्वारा आर्थिक “आर्थिक विकास” प्राप्त करने के विषय में सुझाव दिये। कुछों ने “सन्तुलित विकास” को लक्ष्य माना है तो कुछ ने “कृषि-द्वारा” “विकास” प्राप्त करने के सुझाव पेश किये हैं। महलानबीस ने जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया था तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि “श्रम-पूँजी” (Labour-capital) में सामंजस्य द्वारा “क्षेत्रीय” उन्नति द्वारा “आर्थिक विकास” का लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। कुछ भी हो, इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि विभिन्न देशों में “आर्थिक विकास” किसी न किसी विशेष ढंग से ही होता है। अविकसित देशों की आर्थिक परिस्थिति उन्नत देशों से सम्पूर्ण भिन्न होता है, यही कारण है कि अविकसित देशों के लिये “आर्थिक विकास” के उद्देश्य से भिन्न प्रकार Growth Model को अपनाना पड़ता है।

भारतीय “आर्थिक विकास” के हेतु विशिष्ट ‘प्रणाली’ का अपनाया जाना (Special Theory of Growth for India)—भारतवर्ष मुख्य रूप से एक कृषि-प्रधान देश है। इसी कारण, “आर्थिक विकास” के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कृषि की उन्नति पर अधिक बल प्रदान किया जाये। वास्तविक रूप से, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसी बात की चेष्टा की गई। किन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना ने इस बात को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया कि देश का “आर्थिक विकास” केवल मात्र कृषि पर ही निर्भर नहीं होता। उन्नी अनुभव के आधार पर द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में “सन्तुलित आर्थिक विकास” को प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया है।

भारत में जनसंख्या-अधिव्यय के कारण उत्पत्ति और वितरण व्यवस्था इस प्रकार के होने की आवश्यकता है जिनमें अधिकतम मात्रा में अधिक प्रयुक्त हो सके, एवं देश में अत्यधिक मात्रा में बेरोजगारी विद्यमान न रहे। यह भी एक कारण है जिसके लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं छोटे तथा कुटीर उद्योग के विकास पर प्राथमिकता प्रदान की गई थी। किन्तु देश के नागरिकों का जीवन-स्तर तीव्र गति से तभी ऊँची हो सकती है जब कि देश में बड़ी मात्रा के उद्योग धन्धे एवं व्यवसाय स्थापित हों।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश में औद्योगीकरण का काम यदि शीघ्रता से तथा सन्तुलित रूप से सफल हो सके तो साधारण जनता के जीवन-स्तर में भी तीव्र

गति से उन्नति होना सम्भव होगा एवं "आर्थिक विकास" का लक्ष्य भी प्राप्त हो जायगा। भारत में औद्योगीकरण के पथ पर सबसे बड़ी बाधा यह है कि देश में विनियोग के लिए पूँजी का नितांत अभाव है। साधारण जनता की प्रतिवर्ष प्रति-व्यक्ति आमदनी अत्यन्त कम है। इसके कारण साधारण श्रेणी के मनुष्यों द्वारा कोई भी रकम, किसी भी प्रकार से, "बचत" नहीं हो पाती। "बचत" की कमी के कारण "पूँजी का निर्माण" नहीं हो पाता एवं इसी के परिणामस्वरूप, देश में "उत्पादन" के लिए आवश्यक पूँजी का "विनियोग" नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त, वस्तुओं और सेवाओं की कीमते मुद्रा प्रसार के कारण बढ़े हुए रहने के कारण जितनी आमदनी मध्यम वर्ग में आती है, वे भी कोई "धन" बचा नहीं पाते। यही कारण है कि देश के "आर्थिक विकास" के कार्य में हम अभी बहुत पिछड़े हुए हैं।

देश के कोने-कोने में बैंकिंग प्रणाली अभी तक उपलब्ध नहीं है। यह भी एक कारण है जिसके फलस्वरूप जिनके पास "सामान्य" बचत हो पाती है, वह "उसे" पूँजी का रूप प्रदान नहीं कर पाते हैं। क्रम-वर्द्धित "आर्थिक विकास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि देश की समस्त जनता को "बचत" करने की समस्त सुविधाएँ प्रदान की जाय। भारत में अभी इन "सुविधाओं" की अत्यन्त कमी है। "आर्थिक विकास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह भी आवश्यक है कि देश में एक स्पष्ट निभरशील, दीर्घकालीन एवं सुदृढ़ औद्योगिक नीति हो। इसका अभाव भी साहसी तथा उद्योगपतियों को "विनियोग" के क्षेत्र में हताश बना देता है एवं "आर्थिक विकास" नहीं हो पाता।

भारत में नियोजित रूप से "आर्थिक विकास" को प्राप्त करने के लिये एक ऐस "नियोजन" की आवश्यकता है जिसमें "मनुष्य-विकास" का लक्ष्य रखा गया हो एवं "सर्व-क्षेत्रीय विकास" पर प्राथमिकता प्रदान की गई हो। इसका कारण यह है कि हमारे पास साधन (वित्तीय) की अत्यन्त कमी है। हमें नियोजित रूप से, इसी "सीमित साधन" द्वारा, बहुमुखी एवं तीव्र "आर्थिक विकास" के उद्देश्य की पूर्ति करनी है। यह तभी हो सकेगा जब कि "सर्व क्षेत्र" पर प्राथमिकता के आधार पर "साधनों" का बँटवारा किया जा सके। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं का यदि इस दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाय तो यह पता जायेगा कि हमारे नियोजन अधिकारियों ने इन "नियोजनों" का निर्माण इसी आधार पर किया है।

"पूँजी उत्पादन-प्रनुपात" (Capital-Output Ratio) की ठीक प्रकार से ज्ञात करना या उसका अनुमान लगाना भी भारतीय नियोजकों के लिये एक विशेष समस्या है। उन्नत देशों में तो "पूँजी" के विषय में जानकारी करना बहुत कठिन होता है, और न "उत्पादन" के विषय में जानकारी। बल्कि, अविबधित देशों में, जिसमें भारनियम भी सम्मिलित है, "पूँजी" और "उत्पादन" दोनों के ही विषय में

जानकारी अत्यन्त कठिन है । इस "कठिनता" के बहुत से कारण हैं । इस "कठिनाई" के अस्तित्व से भारत में 'पूँजी-उत्पादन-अनुपात' की जानकारी, या नियोजन के निर्माण में हम और एक स्पष्ट संकेत या लक्ष्य का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन हो जाना है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण में प्रो० महलानोबीस ने एक विशेष "आर्थिक-विकास-नमून" का निर्माण किया था, जिसके आधार पर, इस योजनाकाल में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये चेष्टा की गई । इस "नमून" की विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत उन्होंने "क्षेत्रीय विकास" एवं 'पूँजी-अभय अनुपात' को प्राथमिकता प्रदान की थी । यह "नमूना" 'महलानोबीस नमूने' के नाम से प्रसिद्ध हो गया है । अन्य 'आर्थिक विकास नमूनों' में आधाररूपतया 'पूँजी-उत्पादन-अनुपात' पर बल दिया जाना है, लेकिन, क्योंकि भारतवर्ष में अर्थिक बेरोजगारी है, और महलानोबीस की "योजना" का उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करने का था, इसलिये उन्होंने "पूँजी-अभय-अनुपात" पर बल दिया था । उनका "नमूना" केवल आर्थिक रूप में ही सफल रही ।

द्वितीय योजना के विधेयकों ने कहा था, 'अन्त में, हम दीर्घकालीन योजना के विषय में एक विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं । हमारा क्याल है कि आगामी वर्षों में हम पर अधिकाधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी । यह विचार एशिया और अफ्रिका के विस्तृत और अविकसित भू-भाग के विकास की समस्याओं के विषय में है । यह भू-भाग अनेक राजनीतिक और सामाजिक कारणों से अभी तक प्रायः अविकसित रहा है । यहाँ की कुछ देशों की अर्थव्यवस्था या तो क्षेप समार से अलग अलग रही है या योम्प के उन देशों के साथ जुड़ गई है जिसके साथ उनका राजनीतिक सम्बन्ध हो गया था । ... ज्यों-ज्यों इस भू-भाग में योजनापूर्वक विकास होना चना जायगा, त्यों-त्यों उत्पादन की कुछ विशेष दिशाओं में विशेषता प्राप्त कर लेने, परस्पर लाभदायक व्यापार करने और जानकारी तथा अनुभव का आदान-प्रदान करने के अवसर अधिकाधिक मिलने चने जाएँगे । इन देशों में योजना की प्रगति विभिन्न स्थितियों में है और स्वभावतः इनमें स प्रत्येक देश की मुख्य दृष्टि यह रहेगी कि वह अपने माधनों का अधिकतम विकास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये करे और ऐसी दिशा में करे जो कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उसके लिये अधिकतम लाभदायक हो । फिर भी यह आवश्यक है कि इनके विकास के कार्यक्रम इस प्रकार बनाये जायें कि उनमें तैयार पदार्थों और तकनीक की जानकारी और अनुभव के परस्पर लाभदायक आदान-प्रदान की गुंजाइश रहे । ... भारत की अपनी योजना का निर्माण इस बड़े भू-भाग की प्रादेशिक दृष्टि से करना चाहिए... " १

भारतवर्ष के लिये एक प्रणाली यह भी बताई गई है कि सबसे पहले देश के समस्त प्राचीण क्षेत्रों को उन्नत बनाये जायें, फिर क्षेत्र के आधार पर उन्नति प्राप्त की जाए एवं अन्त में, इस बात की चेष्टा की जाये कि समस्त देश का आर्थिक विकास हो।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि “आर्थिक विकास” की प्राप्ति के उद्देश्य से विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के नियोजन-यत्नियाँ अपनाई जाती हैं। उनके स्वरूप, प्रकृति, प्राथमिकता आदि में अन्तर हो सकता है, परन्तु उनका उद्देश्य सामान्यतः एक ही रहता है—आर्थिक उन्नति। किसी “नमूने” के द्वारा इस “उद्देश्य” की प्राप्ति में शीघ्रता होती है, और “किसी” में देरी। अर्थव्यवस्था के विकास का ‘नमूना’ प्रलग होता है। “आर्थिक विकास” के अध्ययन में अब अर्थशास्त्र के साथ-साथ गणित, सांख्यिकशास्त्र और इकोनोमेट्रिक्स की भी सहायता ली जा रही है।

Growth Models

Growth Models के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग-प्रलग मत हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित प्रकार के हैं

(अ) Prof. Harrod's Views.*

“Let G stand for the geometric rate of growth of income or output in the system, the increment being expressed as a fraction of its existing level. G will vary directly with the time interval chosen

“Let G_w stand for the warranted rate of growth

“If x_0 is output in period 0 and x_1 output in period 1,

$$G = \frac{x_1 - x_0}{x_0} \text{ Since we suppose the period to be short.}$$

x_0 or x_1 may alternatively stand in the denominator

“ x_0 and x_1 are compounded of all individual outputs. Even in the most ideal circumstances conceivable, G would diverge from time to time from G_w .

“Let S stand for the fraction of income which individuals and corporate bodies choose to save. S is total saving divided by x_0 or x_1 . This may be expected to vary with the size of income, the phase of the trade cycle, institutional changes, etc

“Let C stand for the value of the capital goods required for the production of a unit increment of output. The value of C is

* R. H. Harrod—‘An Essay in Dynamic Theory’, Economic Journal, volume XLIX, March 1939, pp. 16-17.

inversely proportional to the period chosen. The value of C depends on the state of technology and the nature of the goods constituting the increment of output. Now, the fundamental equation, in its simplest form is

$$Gw = \frac{S}{C} \quad (I)$$

‘ (Since the value of Gw varies directly and that of C inversely, and the value of S is independent of the unit, the validity of the equation is independent of the unit period chosen)

‘The proof is as follows. Let C_p stand for the value of the increment of capital stock in the period divided by the increment of total output. C_p is the value of the increment of capital per unit increment of output actually produced. Circulating and fixed capital are lumped together,

$$G = \frac{S}{C_p} \quad I(a)$$

is a truism, depending on the proposition that actual saving in a period is equal to the addition of the capital stock. Total saving is equal to Sx_0 . The addition to the capital stock is equal to $C_p(x_1 - x_0)$. This follows from the definition of C_p . And so,

$$Sx_0 = C_p(x_1 - x_0)$$

$$\frac{S}{C_p} = \frac{x_1 - x_0}{x_0} = G$$

If $C = C_p$, then $G = Gw$, and from $I(a)$ we get,

$$Gw = \frac{S}{C} \quad \dots \dots$$

(a) Prof E D Domar's views :¹

“Let investment proceed at an annual rate of I

Let annual productive capacity (net value added) of newly created capital be equal on the average to S

‘ Let σ represent the potential social average productivity of investment

“Let investment increase at an absolute annual rate of ΔI , and let the corresponding absolute annual increase in income be indicated by ΔY

1 E D Domar—*Expansion and Employment*, ‘The American Economic Review’, Volume xxxvii, March 1947, pp 39-41

We have then

$$\Delta Y = \Delta I \frac{I}{a}, \quad \dots \dots (1)$$

where $\frac{I}{a}$ is the multiplier

Let us now assume that the economy is in a position of a full employment equilibrium, so that its national income equals its productive capacity. To retain this position, income and capacity should increase at the same rate. The annual increase in potential capacity equals σ . The annual increase in actual income is expressed by $\Delta I \left(\frac{I}{a} \right)$. Our objective is to make them equal. This gives us the fundamental equation

$$\Delta I \frac{I}{a} = \sigma \quad \dots \dots (2)$$

'To solve this equation, we multiply both sides by a and divide by I , obtaining

$$\frac{\Delta I}{I} = \sigma \quad \dots \dots (3)$$

'The left side of expression (3) = the absolute annual increase of the absolute rate of growth in investment— ΔI —divided by the volume of investment itself or the annual percentage rate of growth of investment. Thus, the maintenance of full employment requires that investment grow at the annual percentage rate of σ .

(न) Prof. Sweezy's Theory (as Analysed by Prof E D Domar¹)

'Examination of Sweezy's Chapter X (*The Theory of Capitalist Development*) which, according to him is based on Otto Bauer's book 'Zwischen Zwei Weltkriegen' published in 1936, pp 186 187 of Sweezy's book reads as

'If I is the net national income in value terms, w the total wage bill (= workers' consumption), l the part of surplus consumed by capitalists and k the part of surplus value added to constant capital (= investment), then we have the following equation :

$$I = w + l + k \quad (1)$$

1 Problem of Capital Accumulation—E D Domar, 'The American Economic Review' Vol xxxviii, No 5, Dec 1948, part IV of the Essay, pp 787—794 (Abstracts only are reproduced here)

"All of these concepts, of course, represent rates of flow per unit of time. If K is the total stock of means of production, then $K = \frac{dk}{dt}$. We assume that the national income steadily rises and that each of its three component parts also rises. Thus if we regard w and I as functions of k , it will always be true that as k increases, w and I will also increase. But since it is a fundamental feature of capitalism that an increasing proportion of surplus value tends to be accumulated and an increasing proportion of accumulation tends to be invested both, w and I must grow less rapidly than k . Hence we have :

$$w = f(k) \text{ such that } 0 < f(k) < 1 \text{ and } f'(k) < 0 \quad (2)$$

And similarly,

$$I = \phi(k) \text{ such that } 0 < \phi'(k) < 1 \text{ and } \phi(k) < 0 \quad (3)$$

Domar's Observations on this

'But expressions (2) and (3) do not necessarily follow from the 'fundamental feature of capitalism. If surplus value is a non-diminishing part of national income (Sweezy's view) and an increasing fraction of surplus value is accumulated, and finally if an increasing proportion of accumulation is invested then what does follow is that the ratio of investment to accumulation to surplus value to consumption and to national income rises.

In other words what is given by the fundamental feature of capitalism is that

$$\frac{d\left(\frac{k}{I}\right)}{dt} > 0 \quad (4)$$

or that
$$\frac{d\left(\frac{k}{m}\right)}{dt} > 0 \quad (5)$$

where $m = w + I$ = total consumption (we can also say that $\frac{dk}{dt} \cdot \frac{I}{k} > \frac{dI}{dt} \cdot \frac{I}{I}$, i.e. that k will grow at a greater relative rate than I . The same holds true for w). But it does not at all follow that $f(k) < 1$ (or that $\phi(k) < 1$). As a matter of fact from what we know about the magnitude of k and w there is a very good presumption in favour of $f(k) > 1$. There is a confusion here between absolute and relative rates of growth. Fortunately, the assumption that $f'(k) < 1$ is not needed for his proof. But the

other one, $f'(k) < 0$ is needed, yet it cannot be said that it necessarily follows from (4) in the general case

'Let us try to re work the problem Our first assumption will be that the ratio investment to income remains constant or increases i e, that

$$\frac{d\left(\frac{k}{I}\right)}{dt} > 0 \quad (6)$$

'The second one is S (average applicable to the new investment as a whole) which or rather the inverse of which Sweezy also used ■ the required ratio between capital and income If

$$I = Ks \quad (7)$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{dk}{dt} S = ks \quad (8)$$

"The expression (7) is the equilibrium condition from the point of view of this problem Differentiating we get

$$I \frac{dk}{dt} > k \frac{dI}{dt} \quad (9)$$

from (8) we obtain

$$\frac{d^2I}{dt^2} = \frac{dk}{dt} S \quad (10)$$

and the substitution of (8) and (10) into (9) gives us

$$I \frac{d^2I}{dt^2} > \left(\frac{dI}{dt}\right)^2 \quad (11)$$

"We shall now prove that the expression (11) is equivalent to the statement that the relative rate of growth will be constant or will increase For

$$\frac{d\left(\frac{\frac{dI}{dt}}{I}\right)}{dt} > 0 \quad (12)$$

immediately gives

$$\frac{I \frac{d^2I}{dt^2} - \left(\frac{dI}{dt}\right)^2}{I^2} > 0 \quad (13)$$

which is identical to (11)

"We can conclude that

(i) If the ratio of investment to income is constant, the

preservation of equilibrium requires that income grow at a constant relative rate

- (11) If the ratio is, as Sweezy assumes, increasing, national income should grow at an increasing relative rate "

(८) Prof Mahalanbis' Model.

Prof Mahalanbis constructed two models, "a bi sector model, and a four sector model which is an elaboration of the basic bi sector model. It is the four sector model which represents the theoretical construction of the Second Five Year Plan. The major targets of the models are a postulated rate of growth of income over a certain definite period of time, say Δy over a period of five years, with a proposed rate of increase in employment over the same period, say Δx . The economy is divided into four sectors: Investment goods industries, Factory organised consumers' goods industries, Small scale, household industries producing consumer's goods, and Service industries.

"The capital output and labour output ratios, giving parameters of capital and labour requirements per unit of increase in national income in each of the sectors of the closed system, are assumed. Then the problem is, how to distribute a given amount of available investment funds among these sectors so as to achieve both the targets. In distributing investment funds, the investment goods industries sector is given a special priority, by allocating to it one third of the total funds for new investment. This allocation is arrived at, from considerations of long seen economic growth (economic growth over twenty or twenty five years). Then the planning problem is reduced to one of distributing the remaining investment funds among the three sectors in such a way as to yield definite increases in income and employment on the basis of the assumed capital output and labour output ratios in different sectors."

1. G. C. Surve—"Monopoly, Competition and Welfare", Bombay, 1960, Ch III, pp 62-63

Please also read—(a) "The Review of Economics and Statistics", Feb, 1959

(b) "A Note on Professor Mahalanbis' Model of Indian Economic Planning"—R. Komiyé

(c) "Contributions to Economic Analysis—The Logic of Investment Planning"—S. Chakravarty.

इनके अनिश्चित भी, और बहुत स विद्वानों ने (जिनके नाम पहले दे दिये गये हैं) अन्य प्रकार के Growth Models की चर्चा की है। सभी के विषय में विशद वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है, इसलिये केवल २/३ के बारे में ही वर्णन की गई है।¹

४—नियोजन की प्रबन्ध सम्बन्धी आवश्यकतायें (Organisational Requirements for Planning)

नियोजन के कार्य को सफल बनाने एवं सन्तुलित रूप से उसका संचालन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य कुशलता से चलना चाहिए। यों तो सभी क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक प्रशासन का कार्य होना चाहिए, परन्तु निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वित्त के क्षेत्र में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में, श्रमिक सम्बन्धी विषयों पर, कृषि सम्बन्धी क्षेत्र में, उद्योग तथा खनिज पदार्थों के विषय में, मात्स्यिकी के विषय में, साधारण प्रशासन एवं प्रचार के विषय में।

1. Selected References :

- (1) R. F. Harrod—"An Essay in Dynamic Theory," Economic Journal, March 1939.
- (2) A. A. Young—"Increasing Returns & Economic Progress", Economic Journal, Dec 1928.
- (3) T. W. Swan—"Economic Growth and Capital Accumulation," Economic Record, Nov. 1956.
- (4) R. M. Solow—"A Contribution to the Theory of Economic Growth," Quarterly Journal of Economics, Feb 1956
- (5) N. Kaldor—"A Model of Economic Growth," Economic Journal, Dec 1957.
- (6) R. F. Harrod—"Towards A Dynamic Economics"
- (7) Joan Robinson—"Economic Growth & Capital Accumulation—A Comment," Economic Record, April, 1957
- (8) Robert Eisner—"On Growth Model and the Neo classical Resurgence", Economic Journal, Dec 1958
- (9) James Tobin—"A Dynamic Aggregative Model", Journal of Political Economy, April, 1955
- (10) W. Fellner—"Trends and Cycles of Economic Activity".
- (11) W. W. Rostow—"The Process of Economic Growth".
- (12) H. A. John Green—"Growth Models, Capital and Stability", Economic Journal, March 1960
- (13) R. Komiyé—"A Note on Professor Mahalanobis' Model of Indian Economic Planning".

वित्त सम्बन्धी प्रशासन कार्य (Financial Organisation) :

नियोजन को सफल रूप देने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक होता है कि वित्त एवं द्रव्य सम्बन्धी प्रशासन का कार्य कुशलतापूर्वक चलता रहे। उनकी अनुपस्थिति में नियोजन की सफलता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। योजना आयोग ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण में इस ओर विशेष ध्यान दिया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार :¹

साधनों की समस्या पर—विशेष रूप से उनके भुगतान-मन्तुलन के पहलू पर—पंचवर्षीय योजना की समस्त आवश्यकताओं की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि योजना के व्यय के वर्ष प्रति-वर्ष के विवरण की दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए। इस दूसरे तत्व पर विचार करते समय कई कसौटियाँ सामने रखनी होगी : जो परियोजनाएँ हाथ में हैं, उन्हें यथाशीघ्र पूरा कर डानने की आवश्यकता, नई परियोजनाओं को यथासमय आरम्भ कर देने की आवश्यकता, ताकि उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पूरा होने का निश्चय हो जाय, विदेशी मुद्रा की उपलब्धि, आदि। योजना के व्यय को विभिन्न स्पष्ट सोपानों में विभाजित करने से पहले, नियोजकों को बहुत-सारे काम करने होंगे। फिर भी, इतना स्पष्ट है कि योजना में सोचे गये कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये, विदेशी सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त, स्वदेशी साधनों के सग्रह का प्रयत्न भी जारी रखना होगा।

बड़े पैमाने पर विकास की किसी भी योजना के लिए ये विचार बुनियादी महत्त्व रखते हैं। देश के आन्तरिक साधनों की उपलब्धि-विषयक सम्भावनाओं के प्रसंग में यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि कई दृष्टियों से इस समय की परिस्थिति गत योजनाओं की अपेक्षा अधिक अनुकूल है। गत दस वर्षों में पूँजी-विनियोग का स्तर काफी ऊँचा उठा है। इसके फलस्वरूप न केवल उत्पादन का स्तर ऊँचा उठा है, बल्कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन-क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सिंचाई, बिजली और परिवहन के क्षेत्र में भी काफी ठोस प्रगति की गई है। दूसरी योजना के समय आरम्भ की गई नई औद्योगिक परियोजनाओं का पूरा लाभ तीसरी योजना की अवधि में मिलने लगेगा। दूसरी योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र की अधिकांश परियोजनाएँ निर्माणावस्था से गुजर रही थीं। तीसरी योजना की अवधि में वे सब कार्यशील हो जायेंगी और आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगेंगी। इन सब अतिरिक्त उत्पादनों को इकट्ठा करके नए पूँजी-विनियोग में प्रयुक्त किया जा सकता है, और किया जाना चाहिए। शिक्षण और प्रशिक्षण की जो सुविधाएँ पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं, और जो तीसरी योजना में और भी बढ़ा दी जाएँगी, उन सब का लाभ आगामी वर्षों में अधिकाधिक परिणाम में दृष्टिगोचर होने लगेगा। यह

1. तृतीय पंचवर्षीय योजना (स्मरेखा), भारत सरकार, पृष्ठ ४६-४७

भी ध्यान देने की बात है कि देश में साहसपूर्वक नये काम आरम्भ करने की प्रवृत्ति, प्रबन्ध के अनुभव और कार्य-कुशलता की मात्रा बढ़ रही है ।

किसी योजना के लिए साधन तलाश करने की समस्या का अभिप्राय, किसी जमे-जमाए अथवा स्थायी कोश से कुछ निकाल लेना नहीं सम्भूत चाहिए । एक हद तक, साधनों में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ होती है । गत वर्षों में परेशानियों और कठिनाइयों के बावजूद जो प्रगति की गई, उससे प्राणामी वर्षों में अधिक परिश्रम करने का आधार तैयार हुआ है । निस्सन्देह, किए हुए पूँजी-विनियोग का, विशेषकर बुनियादी ढाँच के विनियोग का, फल उत्पादन के रूप में प्रकट होने में कुछ समय लगता ही है । परन्तु निर्धनता, अल्प अथवा अल्प विनियोग के कुचक्र से निकलने के लिए यह जरूरी है, कि सभी मध्य साधनों का अधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जाए और उनसे उत्पादन के रूप में जो कुछ प्राप्त हो उसे पुनः पूँजी-विनियोग में मिला दिया जाए । देश का एक महत्वपूर्ण एव ठोस साधन अभ्युक्त जन-शक्ति है । उसका उत्पादन में अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी प्रशासन कार्य (Organisation regarding International Trade) :

अन्तर्राष्ट्रिक और विदेशी दोनों ही प्रकार के व्यापार को ठीक प्रकार से चलाने के लिये सरकार की ओर से अच्छा प्रबन्ध, अच्छी नीति एवं कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है । इनके अभाव में यह कार्य कुशलतापूर्वक सम्भव नहीं होता है । प्रत्येक नियोजनाधिकारी को नियोजन के निर्माण के समय इस ओर सचेष्ट रहना पड़ता है कि नियोजन कार्य को सफल बनाने के लिये इस बात का स्पष्ट संकेत नियोजन में हो कि व्यापार नीति किस प्रकार की होगी एवं प्रशासन की कुशलता के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जायेगा । तृतीय पंचवर्षीय योजना (रूप रेखा) में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है (पृष्ठ ८१-८२) ।

किसी भी देश के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अपने विकास की आरम्भिक दशा में पहले स्वदेश में उस सामान का उत्पादन करे, जिसे वह विदेशों से मँगा रहा है । भारत का औद्योगिक विकास भी अब तक उसके अन्तर्राष्ट्रिक बाजार की दृष्टि से किया जाता रहा है । परन्तु गत कुछ वर्षों के अनुभव से पता चला है कि निर्यात बढ़ाने के लिए भी योजना बनाना उतना ही आवश्यक है । इसके लिए निर्यात की सामर्थ्य बढ़ाने, वर्तमान बाजारों का विकास करने और नए बाजार खोजने की आवश्यकता है । कोई भी विकासरत देश, सत्कार का व्यापार बढ़ाने से, एक हद तक लाभान्वित होने की आशा कर सकता है । परन्तु यह सामान्य बढावा काफी नहीं माना जा सकता । यद्यपि आजकल उद्योग-व्यवसाय में अधिक समुपेत देश पहले से उदार व्यापार-नीतियाँ

अपनाते जा रहे हैं, फिर भी नए विकासोन्मुख देशों के कारण, निर्यात का व्यापार बढ़ाने में बहुत-सी बाधाएँ हैं। जब विभिन्न देश अपने अब तक अप्रयुक्त साधनों का विकास और उपयोग करने लगेंगे, तब व्यापार के प्रादेशिक रूप में परिवर्तन हुए बिना नहीं रह सकेगा। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के गठन और प्रादेशिक रूप में अनेक परिवर्तन हो गए हैं। कई नए व्यापारिक गुट बन गए हैं और बनते जा रहे हैं। इस परिस्थिति में विकासोन्मुख देशों की यह इच्छा होना स्वाभाविक है कि ये गुटबन्धियाँ व्यापार में बाधक न हों। भारत को आगामी वर्षों में अपना निर्यात-व्यापार न केवल राष्ट्रमण्डल के देशों में, बल्कि पूर्व और पश्चिम के अन्य देशों में भी बढ़ाना होगा। हाल के वर्षों में, जिन देशों ने सरकारी व्यापार की प्रणाली अपनाई है, उनके साथ भारत के व्यापार-सम्बन्ध पारस्परिक लाभ के आधार पर काफी मजबूत हुए हैं और आशा है कि उनके साथ जो समझौते हो गए हैं, वे व्यापार का और भी विस्तार करने में सहायक होंगे। अपनी भावी व्यापार-नीतियों का निर्धारण करते समय हमें एशिया और अफ्रीका के पड़ोसी देशों के अतिरिक्त दक्षिण (लैटिन) अमेरिका के देशों के साथ भी अपने व्यापार-सम्बन्ध घनिष्ठ होने की सम्भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए।

देश का वैदेशिक हिसाब अधिक अच्छी तरह समुलित करने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता है, वह अपना निर्यात-व्यापार बढ़ाने के लिए निरन्तर और योजनाबद्ध प्रयत्न करने की है। यह प्रश्न केवल व्यापार-नीति का नहीं है—इसका सम्बन्ध पूँजी-विनियोग, मूल्यों और वित्तीय नीतियों से भी है। तात्कालिक दृष्टि से यह समस्या, आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई उठा कर भी अधिक निर्यात के लिए माल बचा लेने की है। दीर्घ-दृष्टि से हमारा वास्तविक कार्य यह है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था का आधार दृढ़ कर लें, बुनियादी यन्त्रों और अन्य यन्त्रों के उत्पादक अपने उद्योग-व्यवसायों का इतना विकास कर लें कि उनमें जाने वाली पूँजी का औषित्य स्वदेश के ही उत्पादन से प्रमाणित हो जाए, निर्यात के लिए उत्पादन करने लगे और नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त संगठन बना लें। इस कारण, हमें कृषि और उद्योग, दोनों के विकास-कार्यक्रमों को ऐसा बनाना होगा कि उनसे आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त, निर्यात की आवश्यकताएँ भी पूरी होती चली जाएँ—वे भी कुछ कम जरूरी नहीं हैं।

श्रम सम्बन्धी नीति एवं प्रशासन-व्यवस्था (Policy & Organisational Arrangements for Labour)

श्रमिकों के विषय में एक विशेष नीति को अपनाने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत में, जहाँ अधिकतर क्षेत्रों में श्रम-प्रमुख उत्पत्ति प्रणाली अपनाई जाती है, यह भी आवश्यक हो जाता है कि श्रमिक के विषय में एक विशेष नीति अपनाई जाये और उसको कुशलतापूर्वक चलाने के लिये प्रशासन की विशेष

व्यवस्था की जाये। श्रम के बारे में प्रशासन का कार्य अत्यन्त कुशल होना बहुत आवश्यक होता है। इस कार्य में यदि कोई त्रुटि रह जाये, तो नियोजन कार्य की सफलता में बहुत कठिनाइयाँ उपस्थित होगी। यही कारण है कि नियोजन के निर्माण में श्रम-नीति एवं श्रम सम्बन्धी प्रशासन की विशेष व्यवस्था की जाती है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् और पहली पंचवर्षीय योजना के समय श्रम-नीति में जो प्रवृत्तियाँ आरम्भ की गई थी, उन्हें दूसरी योजना के समय दृढ़ तथा विकसित किया गया। इस काल में श्रम-नीति का विकास करने और उसके मूल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी विशेष कार्य किया गया।

उद्योगों में शान्तिपूर्ण परिस्थितियाँ पैदा करने के प्रयोजन से, सरकार ने दस वर्षों से, औद्योगिक झगड़ों को प्रेमपूर्वक निबटाने के लिए सुविधाएँ देने की जिम्मेदारी अपने सिर ले रखी है। औद्योगिक शान्ति की रक्षा के प्रयोजन से ही सरकार ने इन झगड़ों में दखल देने के अधिकार भी ले रखे हैं। इसलिए यह भावना बढ़ती जा रही है कि झगड़ों में एक हद तक तो सरकारी दखल के बिना काम नहीं चल सकता, परन्तु आज के हालात में वास्तविक प्रगति का मार्ग यह है कि दोनों पक्ष मिल कर, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार, परस्पर-सहयोग की व्यवस्था कर लें। हालाँकि आज लोग नहीं समझ रहे हैं, परन्तु जब वे यह समझने लगेंगे कि शक्य केवल शांति की स्थापना नहीं, अपितु औद्योगिक कुशलता के ऊँचे स्तर तक पहुँचना और धमिक-बर्गों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाना भी है, तब औद्योगिक झगड़ों को सुलझाने के लिए इस मार्ग पर चलने का महत्त्व अधिक अच्छी तरह समझा जाने लगेगा।

हाल में विशेष महत्त्व की जो कुछ बातें हुई हैं, उनकी यहाँ संक्षेप में चर्चा कर देना उचित होगा। उनसे पता लगेगा कि तीसरी योजना में श्रम-नीति का लक्ष्य क्या होना चाहिये और आगे किस दिशा में बढ़ना चाहिये। मालिकों और मजदूरों के सभी केन्द्रीय संगठनों ने औद्योगिक अनुशासन की एक सहिता स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर ली है और उस पर सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्र के उद्योगों में १९५८ के मध्य से प्रमल हो रहा है। इस सहिता में मालिकों और मजदूरों, दोनों पर कुछ खास जिम्मेदारियाँ डाल दी गई हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि दोनों के प्रतिनिधियों में सब स्तरों पर रचनात्मक सहयोग होता रहे—न तो काम रुके और न मुकदमेबाजी हो; झगड़ों और शिकायतों का निबटारा आपसी बातचीत, सुलह-समझौते तथा स्वेच्छया नियुक्त पक्षों के द्वारा हो; मजदूर-संगठनों का विकास स्वतन्त्रतापूर्वक होने की सुविधाएँ मिलें, मजदूरों में जापरवाही से काम करने अथवा कर्तव्य की उपेक्षा करने की भावना कम हो जाए और मालिक-मजदूरों के सम्बन्धों में सब प्रकार की जोर-जबर्दस्तियों और दबावों का अन्त हो जाए। स्पष्ट है कि यह विचार नया है, इसके उद्देश्य अति दूरव्यापी हैं और इसके प्रमल का क्षेत्र कठिन है, इसलिए व्यवहार में इसकी जड़ अच्छी तरह जमाने के लिए बहुत समय तक बड़ी ईमानदारी से काम

करना पड़ेगा । अब तक इसके जो परिणाम निकले हैं, वे उत्साहवर्द्धक हैं—काम रुकने के कारण नष्ट होने वाले थमिक-दिनो की संख्या में कमी होने की दृष्टि से भी और औद्योगिक सम्बन्धों के वातावरण में सामान्य सुधार होने की दृष्टि से भी । सभी जानते हैं कि मजदूरों की यूनियनों में आपसी विरोध के दुष्परिणाम मालिकों और मजदूरों, दोनों के लिए कितने शोचनीय होते हैं । दो वर्ष हुए कि मजदूर-संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक व्यवहार-सहिता बना कर उसे स्वीकार कर लिया था । उससे उक्त दुष्परिणाम कुछ कम हो गए हैं । पर दोनों पक्षों की एक सामान्य शिकायत यह रही है कि पंच-निर्णयों और समझौतों का पालन नहीं किया जाता । यदि यह शिकायत आगे भी जारी रही, तो ये दोनों सहिताएँ सवथा निरर्थक और निष्प्रयोजन हो जाएँगी । इसलिए, केन्द्र और राज्यों में एक संगठन बना दिया गया है कि इन सहिताओं और कानूनों अथवा समझौतों के कारण दोनों पक्षों पर जो जिम्मेदारियाँ आती हों, वह उनसे उनका पालन करवाएँ और देखें कि उनसे कितना लाभ हुआ और कितना नहीं ।¹

सांख्यिकीय प्रशासन एवं नीति (Statistical policy and arrangements of Organisation) :

प्रथम योजना विशेष रूप से इसलिये असफल रही थी कि उस समय तक देश में सांख्यिकीय आँकड़े एकत्रित करने के साधन उपलब्ध नहीं थे । किन्तु, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि सांख्यिकीय संस्थाएँ अधिक हों एवं उनके प्रबन्ध एवं प्रशासन के विषय में भी एक निर्धारित नीति हो । नियोजन-निर्माण में आँकड़े एवं सांख्यिकीय साधनों की बहुत आवश्यकता होती है । इनके अभाव में यह कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पाता ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्माताओं ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि तृतीय योजना काल में देश में और बहुत सी सांख्यिकीय संस्थाएँ खोली जाएँगी एवं उनके प्रबन्ध तथा प्रशासन सम्बन्धी प्रशासितियों में भी उन्नति होगी (पृष्ठ १३२-१३३) ।

मसूरी में राष्ट्रीय प्रमाणन अकादमी और प्रशिक्षण निर्देशालय खोले गए हैं । इनमें प्रथम श्रेणी के अखिल भारतीय केन्द्रीय सेवाओं के सदस्यों के लिए एक सम्मिलित प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम की व्यवस्था है । दूसरी योजना में जो और कदम उठाए गए, वे हैं—हैदराबाद में 'प्रशासनिक कर्मचारी-कालेज' की स्थापना तथा 'औद्योगिक प्रबन्ध-मनुस्त्र' का आयोजन । आशा है कि राज्य सरकारें इस बात की शीघ्र ही समीक्षा करेंगी कि तीसरी योजना की अवधि में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सभी स्तरों पर उन्हें कितने और कैसे प्रशासनिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी । दूसरी योजना के अन्तर्गत सात संस्थाओं में व्यवसाय

1 तृतीय पंचवर्षीय योजना (रूपरेखा), भारत सरकार, योजना आयोग, पृष्ठ ८६-८७ ।

प्रशासन और प्रबन्ध के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें से २ सस्थाएं औद्योगिक और उत्पादन-इन्जीनियरी की भी शिक्षा देती हैं। तीसरी योजना में इस क्षेत्र में सुविधाएँ बढ़ाने का विचार है। एक अखिल भारतीय प्रबन्ध सस्थान खोलने के सुभाव पर भी विचार किया जा रहा है।

इन कुछ वर्षों में अक-सकलन-विशेषज्ञों को प्रशिक्षण की अधिक सुविधाएँ देने के बारे में कई कदम उठाए गए हैं। केन्द्रीय अक-सकलन-संघ, भारतीय कृषि-अनुसंधान-परिषद् तथा अखिल भारतीय म्बन्धना एव सार्वजनिक स्वास्थ्य-सस्थान ने सौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण देने के लिए कई प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है। राज्यों के अक-सकलन-कार्यालयों ने जिला अक-सकलन-अधिकारियों, सामुदायिक विकास-खण्डों के प्रगति सहायकों और अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। आशा है कि भारतीय अक-सकलन-सस्थान, जिसे विधिवत् राष्ट्रीय महत्त्व की सस्था घोषित किया गया है, शीघ्र ही अक-सकलन में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों के पाठ्यक्रम का प्रबन्ध करेगा। इस सस्थान में दो साल के व्यावसायिक अक-सकलन-पाठ्यक्रम का प्रबन्ध है। वह कुछ और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था करता है—जैसे, कलकत्ता के अन्तराष्ट्रीय अक-सकलन शिक्षा-केन्द्र के पाठ्यक्रम और अक-सकलन के स्तर नियमन के पाठ्यक्रम। बम्बई के सामाजिक अक-सकलन (डमोक्राफी) प्रशिक्षण एव अनुसन्धान-केन्द्र में राष्ट्रीय सामाजिक अक-सकलन-विद्या का प्रशिक्षण दिया जाता है। कलकत्ता का औद्योगिक अक-सकलन-प्रतिष्ठान औद्योगिक अक-सकलन के क्षेत्र में प्रशिक्षण का प्रबन्ध करता है। सुयोजित विकास की अक-सकलन-सम्बन्धी आवश्यकताएँ तेजी से बढ़ रही हैं। अतः आवश्यक कार्यकर्ता तैयार करने के लिए मौजूदा सुविधाओं को यथासम्भव बढ़ाने का विचार है।

साधारण 'प्रबन्ध' एव प्रशासन की कुशलता (Efficiency for General Administration)

नियोजन के कार्य को सरल तथा सफल बनाने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि नियोजन से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में प्रबन्ध की कुशलता हो एव प्रशासन का स्तर ऊँचा हो। प्रथम, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रशासन की कुशलता पर बल दिया गया। किन्तु, कुछ कारणों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रशासन व्यवस्था अत्यन्त ढीली पड़ गई, जिससे नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति ठीक उस रूप में सम्भव न हो सकी, जिस रूप में आशा की गई थी। इसी कारण से हमारे विधेयकों ने तृतीय नियोजन के निर्माण में प्रशासन सम्बन्धी विषयों पर विशेष ध्यान दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में साधारण प्रशासन की व्यवस्था निम्न रूप में की गई है।¹

1. तृतीय पंचवर्षीय योजना (रूपरेखा), भारत सरकार, योजना आयोग, पृष्ठ ६१-६२

आजकल हमारी प्रशासन-प्रणाली जिस प्रकार चल रही है, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं, जिनके कारण काम की गति मन्द पड़ जाती है। इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रथम तो, इस बात पर जोर रहना चाहिए कि किमी भी काम का परिणाम, निर्धारित नीति और कार्यक्रम के अनुसार, नियत समय में निकाल देने की जिम्मेदारी, सम्बद्ध व्यक्तियों पर डाल दी जाए। प्रशासन की कुछ परम्पराएँ ऐसी हैं, जो यह जिम्मेदारी किसी पर नहीं पड़ने देती। उदाहरणार्थ, सरकार के दफ्तरी महकमों में मूल कार्य की ज्यादा-से ज्यादा जिम्मेदारी अपने सिर ओढ़ लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके विपरीत, उनके काम का मुख्य सम्बन्ध नीति, निगरानी और कार्य-क्षमता का स्तर कायम रखने में होना चाहिए। कुछेक सन्दिग्ध मामलों को छोड़कर आज्ञाओं पर अमल कराने के सब काम उनके लिये नियत महकमों और अधिकारियों पर छोड़ देने चाहिये। यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार के आज्ञा-पालक महकमों, निगमों और सरकारी कम्पनियों को अधिक समर्थ बना कर उन्हें सब काम अपनी जिम्मेदारी से और प्रभावशाली ढंग से करने दिए जायें। दूसरी बात यह, कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को कानून, नियम अथवा सरकारी आज्ञा द्वारा जितना अधिकार दिया जाए, उस हद तक उसके निर्णयों में हस्तक्षेप न किया जाए। यदि कोई अधिकारी अपना कार्य ठीक ढंग से न करे, तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सकती है। जिन मामलों में प्रशासन की आवश्यकता के कारण सरकार या ऊँचे अधिकारी-द्वारा हस्तक्षेप करना आवश्यक जान पड़े, उनमें जिस कानून, नियम या आज्ञा से अधिकार दिया गया था, उसमें सशोधन किया जा सकता है। तीसरी बात यह, कि कोई कार्रवाई करने से पहले अन्त विभागीय सम्मेलनों, सलाह मशविरे और चर्चा कर लेने की जो परम्परा चली आ रही है, उसे यथासम्भव कम कर देना चाहिये, क्योंकि इसका नतीजा प्रायः जिम्मेदारी को बिखेर देने और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी ओर से कोई कार्रवाई न करने के रूप में सामने आता है।

सरकार का काम अब बहुत फँस चुका है और उच्च स्तरों पर बहुत दबाव रहने के कारण, सभी विभागों में मध्यम वर्ग के कर्मचारियों का सदा ठीक-ठीक मार्ग-प्रदर्शन नहीं हो पाता इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन वर्गों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देकर, उन्हें दिन-प्रति दिन के प्रशासन में अधिकाधिक जिम्मेदारी उठाने के योग्य बना दिया जाए।

जैसा कि पहली योजना में भी कहा गया था, यदि प्रशासन के अधिक बड़े लक्ष्यों की पूर्ति करनी है, तो स्वयं शासन-चक्र के ही व्यक्तियों को आगे बढ़ने और नेतृत्व करने का अवसर देना चाहिए, ताकि वे प्रशासन की कुशलता और स्तर में निरन्तर सुधार करके उसे ऊँचा उठा सकें। ये नेता अधिकतर सरकारी कर्मचारियों के उच्च वर्ग में से निकलने। इस विचार पर अमल करने के लिए आजकल केन्द्रीय सरकार एक सुझाव पर विचार भी कर रही है। राज्यों में इस लक्ष्य की पूर्ति के

लिए मुख्य सचिव, आदि कुछ उच्च अधिकारियों को कहा जा सकता है कि वे एक प्रशासन समिति के रूप में कार्य करें। उनको यह जिम्मेदारी हमेशा के लिए सौंपी जा सकती है कि वे प्रशासन में सुधार करने के उपाय सुझाएँ और विभिन्न विभाग जो कारवाहियाँ करें उन पर विचार करें। यह समिति समय समय पर अपनी रिपोर्टें मुख्य मंत्री और मन्त्रिमण्डल के सामने पेश किया करे।

ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की सफलता बहुत बड़ी मात्रा में जिले, खण्ड और गाँव के प्रशासन की कुशलता और ईमानदारी पर निर्भर करती है। इसीलिए कई राज्यों में जिला-प्रशासन की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है और उसे सुधारने के उपाय किए जा रहे हैं। अब कई स्थानों पर, विशेषकर विकास-खण्डों में, लोकप्रिय निकायों का संगठन कर दिया गया है। फलतः स्थानीय जन-शक्ति तथा अन्य साधनों के उपयोग की सम्भावनाएँ बढ गई हैं। परन्तु जैसा कि इसी अध्याय में सामुदायिक विकास के प्रकरण में बतलाया गया है, विकास खण्डों में पंचायत-समितियों के लिए आवश्यक है कि वे तीसरी योजना की अवधि में अपना सारा जोर, सुल-सुविधाएँ बढ़ाने के कार्यक्रमों के स्थान पर, कृषि की उपज बढ़ाने पर लगाएँ और अपने क्षेत्र में योजना को पूरा करने वाली एजेंसी की हैसियत से काम करें। सर्वोच्च प्राथमिकता का विचार और ऊपर के सलाह मशविरे को छोड़कर विकास खण्डों में विकास के सब कार्यों के लिए आखिरी जिम्मेदारी खण्ड पंचायत-समिति पर रहनी चाहिये और इस मार्ग पर निरन्तर आगे बढ़ने रहना चाहिये।

प्रशासन में कुशलता का स्तर ऊपर उठाने की प्रक्रिया सदा चलती ही रहती है। प्रशासन का सामना अधिक-अधिक उत्कृष्ट-भरे और बड़े कामों से होता रहता है और कई क्षेत्रों में काम करने की नई विधियाँ निकालने की जरूरत पड जाती है। कार्य प्रणाली का नियमपूर्वक अध्ययन करने और मन में प्रयोग की वृत्ति रखने से इस क्षेत्र में बड़ी सहूलियत होती है।

द्वितीय भाग
भारतीय नियोजन

भारत के प्रारम्भिक नियोजन (Earlier Indian Plans)

१—संक्षिप्त इतिहास (A Short History)

सम्भवतः भारत के नियोजनावद्ध आर्थिक विकास का प्रथम प्रयास श्री एम. विश्वेस्वरैया द्वारा किया गया था। सन् १९३४ में उनकी पुस्तक 'प्लान्ड इकनॉमी फॉर इण्डिया' (Planned Economy For India) प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने विस्तृत रूप से आर्थिक नियोजन की आवश्यकता तथा महत्त्व पर प्रकाश डाला था, साथ ही एक अनियोजित अर्थव्यवस्था के दोषों का भी विवेचन किया था। इस पुस्तक से हमें ज्ञात होता है कि किसी भी देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए आर्थिक नियोजन का होना नितान्त आवश्यक है। 'असिल भारतीय आर्थिक सम्मेलन' ने भी इनको महत्वपूर्ण बनलाया और सन् १९३४-३५ तथा सन् १९३८-३९ की सालाना बैठक में सम्मेलन ने उक्त पुस्तक (Planned Economy For India) पर विचार विमर्श किया। इस प्रकार से इस पुस्तक की मार्थकता प्रकट हो जाती है। इस पुस्तक में श्री विश्वेस्वरैया ने समस्त भारत के लिए एक दस वर्षीय योजना का सुझाव दिया था जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय को दुगुना करना तथा कारखानों की उत्पत्ति में वृद्धि करना था, जिससे कि प्राचीन समय में विद्यमान कुछ मूलभूत श्रुतियों और कमजोरियों को छोड़े से समय में ही दूर किया जा सके। साथ ही देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए जो बाधित सुधार और विकास के उपाय हैं, उनको लागू किया जा सके। उनके अनुसार ये सुधार और विकास के उपाय निम्नलिखित बातों पर आधारित होने हैं। सार्वजनिक शिक्षा, सुरक्षा, प्रशिक्षण, बड़े उद्योगों की स्थापना के साथ देश का औद्योगीकरण, साधनों की जाँच तथा अकशास्त्र का सकलन, व्यवसायों का संतुलन तथा ग्रामों का पुनरुत्थान आदि।

इसके बावजूद भी कि यह 'भारत का आर्थिक नियोजन' पुस्तक समय के बहुत अनुकूल थी और इन में सुधार के असंख्य महत्वपूर्ण तथ्य थे, किन्तु निम्नलिखित कठिनाइयों के कारण इसे प्रयोग में नहीं लाई जा सकी —

धन की कमी, उचित आँकड़ों का अभाव, विदेशी शासन तथा जनमत की उपेक्षा आदि इन्हीं समस्याओं के कारण यह पुस्तक कभी व्यवहार में नहीं लाई जा सकी और इसके सुधार केवल सिद्धान्त बन कर रह गये ।

सन् १९३५ के बाद जब प्रान्तों में स्वतन्त्र सरकार बनाने की स्वीकृति दे दी गई तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक 'राष्ट्रीय नियोजन समिति' नियुक्त की जिसके अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू थे । इस समिति ने सन् १९३८ में अपना कार्य प्रारम्भ किया ही था कि द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जाने से तथा राजनैतिक उथल-पुथल के कारण इस समिति के कार्य संचालन को काफी धक्का लगा । इस राजनैतिक उथल-पुथल ने समिति के कार्य को ही धक्का नहीं पहुँचाया अपितु कर्मठ कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को भी कार्य क्षेत्र से हटा दिया । इसके बाद सन् १९४७ में कुछ परिवर्तनों के साथ यह समिति पुनर्जीवित हो उठी और पंडित नेहरू की अध्यक्षता में तथा के० टी० शाह के सम्पादकीय नेतृत्व में इसने कई महत्वपूर्ण रिपोर्टें (reports) प्रकाशित की ।

जुलाई सन् १९४४ में जनमत के दबाव के कारण उस समय की भारत सरकार ने एक 'नियोजन तथा विकास विभाग' स्थापित किया जिसके कर्त्ता धर्त्ता आर्देशीर-दलाल (Ardeshir Dalal) थे । इसके फलस्वरूप सन् १९४६ में एक सलाहकार नियोजन बोर्ड स्थापित किया गया जिसका काम "आर्थिक नीति" का निर्धारण करना था । आर्थिक नीति का निर्धारण मुख्यतः निर्माण कार्य करने, जनता के स्तर को ऊँचा उठाने, सबको लाभदायक रोजगार दिलाने, प्राप्त साधनों का अधिकतम उपयोग करने तथा आवश्यक पदार्थों का समान रूप से वितरण करने के लिए था । इसके अलावा सरकार ने विभिन्न उद्योगों के लिए अलग-अलग स्तर पर औद्योगिक उपसमिति (Pannel) की स्थापना की, किन्तु इन सब सघटनों तथा बोर्डों के लिए अन्य कठिनाइयों के अलावा सबसे बड़ी कठिनाई वित्त की थी । अधिकतर अर्थ-शास्त्रियों का विचार था कि वित्त की कठिनाई के कारण आयोजन के उद्देश्यों को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता और भारतीय वित्त की कठिनाई को सरलता से दूर नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत कुछ आशावादी ऐसे भी थे जो आर्थिक विकास के लिए नियोजन को आवश्यक समझते थे । लॉर्ड वॉवेल (Lord Wavell) उन सबसे मुख्य थे और उनका उल्लेख कर देना ही यहाँ पर पर्याप्त होगा, जिसने अपनी दृढ़ विश्वास शक्त के साथ अनेकों बार यह कहा था कि "अगर युद्ध जैसे विनाशकारी कामों के लिए धन प्राप्त किया जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि शान्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए धन प्राप्त नहीं किया जा सके" ¹ अर्थात्

1. "If money can be found for war, money can also be found for peace"—Lord Wavell.

अगर युद्ध के लिए धन मिल सकता है तो शान्ति के लिए भी धन मिल सकता है । किन्तु आर्थिक नियोजन के महत्त्व को इतना भारी सहयोग और स्वीकृति मिलने पर भी व्यवहारिक रूप से तब तक कोई ठोस कार्य न हो सका ।

२—जन-नियोजन (The Peoples' Plan)

यह नियोजन साम्यवादी दल के नेता एम० एन० रॉय तथा उनकी पार्टी द्वारा बनाया गया था । इसमें कम्युनिस्टों की आदर्शवादिता की समस्त विशेषतायें पाई जाती हैं । उनका कहना था कि देश की समस्त आर्थिक गड़बड़ और बुराइयों का कारण देश की पूँजीवादी अर्थव्यवस्था है ।

नियोजन के मूल तत्त्व (Central Idea of the Plan)¹—

(१) भारतवर्ष का भावी राज्य प्रजातन्त्रात्मक हो जो सार्वजनिक रूप से गठित हो । भूमि उत्पादन के साधनों पर उसका अधिकार हो और जो सामान्य उद्योग, बड़े-बड़े उद्योगों तथा बैंकों को अपने नियन्त्रण में रहे ।

(२) भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तथा ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता को दूर कर दिया जाय ।

(३) मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए ।

(४) सहकारी कृषि को प्रोत्साहन दिया जाय ।

(५) राज्य द्वारा मनुष्य की सभी प्राथमिक आवश्यकताओं, जैसे खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य, मकान आदि की प्राप्ति की गारंटी होनी चाहिए ।

(६) उत्पादन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि 'मुनाफाखोरी' की प्रवृत्ति दूर हो जाय । अतिरिक्त पूँजी को पुनर्नियोजित किया जाय जिससे कि उत्पादन बड़े और लोगों को लाभदायक रोजगार मिले ।

(७) ग्रामीण-ऋण-ग्रस्तता के सम्बन्ध में योजना में यह सुझाव रखा गया है कि ७५% ऋण को समाप्त कर दिया जाय और बचे हुए २५% का भुगतान राज्य करे ।

(८) कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र बढ़ाया जाय, जिससे कि अन्न का उत्पादन बड़े । खेती करने के वर्तमान वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाय । खेती मशीनों द्वारा की जाय तथा ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाया जाय ।

(९) कुटीर उद्योग-धन्धों को पनपने से रोका जाय तथा बड़े पैमाने के उद्योग धन्धों के विकास पर बल दिया जाय, जो कि पूर्णरूप से राज्य द्वारा चलाये जाय ।

(१०) व्यापार के सम्बन्ध में कठोर नीति अपनायी जाय । उत्पादक तथा उपभोक्ता में सहयोग हो । विदेशी व्यापार में राज्य एकाधिकार सम्बन्धी नीति अपनाये ।

व्यय तथा लागत

१० वर्ष की अवधि में अनुमानों के आधार पर १५००० करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा । जो निम्न प्रकार होगा:—

व्यय के प्रकार	कुल व्यय (रुपयों में)
१—कृषि	२,६५० करोड़
२—उद्योग	५,६०० "
३—समादवाहन	१,५०० "
४—स्वास्थ्य	७६० "
५—शिक्षा	१,०४० "
६—गृह-निर्माण	३,१५० "
कुल	१५,००० "

यह धन निम्नलिखित साधनों से प्राप्त किया जायेगा:—

आय के साधन	कुल आय (करोड़ रुपयों में)
१—पौन्ड पावना निधि से	४५० " "
२—सार्वजनिक साधन—जायदाद कर, उत्तराधिकार कर, मृत्यु कर आदि	८१० " "
३—भूमि के राष्ट्रीयकरण से प्राप्त आय	६० " "
४—कृषि से प्राप्त आय (पुनर्विनिमय के लिए)	१०,८१६ " "
५—उद्योगों से प्राप्त आय (पुनर्विनिमय के लिए)	२,८३४ " "
कुल	१५,००० " "

उपयुक्त तालिका को देखने में ज्ञात होता है कि यह एक महत्वाकांक्षी योजना है । यह योजना कृषि उत्पादन पर विशेष जोर देती है और प्रौद्योगिक उत्पादन पर कम और प्राथमिक उद्योगों के उपभोक्ता की वस्तुओं के उत्पादन के बजाय कारखानों को प्राथमिकता देती है ।

सम्भावित परिणाम—योजना के पूर्ण हो जाने पर कृषि उत्पादन में ४०% प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन में ६०% प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था और भारतवर्ष का हर व्यक्ति पहले से चौमुनी अच्छी हालत में रहने लगेगा । यह योजना अनुप्य की वर्तमान आवश्यकताओं को १० साल में पूरा करने के साधन प्रदान करती है । किन्तु अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया और इसके परिणाम केवल स्वप्न बनकर रह गए ।

३—गांधीवादी योजना (The Gandhian Plan)

विश्व युद्ध के समय भारत की आर्थिक दशा बहुत शोचनीय हो गई थी। लोगों का जीवन स्तर काफी गिर गया था, उपभोग की मात्रा में काफी कमी हो गई थी जिनके फलस्वरूप साधारण जनता का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। उसी समय गांधीजी जहाँ एक ओर तो भारत की राजनैतिक स्वतन्त्रता को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे; वहाँ दूसरी ओर साधारण जनता की बढ़ती हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी प्रयत्नशील थे, इसलिए साधारण लोगों की भलाई के लिए उन्होंने समय-समय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने जनता के उपभोग के स्तर को बढ़ाने के लिए १० साल की अवधि निश्चित की। उन्होंने कहा था कि साधारण लोगों के जीवन-स्तर को उठाने के लिए समुचित रूप से धन साधनों की उपलब्धि हो जाय तो १० साल के अन्दर भारत का पूर्णरूप से आर्थिक विकास हो जाय। इस सम्बन्ध में एक ओर जहाँ उन्होंने साधनों को जुटाने के लिये प्राणाध्यक्ष की थी वहाँ दूसरी ओर लोगों से आवश्यकताओं को कम करने की भी अपील की। गांधी जी ने स्वयं कोई सुगठित आर्थिक योजना नहीं बनाई थी। वास्तविक रूप से जो गांधी योजना के नाम से पुकारी जाती है वह एस० एन० अग्रवाल द्वारा सकलित गांधी जी के आर्थिक विचार हैं। अपने लेखों में—प्रमुख रूप से 'हरिजन' और 'स्वराज्य' में—गांधी जी ने कहीं-कहीं पर आर्थिक समस्याओं का विवेचन किया तथा आर्थिक कमजोरियों के सुधार के रूप में कुछ आर्थिक पहलुओं का विवेचन जिनका भाग्य चलकर एस० एन० अग्रवाल ने अध्ययन किया और उनकी क्रमिक रूप में रखा। इस प्रकार गांधी योजना की रूपरेखा तैयार हुई। यह एक स्वयंसिद्ध बात है कि ऐसे आयोजनों में मानव जाति से सम्बन्धित समस्त उद्देश्यों और कथनों का समावेश होता है। इस प्रकार गांधी जी के उन विचारों को जो मनुष्य की भौतिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक उन्नति से सम्बन्धित हैं, उचित रूप से आँका गया है। इसके अलावा इस योजना में यह भी संकेत किया गया कि सार्वजनिक कल्याण के सिद्धान्त सादगी, अहिंसा, श्रम की उचित महत्ता तथा मानव-मूल्य पर आधारित हैं। गांधी जी के यही उपदेश इस योजना के मूल आधार थे।

इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थी :

(१) २६०० किलोरी शक्ति की क्षमता वाला सतुलित आहार, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष २० गज कपड़ा, प्रति व्यक्ति के निवास के लिए १०० वर्गफुट जगह, भुपन बुनियादी शिक्षा, उचित स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना।

(२) प्रति व्यक्ति की सालाना आय में कम से कम चौगुनी वृद्धि करना तथा अधिक में अधिक रोजगार की सुविधा प्रदान करना।

(३) योजना पूर्ति की १० साल की अवधि के लिए कम से कम ३५०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। जिनमें से ११७५ करोड़ रुपये अकेली कृषि पर व्यय किये जायेंगे और १००० करोड़ रुपये मुख्य तथा बड़े बड़े उद्योगों पर व्यय किये जायेंगे। ३५० करोड़ रु० ग्रामीण उद्योग धन्धों पर, २०० करोड़ रु० यातायात के साधनों के विकास पर, २६० करोड़ रु० सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, २६५ करोड़ रु० शिक्षा पर तथा २० करोड़ रु० आविष्कार पर और बचे हुए २०० करोड़ रु० अन्य मदों पर खर्च किये जायेंगे।

(४) ग्रामीण जन-कल्याण पर अधिक जोर दिया जायगा। यह मुख्यतः अधिकतम सम्यता और सस्कृति के पुनुरुत्थान के सिद्धान्त पर आधारित होता चाहिये।

(५) ऐसा भी सुझाव दिया गया है कि आन्तरिक व्यवस्था और आर्थिक उत्थान के लिए गाँवों में स्वयं संचालित तथा ग्रामीणों द्वारा चुनी गई पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए जिन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए।

(६) खेती के सम्बन्ध में कृषि की उत्पादक शक्ति को बढ़ाने के लिए तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती में क्रान्तिकारी सुधार किये जायें। सामूहिक सहकारी खेती पर विशेष बल दिया जाय।

(७) बड़े-बड़े महत्वपूर्ण कारखाने तथा सार्वजनिक सेवाओं का संचालन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए जिससे पूरे राष्ट्र का अधिक से अधिक हित हो।

(८) योजना की पूर्ति के लिए धन के बारे में कहा गया है कि २,००० करोड़ रुपये आन्तरिक ऋण के द्वारा लिया जाय, १००० करोड़ रु० मुद्रण से प्राप्त किया जाय तथा ५०० करोड़ रु० करो द्वारा प्राप्त किया जाय।

इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि उपर्युक्त सभी सुझाव योजना के निर्माण काल की समस्याओं को सुलझाने के लिए पूर्ण उपयुक्त थे और उस समय यह योजना पूर्ण सफल हो सकती थी किन्तु फिर भी यह आयोजन कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया। इसकी सफलता में असह्य बाधाएँ थीं। सब तो यह है कि यह योजना यथार्थ से काफी परे थी और महत्वपूर्ण आदर्शों से भरी हुई थी। और चूँकि आदर्श कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता इसलिए इस योजना के सिद्धान्तों को लागू नहीं किया गया।

४—सर्वोदयी योजना (The Sarvodaya Plan)

जैसा कि 'सर्वोदय' शब्द से ध्वनित होता है, इस योजना के निर्माताओं ने ३० जनवरी सन् १९५० ई० में यह प्रकाशित किया था कि सर्वोदयी योजना मनुष्य की सर्वाङ्गीण आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा नैतिक उन्नति के उद्देश्य से

बनाया गया है। इस योजना की रूपरेखा तैयार करने का मुख्य श्रेय श्री जयप्रकाश नारायण को है। उन्होंने कहा था कि “यह योजना कोरी सिद्धान्तवादी नहीं है। अपितु रुढ़िवादी सामाजिक सीमाओं से परे, सामाजिक क्रान्ति की शुरुआत का यह एक सुदृढ़ कदम है। एक नये समाज की तसवीर बनाने का यह पहला कदम है।” आगे चलकर उन्होंने कहा था कि सर्वाङ्गीण सामाजिक-आर्थिक उन्नति के अलावा इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक अहिंसात्मक, शोषण-विहीन, स्वयं-संचालित सहकारी समाज की स्थापना करना है।” अर्थात् एक ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें वर्ग-संघर्ष न हो और जिसमें समाज के प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के लिए उपयुक्त वातावरण हो।

संक्षेप में इस सर्वोदयी योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

(१) कृषि भूमि के स्वामित्व का अधिकार उसके जोतने वाले को दिया जाय। जोतो की असमानताओं को दूर करने के लिए भूमि का पुनर्वितरण किया जाय। सभी आर्थिक जोतों को एक सहकारी फार्म में मिला दिया जाय। भूमि जोतने वालों का शोषण होने में रोका जाय और शोषण करने वालों को कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाय।

(२) राष्ट्रीय आय और सम्पत्ति का समान रूप से न्यायपूर्ण वितरण हो। आय की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाय।

(३) विदेशी लाभ कमाने वालों को देश के बाहर खदेड़ दिया जाय अथवा उनसे उत्पादन की प्रणाली, प्रबन्ध तथा उद्देश्यों को बदलने के लिए कहा जाय—अथवा उनको राज्य के नियन्त्रण में कार्य करने को कहा जाय।

(४) स्थापित उद्योगों का संचालन समाज को दे दिया जाय और वे स्वैच्छाचारी सघों अथवा सहकारी सघों के द्वारा चलाये जाय। विस्थापित उद्योगों में उत्पादन के समस्त साधन या तो समाज द्वारा व्यक्तिगत रूप से एकत्रित किये जाय या सामूहिक रूप से अथवा सहकारी सघों द्वारा।

(५) हमारी वित्तीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य ऐसा हो कि राज्य की आय का ५० प्रतिशत भाग गाँव पंचायतों द्वारा खर्च किया जाय और बचे हुए ५० प्रतिशत से उच्च सत्ता के शासन का खर्च चलाया जाय।

यह सर्वोदय योजना भारत की आर्थिक पहलुओं की कुछ विशेषताओं से सम्बद्ध है। यद्यपि अनुभव के आधार पर यह योजना परीक्षित नहीं की गई फिर भी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के निर्माण तथा सफल संचालन में इसने रास्ता प्रशस्त किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुत कुछ सर्वोदय सिद्धान्त को लेकर बनी।

५—बम्बई योजना (औद्योगिक योजना) [Bombay Plan¹ (Industrialists' Plan)]

भारत के उद्योग धन्धों के विकास के लिए कुछ विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा बनाये गए १५ वर्षीय कार्यक्रम को Bombay Plan की सज्ञा दी गई।

१—इस “१५ वर्षीय आर्थिक योजना” का संक्षिप्त विवरण :

इस योजना में निम्न विषयों पर विचार किया गया था—

- (अ) उद्देश्यों का मानसिक विश्लेषण किया गया था।
- (ब) योजना की सफलता के लिए साधारण रूपरेखा तैयार की गई।
- (स) योजना की माँग देश के साधनों पर आधारित।

२—योजना के लिए दिए गए सुझाव निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित —

- (अ) आर्थिक मामलों में राष्ट्रीय सरकार की खुल कर शक्ति हो।
- (ब) आर्थिक रूप से भारत एक इकाई में गठित हो।

३—योजना के निर्माण और संचालन के लिए एक कार्य-कारिणी का सुझाव दिया गया :

- (अ) एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हो जिसमें विभिन्न प्रकार की शक्तियों से सम्बन्धित विचारों का प्रतिनिधित्व हो, तथा
- (ब) योजना के प्रसारण के लिए एक सर्वोच्च आर्थिक सच का निर्माण हो। उपर्युक्त दोनों संस्थाएँ केन्द्रीय सरकार की सत्ता के नियन्त्रण में कार्य करें। इन दोनों शाखाओं के कार्यों का मिलान तथा प्रांतीय सरकारों से उनके अन्तर्गत सम्बन्ध इस योजना की दो बहुत महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करने की अधिकारी हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जैसा कि योजना में बताया गया, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति औसत आय को १५ वर्षों में दूना करना था और योजना के सफल संचालन के लिए इस १५ वर्ष के समय की ३ से ५ वर्ष की अवधि तक के समय में बाँट दिया गया था। अनुमान लगाया गया कि देश की कुल मौजूदा राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति की सालाना आमदनी से तीन गुनी हो जाय। योजना निमाताओं ने जीवन की सूक्ष्म रूप से आवश्यक आवश्यकताओं का सुन्दर सांख्यिकीय विवेचन किया जो मनुष्य को खाने, पहिनने, रहने तथा स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं से सम्बन्धित है।

1. Brochure on Colombo Plan and India's Progress Towards Planning : Parliament Secretariat, Govt. of India, New Delhi, July 1952, pp. 13-19

योजना का आर्थिक स्वरूप—अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत योजना का आर्थिक स्वरूप इस प्रकार है :—

उनके द्वारा निर्धारित उद्देश्य, १५ साल की योजना अवधि में राष्ट्रीय आय को तीन गुना कर देने के हैं; अर्थात् योजना की शुरुआत से ३ से ५ वर्ष की अवधि में लेकर आखिर के १५ वर्षों तक राष्ट्रीय आय तीन गुनी हो जाय ।

राष्ट्रीय आय की १९३१-३२ की दशा तथा योजना द्वारा वृद्धि की दशा का विवेचन नीचे की तालिका में दिया गया है :—

(करोड़ रुपये में)

१९३१-३२ की आय		योजना की अवधि के पूर्ण होने पर आय			
आय के प्रमुख स्रोत	कुल आय	कुल आय का प्रतिशत	योजना काल की समाप्ति पर कुल आय	योजना के बाद की होने वाली आय का कुल प्रतिशत	योजना से होने वाली आय की प्रतिशत वृद्धि
उद्योग	३७४	१७	२,२४०	३३६	५००
कृषि	१,१६६	५३	२,६७०	४०५	१३०
राजकीय सेवायें	४८४	२२	१,४५०	२२०	२००
अवर्गीकृत आय	१७६	८	२४०	३६	३६
कुल योग	२,२००	१००	६६००	१०००	२१६५ अनुमानित

यह योजना एक सन्तुलित अर्थव्यवस्था स्थापित करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए बनाई गई । अर्थव्यवस्था में सन्तुलन स्थापित करने के लिए योजना में उद्योगों तथा सेवाओं से प्राप्त आय में प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया । यद्यपि इस प्रतिशत परिवर्तन के गठन के बावजूद भी देश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्ववत् बनी रहेगी ।

योजना के मार्ग की कठिनाइयाँ—योजना निर्माताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया कि योजना की समाप्ति कठिनाइयों से भरी पड़ी है । उनमें से मुख्य कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं :—

१—योजना भारतीय जनता के सुदृढ अन्धविश्वास और नियमों के विरुद्ध कार्य करती ।

२—इसमें व्यक्तिगत कठिनाइयों तथा त्याग की आवश्यकता थी ।

३—राजनैतिक विरोधताओं के कारण योजना का विकास अवरोध हो सकता ।

योजना निर्माता, द्वितीय युद्ध के बाद उत्पन्न भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बहुसंख्यक प्रभावों से पहले ही जागरूक थे। उन्होंने इस बात की पहले ही घोषणा कर दी कि यह कार्यक्रम, वास्तविक रूप से, एक दम कायापलट कर देने वाला नहीं है। वित्त के बारे में उनकी धारणा एकदम दूसरी है। उनका कहना था कि एक सुनियोजित अर्थव्यवस्था में, वित्तीय-मंदी के लिये प्राप्त किया जाने वाला धन देश की अर्थव्यवस्था का स्वामी या सदस्य न होकर उसका सेवक तथा साधन मात्र होता है।

योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएँ ।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में योजना निर्माता निम्न लिखित निष्कर्ष पर पहुँचे—

उद्योग —

१—इस आर्थिक नियोजन के लिये उद्योग धन-धन बहुत आवश्यक हैं। इसलिये योजना में प्राथमिक उद्योगों का तीव्र गति से विकास किया जाय।

२—बड़े पैमाने के उद्योग धन-धन के साथ छोटे पैमाने के कुटीर उद्योग-धन-धन के विकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र दिया जाय—मुख्य रूप से उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों पर बल दिया जाय।

३—पूँजी के शुद्ध उत्पादन का अनुपात (ratio) भिन्न-भिन्न उद्योगों में उस सीमा तक भिन्न होता है जहाँ तक कि उसमें पूँजीवादी उत्पादन के साधनों तथा तकनीकी प्रगतियों का उपभोग होता है। जैसे पूँजी से शुद्ध उत्पादन के क्रम को २ मान कर २,२४० करोड़ रुपये के शुद्ध औद्योगिक उत्पादन के लिये योजना में ४,४८० करोड़ रुपये की पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी।

कृषि—योजना में कृषि कार्यक्रमों के लिये १३ प्रतिशत विकास की आशा व्यक्त की गई किन्तु देश की जरूरतों को देखते हुए यह वृद्धि बहुत कम थी। योजना में यह स्पष्ट किया गया कि योजना के प्रथम वर्षों में कृषि पदार्थों के निर्यात के बारे में कोई निश्चय नहीं किया जाएगा। देश की जनता के लिये आवश्यक खाद्य सामग्री की पूर्ति के लिये योजना में कृषि कार्य के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कृषि सम्बन्धी समस्याओं के द्वारा में योजना में कुछ प्रमुख सुझाव दिये गये थे। योजना निर्माताओं के अनुसार —

१—खेतों के दूर-दूर तथा छिटके होने की समस्या को दूर करने के लिये अनिवार्य रूप से सरकारी खेती अपनाई जाय।

२—‘कृषि ऋण प्रसूता’ को दूर करने के लिये, यह सुझाव दिया गया कि जहाँ तक सम्भव हो सके ऋण में से व्याज की रकम को समाप्त कर दिया जाय और बाकी के ऋण को चुकाने के लिये, सहकारी समितियाँ, किसानों को कम व्याज पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करे।

३—योजना में भूमि क्षरण को रोकने के लिये, भूमि को समतल करने तथा वन लगाने का सुझाव दिया गया ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यह प्राशा व्यक्त की गई कि सिंचाई, फसलों के हेर फेर, उत्तम खाद, उन्नत बीज तथा कृषि औजारों के बारे में कृषि का अभिनवीकरण करके प्रति एकड़ उपज में सुधार किया जाय । मॉडल फार्म (Model farm) के सुव्यवस्थित कार्य-क्रम को भी पूर्ण उपयुक्त समझा गया । योजना में कृषि क्षेत्र के लिये अनुमानित व्यय निम्नलिखित थे :

१,०६५ करोड़ रुपया अनावर्तक व्यय के रूप में (Non-recurring)

१५० करोड़ रुपया आवर्तक व्यय के रूप में (recurring)

यातायात के साधन और शिक्षा :

इन कार्य-क्रमों के बारे में निम्नलिखित व्यवस्था की गई —

रेलें—सन् १९३८ ई० में रेलों की कुल लम्बाई ४१,००० मील थी । इस योजना में ४३४ करोड़ की लागत की २१,००० मील लम्बी रेलवे लाइनों के विस्तार की और व्यवस्था की गई । इसके अलावा ६ करोड़ रुपया पुरानी रेलवे लाइनों में सुधार के लिये रखा गया । इस प्रकार बम्बई प्लान में कुल मिला कर ६२००० मील लम्बी रेलवे लाइनों के विस्तार की व्यवस्था की गई ।

सड़कें—ब्रिटिश शासन-काल में भारत में ७४,००० मील लम्बी पक्की तथा २,२६,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें थी । ३०० करोड़ रुपये की लागत की ३,००,००० मील लम्बी सड़कों के निर्माण का कार्य क्रम रखा गया । २,२६,००० मील लम्बी वर्तमान कच्ची सड़कों को पक्का करने के लिए ११३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई ।

जहाजरानी—बन्दरगाहों के विकास के लिए योजना में ५० करोड़ रुपये के व्यय का सुझाव दिया गया है । इसके अतिरिक्त ५ करोड़ रुपया पुराने बन्दरगाहों के विकास के लिये निर्धारित किया गया ।

इस प्रकार योजना में यातायात के विकास के लिये ६६७ करोड़ रु० अनावर्तक (Non-recurring) व्यय के रूप में तथा ४६ करोड़ रु० आवर्तक (recurring) व्यय के रूप में व्यय करने की व्यवस्था की गई ।

शिक्षा—एक सुव्यवस्थित आर्थिक कार्यक्रम के सफल संचालन के लिये जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है । इसके लिये जनता में साक्षरता एवं समझदारी परम आवश्यक है । एवं बड़े पैमाने पर होने वाले ऐसे महान् और गहन कृषि तथा औद्योगिक विकास के लिये बड़ी संख्या में प्रौद्योगिक कार्यकर्त्ताओं, मजदूरों एवं प्रशासकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी ।

हमारे प्राकृतिक साधनों—जैसे खनिज पदार्थों, विद्युत-शक्ति, एवं भूमि आदि की अच्छी जाँच पड़ताल के लिये भी हमें बड़ी संख्या में विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी ।

शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए— प्राथमरी शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, विश्व विद्यालय की शिक्षा तथा वैज्ञानिक एवं अनुसंधान सम्बन्धी शिक्षा आदि। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि योजना काल में निरक्षरता को दूर करने के साथ साथ मातृकृतिक एवं व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाय। योजना में शिक्षा कार्यक्रम पर निम्नलिखित व्यय होगा—

१—२६७ करोड़ रुपया अनावर्तक (Non-recurring)

२—२३७ करोड़ रुपया आवर्तक (Recurring)

गृह-निर्माण कार्य

वर्तमान जनसंख्या एवं भविष्य की वृद्धि को देखते हुए आवास कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। योजना में गृहनिर्माण के लिए निम्नलिखित व्यय की व्यवस्था की गई है—

१—२२०० करोड़ रुपया अनावर्तक (Non recurring)

२—३१८ करोड़ रुपया आवर्तक (recurring)

इसके लिए २०० करोड़ रुपये की पूँजी की राशि आकी गई।

योजना के विभिन्न कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर निम्नलिखित वित्त की आवश्यकता पड़ती है—

करोड़ रुपया

कार्यक्रम	अनावर्तक व्यय Non recurring expenditure	आवर्तक व्यय Recurring expenditure	आवश्यक पूँजी (अनुमानित)
उद्योग	४,४८०	..	४,४८०
कृषि	१,०६५ (८४५)	१५० (४००)	१,२४०
यातायात	८६७	४६	६४०
शिक्षा	२६७	२३७	४६०
स्वास्थ्य	२८१	१८५	४५०
गृह निर्माण	२,२००	३१८	२,२००
अन्य	२००	..	२००
	६,४२० (६,१७०)	६३६ (१,१८६)	१०,०००

योजना के लागत व्यय की प्राप्ति के लिए योजना निर्माताओं ने प्रायः के निम्नलिखित दो प्रमुख स्रोत बतलाए —

१—बाह्य वित्त-व्यवस्था

२—आंतरिक वित्त-व्यवस्था

बाह्य वित्त-व्यवस्था

देश के बाह्य वित्तीय साधनों द्वारा प्राप्त प्रायः को २,६०० करोड़ रुपया आंका गया जो निम्न प्रकार था—

१—देश का साख सतुलन—पौण्ड पावना के रूप में	१,००० करोड़ रुपया
२—स्वरां तथा सजाने के रूप में देश का वह मचित धन जो पूँजी के रूप में विनियोजित होगा	३०० करोड़ रुपया
३—विदेशी ऋण	७०० करोड़ रुपया
४—४० करोड़ रुपये सालाना के आधार पर १५ वर्षों में अनुकूल सन्तुलन से प्राप्त आय	६०० करोड़ रुपया
	<hr/> २,६०० " "

प्रान्तरिक वित्तव्यवस्था :

देश के प्रान्तरिक साधनों से प्राप्त आय की रकम ७,४०० करोड़ रुपया प्रांकी गई जो निम्न प्रकार होती :—

वचन से प्राप्त आय	४,००० करोड़ रुपया
मुद्रा प्रचलन से प्राप्त आय	३,४०० " "
	<hr/> ७,४०० " "
	<hr/> कुल १०,००० " "

योजना निर्माताओं का विश्वास था कि पूँजी अथवा वित्त व्यवस्था एक सुनियोजित अर्थव्यवस्था में सहायक के रूप में गौण कार्य करती है। इस बारे में उन्होंने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये थे :—

१—एक सुनियोजित अर्थव्यवस्था में द्रव्य निर्माण (created money) अशुद्ध या अनुचित कोई चीज नहीं है। यह स्वचालित विशेषता से परिपूर्ण है।

२—नवीन मुद्रा की निकासी जनता की क्रयशक्ति तथा प्राप्त वस्तुओं के विस्तार में अन्तर स्थापित करती है। इस अन्तर को छिपाना या पूरा करना बड़ा कठिन है तथा समाज के विभिन्न वर्गों पर इसके उचित बटवारे के लिए सरकार द्वारा कठोर नियन्त्रण करना आवश्यक हो जाता है।

— द्रव्य को केवल देश के आंतरिक साधनों को मानव-शक्ति एवं सामग्री के रूप में गतिशील बनाने के माध्यम के रूप में अपनाया जाय।

योजना निर्माताओं ने विकास के स्तरों के सही निरूपण के लिए सुनिश्चित कार्यक्रम अपनाए थे, जिनके बारे में उनका कहना था कि उनकी बहुत कुछ सफलता प्राकृतिक साधनों, अथवा, पूँजीगत वस्तुओं तथा प्रबन्धकीय क्षमता की लपलधि पर निर्भर होती है।

योजना के विभिन्न स्तर .

विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के विभिन्न घटनास्थलों के निरूपण करते समय मुख्य रूप से दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जो निम्न प्रकार है :—

(१) अन्य कार्यक्रमों के अलावा विकास के विशिष्ट कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए; मुख्य रूप से आधारभूत उद्योगों के विकास को अधिक महत्त्व दिया जाय ।

(२) “किसी भी प्रकार का नियोजन अश्रुनिपात से रहित नहीं है ।” कुछ भी हो योजना इस तरह की हो कि योजना के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक बोझ न पड़े । इस बारे में यह कहा गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में हसी योजनाओं की तीन कमजोरियों को समाप्त कर दिया जाये और निम्न लिखित बातों का ध्यान रखा जाय —

(१) बृहद् उद्योगों पर अत्यधिक बल न दिया जाय । (२) उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के बारे में उदासीनता न बरती जाय । (३) ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन न दिया जाय जिनमें दीर्घकाल में उत्पादन होने की सम्भावना हो ।

इस प्राथमिक नियोजन के १५ सालों के विकास कार्यों का विवरण निम्न प्रकार था —

करोड़ रुपया

मदें	मूल आय १९३१	प्रथम योजना		द्वितीय योजना		तृतीय योजना		१५ सालों का योग	
		पूँजी	आय में वृद्धि	पूँजी	आय में वृद्धि	पूँजी	आय में वृद्धि	पूँजी	आय में वृद्धि
उद्योग	३७४	७६०	३३०	१५३०	६३६	२१६०	६००	४४५०	१८६६
कृषि	११६६	२०	२४२	४००	४८४	६४०	७७४	१२४०	१५००
सेवायें	४८४	४१०	८३	६७०	२१६	२६००	६५४	४२८०	६६६
अवर्गीकृत	१७६		२१	..	२१	..	२२	...	६४
	२२००	१४००	६८६	२६००	१३६०	५७००	२३५०	१०,०००	४३६६

योजना निर्माताओं ने “राष्ट्रीय आय में वृद्धि” की गणना नहीं की ।^१ इस त्रुटि के बारे में उनका यह कहना था कि योजनाकाल की पूरी अवधि में राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होगी, वह नवीन पूँजी के रूप में विनियोजित धनराशि के बराबर

1. The Planners have not calculated “Increase in Income”.
(According to M. K. Shah.)

होगी। व्यावहारिक रूप से यह सुझाव काफी अच्छा एवं महत्वपूर्ण है और योजना के विभिन्न घटनास्थलों पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए यह सर्वोत्कृष्ट है।

योजना के विभिन्न स्थलों पर राष्ट्रीय आय के विकास कार्यक्रमों का पिछले अनुच्छेदों में जो अनुमान किया गया वह निम्न प्रकार था :—

करोड़ रुपये

प्रथम व्यवस्था के विभिन्न कार्यक्षेत्र	१९३१-३२	योजनाओं की समाप्ति तक		
		प्रथम पंचवर्ष	द्वितीय पंचवर्ष	तृतीय पंचवर्ष
उद्योग वगैरे	३७४	७०४	१,३४०	२,२४०
कृषि	१,१६१	१,४०८	१,८६२	२,६६६
सेवाएँ	१,४८४	१७७	७६६	१,४५०
अवर्गीकृत	१७६	१६७	२१८	२४०
	२,२००	२,३८६	४,२४६	६५६६

६—कोलम्बो योजना

(Colombo Plan)

(अ) योजना का जन्म^१—कोलम्बो योजना की उत्पत्ति, जनवरी १९५० में राष्ट्रमण्डल की राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित मध्यमबल्लोय सम्मेलन में हुई। यह सम्मेलन कोलम्बो में हुआ था। इस सम्मेलन ने विभिन्न देशों की सरकारी समस्याओं को सुनाने के लिए एक सलाहकार समिति (Consultative Committee) नियुक्त की जिससे ससार का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो।

इस समिति की बैठक मई, १९५० में आस्ट्रेलिया के सिडनी नगर में हुई; जिसका सभापतिरत्व, आस्ट्रेलिया के विदेशी मामलों के मन्त्री श्री स्पेंडर (Mr. Spender जो अब Sir Percy हैं), ने किया। इस सभा में सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्रमण्डल के समस्त राष्ट्र अपने अपने प्रदेशों के विकास

1. Colombo Plan (Reference paper No. 28, Govt. of Australia, Jan. 1957) Courtesy : The Australian High Commission in India, New Delhi.

के लिये जुलाई सन् १९५१ से ६ वर्षीय योजनाएं बनावें। राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों को भी इस अनुदान में अपना अपना कार्यक्रम पेश करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रकार इन सब योजनाओं को मिलाकर आर्थिक विकास का एक विशद कार्यक्रम तैयार किया गया। इसके साथ ही साथ योजना के कार्यों में तकनीकी क्षमता के विकास एवं उपलब्धि के लिए तकनीकी सहकारी कार्यक्रम को चलाने का निश्चय किया गया।

योजना में निम्नलिखित देश सम्मिलित हैं—आस्ट्रेलिया, ब्रनाडा, भारत, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान और इंग्लैण्ड—मलाया, सिंगापुर, उत्तरी बोर्नियो, ब्रूनई सरावक सघ को मिला कर। ये सब राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं। लेकिन योजना में इस बात का कतई प्रयास नहीं किया गया कि उसमें केवल राष्ट्रमंडलीय देश सम्मिलित हों। योजना का दरवाजा अन्य राष्ट्रों के लिए भी समान रूप से खुला रखा गया है। इसी कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस योजना में सन् १९५१ में प्रवेश किया।

जो देश स्वेच्छापूर्वक योजना में सम्मिलित हुए वे हैं—ब्रह्मा, कम्बोडिया, इण्डो-नेशिया, जापान, लाओस, नेपाल, फिनीपाइन, थाईलैण्ड तथा वियतनाम। इस प्रकार यह योजना एशिया के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व स्थित समस्त देशों में लागू है।

योजना की प्रवृत्ति^१—भारत सरकार की ससदीय सचिव की बैठक में योजना की प्रवृत्ति का जो निरूपण किया गया है वह इस प्रकार है—

कोलम्बो योजना का उद्देश्य—जैसा कि राष्ट्रमण्डल की समझौते में तय किया गया, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के समस्त देशों के आर्थिक विकास के क्षेत्र एवं गति को विकसित करके, उनकी समस्याओं का सामूहिक रूप में हल करके तथा खाद्यान्नों के उत्पादन पर अधिक बल देकर लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना था। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख कर तथा उपलब्ध साधनों के अनुमानों के आधार पर, मलाया सघ, भारत, उत्तरी बोर्नियो, पाकिस्तान तथा सरावक एवं सिंगापुर की सरकारों ने ६ वर्षीय विकास कार्यक्रम की योजनाएं तैयार की। वर्तमान जीवनस्तर को गिरने से बचाने के लिए तथा आगामी विकास की आधार शिला तैयार करने के लिए इन विकास के कार्यक्रमों को करना नितांत आवश्यक है। कुछ मामलों में तो यह कार्यक्रम पूर्व के विकसित कार्यों की सतत वृद्धि के रूप में ही लागू किया गया है।

इस कार्यक्रम की व्यय लागत मुख्य रूप से सार्वजनिक विनियोग से सम्बन्धित है और इसमें अधिकतर व्यय बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास के लिए सिंचाई, जल-विद्युत, यातायात—रेल सड़क, संचाद-वाहन के साधन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य

1. Brochure on Colombo Plan and India's, Progress Towards Planning, —Govt of India, Parliament Secretariate, New Delhi, P.2,

एवं गृह निर्माण जैसे सामाजिक कार्यों पर उन क्षेत्रों में होगा, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

उपर्युक्त समस्त कार्यक्रमों की ६ वर्षों की अवधि के लिए योजना में १८६८ मिलियन पौण्ड के लागत व्यय का अनुमान किया गया था। योजना की रूपरेखा में विभिन्न देशों की विकास सम्बन्धी समस्त आवश्यकताओं का विवेचन नहीं किया गया। अलग-अलग देशों ने इस योजना में अपने-अपने कार्यक्रमों को सम्मिलित किया है, जिनको ६ वर्षों की अवधि में आसानी से पूरा कर सकते हैं।

योजना के अन्तर्गत भारत की प्रगति¹—भारत की ६ वर्षीय विकास योजना कुछ भूल-भूत आर्थिक मान्यताओं के आधार पर प्रतिपादित की गई, जिनमें से बहुतसी कोरिया में गृह-युद्ध छिड़ जाने के कारण समाप्त हो गई।

(१) उदाहरण के तौर पर कोलम्बो योजना के निर्माण के समय भारत ने अपने व्यापार संतुलन में सन् १९५०-५१ के आयात-निर्यात के आधार पर १,४०० मिलियन रु० की कमी (Deficit) का अनुमान लगाया था किन्तु वास्तव में उस वर्ष ६०० मिलियन रुपये का आधिक्य था।

(२) योजना के ६ साल की अवधि के आरम्भ में औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण सितम्बर सन् १९५० से जुलाई १९५१ के बीच में विकास कार्यों के घरेलू लागत व्यय में काफी वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सब मिला कर कीमतों की वृद्धि, अर्थव्यवस्था में सामान्य संतुलन लाने में, काफी सहायक हुई।

(३) योजना में उन प्राकृतिक प्रकोपो एवं दुर्भाग्यपूर्ण अनावृष्टि की स्थिति का विवेचन नहीं हो सका, जिसके कारण सन् १९५१-५२ में हमारे देश के अन्न उत्पादन को भारी आघात पहुँचा। सन् १९५१-५२ में २½ मिलियन टन अन्न के आयात की व्यवस्था की गई, जो आवश्यक है, को देखते हुए काफी कम थी। वास्तविक रूप से, एक नियन्त्रित अन्न पूति की व्यवस्था के आधार पर भी, उम वर्ष ५½ मिलियन टन अन्न की आवश्यकता पड़ी; जिसका परिणाम यह हुआ कि सन् १९५१-५२ में भारत का व्यापार संतुलन काफी गिर गया।

संशोधित छः वर्षीय योजना में लागत व्यय

भारत के लिए संशोधित ६ वर्षीय कार्यक्रम के लिए २३,३३७ मिलियन रुपये की व्यवस्था की गई। यह संशोधन मुख्य रूप से उन विविध खोजों के आधार पर किया गया था, जो योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाते समय सम्भावित व्यय की उल्लिखित के बारे में किया गया था। जुलाई सन् १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रकाशित हुई, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों पर पाँच वर्षों की

1. 'Brochure on Colombo Plan and India's Progress Towards Planning'. Govt. of India, Parliament Secretariate, New Delhi, pp 7-12.

अवधि के लिए १९,४३० मिलियन रुपये की सार्वजनिक व्यय की व्यवस्था की गई। इसमें से १२,७१० मिलियन रुपये घरेलू साधनों द्वारा प्राप्त करने की आशा व्यक्त की गई। विनियोग की दर साथ ही साथ घरेलू व्यय का औसत इस ६ वर्षीय योजना की तुलना में, पंचवर्षीय योजना में अधिक रहा, जिसमें पंचवर्षीय योजना में १५,३४० मिलियन तथा ६ वर्षीय योजना में ८,५६० मिलियन रुपये की व्यवस्था की गई। समस्त योजनाओं की लागत का अनुमान सम १९५० की कीमतों के आधार पर किया गया जिससे मूल्य परिवर्तनों के कारण उनकी लागत में वृद्धि नहीं हुई। इस लागत वृद्धि का कुछ भाग नए कार्यक्रमों को सम्मिलित करने तथा कुछ पुराने चालू कार्यक्रमों को पूरा करने के कारण हुआ। किन्तु इस लागत व्यय की वृद्धि का अधिकांश भाग मुख्य रूप से लेखा जोखा रखने की प्रवृत्ति (Nature of Book-keeping) के कारण हुआ। यह उतना यथार्थ नहीं जितना कि स्पष्ट है। योजना के बनते समय उन समस्त कार्यक्रमों को जो पहले से चालू थे और जिनको चालू रखना आवश्यक था निकाल दिया गया, किन्तु बाद में पंचवर्षीय योजना में उन कार्यक्रमों को सम्मिलित कर लिया गया।¹

नीचे की तालिका में इस ६ साली योजना के वास्तविक तथा सशोधित व्यय का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि कृषि और सिंचाई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपयोगी कार्यक्रम है, पर पूर्ववत् ही ध्यान दिया गया। बहुउद्देश्यीय नदी घाटी योजनाओं की लागत में सशोधित वर्गीकरण के आधार पर कटौती की गई। इसी प्रकार उद्योग यातायात एवं सबाद बाहन के साधनों की लागत में भी कटौती की गई। इस प्रकार बचाए हुए साधनों की बड़ी मात्रा का उपयोग ईंधन और शक्ति के विकास के लिए किया गया जिससे ऊनर उद्योग, यातायात एवं सबाद बाहन के साधनों की उन्नति निभर है। सामाजिक निर्माण कार्यों के व्यय में जो वृद्धि हुई, वह मुख्य रूप से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के उन कार्यक्रमों को पूरा करने के कारण हुई जिनके बारे में प्रस्तावित ६ वर्षीय योजना में पूर्ण विज्ञप्ति नहीं थी।

छ. वर्षीय योजना के प्रस्तावित तथा सशोधित व्यय

व्यय की मदें कृषि तथा सिंचाई	१९५० की विज्ञप्ति के अनुसार अनुमानित लागत व्यय		मिलियन रुपया कुल सशोधित व्यय	
	कुल लागत	कुल का प्रतिशत	कुल लागत	कुल का प्रतिशत
	३,५७४ १	१६.४	३,६८१ १	१७ १

1 इसमें १५०० मिलियन रुपये की वह धन राशि भी सम्मिलित है। जो ६ साली योजना के अन्तर्गत रेलों के टूट-फूट के कार्यों पर व्यय की गई लेकिन योजना आयोग ने इसको पंचवर्षीय योजना के लागत व्यय में सम्मिलित नहीं किया।

सिंचाई एवं विद्युत आदि

सम्बन्धी बहुउद्देश्यी नदी

योजनाएँ	२,५०५.५	१३६	२,२८४.१	६.८
यातायात व सवादा वाहन	७,०२७.४	३८.२	६,५१५.४	२७.६
ई धन एवं शक्ति	५७५.६	३.२	१,४४३.४	६.२
उद्योग एवं खान	१,७६६.८	६.७	१,२३६.६	५.३
सामाजिक निर्माण कार्य				
तथा अन्य	२,६१२.७	१५.६	४,२६६.८	१८.३
अनिर्धारित ^१	३,६०० =	१५.४
	१८,३६५.४	१००.०	२३,३३६.७	१००.०

पंचवर्षीय योजना तथा छ वर्षीय (कोलम्बो) योजना की तुलना

कोलम्बो योजना तथा पंचवर्षीय योजना के कुछ कार्यक्रमों में रद्दोबदल हो जाने के कारण उनकी सही रूप से तुलना करना सम्भव नहीं है। उदाहरण के तौर पर कोलम्बो योजना में ६ साल की अवधि में रेलों के बिकाम के लिए १५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, किन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए अलग से व्यवस्था की गई और पाँच वर्षों की अवधि के कुल व्यय में इसको सम्मिलित नहीं किया गया। इसी तरह से कृषि, ई धन एवं विद्युत-शक्ति के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का भी पुनर्निर्धारण हुआ, इस कारण दोनों योजनाओं के लागत व्यय की तुलना नहीं की जा सकती।

दोनों योजनाओं के आन्तरिक वितीय साधनों की तुलना करना कठिन है, इसमें मुख्य कठिनाई वर्गीकरण के कुछ परिवर्तनों के कारण आई। इस प्रकार जहाँ कोलम्बो योजना में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के चालू खाते के अन्तर्गत ४६० करोड़ रुपये की धनराशि आँकी गई और ११० करोड़ रुपये सावजनिक व्यय में बचत करके प्राप्त हुआ; वहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की आय लागत में २४१ करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। राज्य सरकारों के आय खाते में, २१३ करोड़ रुपये की कर द्वारा प्राप्त आय पर, ८१ करोड़ रुपये बचत के रूप में प्राप्त हुआ।

आगे की तालिका में इस 'नवीन' योजना को प्राप्त आन्तरिक आय के स्रोतों का वर्गीकरण किया गया है—

1. इस मद की लागत का अधिकांश उपयोग विदेशी विनिमय की उपलब्धि पर निर्भर है। अतः उस कार्यक्रम को योजना द्वारा बाद में प्रकाशित किया जाएगा।

केन्द्र	करोड़ रुपये
१—'संगान खाते' पर अतिरिक्त आय (बचत)	१३०
२—(सिविल एविएशन) प्रसारण, शिक्षा आदि, 'पथिक ग्रन्थ उपजाओ आन्दोलन' तथा बेघरवार लोगों को बसाने आदि विकास कार्यों के लिए दी गई राज्य सरकारों की सहायता के लिए Revenue Account में से निर्धारित किये हुए आय के साधन	११८
३—विकास कार्यों के लिए निश्चित पूँजीगत आय के साधन—	
(अ) सार्वजनिक ऋण	३५
(ब) छोटी २ बचतें व अप्रাপ्त कर्ज	२५०
(स) विविध	७८
४—रेलो की सामान्य आमद में से रेलों के विकास के लिए निर्धारित आय के साधन	३०
५—केन्द्रीय सरकार को प्राप्त कुल आय के साधन	६४१
६—राज्य योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता	२११
७—केन्द्रीय विकास व्यय के लिए प्राप्त आय व साधन	४३०
राज्य	
८—कुल आमद पर प्राप्त अनिश्चित (बचत)	८१
९—कृषि, सिंचाई, जल-विद्युत, मृदक तथा सामाजिक सेवा आदि कार्यों के लिए कुल आमद में निर्धारित आय के साधन	२७५
१०—विकास कार्यों के लिए निश्चित पूँजीगत आय के साधन	
(अ) सार्वजनिक ऋण, तथा	७६
(ब) धन्य	४५
११—केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता (राज्य योजना के अन्तर्गत)	२११
१२—राजकीय विकास व्यय के लिए प्राप्त आय साधन	६६१

कुल व्यय

जहाँ तक व्यय का सम्बन्ध है कृषि, सिंचाई एवं जलविद्युत के लिए कोलम्बो योजना में समान रूप में बल दिया गया है लेकिन उनके कार्यक्रमों में थोड़ी सी घटा बढी कर दी गई है। यद्यपि योजना काल में रेलों के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए अलग व्यवस्था की गई, फिर भी अधिकांश मामलों में व्यय की राशि में संशोधन कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप जहाँ योजना में ६ वर्षों के कार्यक्रम के लिए १,८४० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई वहाँ नवीन पंचवर्षीय आयोजन में १,७६३ करोड़ ६० खर्च हुआ। दूसरे शब्दों में,

नवीन पञ्चवर्षीय आयोजन में छ वर्षीय कोलम्बो योजना की अपेक्षा १०० करोड़ रुपया अधिक खर्च हुआ ।

विदेशी सहायता—कोलम्बो योजना की तरह, जिसकी एक तिहाई वित्त की आवश्यकता विदेशी सहायता से पूरी हुई, नवीन पञ्चवर्षीय योजना को दो भागों में विभक्त किया गया । योजना के प्रथम भाग का कुल व्यय १४६३ करोड़ ६० था जिसमें वे कार्यक्रम भी सम्मिलित थे जो पहले के शुरू किए हुए थे तथा जिनको बिना विदेशी सहायता मिले भी पूरा करना आवश्यक था । बचे हुए ३०० करोड़ ६० की धन राशि दूसरे भाग के विकास कार्यों के लिए रखी गई, जो पूर्णरूप से विदेशी सहायता की प्राप्ति पर निर्भर थी । प्रथम भाग की विदेशी सहायता की निर्भरता को कम करने के लिए, कोलम्बो-योजना के कार्यक्रमों को निकाल कर अथवा उनके महत्त्व को कम करके कुछ नये तथा महत्त्वपूर्ण कार्यों को सम्मिलित कर लिया गया । कोलम्बो योजना के सम्बन्ध में स्थित 'कोमाना कार्यक्रम को नवीन योजना से निकाल देना, इसका ज्वलत उदाहरण है और हमारे उपर्युक्त कथन की पुष्टि करता है ।

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कुछ मिलाकर यद्यपि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अधिक विस्तृत रही तथा विभिन्न कार्यक्रमों की लागत को देखते हुए इसके परिणाम बहुत सुनिश्चित एवं आगामी नियोजन की पृष्ठभूमि के रूप में हुए, फिर भी दोनों योजनाओं की रूपरेखा समान रही । वास्तविक रूप से, योजना आयोग के शब्दों में "प्रथम पञ्चवर्षीय योजना पाँच वर्षों की अवधि में ६ वर्षों के कार्यक्रम को पूरा करने की सूची है ।"

प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलताएँ तथा असफलताएँ (Achievements And Pitfalls of the First Five Year Plan)¹

१—उद्देश्य और पहुँच (Objectives And Approach)

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे—

१. युद्ध तथा देश के बँटवारे से उत्पन्न आर्थिक विपमता को दूर करना ;
२. बहुमुखी उपजति का समुचित विवरण तैयार करना—जिससे कि

राष्ट्र की आय में वृद्धि हो तथा एक निश्चित काल में रहन-सहन का स्तर उन्नत हो जाय। योजना में जहाँ एक ओर इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया था कि पूँजी का विनियोग इस प्रकार का हो, जिससे कि उपलब्ध साधनों द्वारा तत्कालीन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, वहाँ दूसरी ओर इस बात का भी विवेचन किया गया था कि आगे आने वाले समय में इन साधनों का समुचित विकास हो सके तथा वे अधिक से अधिक गतिशील बनें। यह सब एक लम्बे समय की पृष्ठभूमि के आधार पर किया गया था। साथ ही इस बात की भी पूर्ण विवेचना कर दी गई थी कि नियोजन की प्रगति के साथ वर्तमान सामाजिक आर्थिक दशाएँ भी प्रगतिशील हो जायें और सविधान की प्रजातन्त्रात्मक नीति निर्धारण के आधार पर नियोजन का कार्यक्रम चलाया जाय। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना नवीन दिशा के लिए एक ऐसी कार्यवाही थी जिसके अनुसार राज्य विकास की ओर उन्मुख हो तथा आर्थिक क्षेत्र के विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर सामंजस्य स्थापित हो जाय।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण काल की आर्थिक स्थिति बड़ी विपम थी तथा पूँजी के विनियोग के लिए समुचित साधनों की कमी थी। अन्न का अभाव था। कच्चे माल की भारी कमी थी। कारखानों में उनकी क्षमता के अनुसार उत्पाति नहीं हो रही थी। यातायात की दशा बड़ी दयनीय थी। बड़ी संख्या में सीमा पार कर आए हुए विस्थापित लोगो ने एक नई उलझन पैदा कर दी थी और उनके पुनर्वास की समस्या ने हमारे देश की सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दशा को और भी अधिक जटिल बना दिया था।

जून १९५० में कोरिया में युद्ध छिड़ जाने के कारण तथा पैदावार कम हो जाने के कारण अन्न की महंगाई बढ़ गई थी, जिसके कारण अकाल की स्थिति हो गई थी। १९५१ में अन्न की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ४७ लाख टन अन्ने का आयात किया जिससे विदेशों मुद्रा की कठिनाई उपस्थित हुई और हमारा व्यापार सतुलन बिगड़ गया, जिसके फलस्वरूप मुद्रा प्रसार करना पड़ा और कीमतें इतनी बढ़ गई कि उनको कम करना कठिन हो गया। १९३९ ई० की तुलना में मार्च १९५१ में कीमतों का स्तर चार गुने से भी अधिक हो गया अर्थात् १९३९ में थोक वस्तुओं का जो निर्देशनाङ्क १०० था, वह मार्च १९५१ के अन्त में ४६० हो गया। १९५१-५२ में व्यापार सतुलन बिगड़ जाने के कारण देश के व्यापार खाते में १६३ करोड़ रु० का घाटा रहा। युद्ध के उपरान्त किए गए विभिन्न विकास कार्यों के लिए वित्त की कमी पड़ी। राज्य द्वारा किये गए विकास कार्यों तथा केन्द्र द्वारा किये गए विकास कार्यों में भी सामंजस्य न रह सका महाँ तक कि बहुत से नव निर्मित राज्यों की सरकारें तो जन कल्याण के साधारण कार्य करने में भी असफल रही। इस प्रकार कहना न होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा ही सर्वप्रथम देश का अर्थव्यवस्था की मूलभूत आवश्यकताओं तथा उपलब्ध साधनों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई।

प्रस्तुत सूची योजना के विभिन्न मुख्य मदों पर पाँच साल में किये गए तथा निर्धारित खर्च का विवरण प्रस्तुत करती है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास की विभिन्न मदों पर
कुल प्रस्तावित तथा निर्धारित व्यय^१

व्यय के प्रकरण (मदें)	कुल प्रस्तावित व्यय		कुल निर्धारित व्यय	
	करोड़ रुपया	प्रतिशत	करोड़ रुपया	प्रतिशत
१ कृषि तथा समुदाय विकास सम्बन्धी	३५४	१४.६	२६६	१४.८
(अ) कृषि कार्यों पर	२४६	१०.५	२२७	११.३
(ब) सामुदायिक कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाएँ	६०	३.८	५७	२.८
(स) स्थानीय विकास कार्य	१५	०.६	१५	०.७

२. सिंचाई तथा शक्ति (विजली) पर	६४७	२७२	५८५	२६१
(अ) बहुउद्देशीय योजनाओं पर	२५६	१०८	२४१	१२०
(ब) सिंचाई योजना	२१३	६०	१६१	६५
(स) विजली योजनाएँ	१७८	७४	१५३	७६
३. उद्योग तथा खनिज	१८८	७६	१००	५०
(अ) कुटीर तथा लघु उद्योग पन्धे	४६	२१	४४	२२
(ब) बड़े पैमाने के उद्योग तथा खोज कार्य	१३६	५८	५६	२८
४. यातायात तथा सवाद वाहन	५७१	२४०	५३२	२६४
(अ) रेलें	२६७	११२	६७	१३३
(ब) सड़कें व सड़क यातायात	१४७	६२	१४७	७१
(स) अहान, बन्दरगाह व अन्य यातायात पर	६७	४१	७१	३५
(द) डाक तार, संचार तथा सवाद वाहन पर	६०	२५	४७	२३
५. सामाजिक सेवाएँ	५३२	२२४	४२३	२१०
(अ) शिक्षा	१७०	७२	१५३	७६
(ब) स्वास्थ्य	१३८	५८	१०१	५०
(स) गृह निर्माण	४६	२१	३५	१७
(द) श्रम, श्रमकल्याण तथा पिछड़े वर्ग का कल्याण	३६	१६	३७	१८
(५) पुनर्वास	१३६	५७	६७	४८
६. अन्य	८६	३६	७४	३७
कुल योग	२,३७८	१,०००	२,०१३	१,०००

उत्पादन तथा अन्य विकास कार्यों का जो सक्षम योजना में निर्धारित किया गया था वह केवल सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय से ही सम्बन्धित नहीं था अपितु निजी क्षेत्र के कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों के संचालन से भी सम्बन्धित था। योजना में इस क्षेत्र के लिए निर्धारित नियमितताओं का भी उल्लेख किया गया था तथा साथ ही उत्पादन की वृद्धि के लिए विकास नीति का भी उल्लेख किया गया था। निजी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए मांगी गई कुल पूँजी विनियोग की राशि २३३ करोड़ रु० आंकी गई थी। उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित विनियोग की प्रगति योजना के प्रारम्भ में ही प्राप्त हो गई थी। सगठित उद्योगों के लिए निर्धारित विनियोग दर जो प्रथम दो वर्षों में २६ करोड़ रु० प्रति वर्ष थी वह तीसरी साल में ४४ करोड़ रु० हो गई, और चौथी तथा पाँचवीं साल में क्रमशः

५० करोड़ रु० तथा ८१ करोड़ रु० तक हो गई । इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र के लिए योजना में निर्धारित परिणाम, अत्यधिक सतोषप्रद रहे ।

२—उत्पादन की प्रवृत्ति

(Production Trends)

योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से देखें तो योजना की उपलब्धियाँ काफी उत्साहवर्धक रही । निम्न तालिका में कुछ प्रमुख क्षेत्रों में हुए योजना के शुरू तथा अन्त के उत्पादन स्तर को दिखाया गया है ।

उत्पादन के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की सूची

१९५०-५१ व १९५५-५६

उत्पादन के कार्य

प्रतिशत वृद्धि

१९५०-५१ १९५५-५६ १९५१-५६

१—कृषि उत्पादन

१—खाद्य सामग्री (१० लाख टन)	५०.०	६४.८	२६.६
२—कपास (लाख गॉडे)	२६.१	४०.०	३७.५
३—जूट (" ")	३२.८	४२.०	२८.०
४—गन्ना गुठ के रूप में (लाख टन)	५६.२	५८.६	४.३
५—तिलहन (" ")	५०.८	५६.६	११.४
६—तम्बाकू (" ")	२.५७	२.५६	०.८
७—चाय (१० लाख पीण्डो में)	६०.७	६६.८	१०.५
८—मालू (हजार टन)	१६३.४	१८३.६	१२.५

२—औद्योगिक उत्पादन

१—पक्का लोहा (हजार टन)	६७.६	१२७.४	३०.५
२—कच्चा लोहा (" ")	१५७.२	१७८.७	१३.७
३—सीमेंट (" ")	२६८.६	४५६.२	७०.८
४—उर्वरक (Fertilisers)			
(अ) रासायनिक खाद (हजार टन)	४६	३६.४	७५.६.५
(ब) हड्डी आदि की खाद (" ")	५.५	७.१	२६.१
५—(Locomotives) लोकोमोटिव (नादाद)	३	१७.६	
६—मशीन, यन्त्र (लाख)	३३.६४	७८.५४	१३३.५
७—डीजल इंजन (संख्या)	५५३.६	१०३६.६	८७.३
८—Automobiles (नंबर)	१६५.१६	२५२.७२	५३.०
९—Cables & wires A. C. S. R. Conductors (टन)	१३४.६	६७३.०	५४७.१

१०—अलमोनियम (टन)	३६७७	७३३३	६६४
११—सूत उत्पादन			
(अ) Yarn (१० लाख पौण्ड)	११७६	१६३३	३६'०
(ब) मिल का कपडा („ गज)	३७१८	३१०२	३७ २
(स) हाथ करघा वस्त्र („ „)	८१०	१४४६	७६'०
१२—जूट उत्पादन (हजार टन)	८२४	१०५४	२८'०
१३—साईकिलें (हजार में)	१०१	५१३	४०७ ६
१४—सीने की मशीन („ „)	३३	१११	२३६'०
१५—बिजली के लट्टू („ „)	१५०००	२४२२८	६१'०
१६—अल्कोहल (१० लाख गैसन)	५'०	१०'४	१०८'०
१७—घीनी (हजार टन)	१०६४	१७०१	५६'६
१८—वनस्पति („ „)	१५३	२७६	८०'४
१९—कागज तथा दफती („ „)	११४	१८७	६४'०
२०—चमड़े के जूते (हजार जोड़ा)	५१६५	५६६५	६'०
(नए और पुराने ढग के)			

(१) कृषि-उत्पादन

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में कृषि के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। योजना के अन्तिम वर्ष में (सन् १९५५-५६ में) अन्न का कुल उत्पादन ६४'८ मिलियन टन था जो योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ३ मिलियन टन अधिक था। कृषि उत्पादन में क्रान्तिकारी परिवर्तन सन् १९५३-५४ में हुए जबकि अन्न का कुल उत्पादन ६८'८ मिलियन टन था जो पाँच वर्ष के औसत उत्पादन में सबसे अधिक था। इसके बाद सन् १९५४-५५ में भी अन्न का उत्पादन ६६'८ मिलियन टन था जो निर्धारित लक्ष्य में अधिकतम ही था। तिलहन, जूट और कपास के उत्पादन में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई किन्तु उत्पादन की मात्रा प्रतिवर्ष घटती बढ़ती रही। १९४२-५० के कृषि उत्पादन निर्देशनाङ्क को १०० मान कर अगर तुलना करें तो हम देखते हैं कि जो निर्देशनाङ्क १९५०-५१ में ६५'६ था वह १९५३-५४ में बढ़ कर ११४'३ तथा १९५४-५५ में ११६'४ हो गया। यद्यपि योजना के अन्तिम वर्ष में अन्न का उत्पादन १९५४-५५ की तुलना में काफी गिर गया था फिर भी प्रथम वर्ष (१९५०-५१) की तुलना में इसमें १६% की वृद्धि हुई जो आशा से अधिक थी।

(२) औद्योगिक उत्पादन

औद्योगिक उत्पादन में भी तीव्र गति में वृद्धि हुई। प्रारम्भिक साल की तुलना में योजना के अन्तिम वर्ष में यह वृद्धि ४० प्रतिशत थी। यह वृद्धि केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित न थी अपितु सभी प्रकार के कारखानों द्वारा तैयार माल के उत्पादन में वृद्धि हुई। मिल द्वारा बने हुए कपड़े का जो उत्पादन सन् १९५०-५१

मे ३७१८ मिलियन गज था वह १९५५-५६ में बढ़कर ५१०२ मिलियन गज हो गया । यह योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ४०० मिलियन गज अधिक था । चीनी, कपड़े, सिलाई की मशीनो कागज व कागज की दफ्ती (Paper Board) तथा साइ-किलो के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो गया था । वस्तु कहना यह चाहिए कि कुछ एक क्षेत्रों में तो उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ । १९५०-५१ में सीमेंट का उत्पादन २७ मिलियन टन था जो १९५५-५६ में ४६ मिलियन टन हो गया । इसके साथ ही मशीनो के बल पुर्जे बनाने वाले कारखानो तथा बड़ी-बड़ी मशीन बनाने वाले कारखानो के उत्पादन में भी वृद्धि हुई । कुछ नई वस्तुओं का भी उत्पादन शुरू किया गया और उनके उत्पादन में हमें भाशा से अधिक सफलता मिली । इनके लिये कुछ नये कारखाने, जैसे पेट्रोल साफ करने का कारखाना, जहाज बनाने का कारखाना, रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना, पेन्सिलीन बनाने का कारखाना, रासायनिक पदार्थों की उत्पत्ति का कारखाना तथा कोटाणु नासक दवा (D.D.T.) बनाने का कारखाना, आदि की स्थापना हुई । सार्वजनिक क्षेत्र में मिर्दरी का खाद बनाने का कारखाना (Sindri Fertilizer Factory), चित्तारजन का रेलव इंजन बनाने का कारखाना (Chittaranjan Locomotive Works), टेलिफोन फैक्टरी तथा 'इन्टीगल कोच फैक्टरी' में भी मन्तोपजनक प्रगति की ।

आर्थिक निर्माण कार्य — (Economic overheads)

योजना काल में १६३ मिलियन एकड़ भूमि को सिंचित करने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से ६३ मिलियन एकड़ भूमि मिर्चाई के बड़े बड़े साधनों द्वारा सींची गई तथा करीब १० मिलियन एकड़ भूमि छोटे छोटे साधनों द्वारा सींची गई । विजली उत्पादन की क्षमता २३ मिलियन किलोवाट में बढ़कर ३४ मि० किलोवाट होगई । रेलवे यातायात में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई । योजना में १०३८ रेल के इंजन बनाने के, ५६७४ रेल के डिब्बे (coaches) तथा ४९,१४३ माल गाडी के डिब्बे बनाने की व्यवस्था थी किन्तु योजना की समाप्ति पर १५८६ इंजन, ४७५८ डिब्बे तथा ६१,२५७ माल के डिब्बो का निर्माण हुआ । इसके साथ ही साथ योजना के बाहर १९५१-५२ से १९५५-५६ के बीच में २७ से लेकर १७८ इंजन, ३७०७ से लेकर १४,३१७ माल के डिब्बो तथा ६७३ से लेकर १२-१ सवारी डिब्बो का अतिरिक्त उत्पादन हुआ । ४३० मील लम्बी रेलवे लाइनों को पुनः नये समूह में संरक्षित हो गई थी उनका पुनरुत्थान हुआ, ३८० मील लम्बी नई रेलवे लाइनें बनाई गई । ४६ मील लम्बी छोटी लाइना का विस्तार किया गया ।

सड़क निर्माण तथा सड़क यातायात का कार्यक्रम योजना के साथ साथ पूरा हो गया ।

आर्थिक निर्माण कार्यों के लिए योजना में जो रकम निश्चित की गई थी, वह योजना की समाप्ति तक प्राप्त होने वाली अनुमानित आय के अनुसार निश्चित

की गई थी। योजना-काल में इन मंडों पर जो धन व्यय किया गया था वह वास्तविक अनुमानित लागत से कुछ कम ही हुआ और उससे प्राप्त परिणाम भी ८० % से ८५ % तक ही हो सके। इस प्रकार यहाँ पर यह कह देना अनुचित न होगा कि योजना में जो कुछ लागत निश्चित की गई थी, वह अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई जरूरतों को देखते हुए, बहुत कम थी। रेल मार्गों के पुनर्निर्माण का कार्य भी मुख्य रूप से पुनर्व्यवस्थापन का कार्यक्रम ही था। नई रेल लाइनों के विकास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। दक्षिण के साबुनों का विकास भी बिजली की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए कुछ ही अंशों तक सतोपप्रद था। योजना में खनिज पदार्थों (Mineral resources) के विकास को और बहुत कम ध्यान दिया गया। जहाजरानी उद्योग के विकास के बारे में भी लापरवाही बरती गई तथा योजना में जहाज निर्माण के लिए जो कुछ थोड़ी बहुत रकम निश्चित की गई थी उसमें भी कटौती की गई। इस प्रकार इन आर्थिक कार्यों के विकास के सम्बन्ध में योजना का कार्य सतोपजनक नहीं रहा। सामाजिक सेवाएँ (Social Services) —

योजना की अवधि में सामाजिक सेवाओं का विस्तृत रूप से बढ़ाने का कार्यक्रम रखा गया। १९५०-५१ में स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों की कुल संख्या १८७ मिलियन थी, जो १९५५-५६ में बढ़ कर २४८ मिलियन हो गई अर्थात् ३२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। ६ वर्ष से ११ वर्ष की बीच के आयु वाले बच्चों की जो संख्या १९५०-५१ में ४२ प्रतिशत थी वह १९५५-५६ में ५१ प्रतिशत हो गई। ११ वर्ष से १४ वर्ष की आयु के पढ़ने वाले बच्चों की संख्या १३९ प्रतिशत (१९५०-५१) से १९५५-५६ में १९२ प्रतिशत हो गई। प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए योजना काल में अनेक प्रशिक्षण संस्थायें खोली गईं। योजना काल में स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद इंजीनियरी और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या २२०० से ३७०० हो गई और 'डिप्लोमा' लेने वालों की संख्या २७०० से ४००० हो गई। जहाँ एक ओर सामुदायिक विकास कार्यों तथा राष्ट्रीय प्रचार सेवाओं को बढ़ाने के लिए १४००० ग्राम सेवक (Village Level Workers) को कृषि, सहकारिता तथा ग्राम विकास कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया, उनके साथ दूसरी ओर ग्राम लेवल वर्कर्स (Village Level Workers) के लिए भी प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये, जिनमें से १८५० मनुष्यों को त्रिरीक्षण-त्मक प्रशिक्षण दिया गया। लघु तथा कुटीर उद्योग-वन्धों के विकास के लिए भी प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान की गईं। जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में अस्पतालों तथा भण्डारणों (Hospital & Dispensary) की संख्या में विशेष वृद्धि नहीं हुई, फिर भी मलेरिया तथा हैजा आदि बीमारियों को रोकथाम के लिए व्यापक रूप से कार्य किए गए। इस प्रकार सामाजिक कार्यक्रमों के विकास में कुल मिलाकर, अंशतः रूप से योजना सफल रही।

राष्ट्रीय आय (National Income) — योजना में राष्ट्रीय आय के सम्पूर्ण परिणाम निम्न तालिका से प्रदर्शित किये जाते हैं :—

सन् १९४८-४९ की कीमतों के आधार पर मुख्य मदों से प्राप्त कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय (Rs. Abja)^१

मदें	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०
१—कृषि, पशु धन तथा ग्रन्थ सामान्य कृषि क्रियाएँ	४३.४	४६.०	४४.४	४६.०	४६.०	४६.०	४६.०	४६.०	४६.०	४६.०	४६.०	४६.०
२—खान, शिल्पकारी तथा अन्य छोटे उद्योग	१४.८	१५.२	१५.२	१५.२	१५.२	१५.२	१५.२	१५.२	१५.२	१५.२	१५.२	१५.२
३—धानपार, यातायात तथा सवाद वाहन के साधन	१६.६	१७.३	१७.३	१७.३	१७.३	१७.३	१७.३	१७.३	१७.३	१७.३	१७.३	१७.३
४—ग्रन्थ सेवा कार्य	१३.६	१४.३	१४.३	१४.३	१४.३	१४.३	१४.३	१४.३	१४.३	१४.३	१४.३	१४.३
५—कम लागत पर ग्रन्थ घरेलू उत्पादन	८८.७	९१.२	९१.२	९१.२	९१.२	९१.२	९१.२	९१.२	९१.२	९१.२	९१.२	९१.२
६—प्रतिध्वित्त श्रौतत ग्राम (२०)	२४६.३	२४०.१	२४०.१	२४०.१	२४०.१	२४०.१	२४०.१	२४०.१	२४०.१	२४०.१	२४०.१	२४०.१
७—जनसंख्या करोड़ों में	३५.९३२	३६.३३५	३६.३३५	३६.३३५	३६.३३५	३६.३३५	३६.३३५	३६.३३५	३६.३३५	३६.३३५	३६.३३५	३६.३३५

१. Abja = 100 crores

२. Preliminary

योजना काल के पाँच वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय आय में १७.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि तथा सहायक (ancillary activities) उद्योगों के उत्पादन में १४.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। खान (mining), शिल्पकारी तथा अन्य छोटे-छोटे उद्योगों के उत्पादन में १८.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यातायात, व्यापार तथा संचार वाहनों के उत्पादन में १८.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९५३-५४ में कृषि का शुद्ध उत्पादन अधिक रहा। यद्यपि १९५३-५४ की तुलना में यह वृद्धि नाममात्र की (nominal) ही रही। दूसरी ओर अन्य क्षेत्रों के उत्पादन में भी आना में अधिक उन्नति हुई। इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़ी मात्रा के उद्योगों में, विद्युत सारों को देखते हुए, इन पाँच वर्षों में काफी वृद्धि हुई, फिर भी कुल राष्ट्रीय उत्पादन में, इनका उत्पादन कृषि उत्पादन की तुलना में बहुत कम रहा। यद्यपि कुल राष्ट्रीय आय की मात्रा में सन्तोषजनक वृद्धि हुई, किन्तु औसत रूप से यह वृद्धि तीव्रगति से नहीं हुई। उदाहरण के तौर पर १९५३-५४ और १९५४-५५ में राष्ट्रीय उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण अधिकतम कृषि उत्पादन था। इसी प्रकार कृषि उत्पादन की वृद्धि के फलस्वरूप ही प्रथम योजना के तीसरे वर्ष में भी राष्ट्रीय आय में १३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्तिम दो वर्षों में वृद्धि की दर काफी घट गई और १९५५-५६ में तो वृद्धि की दर नाममात्र की (nominal) रही। योजना के आंकृत (record) के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत आय में १०.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

यहाँ पर यह कह देना असंगत न होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय के औसत उपभोग में बहुत कम वृद्धि हुई, अर्थात् आय का औसत उपभोग केवल ८ प्रतिशत ही रहा—जो योजना के इतने बड़े विकास के लिए निर्धारित व्यय और लागत को देखते हुये बहुत कम था। योजना के अन्तिम दो वर्षों के उपभोग व्यय को देखा जाय तो हम देखते हैं कि सन् १९५३-५४ के उपभोग के स्तर (level of consumption) में नहीं के बराबर वृद्धि हुई। खाद्यान्न का जो उपभोग सन् १९५०-५१ में १२.६ औंस प्रति व्यक्ति प्रति दिन था वह १९५५-५६ में १४.४ औंस प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गया और कपड़े का उपभोग, जो १९५०-५१ में ६.७ गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था (जो बहुत कम था) १९५५-५६ में १६.४ गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गया। चीनी का उपभोग जो १९५०-५१ में ०.३७ औंस प्रति व्यक्ति था, वह बढ़ कर सन् १९५५-५६ में ०.५७ औंस प्रति व्यक्ति हो गया। औद्योगिक वस्तुओं के उपभोग में आसानी से उन्नति हुई। उदाहरण के तौर पर लालटेन, साइकिल, सीने की मशीन, बिजली के बल्ब, रेडियो, तथा लाउड स्पीकर आदि की उत्पत्ति में काफी वृद्धि हुई।

३—विनियोग तथा उत्पत्ति (Investment and Output)

योजना में विनियोगों की दर ५ प्रतिशत से बढ़ कर ७ प्रतिशत कर देने का

विचार था, जिससे कि राष्ट्रीय आय और विनियोग में सामंजस्य स्थापित हो जाय। पाँच वर्षों में विनियोग की कुल रकम ३५००-३,६०० करोड़ रुपये आंकी गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में विनियोग की रकम १५०० करोड़ रु० थी जब कि निजी क्षेत्र (Private Sector) में विनियोग की कुल रकम १६०० करोड़ रु० के लगभग थी। कुल मिला कर ३१०० करोड़ रुपया के विनियोग की व्यवस्था की गई। योजना के अन्त में विनियोग का यह स्तर (level-of investment) सन् १९५०-५१ की तुलना में प्रायः दुगुना हो गया।

सार्वजनिक क्षेत्र में ५० प्रतिशत से अधिक विनियोग योजना के अन्तिम दो वर्षों में हुआ। निजी क्षेत्र के विनियोग का स्तर भी इन्हीं वर्षों में अधिक रहा। इस प्रकार विनियोग के अनुसार योजना के दो मुख्य पहलू (Phases) थे। प्रथम पहलू में १९५१-५२ के विनियोग को सम्मिलित करते हुए भी सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में विनियोग बहुत कम रहा जब कि दूसरे पहलू में विनियोग में आश्चर्यजनक अभिवृद्धि हुई। देखने में यह आया कि १९५३-५४ में उत्पादन बहुत अधिक हुआ किन्तु उसके बाद उत्पत्ति की वृद्धि की दर में काफी कमी हो गई। इसका मुख्य कारण योजना के अन्तिम वर्षों में हुई मूल्य वृद्धि का होना था।

राष्ट्रीय उत्पादन (National output)—यहाँ पर यह कह देना असंगत न होगा कि बहुत कुछ विनियोगों के परिणाम योजना के अन्तिम वर्षों में ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि विनियोग करने और उत्पादन होते में कुछ समय लगता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि योजना काल में उत्पादन में जो वृद्धि हुई वह भाग्यवशत (Fortuitous) थी। योजना की रूपरेखा तैयार करते हुये कहीं कहीं तो इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि एक ऐसी सुव्यवस्थित तथा सुस्थिर अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा जो आगे आने वाली योजनाओं का आधार (base) बन सके। इन सब बातों से यह प्रकट होता है कि प्रथम योजना काल में जो वृद्धि हुई वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से काफी महत्वपूर्ण थी—वह वास्तव में आगे आने वाले समूचे आर्थिक विकास के लिये अपने आप में शुरुआत की आधार शिला के रूप में थी। अथवा प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत के क्रमबद्ध आर्थिक विकास का प्रारम्भिक परीक्षण कहा जाना चाहिये।

१९५३ में शहरो में रोजगार की दशा विशेष रूप से शोचनीय हो गई, जिसने कि योजना निर्माताओं को इस बात के लिए विवश कर दिया कि योजना की वास्तविक लागत में, जो शुरू में २,०६६ करोड़ रुपया रखी गई थी, ३०० करोड़ रुपये की और वृद्धि की जाय। यद्यपि रोजगार की इस कमी को दूर करने के लिये बहुत से सफल प्रयोग नियोजित किए गए; और इन प्रयोगों पर किए गये व्यय का दबाव भी सीमित रहा, सार्वजनिक व्यय भी सीमित रहा, निजी क्षेत्र में विनियोग दर भी ऊँची रही फिर भी इन प्रयोगों और कार्यों के द्वारा रोजगार की समस्या को

दूर नहीं किया जा सका बल्कि बेरोजगारी में उल्टी वृद्धि हुई। योजना की अवधि में इन रोजगार के दफ्तरों (Employment Exchanges) में रोजगारों के नाम लिखे जाने वाले रजिस्ट्रो में निरन्तर वृद्धि होती रही। मार्च १९५१-५२ में बेरोजगारी की जो संख्या ३,३७,००० थी वह मार्च १९५५-५६ में बढ़ कर ७,०५,००० हो गई। रोजगार के यह आँकड़े केवल शहरी बेरोजगारी से सम्बन्धित हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी की इनमें कोई गणना नहीं है।

योजना आयोग (Planning Commission) द्वारा की गई जाँच पड़ताल से पता चलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में सब मिला कर रोजगार के काफी अवसर प्रदान किए गये, और योजना के अन्त तक उनमें निरन्तर वृद्धि होती रही। यह एक अलग बात है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में बेरोजगार की कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। फिर भी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्तिम वर्षों में इसमें आधा सुधार हुआ और रोजगार की महत्वपूर्ण (significant) दशाएँ उत्पन्न की गईं। वास्तविकता तो यह है कि उत्पत्ति के कुछ एक क्षेत्रों में तो इतना अधिक विकास हुआ कि कुशल कारीगरों (skilled labour) और प्रशिक्षित व्यक्तियों (Trained Persons) की भारी कमी रही।

४—वित्तीय प्रकरण और कीमतें (Monetary Indicators and Prices)

योजना की समाप्ति पर धन पूति में सब मिला कर १९७६ करोड़ रु० से लेकर २१८४ करोड़ रुपये तक की वृद्धि हुई, जो १० प्रतिशत से कुछ अधिक थी। योजना की समाप्ति पर, घुसघात की तुलना में, कीमतों में १३ प्रतिशत की गिरावट हुई। मार्च १९५१ और १९५३ के बीच म पूति में २१५ करोड़ रुपये की कमी हुई। अगले १२ महीनों में (अर्थात् सन् १९५४ में) ३० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

यही कारण था कि इन वर्षों में हीनार्थ प्रचन्धन (Deficit Financing) का सहारा लेना पड़ा, जबकि उत्पत्ति की वृद्धि दर काफी गिर गई थी।

कीमतों ने भी विस्तृत रूप से वही दख (उत्पत्ति ह्रास का) अपनाया किन्तु उनमें कुछ अंतर था। मार्च १९५१ में थाक वस्तुओं के मूल्य (Wholesale Price) का जो निर्देशनाङ्क (Index) ४५० था मार्च १९५२ में ३७८ रह गया। यह एक ओर तो भारी संख्या में किये गये आयात तथा दूसरी ओर मँहवाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों और वित्तीय उपायों (Fiscal measures) के फलस्वरूप था। यहाँ तक कि मई १९५२ में तो घट कर यह ३६७ ही रह गया। किन्तु इसके तुरन्त बाद थोड़े समय के लिए कीमतों ने बढ़ना शुरू कर दिया और १९५३-५४ में कीमतें अपने पूर्ववत् स्तर पर पहुँच गईं। किन्तु इसी वर्ष कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण कीमतें पुनः गिरने लगी और मुख्य-रूप से अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादन की वस्तुओं में अधिक गिरावट हुई, जिसके फलस्वरूप सरकार ने उचित कीमतों

को बनाए रखने के लिए मजबूत कदम उठाये । जुलाई सन् १९५५ में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक नया परिवर्तन हुआ जिसके फलस्वरूप कीमतों ने बढ़ना शुरू कर दिया और योजना-काल की समाप्ति तक कीमतों में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

जैसा कि सर्वविदित है उस समय से (जु० १९५५) कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिसका मुख्य कारण पूर्ति की स्थिर सख्या पर बढ़ती हुई माँग का दबाव है । सब मिला कर, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वित करने से कोई नया सुधार नहीं हो सका । इसका सर्वप्रथम कारण तो यह था कि उत्पादन की वृद्धि योजना के मध्य में हुई, यद्यपि १९५६ के शुरु तक अर्थव्यवस्था में पूर्ण विकास हो चुका था । ऋण प्रदायगी की स्थिति योजना के प्रारम्भिक समय की अपेक्षा अन्तिम समय में काफी अच्छी रही । योजना बनाते समय इस बात का सादा अनुमान किया गया था कि इस योजना में ऋण प्रदायगी की राशि में १८० से २०० करोड़ रु० तक की कमी रहेगी किन्तु वास्तविकता के आधार पर ऋण स्थिति काफी लाभदायक (favourable) रही । १९५१-५२ में जो १६१ करोड़ रु० की कमी (deficit) थी वह आगे के वर्षों में ही दूर हो गई और ६० करोड़ रु० तथा ४७ करोड़ रु० का क्रमशः अतिरिक्त लाभ (surplus) हुआ । १९५४-५५ में भी बाह्य साधनों के द्वारा ६ करोड़ रु० का लाभ रहा जो योजना के अन्तिम वर्ष (१९५५-५६) में १५ करोड़ रु० होगा ।

कुल मिला कर योजना की अवधि में ३० करोड़ रु० का घाटा (deficit) रहा जो कर्मचारी अनुदान (Official donations) के ६ करोड़ रुपये के ऋण को मिला कर था और हम अपने घरेलू उत्पादन की २६० करोड़ रुपये पौड पावने की राशि में तुलना करे, जो भारत-भरोंकी गेहूँ सन्धि (१९५१-५२) के अनुसार प्राप्त हुई, तो हम यह पाते हैं कि घरेलू उत्पादन की वृद्धि के कारण सँभलाई में वृद्धि हुई । मशीनों तथा अन्य पूँजीगत वस्तुओं का आयात कम हुआ जिसके फलस्वरूप ऋण प्रदायगी की स्थिति योजना की समाप्ति तक अनायास ही स्थिर बनी रही और हमारी अर्थव्यवस्था में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं हुआ ।

५—रचनात्मक तथा नीति सम्बन्धी पहलू

(Structural and Policy Aspects)

प्रथम योजना का प्राथमिक कार्य—जैसा कि योजना निर्माण के समय बताया गया था,—केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विनियोग के कार्यक्रमों को पूरा करना होने पर भी इनके द्वारा प्राप्त परिणाम (Approach) बहुत ही विशद हुए । ऐसा अनुभव किया गया था कि अगरे विकास कार्यक्रमों द्वारा उत्पादन की दर में वृद्धि करना है तथा समुदाय के अन्तर्गत काम की दशाओं को सतोषप्रद करना है तो व्यापक पैमाने पर रचनात्मक तथा सत्यागत परिवर्तन करना अत्यन्त

आवश्यक है। इस बारे में योजना में बहुत से सुझाव दिए गए थे, जो इस उद्देश्य की प्राप्ति के रूप में सहायक हो सकें। ये सुझाव निम्नलिखित हैं — राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड (National Extension) तथा सामुदायिक विकास खण्ड (Community Development Programmes) की स्थापना, भूमि सुधार (Land Reforms) ऋण, व्यापार, गृह निर्माण तथा उत्पत्ति के अन्य कार्यक्रमों के लिए सहकारी संगठनों (Co-operative Organizations) का विकास, सात तथा बैंक व्यवस्था का पुनरुत्थान तथा क्रमिक एवं सुसंगठित विकास के लिये सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में एक नए सामंजस्य की स्थापना आदि हैं।

प्रथम योजना के कार्य काल में इन सब बातों का समुचित विकास हुआ और इसकी वृद्धि के और अधिक तथा तीव्रगामी परिवर्तनों को ध्यान में रख इस दिशा में और अधिक प्रयत्न किए गए। दिसम्बर १९५४ में समद (Parliament) ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके अन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिक नीति का मुख्य उद्देश्य 'समाजवादी समाज की स्थापना' (Socialistic Pattern of Society) रखा गया। अप्रैल १९५६ में औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव (Industrial Policy Resolution) पारित किया गया, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक विकास का अधिकांश उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर रखा गया।

प्रथम योजना काल की अवधि में राज्यों को आर्थिक क्षेत्र में व्यापक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया। जबकि औद्योगिक प्रगति की पूर्ण जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंपी गई, फिर भी राज्य द्वारा इसके लिए कारगर कदम उठाए गए और साथ ही राज्य द्वारा उठाए गए इन कदमों की खूब सराहना हुई और सामान्य रूप से सबने यह समझ लिया कि राज्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना, मार्ग प्रदर्शन करना, वही तक उचित और अनुचित है।

यहाँ पर यह कह देना असंगत न होगा कि प्रथम योजना में विनियोग के सामान्य स्तर (Modest scale) और आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन ने कृषि उत्पादन की वृद्धि तथा राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि पर बहुत कुछ प्रभाव डाला, जिसके कारण राज्य सरकार को उत्पादन को संगठित करने के लिये नियन्त्रण (Control) करना आवश्यक हो गया। १९५३-५४ के अतिरिक्त अन्न उत्पादन के फलस्वरूप अन्न पर से नियन्त्रण उठा लिया गया। इसी प्रकार योजना काल के दूसरे वर्ष से ही ऋण अदायगी की स्थिति (Balance of Payment Position) में निरन्तर-परिवर्तन होता रहा। इसके फलस्वरूप द्वितीय योजना काल में विनियोग के समस्त कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के सफल होते रहे और सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में खुल कर पूँजी का विनियोग हुआ। योजना की सफलता ने इस बात को अन्तिम रूप में पहले से अधिक स्पष्ट कर दिया कि उपयुक्त नीतियों के निर्धारण के लिए तथा उनको कार्यरूप में परिणत करने के लिये मासिकीय तथा विश्लेषण

(Statistical & Analytical) सम्बन्धी साधनों में परिवर्तन करना आवश्यक है । इसके सदर्भ में यह तो सर्वविदित है कि प्रथम योजना काल में लाभ की दृष्टि में विनियोग तत्कालीन उपलब्धि से काफी अधिक रहा । रोजगार की दशा के बारे में प्राप्त आंकड़े, विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग का स्तर और विकास सम्बन्धी विभिन्न आंकड़े, विभिन्न शक्तियों के कार्य करने तथा उनसे प्राप्त परिणामों को प्रकट करने में सर्वथा असमर्थ रहे हैं । विभिन्न नक़्शों का तथा क्षेत्र और उपक्षेत्रों का एक दूसरे से सामंजस्य प्रकट करने का कार्य भी बड़ा दुरुह है । किन्तु विचार विमर्श करने के नए नए तरीकों का विकास तथा उनका विश्लेषण और योजना बनाने के नये-नये तरीके खोजना तथा विभिन्न परिस्थितियों में योजना की सफलता के कार्यक्रमों का निरूपण करना आजकल बहुत आसान हो गया है, तथा आगे जाने वाली विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा । यही नहीं नई परिस्थितियों के अनुसार नये-नये विचार और योजनाएँ भी बनाई जायेंगी । इस प्रकार भावी योजनाओं की सिद्धि विचारों की समृद्धि पर ही आधारित है ।

६—उपसंहार

(Conclusion)

हम यह कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि एवं औद्योगिक दोनों ही प्रकार के उत्पादन के स्तर में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने में काफी सफल रही है । इसके द्वारा बहुत रचनात्मक तथा सस्यागत परिवर्तन भी हुये हैं । योजना के अनुसार जनता की जिज्ञासा में वृद्धि हुई है तथा उन्हें अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहन मिला है और आजकल तीव्र विकास के लिए जनता में काफी जोश व्याप्त है । प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास का पूर्व रूप से प्रथम कारगर उपाय था । हमें इस बात का हर्ष है कि साधनों की गतिशीलता तथा विभिन्न स्तरों पर साधनों की कमी होना तथा टूट फूट होना आदि बातें, जो अधिकतर विकास कार्यक्रमों के बारे में घटित होती हैं, वे प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में घटित नहीं हुईं और यह भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि विनियोग की सापेक्षिक पूर्ति तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सामंजस्य होने से दोनों ही दृष्टिकोणों से जो कार्य हुआ वह आशा से बहुत बढ़ कर हुआ ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन एवं आशाएँ^१

(Appraisals and Prospects of the Second Five Year Plan)

१—कृषि और सामुदायिक विकास

(Agriculture & Community Development)

पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सामुदायिक विकास (Agriculture and Community Development) के कार्यक्रमों को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को काफी महत्त्व दिया गया। जो लक्ष्य रखे गये थे वे आवश्यकता को देखते हुये काफी कम थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों पर 'स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल डवलपमेंट काउन्सिल, (Standing Committee of National Development Council) द्वारा जनवरी सन् १९५८ में पुनर्विचार किया गया। कमेटी द्वारा जो कागजात प्रस्तुत किये गये थे उनमें यह स्पष्ट कहा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के जो लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं वे आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही कम हैं और राष्ट्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह अत्यन्त आवश्यक है कि कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों को यथेष्ट महत्त्व दिया जाय। कमेटी ने १९४६-५० से लेकर १९५६-५७ के बीच के कृषि उत्पादन का सिंहावलोकन किया तो पाया कि कृषि उत्पादन के परिणाम विभिन्न राज्यों में एक से नहीं रहे, साथ ही किसी किसी राज्य में तो कुल लागन के बराबर भी उत्पादन नहीं हुआ। केवल २ प्रतिशत अथवा २.५ प्रतिशत उत्पादन में सालाना

1. Based on

1. Achievements and Prospects of the Second Five Year Plan, Planning Commission, Govt. of India, 1959
2. Progress Reports of the Second Five Year Plan (Govt. of India)
3. Answers to Questions put in the Parliament (and subsequently published in newspapers)
4. Newspapers and Journals.

वृद्धि हो जाने से किसी भी वस्तु के कार्यक्रम को पूर्ण नहीं सम्भवा जा सकता । राष्ट्रीय विकास के लिये उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि आवश्यक है । इस बारे में उपरोक्त कमेटी द्वारा निम्न विचार प्रकट किये गए :

१—सिंचित क्षेत्र तथा वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रति एकड़ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किया गया ।

२—सिंचाई की बृहत् तथा मध्यम योजनाओं से प्राप्त जलविद्युत शक्ति का सही-सही तथा क्रमबद्ध उपयोग नहीं किया गया तथा उनका विकास भी सन्तोषप्रद नहीं रहा ।

३—सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएँ—जिनके विकास के बारे में बहुत जोर दिया गया था और जिनके बारे में कहा गया था कि इनके द्वारा मानव शक्ति का अधिक उपयोग होगा तथा सिंचाई की अधिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी—की उन्नति विस्तृत रूप से न हो कर क्षेत्रीय रूप में हुई और उसके लिये जो जन सहयोग अपेक्षित सम्भवा गया था उसकी कमी रही । राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों तथा सामुदायिक विकास क्षेत्रों में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए निर्धारित राशि का सही उपयोग नहीं किया गया और इस क्षेत्र में जो छोटी सिंचाई योजनाओं को 'कृषि क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाओं' से सम्बद्ध करने का विचार था उसकी भी पूर्ण उपेक्षा की गई ।

४—छोटी सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिये—मुख्य रूप से तालाबों के निर्माण के लिये—योजना में जो अधिकतम राशि निर्धारित की गई थी; वह भी सन्तोषप्रद नहीं थी ।

५—कृषि बीज उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम की पूर्ण उपेक्षा की गई । इस बारे में सर्वसं महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ तक हो सके कृषि बीज फार्मों (Seed farms) की स्थापना ग्राम्य स्तर पर हो और प्रत्येक ग्राम के लिये इस प्रकार की योजना बनाई जाय जिससे गाँव की समस्त जरूरतों को पूरा किया जा सके ।

६—विदेशी विनिमय की कमी के कारण, रासायनिक खाद की पूर्ति उसकी माँग की वृद्धि के साथ मेल न खा सकी, और इस कमी को पूरा करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि हरी खाद (Green manure), Organic manure तथा खाद बनाने की अन्य स्थानीय सामग्री का पूर्ण विक्रम किया जाये ।

७—प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक कुटुम्ब को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिये ग्राम्य संस्थाओं जैसे पंचायत तथा सहकारी समितियों की स्थापना की जाय । ग्राम्य नियोजन (Village Planning) के लिये भी इन संस्थाओं का विकास अत्यन्त आवश्यक है ।

८—कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों तथा साक्ष सम्बन्धी कार्यक्रम (Credit) में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किया जाय। ये कार्य ग्राम्य स्तर (Village level) पर करना अत्यन्त आवश्यक है।

सिचाई द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण उपयोग उठाने में कमी के कारणों का विवेचन करते हुए कमेटी ने कहा कि जहाँ पर सिचाई के साधनों का पूरा उपयोग नहीं उठाया गया है वहाँ पर सबसे प्रमुख बाधा नहरों की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई। ऐसा देखने में आया कि जहाँ पर सिचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया वहाँ पर खेतों तक पानी पहुँचाने के लिये नालियाँ तथा बम्बे बनाने के काम में बड़ी ढील बरती गई और इस काम में सबसे बड़ी बाधा, किसानों की इन साधनों की उदासीनता और लापरवाही के कारण पैदा हुई। इस बारे में यह तय किया गया कि जो काम अधूरा रह गया था उसको पूरा करने के लिये शीघ्र कदम उठाए जायें और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड तथा सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन तथा छोटी सिचाई योजनाओं के लिये जो धन राशि निर्धारित की गई थी, उसका उपयोग खेतों तक नाली और बम्बा बनवाने के लिये तथा तत्सम्बन्धित कृषि कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये किया जाय। गाँव में नालियाँ बनाने की जिम्मेदारी योजना अधिकारियों (Project authorities) के ऊपर रखी जाय। इसके लिये स्वेच्छाचारी श्रम का सहारा लिया जाय। प्रशासकीय सलाहकार समिति (Administration Advisers' Committee) के कार्य क्रम की जो रिपोर्ट तैयार हुई उसमें विस्तृत रूप से यह सुझाव दिया गया था कि विभिन्न राज्यों में सिचाई सुविधाओं का पूरा उपयोग उठाने के लिये व्यापक स्तर पर कार्य किया जाय। इसके अन्तर्गत समिति ने निम्नलिखित सुझाव पेश किये थे —

(१) खेतों के लिये नालियों का निर्माण किया जाय तथा सिचाई सम्बन्धी अन्य कामों को पूरा किया जाय।

(२) विभिन्न बांध योजनाओं द्वारा सिंचित क्षेत्रों का तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाय।

(३) आदर्श कृषि फार्म (Demonstrative Plots) की स्थापना हो तथा सिचाई युक्त जुताई के लिए उचित सलाह तथा स्तर निर्धारित किया जाय।

(४) जिन लोगों के खेतों को सिचाई की पूरा सुविधाएँ प्राप्त हो उनसे एक निर्धारित नियम के अनुसार अनिवार्य आबपाशी कर वसूल किया जाय।

(५) ग्राम्य स्तर पर मिली जुली बीज बोनो की प्रणाली अपनाई जाय।

(६) हरी खाद के उपयोग के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर एक आन्दोलन चलाया जाय।

(७) उन्नत बीज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाय। सरकारी कृषि फार्मों पर इन बीजों का उत्पादन किया जाय और बीज भण्डारों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाय।

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) द्वारा दिये गये इन सुझावों और सुधारों को सन् १९५६-६० में बहुत महत्व मिला और इनका काफी प्रचार हुआ। कृषि उत्पादन और उसकी वृद्धि को ध्यान में रख इन सिद्धान्तों का योजना निर्माताओं द्वारा स्वागत किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि योजना के प्रथम दो वर्षों में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रहा, यद्यपि राज्य स्तर पर उत्पादन की वृद्धि के लिए अनेक कार्य किए गये।

योजना के कुछ वर्ष बीतने के पश्चात् कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों को पूरा करने के सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और सालाना स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न किए गये। फिर भी इस कार्यक्रम में पूर्ण उत्साह से भाग नहीं लिया गया और इसमें काफी त्रुटियाँ रही। इस योजना के कार्यक्रम के प्रत्येक पहलू का सही विवेचन होना चाहिये था तथा प्रत्येक पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए समुचित आंकड़ों (Statistics) की आवश्यकता अपेक्षित थी। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि उत्पादन की वृद्धि के जो अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वह वर्तमान उत्पादन की स्थिति को ध्यान में रख कर किये जाते हैं किन्तु कार्यक्रम की अवधि के समाप्त होने पर जब वाद में हम इन लक्ष्यों की जाँच करते हैं तो वह विकास मूचना तथा वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हर कदम पर अपूर्णता तथा असफलता के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। इस कमी का वास्तविक रूप हम १९५६-५७ के लक्ष्यों में पाते हैं, जिसमें योजना निर्माताओं ने सन् १९५६-५७ के लिए १३ मिलियन टन प्रति वर्ष अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था किन्तु १९५७-५८ तक दो सालों में केवल २.३ मि० टन अतिरिक्त अन्न का ही उत्पादन हुआ। इन दो सालों में हुए कृषि कार्यक्रम की ग्रन्थ मदों के बारे में योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये गए वे नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं —

लाख टन

विभिन्न कार्यक्रम	योजनाओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य	१९५६-५७ की प्राप्ति	१९५७-५८ का कुल अनुमानित प्राप्ति
१—वृद्धि सिंचाई योजनाएँ	३०.२	१.७	२.७
२—लघु सिंचाई योजनाएँ	१८.९	३.०	४.०
३—उर्वरक तथा खाद	३७.७	०.९	७.७
४—ऊन्नत बीज	३४.०	१.७	२.०
५—भूमि विकास	६.४	०.६	१.७
६—भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य	२४.७	२.२	४.०
कुल	१५४.६	१३.१	२३.१

सन् १९५८-५९ में कृषि उत्पादन की प्रगति में एक नया मोड़ आया। कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसके निम्नलिखित कारण थे — १ मानसून का सहयोगी

रूप तथा रबी आन्दोलन के साथ किए गये अन्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रम। केन्द्रीय कृषि एवं साधन मन्त्रालय ने कहा था कि अन्न उत्पादन के निर्देशनाङ्क जो १९४६-५० में १०० था, बढ़ कर १९५६-६० में १३१.० हो गया अर्थात् १० वर्ष की अवधि में ३१ प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् १९५७-५८ के उत्पादन की तुलना में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९५७-५८ की साल वा निर्देशनांक १२३.६ था। इस वर्ष अनाज का उत्पादन ७२.५ लाख टन हुआ, जो पिछले तीन वर्षों की तुलना में सबसे अधिक था। अन्य वस्तुओं जैसे जूट, तिलहन, गन्ना (कच्चे गुड के रूप में) क्रमशः ५२ पिनियन गांठें, ६.६ मिलियन टन तथा ७.२ मिलियन टन उत्पादन हुआ, केवल कपास के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई और उमका उत्पादन १९५७-५८ के ही बराबर रहा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी विकास के प्रभाव की चर्चा करते हुए यह कहा जा सकता है कि इसका सबसे अच्छा प्रभाव सन् १९५८-५९ में हुआ। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार को कृषि-विकास के लिये दी जाने वाली राज्य सरकारों की सहायता को बन्द नहीं करना चाहिये। कमेटी के सुझाव को मान कर केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५६-६० के कृषि कार्यक्रमों के लिए ३६.८७ करोड़ रुपये की रकम प्रदान की। इस प्रकार १७.४८ करोड़ रुपया दीर्घ-कालीन ऋण के रूप में तथा ४३.६ करोड़ रुपया अनुदान के रूप में दिया गया। केन्द्रीय सरकार की इतनी बड़ी सहायता के फलस्वरूप दूसरी योजना में छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ६ मिलियन एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध मानव शक्ति की तुलना में बहुत कम था। उसके बारे में भी यह सन्देह व्यक्त किया जाता है कि योजना अवधि की समाप्ति तक शायद यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सके क्योंकि योजना काल के प्रथम दो वर्षों में केवल ३.५ मिलियन एकड़ भूमि ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचित की जा सकी।

१९५६-५७ में कृषि बीज फार्मों की संख्या केवल ३४३ थी, जब कि योजना का लक्ष्य ४१८५ बीज फार्मों की स्थापना करने का था। योजना काल की दूसरी साल में (१९५०-५१) १४१६ कृषि फार्म खोलने का अनुमान किया था, जब केवल १०६४ कृषि फार्म ही निर्धारित किये जा सके। १९५६-६० में बीज फार्मों की स्थापना के लिये सरकार ने ४७ करोड़ रुपये दिए जिनसे ७८८ फार्मों की स्थापना हो गई। इस प्रकार १९५६-६० तक २७०० कृषि फार्मों की स्थापना हुई जिनमें से २४०० पर उन्नत बीजों का उत्पादन आरम्भ हो गया।

कृषि बीज फार्मों की स्थापना के बारे में आवश्यकता इस बात की है कि इनके लिए जो जमीन प्राप्त की गई है उसके शीघ्र उपयोग के लिए इन कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा किया जाय, जिससे नि अल्पकाल में ही उन्नत बीज की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। राज्यों से भी इस बारे में आशा की गई कि वे सिंचित तथा वर्षा वाले क्षेत्रों में शीघ्र से शीघ्र कृषि बीज फार्मों की स्थापना करें, साथ ही जिन क्षेत्रों की मुख्य उपज गेहूँ और चावल है, वहाँ पर उन्नत बीज के फार्म खोले जायें।

साधारण तौर पर इन दो फसलों के लिए आज व्यापक क्षेत्र में उन्नत बीज की सुविधाएँ प्राप्त हैं ।

रामायनिक खाद की पूर्ति में विदेशी विनिमय की जो बाधा है वह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है । पिछले ६ वर्षों में अर्थात् १९५१-५२ से १९५६-५७ के बीच उर्वरक की माँग ३ लाख टन से बढ़ कर ९ लाख टन हो गई । योजना में प्रमोनियम सल्फेट के रूप में १८५ लाख टन खाद प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था फिर भी खाद की बढ़ती हुई माँग को देखते हुये यह बहुत कर्म था । सन् १९५७ के अन्त में स्थानीय खाद बनाने के सम्बन्ध में दो योजनायें (schemes) बनाई गई । १९५७-५८ में स्थानीय खाद विकास कार्यक्रम ७४८ राष्ट्रीय प्रसार सेवा सामुदायिक खण्डों में फैल गया तथा २०२३ पचासवीं के क्षेत्र में इस कार्यक्रम को अपनाया गया । इस दिशा में बड़े ही ठोस कदम उठाए गए, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में मोनजाइट सैंड (Monazite Sand) की प्राप्ति हुई है जिसका प्रयोग थोरियम और यूरेनियम को बनाने के लिए किया जायेगा ।

१९५६-५७ में कृषि-उत्पादन के कार्यक्रम पर व्यय होने वाले धन का विवरण

करोड़ रुपये

खर्च की मदें	१९५६-५७ वास्तविक	१९५७-५८	
		निर्धारित लागत	कुल वास्तविक लागत
कृषि उत्पादन	६४	१६४	१३३
लघु सिंचाई योजनाएँ	१३६	१६०	१५२
भूमि का विकास	३२	४०१	३७७
कुल	२३२	३६५	३२२

१९५६ से १९५९ तक तीन वर्षों में कृषि उत्पादन के लिए करीब ६५ करोड़ रु० का अनुमानित व्यय हुआ । कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों को और अधिक तीव्र करने के लिए यह मुझाव दिया गया था कि योजना की अवधि तक इनके लिए निर्धारित १७० करोड़ की रकम को बढ़ा कर २१८ करोड़ रु० कर दिया जाय । इस वृद्धि की अधिकतम राशि अर्थात् (३० करोड़ रु०) छोटी सिंचाई योजनाओं

पर व्यय की गई और अन्य कार्यक्रमों पर केवल १२ करोड़ रु० खर्च किए गए। यह धनराशि, वास्तव में कृषि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्य में अतिरिक्त वृद्धि के लिए खर्च की गई।

२—सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programmes)

भारत सरकार ने इस बात का निश्चय किया है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सन् १९६३ तक समूचे देश की सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाय। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र सभ के एक मिशन ने जो यह सुझाव दिया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सारे देश में फैला दिया जाय, वह अस्वीकृत कर दिया गया है।

सन् १९५६-५७ में ४६५ ब्लॉक (Blocks) तथा १९५७-५८ में ५६७ विकास खण्डों की राष्ट्रीय प्रसारण योजना के अन्तर्गत लाया गया। इन दो वर्षों में करीब ४४० सामुदायिक विकास खण्डों की राष्ट्रीय प्रसार सेवा में परिवर्तित किया गया। सब मिलाकर दूसरी योजना के दूसरी साल की समाप्ति तक इन सामुदायिक विकास खण्डों द्वारा १५० मिलियन जनसंख्या वाले २७६००० गांवों में सेवा कार्य किया गया। इन दो वर्षों की अवधि में इस कार्यक्रम पर करीब ५३ करोड़ रु० खर्च हुआ।

३—कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य उपलब्धियाँ (Other Achievements allied to Agriculture)

अन्न उत्पादन, सिंचाई योजना तथा सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के अलावा कृषि उत्पादन के अन्य कार्यों में भी काफी विकास हुआ। अक्टूबर १९५६ तक ६,६०० एकड़ भूमि ट्रैक्टरों द्वारा जोती गई। अकेले सन् १९५८-५९ की साल में ६७६ लाख एकड़ भूमि केन्द्रीय ट्रैक्टर सभ के ट्रैक्टरों द्वारा जोती गई।

पशु पालन, डेरी उत्पादन, मत्स्य पालन तथा वन विकास कार्यक्रमों में भी असाधारण प्रगति हुई। ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दूध का उत्पादन बढ़ाने तथा पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए १९६ नए फुनिम पशु गर्भाधान केन्द्र खोले गए तथा १०७ पुराने गर्भाधान केन्द्रों का पुनरुत्थान किया गया। ४५ ग्राम्य प्रसार केन्द्र खोले गए; १७०४७ बछड़ों के पालन पोषण के लिए सहायता दी गई। पशुओं के चारे की व्यवस्था एवं उनकी विक्री की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी आवश्यक कदम उठाए गए।

कुक्कुट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बम्बई, उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश में ३ क्षेत्रीय कुक्कुट विकास केन्द्र खोले गए, इनके अतिरिक्त एक कुक्कुट केन्द्र दिल्ली प्रदेश में पहले से ही स्थापित था। मछली उद्योग के विकास के लिए ग्राम्य स्तर पर बड़े ही सराहनीय कार्य किए गए। इस सम्बन्ध में बहुत से भिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया

गया तथा सहकारी समितियों के द्वारा भी मछली उद्योग के विकास के लिए भी सहायता दी गई। वन लगाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को १६१ लाख रु० कर्ज तथा अनुदान के रूप में दिया। भूमि क्षरण (Soil erosion) को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने १८० स्थानों पर प्रयास किया, जिससे ८४६ लाख एकड़ जमीन को फायदा हुआ तथा ३६ करोड़ रुपया खर्च हुआ। चकवन्दी विकास कार्यक्रम के लिए भी सराहनीय प्रयत्न किए गए। सन् १९५८-५९ के चकवन्दी कार्य के लिए राज्य सरकारों को ७६२ लाख रुपये की सहायता प्राप्त हुई।

सन् १९५८-५९ के लिए, योजना में, ३६ करोड़ रु० इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए। इस वर्ष में सामुदायिक विकास के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए वह बहुत कुछ आयोजन समिति (Committee on Plan Projects) द्वारा सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों के लिए नियुक्त निरीक्षण समिति (Study Team) का सिफारिशों के आधार पर किए गए। इसी वर्ष इन कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में पुनर्विचार हुआ और सर्व-सम्मति से यह तय किया गया कि बजाय इसके कि द्वितीय योजना की अवधि की समाप्ति तक सब गांवों में सामुदायिक विकास खण्डों की स्थापना की जाय, (जैसा कि योजना के आरम्भ में कहा गया था) आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम को धीरे धीरे तथा सुचारु रूप से चलाया जाय तथा करीब १०७५ विकास खण्डों की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में की जाय और इस कार्य को अक्टूबर १९६३ से पहले समाप्त न किया जाय।

दूसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए और मुख्य रूप से कृषि उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जाय, जो निम्नलिखित बातों पर आधारित है। इसके लिए निम्नलिखित बातें अनिवार्य हैं —

(१) विभिन्न विकास खण्डों का, जो समान एजेंसी के तौर पर सम्मिलित रूप में कार्य करते हैं, विस्तार किया जाय।

(२) उन सार्वजनिक संस्थाओं का विस्तार किया जाय जो स्थानीय श्रम साधनों द्वारा स्थानीय विकास कार्यक्रमों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाती है।

(३) सहकारी समितियों के बारे में यह सुझाव दिया गया है कि सन् १९६०-६१ तक २८००० साधन सहकारी समितियों की स्थापना की जाय। इसमें से १०,००० नई समितियाँ खाली जायें तथा बाकी का सहकारी पुनर्गठन किया जाय।

इन कार्यक्रमों के विकास कार्य की गति काफी धीमी रही। इसी कारण कृषि उत्पादन तथा छोटी सिंचाई योजना सम्बन्धी कार्यक्रमों के बारे में व्यय की राशि पर पुनर्विचार हुआ और यह तय किया गया कि इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित १७१ करोड़ रु० की कुल लागत में कटौती की जाय। फलस्वरूप, इनके विकास के

लिए उपयुक्त पैमाना निर्धारित कर विभिन्न मदों के खर्चों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए :—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यक्रमों पर निर्धारित

वास्तविक तथा सशोधित व्यय

(रुपया करोड़ों में)

विकास के कार्यक्रम	द्वितीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित वास्तविक रकम			योजना के अन्तर्गत पुनर्निर्धारित रकम		
	कुल	केन्द्र द्वारा	राज्यों द्वारा	कुल	केन्द्र द्वारा	राज्यों द्वारा
१—पशु पालन तथा दूध की पूर्ति	५६	५८	५०.०	३६	६	३०
२—जंगलात (भूमि क्षरण रोकने के लिए)	४६	६०	४०.०	३६	६	३०
३—मत्स्य पालन	१२	३८	८०	१०	३	७
४—अन्न गोदाम, क्रय विक्रय तथा सहकारिता	४७	४०	४३.०	४०	४	३७
५—विविध	१०	०.६	६.५	७	१	६

४—सिंचाई एवं जल-विद्युत शक्ति

(Irrigation & Power)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जल तथा विद्युत शक्ति के विकास के लिए कुल लागत का १२ प्रतिशत भाग निर्धारित किया गया और इस लागत में से ३६ प्रतिशत रकम राज्यों द्वारा व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। १९५८-५९ के अन्त तक इस सम्बन्ध में कुल मिला कर ४७६ करोड़ रुपया खर्च हुआ, जिसमें से २५७ करोड़ ६० बहुउद्देशीय (Multi-purpose) सिंचाई योजनाओं के लिए रखा गया। १९३ करोड़ ६० विद्युत शक्ति के विकास के लिए तथा बाकी का २९ करोड़ रुपया अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया। १९५६-५७ में कुल व्यय १५० करोड़ रुपया हुआ। इसी प्रकार १९५७-५८ में १६६ करोड़ तथा १९५८-५९ में अनुमानित व्यय १६० करोड़ रुपया हुआ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के विकास की प्राथमिकता दी गई क्योंकि एक तो इन पर व्यय कम होता है और दूसरे इनके द्वारा तत्काल ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई कार्य सम्बन्धी उपयोगिता एवं उपलब्धि में बहुत अन्तर रह गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ८५ मिलियन एकड़ जमीन की सींचन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु योजना की समाप्ति तक केवल

६३ मिलियन एकड़ भूमि ही सीधी जा सकी। वास्तविक रूप से सिंचित क्षेत्र तो केवल ४ मिलियन एकड़ से कुछ ही ज्यादा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई सम्बन्धी इस कार्यक्रम को पूरा करने में दो समस्याएँ सामने आयी। (१) प्रथम कठिनाई प्रथम योजना द्वारा प्रारम्भ की गई सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के सम्बन्ध में आई। चूँकि पिछले कार्य को पूरा करना जरूरी था अतः नए कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में देर हुई। (२) दूसरी मुख्य कठिनाई सिंचाई सुविधा द्वारा उपलब्ध उपयोग उठान के लिए साधनों की कमी के बारे में थी क्योंकि किसी भी काम के लिए एक साथ साधन जुटाना बड़ा कठिन होता है।

उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि सिंचाई सुविधाओं के बदले में प्रावपाशी की व्यवस्था नहीं की गई थी सिंचाई कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ न उठाया जा सका। और इस काम में काफी ढील बरती गई। सरकारी तौर पर भी इस बात की व्यवस्था नहीं की गई कि प्रस्तुत क्षेत्र के समस्त खेतों को पानी लेना अनिवार्य है। यह बात मुख्य रूप से ट्यूब वेल (Tube Well) द्वारा सिंचाई के सम्बन्ध में हुई। इसी प्रकार दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के कुछ कार्यक्रमों के बारे में भी यही कठिनाई आयी। जैसा कि रिपोर्ट से विदित होता है, सन् १९५६ तक ३००० 'नलकूपों' का निर्माण हुआ - जिनमें से २९७८ कुँओ द्वारा सिंचाई का कार्य शुरू हो गया और बाकी के कुँओ द्वारा भी शीघ्र ही सिंचाई कार्य शुरू हो जाने की आशा व्यक्त की गई।

द्वितीय योजना में १२ मिलियन एकड़ भूमि की अतिरिक्त सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसमें से ६ लाख एकड़ भूमि छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचित करने का कार्यक्रम था और ३ लाख एकड़ वृहद् सिंचाई योजनाओं द्वारा। किन्तु सन् १९५६-६० तक हुई वास्तविक उन्नति को देखने से पता चलता है कि समुचित धन की उपलब्धि होने के बावजूद भी कुल मिलाकर योजना की अवधि समाप्त होने तक १०.४ मिलियन एकड़ भूमि के लिए ही सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध की जा सकी। सिंचाई सुविधाओं द्वारा वास्तविक तथा अनुमानित रूप में सिंचित भूमि का विवरण इस प्रकार है

मिलियन एकड़ों में

साल	दूसरी योजनाओं में अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई सुविधा	अपेक्षित अनुमानित भूमि के लिए सिंचाई सुविधा
१९५६-५७	२०	०.६८ वास्तविक
१९५७-५८	२०	१.११ (अपेक्षित)
१९५८-५९	२०	२.०२ अनुमानित
१९५९-६१	६०	०.५६ लक्ष्य

सन् १९५६ के सिंचाई कार्यक्रमों के लिए योजना में २० करोड़ रु० की व्यवस्था की गई, जिसके द्वारा २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की गई। बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए योजना में ६० करोड़ रुपये की लागत की व्यवस्था की गई जिसमें से करीब १२ करोड़ रुपया कोसी बाढ़ नियन्त्रण के लिए तथा दामोदर घाटी योजना (D. V. C. Projects) के लिए, तथा करीब ४८ करोड़ रुपया अन्य बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया। कोसी बांध के सम्बन्ध में ऐसी आशा व्यक्त की गई कि यह १९६२ से पहले ही बन कर तैयार हो जायगा। नेपाल, भूटान तथा सिक्किम की सरकार ने मिलकर ८१ विद्युत तथा श्रुतु विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जिनमें से ५८ केन्द्र नेपाल में तथा २३ भूटान में हैं।

विद्युत शक्ति सम्बन्धी कार्यक्रम

जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई तो उस समय बिजली की क्षमता के दीर्घकालीन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए १९५० की ७ मिलियन किलोवाट की उत्पादन शक्ति को बढ़ा कर १९६५ में १५ मिलियन किलोवाट कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके साथ ही दूसरी योजना में अतिरिक्त विद्युत शक्ति का लक्ष्य ३५ मिलियन किलोवाट रखा गया, जिसमें से २६ मिलियन किलोवाट का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा हुआ, ३००,००० किलोवाट बिजली का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा तथा औद्योगिक संस्थाओं के लिए आवश्यक ३००,००० किलोवाट शक्ति का उत्पादन स्वयं औद्योगिक केन्द्रों द्वारा किया गया। दामोदर घाटी क्षेत्न की २२५,००० किलोवाट बिजली की आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही साथ १२५,००० किलोवाट अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने का निश्चय किया गया। यह निश्चय इसलिए किया गया, ताकि रेलों तथा अन्य उद्योगों की बिजली सम्बन्धी जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके।

योजना में विद्युत शक्ति के विकास के लिए ४२७ करोड़ रुपये के निनियोग की व्यवस्था की गई, जिसमें से १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में क्रमशः ७५ करोड़ तथा ८५ करोड़ रुपया व्यय हुआ तथा १९५८-५९ में ८३ करोड़ रुपया व्यय हुआ। इस प्रकार १९५६ से १९५९ तक के तीन वर्षों में करीब २४० करोड़ रुपया बिजली उत्पादन पर व्यय हुआ जिससे ७७०,००० किलोवाट बिजली का कुल उत्पादन हुआ। जिसमें से १७८,००० किलोवाट अकेले १९५६-५७ में पैदा की गई तथा ३१०,००० किलोवाट १९५७-५८ में पैदा की गई, बाकी का उत्पादन १९५८-५९ में हुआ।

निजी क्षेत्र में, योजना के प्रथम तीन वर्षों का बिजली का उत्पादन १५७,००० किलोवाट आँका गया, जिसमें से १५०,००० किलोवाट का उत्पादन टाटा विद्युत शक्ति कम्पनी (Tata Power Company) के ट्रॉम्बे स्कीम (Trombay

Installation) द्वारा किया गया । इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विद्युत शक्ति कार्यक्रम में सबसे बड़ी बाधा विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) की है; जिसके द्वारा बड़ी विद्युत मशीनों का आयात होता है । ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में मोटर तथा अन्य मशीनरी सम्बन्धी कलपुर्जों के उत्पादन करने वाले कारखानों में जो वृद्धि हुई वह भी विदेशी विनिमय द्वारा आयात की गई विद्युत मशीनों द्वारा ही हुई । नवीन अनुमानों के अनुसार "Core Project" की सूची में सम्मिलित विद्युत योजनाओं के लिए ३६ करोड़ रुपये की विदेशी विनिमय राशि रखी गयी तथा अन्य योजना के लिए केवल ३४ करोड़ रुपये की विदेशी विनिमय की राशि निर्धारित की गई । इस लागत के असावा ३ करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की प्रतिवर्ष अतिरिक्त आवश्यकता समझी गई, जिसके द्वारा पूर्व स्थापित बिजली घरों की मरम्मत का कार्य किया गया ।

यद्यपि इन समस्त कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए व्यापक पैमाने पर हर सम्भव कदम उठाए गए किन्तु फिर भी इस कार्य में बहुत कुछ विलम्ब हुआ और नए बनाए गए बिजली घरों द्वारा १९५६-६० तक कोई लाभ नहीं उठाया जा सका । अनुमान यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई नवीन योजनाओं का पूर्ण लाभ, योजना अवधि के समाप्त होने से पूर्व, नहीं उठाया जा सकता । वर्तमान उपलब्धियों के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा स्थापित बिजली घरों में, योजना की समाप्ति तक केवल २५ मिलियन किलोवाट बिजली प्रतिवर्ष प्राप्त हो जायगी और निजी क्षेत्र द्वारा १७५,००० किलोवाट बिजली की क्षमता का ही उपभोग हो सकेगा । इसमें औद्योगिक स्थापनाओं द्वारा उत्पादित ३००,००० किलोवाट बिजली की मात्रा भी शामिल होगी, जो उद्योगों के निजी उपभोग के लिए होगी । इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल मिला कर करीब ३ मिलियन किलोवाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा, जबकि योजना का लक्ष्य ३५ मिलियन किलोवाट बिजली पैदा करने का था अर्थात् करीब ५००,००० मिलियन की कमी रहेगी ।

योजना में सम्मिलित बिजली के तारों को लगाने तथा बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें सतोषजनक सफलता मिली । योजना का लक्ष्य ३०,००० मील लम्बी तार की लाइन बनाने का था जिसमें से १०,००० मील लम्बी तार की लाइन का निर्माण तो अकेले १९१६-५७ तथा १९५७-५८ की साल में ही हो गया । इस प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १०,००० गांवों को बिजली प्रदान करने के लिए ७५ करोड़ रुपये की घनराशि रखी गयी, जिसमें से प्रथम दो वर्षों में करीब ४५०० गांवों को बिजली प्रदान की गई । सन् १९६० में भारत-कनाडा अणु सन्धान द्वारा एक जाँच आयुक्त की नियुक्ति की गई जिसका मुख्य उद्देश्य भू-भौतिक इजी-नियरी तथा Isotope के उत्पादन के सम्बन्ध में खोज करना था जो कृषि उद्योग एवं दवाइयों के विकास के लिए आवश्यक रूप से सहायक सिद्ध हुई । इस समय केन्द्रीय

मरकार योजना की खानों से दूर बिजली घर बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है और ऐसा बिजली घर सर्वप्रथम राजस्थान में स्थापित होगी जहाँ पर कि पानी और कोयले की बहुत कमी है।

५ — गाँव और कुटीर उद्योग धन्धे

(Village & Cottage Industries)

कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग हमारे देश के प्राथमिक होने और राष्ट्रीय योजना के ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जिनकी कमी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पहली पञ्चवर्षीय योजना में इन उद्योगों के विकास के लिए केवल १० करोड़ रुपया की राशि रखी गई जो इनकी उपयोगिता को देखते हुए बहुत कम थी। दूसरी पञ्चवर्षीय योजना में इन उद्योगों के विकास के लिए २०० करोड़ रुपया की राशि रखी गई। विभिन्न उद्योगों के लिए मोटे तौर पर इस रकम का विभाजन इस प्रकार से किया गया है।

उद्योग	करोड़ रुपया
हाथ करपा	३६०५
छोटे पैमाने के उद्योग	४६००
औद्योगिक सहजान	१५००
दस्तकारी	६००
खादी तथा सामोद्योग	६५००

अम्बर चर्खों के कार्यक्रम का वर्ष इसमें शामिल नहीं है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य एक सुव्यवस्थित, सुगन्धित, विकेंद्रित औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करना है; जिसके द्वारा रोजगार की अधिक से अधिक दशाएँ उपलब्ध हों, तथा जनता की उपयोग सम्बन्धी समस्याएँ जल्द से जल्द पूरी हो सकें। जून १९५६ में निर्धारित सूची बल उत्पादन का लक्ष्य ६००० मिलियन गज से बढ़ा कर १९५६ में ८४०० मिलियन गज कर दिया गया। अम्बर चर्खों के कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ करपा के द्वारा कपड़े के उद्योग की बढ़ाने के बारे में विचार विमर्श किया गया और इसके लिए १५० मिलियन गज कपड़े का प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

१९५६-५७ में हाथ करपा द्वारा १६०० मिलियन गज कपड़े का उत्पादन हुआ; जो १९५५-५६ की तुलना में १३० मिलियन गज अधिक था। १९५७-५८ में करीब १,६५० मिलियन गज कपड़े का उत्पादन हुआ। इन दो वर्षों के उत्पादन को देखने से यह अनुमान लगाया गया कि पाँच वर्षों की अवधि में हाथ करपा के कपड़े का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह साध्य पूरा न हो सके; क्योंकि प्रथम दो वर्षों में अम्बर चर्खों द्वारा ७०० मिलियन गज कपड़े का उत्पादन हुआ, जबकि पाँच सालों के उत्पादन का लक्ष्य १५० मिलियन गज रखा गया था। इसी प्रकार बिजली पनबट्टियों द्वारा संचालित छोटे उद्योग धन्धों के उत्पादन का लक्ष्य भी

अपूर्ण ही रहेगा । द्वितीय योजना में ६२ औद्योगिक संस्थान स्थापित करने की व्यवस्था की गई जिसमें से ११ औद्योगिक संस्थान पहले दो वर्षों में ही कायम कर दिये गये तथा १६ संस्थान तीसरी वर्ष में खोलने की व्यवस्था की गई । छोटे उद्योगों को 'मार्केटिंग' तथा प्रशिक्षण की सुविधाएँ देने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय ४ लघु उद्योग संस्थाएँ, १२ बड़ी संस्थाएँ, २ शाखा संस्थाएँ तथा २७ प्रसारण केन्द्रों की स्थापना १९५७-५८ की समाप्ति तक हो गई । १९५८-५९ में एक और क्षेत्रीय संस्था, २ बड़ी संस्थाएँ, ३३ अन्य प्रसारण केन्द्रों की स्थापना की गई ।

योजना के प्रथम दो वर्षों में लघु उद्योग तथा ग्राम उद्योगों पर कुल ५६ करोड़ के करीब रुपया खर्च हुआ । तीसरी साल में यह खर्च बढ़कर ६१ करोड़ रुपया हो गया । सन् १९५६-५९ में इस बारे में एक नई समस्या आयी,—वह इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए केन्द्रीय राज्य सरकारों के पास धन की कमी के सम्बन्ध में थी । इस बात के प्रमाण मिले हैं कि राज्यों में लघु उद्योगों को चलाने के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम बनाए गए, उनके लिए निर्धारित रकम के अलावा और अधिक धन की आवश्यकता पड़ी, जिसका वास्तविक आमदनी पर गहरा प्रभाव पड़ा । वर्तमान प्रगति की दर के दृष्टिकोण के आधार पर, योजना के अन्तिम दो वर्षों में, इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए काफी धन की आवश्यकता अपेक्षित समझी गई है ।

इसी प्रकार हथकरघा उद्योग के उत्पादन के सम्बन्ध में यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अगर, इस उद्योग के लिए निर्धारित ७०० मिलियन गज कपड़े के लक्ष्य को पूरा करना है तो इसके लिए अन्तिम दो वर्षों में काफी धन जुटाना पड़ेगा अथवा मिल के कपड़े का उत्पादन बढ़ाना होगा । इस हथकरघा उद्योग में प्रयुक्त विजली संस्थानों के कारण भी काफी अनुविधा आयी जिसको देखते हुए यह आशा व्यक्त की गई कि हथकरघा उद्योग के उत्पादन में तीव्रता लाना असम्भव ही रहेगा । लघु उद्योगों के लिए निर्धारित राशि का पूर्णरूप में उपभोग किया गया । औद्योगिक संस्थानों की स्थापना के बारे में भी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उनको पूरा करने के पूर्ण प्रयास किए गए, फिर भी पाँच वर्ष की अवधि तक लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त धन की आवश्यकता महसूस हुई और अब तो यह कहा जाता है कि धन की कमी के कारण समस्त औद्योगिक संस्थानों की स्थापना नहीं हो सकेगी तथा कुछ संस्थानों की स्थापना का कार्यक्रम तीसरी योजना के लिए छोड़ दिया जायेगा ।

६—विशाल तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग

(Large and Medium Industries)

पहली पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास का जो कार्यक्रम रखा गया था वह विकास की दृष्टि से सतोपजनक नहीं था । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में

औद्योगिक विकास के लिए—सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों के लिए— १०६४ करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। यह प्रथम योजना में निर्धारित २६३ करोड़ रुपये की रकम से ३.३ गुनी अधिक थी। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के सम्बन्ध में करीब ४६ प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्पादन का केवल ३८% ही था।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक उद्योगों, जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, भारी रासायनिक उत्पादन के उद्योग, भारी इंजीनियरी का सामान तथा मशीनें बनाने वाले उद्योग को काफी महत्व दिया गया। इस प्रकार, दूसरी योजना का कुल लागत का ८० प्रतिशत भाग भारी उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों के ऊपर खर्च किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान राष्ट्र के वर्तमान महत्वपूर्ण उद्योग जैसे, पटसन, सूती कपड़ा और चीनी के उद्योगों को आधुनिक रूप देने तथा अभिनवीकरण करने को दिया गया। इस कार्यक्रम के लिए योजना में १५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। साधारण उत्पादन के कार्यक्रमों तथा उपभोग्य पदार्थों के उत्पादन-धर्मों को सम्मुख रख बहुत कुछ उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया।

७—सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक कार्यक्रम

(Industrial Projects in the Public sector)

सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक कार्यक्रम के प्रत्यक्ष विनियोग के लिए योजना में ५२४ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई। इसमें से ६०-६५ करोड़ रुपये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation) की स्थापना के लिए दिए गए। लोहा तथा इस्पात के उद्योग के लिए २२६ करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की व्यवस्था की गई थी, वह बढ़ाकर ३०२ करोड़ ४० कर दी गई।

१९५६-५७ तक, प्रथम योजना द्वारा परिचालित, बहुत से औद्योगिक कार्यक्रम पूरे हो गए, जो इस प्रकार थे अलवाई का डी० डी० टी० बनाने का कारखाना, दिल्ली के डी० डी० टी० कारखाने का विस्तार, हिन्दुस्तान यान्त्रिक कारखाने का विस्तार, Expansion of Hindustan Antibiotics तथा सरकार द्वारा संचालित मैसूर की पोर्सलेन फैक्टरी (The Porcelain Insulators schemes at the Government Porcelain Factory at Mysore) का विस्तार करना, बंगलूर स्थित सरकारी साबुन बनाने की फैक्टरी; मैसूर स्थित नल पाइप बनाने का लोहे तथा इस्पात का कारखाना नेपा (NEPA) औद्योगिक सस्थान के अन्तर्गत बिहार सुपर फास्फेट फैक्टरी का निर्माण आदि। इन कार्यक्रमों के पूरा होने के परिणाम स्वरूप डी० डी० टी० उत्पादन की क्षमता २१०० टन की हो गई है, पेन्सिलीन की १६२ मिलियन मीगा इकाइयों में तथा सुपर फास्फेट की ३३००० टन। नेपा में इस समय ३० हजार टन अख्तारी कागज तैयार किया जाता है और

१९५६-६० में २५००० टन प्रतिवर्ष इन्सुलेशन की उत्पादन क्षमता की व्यवस्था की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों पर लगभग ३ करोड़ रु० खर्च किया जाएगा।

१९५६ के अन्त तक निम्नलिखित औद्योगिक कार्यक्रमों को पूरा करने की आशा व्यक्त की गई —

योजनायें	नवीन या अतिरिक्त क्षमता
१—सिन्धी खाद फैक्टरी का विस्तार	४७,००० टन नत्रजन का उत्पादन
२—भिलाई और रूरकेला में प्रथम लौह भट्टी का निर्माण	७००,००० टन ढलवाँ लोहे का प्रतिवर्ष उत्पादन
३—पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर स्थित कोक फैक्टरी का निर्माण	२८५,००० टन (Hard Coke) प्रतिवर्ष उत्पादन
४—भारी औद्योगिक मशीनें बनाने वाले हिन्दुस्तान यांत्रिक कारखाने का विस्तार	४०० Lathes, औद्योगिक मशीनो तथा उनके पुर्जों का प्रति वर्ष उत्पादन (पूर्व-क्षमता के आधार पर)
५—हिन्दुस्तान केबिल तथा लोहे के बड़े तार तैयार करने का कारखाना	५६० मील लम्बे तार (Cable) तथा ३०० मील लम्बे (Co-axil) तार तैयार करना

योजना आयोग द्वारा ऐसी आशा व्यक्त की गई है कि निम्नलिखित औद्योगिक संस्थानों में तो दूसरी योजना की समाप्ति तक उत्पादन शुरू हो जाएगा —

औद्योगिक कार्यक्रम	नवीन या अतिरिक्त उत्पादन क्षमता
१—भिलाई रूरकेला तथा दुर्गापुर के इस्पात के कारखाने	२२ मिलियन टन इस्पात, ६००,००० टन कच्चा लोहा।
२—नगल का खाद का कारखाना	७०,००० टन नत्रजन।
३—खदान सम्बन्धी लिगनाइट योजना	३५ मिलियन टन लिगनाइट।
४—हिन्दुस्तान एन्टिवायोटिक विस्तार के अन्तर्गत स्ट्रैप्टोमाइसिन का कारखाना	४५,००० कि० ग्रा० स्ट्रैप्टोमाइसिन
५—सैसूर के लोह इस्पात उद्योग के विस्तार के अन्तर्गत फॅरो सिलिकन का उद्योग	१५,००० टन फॅरो सिलिकन
६—बिजली प्रोक्सेन इन्सुलेटर उद्योग विहार	२,००० टन इन्सुलेटर
७—हिन्दुस्तान शिप यार्ड का विस्तार	८ से १० जहाज प्रतिवर्ष निर्माण करने का विचार
८—उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेण्ट फैक्टरी का विस्तार	२३१,००० टन सीमेण्ट प्रतिवर्ष

जिनमें से कुछ पहिया यन्त्रों के कारखानों का निर्माण १९६१ के मध्य तक होने की आशा व्यक्त की गई है ।

दूसरी योजना के अन्तर्गत, इन समस्त कार्यक्रमों के लिए ५५८ करोड़ रु० की रकम आँसी गई थी तथा करीब ३२८ करोड़ रु० विदेशी मुद्रा के खर्च का अनुमान लगाया गया था । इनमें से १६६ करोड़ रु० के लागत खर्च तथा १०७ करोड़ रु० के विदेशी मुद्रा के खर्च के कार्यक्रमों की तृतीय योजना के शुरू तक पूरा करने की आशा व्यक्त की गई है ।

उपयुक्त विवेचन से यह वान बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रगतिशील औद्योगिक कार्यक्रमों की पूर्ति में काफी समय लगेगा और उन पर विनियोग किए गए रुपये का लाभ तृतीय योजना के आरम्भ से पहले नहीं उठाया जा सकता । इस कारण से यह भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करने के लिए कुछ उद्योगों—जैसे खाद निर्माण, भारी औद्योगिक मशीन-निर्माण आदि के लक्ष्यों में से कटौती करना अनिवार्य होगा । जैसा कि योजना-निर्माताओं ने योजना बनाते समय पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि "सम्मिलित वित्त की उपलब्धि के लिए जो अनुमान लगाए हैं, उनके सर्वथा सही होने का दावा नहीं किया जा सकता और उनका पूरा होना अनेक ऐसे मदों पर निर्भर करता है, जिनकी ठीक-ठीक कल्पना करना आज असंभव प्रतीत नहीं होती ।"

निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति

सार्वजनिक क्षेत्र की भाँति निजी क्षेत्र में भी लोहे तथा इस्पात के उद्योगों के लिए विशेष महत्व दिया गया है । निजी क्षेत्र में उद्योग-धन्धों की स्थापना के लिए दूसरी योजना में ६८५ करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है । इसमें से ५३५ करोड़ रु० का नवीन विनियोग होगा तथा १५० करोड़ रु० पुराने कारखानों की दुरु-दस्त-सम्भरणी कामों में लगाए जाएंगे । इस क्षेत्र के विकास के लिए ३२० करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें से २५० करोड़ रुपये नवीन विनियोग में लगाए जायेंगे । किन्तु १९५६-६० में जब योजना पर पुनर्विचार हुआ तब निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए निर्धारित ६८५ करोड़ रु० की लागत को बढ़ाकर ८४० करोड़ रु० कर दिया गया तथा १२० करोड़ के लगभग की वृद्धि विदेशी विनिमय की राशि में की गई ।

योजना का अध्ययन करने में पता चलता है कि योजना काल के प्रथम वर्ष में ही करीब १३५ से १४० करोड़ रुपये के बीच में विनियोग हुआ । इतना ही विनियोग अगली साल किया गया । औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) ने भी इस कार्य में काफी सहायता की । उक्त निगम द्वारा १९५६-५७ में १०४ करोड़ रुपया निजी क्षेत्र के उद्योगों को कर्जों के रूप में दिया जबकि

१९५५-५६ में केवल २२ करोड़ रुपये का ही कर्ज दिया गया था। इसी प्रकार इस्पात के उद्योग के विकास के लिए तथा कैलटैक्म ग्रॉथल शुद्धि कारखाने के लिए, विदेशी पूँजी के अन्तर्गत, काफी सहायता मिली।

इतनी अधिक रकम की प्राप्ति के बावजूद भी निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए विदेशी विनिमय की कठिनाई बनी रही। योजना काल के प्रथम वर्ष, अर्थात् १९५६ में ही विदेशी विनिमय की एक बहुत बड़ी राशि निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास में खर्च हो गई। इसी प्रकार दूसरी वर्ष अर्थात् १९५७-५८ में भी विदेशी विनिमय की रकम का काफी विनियोग हुआ किन्तु आगे के वर्षों में, इस क्षेत्र के लिए विदेशी विनिमय की काफी कमी होती गई। निजी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में दूसरी बाधा विद्युत शक्ति की कमी के कारण पैदा हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि इन क्षेत्र में जल विद्युत विकास का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया उसमें काफी लापरवाही बरती गई तथा प्रस्तावित रकम का दुरुपयोग किया गया। इन सब कार्यों का कारण विदेशी विनिमय की कठिनाई थी।

इस तरह, इन सभी विषय परिस्थितियों के कारण, निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित औद्योगिक कार्यक्रम सफलता पूर्वक नहीं चलाए जा सके। यहाँ पर यह कहना कठिन है कि इन सब परिस्थितियों का एकमात्र कारण विदेशी विनिमय की कठिनाई था किन्तु वास्तविकता के आधार पर तो इसके और भी कई कारण थे। योजना के अन्तिम वर्षों में कुछ विशिष्ट उद्योगों के लिए, विदेशी विनिमय की काफी सुविधा प्रदान की गई जो निम्न प्रकार है —

- १—वे औद्योगिक कार्यक्रम जो (केन्द्रीय उपाय) कोर स्कीम (Core Plan) से सम्बन्धित हैं जैसे रिफ़ाइनरी उद्योग, रेल के डिब्बे बनाने वाले उद्योग आदि।
 - २—उन औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए, जो उन्नति के शिखर तक पहुँच गए हैं तथा जिनमें बहुत माल पहले ही विदेशी विनिमय के द्वारा ही उत्पादन होता रहा है।
 - ३—उन औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए भी जो बहुत ही छोटे समय में विदेशी विनिमय की राशि को कमा कर लौटा दये, विदेशी विनिमय की सहायता दी गई है।
- अन्य हम विभिन्न उद्योगों में हुई उत्पादन की वृद्धि का विवरण देते हैं।

विभिन्न उद्योगों में उत्पादन की मात्रा को प्रकट करने वाली तालिका

उद्योग-धन्धों के नाम	इकाइयाँ	उत्पादन क्षमता		वर्तमान उत्पादन		वर्तमान उत्पादन की मात्रा को प्रकट करने वाली तालिका	
		योजना का लक्ष्य	दल क्षमता	वर्तमान उत्पादन	वर्तमान उत्पादन की मात्रा को प्रकट करने वाली तालिका	वर्तमान उत्पादन की मात्रा को प्रकट करने वाली तालिका	वर्तमान उत्पादन की मात्रा को प्रकट करने वाली तालिका
तोहा तथा इस्पात उद्योग (विश्वी का इस्पात)	मिलियन टन	२.३	१.३	२.३	२.३	२.३	२.३
अल्युमिनियम	टन	३०,०००	७,५००	३०,०००	३०,०००	३०,०००	३०,०००
फैरी मैग्नीज	"	१७०,०००	१२,०००	१७०,०००	१,१४,०००	१,१४,०००	१,१४,०००
सुपर फास्फेट (P_2O_5)	हजार टन	१२०.०	५०	१२०.०	५०*	५०*	५०*
सल्फ्यूरिक एसिड	"	५००	२५२	५००	४२०	४२०	४२०
लोहा तथा	"	२५३	१०५	२५३	३२०	३२०	३२०
कार्बिक सोडा	"	१५०	४५	१५०	१२४	१२४	१२४
क्रोमिक विस्कोरक	"	५	...	५	५	५	५
पेट्रोल का शोधन	मिलियन टन	४.३	४.३	४.३	४.३	४.३	४.३
प्लास्टिक, सिमेंटिक बनाने वाला चूर्ण	टनो में	१२,८१०	३,७३०	१२,८१०	३,७३०	३,७३०	३,७३०
सोमेट	मिलियन टन	१६.०	४.६३	१६.०	६.३	६.३	६.३
रिफ़्टरीज	१००० टन	१००० (१२५०)	४६८	१०००	४६८	४६८	४६८
रबर उत्पादन (मोटर गाड़ियों के टायर)	१००० नबर	१,४५०	१,०६२	१,४५०	१,७७४	१,७७४	१,७७४
डाईस्टफ तथा मध्य प्रसिद्ध डाईज	मिलियन टन	२७.०	११.७	२७.०	१२.०	१२.०	१२.०
सूती वस्त्र बनाने वाली मशीनें	करोड़ रुपया	१७.००	७.५	१७.००	१०.०	१०.०	१०.०
यूट उत्पादन मशीनरी	"	२.५	०.४	२.५	१.०	१.०	१.०

* तथा प्रमोनिम सर्फेट क रूप में P_2O_5 ३७०० टन लोहे का उत्पादन । † विविध फास्फेटिक साद पर विनियोजित ३६००० P_2O_5 का उत्पादन

योजना के प्रकाशन के बाद बपास उत्पादन के लक्ष्य में परिवर्तन कर दिया गया। इसके सम्बन्ध में सरकार ने २१ मिलियन तकुरो (Spindles) तथा १८,००० स्वचालित चरों को लायसेन्स देने का निर्णय किया था। इस सम्बन्ध में योजना द्वारा जो ३० करोड़ रुपया विनियुक्त रखी गई थी उसको बढ़ाकर ६० करोड़ ६० कर दिया गया। मशीन लगाने पर तकुरो को लायसेन्स दिया गया। चीनी उद्योग के बारे में २१५ लाख टन उत्पादन का अनुमान दिया गया, जिसकी १९६०-६१ तक पूरा हो जाने की आशा व्यक्त की गई। इस उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता भी ओक्षित नहीं रही। कागज उद्योग के सम्बन्ध में ऐसी आशा व्यक्त की गई कि यदि इसकी १ = करोड़ ६० के विदेशी विनिमय की सहायता मिल जाय तो इसकी उत्पादन क्षमता ४१०,००० टन हो जाय। यद्यपि इस उद्योग की क्षमता में ५०,००० टन की कमी रही किन्तु फिर भी ३५०,००० टन की उत्पादन क्षमता की प्राप्ति भी संतोषजनक हो सकती है।

नकली रेशम तथा नाइलोन उद्योग की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का विचार किया गया तथा इसकी उत्पादन क्षमता ७७० मिलियन पौण्ड होगई जो योजना के निर्धारित लक्ष्य से काफी बढ कर थी। इस सम्पूर्ण उत्पादन क्षमता में ४ लाख पौण्ड नकली रेशम का बच्चा पाया तथा ०.४८ लाख पौण्ड नाइलोन का धागा सम्मिलित है, जिसमें से कुछ धागे का प्रयोग नखली उद्योग की जाल बनाने सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

भारी औद्योगिक मशीनरी के उद्योगों की स्थापना के लिए भी विदेशी विनिमय की व्यवस्था की गई है और उद्योगों के लिए ३०,००० टन की फालतू लुगदी (Dissolving Pulp) के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया ताकि नकली रेशम तथा स्टेपिल फाइबर उद्योग (Staple Fiber Industry) के लिए विदेशों से जो कच्चा माल आयात किया जाता है उसकी निर्भरता समाप्त हो जाय।

निजी क्षेत्र में औद्योगिक कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता कपास तथा जूट उत्पादन सम्बन्धी उद्योगों का अभिनवीकरण करने का कार्यक्रम (Modernization Programme) था। योजना के अन्तर्गत चीनी उद्योग के विकास के लिए भारी जोर दिया गया और इसने पुनरुत्थान के लिए ५० करोड़ ६० की राशि रक्ती गई। इस प्रकार लोहे तथा इस्पात उद्योग सहित इन समस्त उद्योगों के अलावा अन्य बहुत से छोटे-छोटे पैमाने के उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए भी विचार विमर्श हुआ और उनके विकास के लिए करोड़ों ६० का अनुदान दिया गया। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की द्वितीय वर्ष की अवधि के समाप्त होने तक कपास तथा जूट उद्योग के लिए, मशीनरी के आयात में, ३५ करोड़ ६० खर्च होगा किन्तु चीनी उद्योग की मशीनरी के लिए सम्भवतः इतनी बड़ी धन राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और काफी विदेशी विनिमय की वचत होगी। अगर विदेशी

विनिमय की वृद्धि होगी। अगर विदेशी विनिमय की जरूरत के बारे में वास्तविक अनुमान सही निकलते हैं तो भी वजट के सन्तुलन के लिए ३५ करोड़ ६० अतिरिक्त विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ेगी। किन्तु इस बारे में यह कहना कठिन है कि इसकी प्राप्ति किस हद तक हो सकेगी क्योंकि यह बहुत कुछ सीमा तक कपास तथा जूट उद्योग के लिए दी गई अमरीका की आर्थिक सहायता तथा जापानी ऋण-राशि पर आधारित है।

मुविधा के तौर पर हमें यहाँ पर निजी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के कुछ प्रमुख तथ्यों को प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा —

(घ) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर ३२ करोड़ ६० की विदेशी विनिमय की राशि प्राप्त हो जाय तो पूर्व तालिका के कालम नम्बर ५ की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त हो जाय और इसी सदर्भ में ऐसी आशा व्यक्त की गई थी कि अगर सन् १९५८-५९ तथा १९५९-६० में इनमें से कुछ उद्योगों के लिए दी जाने वाली अमरीकी आर्थिक सहायता तथा जापानी ऋण राशि प्राप्त हो जाय तो ३२ करोड़ की विदेशी विनिमय की राशि को प्राप्त करना कुछ असम्भव न होता परन्तु ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा १०० करोड़ की अतिरिक्त धन राशि की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि पूर्व की तालिका के कालम ३ में वर्णित उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काफी विदेशी विनिमय की आवश्यकता अपेक्षित समझी गई थी जो वास्तविकता के आधार पर व्यायसगत थी।

(व) कालम ५ में वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं —

१—अल्युमिनियम, फॉरोमेगनीज तथा वास्तिक सोडा के बारे में जो उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनको सम्पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

२—भारी रासायनिक पदार्थों के लिए जो उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए थे (कुछ रासायनिक घोल तथा कान्स्टिक सोडा को छोड़कर) वे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जायेंगे किन्तु सीमेंट तथा डाईस्टफ के उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति में थोड़ी कमी रह जायगी। इसी प्रकार रिफ़ैक्टरी के लक्ष्यों में भी अपेक्षाकृत कुछ कमी रह जायगी।

३—इंजीनियरिंग उद्योगों के क्षेत्र में 'स्ट्रक्चरल फॉरीकेशन' तथा चीनी के लिए आवश्यक मशीनों को छाड़कर अन्य सभी प्रकार की मशीनों के उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ कमी रहेगी किन्तु रेल के इन्जन, बैगन तथा वाइसिकलो के उत्पादन लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो जायेंगे। मोटर गाड़ियों के उत्पादन में काफी कमी रहेगी तथा इसके उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में ८० प्रतिशत तक ही आत्म-निर्भरता मिल सकेगी।

४—विद्युत इंजीनियरिंग उद्योगों के लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो जायेंगे तथा कुछ

क्षेत्रों में तो लक्ष्य से भी अधिक प्राप्ति हो जाएगी किन्तु विर (VIR) तथा प्लास्टिक केबल्स के सम्बन्ध में कुछ कमी रहेगी ।

५—उपभोग्य वस्तु उत्पादन करने वाले उद्योगों के लक्ष्य भी लगभग प्राप्त हो जायेंगे, केवल कागज, भस्मवारी कागज, नकली रेशम के कच्चे धागे—(Filaments) तथा चीनी के सम्बन्ध में कुछ माफूसी भी कमी रह जायगी । नवली रेशम उद्योग के प्रारम्भिक लक्ष्यों की प्राप्ति में धाधिक्य रहेगा तथा चीनी उत्पादन के लक्ष्यों की भी पूर्ण रूप से प्राप्ति हो जायेगी ।

पूर्ण विवेचन के आधार पर, मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के प्रारम्भिक लक्ष्यों की, ७० से ८० प्रतिशत तक, प्राप्ति हो जाएगी । जब ३५ करोड़ ६० के विदेशी विनिमय की प्राप्ति हो जाएगी तो उद्योगों के अभिनवीकरण तथा पुनरुत्थान सबही सभी कार्यक्रम पूरे किए जा सकेंगे ।

८—औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि¹

सन् १९५६ में वाणिज्य तथा उद्योग के क्षेत्र में—औद्योगिक उत्पादन, निर्यात आय (Export Earning), मशीन निर्माण उद्योग तथा अन्य औद्योगिक कार्यों में—सांख्यिक तथा निजी दोनों ही क्षत्रों में—तीव्र विकास हुआ । वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की सन् १९५६ ६० की वार्षिक 'रिपोर्ट' में कहा गया है कि विदेशी विनिमय की कठिनाई हल हो गई थी औद्योगिक उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी । सन् १९५६ का औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक था ।

मंच तो यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में, औद्योगिक उत्पादन की सूची में वर्णित वस्तुओं के अलावा काफी वृद्धि हुई है । पेनिसिलिन जिसका कि सन् १९५१ से उत्पादन हो रहा है, औद्योगिक सूची में नहीं है । इसी प्रकार सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग तथा चीनी उद्योग के विकास बारे में भी सूची में पूर्ण विवरण दिया गया है जो आजकल काफी उत्पादन कर रहे हैं ।

अन्य औद्योगिक वस्तुएँ जिनका कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में महत्वपूर्ण विकास हुआ है इस प्रकार है—चीनी उद्योग, डीजल इंजन, मशीनों के छोटे-छोटे कल पुर्जे, छोटे मोबाइल्स, सल्फूरिक एसिड, लोहा तथा इस्पात, अल्यूमीनियम, सुपरफास्फेट, सोडा एश, सीमेन्ट, साईकिल, कागज तथा कागज की दपती (Board) आदि । ३१ सितंबर १९६० को उद्योग मन्त्रालय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि उपर्युक्त वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य जो दूसरी पंच वर्षीय

योजना में निर्धारित किए गए थे, योजना की अवधि तक उनकी पूर्णरूप से प्राप्ति हो जाएगी ।

इस्पात तथा लोहे की खपत को बढ़ाने के लिए इन्जीनियरिंग उद्योगों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है । कास्टिक सोडा, मोडा एश, सल्फूरिक एसिड सीमेन्ट तथा कैल्शियम कार्बाइड की उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और उत्पादन की बहुत सी नई दिशाएँ परिचालित की गई हैं जिनमें 'हाइड्रोजन पॅरोक्साइड' (Hydrogen Peroxide) उद्योग और खानों के खोज कार्य, एमोनियम नाइट्रेट तथा एसिटोन (Acetone) आदि प्रमुख हैं ।

भारी उद्योग—उन भारी उद्योगों में, जो निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, भोपाल का विद्युत शक्ति का भारी कारखाना—जो ब्रिटिश सरकार की सहायता से स्थापित किया गया है—इस्पात के उद्योग की मशीन सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करेगा । साथ ही इसकी मशीनों की उत्पादन क्षमता को ४५,००० टन से बढ़ाकर ८०,००० टन प्रतिवर्ष कर देने का निश्चय किया गया है ।

इन दो बड़े कारखानों के अतिरिक्त अन्य मशीनों के उत्पादक कारखानों को—जिनमें खान खोदन की मशीनें, बड़ी-बड़ी प्लेट और 'बैसल' बनाने वाले कारखाने और दो अन्य विद्युत उत्पादन के कारखाने सम्मिलित हैं—भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया गया और योजना ने भी इनके तत्काल विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ।

सावजनिक क्षेत्र के अन्य कारखानों में जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन कार्य शुरू कर दें, खाद उत्पादन के कारखाने मुख्य हैं, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे । इसके अलावा दवाइयाँ बनाने के कारखाने, रासायनिक उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति करने के कारखाने, एक्सरे, फिल्म तथा सिनेमा की मशीन बनाने के कारखानों का कार्य भी हाथ में लिया गया है ।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से औद्योगिक संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में लायसेन्स प्राप्त करने के बहुत से प्रार्थना पत्र आए जिनमें बहुतों को औद्योगिक (विकास तथा कानून) नियम (Industries Development and Regulation Act) के अनुसार लायसेन्स दिये गये । विभिन्न उत्पादन में काफी वृद्धि हो रही है । कुछ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन का विवरण नीचे दिया जाता है —

वस्तुएं	उत्पादन प्रतिवर्ष
ट्रांसफोरमर्स	२,३००,००० KVA
औद्योगिक ढाँचे (Structurals)	२०,००० टन प्रतिवर्ष
इस्पात कास्टिंग्स (Steel Castings)	१८,००० टन प्रतिवर्ष
अल्यूमीनियम	७५,००० टन प्रतिवर्ष

सरकार ने दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला के इस्पात के कारखानों के विस्तार और विकास करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। मितम्बर १९५६ के अन्त तक रूरकेला और भिलाई में बच्चे लोहे (Pig iron) का कुल उत्पादन क्रमशः १,७३, ०१६ मेट्रिक टन तथा ३,२१, ०४६ मेट्रिक टन हुआ। भिलाई कारखाने में उत्पादन प्रथम दो वर्षों में ही लक्ष्य से अधिक होने लगा है।

तेल पड़ताल के अन्तर्गत ४ कुएँ सम्भाव्य क्षेत्र (Campay Area) में— तथा ६३ कुएँ नाहर कटिया, हुगरीजन तथा मुरान क्षेत्र में खनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी तेल प्राप्ति के लिए कुएँ खोदे जाएंगे। उपर्युक्त ४ कुओं में से ३ पर उत्पादन कार्य शुरू हो गया है, नाहर कटिया हुगरीजन, मुरान क्षेत्र के ४२ कुओं से तेल निकाला जा रहा है, २ स रैम उत्पादन की जाती है, ६ सूँचे पड़े हैं तथा १० कुँआ का पुन परीक्षण होगा।

घड़ियों का निर्माण—ब्रैंगलोर में घड़ियों का कारखाना स्थापित होने जा रहा है जो सार्वजनिक क्षेत्र में होगा तथा १ मिलियन घड़ियाँ प्रति वर्ष बनाई जाएंगी। यह कारखाना जापानी सहायता से चलाया जाएगा। इसके अलावा फ्रान्स भारत सम्झौते के अन्तर्गत सरकार दो अन्य घड़ियों के कारखाने खोलने का विचार कर रही है जो निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे।

चिकित्सालय सम्बंधी उपकरण—अभी हाल में ही एक्स-रे व विद्युत-चिकित्सालय (Electro-medical) के (मोडार बनाने) के लिए चार कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों के लिए मोडार बनाने के लिए लखनऊ में एक कारखाना स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। १९५६ में क्लिनीकल परामीटर बनाने के लिए ३ अन्य कार्यक्रमों की भी स्वीकृति दी गई है। सर्जरी का सामान बनाने के लिए एस के सहयोग से एक कारखाना की स्थापना का सुझाव दिया गया है। लघु उद्योग सेवा संस्था (Small Industries Service Institute) के अन्तर्गत बम्बई में एक कारखाना स्थापित किया गया है।

(Antibiotics Plant) एक अमरीकी फर्म ने यह सुझाव दिया है कि Antibiotics का एक 'प्लांट' एंथ वायु को शुद्ध करने वाले यन्त्रों (Tetracyclines) व निर्माण के लिए एक कारखाना चंडीगढ़ में स्थापित किया जाय। भारत सरकार ने इस सुझाव की स्वीकार कर लिया है।

सीमेन्ट उत्पादन—१९६०-६१ तक सीमेन्ट का उत्पादन बढ़कर १० मिलियन टन हो जाएगा और वार्षिक उत्पादन ६ मिलियन टन हो जाएगा। १९५६ में सीमेन्ट का कुल उत्पादन ६८२ मिलियन टन हुआ था।

दुर्गापुर में एक 'मेकैनिक्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट' (Mechanical Engineering Institute) की स्थापना की जा रही है। इसके लिए अमरीकी विशेष

कोष द्वारा ६,६१,४०० डॉलर की रकम सन् १९६० से आगामी चार वर्षों के लिए सहायता के रूप में दी जाएगी। इस राशि के अन्तर्गत, वैज्ञानिक यंत्र (apparatus) तथा उपकरणों (equipment) की लागत, मशीनों तथा औजारों की लागत, फैनोशिप तथा विशेषज्ञों की सेवा का व्यय भी सम्मिलित है।

धूपकिरण की प्रयोगशाला (Cosmic Ray Laboratory)—सरकारी स्तर पर यह तय किया गया है कि कश्मीर में सूर्य की किरणों की खोज के लिए ऊँचाई पर एक प्रयोगशाला स्थापित की जाए। इसी सदर्भ में गुलमर्ग अफरवात (Apharbat) में दो प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं, जिनमें गुलमर्ग की प्रयोगशाला का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

रबर उत्पादक उद्योग (Rubber Products Plants)—वाणिज्यदल की नियमित आयात बैंक ने पंजाब के गुडगाँव जिले के वल्लभगढ़ स्थान पर एक औद्योगिक संस्था की स्थापना के लिए २२५ करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। बैंक ने यह कर्ज मुरय रूप से रबर के टायर बनाने के लिए दिया है। इसके अलावा रबर की अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी विभिन्न स्थानों पर कारखाने की स्थापना के बारे में भी विचार विमर्श हो रहा है।

उद्योगों में निवेश (Investment in Industries)—द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में सावजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में संगठित उद्योगों की स्थापना में क्रमशः ४२७ करोड़ तथा ५६३ करोड़ रुपये का निवेश हुआ।

१९५६ में इस्पात के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। १९५६ में इस्पात का कुल उत्पादन १,७६७ ६६२ टन हुआ जबकि १९५५ में कुल उत्पादन १,३६१,२५४ टन ही था।

धातु के छोटे छोटे टुकड़ों का उत्पादन (Production of billets)—भिलाई के इस्पात कारखाने का कुल उत्पादन ७७०,००० टन था जिनमें से १५,००० टन के धातु के छोटे छोटे टुकड़ों का उत्पादन हुआ। इसके अलावा जमशेदपुर, वर्नेपुर तथा दुर्गापुर में भी धातु के टुकड़ों का उत्पादन होगा, जो देश की वर्तमान आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे। पिछले दो वर्षों में ४८४ इस्पात उद्योग के इंजीनियरों को उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कराने हेतु विदेश भेजा गया। इन इंजीनियरों (अभियन्ताओं) में इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, पश्चिमी जर्मनी तथा आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

सूती वस्त्र उद्योग—सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में १९५६ ६० तक ३५ मिलियन पीण्ड सूत की वृद्धि हुई है। १९५६ में सूत कारखानों द्वारा १७२० मिलियन पीण्ड सूत का उत्पादन हुआ जबकि १९५५ में कपड़े का उत्पादन १६८५ मिलियन पीण्ड था। १९५६ में मिल के कपड़े का उत्पादन ४६२७ लाख गज हुआ।

प्लास्टिक उद्योग—इस उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे पोलिस्टर्न (Polysterne) व पोलिथिलीन (Polyethelene) आदि का उत्पादन पहले से ही हो रहा है और यह आशा है कि निकट भविष्य में हम बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के तैयार माल का निर्यात करने में सफल हो जाएंगे। सरकार ने प्लास्टिक उद्योग के लिए आवश्यक स्वदेशी कच्चे माल जैसे गमामयिक वस्तुएँ के उत्पादन के लिए भी कदम उठाए हैं। प्लास्टिक पर आधारित फाउन्टेन पेन, झालों के चदमे तथा चमड़े के निर्यात व्यापार का काम देश में बहुत दिनों से चालू है।

लाख का उत्पादन—१९५६ में लाख का कुल उत्पादन ११ लाख मन से भी अधिक हुआ। कुल उत्पादन का ७५ प्रतिशत घबरेले बिहार और मध्यप्रदेश में हुआ।

शक्ति-साधनों का वितरण—भारत सरकार सम्पूर्ण देश में शक्ति साधनों के विकास एवं वितरण के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम (Supergrid system) तैयार कर रही है। जल विद्युत शक्ति आयोग (The Water Power Commission) पूर्ण अनुभव के आधार पर दक्षिणी भाग के लिये एक क्षेत्रीय ढाँचे का गठन कर रही है जिसमें आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा केरल प्रदेश शामिल होंगे।

रेडियो Isotope के कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान शाला (Indian Agriculture Research Institute) द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोर्स चालू किया गया है, जिसके द्वारा कृषि कार्यों को रेडियो Isotope से संचालित किया जावेगा। भारत सरकार ने यह कोर्स सर्वप्रथम यूनेस्को UNESCO, एफ० ए० ओ० (F A O) तथा अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति संस्था (International Atomic Energy Agency) की सहायता से चलाया था।

अणुशक्ति केन्द्र—अनुमान है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम अणुशक्ति उत्पादन केन्द्र की स्थापना पश्चिमी भारत में, बम्बई और अहमदाबाद के बीच की जाएगी। इसके पलावा देश के उन भागों में, जो कोयला क्षेत्र से दूर हैं—जैसे दिल्ली तथा मद्रास और राजस्थान के बीच—अणुशक्ति के केन्द्रों का स्थापित किया जाना विचाराधीन है। अब एक केन्द्र चालू हो गया है।

मोटर ठेलो—मार्च १९५६ तक ३६,४६८ मोटर ठेलो का निर्माण हुआ जो अन्य सालों की तुलना में काफी अधिक था। दूसरी योजना की पूरी अवधि के लिये ६५,००० मोटर ठेलो के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु १९६०-६१ तक केवल ६२,०६० मोटर ठेलो का ही निर्माण हो सकेगा।

स्कूटर—स्कूटरों के उत्पादन के लिए सरकार दो और कारखानों को लाइसेंस देना का विचार कर रही है। इस समय स्कूटरों का उत्पादन ६०० स्कूटर प्रतिमास है, किन्तु स्कूटर के जब दोनों कारखानों द्वारा काम चालू किया जायेगा तो १५०० स्कूटर प्रतिमास बनाए जाएंगे। स्कूटर निर्माण करने का

दूसरा कारखाना १९६० के अन्त तक खुल जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से मैसूर में एक तीसरा कारखाना भी खोला जायेगा। इस प्रकार स्कूटरों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य—१५०० स्कूटर प्रतिवर्ष—से अधिक होने लगेगा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारी विद्युत सम्बन्धी कार्यक्रम—विद्युत सम्बन्धी भारी सामान बनाने के लिए, भारत सरकार ने चेकोस्लोवाकिया की सहायता के द्वारा, एक कारखाना खोलने का निश्चय किया है। इसके माध्यम से एक दूसरा कारखाना रूस की सहायता द्वारा भी स्थापित किया जायेगा। भोपाल के विद्युत यंत्र कारखाने में जुलाई १९६० से उत्पादन कार्य शुरू हो गया है। निश्चय यह किया गया है कि विद्युत यंत्रों के सामूहिक उत्पादन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जाय तथा इन उद्योगों का उत्पादन २५ करोड़ रु० प्रतिवर्ष से बढ़ाकर ५० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दिया जाय।

सिलाई की मशीनें—सन् १९५६ में कुल मिलाकर २,६०,००० मिलाई की मशीनों का उत्पादन हुआ जिनमें से २०,३५,००० रु० की कीमत की १७-१५ मशीनों का विदेशों को निर्यात कर दिया गया।

टेलीप्रिन्टर्स (Teleprinters)—देश के औद्योगिक वर्ग ने यह इच्छा प्रकट की है कि भारत सरकार ने उनसे विचार विनिमय कर लिया है और यह आशा की जाती है कि १९६१-६२ तक, टेलीप्रिन्टर्स बनाने का कारखाना खुल जाएगा।

सल्फर (Sulphur)—भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि एन० आई० डी० सी० (N I. D C) के अन्तर्गत बिहार में एक ऐसे निगम की स्थापना की जाय जो पाइरिट्स (Pyrites) से सल्फर (Sulphur) बना सके। इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में निकट भविष्य में लगभग २,००० टन बच्चा सल्फर (Ore) नार्थ का परीक्षण के हेतु भेजी जा रही है। इसके परीक्षण के बाद औद्योगिक ढाँचे तथा मशीनों के तैयार करने में काफी मदद मिलेगी।

घनाज का मग्न—गेहूँ का अधिक माना में सग्रह करने के लिए, ऊपर उठाने के यंत्रों से सज्जित भंडार (Silos) बनाने का सुझाव दिया गया है। ये भंडार कलकत्ता के पास कल्याणी तथा बम्बई के पास बॉरिविली (Borivili) में स्थापित किये जायेंगे। इसके अलावा कुछ प्रमुख बन्दरगाहों पर, जहाँ विदेशों से गेहूँ आयात होकर आता है, भी गेहूँ के भंडार बनाये जाएंगे। यदि उपयुक्त भूमि मिल जाय तो ऐसे भंडार बम्बई, कलकत्ता तथा कादला आदि बन्दरगाहों पर बनाये जाएंगे।

रेडियो सेंट—रेडियो सेंट के निर्माण का कार्य प्रस्तुत वर्ष (१९६०-६१) के अन्त तक पूरा हो जाएगा। फिलहाल कुछ फर्मों ने ट्राममीटर बनाने के कारखानों की स्थापना के लिए लायसेंस के हेतु प्रार्थनापत्र भेजे हैं। इसके अलावा

सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित बंगलौर की भारत इलेक्ट्रॉनिक लि० कम्पनी ने भी ट्रांसमीटर व रेडियो बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया है।

ट्रैंक्टरों का निर्माण—ट्रैंक्टरों के उत्पादन का कार्य इस समय दो कारखानों में हो रहा है। इसके अलावा ब्रिटिश मॉडिल के १.२५० ट्रैंक्टर बनाने के लिए भी एक फर्म को लायसेंस दिया गया है। कृषि कार्य की ट्रैंक्टर सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक जर्मन फर्म से समझौता किया गया है। इस प्रकार ट्रैंक्टरों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में बड़े पैमाने पर ट्रैंक्टर बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

मशीनों के औजार (Tools)—मशीनों के छोटे छोटे औजारों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने बंगलौर की हिन्दुस्तान मशीन उपकरण के कारखाने की उत्पादन क्षमता को दुगुना करने का विचार किया है जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जावेगा।

फाउंटनपैन—१९५६ में भारतवर्ष में करीब ११-१२ मिलियन फाउंटन पैनो का निर्माण हुआ जिनकी कीमत १,५७,००० रुपये थी।

६—खनिज साधनों का विकास (Development of Mineral Resources)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थों के बारे में सुनियोजित सर्वेक्षण और ध्यौरेवार पड़ताल की व्यवस्था की गई थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि देश में ये पदार्थ किस-किस किस-किस के और किस-किस माना में उपलब्ध हो सकते हैं। द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास पर जो विशेष बल दिया गया है, उसके कारण इस बारे में पूरे-पूरे ध्यौरे का पता लगाना और भी आवश्यक हो गया है, कि देश में कितना और किस प्रकार का खनिज भंडार है। दूसरी योजना के खनिज विकास कार्यक्रम में कोयले को प्रथम स्थान दिया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में कोई ६ करोड़ टन कोयले की मांग होगी। इस कारण कोयले के उत्पादन, कोयले की धुलाई तथा सफाई (Coal washeries), तेल की जांच पड़ताल और खोज सम्बन्धी कार्यक्रमों को विशेष महत्त्व दिया गया है। इन कार्यक्रमों को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार के भूसर्वेक्षण विभाग (Geological Survey Deptt.) तथा खनिज सर्वेक्षण कार्यालय के ऊपर रखी गई है। इस सम्बन्ध में दूसरी पंचवर्षीय योजना में ७२५ करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही ३६६ करोड़ रु० के विदेशी विनिमय के खर्च की लागत निश्चित की गई।

१९५५-५६ में कोयले का कुल उत्पादन ३८ मिलियन टन हुआ और पंचवर्षीय योजना में २२ लाख टन से ६० लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें

से १२ लाख टन का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में होगा तथा १० लाख टन का उत्पादन निजी क्षेत्र में होगा। इन दोनों क्षेत्रों का कार्यक्रम योजना के मुख्य भाग (core) में सम्मिलित किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रम के लिये मोटे तौर पर ६० करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई जिसमें से १२ करोड़ रुपये गृह निर्माण के लिए रखा गया; यद्यपि योजना की शुरुआत में केवल ४० करोड़ रुपये ही रखे गए थे। कुल लागत में से करीब १२ करोड़ रुपये प्रथम तीन वर्षों तक खर्च हो गया।

१९५६-५७ में कोयला उत्पादन में १.८४ मिलियन टन की वृद्धि हुई। १९५७-५८ में वृद्धि का लक्ष्य ३.२ मिलियन टन था। इस साल के प्रथम ११ महीनों में प्रति माह औसत उत्पादन ४३.३ मिलियन टन हुआ जोकि १९५६-५७ के साल के उत्पादन में ३ मिलियन टन अधिक था। सन् १९५९ में दोनों ही क्षेत्र में कोयले का उत्पादन ४७ मिलियन टन के लगभग हुआ जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र में ६.७५ मिलियन तथा निजी क्षेत्र में ४०.३३ मिलियन टन हुआ। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि योजना काल की पूरी अवधि में कोयले के ६० मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य में ३ से ४ मिलियन टन की कमी रह जाएगी। किन्तु सन् १९६०-६१ में १५-१६ मिलियन टन की कमी महसूस की जा रही है। फूले हुए कोयले की मात्रा बढ़ाने के लिए योजना में कोयला साफ करने के ४ कारखाने खोलने का विचार किया गया है। कारागली के कोयला साफ करने के कारखाने समेत अन्य सभी कारखानों का निर्माण योजना अवधि की समाप्ति के साथ साथ पूरा हो जाएगा। बढती हुई ज़रूरतों को देखते हुए इस तरह के कोयले का उत्पादन बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। तेल की पड़ताल का कार्य भी योजना के प्रारम्भ से ही बड़े जोर जोर से किया जा रहा है। १९५६-५९ में इस कार्य पर ७ करोड़ रुपये खर्च किया गया। फ़िक्कल में भूगर्भ वैज्ञानियों ने अनेक तेल क्षेत्रों का पता लगाया है और इस सम्बन्ध में अभी भी कार्य जारी है। १९६०-६१ तक तेल निकालने के ५ नए कुओं का निर्माण हो चुका है। यह कार्य स्तेनवेक भारतीय सम्झौते (Indo Stanvac Agreement) के अन्तर्गत किया जा रहा है और इस समय पश्चिमी बंगाल तथा बिहार के तेल क्षेत्रों की जांच हो रही है। अभी हाल में ही बर्मा तेल कम्पनी के माफ़े में एक नई रूपी कम्पनी (Rupco Company) का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा नाहौर कटिया तेल क्षेत्र का निर्माण होगा तथा तेल निकालने के लिए नल लगाए जाएंगे। यह कार्य दो अवधियों (Stages) में पूरा होगा। प्रथम अवधि के अन्तर्गत नाहौर कटिया से गौहाटी तक एक पाइप लाइन बनाई जाएगी तथा ०.७५ लाख टन की क्षमता वाले एक तेल साफ करने के कारखाने की स्थापना होगी। द्वितीय अवधि (Stage) के अन्तर्गत बरोनी (Barauni) तक पाइप लाइन का विस्तार होगा और वहाँ १.५ से २.० मिलियन टन की क्षमता वाले एक तेल साफ करने वाले कारखाने

की स्थापना होगी। सरकारी हिस्सेदारी से बनी रूपी कम्पनी तथा गौहाटी के तेल साफ करने के कारखाने के निर्माण पर योजना बाल में, २४ करोड़ रु० की राशि खर्च की जाएगी। साथ ही पश्चिमी जर्मनी भूगर्भसामग्री तथा भूगर्भवेत्ताओं द्वारा तेल उद्योग के विकास के लिए जाँच पड़ताल की जाएगी।

कोयला उत्पादन के विकास के सम्बन्ध में बहुत कुछ उन्नति हुई है। यद्यपि भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग तथा खनिज सर्वेक्षण कार्यालय के विकास बाय में काफी ढील घटती जा रही है जिसके कारण भू-भौतिक तथा भू-रसायनिक तरीकों और उपयोगों का तथा जाँच पड़ताल का कार्य उस स्तर से नहीं चल रहा है जैसी कि आशा व्यक्त की गई थी। जुलाई सन् १९६० से इस काम में कुछ तेजी अवश्य आ गई है और वर्तमान अनुमानों के आधार पर ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है कि इस कार्य पर करीब ८५ करोड़ रु० खर्च हो जाएगा।

८—यातायात और सवाहन

(Transport & Communication)

यातायात और सवाहन के लिए द्वितीय योजना में १३ अरब ८५ करोड़ रुपये स्वीकार किया गया है जिसमें से ६ अरब के लगभग रुपये रेलवे पर खर्च किया जाएगा। नीचे हम यातायात के विभिन्न साधनों का वर्णन करते हैं :

रेल (Railways) :

दूसरी योजना में रेलवे यातायात का अत्यधिक विस्तार करने का निश्चय किया गया है क्योंकि यातायात का अधिकतम भार उमें ही वहन करना पड़ता है तथा भविष्य के लिए भी ऐसी ही सम्भावनाएँ हैं। इस दृष्टि से रेलों के विकास के लिए योजना में ११२५ करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है जिसमें २२५ करोड़ रु० का घिसावट व्यय (depreciation) भी शामिल है। इसी सदर्थ में ४२५ करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय भी स्वीकार किया गया है।

यद्यपि यह अनुमान लगाया गया था कि योजना के अन्तिम वर्ष तक सामान यातायात (Freight Traffic) का वजन ६१ मिलियन टन हो जाएगा और कुल वजन ले जाने के सम्बन्ध में १८१ मिलियन टन की वृद्धि होगी लेकिन योजना में वजन के सम्बन्ध में निम्नलिखित सीमा निर्धारित कर दी गई थी :

	मिलियन टन
१. कोयला	१३
२. फोलाद—कोयले को छोड़कर कच्ची सामग्री सहित	१८
३. सीमेन्ट	४
४. फुटकर माल	७
कुल	४२ लाख टन

यात्री गाड़ियों के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत तथा योजना की कुल अवधि में १५ प्रतिशत वृद्धि करने का निश्चय किया गया है फिर भी इससे बढ़ती हुई भीड़ का सामना करने की कोई आशा व्यक्त नहीं की गई है।

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रेल कार्यक्रम के लिए जो ११२५ करोड़ रुपया स्वीकार किया गया था मूल्य वृद्धि के कारण उसमें १०० करोड़ रुपए की वृद्धि और होगी। चूंकि आय के सीमित साधनों को देखते हुए इस बढ़ी हुई राशि का जुटाना सम्भव नहीं है। साथ ही विदेशी विनिमय की भी कमी है। अतः इस कारण रेल के कुछ कार्यक्रमों को फिन्हास स्थगित कर देना पड़ेगा। स्थगित होने वाले कुछ कार्यक्रम नीचे दिये जाते हैं—

१. कलकत्ता क्षेत्र के सियाल्दा डिबोजन तथा टम्बारम-बिलूपुरम विभाग का विद्युतीकरण कार्यक्रम,

२. मीटर गेज कोच फैक्टरी (Metre Gauge Coach Factory)

३. इन्टीग्रल कोच फैक्टरी (Integral Coach Factory-Furnishing Unit)

४. गुना तथा उज्जैन के बीच में नई रेल लाइन का निर्माण।

रेलवे बोर्ड ने इस बात पर अपनी स्वीकृति दे दी है कि विदेशी विनिमय में ४८ करोड़ रुपए की बचत की जाय। इसके बारे में योजना के प्रारम्भ में कोई ध्यान नहीं दिया गया था। लक्ष्यों की पूर्ति के सम्बन्ध में ऐसी आशा व्यक्त की जाती है कि सन् १९६०-६१ तक रेलें ४२ मिलियन टन अनिश्चित माल की दुलाई करने में समर्थ हो जाएगी किन्तु इस मात्रा के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सवारी गाड़ियों के सम्बन्ध में जो ३ प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था वह भी योजना की अवधि तक पूरा हो जाएगा। रेलवे विकास के लिए दूसरी योजना की कुल लागत, प्रथम तीन वर्षों में हुए अनुमानित व्यय तथा आखिरी दो वर्षों में होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत रेलवे विकास पर हुए व्यय की सारिणी

करोड़ रुपया

विवरण कार्यक्रम	योजना में निर्धारित लागत	१९५६-५७ का व्यय	५७-५८ का अनुमानित व्यय	५८-५९ की बजट लागत	५९ से ५९ तक का अनुमानित व्यय	१९५९-६१ तक के व्यय या अनुमान	कुल व्यय १९५६ से ६१ तक का
रेल	१८००.००	१३४.००	१८०.००	२१५.००	२३८.००	३७५.५०	८८६.५०

नोट—इसमें २२५ करोड़ रुपये की वह राशि सम्मिलित नहीं है जो घिसाई व्यय खाते में उपलब्ध की गई है। इस ६०० करोड़ ६० की योजना लागत में ३५ करोड़ ६० विशाखापट्टम बन्दरगाह रेल निर्माण की व्यय सम्मिलित है किन्तु अब विशाखापट्टम बन्दरगाह रेल निर्माण की जिम्मेदारी रेल मन्त्रालय से यातायात मन्त्रालय को सौंप दी गई है। (W.C.F., 1. 10. 56)

विदेशी लोग जो भारत में परिभ्रमण के लिए आते थे उनकी संख्या में सन् १९५१ की तुलना में चार गुनी वृद्धि हुई। १९५८ में पाकिस्तानियों को छोड़ कर ६२,२०२ विदेशी यात्री भारत में आए। १९५६ में प्रथम ग्यारह महीनों में ७५,५१२ विदेशी यात्री भारत में आए। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की गणना के अनुसार १९५६, ५७, ५८ में इनसे क्रमशः १५.५, १६.०० तथा १७.५ करोड़ रुपये की आमदनी हुई।

विदेशी व्यापार (Foreign Trade)—कमेट्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि सन् १९५६ में विदेशी व्यापार आय में काफी वृद्धि हुई। सन् १९५६ में विदेशी व्यापार को ६२६ करोड़ की आय हुई। पिछले वर्ष की तुलना में १०.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। सबसे अधिक वृद्धि साल के पिछले पाँच महीनों में हुई, यह वृद्धि ५२ करोड़ रुपये प्रति माह थी। जबकि १९५७ में यह आय ५३.० करोड़ और १९५८ की ५३.४ करोड़ रुपया थी।

सन् १९५६ तक बहुत सी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई। सबसे अधिक वृद्धि कारखानों के तैयार माल, सूती वस्त्र, हाथ करघा क वस्त्र, चमड़े की वस्तुओं तथा खाल के निर्यात में हुई। पिछले साल से सीमेन्ट तथा कच्चे लोहे तथा कुछ इन्जीनियरिंग के सामान का निर्यात भी शुरू हो गया है।

कृषि की व्यापारिक फसलों की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। चाय, नपास, तम्बाकू तथा तिलहन के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई अपितु कुछ अंशों तक इनके निर्यात में काफी गिरावट हुई।

राष्ट्रीय आय—राष्ट्रीय आय की वृद्धि का रूप विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्पादन के विकास में देखा जा सकता है। दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि करना था जिसमें कि देश के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो जाय और प्रति व्यक्ति औसत आय में भी वृद्धि हो जाय। इस दृष्टिकोण के आधार पर योजना की ५ साल की अवधि में २५ प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था।

सन् १९५८-५९ में भारत की राष्ट्रीय आय, १९४८-४९ की कीमतों के आधार पर, ११,६६० करोड़ रुपया थी, १९५७-५८ में १०,८६० करोड़ रुपया तथा १९५५-५६ में १०,४८० करोड़ रुपया थी। इसी प्रकार १९४८-४९ की कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत आय, सन् १९५८-५९, ५७-५८ तथा ५६-५७ में क्रमशः २६३ ६ ६०, २७७ १ ६०, तथा २७३ ६ ६० हुई। १९५८-५९ की राष्ट्रीय आय की सीमा केवल अनुमानों के आधार पर ही की गई है जो १९५६ की साल के अक्टूबर महीने तक की उत्पादन-प्रगति पर ही आधारित है।

सन् १९५७-५८ में कृषि उत्पादन में काफी कमी हुई जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में भी कमी हुई। इसी प्रकार कृषि उत्पादन की कमी के कारण सन् १९५८-५९ में भी राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई वह भी पिछली वर्ष की तुलना में काफी कम थी। १९४८-४९ की कीमतों के आधार पर १९५८-५९ में राष्ट्रीय आय में ८०० करोड़ रु० की वृद्धि हुई जिसमें ५७० करोड़ रु० की वृद्धि अकेले कृषि उत्पादन के कारण हुई। दूसरे शब्दों में १९५७-५८ की तुलना में सन् १९५८-५९ में राष्ट्रीय आय में ७३ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निम्नलिखित तालिका में सन् १९४८-४९ की कीमतों के आधार पर पिछले ११ वर्षों की राष्ट्रीय आय तथा प्रतिव्यक्ति औसत आय का विवरण दिया गया है :

वर्ष	कुल राष्ट्रीय आय (करोड़ रुपये में)	प्रति व्यक्ति औसत आय (रु०)
१९४८-४९	८,६५०	२४६.६
१९४९-५०	८,८२०	२४८.६
१९५०-५१	८,८५०	२४९.३
१९५१-५२	९,१००	२५०.१
१९५२-५३	९,४६०	२५६.६
१९५३-५४	१०,०३०	२६८.७
१९५४-५५	१०,२८०	२७१.९
१९५५-५६	१०,४८०	२७३.६
१९५६-५७	११,०००	२८३.५
१९५७-५८	१०,८९०	२७७.१
१९५८-५९	११,६९०	२९३.६

प्रस्तुत तालिका से ज्ञात होता है कि दूसरी योजना के प्रथम ३ वर्षों अर्थात् १९५६-५९ तक राष्ट्रीय आय में वास्तविक रूप से ११.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि प्रतिवर्ष वृद्धि के आधार पर तीनों वर्षों में १५ प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल की पाँच वर्षों की अवधि में अर्थात् १९५१-५६ से १९५५-५६ तक राष्ट्रीय आय में १८.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दोनों योजनाओं की ऊपर कही कुछ अवधि में प्रतिव्यक्ति की औसत आय में क्रमशः ७.३ तथा ११.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्तमान कीमतों के आधार पर सन् १९५८-१९५९ में १०,४७० करोड़ रु० तथा १९५७-५८ में ११,४०० करोड़ रु० की राष्ट्रीय आय हुई जबकि १९५५-५६ में यह आय केवल ९९८० करोड़ रुपया थी। इसी प्रकार वर्तमान कीमतों के आधार पर, १९५८-५९, ५७-५८, तथा ५६-५७ में क्रमशः ३१३२, २९०१, २६०९ रु० की प्रतिव्यक्ति औसत आय हुई।

२६ दिसम्बर सन् १९५९ तक भारतीय जहाजरानी की वहनीय मात्रा में अनुमानत ७२९ लाख टन की अभिवृद्धि हुई जबकि सन् १९५८ का कुल उत्पादन ६३८ लाख टन था। उक्त आंकड़े सरकारी यातायात विभाग द्वारा प्रकाशित किए गए हैं।

प्रस्तुत वर्ष सन् १९५९-६० में मर्चेण्ट शिपिंग एक्ट आफ १९५८ के अनुसार १ करोड़ रु० की लागत से जहाजरानी विकास कोष की स्थापना की गई जिसमें से कोष की समिति (Fund Committees) ने ५२ लाख रु० १९५९-६० में व्यय किए तथा ७३५ लाख रुपए सरकार द्वारा कर्ज के रूप में दिए गए।

जहाजरानी उद्योग

युद्ध के बाद जहाजरानी की प्रगति होने की जो आशा की गई थी वह बहुत ही धीमी रही है। दूसरी योजना में जहाजरानी के विकास के लिए ४५ करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें ८ करोड़ रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधूरे कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए रखा गया है। योजना में १८०,००० जी० आर० टी० टन के लिए नए जहाज बनाने का निश्चय किया गया है जिससे पुराने जहाजों को हटाया जा सके। योजना की अवधि में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ४५ करोड़ रु० की प्रतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी।

निम्नलिखित तालिका में जहाजरानी विकास के लिए निर्धारित राशि को बताया गया है। योजना के प्रथम ३ वर्षों का खर्च तथा अन्तिम २ वर्षों के खर्च को अलग-अलग प्रदर्शित किया गया है।

प्रकरण	कुल लागत	करोड़ रुपया					
		५६-५७ का व्यय	५७-५८ का प्रस्तावित व्यय	५८-५९ का बजट लागत	५९ से ५९-५९ का अनुमानित व्यय	५९ से ६० का अनुमानित व्यय	६० से ६१ तक का कुल व्यय
जहाजरानी	४५०० ^१	८९७	९४३	९८८	२८२८	२५००	५४१८

१ जिसमें जलवाहक जहाज उद्योग मैरीन नोटिकल इन्जीनियरिंग कालिज तथा अन्टमन ट्रॉप के जहाजों का खर्च सम्मिलित नहीं है।

बन्दरगाह एवं गोदी (Harbours and Ports)

दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े-बड़े बन्दरगाहों, जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, विशाखापट्टनम्, कोचीन तथा कादिला आदि के विकास और विस्तार के लिए ४३.५ करोड़ रु० रखा गया है। किन्तु समस्त बन्दरगाहों के विकास के लिए ७६.६ करोड़ रु० की राशि रखी गई है इसके अलावा जो अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ेगी वह बन्दरगाहों के निजी साधनों द्वारा पूरी की जाएगी। बन्दरगाहों की निजी देम १८ करोड़ रुपया आंकी गई है किन्तु बन्दरगाहों के पुनर्निर्धारित कार्यक्रमों के लिए १० करोड़ रु० के खर्च का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार उपलब्ध आय के स्रोत तथा अनुमानित अतिरिक्त व्यय में काफी अन्तर है। १०० करोड़ रु० के विदेशी विनिमय की जो आवश्यकता समझी गई थी उसमें से भी केवल ३५ करोड़ रुपया प्राप्त हो सकेगा।

योजना में बन्दरगाहों के द्वारा माल ढोने के सम्बन्ध में २५ मिलियन टन से ३२ मिलियन टन प्रतिवर्ष के लदान का निश्चय किया गया। किन्तु मुख्य बन्दरगाहों द्वारा १९५८-५९ में कुल माल का आयात-निर्यात २८.७ मिलियन टन ही हुआ जबकि पिछली साल (१९५७-५८) में ३१ मिलियन टन माल ढोया गया।

१९५६-६० के सरकारी बजट में बन्दरगाहों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित व्यय का निर्धारण किया गया था—

१४५ लाख रुपया	कादिला बन्दरगाह के विकास के लिए।
२८ " "	गान्धी नगर-निर्माण योजना के लिए (जो बन्दरगाह या गोदी से सम्बन्धित होगा)।
६० " "	का शहर कलकत्ता तथा बम्बई आदि बड़े-बड़े बन्दरगाहों के विकास के लिए सहायता के रूप में दिया जावेगा।

इसी प्रकार १९६०-६१ के केन्द्रीय बजट में बन्दरगाहों के विकास के लिए निम्नलिखित धन-राशि निर्धारित की गई है—

१८२ लाख रु०	कादिला बन्दरगाह के लिए।
२५ " "	गान्धी नगर-निर्माण कार्य के लिए।
७७ " "	विशाखापट्टनम् के केन्द्रीय विकास के लिए।

उसके साथ ही ३०० लाख रु०, बड़े-बड़े बन्दरगाहों के केन्द्रीय विकास कार्यक्रम के लिए (जिसमें कि कलकत्ता और कोचीन के बन्दरगाह आते हैं) दिया जावेगा।

इस प्रकार योजना की अवधि में अब तक जो कार्य किए गए हैं तथा आगे के कार्य क्रम के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उससे अनुमानों के आधार पर यह आशा व्यक्त की जाती है कि पूरे पांच वर्ष में लगभग २ करोड़ ५० लाख टन माल का आयात हो सकेगा। इसके साथ ही इस बात का भी निश्चय किया गया है

कि बन्दरगाहों सम्बन्धी दीर्घकालीन कार्यक्रमों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जायेगा तथा ऐसे कार्यक्रमों को, जो थोड़े ही समय में पूरे हो सकें, हाथ में लिया जावेगा। हमारे योजना में जो बड़ा ध्येय स्वीकार किया गया है उसके अनुसार पहली योजना द्वारा हाथ लिए कार्यों को पूरा किया जावेगा। गोदियो का आधुनिकीकरण करके उन्हें आवश्यक सामान से सज्जित किया जावेगा जिससे देश में होने वाले औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकेंगी। योजना में प्रमुख बन्दरगाहों से सम्बन्ध रखने वाले सब कार्यों के लिए ४३.५ करोड़ रुपये रखा गया है। जो काम पहली योजना में शुरू किए गए कार्यक्रमों के पूरा करने के साथ किए जाएँगे उनमें कुल ७६.६ करोड़ रुपये खर्च होना का अनुमान है। समुद्री यात्रा सस्त्रानों के छोटे छोटे हिस्सों का विकास करने के लिए पारादीप, मंगलौर और मालपी में सबन्धु गोदियों की व्यवस्था करने के समस्त कार्यों को करने के लिए और सेतु समुद्रम योजना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक काम करने के लिए जिनमें तुनु-कुडि का विकास भी सम्मिलित है, योजना में ५ करोड़ २० के लगभग की व्यवस्था की गई है। योजना के अनुसार नए प्रकाश स्तम्भों का निर्माण और वर्तमान प्रकाश-स्तम्भों का आधुनिकीकरण इस दृष्टि से किया जायेगा जिससे उनको वर्तमान साधनों से लैस किया जा सके।

योजना के अन्तर्गत कुल लागत व्यय का व्यौरा निम्नलिखित सूची में दिया गया है जिसमें प्रथम ३ वर्षों का तथा अंतिम दो वर्षों के खर्च को अलग-अलग बताया गया है—

करोड़ रुपये

कार्य का प्रकार	योजना में प्रस्तावित लागत	५६-५७ का व्यय	५७-५८ का अनुमानित व्यय	५८-५९ की बजट लागत	५९ से ६६ तक का अनुमानित व्यय	६६ से ६९ तक के वर्षों का अनुमान	६९ से ७१ तक की कुल लागत
बन्दरगाह	४०.००* १८.००†	८.०१	८.२६	६.००	२५.३०	१८.२०	४३.५० १८.००†

सड़क यातायात

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के विकास के लिए २४६ करोड़ ६० रखा गया है। इसके अलावा २५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सड़क कोष (Central Road

* इसमें ३५ करोड़ ६० का विशाखापट्टनम का व्यय सम्मिलित नहीं है जो पहले रेलवे कार्यक्रम में सम्मिलित था।

† यह १८ करोड़ का राशि बन्दरगाहों के निजी आय के स्रोतों द्वारा प्राप्त की जाएगी।

Board) से प्राप्त होगा। इसमें से ६४'७ करोड़ रु० केन्द्रीय सड़क निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत यातायात मन्त्रालय द्वारा दिया जायेगा तथा १५१'४ करोड़ रुपया राज्य सरकारों द्वारा खर्च किया जायेगा। योजना में २०,००० मील लम्बी पक्की सड़कों का निर्माण होगा। इसके अलावा अन्य छोटी कच्ची तथा पक्की सड़कों, बड़े-बड़े पुलों तथा पुलियों का भी निर्माण होगा। यह आशा की जाती है कि इस धन राशि से नागपुर योजना के अनुसार स्थिर किया गया कार्यक्रम करीब करीब पूरा कर लिया जायेगा।

पहली पंचवर्षीय योजना में बड़ी राष्ट्रीय सड़कों के विकास के लिए जिनमें जम्मू और काश्मीर की बनिहाल सुरग भी सम्मिलित है, २८ करोड़ रुपया रखा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए ५५ करोड़ रुपया रखा गया है। कार्य की मितव्ययता से करने तथा निरन्तर जारी रखने के लिए योजना की अवधि में वस्तुतः ८७ करोड़ ५ लाख रुपया का काम हाथ में लिया जाएगा। पहली योजना में शुरू किए काम को जारी रखने के लिये ६०० मील लम्बी नई सड़कें—एक दूसरे से आपस में मिलाने के लिए तथा ६० बड़े पुल बनाए जायेंगे। केन्द्रीय सरकार ने पहली योजना की अवधि में राष्ट्रीय सड़कों के अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यक सड़कों के निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ है। यह कार्य दूसरी योजना की अवधि में भी जारी रहेगा। इनमें पाठी बरदपुर सड़क, पश्चिमी तटवर्ती सड़क तथा पठानकोट ऊषमपुर के बीच की एक दूसरी सड़क भी सम्मिलित है। १९५४ में शुरू की गई वे अन्तर्राष्ट्रीय सड़कें भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, जिनका निर्माण आर्थिक दृष्टि से आवश्यक था। विभिन्न राज्यों में गाँवों की सड़कों के निर्माण एवं सुरक्षा व्यवस्था और उन पर विभिन्न सूत्रों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में समन्वय पैदा करने के लिये पूरी सावधानी रखने के कार्य को भी दूसरी योजना के कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

दूसरी योजना में सड़क यातायात पर किए गए कुल व्यय की सूची

खर्च के प्रकरण	योजना लागत	५६-५७ का व्यय	५७-५८ का प्रस्तावित व्यय	५८-५९ का वजेट अनुमान	५९ से ५९ तक का अनुमानित व्यय	५९ से ६१ तक का अनुमानित व्यय	कुल व्यय ५६ से ६१ तक का
केन्द्रीय कार्य-क्रम (केन्द्रीय प्रा. को छोड़कर)	८२'००	१४'२३	१३'११	१८ ६७	४०'०५	२६ ००	६६'०५

राज्य सरकार की योजना (पांडिचेरी व के द्रीय प्रांत समेत)	१६४ १२	२८ ४८	३१ १७	२६ ५६	८७ २१	६३ ००	१५० २१
कुल व्यय	२४६ १२	४२ ७१	४४ ३२	४२ २३	१२७ २६	६२ ००	२१६ २५

संचार और प्रसारण

योजना में संचार साधना एवं प्रसारण के विकास के लिए ११० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से ५१ करोड़ रुपये विदेशी विनियम से प्राप्त होगा। पूरे व्यय का और बार वणन इस प्रकार है

व्यय की विभिन्न मदें (Items)	कुल लागत	विदेशी विनियम से प्राप्ति
१—डाक व तार विभाग	६३ ००	१७ ८६
२—भारतीय टेलीफोन उद्योग	० ५०	० ७०*
३—वैदेशिक संचार सेवाएँ	२ ००	१ १०
४—भारतीय मनु विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Deptt.)	१ ५०	० ८४
५—Civil Aviation Deptt.	१२ ५०	५ ६८
६—Indian Airlines Corporation	१६ ००	७ ७५
७—Air India International	१४ ५०	१६ ८२†
योग	११० ००	५० ७८

डाक व तार विभाग के कार्यक्रम में स्थानीय तार सेवाओं की योजना पर २६ करोड़ रुपये व्यय होगा और ८५ करोड़ रुपये टंक फोन व सांख्यिक फोन पर व्यय होगा। यन्त्रें हुए ४२ १४ करोड़ रुपये डाकखानों पर व्यय किए जायेंगे। इसके चलाना १ करोड़ ८५ लाख रुपये डाक तार विभाग अपनी आमदनी में से योजना की अवधि में नए डाकखाने खोलने पर व्यय करेगा। इन दोनों कार्यक्रमों में विदेशी विनियम की राशि भी सम्मिलित है। स्थानीय तार सेवाओं व सम्बन्ध में ऐसी आशा

* यह रुपये २१८ लाख रुपये के अनुमानित व्यय से अलग है जिसका अधिकांश भाग उद्योगों के निजी साधनों द्वारा प्राप्त होगा।

† इसमें कुछ रकम बढ़ भी है जो निगम के निजी साधनों द्वारा एकत्र की जायगी।

व्यक्त की गई है कि योजना की अवधि में १,८०,००० नए फोन लगाए जा सकेंगे। योजना में सारे देश में टुक फोन की व्यवस्था का यथेष्ट रूप से प्रबन्ध किया गया है। योजना के अन्तर्गत बम्बई-दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली अमृतसर, अम्बाला शिमला, और थाना-पूना के बीच लम्बे भूमिगत तार बिछाने का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है।

टेलीफोन के विस्तार का कार्यक्रम मुख्यतः देश में टेलीफोन के यन्त्र और ऐक्सचेंज लाइन बनाने तथा भारतीय टेलीफोन उद्योगों के उत्पादन कार्यक्रमों पर निर्भर करता है। दूसरी योजना में मोटे तौर पर भारतीय टेलीफोन उद्योगों के कार्यक्रम में ४० हजार ऐक्सचेंज लाइन तथा ६० हजार टेलीफोन यन्त्र प्रतिवर्ष बनाने का निश्चय किया गया है। उद्घयन विभाग के लिए योजना में १०५ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके बारे में यह कहा गया है कि विदेशी विनिमय की कमी के कारण उद्घयन विभाग के कुछ कार्यक्रम स्थगित करने पड़ेंगे और इस सम्बन्ध में योजना द्वारा प्रस्तावित रकम में वृद्धि करनी पड़ेगी। उद्घयन निगम के जो दो कार्यक्रम हैं उनका विकास पूर्ण रूप से हो सकेगा।

प्रसारण—प्रसारण के विकास के लिए योजना में ६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से ३५२ करोड़ रुपये विदेशी विनिमय से प्राप्त होगा। योजना में प्रत्येक भाषा के क्षेत्र में कम से कम एक सत्रेण केन्द्र के कायम किए जाने और देश के सभी क्षेत्रों को प्रसारण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना का लक्ष्य यह है कि इस समय प्राप्त सेवाओं का विस्तार सभी भाषाओं के लिए यथामुम्भव अधिक से अधिक क्षेत्र में बाँट दिया जाए। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए बढ़ती हुई माँग और राष्ट्रीय प्रसारण के देशव्यापी सत्रेण की आवश्यकता को देखते हुए, यह प्रस्ताव किया गया है कि दिल्ली में १००-१०० किलोवाट के पार्ट-वेव तथा मीडियम वेव सत्रेण केन्द्र लगाए जाँय जिनसे वैदेशिक प्रसार सेवाओं की अनिश्चित सुनिश्चाई प्राप्त हो जाएँगी। इसी प्रकार कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में भी ५०-५० किलोवाट के सत्रेण केन्द्र बनाए जाएँगे। देहाती क्षेत्रों में १ हजार से अधिक आवादी वाले गाँवों में सामुदायिक अथवा पंचायती रेडियो लगाए गए हैं। स्टुडियो तथा टेलीविजन के निर्माण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है।

योजना की अवधि में संचार व प्रसारण सम्बन्धी

निम्नालिखित व्यय होगा

मदें	योजना द्वारा प्रस्तावित लागत	५६-५७ का व्यय	५७-५८ का प्रस्तावित व्यय	५८-५९ का वजट अनुमान	५९ से ५९ तक का अनुमानित व्यय	५९ से ६१ तक के व्यय का अनुमान	५९ से ६१ तक का कुल व्यय
------	------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------

संचार	६'००	१'४५	१'१७	१'३०	३'६२	२'५०	६'५
प्रसारण	११०'००	१८'५०	२०'१४	२१'७७	६०'४१	३७'००	६७'५

६—'कोर' कार्यक्रम

(Core-project)

१९५७ में ही इस बात की आवश्यकता समझी गई थी कि योजना की उन प्राथमिकताओं को सही रूप से प्रकट कर दिया जाय जो विदेशी विनिमय पर आधारित हैं ताकि योजना की नींव मजबूत करने वाले प्रथम योजना की पृष्ठभूमि तैयार वाले कार्यों को सफलतापूर्वक चलाया जा सके। 'कोर' कार्यक्रम (Core Project) में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित हैं— लोहा तथा इस्पात उद्योग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के कोयला तथा लिग्नाइट (Lignite) सम्बन्धी कार्यक्रम, बड़े-बड़े बन्दरगाहों तथा रेलवे विभाजन के कार्यक्रम, कुछ चुने हुए विद्युत सम्बन्धी कार्यक्रम जो कि बहुत समय पूर्व में ही विदेशी सहायता द्वारा चलाए जा रहे हैं।^१

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए 'Core Project' में १६०० करोड़ रुपए की विदेशी विनिमय की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से करीब १,१२० करोड़ रुपया प्रथम तीन वर्षों में खर्च होने की आशा व्यक्त की गई थी।

सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में Core Project के अन्तर्गत ६६२ करोड़ के विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ेगी। इस रकम के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है—

करोड़ रुपया

Projects	द्वितीय योजना की कुल विदेशी विनिमय की लागत	३१-३-५८ तक हुआ कुल वास्तविक व्यय	कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रतिरिक्त धनराशि
इस्पात			
(अ) सार्वजनिक क्षेत्र			
१-मिलाई का इस्पात का कारखाना	८५.६७	८०.६८	४.९९
२-रूरकला " "	१२०.००	१०७.३५	१२.६५
३-दुर्गापुर " "	६५.६०	६०.६०	५.००
४-मंसूर लोहे तथा इस्पात कार्यक्रम का फंडो सिलेक्शन उद्योग	०.६५	०.६५	...
(प्र) निजी क्षेत्र	८६.३५	७४.४३	११.९२

कोयला			
(अ) सार्वजनिक क्षेत्र			
१-एन० सी० डी० सी० (N.C.D.C.)	१५'००	५'८३	६'१७
२-सिंगरैनी कालरीज	०३'२५	१'८५	१'४०
(आ) निजी क्षेत्र			
१-कोयला साफ करने के कारखाने	१०'००	३'३०	६'७०
२-(Naveli) नेवली लिग्नाइट प्रोजेक्ट (खदान कार्य)	७'५०	२'५०	५'००
रेलवे (विदेशी विनिमय की आवश्यकता वाले कार्यक्रम)	१०'५०	६'७०	३'८०
बन्दरगाह (बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विजया-पटनम तथा अन्य) (Dredger Pool)	४३१'६३ ^१	२५८'०० ^२	१७३'६३ ^२
विद्युत शक्ति सम्बन्धी कार्यक्रम	३५'००	८'८६	२६'११
	६०'४०	२४'४०	३६'००
	६६१'८५	६६५'४८	२६६'३७

'Core Project' के सम्बन्ध में आवश्यक विदेशी विनिमय की प्रत्येक जरूरतों के लिए ८० करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें से कटौती करने की कोई घोषणा नहीं की गई है। इस प्रकार द्वितीय योजना में अधिकाधिक प्रयत्न इस बात का किया गया है जिसमें 'Core Project' की सभी मदों को विदेशी सहायता सम्बन्धी अपनी (निजी) जरूरतों को बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा करने का सुभवसर मिल सके तथा जो योजनाएँ विदेशी सहायता प्राप्त करने में अग्रगण्य रहेंगी उनके लिए सरकार द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय से सहायता दी जावेगी।

१०—सामाजिक सेवाएँ

(Social Services)

प्रत्येक स्वतन्त्र देश की केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि देश के आर्थिक विकास के लिए समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों को वह स्वयं पूरा करे। इस प्रकार समाज कल्याण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यों का व्यय सरकार स्वयं सहन करती है। ऐसे समय में, जबकि किसी देश का तीव्रगति में व्यापक पैमाने पर, औद्योगिक विकास किया जा रहा हो, समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों को करना नितांत आवश्यक है जिससे कि रहन-सहन के स्तर में जो विपरीतताएँ हैं व दूर हो जायें तथा सबको उन्नति

१. विद्युत सम्बन्धी विदेशी सहायता का पूरा विवरण सिचाई एवं जल विद्युत विकास के तृतीय अनुभाग में दिखलाया गया है।

२. इसमें रेलवे विद्युतीकरण कार्य कम के अंतर्गत हुए डाक व तार सम्बन्धी जरूरतों का ९.६२ करोड़ रु० भी सम्मिलित है।

करने के समान धनमय प्राप्त हो सकें और नए विकास कार्यों से अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो। सामाजिक सेवाओं के कार्य क्षेत्र में सरकारी साधनों के अलावा अन्य साधनों जैसे व्यक्तिगत सेवा कार्य, स्थानीय सामुदायिक विकास कार्य तथा स्वैच्छाचारी धर्म से भी प्रगति होगी। जनतन्त्रोप प्रणाली का दावा है कि देश के अन्दर वर्तमान सभी साधनों को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करना चाहिए।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए जो साधन प्रदान किए जाएंगे उनसे ६४५ करोड़ रुपये की धन्य होगी धर्मार्थ योजना की कुल लागत का १६.७ प्रति भाग सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया जावेगा। इसमें से ४५६ करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा खर्च किया जायेगा तथा १६६ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय किया जावेगा। सामाजिक सेवाओं की विभिन्न मदों पर योजना में जो रकम निर्धारित की गई तथा १६५८-५९ में जो उसका पुनर्निर्धारण किया गया उसका व्यौरा निम्न लिखित तालिका में दिया गया है।

विभिन्न सामाजिक सेवाएँ	द्वितीय योजना की प्रस्तावित लागत व्यय			योजना द्वारा दुबारा निर्धारित की गई धन राशि (व्यय)		
	कुल केन्द्रीय राज्यों का व्यय व्यय व्यय			कुल केन्द्रीय राज्यों का व्यय व्यय व्यय		
१—शिक्षा	३०७	६५	२१२	२८५	७५	२१०
२—स्वास्थ्य	२७४	६०	१८४	२५१	७५	१८०
३—गृह-निर्माण	१२०	४७	७३	१००	२७	७३
४—पिछड़ी जातियों का कल्याण	६१	३२	५६	८३	२४	५६
५—पुनर्वासि	६०	६०	...	६०	६०	...
६—सामाजिक कल्याण धर्म, धर्म-कल्याण तथा शिक्षित बेरोजगारी का कार्यक्रम	६३	४२	२१	५०	३०	२०

सन् १९१६ में योजना पर जब पुनर्विचार हुआ तो सामाजिक सेवाओं के लिए १८ प्रतिशत खर्च की व्यवस्था की गई जबकि योजना का लक्ष्य १६.७ प्रतिशत खर्च का था जैसा कि उपर्युक्त तालिका को देखने से विदित होता है।

शिक्षा (Education) :

आर्थिक विकास की गति जितनी तेज की जा सकती है और उससे जो लाभ उठाए जा सकते हैं, उनको निश्चित करने में शिक्षा-पद्धति का विशेष महत्त्व होता

है। इसी उद्देश्य से दूसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के तीव्र विकास के लिए ३०७ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जबकि पहली योजना में केवल १६६ करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई थी।

सन् १९५६-५७ में शिक्षा के विकास पर २३ करोड़ रुपया खर्च किये गये। १९५७-५८ में बढ़कर ये खर्च ३७ करोड़ रुपये हो गया और करीब ५० करोड़ रुपया सन् १९५८-५९ में व्यय हुआ। वर्तमान प्रगति के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक शिक्षा पर केवल १०६ करोड़ रुपय खर्च किये जा सकेंगे जबकि योजना में ३०७ करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से करीब २७ करोड़ रुपया राज्यों द्वारा तथा ८० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय किया जायगा। निम्नलिखित तालिका में योजना की प्रथम तीन वर्षों की शिक्षा-प्रगति का व्योरा दिया गया है।

प्रकरण (Item)	इकाई	पंचवर्षीय योजना लक्ष्य	१९५६-५७ की प्रगति	१९५७-५८ की वास्तविक प्रगति	१९५८-५९ की प्रगति का निर्धारित लक्ष्य	१९५६ से ५९ तक प्रगति
१—विभिन्न आयु वालों के लिए स्कूल सम्बन्धी सुविधाएँ	लाख					
६—११	"	७७.२८	२०.००	२१.२५	२२.५०	६३.७५
११—१४	"	१२.६३	२.७०	३.००	३.३५	६.०५
१४—१७	"	७.६७	२.६०	२.६०	२.६०	७.८०
२—शिक्षा संस्थाएँ	कुल					
१—प्राइमरी स्कूल	संख्या	५२,७६२	२२,२००	२३,६००	२५,०००	७०,८००
२—जूनियर बेसिक मिडिल स्कूल	"	२७,४४०	५,६५०	४,७००	६,७००	१४,०५०
३—सीनियर बेसिक मिडिल स्कूल	"	३,४५५	१,३५०	१,५००	१,६७५	४,५२५
४—हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) स्कूल	"	१५२५	१,४४०	१,४४०	१,४४०	४,३२०
५—बहु उद्देशीय शिक्षा संस्थाएँ	"	८३७	११७	१३३	१५०	४००

तकनीकी शिक्षा (Technical Education) के लिए योजना में ४८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जो बढ़ा कर ५७ करोड़ कर दी गई। इस कार्यक्रम पर प्रथम तीन वर्षों में २२ करोड़ रुपये खर्च किया गया। अभियंता अधिकारी समिति (Engineering Personnel Committee) ने तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम की २,७६४ सीटें तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Diploma Courses) की ८,२२१ सीटें बढ़ाने की सिफारिश की। प्रस्तुत सीटें वर्तमान शिक्षा संस्थाओं का विस्तार करके बढ़ाई जाएंगी। १८ नए विद्यालय तथा ६२ प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापित की जाएंगी। प्रस्तुत तालिका में योजना के प्रथम तीन वर्षों की शिक्षण संस्थाओं की प्रगति का विवरण दिया गया है, जिससे विदित होता है कि शिक्षा विकास का वर्तमान लक्ष्य, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से काफी बढ़ा चढ़ा कर घोषित किए गए हैं :

विकास का कार्यक्रम	१९५६-६१ की योजना का लक्ष्य	Original Est (वास्तविक अनुमान)	१९५६-५७ की प्रगति	१९५७-५८ की प्रगति	१९५८-६१ का सामयिक लक्ष्य (Provisional targets)
इंजीनियरिंग कॉलेज (संख्या)		१६	८	२	६
अतिरिक्त प्रशिक्षण	१०१०	५४८८	८४०	२६४६	२००२
प्रौद्योगिक बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण संस्थाएँ (Polytechnics) (संख्या)	२३	५५	११	१२	३२
अतिरिक्त प्रशिक्षण	२६००	११७६६	१३२०	१६७०	४८०६

बमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें देहाती क्षेत्र में और अधिक प्राथमिक एवं प्रारम्भिक पाठशालाएँ खोलने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। योजना में २३४,००० प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया था, उसमें से करीब २००,००० अध्यापकों की नियुक्ति योजना के प्रथम तीन वर्षों में हो-की गई। शिक्षा की वर्तमान बढ़ती हुई माँग को देखकर यह कहना कठिन है कि अभी कितनी और पाठशालाएँ खोली जायँ और कितने व्यक्तियों को प्राथमिक पाठशालाओं के लिए अध्यापन कार्य का प्रशिक्षण दिया जाय। फिर भव्य तक की हुई प्रगति को देखकर ऐसी आशा व्यक्त की जाती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में काफी व्यक्तियों को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित कर दिया जावेगा।

स्वास्थ्य (Health) :

द्वितीय योजना में स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए २७४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से १०८ करोड़ रु० योजना के प्रथम तीन वर्षों में खर्च हुआ। इसमें से ६८ करोड़ रु० राज्यों द्वारा तथा ४० करोड़ रुपया केन्द्र द्वारा व्यय किया गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित मदों पर खर्च किया गया,— मलेरिया नियंत्रण, शहरी जल व्यवस्था, आरोग्य-शिक्षा, चिकित्सा प्रशिक्षण एवं परिवार नियोजन। राज्यों द्वारा अस्पताल तथा अफाखाने, शहरी तथा ग्रामीण जल व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों, रोगों की रोकथाम तथा प्रशिक्षण आदि कार्यों पर व्यय किया गया।

दूसरी योजना में करीब ३००० प्राथमिक स्वास्थ्य सत्याएँ खोलने का विचार किया गया, जिनमें से ११२० सत्याएँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा बाकी को राष्ट्रीय प्रसार खंडों के अन्तर्गत स्थापित की जाएँगी। करीब ६०० प्राथमिक सत्याएँ योजना के प्रथम दो वर्षों में स्थापित की गईं। योजना की प्रवधि में ६ नये मेडिकल कॉलिज खोलने तथा १४ पुराने कॉलिजों का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसी कार्यक्रम में २५०० परिवार नियोजन केन्द्र खोलने का विचार था। सन् १९१८-५६ तक करीब ६३५ परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किए गये। स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए सशोधित व्यय की राशि २५५ करोड़ रु० रखी गयी।

११—गृह-निर्माण कार्य

(The Housing Programme)

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गृह-निर्माण कार्य के लिए १२० करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई। योजना में इस कार्यक्रम के लिए कुल प्रस्तावित व्यय एवं मकानों की संख्या का विवरण निम्नप्रकार है—

विवरण	योजना द्वारा प्रस्तावित व्यय (करोड़ रु०)	पंचवर्षीय नियोजन का लक्ष्य (मकानों की संख्या)
१—सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास	४५	१,२८,०००
२—कम आय वालों के लिए आवास	४०	६८,०००
३—बागान मजदूरों के लिए आवास	२	११,०००
४—गन्दी वस्तियों को हटाने और हरिजनों के लिए आवास	२०	१,१०,०००
५—ग्रामीण आवास	१०	१,३३,०००
६—मध्यम आय वाले लोगों के लिए आवास	३	

अनुमान है कि द्वितीय योजना के प्रथम ३ वर्षों में करीब ४० करोड़ रु० खर्च हुआ। सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५६-५९ में ४२,६०० इकाइयों का निर्माण, कम आय वालों के लिए आवास कार्यक्रम में ३२,३०० इकाइयाँ तथा गन्दी बस्तियों को हटाने और हरीजनो के लिए आवास में २२,००० इकाइयों का निर्माण हुआ। ग्रामीण आवास का कार्यक्रम सन् १९५८-५९ से आरम्भ किया गया। गृह-निर्माण के लिए सशोधित व्यय की धन राशि १०० करोड़ रु० रखी गई है अर्थात् निर्धारित व्यय में २० करोड़ रुपए की कटौती की गई। गृह-निर्माण के लिए जो ८४ करोड़ रुपया रखा गया था, उसमें से ६४ करोड़ रुपया राज्य सरकारों द्वारा तथा २० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च किया जायेगा। विभिन्न मदों पर राज्य तथा केन्द्र द्वारा व्यय की जाने वाली धन राशि का विवरण नीचे की तालिका में दिया जाता है।

करोड़ रुपया

गृह निर्माण कार्यक्रम	केन्द्र द्वारा व्यय	राज्यों द्वारा व्यय
सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास	२५	२४'५
ग्रामीण आवास	६०	०२
गन्दी बस्तियों को हटाने का कार्यक्रम	११५	४०
बागान मजदूरी के लिए आवास	...	०'६
कम आय वाले लोगों के लिए आवास	...	३५०

व्यय के उपर्युक्त प्रकरण एवं धन राशि को देमने से पता चलता है कि योजना के अंतिम वर्षों में आवास के विभिन्न कार्यक्रमों की गति काफी धीमी रहेगी जैसा कि सन् १९५८-५९ के लिए निर्धारित व्यय में काफी कटौती की गई। इसी आधार पर अन्य मामलों में भी कटौती करने का अनुमान है।

१२—अन्य सामाजिक सेवाएँ

(Other Social Services)

इस कार्यक्रम में पिछले वर्गों का कल्याण, समाज कल्याण सेवाएँ तथा अमनीति के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। पिछले वर्गों के कल्याण के लिए दूसरी योजना में ६१ करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था की गई, जिसमें से ५९ करोड़ रुपया राज्यों द्वारा तथा ३२ करोड़ रुपया केन्द्र द्वारा व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। सन्

१९५६ से ५९ तक इस कार्य पर करीब ३५ करोड़ रुपया खर्च हुआ । १९५८-५९ में सशोधित व्यय की राशि ८३ करोड़ रुपया रखी गई है जिसमें से ५९ करोड़ रुपया राज्यों द्वारा व्यय किया जावेगा । समाज कल्याण कार्य, श्रमनीति कार्यक्रम तथा शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में १९५६ से ५९ तक करीब १५ करोड़ का रु० खर्च किया गया । इस सम्बन्ध में योजना के अन्तिम वर्षों के कार्यक्रम के लिए सन् १९५९-६० में एक घोषणा की गई, जिसके अनुसार योजना के कार्य-काल में दस्तकारी प्रशिक्षण का लक्ष्य ३०,००० मनुष्यों से बढ़ाकर ५०,००० मनुष्य कर दिया गया ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—आलोचनात्मक अध्ययन

(Second Five Year Plan —A critique)

दूसरी पंचवर्षीय योजना के मसविदे पर विचार करने का कार्य अप्रैल सन् १९५४ में आरम्भ हुआ तथा १९५६ में इस पर कार्य आरम्भ किया गया। उस समय से लेकर अब तक योजना की कटु आलोचना की गई। आलोचना के कुछ भ्रम तो विलकुल निराधार एवं भट्टे हैं लेकिन आलोचना के कुछ भ्रम तो ऐसे हैं जो समय और साधनों की दृष्टि से उपयुक्त एवं सत्य हैं।

सर्वप्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विषय रूप से सहस्राकांक्षी योजना बतलाया गया। इसके बारे में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित व्यय ४८०० करोड़ है जबकि प्रथम योजना में केवल २२४८ करोड़ रुपए की धन राशि ही थी। इस प्रकार द्वितीय योजना का लगत व्यय पहली योजना की तुलना में दुगुना हो गया। लागत व्यय में हुई दुगुनी वृद्धि ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। क्याही अच्छा होता यदि योजना पर अंतिम निर्णय करने से पहले योजना अधिकारी निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते —

१—देश में पूँजी की वर्तमान वृद्धि की दर को देखते हुए क्या यह सम्भव है कि योजना लागत के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे प्राप्त हो जाएंगे ?

२—क्या घाटे की अर्थ व्यवस्था करने से तथा नोटों के अधिक प्रचलन से मुद्रा प्रसार (Inflation) में वृद्धि नहीं होगी ?

३—क्या हम आशा करें कि दूसरी योजना में विदेशी सहायता की जो आवश्यकता अपेक्षित समझी गई है, वह हम पूर्व रूप से मिलती रहगी और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पड़ेगी ?

४—योजना में समाजवादी समाज का जो लक्ष्य रखा गया है उसके अन्तर्गत राष्ट्र के मुख्य मुख्य तथा महत्वपूर्ण उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की नीति से तथा "सभी उद्योगों का १० वर्ष के अन्दर राष्ट्रीयकरण कर दिया जावेगा" की घोषणा से क्या यह आशा की जा सकती है कि निजी क्षेत्र के लिए योजना

मे जो पूँजी के विनियोग की दर निश्चित की गई है, वह निर्धारित दर पर मिलती रहेगी ?

५—वया योजना मे निर्धारित राष्ट्रीय आय की दर को प्राप्त किया जा सकता है ? इस सम्बन्ध मे बी० आर० शिनॉय ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया है
' it is built on the basis of 25 to 27 per cent increase in the National Income in 5 years This would require an increase in net investment from 6.75 per cent of the National Income to 10.95 per cent in 1960-61' ¹

दूसरी योजना के पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत से २७ प्रतिशत तक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सन् १९६०-६१ तक विनियोग की दर में ६.७५ प्रतिशत से लेकर १०.९५ प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी किन्तु अगर हम नीचे की तालिका को देखें तो भालूम होगा है कि हमारे ध्येय बहुत ही ऊँचे तथा अप्राप्य हैं।

विशुद्ध घरेलू पूँजी के उत्पादन की तालिका

करोड़ रुपया

वर्ष	शुद्ध घरेलू पूँजी उत्पादन	राष्ट्रीय आय	दूसरे कालम का तीसरे पर प्रतिशत
१९४८-४९	४४६	८,५८०	५.२
१९४९-५०	५२४	९,०००	५.८
१९५०-५१	५८९	९,५००	६.२
१९५१-५२	६७२	१०,०००	६.७
१९५२-५३	६५९	९,८००	६.७
१९५३-५४	७१९	१०,५००	६.८

(B R Shenoy)

'योजना आयोग इन प्रश्नों का सतोपजनक उत्तर देने में समर्थ नहीं, बल्कि कि वह 'अनाप शनाप' खर्च को सही साबित करने में असमर्थ रहा। दूसरी योजना समाप्त होने को है और अगर कोई देवी घटना घटित न हो तो योजना काल में उसके आदर्श प्राप्त नहीं किए जा सकते, जैसा कि योजना आयोग ने अब आकर स्वयं अनुभव किया है। योजना आयोग की विज्ञप्ति में—जो जून सन् १९६० को प्रकाशित हुई थी—कहा गया था कि "कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों को छोड़कर योजना के शेष उद्देश्य अधूरे रह जायेंगे।"

1 B R Shenoy, in his note of dissent to the Planframe of Second Plan

हमारे देश की जनता के प्रत्यक्ष वक्ता में इस महत्वाकांक्षी अनुमानित योजना की सफलता के बारे में काफी सन्देह व्याप्त है। लागू की यह धारणा है कि अगर ग्रासपीय पद्धति एवं संगठन पर ही अधिष्ठान जोर दिया गया तो योजना को लक्ष्य व भी प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि भारत की ग्रासन पद्धति इतनी अनुशासित एवं माय्य नहीं है कि योजना में निर्धारित सम्पूर्ण अनुमानों (figures) को पूरा कर सके। इनमें सहज कल्पना प्रथम योजना की उन्नति को देखकर की जा सकती है (1) जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निर्धारित करत समय कहा गया था कि वर्तमान शासन पद्धति से, प्रत्येक व्यक्ति को उचित परिष्कृत रूप से अर्द्ध परिणामों की प्राप्ति करना व्यर्थ है।

योजना के उद्देश्य प्राप्त करने के बारे में एक और बड़ी कठिनाई जन सहयोग की है। कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में सरकार ने तरह तरह का प्रचार किया किन्तु फिर भी वह जनता को विश्वास दिलाने में असमर्थ रही कि पंचवर्षीय योजना द्वारा सरकार जो कुछ कर रही है वह जनता की भलाई के लिए ही है। इसका एक कारण सच्चे नेतृत्व (Leadership) का अभाव है। ए० हैरी (Harry A.) ने सच्चे प्रजातन्त्रीय नेताओं को जो गुण बतलाए हैं वे भारत के अधिकांश नेताओं में नहीं मिलते—

नेता वह होना है जो विचारों को कार्यरूप में परिणत करे 1

एक नेता में चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो क्रियात्मक गति होनी चाहिए। उसे केवल विचारशील नहीं होना चाहिए—साथ ही केवल ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए जो शीघ्रतः रूप से वास्तविकता से परे हों—उसके अन्दर उन विचारों को कार्य रूप में परिणत करने एवं व्यावहारिक बनाने की भी क्षमता होनी चाहिए। अर्थात् विचार एवं भावना में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। भारत के अधिकांश नेताओं में ये गुण नहीं पाए जाते यही कारण है कि उनके द्वारा निर्धारित योजनाएँ एवं विचार को अंशतः बन कर रह जाते हैं। इस प्रकार इन योजनाओं की सफलता के लिये जो जनता का समर्थन अपेक्षित है वह नहीं मिल पाता। अपने देश की योजनाओं के लिये प्राप्त इस जन सहयोग की अगर हमें अथवा देशों—जैसे पोलैंड संयुक्त अरब गणराज्य चीन जर्मनी तथा सोवियत रूस में प्राप्त जन सहयोग—में तुलना करें तो हम पाते हैं कि वहाँ की जनता में नियोजन के प्रति विशेष उत्साह एवं लगन है जिसके कारण वहाँ की योजनाएँ सदा सफल रहती हैं और योजना के लक्ष्य समय से पहले ही पूरे हो जाते हैं।

1. The leader is one who must turn ideas into accomplishment
(HARRY A. OVER Street in leadership Democracy)

दूसरी पंचवर्षीय योजना में भ्रष्टाचार, पक्षपात, 'भाई भतीजावाद' (Nepotism) और कुछ अंशों तक जातिवाद एवं प्रान्तीयता को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । परिणामस्वरूप योजनाएँ व्यापक रूप से असफल रही हैं । परम्परानुसार सरकारी उच्च अधिकारी सरकारी धन को शोषण का प्रमुख साधन मान कर खूब दुरुपयोग करते हैं और आम जनता भी उन्हीं का अनुसरण करती है । इस प्रकार वे लोग सरकारी रुपये को निजी खर्च में लाते हैं । इस अन्दरूनी कमजोरी के कारण देश शनैः शनैः अवनत अवस्था को प्राप्त होता जा रहा है । जैसा कि महान् इतिहासकार—टॉयनबी (Toynbee) का कथन है —“सत्तार की महान् सभ्यताओं के नष्ट होने के कारण, बाहरी घाज़मण न हो कर नेत्र के अन्दर व्याप्त आन्तरिक भ्रष्टाचार होने है ।”¹ यद्यपि योजना आयोग ने इस बात का उल्लेख किया है किन्तु उसने यह नहीं बतलाया कि इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने अथवा सरकारी धन व सामग्री का शोषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जायें ?

दूसरी पंचवर्षीय योजना की एक अन्य मुख्य कमजोरी सांख्यिकी पर अधिक बल देने के सम्बन्ध में है । अधिकतर सरकारी प्रॉकडो एवं विभिन्न विकास कार्यों की गणना सांख्यिकी के आधार पर की जाती है । परन्तु हमारे देश में सांख्यिकी के जो प्रॉकडो प्राप्त हैं वे काफी कम, दोषपूर्ण एवं अधूरे हैं, इस प्रकार इन दोषपूर्ण सूचनाओं के आधार पर जो गणना की जाती है उससे विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते ।

‘समाजवादी समाज’ की स्थापना के साथ ही योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) की अपनाने का आश्वासन दिया गया, किन्तु इस आदर्शपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना में जो कदम उठाये गये, वे बड़ी आलोचना के विषय बन गए, जैसा कि योजना में वर्णित शब्दों से विदित होता है

“नवीन उत्पादक वस्तु उद्योगों (New Producers' goods Industries) का विकास मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में होगा निजी क्षेत्र प्राथमिक उद्योग जैसे—सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुओं के उत्पादन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा”²

(Continued from page 326)

a leader in any field must have creative courage. He must not have only ideas that go beyond the average and beyond what is accepted—He must be willing and able to put them to a test.”

1. The great civilization are destroyed not as a result of external aggression but as a consequence of inner corruption.”

—Toynbee

2. ‘The new producers’ goods industries would be developed in the public sector. The private sector would continue to play an important part in the development of basic Industries like cement, chemicals etc.”

सन् १९५८ की औद्योगिक नीति के अनुसार—जिसकी वि दिसम्बर सन् १९५४ में व्याख्या की गई थी—“मूल और सामरिक महत्व के सारे उद्योग और लोकोपयोगी सेवाओं का विकास सार्वजनिक क्षेत्र में होगा। अन्य ऐसे उद्योग भी जो राष्ट्रीय विकास के लिये परमावश्यक हैं और जिनके लिये ज्यादा पूँजी की आवश्यकता होती है, सार्वजनिक क्षेत्र में ही चलाए जायेंगे।”¹

समाजवादी दृष्टि की समाज व्यवस्था के द्रुत विकास के लिए निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक विकास आवश्यक है। सार्वजनिक आय की वृद्धि के लिए सरकार आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उद्योग को अपने हाथ में ले सकती है—इसमें बैंक, बीमा (Insurance), कुछ चुनी हुई वस्तुओं के विदेशी व्यापार तथा आन्तरिक व्यापार सम्बन्धी कार्य हैं। “कर प्रणाली का इस तरह से निर्धारण हो और ऐसे परिवर्तन किये जायें कि समाज के पास उद्यम करके जो वित्तीय फायदे की रकम बचे उसका अधिक से अधिक हिस्सा सार्वजनिक सत्ता के हाथ में आए।” “सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जाय।”²

दूसरी योजना में वर्णित उपर्युक्त कुछ उद्धरणों से सिद्ध होता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र के लिये बिनियोग एवं विकास के लिये जो धन-राशि निर्धारित की गई थी वह काफी कम थी। हमारा मुख्य लक्ष्य पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे समाजवादी अर्थ व्यवस्था की ओर अग्रसर होना है, किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करें। इसके लिए और भी रास्ते हैं।

यह तो सर्वविदित है कि पूँजी निर्माण में अभी कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है और वर्तमान आर्थिक ढाँचे में विकास की दर को देखते हुए भविष्य में भी इससे वृद्धि होने की कोई सम्भावना नहीं है। इसके साथ ही साथ योजना में राष्ट्रीय आय

1 “Key Industries would be established and developed in Public Sector generally in accordance with the Industrial Policy Declaration of 1948 as interpreted on December 1954. Government would also take up the production of certain consumers goods, which are of strategic importance for the growth of National Economy.”

2 The Public Sector must be expanded rapidly and relatively faster than the Private Sector for a steady advance to a Socialistic Pattern of Society to increase income, the government will be prepared to enter into such activities as banking, insurance, foreign trade or internal trade in selected commodities. . . the tax system would be directed towards collection of an increasing part of the growing national income. the Public sector will be extended.”
Second Five Year Plan—Target (aim)

की वृद्धि का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके प्राप्त होने की भी बहुत कम सम्भावनाएँ हैं ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न विकास कार्यों के लिए विदेशों से काफी पूँजी तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायता अपेक्षित समझी गई है किन्तु परिवर्तनशील राजनैतिक वातावरण में, जब कि देश तीव्र गति से समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा हो, विदेशों से किसी प्रकार की पूँजी सम्बन्धी या तकनीकी सहायता प्राप्त करना एक दम असम्भव नहीं तो भ्रामक अवश्य है । यह धात मुख्य रूप से पश्चिमी गुट—जो पूर्ण रूप से पूँजीवादी विचारधारा के अनुयायी तथा समर्थक है सम्बन्ध में कही जा सकती है ।

निजी पूँजी की प्राप्ति भी अनुमानित दर पर प्राप्त नहीं हो सकेगी । क्योंकि पूँजी का विनियोग खास तौर से उन उद्योगों में बहुत कम होगा जो प्राथमिक महत्व के हैं, किन्तु जो निकट भविष्य में सरकार द्वारा चलाये जाने वाले हैं । इसका परिणाम यह होगा कि बहुत सी पूँजी या तो बेकार पड़ी रहेगी अथवा उन उद्योगों की ओर उन्मुख होगी जो महत्वपूर्ण नहीं हैं । यही नहीं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन तथा उपभोग पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए हैं जिनकी दर भी बहुत अधिक है । आज चारों ओर बेरोजगारी फैली हुई है और प्रतिव्यक्ति औसत आय भी बहुत कम है, दूसरे बढ़ती हुई कीमतों की वृद्धि के कारण लोगों के रहन सहन का खर्च बहुत बढ़ गया है, जिसके फलस्वरूप ऐसे लोग बहुत ही कम रह गए हैं जो बचत कर सकते हैं । यह तो सुनिश्चित है कि बिना बचन के पूँजी का निर्माण नहीं हो सकता और बिना पूँजी के निजी क्षेत्र में विनियोग नहीं बढ़ सकता ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वसाधारण की दिन प्रति दिन की समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया—मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है । जीवनोपयोगी वस्तुओं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आदि की पूर्ति के लिए बहुत कम ध्यान दिया गया है, जिससे विदित होता है कि उपभोग स्तर को तो एक दम झुला दिया गया है ।

गृह निर्माण की समस्याएँ¹—आजकल हमारे देश में मकानों की भारी कमी की समस्या उत्पन्न हो गई है । यह समस्या अनाज की कमी की समस्या से कम महत्वपूर्ण नहीं है । इसका प्रमुख कारण तो यह है कि हमारे देश की अधिकांश जनता गरीब तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, जिसके फलस्वरूप उपलब्ध साधनों का वांछित लाभ नहीं उठाया जा सकता । समाज में अच्छे मकान की बड़े पैमाने पर कमी है; किन्तु यह कारण तो उस पेचीदा समस्या का केवल एक पहलू है । जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि ने, दूसरे महायुद्ध तथा योजनावद्ध आर्थिक विकास के कारण औद्योगीकरण के विकास ने, तथा देश के बँटवारे के कारण

पाकिस्तान से आए हुए हजारों शरणार्थियों ने, शहरों तथा देहातों में विद्यमान मकानों की समस्या को, और भी जटिल बना दिया है।

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार हमारे देश में उस समय ६४४ मिलियन मकान थे जिनमें अनुपयुक्त निवास करते थे। उसमें से ५४० मिलियन मकान देहातों में, तथा १०४ मिलियन शहरों तथा बस्तों में थे। इन मकानों द्वारा २६५ मिलियन देशी जनसंख्या को आवास सुविधाएँ प्राप्त थीं। आवास का औसत, ५४ व्यक्ति प्रति मकान देहातों में तथा ६ व्यक्ति प्रति मकानों शहरों में था। प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि पिछले बीस सालों से हमारे देश को आवासीय ३ से ४ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ी है, लेकिन गृहनिर्माण हर वर्ष २ से २५ प्रतिशत तक बढ़ा है।

गृह निर्माण की समस्या, आज जिन रूप में हमारे देहातों तथा शहरों में विद्यमान है, वह स्वभाव, परिणाम तथा महत्व की दृष्टि से भिन्न है। गाँवों में एक ओर तो मकानों की संख्या कम है, दूसरी ओर अत्यधिक कम मकानों की कमी है, जबकि शहरों में मुख्य रूप से मकानों की संख्या कम है। एक मकान प्रति परिवार के अनुसार, सन् १९५१ में २५ मिलियन मकानों की कमी का अनुमान लगाया गया था। सन् १९५१ से १९६१ तक की दशावधि में ८-९ मिलियन मकानों की कमी का अनुमान लगाया गया है, इस कमी का अनुमान सन् १९५१-१९६१ के बीच हुई ३३ प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि के आधार पर किया गया है जिसके अनुसार सन् १९६१ के अन्त तक ४४ मिलियन नये मकानों के निर्माण की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा पुराने मकानों का पुनर्निर्माण करने तथा गंदी बस्तियों को हटाने के लिए २ मिलियन मकानों की अतिरिक्त आवश्यकता महसूस की गई है। किन्तु इतनी अधिक ज़रूरतों के बावजूद भी दूसरी पंचवर्षीय योजना तक शहरी क्षेत्र में केवल ३ मिलियन मकानों का ही निर्माण हुआ। इस प्रकार सन् १९६१ तक ५९ मिलियन मकानों के निर्माण की कमी रहेगी (८९-३०=५९) जिसके लिए अतिरिक्त वित्तीय, प्रशिक्षण तथा समान सम्बन्धी साधनों की आवश्यकता पड़ेगी।

दूसरे महायुद्ध के बाद तथा पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत से देश में व्यापार तथा उद्योग बन्धों का काफी विकास हुआ है। विशेषरूप से सन् १९५१ के बाद से शहरों के विकास के कारण तेजी से मकान निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई है।

तेजी से विकसित होने वाली शहरी आवादी की बढ़ते समय में ही आवास प्रदान करने की समस्या ने शहरों में उपलब्ध स्थानों पर काफी प्रभाव डाला है, जिसके फलस्वरूप शहरों में मकान बनाने के प्लानों की कीमत काफी बढ़ गई है। इसके अलावा मकानों के कारण 'गहन आवास' अस्वास्थ्यकर आवास तथा गंदी बस्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। दूसरे पुराने तथा जीर्णोद्धार मकानों

के उद्धार का कार्य भी बहुत धीमी गति से हुआ है जिसके कारण शहरी आवास की समस्या और भी अधिक जटिल हो गई है।

शहरी आवास व्यवस्था में कमी का मुख्य कारण यह है कि गृह निर्माण के लिये पूँजी विनियोग की दर काफी कम है। किन्तु इस समस्या का पूर्णरूप से जिम्मेदार केवल यही कारण नहीं है। पूँजी विनियोग के कमी के सदर्थ में अनेक कारण हैं, जैसे—जमीन के मूल्य में वृद्धि, गृह निर्माण के लिए ईंटों के मूल्य में वृद्धि, जिसके फलस्वरूप शहरी पूँजी का एक बहुत बड़ा भाग इनमें खप जाता है। इसके अलावा, सम्पत्ति कर उत्तराधिकारी कर तथा आय कर के अन्तर्गत मकानों से होने वाले लाभ पर सरकार ने रोक लगा दी है, जिसके कारण गृह निर्माण सम्बन्धी समस्त सरकारी नियम असफल हो रहे हैं। इस प्रकार इन समस्त तथ्यों के कारण शहरी में गृह-निर्माण तीव्र गति से नहीं हो रहा है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना-काल में, शहरी गृह-निर्माण समस्या को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसके समाधान के लिए तत्काल प्रयत्न किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कम आय वाले तथा मध्यम आय वाले लोगों के लिए और जो पाकिस्तान से भाग कर आने वाले लोगों के लिए आवास व्यवस्था को सम्मिलित किया गया। इन कार्य को इस तरह करने का विचार किया गया जिसमें लोगों की आमदनी के अनुसार उम्मेद कम किराए पर मकान मिल सकें। साथ ही गन्दी बस्तियों को हटाने तथा गन्दगी को रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों को वर्ज तथा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि की गई। मध्यम आय वाले लोगों के लिए आवास कार्यक्रम—जिमके लिए दूसरी योजना में ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई—विशेष प्रगति नहीं हुई। इसके मुख्य कारण थे भूमि की स्थिति के अनुसार उनकी कीमत के निर्धारण की अनुविधा, मकान बनाने योग्य भूमि की कमी, राज्य द्वारा भूमि की उचित दर निर्धारित न करना, कीमतों की वृद्धि के कारण गृह-निर्माण पर बढ़ता हुआ व्यय तथा मजदूरी की वृद्धि आदि। कुछ राज्यों में तो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त गृह-निर्माण कार्य में बिल्कुल लापरवाही बरती गई। इसका मुख्य कारण यह था कि उन राज्यों में गृह निर्माण कार्य पर धन व्यय करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय वित्तीय स्थापनाओं को सौरी गई। इस वर्ग से महकारी समस्याओं के सदस्य भी बहुत कम बने, क्योंकि एक तो बेरोजगारी के कारण इन वर्ग के लोगों पर सामाजिक भार अधिक बढ़ गया था, दूसरे जीवन-निर्वाह सम्बन्धी खर्च में भी काफी वृद्धि हो गई थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत सरकार ने कम आय वाले लोगों के लिए आवास के कार्यक्रम पर २१.५३ करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया था, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा ४०,६४२ मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु योजना की अवधि में केवल ३,६३० मकानों का निर्माण हुआ जिन पर केवल ११.१४ करोड़ रुपये व्यय हुआ। द्वितीय योजना के प्रथम तीन

वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा ३२,३०० इकाइयों के निर्माण के लिए धन-राशि प्रदान की गई, किन्तु इन तीन सालों की प्रगति की देखने से पता चलता है कि योजना की अवधि समाप्त होने तक गृह-निर्माण कार्य के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इस कार्य में सफलता प्राप्ति न होने के कारण हैं—१—कच्चे माल की कमी, २—विकसित भूमि की दुर्लभता, ३—इस वर्ग के लोगों द्वारा सहकारी समितियाँ न बनाना, आदि तथा इन समिति के सदस्यों में पर्याप्त उत्साह की कमी।

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के कार्यक्रम के लिए, जो सन् १९५२-५३ से शुरू किये गये थे, राज्य सरकारों ने ४ $\frac{१}{२}$ प्रतिशत तथा ५ प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने तथा कुल लागत का ५० प्रतिशत व्यय ऋण के रूप में देने का आश्वासन दिया था मालिकों और औद्योगिक कर्मचारियों की सहकारी समितियों को लागत का २५% व्यय सहायता के रूप में तथा २७ $\frac{३}{४}$ % से लेकर ४० प्रतिशत कर्ज के रूप में दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जहाँ इस कार्य के लिए २२.६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से ११.७ करोड़ रु० सहायता के रूप में तथा १०.९ करोड़ रु० कर्ज के रूप में था, वहाँ योजना की समाप्ति तक केवल १३.३६ करोड़ रु० ही खर्च हुआ—अर्थात् ८.७७ करोड़ रु० कर्ज के रूप में तथा ४.५९ करोड़ रु० सहायता के रूप में मिला। प्रथम योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ७६,६७६ इकाइयाँ बनाने का लक्ष्य था, जबकि योजना की समाप्ति तक कुल ४२,८३४ इकाइयों का निर्माण हुआ। कुल इकाइयों के निर्माण में से ३७,२१७ इकाइयाँ राज्यों द्वारा, ७०७६ मालिकों द्वारा, तथा ५३८ सहकारी समितियों द्वारा निमित्त की गई। १९५८-५९ तक, ४२,६०० औद्योगिक कर्मचारी-आवास-इकाइयों को कर्ज तथा सहायता प्रदान की गई।

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास कार्यक्रम के विकास पर तीव्र औद्योगिकरण के संदर्भ में विचार करे तो हम देखते हैं कि द्वितीय योजना में इस कार्यक्रम की प्रगति काफी धीमी रही। औद्योगिक कर्मचारियों को अच्छी आवास सुविधा प्रदान करने में एक कठिनाई यह है कि मजदूरी की दर कम होने के कारण वे मकानों का किराया देने में असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में अधिकतर मजदूर अस्वास्थ्य-कर मकानों और गन्दी बस्तियों में रहना पसन्द करते हैं। उनका कहना है कि वहाँ पर साफ मुथरी मजदूर बस्तियों के मकानों का किराया देना पड़ता है, जो उनकी आमदनी की स्थिति को देखते हुए असुविधाजनक है।

गन्दी बस्तियों को हटाने और हरीजनों के आवास का कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत देर से शुरू किया गया। योजना में इस कार्य के अन्तर्गत ११०,००० इकाइयों के निर्माण के लिए २० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुल लागत का २५ प्रतिशत सहायता के रूप में तथा ५० प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण के रूप में देने का वचन दिया। गन्दी बस्तियों को हटाने का कार्य इसलिये शुरू किया गया जिससे लोगों की अधिक से अधिक कठिनाई

दूर हो जायें और उनके रहने के लिए ऐसे आवास बनाए गए जिनके लिए पैसा खर्च करने में उन्हें अधिक मुर्बावत न उठानी पड़े तथा उनके रोजगार की स्थिति पूर्ववत् चलती रहे। किन्तु इस कार्य की गति भी काफी धीमी रही। इसके मुख्य कारण उपयुक्त भूमि की प्राप्ति में विलम्ब तथा मुआवजे की ऊँची दर, प्राथमिक सामान जैसे इस्फान आदि की कमी, मेहतरो द्वारा गन्दी बस्तियों को छोड़ने में उतनाही प्रकट न करना तथा, आवश्यक सेवा कार्य योग्य मैदानों की कमी आदि थे। गन्दी बस्तियों के पुनरुद्धार के लिए जो उप-समिति नियुक्त की गई, उसका कर्त्तव्य है कि इस कार्य की सफलता में प्रमुख बाधा गृहनिर्माण कार्य को संचालन करने वाले लोगों में आपसी सहयोग की कमी है।

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रथम पंचवर्षीय योजना में पुनर्वास मन्त्रालय ने ३२३,००० इकाइयों के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष अथवा सहायता रूप में अपना योग दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ६५००० इकाइयों का निर्माण हुआ। सन् १९५१ से अब तक, शहरों तथा गाँवों में मकानों की इकाइयों के लिए इस मन्त्रालय ने करीब ६५ करोड़ रुपये खर्च या सहायता के रूप में व्यय किया है। पाकिस्तान में आए हुए विस्थापित व्यक्तियों ने जब से शहरों में रहने की इच्छा प्रकट की है, तब से उनके लिए शहरों में १६ लाख विकसित बस्तियाँ तथा १३६ कालोनियों का निर्माण हुआ है, जिनमें विभिन्न स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विक्रित सम्बन्धी एवं नागरिक सम्बन्धी अन्य अनेक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा करीब १,००,००० मकानों की इकाइयों का निर्माण देहाती क्षेत्र में हुआ है।

देहातों के लिए योजनाएँ—ग्रामीण गृह-निर्माण की समस्या को सुलझाने का कार्य कुछ ही वर्षों में शुरू हुआ है। इस कार्य का मुख्य अंग ग्राम-नियोजन (Village Planning) को है। यह बड़े हर्ष की बात है कि हमारे गाँवों में गृह निर्माण की समस्या घटिक गम्भीर नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि गाँवों की अग्रिकाश जनता शहरों की ओर भागती है, दूसरे गाँवों में जनसंख्या वृद्धि की दर भी काफी कम है। यह बात इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सन् १९४१ और १९५१ के बीच ग्रामीण जनसंख्या में केवल ०.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उनी समय में शहरी जनसंख्या की वृद्धि की दर ४१-२०,० थी। गाँवों में, व्यापक क्षेत्र में, बड़े-बड़े मकान हैं, जो काफी सम्वे चौड़े तथा पुराने जमान के बने हुए हैं, जिनका गली, जिला, धेर या अहाना कहते हैं। इनको सुधारने का कार्य भी आवश्यक है ताकि इनमें निवास करने की अधिक से अधिक स्वाम्यवर्षक और आरोग्यप्रद सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें और इस कार्य को शीघ्र करने की आवश्यकता है।

इस समय ग्रामीण गृह-निर्माण कार्य के अन्तर्गत मुख्य रूप में ३ कार्यक्रम चालू हैं : १—ग्रामीण गृह योजना सम्बन्धी कार्यक्रम (Village Housing Projects Scheme) २—खेतिहर मजदूरों के लिए आवास के कार्यक्रम (Agricultural

Labour Housing Scheme) ३—देहातो में सरकारीयों के लिए पुनर्वासि सम्बन्धी कार्यक्रम (The Rehabilitation of Refugees in Rural Area Scheme) इस कार्य की प्रगति में भी अनेक बाधाएँ हैं, जैसे—ग्रामीण जीवन की विविध समस्याएँ, मरहमों वित्त की कमी, आदि। इसके लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण समुदाय में आय में गिरावट बराबर करने की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न किए जाएँ। साधनों की अतिरिक्त वृद्धि के लिए ग्रामीण श्रम तथा सामान में गतिशीलता उत्पन्न की जाय और सरकार से वित्त सम्बन्धी अधिकार अधिक सुविधाएँ प्राप्त की जाएँ।

प्रायः देखने में यह आया है कि इन विकास कार्यक्रमों का करने में लिए ग्रामीण जनता में उत्साह की कमी है। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण गृह-निर्माण योजना में भाग्य करने वाले अधिकारियों का रवैया दोषपूर्ण तथा सहानुभूति-रहित है। उनमें अच्छी तरह से पथ प्रदर्शन करने तथा उत्साह पैदा करने की कमी है। इस कमी को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि ग्रामीण गृह-निर्माण कार्य पचायतों को सौंप दिया जाय। पचायतों के लिए यह आवश्यक कर दिया जाय, कि वे श्रम को गतिशील बनाने, ग्रामीण जनता को सहकारिता के आधार पर गृह निर्माण करने की शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ और समय-समय पर उनका सर्वेक्षण करती रहें।

निर्माण दर की वर्तमान धीमी गति इस बात की ओर संकेत करती है कि गृह-निर्माण कार्य की नीति का निर्धारण इस तरह में हो, जिससे कि विभिन्न आय-समूहों की आवश्यकता को विभिन्न आवास इकाइयों द्वारा पूरा कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति की सफलता राज्य द्वारा उठाए गए उन विषात्मक कदमों पर निर्भर करती है जिनके द्वारा सरकार निजी साहबियों द्वारा मध्यम आय वाले लोगों के आवास सम्बन्धी कार्यक्रमों की रुढ़िवादी, प्रशासकीय तथा वित्तीय कठिनाइयों को दूर करती है; कम आय वाले लोगों के लिए गाँवों तथा शहरों में गृह-निर्माण की जिम्मेदारी निभाती है तथा शहरी क्षेत्र से गन्दी वस्तुओं को हटाने के कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि तैयार करती है। गृह-निर्माण की नीति इस तरह की होनी चाहिए जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर गृह निर्माण सम्बन्धी मामलों के कारखानों का विकास हो तथा गाँवों में सहकारिता के आधार पर स्थानीय साधनों द्वारा गृह निर्माण सम्बन्धी सामग्री का उत्पादन हो, जिसमें बढती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके।

इसके अलावा गृह-निर्माण सम्बन्धी नीति का औद्योगिक विकास की बिन्दु-... करण की प्रवृत्ति से सामंजस्य स्थापित कर दिया जाय। शहरी क्षेत्र में मकानों की कमी का एक मुख्य कारण यह है कि अधिकांश उद्योग-धन्धे और कारखाने ऐसे अनुचित तथा सकीर्ण स्थानों पर बने हैं जहाँ कि उन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए समुचित तथा आरोग्यवर्धक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं की जा सकती। अतः औद्योगिक विकेन्द्रीकरण का गृह निर्माण के कार्यक्रम से महत्वपूर्ण सम्बन्ध है।

अन्त में गृह-निर्माण की नीति को रोजगार कार्यक्रम से सम्बद्ध कर देना भी

नितात आवश्यक है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी तथा ग्रामीण क्षेत्र की अर्ध-बेरोजगारी की कठिनाइयों को दूर करना है। गृह निर्माण एक ऐसा कार्य है, जो बेरोजगार लोगों को व्यापक रूप से बहुत शीघ्र रोजगार दिला सकता है, और हमारी सामाजिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस कार्य में बड़े पैमाने पर श्रम को गतिशील बनाने में एक अच्छा उचित उपयोग करने की शक्ति सम्मिलित है। एक ऐसे देश में, जहाँ की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती रहती है, गृह-निर्माण का कार्य ही एक ऐसा मन्त्र साधन है, जिसके द्वारा अधिक से अधिक रोजगार की दशाएँ उत्पन्न की जा सकती हैं।

ऊपर कही गई गृह-निर्माण नीति को कार्यरूप में परिणत करने और सफल बनाने के लिए कुछ अनिवार्य साधनों का होना अत्यन्त अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह ऐसा कानून बनाए, जिससे प्रत्येक राज्य में एक गृह निर्माण वित्त-निगम (Housing Finance Corporation) की स्थापना हो और जो केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय (Financial Agency) के रूप में कार्य करे। यह वित्त-निगम अपनी धन सम्बन्धी आवश्यकताओं को जनता द्वारा पूरा करे, तथा गृह-निर्माण करत लोगों को कम ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करे। इसके लिए जीवन बीमा निगम तथा छोटी वृत्त योजनाओं वाले सघ अधिक मात्रा में धन प्रदान करे जिससे कि गृह-निर्माण करने वाली कम्पनियों की विनियोग दर बड़े, जैसा कि संयुक्त प्रारंभ गण राज्य में होता है। वहाँ पर मध्यम आय वाले लोगों के लिए आवास-अवस्था सम्बन्धी खर्च जीवन बीमा निगम द्वारा दिया जाता है।

गृह-निर्माण कार्य में नवीन विनियोग की हतात्म्यता करन वाला प्रमुख कारण, स्थानीय मन्त्रालयों (Local authorities) द्वारा लगाए गए करों का भार है। खास तौर से बड़े-बड़े नगरों, जैसे—बम्बई और कलकत्ता, में तो इन करों का भार बहुत अधिक है, जबकि जायदाद कर (Property Tax) में कर की वृद्धि प्रगामी (Progression) को लागू करने का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। गृह-निर्माण के कार्य में विनियोग की दर को बढ़ाने तथा विनियोग करने वालों को उत्साहित करने के लिए सरकार को चाहिए कि कम किराया मिलने वाले मकानों पर सम्पत्ति कर की दर में थोड़ी सी कटौती कर दे।

गृह निर्माण कार्य को तीव्र करने के लिए स्थानीय सरकारें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करें। इसके लिए वे भूमि के विकसित खण्डों (Plots) को घटी हुई कीमत पर महकारी आवास मन्त्रालयों, निजी मन्त्रालयों (Private Companies) या व्यक्तियों (Individuals) को बेचे अथवा किराये पर दे। इस छूट के फलस्वरूप मध्यम तथा कम आय वाले लोगों को गृह निर्माण में काफी सहायता मिलेगी।

अन्य मुभावों के अनुसार मकान के किराये में नियमितता हो अथवा हर एक तरह के मकान की किराए की दर निश्चित करदी जाय तथा मकान सम्बन्धी कार्यों में वर्तमान तरीकों को अपनाया जाय।

गृह-निर्माण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए धन तथा धन-सम्बन्धी प्रयत्न अनिवार्य हैं। देश की जनता को गृह-निर्माण कार्य का प्रशिक्षण दिया जाना तथा इस कार्य को मिल जुल कर करने का प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। यह सुभाव मुख्य रूप से देहाती क्षेत्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है, जहाँ पर आपसी सहयोग से बड़े-बड़े कार्यक्रम पूरे किए जा सकते हैं। आपसी सहयोग की इस प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए सामाजिक शिक्षा का सहारा लिया जाय और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की कार्य क्षमता की वृद्धि के लिए उन्हें आत्मविश्वास तथा सहकारिता की शिक्षा दी जाय।

शिक्षा—शिक्षा के महत्व को देखते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना में उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया। योजना में साधारण तथा टेक्नीकल दोनों ही तरह की शिक्षा को देश में विकसित करने के लिए यद्यपि एक लम्बी रकम निर्धारित की गई, किन्तु वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए यह बहुत कम रही। मोटे तौर पर एकदम अपूर्ण रही। देखने में यह आता है कि जब कभी कोई योजना अधिकारी योजना के लक्ष्य में कटौती करने को सोचते हैं तो वे सबसे पहले शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के व्यय के बजट में भारी कटौती करते हैं—मानो राष्ट्रीय विकास में यह कोई कम महत्वपूर्ण अंग हो लेकिन सच तो यह है कि शिक्षा का महत्व ठीक इसके विपरीत है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के बारे में भी यही बात चरितार्थ होती है। संसार का कोई भी राष्ट्र तब तक सामाजिक, आर्थिक अथवा नैतिक दृष्टि से उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि शिक्षा और शिक्षा-प्रणाली पर उचित बल न दिया जाय।

दूसरी योजना में मिशनर इस मामूली सी घोषणा, कि “बाढ़ों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण उपायों को प्रयोग में लाने से सम्बन्धित कार्यों की ओर प्रमुख ध्यान दिया जाएगा” के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे—फसलों को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़ों और रोगों की रोकथाम तथा किसानों की दशा को सुधारने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया। कृषि कार्यक्रम के सम्बन्ध में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, जैसे—फसलों में कीड़े-मकोड़ों का लगना, टिड्डियों का आक्रमण, बाढ़, सूखा, भूमि-क्षरण तथा सिंचाई की कमी आदि। किन्तु योजना में इन कठिनाइयों का वही रूप से निरूपण नहीं किया गया और उनके लिए समुचित धन व्यय नहीं हुआ। जैसा कि बी० आर० सैनीय ने कहा है कि “दूसरी योजना में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि बाढ़ों की रोकथाम किस तरह हो तथा इस सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यों पर कितनी धन राशि व्यय की जाय।” देखने में यह आया है कि सरकार ने बाढ़-निवन्त्रण के लिए अब तक जो कार्य किये हैं वे सब अपूर्ण रहे हैं और अब तो हमारा योजना आयोग यह सोचने लगा है कि “बाढ़ों की कभी रोक थाम नहीं हो सकती, यह तो दैवी प्रकोप है, केवल इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है।” किन्तु योजना आयोग का इस तरह सोचना एक भारी भूल है क्योंकि अगर कठिन

मेहनत और पूरी लगन के साथ कार्य किया जाय तो दुनिया की हर बुराई तथा कम-जोरी को दूर किया जा सकता है ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programmes)—सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारम्भ किए २ वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ रहा है । कार्यक्रम की रूपरेखा देहाती क्षेत्रों के लिये विकास एवं कल्याण कार्यों के हेतु बनायी गई थी—ग्रामीण लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखा गया था । इस बात की आशा की गई थी कि यह ग्रामों में आर्थिक क्रान्ति लाने में सफल होगा और हम प्रकार सारा देश लाभान्वित होगा । इस कार्य को निर्धारित किए जाने के पूर्व देश के लब्ध-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इन कारणों का अनुसन्धान किया, कि युद्ध काल में और युद्धोपरान्त जो 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन छेड़ा गया था, वह आखिर सफल क्यों नहीं हुआ ? इस सम्बन्ध में अनेक विकास क्षेत्रों में—विशेष रूप से इटावा में—अध्ययन किये गए ।

इस बात की आशा की गई थी कि एक विशद कार्यक्रम तैयार करने से ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बेरोजगारी तथा अर्ध-बेरोजगारी के कारण जो अपार मानव शक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है उसका उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकेगा । इससे आर्थिक क्रान्ति का सूत्रपात होगा । कृषि उत्पादन में वृद्धि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा ।

इसमें सन्देह नहीं कि इस कार्यक्रम में कुछ सफलताएँ मिली हैं, लेकिन सफलता का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह अपूर्ण रहा । २ अक्तूबर, सन् १९६० तक की २ वर्षों की अवधि में १६२ करोड़ की आबादी वाले ३,८०,००० गाँवों में सामुदायिक विकास कार्य किया गया । १ अप्रैल सन् १९६० तक १७३२५ करोड़ रुपए का सरकारी व्यय हुआ । ८७ करोड़ रुपया सर्व साधारण के योग से प्राप्त हुआ । सहकारिता आन्दोलन की प्रगति इस प्रकार हुई—सन् १९५८-५९ तक प्राथमिक सहकारी समितियाँ, १०५००० थीं । १९५०-५१ में यह संख्या बढ़ कर १८३००० हो गई । समितियों की सदस्य संख्या ४४ लाख से बढ़ कर १०२ करोड़ हो गई । सिचाई का क्षेत्र १९५०-५१ में ५७५ लाख एकड़ था, वह सन् १९६०-६१ तक ७०० लाख एकड़ हो गया । ३९ लाख एकड़ अनुत्पादक भूमि में खेती बढ़ाई गई जब कि दूसरी योजना का लक्ष्य ६० लाख एकड़ का था । इसी प्रकार अन्य विकास कार्यों के लक्ष्य भी अधूरे ही रहे ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यद्यपि कृषि-उत्पादन में कुछ सुधार हुआ फिर भी कृषि का उत्पादन अब भी मौसम पर ही निर्भर करता है । आबादी की तीव्र वृद्धि को ध्यान में रख कर, योजना में अन्न उत्पादन का लक्ष्य नहीं रखा गया । जो भी हो, जितनी यह बात १० वर्ष पूर्व सच थी उतनी ही आज भी सच है कि कृषि-

प्रधान देता होते हुए भी भारत अपनी खाद्य सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है ।

देशी तथा विदेशी प्रेक्षकों ने यह सही ही कहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना में जो विकास कार्यक्रम तैयार किए गए, वे लोगों के मन में योजनाओं के प्रति श्रद्धा और उत्साह उत्पन्न करने में असमर्थ रहे हैं । योजना आयोग के 'मूल्यांकन कार्यक्रम समूह' ने अप्रैल सन् १९६० में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि लोग हर एक विकास कार्यक्रम को 'सरकारी फायदे की स्कीम' समझते हैं । यही कारण है कि अधिकांश ब्लॉकों में सर्वसाधारण वा रबीया विकास कार्यक्रम की सफलता के पक्ष में नहीं है ।

इसमें अधिकांश दोष अधिकारियों का है साथ ही राज्य विधानसभाओं और ससद में जनता के प्रतिनिधियों का भी दोष है । उन्हें विकास के कार्यों में जनता का नेतृत्व करना चाहिए । इनके साथ ही बहुत कुछ दोष उन राज्य सरकारों का है, जो शासन के विकेंद्रीकरण के लिए तत्पर नहीं । प्रजातन्त्र में विकास योजनाओं के प्रति जनता में विश्वास पैदा करने के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक है । केवल माध्य और राजस्थान में ही इस दिशा में कदम उठाए गए हैं । यद्यपि वहाँ पर कुछ दिक्कतें आई हैं । किन्तु इस घात के बिना दृष्टिगोचर हुए हैं कि लोगों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ रही है । उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने जिला परिषद् और क्षेत्र समिति बिल के द्वारा जिला परिषदों और क्षेत्रीय समितियों को कुछ अधिकार देने जा रही है, पर शासन का तत्त्व अपने पास ही रखेगी—इसका नाम जनतन्त्रीय विकेंद्रीकरण होगा ।

औद्योगिक प्रगति (Tight money checks Industrial expansion)—२६ मार्च १९५७ को हुई इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की सालाना बैठक में औद्योगिक प्रगति के बारे में बोलते हुये श्री एल० एन० बिट्टला ने कहा था कि हम द्वितीय योजना के वर्ष को पूरा कर रहे हैं, किन्तु योजना के प्रथम वर्ष में पहले ही 'द्रव्य बाजार' में जो संचित धन (funds) की कमी शुरू हो गई थी, वह अब इतनी अधिक बढ़ गई है जितनी पहले कभी नहीं थी । यहाँ तक कि मन्दी काल (off seasons) में भी बाजार में द्रव्य की कमी रहती है । रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में द्रव्य के लेन देन की अनिश्चितता के कारण 'बाजार की सुरक्षा' (Security market) तो बिल्कुल सुप्त सी हो गई है । शेयरों और सिक्क्योरिटियों के भावों (मूल्यों) में भारी गिरावट हुई है । देश की वित्तीय प्रवृत्ति को मापने का सारा कार्य stock exchange करता है । उद्योगों की वित्त सम्बन्धी कठिनाइयाँ इनकी अधिक हैं कि अच्छे अच्छे कारखानों तक में उधार का आधार १०-१२ प्रतिशत व्याज पर रह गया है । उधार की इस दर को देखते हुए भावी औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है ।

विदेशी विनिमय की कठिनाई भी एक बड़ी समस्या है... .. किन्तु इससे भी अधिक विकट समस्या आंतरिक वित्त (internal finance) की है। जब तक देश में द्रव्य के आन्तरिक साधनों की उपलब्धि न होगी तब तक बड़ी मात्रा में मिलने वाली विदेशी विनिमय की घनराशि किसी काम की नहीं होगी। जब हम किसी कारखाने में १ करोड़ रुपये का विनियोग करते हैं, तो उसका ५० प्रतिशत देश के आन्तरिक साधनों पर व्यय करना पड़ना है और बाकी का ५० प्रतिशत बाहर मशीनरी तथा अन्य कल पुर्जों में व्यय करते हैं जिसके लिए हमें पूर्ण रूप से देश के बैंक द्रव्य की सहायता नहीं मिलती, जब कि किसी भी नये उत्पादन कार्य को शुरू करने के लिये हमें ६० प्रतिशत से लेकर ६५ प्रतिशत तक आन्तरिक पूँजी व द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब तक देश के आन्तरिक साधनों का विकास नहीं किया जायेगा, तब तक हमारे लिये योजना में निर्धारित, निजी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लक्ष्यों को, पूरा करना कठिन होगा और जब निजी क्षेत्र योजना के लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो सार्वजनिक क्षेत्र के लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की आय का मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र ही है।

बचत कार्य में कमी

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्य करती है, लेकिन धन सम्बन्धी जरूरतों की अन्तिम पूर्ति बचत द्वारा होती है। कर की वृद्धि के कारण निजी बचत का क्षेत्र एकदम संकुचित हो गया है। द्रव्यपूर्ति का दूसरा साधन सामूहिक बचत (Corporate Saving) है, किन्तु तत्कालीन सरकारी बंदमो के फलस्वरूप यह स्रोत समाप्त हो रहा है। सन १९६० के बजट पर बोलते हुए वित्तमन्त्री ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया था।

विदेशी विनियोग के द्वारा भी द्रव्य की पूर्ति में सहायता मिलती है, लेकिन विदेशी पूँजी तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कि देश के अन्दर उसके लिए उपयुक्त वातावरण न बनाया जाय। जिन लोगों ने चीन का भ्रमण किया है वे जानते हैं कि योजनाओं की सफलता के लिए चीन में विदेशी पूँजी किस तरह प्राप्त करते हैं। वहाँ पर ७०% पूँजी की आवश्यकता को दीर्घकालीन आधार पर पूँजी गत वस्तुओं के रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों से हम इस तरह पूँजी सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते। जब तक हमारे देश में विदेशी पूँजी को आकर्षित तथा प्रोत्साहित करने के लिए उचित वातावरण पैदा नहीं किया जाएगा तब तक विदेशी पूँजी से प्राप्त सहायता की घन राशि में कमी होती जायगी।

ऐसा सुझाव दिया गया है कि द्रव्य बाजार को सरल बनाने के लिए मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाय। कभी कभी लोगों की क्रयशक्ति पर रोक लगाकर और द्रव्य पर आवश्यक नियन्त्रण करने का भी सुझाव दिया गया है, जिसके फलस्वरूप उपभोग में कमी हो और कुनिम रूप से वस्तुओं की पूर्ति बढ़

जाय। किन्तु ये कार्य योजना के उद्देश्य के विपरीत है। सब कुछ होते हुए हमारे रोजगार की अधिक से अधिक सुविधाएँ उत्पन्न करना तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। हम कीमतों को कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे बेरोजगारी फैलती है और लोगों का जीवन स्तर गिरता है। इतने सब कार्यों के होते हुए भी, हम देखते हैं कि कृषि पदार्थों की कीमतें बढ़ती है। इस प्रकार एक ओर तो औद्योगिक उत्पादन की वस्तुओं जैसे, कपड़े की कीमतें गिरती हैं, मिलों के पास स्टॉक समाप्त हो जाता है, उपभोग कम होता जाता है और दूसरी ओर कृषि उत्पादन की वस्तुओं की कीमतें ऊँची दर पर स्थिर हो जाती हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि मुद्रा संकुचन अथवा साख नियन्त्रण का कृषि वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि को रोकने के लिए सर्वोत्तम ढंग यह है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाय।

एक विकसित अर्थव्यवस्था में अगर थोड़ा सा मुद्रा स्फीति कर भी दिया जाय तो कोई अनुचित बात नहीं है। औद्योगीकरण से तीव्र मुद्रा स्फीति होता है। यह बात सर्वविदित है कि जहाँ पर किसी आदमी के लिए प्राकर्षण होता है वह उसी तरफ उन्मुख हो जाता है, इसी तरह थोड़ी सी मुद्रा स्फीति से अधिक औद्योगीकरण को प्राकर्षण मिलता है, जबकि लोगों की श्रमशक्ति को नियन्त्रित करने अथवा साख पर नियन्त्रण करने से औद्योगीकरण की वृद्धि मारी जाती है।

बैंकिंग सम्बन्धी पड़चनें (Banking Bottleneck)

सरकार विभिन्न स्थानों द्वारा 'द्रव्य-वाजार' से द्रव्य को वापस ले लेती है—उत्पादन कर के रूप में, कर्ज के द्वारा तथा 'अतिरिक्त बजट' (Surplus budgets) के द्वारा। इस तरह से इकट्ठा किया हुआ धन बैंकों के पास शोध नहीं लौटता। अन्य देशों में एक रुपये के नोट ६ बार बाजार में चलने को पाते हैं जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अधिकतर सरकारी व्यय या तो विदेशों से माल खरीदने में व्यय किया जाता है या देहाती क्षेत्र के उन लोगों पर व्यय किया जाता है जो बैंकों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते अथवा जिनमें विनियोग करने की प्रवृत्ति नहीं होती।

हमारी बैंकिंग व्यवस्था भी इतनी सगठित नहीं है कि वह देहाती क्षेत्र से धन आकर्षित कर सके। नतीजा यह होता है कि बैंकिंग तथा विनियोग करने वाला वर्ग, जो देश के औद्योगीकरण में तथा धन में वृद्धि करता है, भूलो मरता है, जबकि देहाती क्षेत्र की जनता के पास धन की इतनी अधिक मात्रा हो जाती है जिससे मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को आमानों से रोका जा सकता है। मुद्रा स्फीति का यह चक्र औद्योगीकरण में काफी वृद्धि कर सकता है अगर अतिरिक्त धन रखने वाली ग्रामीण जनता भी विनियोग करने वालों की मदद करे। उपर्युक्त मुद्दा ही केवल

मुद्रा सकट को दूर करने के लिए काफी नहीं है किन्तु अगर उपर्युक्त साधनों को सरकारी अफसरों द्वारा सतकता से अपनाया जाय तो वे 'द्रव्य बाजार' में विद्यमान समस्त कमियों को दूर कर सकने हैं और इस तरह मुद्रा स्फीति में सहायक हो सकते हैं ।

औद्योगिक उत्पादन के निर्यात में वृद्धि (Developing export of Industrial Product)

फंडेशन ऑफ इंडियन चैम्बरस ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री के अध्यक्ष लक्ष्मीपत सिंघानिया का कहना है कि भारतीय इतिहास के इस कठिन युग में हमारे राष्ट्र का सम्पूर्ण ध्यान अर्थव्यवस्था के निर्माण सम्बन्धी महान् कार्य पर केन्द्रित होना चाहिए, हमको सावजनिक तथा निजी क्षेत्र के निर्धारण के लिए बहस अथवा कटुता की ओर अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए ।

फंडेशन के ३० वें मालाना अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए श्री सिंघानिया ने कहा था—'आर्थिक प्रगति नियन्त्रित तथा सकुचित क्षेत्र द्वारा न तो कभी हुई और न आगे ही हो सकती है तथा क्षेत्र निर्धारण के लिये व्यर्थ का विवाद करने से तो यह प्रगति कदापि नहीं हो सकती । यह एक ऐसा कार्य है, जिसमें विकास के प्रत्येक स्तर के लिए सभी क्षेत्रों के आन्तरिक सम्बन्ध की आवश्यकता निहित है ।'¹

उन्होंने नवीन निर्यात उद्योगों की स्थापना तथा वर्तमान उद्योगों के विकास पर भी जोर दिया । उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे स्तर पर पहुँच गये हैं जबकि औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात स्तर के विकास पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है ।² यह अनिवाय ही है कि निर्यात के विकास का सम्मिलित राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में निभाया जाय । प्रतियोगिता पूरे विश्वबाजार में, वस्तु की किस्म, कीमत और विक्री के ढंग की गणना सर्वप्रथम की जाती है । इसलिए हमारे उत्पादन के तरीके एकदम नवीन और आधुनिक होने चाहिए । इसलिए सरकार तथा थर्मिक दोनों ही से यह अपील करता हूँ कि वे कम लागत पर अच्छे किस्म का उत्पादन करने में उद्योगों की मदद

1 'Economic advancement does not and cannot proceed through rigid and water tight sectors, much less through—acrimonious discussion It is a process which involves—interpretation of sectors at each state of development'

Speech of L. Sighania (Hindustan Times 24 3 57)

2 "We have reached a stage when more attention must be given to developing the export of Industrial product"

करे। उद्योग और व्यापार की भी अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। केवल मशीनें ही उत्पादन की क्रियाशील पूँजी नहीं है। दिमागी सुझाव इस कार्य में बड़े पैमाने पर सहायक है। अगर उद्योगों का प्रबन्ध सुचारु रूप से किया जाय और खूब सोच विचार कर काम किया जाय तो बिना किसी सन्देह के हम अपने प्रयास में सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं।

प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारतीयों की अज्ञानता के बारे में विचार व्यक्त करते हुए श्री सिद्धानिया ने कहा था कि यद्यपि हमारे देश में चतुर कारीगरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं, फिर भी इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कारीगरों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में सतर्कता पूर्ण विस्तृत कार्यक्रम की आवश्यकता है। उनका कहना था कि माँग और पूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की क्षमता वाले वर्गों के विकास पर अत्यधिक ध्यान देना आवश्यक है।

विदेशी विनिमय

देश के लिए विदेशी विनिमय (मुद्रा) सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री सिद्धानिया ने कहा था कि सन् १९५६-५७ में चाय और मूँगफली को छोड़ अन्य वस्तुओं के निर्यात में काफी कमी हुई। इसके प्रतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग की वस्तुओं, मैंगनीज और कपास तथा तेल के निर्यात व्यापार में भी काफी कमी हुई।

श्री सिद्धानिया ने कहा, "यह स्पष्ट है कि अगर द्वितीय पंच वर्षीय योजना की वृद्धि दर में कोई कटौती न की गई तो देश के अन्दर विद्यमान मुख्य-मुख्य उद्योगों के वच्चे माल में निरन्तर वृद्धि होगी और पूँजीगत वस्तुओं का आयात भी प्रतिवर्ष बढ़ता रहेगा, जिससे विदेशी मुद्रा विनिमय की कठिनाई बढ़ेगी। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार पूँजीगत वस्तुओं तथा अन्य मशीन सम्बन्धी कल-पुर्जों के आयात पर रोक लगाये। इसके लिए मैं यह समझता हूँ कि सरकार पदाधिकारियों और उद्योगपतियों की एक छोटी सी समिति नियुक्त करे जो सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों की आयात सम्बन्धी ज़रूरतों के बारे में विचार करे; और इस बात की निगरानी करे कि अनधिकृत वस्तुओं की पूर्ति में किस तरह वृद्धि हो; साथ ही यह कमेटी प्राथमिक वस्तुओं के क्रम को पूर्ववत् रखने के सम्बन्ध में कुछ खाम-खास वस्तुओं के आयात में कटौती के बारे में भी विचार विमर्श करे।"

आगे श्री सिद्धानिया ने कहा कि सरकारी नीतियों का निर्धारण इस तरह हो, जिससे निजी साहसियों को प्रोत्साहन मिले और उनके विस्तृत औद्योगिक कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा न हो। हम देखते हैं कि आज हमारे देश में औद्योगिक विकास की ओर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और समाज का एक ही वर्ग इस दिशा में जोशिम उठाने के लिए कार्य करता है। आर्थिक कार्यों के विकास से

पता चलता है कि औद्योगिक विकास की ओर से बहुत से लोगो की रुचि अनावश्यक रूप से घटती जा रही है । इसका मुख्य कारण हमारा आर्थिक रूप से पिछड़ापन न होकर आर्थिक स्रोतों का एक ही शक्ति के हाथों केन्द्रित हो जाना है । आज सरकारी नीतियों के कारण लोगो में उद्योगो की स्थापना के लिए जोखिम उठाने में बहुत सी आशंकाएँ व्याप्त हैं । परिणामस्वरूप, आज अगर कोई व्यक्ति नवीन उद्योग की स्थापना करना चाहे तो, विभिन्न कम्पनी एक्ट तथा विभिन्न भ्रम कानूनों को समझाने वाले सलाहकारों को रखे बिना, इस कार्य में वह कभी सफल नहीं हो सकता ।

पूँजी निर्माण (Capital formation) :

पूँजी का निर्माण बचत पर निर्भर करता है और बचत का विकास सरकार की वित्त सम्बन्धी नीति के उचित निर्धारण पर निर्भर करता है । इस सम्बन्ध में उद्योग और व्यापार से बहुत कुछ योगदान की आशा की जा सकती है, जिसके लिए अनावश्यक रूप से उच्च कर की दर तथा साख्त नियन्त्रण सम्बन्धी कदमों को एक दम समाप्त कर दिया जाय ।

“यह सत्य है कि जब कभी देश में मुद्रास्फोटिता का दबाव बड़े तो उसे शीघ्र कम कर देना चाहिए । किन्तु मूल्य वृद्धि एक बरदान के समान है इससे उत्पादन में वृद्धि होती है । इसके साथ ही ध्यान रखने योग्य दूसरी बात यह है कि मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय व्यय में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे देश के अन्दर निर्माण कार्य द्रुतगति से होने लगता है । द्वितीय योजना के पूर्वार्द्ध का अनुभव बतलाता है कि सन् १९५६-५७ तथा १९५८-५९ के बीच में सरकारी नीति और साख्त नियन्त्रण कार्यों का उद्देश्य कीमतों की वृद्धि रोकना था जबकि औद्योगिक विस्तार द्वारा उत्पादन वृद्धि पर बहुत कम ध्यान दिया गया ।”

आज कल विनियोग की दर में सबसे बड़ी बाधा कर की ऊँची दर है । निम्नलिखित वित्त नीति के अपनाने का मुख्य कारण यही है । जैसा कि श्री सिंघानिया ने कहा है कि “कर की ऊँची दर पूँजी बाजार की स्वस्थ प्रगति को रोकती है । अगर कर की दर पूर्व अवस्था में ही रहे, तब भी पूर्ण विकसित पूँजी के बाजार की क्रियाशीलता में बाधा पड़ती है ।”¹

श्री सिंघानिया के अनुसार भारत जैसे एक अर्द्ध-विकसित देश में, उपभोग को बढ़ाने के साथ साथ बचत बढ़ाने की भी एक विपत्ति समस्या है । उद्योग और व्यापार का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जबकि औद्योगिक उत्पादन की खपत के लिए विस्तृत बाजार हो, और उत्पादन की यह खपत मुख्य रूप से लोगो की आय-बचत और उपभोग पर निर्भर है ।

1 “ The higher rate of taxation check the healthy growth of capital market even as it is, we do not have a well developed capital market ”— Mr Singhania

स्टेट बैंक के कार्यों का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार किया जाय । श्री सिंहानिया के अनुसार “यह एक बहुत लाभदायक बात होगी, क्योंकि इससे शहरी क्षेत्र के व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।” इस सन्दर्भ में उनका कहना है कि “ग्रामीण क्षेत्रों पर स्टेट बैंक द्वारा जो व्यय किया जाय वह शहरी क्षेत्रों पर न किना जाय क्योंकि औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में धन की अब भी बहुत कमी है ।”

सिंहानिया के कथनानुसार “हमारा ध्येय बचत को इस तरह से संगठित करने का होना चाहिए, जिससे पूँजी की मात्रा में वृद्धि हो तथा यह बचत अधिक साधनों का उपभोग करने में समर्थ हो । साथ ही साथ जनता के लिए अधिक से अधिक उपभोग की वस्तुएँ उपलब्ध हों ।”

योजना के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता।

(Need to Reshape the Plan)

सन् १९५९ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसविदे पर विचार करने के लिए लोकसभा में विचार विमर्श हुआ । प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री अशोक मेहता ने योजना के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा था कि जब हम यहाँ पर भारतीय जनता के नये भाग्य के निर्धारण पर विचार करने बैठे हैं, तो हमें योजना के तथ्यों की स्पष्ट जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है । द्वितीय योजना के प्रथम चार अध्यायों में नियोजन के तथ्यों का बड़े ही सुन्दर तथा सामंजस्यपूर्ण ढंग से विवेचन किया गया है, इसके साथ ही उनमें जनतन्त्र के ढाँचे के विकास सम्बन्धी समस्याओं तथा सीमाओं का भी विवरण है । “मुझे यह देख कर बहुत ही आश्चर्य हुआ, कि योजना के २६ अध्याय प्रथम चार अध्यायों के आधार पर ही तैयार किए गए हैं । २६ अध्यायों में क्रमिक विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वे किसी न किसी रूप में प्रथम चार अध्यायों द्वारा प्रभावित हैं तथा उन्मीलित हैं । मैं नहीं समझता कि योजना आयोग ने जो समस्याओं और उसके स्वरूप की धूरी तथा स्पष्ट जानकारी रखता है, ऐसी भूल क्यों की, जबकि योजना का प्रत्येक अध्याय विकास सम्बन्धी सुदृढ कार्यक्रमों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित है ।”

“प्रधान मन्त्री ने हमको अपना दृष्टिकोण विकसित करने को कहा है । उन्होंने हमको कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए आमन्त्रित किया है । हम उनके इस विचार से पूर्ण सहमत हैं कि उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने के पश्चात् आने वाली मुसीबतों को सहन करने योग्य बनाने के लिए तथा उसके अन्त के बारे में सोच लेना अत्यन्त आवश्यक है । किन्तु हमारे प्रधान मन्त्री आगे बढ़ने की जल्दबाजी में, यह अनुभव करना भूल जाते हैं कि आगे आने वाली दो योजनाएँ भी हमारे लिए विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । स्वयं दूसरी योजना में यह कहा गया

है कि उन्नति करने में अभी दस वर्ष लगेंगे । उन्नति के प्रवेश मार्ग को पार करना बहुत जरूरी है । विकास की वास्तविकता आर्थिक कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के सही संचालन में निहित है । अपने-अपने समय और स्थान पर सभी योजनाएँ महत्वपूर्ण हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि एक विशाल दृष्टिकोण को अपनाकर ही हम दरिद्रतारूपी ढलदल से निकल कर सम्पन्नता की चमकीली चट्टान पर पहुँच सकते हैं । किन्तु पूर्ण विकास के कार्य में एक समय लगता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही वह महत्वपूर्ण समय है जबकि हम उन्नति के द्वार (Threshold) को पार करते हैं ।

इस प्रवेश मार्ग को पार करने की कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं । मैं देखता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस प्रवेश मार्ग को पार करने के महत्व पर उचित ध्यान नहीं दिया है । इसका महत्व द्वितीय योजना के प्रस्ताव में पृष्ठ २१ पर दिया गया है, जिसमें योजना आयोग ने कहा है

१. "हमारा ध्यान मुख्य रूप से साधनों की गतिशीलता पर केन्द्रित होना चाहिए, न कि योजना में निर्धारित लक्ष्यों से प्राप्त उपलब्धियों पर ।

२. 'अगर हम इस प्रवेश मार्ग को पार करना चाहते हैं तो हम अपने जीवन स्तर में वृद्धि नहीं कर सकते । यह विकास का एक प्रमुख (Imperative) नियोजन है । हम विकास के तर्क से भी अपना ध्यान नहीं हटा सकते । अगर साधारण जनता की औसत आय में वृद्धि होती है तो विकास के लक्ष्य और गतिशीलता में एक-दम कमी हो जायगी जिसका परिणाम यह होगा कि प्रवेश मार्ग एक दम विस्तृत तथा बड़ा हो जाएगा और तब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने में असमर्थ हो जाएँगे । इसी कारण से यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हम अपनी अन्ध विश्वास तथा भोली-भाली जनता के बारे में इस बात का पता लगायें कि वह किस तरह से इस तथ्य को हृदयगम्य करके, अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रख कर, योजना के लक्ष्यों को पूर्ण करने में योगदान देती है । प्रथम पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में जनता ने काफी सहयोग दिया । प्रथम योजना काल में प्रतिव्यक्ति औसत उपभोग का व्यय ६ प्रतिशत हुआ, जिसकी वृद्धि दर ३-४ आना सालाना प्रति व्यक्ति रही । जनता की जरूरतों की देखते हुए यह वृद्धि बहुत कम रही । अतः स्वभावतः यह प्रश्न उठा कि दूसरी योजना में वृद्धि की दर क्या हो ? इसी तथ्य को ध्यान में रख कर, हमने एक बड़ी और शक्ति-शाली योजना बनाई है । देखें इसके परिणाम क्या होंगे ?"

योजना के परिणाम निम्न प्रकार होंगे - अनाज के उपभोग में एक औसत प्रति व्यक्ति की वृद्धि होगी, कपड़े के उपभोग में १ या २ गज की वृद्धि होगी । इस बारे में अपनी जनता को अधिक कुछ नहीं कर सकते । सामाजिक उत्थान की प्राप्ति में निस्सन्देह प्रचंडी वृद्धि होगी—उदाहरण के तौर पर सड़को, स्कूलों तथा उद्योगों

की सख्या में काफी वृद्धि होगी किन्तु इस दिशा में भी हम अधिक आगे नहीं बढ़ सकेंगे और जनता के लिए हमारी देन साधारण ही रहेगी, तथा यह उस प्रकार के दातावरण के संबंधात् विपरीत है। साथ ही यह उन समस्त कठिनाइयों के विपरीत है जो विकास कार्यों को चलाने में उठाने पड़ती हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में सरकार विकास कार्यों को सगठित करने का प्रयत्न पूँजीवादी तरीकों द्वारा करती थी जहाँ पर उत्पादन का समस्त कार्य अनहस्तक्षेप की नीति (Laissez faire) से 'जगन्नाथ जी के रख' अथवा तानाशाही के रूप में होता था, जिस पर पदें डाल दिये जाते थे जिससे कि लोग अन्दर की घटनाओं के बारे में न जान सकें। अथवा कम से कम खुले रूप में बहने अथवा आलोचना तथा विरोध करने से रोका जा सके।

हम सब लोगों का यहाँ पर आह्वान एक नवीन प्रयोग के बारे में विचार करने के लिए हुआ है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें जनतन्त्र को विकास से सम्बद्ध करना है, जो पहले कभी सिद्ध नहीं किया गया। जिस स्तर से हमको आगे बढ़ना है उसको एक छरफ छोड़ दो। इतिहास में सम्भवतः यह पहला ही प्रयत्न है जबकि किसी देश ने अपने विकास कार्यों को राजनैतिक प्रजातन्त्र द्वारा हल करने का बीड़ा उठाया हो। अगर हम काय को करना है तो यह निश्चय है कि बहुत शीघ्रता से और थोड़े समय में हम अपने देशवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि नहीं कर सकते।

द्वितीय विशेषता

दूसरी पञ्चवर्षीय योजना की दूसरी विशेषता, जिस पर योजना आयोग ने सही रूप से गौर नहीं किया है, इसके बारे में श्री अर्थोक लेहता ने आर्थर-लुईस (Arthur Lewis) की पुस्तक *The Theory of Economic Growth* के २३५ व पेज का उद्धरण दिया है, जिसमें श्री लुईस (Lewis) कहते हैं —

“इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) की व्याख्या भयवा कहना चाहिए कि पूँजी उत्पादन में यथायक वृद्धि करने का सबसे सरल साधन द्रव्य कमाने की (opportunities) दशाओं में यथायक वृद्धि कर देने में निहित है—चाहे ये नवीन दशाएँ नयी खोजों (Invention) के ही अथवा संस्थाओं के परिवर्तनों के कारण—जो वर्तमान सम्भावनाओं का शोषण करना सरल बना देती है। इंग्लैण्ड, जापान तथा रूस में जो भी औद्योगिक क्रांतियाँ हुईं, वे सब इसी स्तर पर घटित हुईं। इन समस्त मामलों में प्रत्याशित फल यह होता है कि उत्पादन वृद्धि से लाभ होता है, वह ऐसे वर्ग—मजदूर किसान—को नहीं मिलता जो अपना उपयोग बढ़ा सकें, परन्तु यह सारे का सारा लाभ या तो निजी लाभ में अथवा मार्बर्जनिज्म के रूप में चला जाता है, जहाँ पर कि वह पूँजी के निर्माण और वृद्धि में सहायक होता है। इससे लाभ यह होता है कि मजदूरों को बड़ी सख्या में रोजगार मिल जाता है लेकिन उनकी वास्तविक मजदूरी में उत्पादन के अनुसार—वृद्धि नहीं होती।”

“अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा एक और क्षेत्र होता है जो पूँजी का उपभोग करने वाला क्षेत्र कहनाता है। यह पूँजी का उपभोग करने वाला ही क्षेत्र होता है, जो अर्थव्यवस्था को एक बड़े पैमाने पर लाभान्वित करता है। अधिक विकास की एक मुख्य बात यह होती है कि वितरण के अर्थ साधनों—मजदूरी, लगान और वेतन—के वजाय लाभ बहुत तेजी से बढ़ना है। लाभ विकास का आधार है, अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग अभिक है। एक पूर्ण रूप से राजतन्त्र (Totalitarian) देश में इस उत्पादन का सारा उपभोग तथा निर्धारण राज्य द्वारा किया जाता है। एक अनहस्तक्षेप की विचार धारा वाले देश में इस उत्तोलक का उपभोग पूँजीपतियों द्वारा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि हमारे देश की सरकार, जो कि हमारी अर्थ-व्यवस्था को समाजवाद के आधार पर विकसित करने को उत्सुक है, किस तरह ‘उत्तोलक’ को काम में लाएगी ? इस तथ्य के बारे में योजना आयोग ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है।”

“अब योजना की पूर्ति के साधनों में वृद्धि करने का सवाल उठता है। यहाँ एक मुख्य बात ध्यान रखने की यह है कि साधनों का विकास इस तरह से हो जिससे कि जिन लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि न हो वे यह अनुभव करें कि साधनों के विकास से देश के अन्दर वर्तमान असमानताओं में कोई वृद्धि नहीं हुई। मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य होता है कि योजना आयोग ने योजना के प्रारम्भिक तत्वों को बिल्कुल भुला दिया। योजना आयोग विकास के मुख्य तत्व को भुला कर, कर की मात्रा और दर में औसत से अधिक वृद्धि कर रहा है। कर की प्राप्ति राष्ट्रीय आय की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ बढ़ रही है।”

“दूसरा सवाल मुद्रा प्रसार का है। मुद्रा प्रसार से साख के प्रचलन में वृद्धि होती है। साख का प्रचलन अधिकतर बैंकों से होता है, जो बड़े पूँजीपतियों और व्यापारियों के अधिकार में है। वित्तमन्त्री सम्भवतः इसलिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के विचार से सहमत नहीं हैं। प्रधान मन्त्री सोचते हैं कि हम इन सब बातों का नुभाव राष्ट्रीयकरण की नीति को अव्यावहारिक (Theoretical) रूप से सन्तुष्ट करने के लिए देते हैं, और चूँकि हम अपनी अर्थव्यवस्था के बूड़े कंकड़ (Junk) को इकट्ठा करके फेंकने की इच्छा रखते हैं।”

“दूसरी योजना के बारे में एक और तथ्य है। ८३ पेज पर योजना आयोग ने लिखा है कि “...राज्य को प्रत्यक्ष रूप से अतिरेक कर अथवा राजकीय उद्योगों से लाभ के रूप में प्राप्त सार्वजनिक बचत की मात्रा जितनी ही कम होगी, उपभोग के स्तर को नीचा रखने के साधनों अथवा कम करने के तरीकों को अपनाने की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जाएगी।”

“दूसरी योजना के बारे में लोगों ने बहुत ही जिज्ञासापूर्ण रव्य अपनाया है। वे करो का विरोध करते हैं, राजकीय उद्योगों के लगान में वृद्धि नहीं होने देना चाहते

हैं तथा हर प्रकार के नियन्त्रण के विरुद्ध हैं। अगर हम इन लोगों को नाराज रखेंगे तो हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। योजना आयोग के सभी सदस्य जनमत में फैले आमक विचारों का निवारण करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं लेकिन इसके लिए वह तैयार नहीं होते। वे यह नहीं कहते कि नहीं, अगर हम अपने विकास कार्यक्रमों को पूरा करना है, अगर हमें अभाव और गरीबी के बातावरण से अलग हट कर समृद्धि के साम्राज्य को प्राप्त करना है, तो कर इसी दर से लगाने चाहिए और नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य भी इसी ढंग से करने होंगे।”

“अगर देश में उन्हीं लोगों को एकत्रित करना है, जो देश की आजादी के लिए लड़े थे अथवा केवल उन्हीं लोगों का सम्मेलन करना है जो आजादों की इस सड़क को गरीबी और अभाव को दूर करने के लिए आगे भी जारी रखना चाहते हैं, और अगर हमें यह कार्य करना है,—तो हमको प्रजातन्त्र और विकास (development) के बीच में एक आध्यात्मिक नहर (Spiritual Suez) का निर्माण करना चाहिए जिससे, गरीबी से अमीरी तक की मानवयात्रा की दूरी कम हो जाय और किसी को किसी प्रकार का अभाव न रहे।”

दूसरी योजना की वित्तीय पूर्ति के लिए कालडोर की कर-नीति का प्रस्ताव

(Kaldor's Tax Proposals For Financing The Second Plan)¹

योजना आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक विकास कार्यक्रमों पर व्यय करने के लिए ४५० करोड़ रुपया के अतिरिक्त कर लगाने का सुझाव दिया है। करो की यह वृद्धि ३५० करोड़ रु० के उस अतिरिक्त धन से भी अधिक होगी, जो वर्तमान करो की दर और ढांचे में कोई परिवर्तन न किया जाय। योजना काल में इस अतिरिक्त धन राशि की वृद्धि केन्द्र तथा राज्यों में ५०-१० प्रतिशत के आधार पर होगी।

इस कराभिव्य के अलावा केन्द्रीय सरकार ४०० करोड़ रु० की अतिरिक्त धन राशि को जुटाने का प्रयत्न करेगी, जो योजना के वित्तीय पहेलू में खाई (gap) के रूप में छोड़ दी गई है।

इस प्रकार कुल मिलाकर योजना काल में केन्द्रीय सरकार को $450 \times \frac{1}{2} + 400$ करोड़ = ६२५ करोड़ रु० की व्यवस्था करनी होगी, जो बहुत ही दुष्कर है। प्रोफेसर कालडोर ने भारत की विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया और उसके बाद यह सुझाव दिया कि ‘द्वितीय योजना की वित्तीय माँग को पांच वर्षों में

प्राप्त १२५० करोड़ रु० के अतिरिक्त करो द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता।¹ आगे उ-होने कहा कि “वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय ग्रंथ-व्यवस्था, पांच वर्ष के कायकाल में, ८०० करोड़ रु० में अधिक घाटे के व्यय की राशि को वहन नहीं कर सकती .. . इस आधार पर योजना में ४५० करोड़ रु० अतिरिक्त कर के रूप में, ४०० करोड़ रु० ‘गैप’ (gap) के रूप में, ४०० करोड़ रु० अतिरिक्त व्यय के रूप में प्राप्त करने की व्यवस्था की है, इस प्रकार कुल मिलाकर दूसरी योजना में १२५० करोड़ रु० की धन राशि को करो द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई, इससे से २२५ करोड़ रु० के राज्यों के हिस्से को निकाल कर (१२५०-२२५= १०२५) केन्द्रीय सरकार को १०२५ करोड़ रु० की व्यवस्था करनी होगी।

अतिरिक्त करो की प्राप्ति की सम्भावनाओं के बारे में प्रो० कालडोर का मत यह था कि “भारतवर्ष में आय कर की वर्तमान प्रणाली बड़ी कठिन, साथ ही साथ बहुत उदार है। यह कठिन इसलिए है कि आय कर की अधिकतम सीमा, कुल आय का ६२ प्रतिशत रखी गई है, जिससे कर प्रवर्तन में कमी होकर कर वसूल में वृद्धि होती है। यह प्रणाली उदार इस कारण है क्योंकि इसने आय की बहुत सी दोषपूर्ण तथा गलत परिभाषायें अपनायी हैं। जिससे कर दाता जानबूझ कर अपने लाभ तथा जायदाद की आय पर कर देने से आसानी से बच जाता है।”

इस बारे में उनके सुझाव निम्नलिखित हैं —

(१) “आय की परिभाषा में विद्यमान सभी कमजोरियों (loop holes) को दूर करने के लिए एक ऐसी प्रणाली अपनायी जाय जो जायदाद और पूँजीगत परिवर्तनों के बारे में पूरी-पूरी जानकारी दे तथा उससे ठोस फल की प्राप्ति हो।”

(२) “१०,००० से ऊपर होने वाली वार्षिक व्यक्तिगत आय का तथा ५०,००० से ऊपर की व्यावसायिक आय का समुचित रूप से आवश्यक तौर पर लेखा जोखा हो।”

(३) “वर्तमान आय कर को समाप्त करके उसके स्थान पर—पूँजीगत लाभ कर, दान कर, तथा व्यक्तिगत व्यय कर के रूप में समस्त पूँजी पर सालाना कर लगाये जाय। इन सब पर एक साथ कर निर्धारित (Assessment) किया जाय।”

(४) “२५००० रु० से ऊपर की आय पर कर की दर ४५ प्रतिशत से अधिक न रखी जाय। १५ लाख रु० से ऊपर की जायदाद पर लाभ कर की दर १३% हो, दान कर की अधिकतम दर, (४० लाख से अधिक मूल्य की जायदाद पर) ३० प्रतिशत, व्यय कर की दर, प्रति व्यक्ति के ५०,००० रु० के सालाना व्यय पर, ३००% हो। पूँजी पर लाभ के कर की दर आयकर की दर के अनुसार हो।

1 “The requirement of the Second Plan could not be met without any additional taxation of Rs 1250 crores in five years”—Kaldor

(५) "ये समस्त कर प्रगतिशील (Progressive) होनी चाहिए ।"

(६) "जायदाद पर कर की कम से कम छूट की सीमा १ लाख रु० हो, तथा व्यक्तिगत व्यय की सीमा १० ००० रुपया हो ।"

(७) "जायदाद कर, दान कर तथा व्यक्तिगत व्यय कर की दर कम से कम क्रमशः ३%, १०% तथा २५% हो ।"

प्रोफेसर कालडोर का अनुमान था कि अगर इन समस्त करों को प्रस्तावित दर पर एक साथ लगाया जाय तो इनसे प्रतिवर्ष ६० से १०० करोड़ रु० की अतिरिक्त आय होगी ।

भारत की राष्ट्रीय आय के प्राप्त आँकड़ों के आधार पर प्रोफेसर कालडोर ने यह अनुमान लगाया था, कि कृषि तथा उससे सम्बन्धित कार्यों को छोड़ कर, हम समय करीब ५७६ करोड़ रुपये की आय की न तो कोई गणना होती है और न उस पर कर (Tax) हो लगाया जाता है । अगर समस्त राष्ट्रीय आय का सही रूप से हिसाब लगाया जाय, तो आयकर में २०० से ३०० करोड़ रु० की अतिरिक्त आयदानी हो ।

पन्त ने श्री कालडोर ने कहा कि "कर से बचने की समस्त कमियाँ को पूर्णरूपेण दूर करना, करों की आय पर अत्यधिक जोर देना तथा समस्त करों की क्रमिक रूप से उधाना बड़ा ही कठिन है । ' अगर प्रत्यक्ष करों में ही क्रिये गये सुधार सफल हो गए तो भी उनके द्वारा कर, आय सम्बन्धी ज़रूरतों को पूर्णरूप से समुष्ट नहीं किया जा सकता ।"

इस प्रकार हम इन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं कि द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना की वित्तीय लागत को पूरा करने के लिए सरकार के पास केवल दो ही उपाय बचे रह जाते हैं—

(१) योजना के लागत व्यय में कटौती की जाय और इस प्रकार तीव्र आर्थिक विकास की सम्भावनाओं को कम किया जाय, या

(२) घाटे की वित्त-व्यवस्था (Deficit financing) का सहारा लिया जाय जिसके कारण मुद्रा प्रसार के दबाव में तीव्र अभिवृद्धि हो ।

हमारी राष्ट्रीय सरकार ने योजना के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए दूसरे साधनों को अपनाया है । अर्थात् दूसरी योजना के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार ने घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लिया है ।

विश्व बैंक मिशन द्वारा द्वितीय योजना की आलोचना^१

(Criticism of the Second Plan by the World Bank Mission)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अधिकोषण (Bank) का विकास तथा पुनर्निर्माण से सम्बन्धित जो मिशन—द्वितीय योजना की अन्तिम विज्ञप्ति के प्रकाशन के तुरन्त बाद

1. Based on their Memorandum to the Govt of India

भारत में आया, उसने दूसरी योजना के बारे में भारत सरकार को एक पत्र (Memorandum) दिया था। उस स्मरण-पत्र में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये गये थे—

(१) योजना का आकार बहुत ही विस्तृत है।

(२) योजना के आकार को देखते हुए कीमतों को स्थिर रखने तथा अन्न पूर्ति के विकास के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं वे नाकाम्य हैं।

(३) योजना का ढाँचा—मुख्य रूप से यातायात की जरूरतों के बारे में असन्तुलित है।

(४) छोटे-छोटे कारखानों के प्रभावशाली विकास का योजना के सन्तुलन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

(५) १२०० करोड़ रुपये की घाटे की व्यवस्था के कारण मुद्रा की पूर्ति में अनावश्यक रूप से वृद्धि होगी, जो हमारे अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतों को देखते हुए काफी अधिक होगी।

(६) “योजना निर्धारित विकास की एक सुनियोजित नीति का सहारा चाहती है।”¹

(७) योजना में पाँच साल की अवधि में, १०० करोड़ रुपये के निजी क्षेत्र के निजी विनियोग (विदेशों से) की आवश्यकता बाधित समझी गई है, जो सब एवं व्यावहारिक नहीं है। क्योंकि वर्तमान समय में सरकार ने विकास की जो नीतियाँ एक रख अपनायी हैं वह विदेशी पूँजी को आकर्षित करने में समर्थ नहीं है।

(८) व्यक्तिगत व्यवसाय के महत्व को अच्छी तरह से नहीं समझा गया है और योजना में इसके विकास के लिये कोई घोषणा प्रकाशित नहीं की गई है।

द्वितीय योजना और घाटे की अर्थव्यवस्था

(Deficit Financing and the Second Plan)

अधिकांश लोगों के विचार में घाटे की अर्थव्यवस्था मुद्रा प्रसार को तीव्र करती है। ये लोग मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) के अनुयायी हैं। उनके अनुसार “घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण द्रव्य की कुल मात्रा में अनावश्यक रूप से वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप सामान्य कीमतों के स्तर में भी वृद्धि होने लगती है और जैसा कि स्पष्ट है पूर्ण रोजगार के स्तर पर, उत्पत्ति की सीध में नहीं के बराबर परिवर्तन होता है। अर्थात् पूर्ववत् दशा बनी रहती है।”²

1. “The plan need is wanting in a well conceived export promotion policy.”

2. Indian Economics—P N. Chatterjee, pp. 622—623.

डाक्टर V K R V Rao के मतानुसार “घाटे की वित्तीय व्यवस्था मुद्रा स्फीति के समानार्थी (Synonymous) के रूप में कार्य करती हैं। क्योंकि अल्पकाल में विनियोग और बचत में जो अन्तर होता है वह कीमतों की वृद्धि के कारण ही होता है। दीर्घकाल में जब कि आर्थिक विकास तेजी से होता है, और बचत विनियोग का यह अन्तर समाप्त होजाता है यह कार्य मुख्य रूप से स्वेच्छाचारी बचत के द्वारा सम्पन्न होता है। इस प्रकार दीर्घकाल में मुद्रा स्फीति का प्रभाव समाप्त होता जाता है।”

प्रोफेसर बी० आर० शैनोए (Prof B R Shenoy) ने अपने ‘Note of Dissent’ में कहा है कि “वित्तीय घाटे से विनियोग और बचत की दर में जो असंतुलन (disequilibrium) पैदा होजाता है उसके कारण कीमतों में वृद्धि होकर मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होजाती है।” आगे श्री शैनोय का कहना है कि “अगर तीव्र आर्थिक विकास के लिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था आवश्यक ही है, तो उसकी गति धीमी रखी जाय, जिससे कि विनियोग और बचत की दर में सामंजस्य स्थापित किया जा सके और मुद्रा स्फीति को समाप्त किया जा सके।”

कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो उपर्युक्त विचार से सहमत नहीं हैं। उनके विचार में देश के आर्थिक विकास के लिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है। डाक्टर ए० दास गुप्ता के अनुसार ‘एक अल्प विकसित देश के आर्थिक विकास के लिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था परम आवश्यक है। यह वह अस्त्र है जिसके द्वारा, एक अल्प विकसित देश की केन्द्रीय सरकार, एक ही समय में पूँजी निर्माण तथा रोजगार की दशाएँ उत्पन्न करने के, दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है।’ उन्होंने द्वितीय योजना के निर्माण के सम्बन्ध में ‘Economic Weekly’ में एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें लिखा था कि द्वितीय योजना में १२०० करोड़ रुपये की जो वित्तीय घाटे की व्यवस्था की है उससे कीमतों में कोई गम्भीर वृद्धि नहीं होगी। उनके अनुसार इस समय देश में १,३०० करोड़ ६० की मात्रा के कागजी नोटों का प्रचलन है। वित्तीय घाटे के कारण द्रव्य की मात्रा में १,२०० करोड़ ६० की और वृद्धि हो जाएगी। इसमें से २०० करोड़ ६० पौण्ड पावने की राशि से प्राप्त होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर १,३०० करोड़ रुपये के करीब कागजी मुद्रा का प्रचलन होगा, जो वर्तमान मुद्रा प्रचलन में ७७% अधिक होगा। योजना में उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य २५ प्रतिशत रखा गया है। द्रव्य प्रचलन की गति (Velocity) को स्थिर मान कर तथा साख मुद्रा को कम रख कर कीमतों में कुल मिलाकर ६% से ११% तक की सालाना वृद्धि होगी। रोजगार की अनेक दशाओं की उपलब्धि को देखते हुए कीमतों की यह वृद्धि कोई विशेष हानिकारक नहीं होगी।”

बादविवाद की प्रकृति चाहे जो हो, किन्तु इस बात को हम कदापि अस्वीकार नहीं कर सकते कि दूसरी योजना में वित्तीय घाटे की जो व्यवस्था की गई है उसके कारण बहुतसी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है। एक देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए थोड़ी मात्रा के घाटे की वित्तीय व्यवस्था लाभदायक है किन्तु घाटे की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इसकी कीमतों की वृद्धि के रूप में गम्भीर परिणाम निकलते हैं, जैसा कि दूसरी पंच वर्षीय योजना काल में हुआ।

योजना में उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों के विकास पर कोई बल नहीं दिया गया है और जब तक उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन पर विशेष बल नहीं दिया जायगा, तब तक देश को इन वस्तुओं के लिए विदेशों पर अवलम्बित रहना पड़ेगा। ये उद्योग दीर्घकाल में उपभोग की वस्तुओं के उद्योग पर प्रभाव डालते हैं, अतः क्याही अच्छा होता कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर बल न देकर उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता। सच तो यह है कि द्वितीय योजना के प्रत्येक कार्यक्रम में बहुतसी कमियाँ तथा बुराइयाँ भरी हुई हैं। उदाहरण के तौर पर असन्तुलन, असहयोग, अकर्मण्यता तथा साधनों की कमी आदि। इनमें से कुछ तो काफी महत्वपूर्ण हैं और कुछ बहुत कम। इन सब दोषों की ओर दृष्टिपात न करके हम केवल इतना कह सकते हैं कि हमारे योजना-धिकारी विद्यम परिस्थितियों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, यही कारण है कि वे निर्बोध सर्वाङ्गीण उन्नति प्राप्त करने में असफल रहे हैं। क्या हम आशा करें कि हमारी आगे आने वाली योजनाओं में ये दोष नहीं रहेगे ?

तृतीय पंचवर्षीय योजना

The Third Five Year Plan

✓ १—योजना की रूपरेखा^१

(The Planframe)

तीसरी योजना के उद्देश्यों का, और मोटे रूप से जिन आर्थिक विचारों को सामने रख कर इसके परिमाण और पूँजी विनियोग के रूप का निश्चय किया गया है, उनका उल्लेख पहले अध्यायो में हो चुका है। इस अध्याय का उद्देश्य, संक्षेप में, इस योजना की प्राथमिकताओं को बतलाना, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई गई पूँजी के विभाजन का चित्र प्रस्तुत करना और योजना के लक्ष्यों का प्रारम्भिक मूल्य आकना है। इसमें यह बतलाने का यत्न भी किया जाएगा कि केन्द्र और राज्यों में योजना के व्यय का प्रारम्भिक विभाजन कैसे होगा। विभिन्न क्षेत्रों के जिन लक्ष्यों का यहाँ संकेत किया जाएगा, वे सब अस्थायी होंगे। उनका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि उनसे केन्द्र और राज्यों को आगे अध्ययन करने में सहायता मिले। परियोजनाओं, कार्यक्रमों और उन्हें पूरा करने के क्रम का अध्ययन अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा और उसके परिणाम योजना की अन्तिम 'रूप' में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। प्राथमिकताएँ

किसी भी पंचवर्षीय योजना के पूँजी-विनियोग के रूप से पता चल सकता है कि योजनाकाल में उसकी प्राथमिकताएँ क्या रहनी और उसके विभिन्न भागों में से किस पर कितना जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इनका निश्चय, उस समय विद्यमान आर्थिक परिस्थिति और सम्भावित प्रवृत्तियों का विचार करके, देश की बुनियादी आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करके और दीर्घकालीन लक्ष्यों को देख कर भी किया जाता है। इसलिए इनका निश्चय करते समय अनेक विचारों में सन्तुलन रखने की होदियारी भी बरतनी पड़ती है।

विकास के नवो में स्वभावतः सबसे प्रथम स्थान कृषि का है। देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देना और उद्योगों तथा निर्यात की आवश्यकताएँ पूरी कर देना तीसरी योजना का एक प्रधान लक्ष्य है। इसलिए कृषि के उत्पादन को यथासम्भव उच्चतम स्तर तक उठाना होगा, ताकि ग्रामीण लोगों की आमदनी और रहन-महन का स्तर भी अन्य क्षेत्रों के लोगों के साथ-साथ ऊँचा उठे। कृषि उत्पादन का स्तर देख कर यह भी पता लगता है कि समस्त अर्थ-व्यवस्था की तरक्की किस रूप-रंग से हो रही है। यों भी, कृषि अर्थ-व्यवस्था का विस्तार और ग्रामीण जन-शक्ति तथा अन्य साधनों का उपयोग करने में परस्पर गहरा सम्बन्ध है। यह तीसरी योजना का एक बड़ा लक्ष्य भी है। इसी कारण, इस योजना में कृषि और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए पर्याप्त साधन मुहैया करने का प्रयत्न किया गया है। सोचा गया है कि यदि योजना के भागें बढन पर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की प्रगति और तेज करने के लिए, विशेषकर ग्रामीण जन-शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए, और साधनों की आवश्यकता पड़े, तो वे भी जुटा दिये जाय।

सामान्य विचारों के द्वितीय वर्ग का सम्बन्ध योजना में उद्योग, विजली और परिवहन के क्षेत्र की प्रदान की गई प्राथमिकता से है। अर्थ-व्यवस्था को उच्चतर स्तर पर ले जाने और उसकी गति को तीव्र करने के लिए इन क्षेत्रों का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। यह मानी हुई बात है कि आगे बढने के क्रम में एक मजिल ऐसी आ जाती है कि उससे आगे कृषि की उन्नति और जन-शक्ति का विकास उद्योगों की प्रगति पर ही निर्भर करने लगते हैं। इसलिए, कृषि और उद्योगों को सदा विकास की एक ही प्रक्रिया का समन्वय भ्रम मान कर चलना चाहिए। जब तक अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी गति की दशा में नहीं पहुँच जाती, तब तक औद्योगिक विकास के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बड़ी मात्रा में पड़ती ही रहेगी।

चूँकि बड़ी परियोजनाओं में लगाई हुई पूँजी से, उत्पादन-वृद्धि-रूपी फल की प्राप्ति, बहुधा बहुत समय के पश्चात् होती है, इसलिए उनकी योजना काफी पहले से बना लेनी चाहिए और दीर्घकाल पश्चात् तथा अपेक्षाकृत कम समय में फल देने वाली परियोजनाओं में एक उचित अनुपात रख लेना चाहिये।

उद्योग, विजली और परिवहन आदि प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकताओं का निश्चय सावधानीपूर्वक कर देना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनमें सुरन्त ही हेर फेर किया जा सके। दूसरे, इन क्षेत्रों के कार्यक्रमों का संचालन समन्वयपूर्वक होना चाहिए। परस्पर-सम्बद्ध परियोजनाओं की पूर्ति एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुये कार्यों की भाँति करना चाहिए, ताकि काम मनोपन्नक सोपानों में बाँट कर किया जा सके और परियोजनाओं के प्रत्येक वर्ग पर किये गए व्यय से अधिकतम लाभ मिल सके।

औद्योगिक क्षेत्र की योजना, समस्त अर्थ-व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर बनाई जा रही है और बना करते समय

योजना के सरकारी और निजी क्षेत्रों को एक मान लिया गया है। उपलब्ध प्राकृतिक साधनों और देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं का तकाजा है कि बुनियादी उद्योगों पर—विशेषकर इस्पात, यन्त्र-निर्माण, ईंधन और बिजली पर—ज्यादा जोर दिया जाए। इन उद्योगों और कृषि में जो उन्नति होगी, बहुत-कुछ उस पर ही यह निर्भर करेगा कि हमारी अर्थ-व्यवस्था भविष्य में अपना विकास अपने ही साधनों से कहाँ तक कर सकती है।

तीसरी योजना में प्राथमिकताओं के एक अन्य जिस वर्ग पर ध्यान दिया जा रहा है, वह समाज सेवाओं और उनमें सम्बद्ध विकास-क्षेत्रों से सम्बन्धित है। आर्थिक और सामाजिक विकास के फलड़ों को बराबर रखने के लिए इन पर ध्यान देना परम आवश्यक है। अनुभव बतलाता है कि देश की जन-शक्ति का विकास करने, लोगों में उत्साह भरने और उन्हें समझ-बुझाकर काम में लगाने के लिए, शिक्षा और समाज-सेवाओं के महत्त्व का बखान चर्चों में नहीं किया जा सकता।

इस वर्ग में सम्मिलित कई विकास-कार्य तो—जैसे, वैज्ञानिक अनुसन्धान, तकनीकी शिक्षा, कारीगरों का प्रशिक्षण और औद्योगिक क्षेत्रों में मकान बनवाना तथा बस्तियाँ बसाना, आदि—ऐसे हैं, जिनका आर्थिक विकास के साथ सीधा सम्बन्ध है। कुछ और कार्य व्यापक सामाजिक दृष्टि से अनिवार्य हैं—जैसे, शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य तथा बिकृति-सेवाओं की व्यवस्था, परिवार-नियोजन, गांवों और शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था और जनता के पिछड़े हुए वर्गों के लिए कल्याण-कार्यों की व्यवस्था। योजना में, उपलब्ध साधनों की सीमा का ध्यान रखते हुए, इन सब सेवाओं की व्यवस्था रखी गई है। योजना के आगे बढ़ने पर, कम से-कम कुछ कार्यों में अधिकाधिक प्रगति करने का प्रयत्न किया जाएगा।

तीसरी योजना में साधनों का विभाजन करते समय इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन का और जनता में वृद्धि का स्तर वर्ष-प्रति-वर्ष ऊँचा होता चला जाये। यह भी आवश्यक है कि पूँजी के एकत्र होने और उसके उपयोग में लगने में अनावश्यक बिलम्ब न हो। सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में हर कदम पर यह ध्यान रखना चाहिये कि जो पूँजी पहले लग चुकी है और जो आगे तीसरी योजना में लगाई जाएगी, उससे उत्पादन वृद्धि के रूप में अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

व्यय और पूँजी विनियोग का विभाजन

योजना में, सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के व्यय की चर्चा की गई है। सरकारी क्षेत्र में पूँजीगत व्यय और चालू व्यय में अन्तर किया गया है—‘चालू व्यय’ में मतलब कर्मचारियों के व्यय और घाटा बराबर करने के लिए दी गई सरकारी सहायता, आदि से है। तीसरी योजना में अब मिलाकर १०,२०० करोड़ ६० पूँजी-विनियोग करने का विचार है। इसमें से ६,२०० करोड़ ६० सरकारी

क्षेत्र में और ४,००० करोड़ रु० निजी क्षेत्र में लगाये जायगे। सरकारी क्षेत्र में अन्दाजन १,०५० करोड़ रु० का चालू व्यय होगा। उसे मिलाकर इस क्षेत्र का समस्त व्यय ७,२५० करोड़ रु० हो जायगा। निजी क्षेत्र में पूँजी-विनियोग में २०० करोड़ रु० की वह राशि भी शामिल है, जो पूँजी-संग्रह के प्रयोजन सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में ले जाई जायगी। नीचे की तालिका में तीसरी और दूसरी योजनाओं के व्यय और पूँजी-विनियोग की तुलना की गई है।

दूसरी और तीसरी योजनाओं का व्यय और पूँजी-विनियोग^१

(करोड़ रुपये)

	सरकारी क्षेत्र			निजी क्षेत्र ^२	समस्त पूँजी-विनियोग
	योजना का व्यय	चालू व्यय	पूँजी-विनियोग		
दूसरी योजना	४,६००	६५०	३,६५०	३,१००	६,७५०
तीसरी योजना	७,२५०	१,०५०	६,२००	४,०००	१०,२००

इससे प्रकट है कि तीसरी योजना का समस्त पूँजी-विनियोग दूसरी योजना के पूँजी विनियोग से लगभग ५१ प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, सरकारी क्षेत्र के पूँजी-विनियोग और प्रस्तावित व्यय में क्रमशः लगभग ७० प्रतिशत और ५८ प्रतिशत की, और निजी पूँजी-विनियोग में लगभग २६ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

नीचे की तालिका में तीसरी योजना के प्रस्तावित व्यय और पूँजी-विनियोग का विभाजन दिखलाया गया है।

- यहाँ बार-बार प्रयुक्त दो शब्दों का अभिप्राय संक्षेप में समझ लेना चाहिए :
 - (१) 'पूँजी-विनियोग' वह व्यय है, जो भवनों, मशीनों और इसी प्रकार के अन्य उपकरणों, आदि भौतिक सम्पदा पर किया जाता है। इसमें सम्पदा के निर्माण में लगाये गये लोगों पर होने वाला व्यय भी शामिल है। यह शब्द मोटे हिसाब से पूँजी खर्चे होने वाला व्यय के लिए प्रयुक्त हुआ है।
 - (२) 'चालू व्यय' मोटे हिसाब से योजना के कार्यों पर राजस्व खर्चे पर किया गया व्यय है। यह व्यय 'पूँजी विनियोग' से भिन्न है।
- इन श्रृंखला में वह पूँजी-विनियोग शामिल नहीं है, जो सरकारी क्षेत्र से वरतावर्तित साधनों से किया गया हो।

तीसरी योजना में प्रस्तावित व्यय और पूँजी-विनियोग

(करोड़ रुपये)

विकास का विभाग	सरकारी क्षेत्र			निजी क्षेत्र का पूँजी-विनियोग	समस्त पूँजी-विनियोग
	योजना का प्रस्तावित व्यय	चालू व्यय	पूँजी-विनियोग		
१. कृषि, छोटी सिंचाई और सामुदायिक विकास	१,०२५	३५०	६७५	८००	१,४७५
२. बड़े और मध्यम सिंचाई-कार्य	६५०	१०	६४०	—	६४०
३. विजली	६२५	—	६२५	५०	६७५
४. ग्रामीण और छोटे उद्योग	२५०	६०	१६०	२७५	४३५
५. उद्योग और खानें	१,५००	—	१,५००	१,०००	२,५००
६. परिवहन और संचार	१,४५०	—	१,४५०	२००	१,६५०
७. समाज सेवाएँ	१,२५०	६००	६५०	१,०७५	१,७२५
८. इन्वेण्टरियाँ	२००	—	२००	६००	८००
सर्वयोग	७,२५०	१,०५०	६,२००	४,०००	१०,२००

पहली योजना के समय देश की अर्थव्यवस्था में वार्षिक पूँजी-विनियोग लगभग ५०० करोड़ रु० से बढ़ते-बढ़ने कोई ८५० करोड़ रु० तक पहुँच गया था। दूसरी योजना के अन्त तक वार्षिक पूँजी-विनियोग के १,४५० करोड़ रु० से १,५०० करोड़ रु० तक पहुँच जाने की आशा है। तीसरी योजना की समाप्ति पर वार्षिक पूँजी-विनियोग का विस्तार शायद २,५०० करोड़ रु० के आसपास पहुँच जाएगा। पहली योजना में सरकारी पूँजी-विनियोग लगभग २०० करोड़ रु० प्रतिवर्ष से आरम्भ होकर योजना-समाप्ति तक ४५० करोड़ रु० हो गया था। दूसरी योजना के अन्त तक इसके लगभग ८०० करोड़ रु० और तीसरी योजना के अन्त तक कोई १,५०० करोड़ रु० हो जाने की आशा है।

तीसरी योजना में भी पूँजी-विनियोग का सामान्य रूप वही रहेगा, जो दूसरी योजना में था, परन्तु सरकारी क्षेत्र में कृषि, उद्योग, बिजली और समाज-सेवा के कुछ पहलुओं पर ज्यादा जोर दिया जायगा। दूसरी और तीसरी योजनाओं में विभिन्न कार्यों के लिए जो व्यय प्रस्तावित किया गया है, उसका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है।

**योजना के सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित व्यय का
विभिन्न कार्यों में विभाजन**

(करोड़ रुपये)

	प्रस्तावित व्यय		सारे व्यय का प्रतिशत	
	दूसरी योजना	तीसरी योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
१. कृषि और छोटे सिंचाई कार्य	३२०	६२५	६.६	८.६
२. सामुदायिक विकास और सहकारिता	२१०	४००	४.६	५.५
३. बड़े और मध्यम सिंचाई-कार्य	४५०	६५०	६.८	८.०
४. योग १, २ और ३ का	९८०	१,६७५	२१.३	२१.१
५. बिजली	४१०	६२५	८.६	१२.८
६. ग्रामीण और छोटे उद्योग	१८०	२५०	३.६	३.४
७. उद्योग और खानें	८८०	१,५००	१६.१	२०.७
८. परिवहन और संचार	१,२६०	१,४५०	२८.१	२०.०
९. योग ५, ६, ७ और ८ का	२,७६०	४,१२५	६०.०	५६.६
१०. समाज-सेवाएँ	८६०	१,२५०	१८.७	१७.२
११. इन्वेस्टिमेंट्स	—	२००	—	२.८
सर्वयोग	४,६००	७,२५०	१००	१००

योजना के निजी क्षेत्र का पूँजी-विनियोग मोटे हिसाब से दो भागों में बँटा हुआ है—(१) उद्योगों, खानों बिजली और परिवहन के संगठित कारोबार में लगा हुआ और (२) कृषि, ग्रामीण और छोटे उद्योगों और ग्रामीण तथा शहरी मकानो-सरोजि विभिन्न कामों में बिखरा हुआ। दूसरे भाग के विषय में जानकारी स्वभावतः बहुत अनिश्चित है, परन्तु हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र के संगठित कारोबार की जानकारी अधिक निश्चित और स्पष्ट हो गई है। निजी क्षेत्र के विविध कार्यों में विभक्त पूँजी-विनियोग का विवरण साधन-विषयक अध्याय में दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित व्यय

इस समय प्रस्तावित व्यय-विभाजन स्वभावतः ग्रंथायी हैं। यहाँ इनके निर्देश का प्रयोजन यह है कि केन्द्र और राज्य-सरकारों को अपने कार्यक्रमों और परियोजनाओं की विस्तृत परीक्षा करने और विकास के प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकताओं का क्रम निश्चित करने में सहायता मिले। योजना के जिन भागों की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्यों के ऊपर है, उनके व्यय का अन्तिम निश्चय राज्य-सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं और उनके द्वारा विविध कार्यक्रमों पर डाले गए जोर को देख कर किया जायगा। राज्य-सरकारें भी यह जोर इन कार्यक्रमों के दावों की तुलना करके और उपलब्ध वित्तीय साधनों को देख कर ही डालेंगी। कई क्षेत्रों में योजना के लक्ष्य का निश्चय जिलों और विकास-खण्डों की योजनाओं को देख कर किया जाएगा—उदाहरणार्थ, कृषि के कार्यक्रमों, सहकारिता के विकास, ग्रामोद्योगों, गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था और ग्रामीण जन शक्ति का पूरा उपयोग करने के लिए शुरू किए जाने वाले कामों का। हम रुपये के कई भागों में प्रसंगवश ऐसे कई क्षेत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिनमें शीघ्र विकास करने के प्रयोजन से वर्तमान लक्ष्यों को ऊँचा करना और उनके लिए नियत व्यय में यथोचित परिवर्तन करना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, खयाल है कि कृषि, ग्रामीण तथा छोटे उद्योगों, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और जन-शक्ति का उपयोग करने के लिए शुरू किए गए खास निर्माण-कार्यों के जो कार्यक्रम और लक्ष्य निश्चित किए जा चुके हैं, उनकी जब राज्य सरकारों और केन्द्रीय मन्त्रालयों-द्वारा परीक्षा की जायगी, तब उनके लिए अतिरिक्त स्वदेशी साधन उपलब्ध करने की आवश्यकता प्रतीत होगी और इसलिए उन्हें आवश्यक साधन दे दिए जायेंगे। जिन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, उनके लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो जाने पर उन्हें आवश्यक स्वदेशी साधन देने का भी पूरा प्रयत्न किया जायगा।

प्रस्तावित व्यय के केन्द्र और राज्यों में विभाजन का पूरा रूप तब ज्ञात होगा, जब राज्यों की योजनाओं पर उनके साथ विचार होगा। परन्तु अपनी योजनाएँ बनाने में राज्यों की सहायता करने के लिए यहाँ व्यय का ग्रंथायी विभाजन प्रस्तुत किया जा रहा है।

केन्द्र और राज्यों में व्यय का विभाजन

(करोड़ रुपये)

	योग	केन्द्र	राज्य
१—कृषि, छोटे सिंचाई-कार्य और सामुदायिक विकास	१,०२५	१७५	८५०
२—बड़े और मध्यम सिंचाई-कार्य	६५०	५	६४५
३—विजली	६२५	१२५	५००

४—ग्रामीण और छोटे उद्योग	२५०	१००	१५०
५—उद्योग और खानें	१,५००	१,४७०	३०
६—परिवहन और संचार	१,४५०	१,२२५	२२५
७—समाज-सेवाएँ	१,२५०	३००	९५०
८—इन्वेष्टरियाँ	२००	२००	—
सर्वयोग	७,२५०	३,६००	३,६५०

यह विभाजन यह मान कर किया गया है कि सामान्य सिद्धान्त यह रहेगा कि जिन विकास-कार्यों की राज्य-सरकारें पूरा करेंगी, वे राज्यों की ही योजनाओं के भाग होंगे, और केवल कुछ प्रकार के कार्य मन्त्रालयों की योजनाओं में केन्द्र-द्वारा प्रवर्तित दिलाए जाएंगे। इस प्रकार, चाहा है कि राज्यों की योजनाओं का क्षेत्र विस्तृत कर राज्यों के विभिन्न कार्यक्रमों को एक साथ मिला कर पूरा किया जा सकेगा।

विदेशी मुद्रा

नीचे की तालिका में दिखलाया गया है कि विकास के विभिन्न कार्यों के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और उनमें से प्रत्येक में कितनी पूँजी लगाने की बात सोची जा रही है। इस तालिका में सरकारी और निजी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को इकट्ठा ही दिखलाया गया है।

विदेशी मुद्रा की आवश्यकता

(करोड़ रुपये)

	पूँजी- विनियोग	विदेशी मुद्रा की आवश्यकता
१—उद्योग और खानें (छोटे उद्योगों को शामिल करके)	२,६३५	१,१६०
२—बिजली	९७५	२७०
३—परिवहन और संचार	१,६५०	३००
४—कृषि, सामुदायिक विकास और सिंचाई	२,११५	७५
५—समाज-सेवाएँ (निर्माण-कार्य शामिल करके)	१,७२५	८०
६—इन्वेष्टरियाँ	८००	—
सर्वयोग	१०,२००	१,६१५

परियोजनाओं का सोपानों में विभाजन

तीसरी योजना के समान विशाल और विस्तृत योजना का विकास करते समय उसकी विभिन्न परियोजनाओं और व्ययों को ठीक-ठीक सोपानों में बाँट लेना निहायत जरूरी है। इसके बिना यह सम्भव नहीं है कि योजना पर जुस्ती से ध्रमल

हों, पूँजी-विनियोग का हर वर्ष मिलने वाले स्वदेशी और विदेशी साधनों के साथ मेल बैठता रहे और इस बात का निश्चय हो कि योजना के हर सोपान में कुछ परियोजनाओं पर अमल हो रहा है और योजना निरन्तर आगे बढ़ रही है और फायदा पहुँचा रही है । परियोजनाओं और कार्यक्रमों को सोपानों में बाँटने का भारी कार्य हल्का करने के लिए निम्नलिखित मोटी कसौटियाँ रखी गई हैं

- १—परियोजनाओं का सोपानों में विभाजन दृढ़ता से योजना की भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार, विशेषकर जन-शक्ति तथा कच्चे माल की उपलब्धि और बिजली तथा परिवहन, आदि सम्बद्ध सेवाओं को देख कर ही करना चाहिए ,
- २—जो परियोजनाएँ हाथ में हो अथवा इसी योजना से बच रही हों, उन्हें पहले और जल्दी पूरा करना चाहिए । ये परियोजनाएँ न्यूनतम आवश्यक समय में पूरी हो जाएँ, इसके लिए वार्षिक योजनाओं में पर्याप्त साधनों की व्यवस्था कर देनी चाहिए ,
- ३—उत्पादन वर्ष-प्रति-वर्ष निरन्तर जारी रहना चाहिए । सोपानों में कार्य-विभाजन ऐसा होना चाहिए कि हर कदम पर पूँजी-विनियोग से अधिकतम लाभ मिलने का निश्चय होता रहे और बिलम्ब से फल देने वाली तथा अपेक्षाकृत घीघ्र फल देने वाली परियोजनाओं में उचित सन्तुलन रहना चाहिए ,
- ४—विभिन्न परियोजनाओं में समस्त अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करते समय इन वस्तुओं की उपलब्धि पहले हो जाने का ध्यान रखना चाहिए
 - (क) कृषि का उत्पादन जल्दी बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तुएँ—जैसे, उर्वरक ,
 - (ख) जिन वस्तुओं के समय पर न मिलने पर सभी काम रुक जाने का भय हो—जैसे, परिवहन, बिजली और कच्ची धातुएँ गलाने का कोयला, आदि,
 - (ग) निर्यात की योजना पूरी करने के लिए आवश्यक वस्तुएँ ;
 - (घ) जो वस्तुएँ अनिवार्य रूप से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम दे सकें—जैसे, मशीन, मिश्रित धातुएँ और पुर्जे बनाने का इस्पात, आदि , और
 - (च) तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रम ।

प्रत्येक क्षेत्र की परियोजनाओं को सोपानों में बाँटने के लिए तो ऊपर लिखी कसौटियाँ सामने रखी ही जाएँगी, परन्तु समस्त योजना की दृष्टि से आवश्यक होगा कि सोपानों के स्वीकृत क्रम को पूरा करने के लिए जिन साधनों की (विदेशी मुद्रा

की भी) आवश्यकता पड़े, वे सब वापिक योजनाएँ बना कर अवश्य पूरे कर दिए जाएँ। इसी प्रकार, इस्पात, सीमेंट और बिजली, आदि मौलिक आवश्यकता की वस्तुओं की प्रति वर्ष जितनी आवश्यकता हो, उतनी मात्रा में उनकी आपूर्ति का प्रयत्न अवश्य कर दिया जाए।

राष्ट्रीय विकास की पंच-वर्ष-व्यापिनी योजना के प्रारम्भ में प्रस्तावित वित्तीय व्यय से योजना का सारा चित्र स्पष्ट नहीं हो सकता—उससे अधिक-से-अधिक एक ऐसे ढाँचे की ही कल्पना हो सकती है, जिसमें रह कर कार्यकर्ताओं के विभिन्न संगठन अपने कार्यक्रम बना लें और उन्हें पूरा करने का निश्चय कर लें। इन कार्यक्रमों के लिए वर्ष-प्रति-वर्ष जो वित्त-राशि दी जाएगी, वह भी अनिवार्यतः काम की प्रगति, कुशलता और सफलता को देख कर ही दी जाएगी। इसलिए मूल समस्या यह रहेगी कि विकास के प्रत्येक क्षेत्र में, दिए हुए व्यय से अधिकतम लाभ किस प्रकार उठाया जाए। प्रत्येक क्षेत्र में इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन लक्ष्यों की पूर्ति अत्यावश्यक है, उन्हें अपेक्षाकृत गौरव लक्ष्यों से प्राथमिकता दे दी जाए। सब क्षेत्रों में मुख्य कसौटी यह रहेगी कि पंचवर्षीय योजना से जो साधन उत्पन्न हो अथवा माँग निकले, उनसे पचाशीघ्र पूरे लाभ प्राप्त होने लें।

बहुत-से विकास-कार्यों को पूरा करते समय सरकारी अनुदान अथवा ऋण उठा सकने के लिए सरकारी सहायता का आश्रय लिया जाता है। जहाँ कहीं ऐसी सरकारी सहायता दी जाए, वहाँ अच्छी तरह देखभाल कर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि कार्य के उद्देश्य की हानि किए बिना सहायता को बन्द अथवा कम किया जा सकता है या नहीं। यह भी देखा गया है कि बहुत-से विकास-कार्य स्थानीय लोगों के सहयोग से अथवा उनसे लाभ उठाने वालों की सहायता से किए जा सकते हैं, परन्तु व्यवहार में इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्तिम बात यह कि प्रत्येक कार्यक्रम और परियोजना के निर्माण मूलक भाग की जाँच योजना बनाने के समय ही वार्षिकी से कर लेनी चाहिए, ताकि निर्माण के काम में ज्यादा-से-ज्यादा किफायत की जा सके।

योजना के लक्ष्य

विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों का रूप अभी अस्थायी है। अभी योजना के निम्न क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ सप्ताह मन्तविरा चल रहा है। उसके पूरा हो जाने पर ही सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों की औद्योगिक योजना का पूरा चित्र सामने आ सकेगा। उद्योगों, खानों और परिवहन तथा संचार की बहुत-सी परियोजनाओं की जिम्मेदारी केन्द्रीय मन्त्रालयों पर है। उनकी सफलता तब होना अभी बाकी है—अभी तो उनके विषय में जाँच और प्रारम्भिक तैयारी का ही काम हो रहा है। राज्य-सरकारों की योजनाओं—

विशेषकर कृषि, छोटे उद्योगों, सड़कों और समाज-सेवाओं सरीखे विभागों—की रूप-रेखाएँ बाद में प्राप्त हो सकेंगी और तब उनमें जिलों की स्थानीय योजनाओं और अन्य अध्ययन के आधार पर संशोधन किए जाएंगे। इन परिस्थितियों में, इस रूपरेखा में निर्दिष्ट भौतिक लक्ष्यों को, तीसरी योजना के लिए किए जाने वाले प्रयत्न की विशालता का सूचकमात्र समझना चाहिए। उन्हें पेश कर देने का बड़ा लाभ यह है कि उससे सारा चित्र सामने आ जाता है और योजना की असंगतियों अथवा निर्बलताओं की ओर ध्यान आकृष्ट हो जाता है।

राष्ट्रीय आय और रोजगार

योजना के विविध भागों के लिए पेश किए गए विकास के लक्ष्यों पर विचार करने से पता चलता है कि राष्ट्रीय आय में ५ प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक वृद्धि हो जाने की सम्भावना है। रोजगार के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि तीसरी योजना के पाँच वर्षों में लगभग १ करोड़ ५० लाख नए थमिक बढ जाएँगे। उनमें से लगभग १ करोड़ ५ लाख कृषि-भिन्न रोजगारों में और ३५ लाख कृषि में खप सकेंगे।

सन्तुलन और लचीलापन

इस योजना का ढाँचा तैयार करते समय ऐसा प्रयत्न किया गया है कि देश की अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक भाग में उचित सन्तुलन बना रहे। उदाहरणार्थ, इस्पात, कोयला, बिजली और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता का अन्दाजा एहतियात के साथ लगा कर, योजना में उसे पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। इसी प्रकार, रेलों की योजना बनते समय, विभिन्न विकास कार्यों के कारण ट्रंकिंग में जितनी वृद्धि हो जाने की सम्भावना है, उसका खयाल रखा गया है। जब योजना का काम वर्तमान प्रारम्भिक अन्दाजों से आगे बढ जाएगा और परियोजनाओं के सौपानों और विभिन्न प्रदेशों की आवश्यकताओं तथा साधनों पर विचार किया जाएगा, तब न केवल प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों, अपितु उनके लिए रखे गए वित्तीय व्यय में भी, अन्वय परिवर्तन करना पड़ेगा।

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, कई क्षेत्रों में कार्यक्रमों के सौपान निर्दिष्ट करते समय एक बड़ा खयाल यह रखना पड़ता है कि विदेशी मुद्रा कितनी मिल सकती है। चूँकि इस सम्बन्ध में स्थिति काफी समय के बाद ही स्पष्ट होगी, इसलिए इस समय ऐसा उचित समझा गया है कि जिन परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें योजना में शामिल करने का निश्चय करते समय उद्धार रक्षित रखी जाए। इसीलिए, औद्योगिक परियोजनाओं को निम्नलिखित पाँच वर्गों में बाँट दिया गया है

- (१) वे परियोजनाएँ, जिन्हें वार्यान्वित किया जा रहा है और जो दूसरी योजना में शुरू की गई थी।

- (२) वे नई योजनाएँ, जिनके लिए विदेशी सहायता मिलने का निश्चय हो चुका है।
- (३) वे नई परियोजनाएँ, जिन्हें इस समय योजना में सम्मिलित माना जा सकता है। इनमें से अधिकतर की तैयारी काफी आगे तक हो चुकी है, परन्तु उनके लिए अभी विदेशी मुद्रा की व्यवस्था नहीं हुई।
- (४) वे नई परियोजनाएँ, जिनकी तैयारी का काम अभी बहुत आगे तक नहीं पहुँचा और जिनके लिए अभी विदेशी मुद्रा का प्रवण्य भी नहीं हुआ। इन्हें योजना में शामिल करने का पक्का निश्चय अभी नहीं किया गया, परन्तु इनकी तफ्तील पूरी करके, इन्हें योजना में शामिल करने के बारे में पीछे विचार किया जाएगा।
- (५) वे परियोजनाएँ, जो कुछ उलझी हुई हैं और जिनकी पूर्ति कुछ ऐसी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जो इस समय पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं।

इनके अतिरिक्त भी अन्य कुछ लक्ष्य इसके निर्माण में अपनाये गये हैं। किन्तु सभी के विषय में विचार रूप से वर्णन करना इस स्थान पर सम्भव नहीं है।

कृषि और सिंचाई

कृषि का उत्पादन तीसरी योजना में ३० से ३३ प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा, परन्तु यह उन लक्ष्यों पर निर्भर करेगा, जो क्षेत्रीय कृषि-योजनाओं का विवरण देते लेने के बाद निर्दिष्ट किए जाएंगे।

कुछ महत्वपूर्ण कृषि-वस्तुओं के अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य निम्नलिखित हैं।

कृषि-वस्तुओं के अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य

वस्तु	अतिरिक्त उत्पादन	वृद्धि का प्रतिशत
खाद्यान्न (करोड़ टन)	२.५ से ३	३३-४०
तिलहन (लाख टन)	२० से २३ तक	२८-३२
गन्ना (गुड़ के रूप में लाख टन)	१८ से २० तक	२५-२८
कपास (लाख गांठें)	१८	३३
पटसन (लाख गांठें)	१०	१८

इसके अतिरिक्त, फल, सब्जी, दूध, मछली, मांस और अण्डे सरीसृप खाद्य-पदार्थों और नारियल, सुपारी, काजू, बाली मिर्च, छोटी इलायची, तम्बाकू, लाख और इमारती लकड़ी-जैसी अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे।

खाद्यानो के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है, उससे प्रत्येक व्यक्ति को प्रति दिन लगभग साढ़े सात छटाक अनाज और डेढ़ छटाक दाल खाने को मिलने के बाद, सकट के समय के लिए कुछ बच भी जाएगा। आशा है कि कपास का लक्ष्य पूरा हो जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष १७ ५ गज सूती कपड़ा मिल जाने के बाद निर्यात के लिए भी कुछ बच जाएगा।

कृषि का विकास करने के लिए जो विविध कार्यक्रम रखे गए हैं, उनमें बड़े तथा छोटे सिंचाई कार्यों से २ करोड़ एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचाई का लाभ पहुँचाने लगेगा। यह अ-दाजा इस बात की ग्युं जायस रखकर लगाया गया है कि कुछ पुराने सिंचाई-कार्य अंशतः या पूर्णतः बन्द हो जाएँगे या इसी तरह के कुछ और बिचन पड़ जाएँगे। इसे मिलाकर, तीसरी योजना के अन्त तक सिंचाई का कुल क्षेत्रफल ६ करोड़ एकड़ हो जाएगा। लगभग ४ करोड़ एकड़ में बिना सिंचाई के खेती करने की विधियों का प्रयोग किया जाएगा। भूमि-रक्षा के उपायों का विस्तार और भी एक करोड़ ३० लाख एकड़ भूमि में कर दिया जाएगा। नम्रजन के हिसाब से नम्रजनयुक्त उर्वरकों की खपत बढ़ा कर १० लाख टन और फास्फेटवाले उर्वरकों की खपत ४ से ५ लाख टन तक कर दी जाएगी। ५ करोड़ एकड़ अतिरिक्त भूमि में हरी खाद से खेती की जाएगी और ७ करोड़ ५० लाख एकड़ क्षेत्र में पौधों की रक्षा के उपायों का विस्तार किया जाएगा।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विस्तार अक्टूबर १९६३ तक देश के सभी गावों में कर दिया जाएगा। सहकारिता-विकास के कार्यक्रम को नवम्बर १९५८ में राष्ट्रीय विकास-परिषद् द्वारा निर्दिष्ट दिशा में अधिक तीव्र कर दिया जाएगा और कृषि के विकास में सहकारी संस्थाओं द्वारा दी हुई वित्तीय सहायता बड़ा काम करने लगेगी।

उद्योग और बिजली

औद्योगिक क्षेत्र में खास जोर उन उद्योगों के विकास पर दिया जाएगा, जिनसे अर्थ-व्यवस्था के स्वावलम्बी बनने में सहायता मिलती है, अर्थात् इस्पात, यन्त्र निर्माण और उत्पादक-सामग्रियों का उत्पादन। उपभोक्ता पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी आवश्यक उपाय किए जाते रहेंगे।

लोहे और इस्पात का विकास इस्पात की सिल्लियों के १ करोड़ २ लाख टन और विक्री के लिए कच्चे लोहे के १५ लाख टन के लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। आशा है कि इस क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन और क्षमता की पूर्ति अधिकतर सरकारी क्षेत्र में ही हो जाएगी। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात-कारखानों का और विस्तार करने की बात सोची जा रही है, और ये मिलकर इस्पात की ५५ लाख

टन सिल्लियाँ तैयार कर सकेंगे। सरकारी क्षेत्र में लोहे का चौथा कारखाना बोकारो में स्थापित किया जाएगा। आशा है कि इस्पात की २ लाख टन सिल्लियाँ लोहे की कठारन गलाने वाली बिजली की भट्टियों से और २ लाख टन कच्चा लोहा छोटी घमन-भट्टियों से भी मिल सकेगा। ये सब भट्टियाँ योजना के निजी क्षेत्र में खोलने का विचार है। २ लाख टन मिथ धातुएँ और पुर्जे बनाने का खास इस्पात तैयार करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे।

मशीनों और इंजीनियरी उद्योगों की तीसरी योजना की अवधि में महत्वपूर्ण उन्नति होगी। इस विभाग के लिए दिए हुए सुझावों में ये परियोजनाएँ भी शामिल हैं—भारी मशीनें बनाने का कारखाना, डलाई का कारखाना, कोयला-बातों की मशीनें बनाने का कारखाना, भारी इमारती सामान बनाने का कारखाना, धातु की भारी चार्ज और जहाज बनाने का कारखाना, मशीनों के भारी औजार बनाने का कारखाना, बगलौर के 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' कारखाने का उत्पादन दुगुना करना, भोपाल के बिजली का भारी सामान बनाने वाले कारखाने का विस्तार, बिजली का भारी सामान बनाने के दो नए कारखाने और भारी दवाब वाले वायुमय और द्रव्य बनाने के कारखाने खोलना।

आशा है कि योजना के निजी क्षेत्र में भी मशीनें बनाने के कुछ कार्यक्रम पूरे किए जा सकेंगे और वे सरकारी क्षेत्र के इन कामों के पूरक साबित होंगे। कपड़ा, चीनी, सीमेंट, कागज, आदि कुछ उद्योगों के कारखानों में १९६५-६६ तक मशीनों की जितनी माँग होने की सम्भावना है, उसके आधार पर ऐसे कार्यक्रम बना लिए गए हैं कि इन उद्योगों के लिए कारखानों के पूरे यंत्र विदेशों से मगाने की आवश्यकता काफी घट जाए। दूसरी योजना के अन्त में तंत्रजन के हिसाब से तंत्रजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन २,१०,००० टन रहेगा, जिसे बढ़ाकर तीसरी योजना के अन्त तक १० लाख टन कर दिया जाएगा। फास्फेटवाले उर्वरकों का उत्पादन भी काफी बढ़ा देने का विचार है। दूसरी योजना में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य ६ करोड़ ७० लाख टन अतिरिक्त कोयले का उत्पादन करके, उसका परिमाण ६ करोड़ ७० लाख टन तक पहुँचा देने का विचार है।

अब तक जितना तेल भूगर्भ में विद्यमान होने का निश्चय हो चुका है उसके आधार पर आया है कि नहरकटिया के इलाके में प्रतिवर्ष २७.५ लाख टन कच्चा तेल निकलेगा। नहरकटिया का यह कच्चा तेल साफ करने के लिए नूनमती और बरौनी में तेल साफ करने के कारखाने पूरे करने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, जिन सम्भान, आदि जिन इलाकों में तेल निकलने के लक्षण अनुकूल जान पड़ते हैं, वहाँ अतिरिक्त कच्चा तेल खोजने की भी व्यवस्था की गई है।

अब तक जो अन्य लक्ष्य प्रस्तावित हुए हैं, उनमें से कुछ ये हैं।

कतिपय महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य

	वार्षिक उत्पादन	
	१९६०-६१	१९६५-६६
अल्युमीनियम (हजार टन)	१७	७५
सीमेण्ट (लाख टन)	८८	१३०
कागज (हजार टन)	३२०	७००
गन्धक का तैजाव (हजार टन)	४००	१,२५०
कास्टिक सोडा (हजार टन)	१२५	३४०
चीनी (लाख टन)	२२५	३०
मिल के सूती वस्त्र (करोड़ गज)	५००	५८०
वाइसिकिलें (संगठित कारखानों में निर्मित) (हजार)	१,०५०	२,०००
सिलाई की मशीनें (हजार)	३००	४५०
मोटोराडिया	५३,५००	१,००,०००

दूसरी योजना के अन्त तक बिजली की उत्पादन क्षमता ५८ लाख किलोवाट हो जाने की सम्भावना है। तीसरी योजना के अन्त तक बढ़ा कर १ करोड़ १८ लाख किलोवाट कर देने का विचार है। बिजली के कार्यक्रम में परमाणु-शक्ति-द्वारा भी ३ लाख किलोवाट बिजली तैयार करने की परियोजना शामिल है। आशा है कि तीसरी योजना के समय १५ हजार और कस्बों तथा गांवों से बिजली पहुँचाई जा सकेगी। तब, इस प्रकार के कस्बों और गांवों की संख्या ३४ हजार हो जाएगी।

राज्य-सरकारों और छोटे उद्योगों के अखिल भारतीय बड़े छोटे उद्योगों के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, और उनमें औद्योगिक वस्तियों की स्थापना, खादी (अम्बर-खादी शामिल करके) तथा ग्राम उद्योगों हथकरघो, हस्तकिल्पो, रेशम और नारियल के रेशों के कार्यक्रम भी शामिल हैं। मोटे तौर पर, उद्देश्य यह है कि निजी और सहकारी संस्थाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी, कर्ज और कच्चे माल, आदि की सुविधाएँ देकर उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अस्याई रूप से लक्ष्य यह रखा गया है कि विकेन्द्रित क्षेत्र का, अर्थात् हाथ तथा बिजली के करघों के कपड़े और खादी का उत्पादन १९६०-६१ के २६१ करोड़ गज के लक्ष्य से बढ़ाकर १९६५-६६ में ३५० करोड़ गज और रेशम का ३७ लाख पौण्ड से बढ़ाकर ५० लाख पौण्ड कर दिया जाए। औद्योगिक वस्तियों की संख्या दूसरी योजना में ६० थी, जो तीसरी योजना के अन्त तक ३६० कर दी जाएगी। छोटे उद्योगों के कार्यक्रमों में जोर इस बात पर दिया जाएगा कि उनका विकास छोटे कस्बों और गांवों में हो और उनका सहायक उद्योगों के रूप में, बड़े

उद्योगों के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध जोड़ दिया जाय। दम्नशिल्पों और नारियल के रेशों से बनी चीजों के कार्यक्रम विशेष रूप से इस तरह रखे जाएंगे कि उनके माल अधिक बटिया बनें और विदेशों को निर्यात किए जा सकें।

परिवहन और संचार

आशा है कि तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में रेलों लगभग २३ करोड़ ५० लाख टन तक माल ढोने-योग्य हो जाएंगी। इनकी तुलना में, वे १९६० में १६ करोड़ २० लाख टन तक ही पहुँच पाएंगी। इसी अवधि में, १,२०० मील लम्बी नई रेल-लाइनें बिछाई जाएंगी। १९६०-६१ के अग्न तक, आशा है कि, पक्की सड़कों की लम्बाई १,४४,००० मील हो चुकेगी। तीसरी योजना के समय इनमें २०,००० मील सड़कों की और वृद्धि कर दी जाएगी। सड़कों पर माल की दुलाई का विस्तार प्रायः निजी क्षेत्र के हो जिम्मे रहेंगा। माल ढोनेवाली गाड़ियों के सम्बन्ध में मोटा अन्दाजा यह है कि तीसरी योजना की अवधि में उनकी संख्या २ लाख से बढ़कर ३ लाख हो जाएगी। पानी के जहाजों का बजट तीसरी योजना के अन्त में ६ लाख ग्रीन रजिस्टर्ड टन होने की आशा है। इस समय उसमें २ लाख रजिस्टर्ड टन की वृद्धि कर देने का विचार किया जा रहा है, परन्तु इस संकल्प को प्रत्यक्ष माना जा रहा है और इस पर और अधिक विचार किया जाएगा।

समाज-सेवाएँ

हाल के वर्षों में समाज-सेवा की दिशा में किन्ती प्रगति हुई है, इसका पता इस बात से लग सकता है कि समाज-सेवाओं के लिए अधिक साधनों की माग होने लगी है और लोग उनसे अधिक आनाएँ करने लगे हैं। तीसरी योजना में, समाज-सेवा के कई कार्यों में बड़ी प्रगति हो जाने की आशा है। ६ से ११ वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर देने का विचार है। कई पिछड़े हुए इलाकों में लड़कियों की शिक्षा में प्रगति मन्द होगी, यह खयाल करके अन्दाजा लगाया गया है कि ६ से ११ वर्ष तक की आयु के सब बच्चों में पढ़नेवाले बच्चों का अनुपात ६० प्रतिशत से बढ़कर ८० प्रतिशत, ११ से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों में २३ प्रतिशत से बढ़कर ३० प्रतिशत और १४ से १७ वर्ष तक की आयु के बच्चों में १२ प्रतिशत से बढ़कर ११ प्रतिशत हो जाएगा। १९६०-६१ में विद्यालयों के सब बच्चों की संख्या ४ करोड़ १० लाख होगी, जो १९६१-६६ में बढ़कर ६ करोड़ ५० लाख हो जाएगी।

वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की ओर अधिक सहायता दी जाएगी। आशा है कि कालेजों में विज्ञान के विषय लेनेवाले विद्यार्थियों की संख्या सब विद्यार्थियों के ३० प्रतिशत से बढ़ कर ४० प्रतिशत हो जाएगी। दूसरी योजना के अन्त में इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटैक्नीकों की क्षमता ३७,००० विद्यार्थियों को प्रविष्ट कर सकने की होगी। तीसरी योजना के अन्त तक उनकी यह क्षमता बढ़ कर

५२,५०० विद्यार्थियों को ले सकने की हो जाएगी। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और इंजीनियरी संस्थाओं को तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आशिक समय लगाकर और पत्र व्यवहार द्वारा पढाई कर सकने की भी विशेष व्यवस्था की जाएगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में रजिस्टर्ड डाक्टरों की संख्या ८४,००० से बढ़ा कर १,०३,२००, अस्पतालों में रोगी शय्याओं की संख्या १,६०,००० से बढ़ाकर १,६०,०००, और अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या १२,६०० से बढ़ा कर १४,६०० कर देने का विचार है। प्रारम्भिक स्वास्थ्य-केन्द्रों की संख्या २,८०० से बढ़ा कर ५,००० कर दी जाएगी। परिवार नियोजन के कार्यक्रम को बहुत अधिक प्राथमिकता दी जाएगी और विलनिको की संख्या १,८०० से बढ़ाकर ८,२०० कर दी जाएगी। कम आमदनी वाले लोगों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए घर बनाने, गन्दी बस्तियाँ साफ करने और सुधारने और घर बनाने के लिए जमीन लेकर उसे सुधारने के कार्यक्रमों का भी विस्तार किया जाएगा। घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता आवास वित्त-निगमों की मार्फत दी जाएगी।

तीसरी योजना में एक कार्यक्रम स्थानीय विकास-कार्यों का भी सम्मिलित किया जाएगा, ताकि गावों के निवासी भी कुछ न्यूनतम सुविधाओं का लाभ उठा सकें। ये सुविधाएँ हैं—(१) पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना, (२) प्रत्येक गाव का सड़क द्वारा समीप की मुख्य सड़क से अथवा समीप के रेलवे स्टेशन से सम्बन्ध जोड़ देना, और (३) गाव के विद्यालय भवन का निर्माण। यह भवन गाव की चौपाल या गाव के पुस्तकालय का भी काम दे सकेगा।

तीसरी योजना के इस समय सोचे हुए सद्य हमारी धर्म व्यवस्था, को स्वचालित प्रगति के मार्ग पर काफी आगे बढ़ा देंगे। इस बात के लिए भी आधार तैयार किया जाएगा कि चौथी योजना में इस प्रगति को और भी अधिक तेज किया जा सके, परन्तु पहले ही बहुत बड़ी मात्रा में जो पूँजी सगई जा चुकी है, उसका विचार करते हुए यह आवश्यक है कि उससे जो उपलब्धियाँ हों, उनसे अधिकतम लाभ उठा लिया जाए। स्वयं विकास की प्रक्रिया भी उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के नए अवसर उपस्थित करेगी। बस, प्रयत्न यह रहना चाहिए कि जन शक्ति का यथासम्भव पूरा उपयोग करके और जनता की बचत को एकत्र करके इन अवसरों से लाभ उठाया जाए।

२—योजना के लिये साधन^१ (Resources for the Plan)

सरकारी क्षेत्र में वित्त-व्यवस्था की योजना

तीसरी योजना के सरकारी क्षेत्र में अब तक के अध्ययन के फलस्वरूप प्रस्तावित व्यय की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में जो योजना तैयार की गई है, वह नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जाती है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, दूसरी योजना में जिस-जिस मूल खर्च जितना-कुछ मिलने की आशा है, उसे भी, तुलनात्मक अध्ययन के लिए, साथ में दे दिया गया है।

वित्तीय साधन

	(करोड़ रुपये)	
	दूसरी योजना	तीसरी योजना
१—करो की वर्तमान दरों के आधार पर, राजस्व से बची हुई राशि	१००	३५०
२—वर्तमान आधार पर, रेतों से प्राप्त मांग	१५० ^३	१५०
३—वर्तमान आधार पर, अन्य सरकारी उद्योग-व्यवसायों से होने वाली बचत	३	४४०
४—जनता से लिए हुए ऋण	८००	८५०
५—छोटी बचतें	३८०	५५०
६—प्रिविडेण्ट-फण्ड, मुसाहाली कर, इस्पात-समीकरण-कोश और पूँजी खाते में जमा विविध रकमें	२१३	५१०
७—नए कर, जिनमें सरकारी उद्योग-व्यवसायों में अधिक बचत करने के लिए किए जाने वाले उपलब्ध शामिल हैं	१०००	१,६५०
८—विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखाई गई रकमें	६८२	२,२००
९—घाटे की ग्रन्थ-व्यवस्था	१,१७५	५५०
योग	४,६००	७,२५०

ऊपर जो अनुमान दिए गए हैं, उनकी सख्त व्याख्या नीचे पैराग्राफों में की गई है।

राजस्व से बची हुई राशि : राजस्वगत आय और व्यय के वर्तमान अनुमानों के अनुसार तीसरी योजना की अवधि में, योजना के लिए राजस्व से ३५० करोड़

१. तृतीय पंच वर्षीय योजना, रूपरेखा, अध्याय ४
२. इसमें बढ़ाए हुए किराए और सादे भी शामिल हैं।
३. इस तालिका की प्रिविडेण्ट-मर्यादा २ में शामिल है।

रुपये की राशि बचती है। यह अनुमान लगाते समय इस बात का भी खयाल रखा गया है कि तीसरी योजना की अवधि में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ जाएगा और कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि की प्रवृत्ति रहेगी। व्यय का हिमाव्र लगाते समय आगामी वर्षों में भी पुराने ही रख जारी रहने की कल्पना की गई है और दूसरी योजना के अन्त तक जो कार्यक्रम पूरे हो चुकेंगे, उनके निर्वाह-व्यय का भी हिसाब सगा लिया गया है।

रेलों से प्राप्त भाग : यह राशि, रेलों की सम्भावित चालू आय में से, उनके प्रबन्ध का व्यय (व्यय में बननी हुई लाइनों का खर्च नहीं गिना गया, क्योंकि उसे विनियोग माना जाता है) ६५ ७० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से उनकी घिसाई और लाभांश घटा कर निकाली गई है।

ग्रन्थ सरकारी उद्योग व्यवसायों से होने वाली बचत : केन्द्रीय सरकार के उद्योग-व्यवसायों (लोहे तथा इस्पात, सर्वरक, तेल निकालने तथा साफ करने और डाक-तार, आदि) से ३०० करोड़ रुपये और राज्य-सरकारों के उद्योग-व्यवसायों (बिजली-बोर्डों, परिवहन-संस्थाओं, आदि) से १४० करोड़ रुपये बचने का अनुमान है। यह अनुमान लगाते समय इन सरकारी उद्योग-व्यवसायों के प्रबन्ध और घिसाई, आदि का व्यय निकाल दिया गया है। चूँकि ये अनुमान मोटे तौर पर स्वीकृत मान्यताओं के आधार पर लगाए गए हैं, इसलिए इन्हे मोटे ढंग का ही मानना पड़ेगा। योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व, केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य-सरकारों के साथ अधिक विस्तृत रूप में विचार-विनिमय किया जायगा।

जनता में लिए हुए धन - दूसरी योजना में इस सूत्र से ८०० करोड़ रु० मिलने का अनुमान है। परन्तु इसमें अमेरिका के पी० एल० ४८० के कोष की रकम से स्टेट बैंक-द्वारा की जानेवाली सरकारी सिक्कुरिटियों की खरीद भी शामिल है। तीसरी योजना में, सभी विदेशी सहायताओं की राशि—पी० एल० ४८० की राशि भी—विदेशी सहायता के रूप में वजत में दिखाई गई रकमों में शामिल कर ली गई हैं। फिर भी, तीसरी योजना में इस मद से ८५० करोड़ रुपये मिलने का जो अनुमान लगाया गया है, उसके पीछे यह मान्यता है कि जीवन-बीमा-निगम और विविध प्राविडेण्ट फण्ड सरकार को पहले की अपेक्षा अधिक धन देंगे। इस राशि में इनामी बीण्डों की सम्भावित आमदनी भी शामिल है।

छोटी बचतें दूसरी योजना में इस सूत्र से जितनी राशि एकत्र हुई थी, उसकी तुलना में प्रति वर्ष औसतन ११० करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान बेशक ऊँचा है, परन्तु यह एक ऐसा सूत्र है, जिसका विकास परिश्रम पूर्वक किया जाना चाहिये।

प्राविडेण्ट फण्ड, खुशहाली कर आदि इस मद में २३० करोड़ रुपये तो प्राविडेण्ट-फण्डों में अधिक जमा होने का अनुमान है, और ७५ करोड़ रुपये खुशहाली करों से, १६० करोड़ रुपये इस्पात-समीकरण-कोष से तथा ४५ करोड़ रुपये ग्रन्थ विविध पूँजी-खातों से मिलेंगे।

विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखाई गई रकमे . जैसा कि इसी अध्याय में आगे चल कर तीसरी योजना की अवधि में भुगतान-सन्तुलन-विषयक विचार-विमर्श के क्रम में स्पष्ट होगा, इस योजना के लिये कुल ३,२०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी । इसमें से ४५०-५०० करोड़ रुपये तो तीसरी योजना की अवधि में भुगताई जाने वाली विदेशी देनदारियाँ हैं । लगभग ३०० करोड़ रुपये योजना के निजी क्षेत्र में चले जायेंगे । इसमें विदेशी पूँजीपतियों द्वारा लगाई हुई निजी पूँजी और विश्व-बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम तथा अमेरिका के आयात निर्यात बैंक से प्राप्त ऋण भी शामिल है । अन्तिम बात यह, कि अमेरिका के साथ हाल में पी० एल० ४८० के अन्तर्भूत हुए समझौते के अनुसार प्राप्त होने वाली लगभग ६०८ करोड़ रुपये की समस्त सहायता में से लगभग दो सौ करोड़ रुपये उस सकटकालीन अन्न-नोप (४० लाख टन गेहूँ और १० लाख टन चावल) में लग जायेंगे, जिससे भूख विषयक साधन उपलब्ध नहीं होंगे । इस प्रकार, विदेशों से प्राप्त समस्त ३,२०० करोड़ रुपये में से—यह मान कर कि इतनी राशि मिल ही जाएगी उपर्युक्त तीन रकमे घटानी होगी, जिनका योग लगभग १,००० करोड़ रुपया होता है । फलतः शेष २,२०० करोड़ रुपये की गणना सरकारी क्षेत्र के बजट-साधनों में की जा सकेगी ।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था : जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तीसरी योजना में घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गुंजायश बहुत कम है । घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सुरक्षित परिमाण तय करने की कोई निश्चित विधि नहीं है । इस प्रसंग में, प्रचलित मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने के दोनो तरीको—बजट के माध्यम से और बैंको द्वारा ऋण ग्रहण—पर एक साथ विचार करना उचित है । उत्पादन में वृद्धि के रुख का खयाल करके ऐसा सोचा जा सकता है, कि तीसरी योजना में नोटों का चलन ३३ प्रतिशत तक बढ़ जाने पर भी मूल्यों पर कोई विशेष दबाव नहीं पड़ेगा । यदि यह मानकर चलें, कि तीसरी योजना की अवधि में अतिरिक्त मुद्रा का चलन और माल का अतिरिक्त उत्पादन, दोनों में सन्तुलन स्थापित रहेगा, तो दूसरी योजना के अन्त में प्रचलित मुद्रा के समस्त परिमाण के आधार पर तीसरी योजना की अवधि में मुद्रा के चलन में ६५० करोड़ रुपये तक की वृद्धि की जा सकेगी । मुद्रा के चलन में कुछ वृद्धि बैंक प्रणाली द्वारा होगी । यदि उसे पृथक् कर दें, तो तीसरी योजना की अवधि में बजटों में ५५० करोड़ रुपये तक की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गुंजायश है । परन्तु यहाँ इस बात पर जोर दिया जाना आवश्यक है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी निर्णय समय-समय पर आर्थिक परिस्थितियों की जाच करके हो किया जाना चाहिये । यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई—विशेषकर कृषि के क्षेत्र में—और मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों पर कहा तक काबू पाया गया ।

प्रतिरिक्त कराधान

योजना के पांच वर्षों में प्रतिरिक्त कर लगाने का लक्ष्य १,६५० करोड़ रु० रखा गया है और योजना की सफलता के लिए इसकी पूर्ति अत्यावश्यक है। इस समय भारत में सरकार को करो द्वारा राष्ट्रीय आय के लगभग ८५ प्रतिशत भाग की आमदनी होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कारण करो की आमदनी में होने वाली स्वाभाविक वृद्धि और तीसरी योजना की अवधि में लगाए जानेवाले प्रतिरिक्त करो के द्वारा, यह अनुपात ११ प्रतिशत तक हो जायगा। सरकार के विकास-कार्यों की द्रुत प्रगति को देखते हुए करो के भार में इतनी वृद्धि बहुत अधिक नहीं मानी जा सकती। फिर भी, १,६५० करोड़ रुपये के प्रतिरिक्त कर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केन्द्रीय और राज्य-सरकारों को विशेष प्रयत्न करना होगा और अपने करो के ढाँचे को विस्तृत करना पड़ेगा। अब तक लगाए गए अनुमानों के अनुसार, राज्यों को प्रतिरिक्त कर का अपना लक्ष्य उपर्युक्त राशि का कम-से-कम एक तिहाई भाग निश्चित करना पड़ेगा।

यह स्पष्ट है कि किसी विशेष अवधि में कर लगाने की सीमा का निश्चय, केवल पूँजी विनियोग की आवश्यकता और विकास के अन्य व्ययों के आधार पर नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, यह योजना जितनी बड़ी बनाई जा रही है, उसे देखते हुए कर लगाने का पर्याप्त प्रयत्न किए बिना उसे पूरा भी नहीं किया जा सकता। इस समस्या के दोनों ही पहलुओं को, अर्थात् आवश्यकता और व्यावहारिक सम्भावनाओं को, एक साथ अपनी नजर में रखना होगा। इस प्रसंग में, कर लगाने के आर्थिक तथा अन्य पक्षों पर विचार करना और उनमें सतुलन स्थापित करना भी आवश्यक है। राष्ट्रीय आय में, और विशेषकर खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में, सम्भावित वृद्धि को देखते हुए, १,६५० करोड़ रुपये के प्रतिरिक्त कर लगाने का लक्ष्य व्यवहार की सीमा के भीतर ही प्रतीत होता है। और, यह देखते हुए, कि अन्य सभी वित्तीय सूत्रों का पूरा पूरा लाभ उठाया जाएगा यह लक्ष्य न्यूनतम आवश्यकता का भी सूचक है।

कर-सम्बन्धी विस्तृत विवरण का निश्चय उस समय की आर्थिक परिस्थिति को देख कर करना पड़ेगा। फिर भी, इतना स्पष्ट है कि तीसरी योजना की पूर्ति के लिए, सरकारी उद्योग-व्यवसायों में अधिक बचत करने के उपायों के प्रतिरिक्त, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों ही प्रकार के कर बढ़ाने पड़ेंगे।

जहाँ तक आय कर और निगम-कर का सम्बन्ध है, उनको आय बढ़ाने के लिए मुख्यतः कर-प्रशासन को अधिक चतुर बनाना होगा, कम्पनियों के व्यय खातों पर निगरानी रखनी होगी और कर की अदायगी से बच निकलने के प्रयत्नों को रोकथाम करनी होगी। यह ठीक है कि अप्रत्यक्ष कर लगाने और सरकारी उद्योग-व्यवसायों में तैयार हुए माल का मूल्य बढ़ाने से मूल्यों और लागत, दोनों में वृद्धि

होने लगती है, परन्तु ये सब उस बलिदान के अंग हैं, जो कि पूर्णतः स्पष्ट और आवश्यक हैं ।

यहां मूल्यों पर अप्रत्यक्ष करो और घाटे की अर्थ-व्यवस्था के तुलनात्मक प्रभाव के विषय में भी दो शब्द कह देना उचित है । इन दोनों प्रभावों में मुख्य अन्तर यह है कि घाटे की अर्थ व्यवस्था का प्रभाव तो बाजार पर कुछ उटपटाग ढंग में और मुहृद रूप में पड़ता है, परन्तु अप्रत्यक्ष करो के परिणामस्वरूप लोगों की फालतू क्रय-शक्ति विभट जाती है । अप्रत्यक्ष कर मूल्य बढ़ा कर मुद्रास्फीति की क्षमता को कम कर देते हैं और घाटे की अर्थ-व्यवस्था उसे और बढ़ा देती है । कुछ परिस्थितियों में, अप्रत्यक्ष कर उन अनुचित लाभ का प्रवाह सरकारी खजाने की ओर मोड़ देते हैं, जो सामान्यतः बिचौलियों और व्यापारियों की तिजोरियों में जाकर जमा हो जाता ।

विकास में सलग्न अर्थ-व्यवस्था में, कराधान एक महत्वपूर्ण कार्य यह करता है कि उपभोग की मात्रा को पूँजी-विनियोग-द्वारा विभक्तित सीमा के भीतर ही रोक रखता है । प्रत्यक्ष कर, इसी परिणाम को व्यय हो सकने योग्य भाग घटाकर प्राप्त करता है । अप्रत्यक्ष कर उस भाग की मात्रा घटा देता है, जो व्यय होने वाली भाग द्वारा खरीदा जा सकता है । वही-सा कर कितना लगाया जाए, इसका निश्चय सामने विद्यमान परिस्थिति पर विचार करके ही किया जाना चाहिए । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों के प्रभाव बहुधा अस्पष्ट होते हैं, इसलिए कर लगाने का निश्चय करते समय सावधानी पूर्वक यह देखा जाना चाहिए कि अर्थ-व्यवस्था पर बहुत अधिक तनाव तो नहीं पड़ता और खिचाव भयाहित दिशा में तो नहीं हो रहा । यहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि पर्याप्त कराधान न होने की अवस्था में दो ही विकल्प बचते हैं—(१) धीमी गति से विकास और (२) ऐसी स्थिति का निर्माण, जिसमें बड़ी हुई क्रय-शक्ति वस्तुओं और सेवाओं की सीमित प्राप्यक्षमता पर दबाव डालती है । कराधान उन क्षेत्रों में से एक है, जिसमें अभी किए गए बलिदान आगे चल कर मिलन वाले लाभ की तुलना में अधिक भारी मालूम पड़ते हैं । फिर भी, इतना स्पष्ट है कि विकास की प्रक्रिया से जनता के सभी वर्ग लाभान्वित होते हैं । विकास लोगों के लिए, उपर्युक्त अतिरिक्त कराधान के बावजूद, उपभोग की मात्रा बढ़ावा सम्भव होया । इस तरह, यह बलिदान सापेक्ष है, संपूर्ण नहीं । सरकारी खजाने में पूँजी-विनियोग की वृद्धि की अवस्था में जनता द्वारा अधिक बचत और सरकारी उद्योग व्यवसायों की अधिक बचत के साथ-साथ कराधान किसी विकास योजना के महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं ।

निजी क्षेत्र का पूँजी-विनियोग

योजना के निजी क्षेत्र में पूँजी-विनियोग का सम्बन्ध न केवल संगठित उद्योगों, खानों, बिजली और परिवहन से, बल्कि कृषि, ग्राम तथा लघु उद्योगों,

शहरी तथा ग्रामीण आवास, आदि से भी है। उपलब्ध सध्यों के आधार पर इस सारे क्षेत्र के लिए पूंजी-विनियोग की कोई सार्यक योजना प्रस्तुत कर सकना सम्भव नहीं है। हा, गत वर्षों की प्रवृत्तियों के साथ तुलना करके इस बात का थोडा-बहुत निश्चय अवश्य किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में जितनी पूंजी लगाने की बात कही गई है, वह कहाँ तक व्यावहारिक होगी। नीचे की तालिका में दिखलाया गया है कि दूसरी योजना के आरम्भ में लगाए गए अनुमानों और रिजर्व बैंक-द्वारा हाल में किए गए अध्ययन के आधार पर संशोधित अनुमानों के साथ तुलना करने पर, तीसरी योजना में निजी क्षेत्र की प्रमुख मदों में कितना पूंजी-विनियोग हो सकता है।

योजना के निजी क्षेत्र का पूंजी-विनियोग

(करोड रुपये)

	दूसरी योजना		तीसरी योजना
	प्रारम्भिक अनुमान	संशोधित अनुमान	अनुमान ¹
१. कृषि (सिंचाई-सहित)	२७५	६७५	८५०
२. बिजली	४०	४०	५०
३. परिवहन	८५	१३५	२००
४. ग्रामीण और लघु उद्योग	१००	२२५	३२५
५. बड़े और मध्यम उद्योग तथा खनिज पदार्थ	५७५	७०० ^२	१,०५० ^२
६. आवास और अन्य इमारती काम	६२४	१,०००	१,१२५
७. इन्वेण्टरिया	४००	५२५	६००
योग	२,४००	३,३००	४,२००

इससे प्रकट होता है कि दूसरी योजना के संशोधित निजी पूंजी विनियोग की तुलना में, तीसरी योजना में कहीं अधिक पूंजी लगाने की बात सोची जा रही है—खास कर बड़े और मध्यम उद्योगों में, जिनका विनियोग ७०० करोड रु० से बढ़ा कर १,०५० करोड रुपये कर दिया गया है। अन्य क्षेत्रों के विनियोग में वृद्धि अपेक्षाकृत कम होगी, और खयाल है कि ये विनियोग सामान्य सूत्रों से ही पूंजी लेकर किए जायेंगे। उक्त सूत्रों में किसानों, शिल्पकारों, कारीगरों और छोटे उद्योग तथा व्यापार करने वालों की बचत और संगठित तथा असंगठित महाजनो से तथा

१. ये आकड़े निजी क्षेत्र के सम्पूर्ण पूंजी-विनियोग के शीर्षक हैं, और इनमें सरकारी क्षेत्र से दस्तान्तरित साधनों से होने वाला पूंजी-विनियोग भी शामिल है।

२ इन अंशों में यन्त्रों को आधुनिक बनाने और बदलने के लिये किया जाने वाला पूंजी-विनियोग शामिल नहीं है।

कुछ हद तक सरकार और रिजर्व बैंक से लिए हुए ऋण भी शामिल हैं। इन कामों में लगी हुई पूँजी का इतना अधिक भाग अपने पास से लगाया हुआ था कि उक्त विविध स्रोतों से लिया हुआ है, कि उनमें से प्रत्येक सूत्र की सीमा और सम्भावना का स्पष्ट चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न तक करना एक कठिन काम है।

यदि बड़े और मध्यम उद्योगों में लगाने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की समस्या रह गई। यहाँ भी बहुत-कुछ अनुमान पर ही निर्भर किया गया है, परन्तु उद्योगों और कारखानों से सम्बन्धित अध्याय में मोटे तौर पर कुछ अनुमान दिए गए हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योजना के निजी क्षेत्र में लगाये जाने वाले ४,२०० करोड़ रु० में से २०० करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र से प्राप्त किये जाएँगे। रिजर्व बैंक भी कृषि, लघु उद्योगों और निजी क्षेत्र के कुछ वित्त-निगमों की काफी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र को ३०० करोड़ रु० तक की विदेशी सहायता मिल सकती है। दूसरी योजना के समय निजी क्षेत्र में पूँजी-विनियोग की जो प्रवृत्तियाँ दिखलाई दी और विकास-कार्यों-द्वारा उत्पन्न नये अवसरों से लाभ उठाने में, निजी क्षेत्र जैसी तत्परता दिखला रहा है, उससे आशा बधती है कि निजी क्षेत्र में जितने पूँजी-विनियोग की रूपना की गई है, उसका पूरा होने में अल्पकाल कठिनाइयाँ पेश नहीं होंगी।

अन्त में यह प्रश्न आता है कि पूँजी-विनियोग के लिए समाज में जो साधन उपलब्ध होंगे, वे सब मिल कर भी पर्याप्त सिद्ध होंगे, या नहीं। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताएँ, स्वदेशी वस्तु और उपलब्ध विदेशी सहायता को मिला कर ही पूरी की जाएँगी। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के हेतु पूरा-पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा।

विदेशी साधन

आन्तरिक साधनों का अनुमान लगाने में तो बहुत-सी कठिनाइयाँ उपस्थित होती ही हैं, योजना के लिए विदेशी साधन कितने मिल सकेंगे, इसका अनुमान लगाने के लिए आगामी पाँच वर्षों में भ्रुगतान-सन्तुलन के रत्न के सम्बन्ध में पहले से कुछ कह सकना और भी कठिन है। इसके बावजूद आयात और निर्यात की हानि की प्रवृत्तियों और तीसरी योजना की अवधि में देश के आन्तरिक उत्पादन तथा माँग में सम्भावित परिवर्तनों का अध्ययन करने के उपरान्त जो चित्र सामने आता है, उसकी मोटी-मोटी बातें नीचे की तालिका में प्रस्तुत की गई हैं।

तीसरी योजना की अवधि में अनुमानित भुगतान-संतुलन

(करोड़ रुपये)

	१९५६-५७ से १९५८-५९ तक का औसत	१९६१-६२	१९६१-६२ से १९६५-६६ तक के पाव वर्षों का योग	१९६१-५२ से १९६५-६६ का वार्षिक औसत
१. निर्यात	६०२	६५०	३,४५०	६६०
२. भ्रष्ट (शुद्ध) (सरकारी दान छोड़ कर)	१०१	४५	१२०	२४
३. पूँजी का व्यवहार (शुद्ध) (नए सरकारी ऋणों और निजी विदेशी विनियोग को छोड़ कर)	-२२ ^१	-१५०	-५००	१००
४. आयात के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा (प्रविष्टि १ से ३ तक का योग)	६८१	५४५	३,०७०	६१४
५. काम चालू रखने के लिए किए हुए आयात	७२८	७३०	३,५७०	७१४
६. विकास की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए होने वाले आयात के क्षेत्र में उपलब्ध विदेशी मुद्रा (प्रविष्टि ४ और ५)	-४७	-१८५	-५००	-१००

तीसरी योजना की अवधि में निर्यात-द्वारा होने वाली समस्त कमाई का अनुमान ३,४५० करोड़ रु०, अर्थात् औसतन ६६० करोड़ रु० प्रति वर्ष लगाया गया है। १९५८-१९५९ में निर्यात से ५७६ करोड़ रु० की और १९५९ में ६४५ करोड़ रु० की कमाई हुई थी। तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में निर्यात का अनुमान ६५० करोड़ रु० लगाया गया है। तीसरी योजना की अवधि में उत्पन्न होने में सम्भावित वृद्धि और निर्यात बढ़ाने के निरन्तर प्रयत्न के फलस्वरूप, सम्भव है, कि आगामी वर्षों में

१. इस अंक में 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष' और 'पी० एल० ४८०' खातों से प्राप्त राशियाँ शामिल नहीं हैं, परन्तु निजी खातों में प्राप्त पूँजी शामिल है।

निर्यात की मात्रा बढ़े। वास्तव में, उद्देश्य तो उपर्युक्त स्तर से भी ऊँचा उठना होना चाहिए।

अदृश्य प्राप्तियाँ का परिमाण हाल के वर्षों में घटता चला गया है। इसका कारण कुछ तो यह है कि विदेशों में लिए हुए ऋणों पर देय व्याज बढ़ना चला गया और कुछ यह कि ब्रिटेन से प्रान्तव्य स्टॉलिंग राशि की मात्रा घट गई। दूसरी योजना की अवधि में जो ऋण लिए गए, उन पर और तीसरी योजना की अवधि में जो ऋण लिए जाएँगे, उन पर देय व्याज की राशियाँ मिल कर खासी बढ़ी हो जाएँगी। इन देनदारियों और इस खाते की अन्य प्राप्तिवो तथा अदायगियों के हल का खयाल करते हुए, पाँच वर्षों में अदृश्य प्राप्तिवो की कुल वचत ₹२२ करोड़ ६० अथवा प्रोस-तन २४ करोड़ ६० प्रतिवर्ष मानी जा सकती है। इसके मुकाबले में ₹६५६-५७ से ₹६५८-५९ तक का वार्षिक प्रोसत ₹०१ करोड़ ६० या।

दूसरी योजना के अन्त तक जो देनदारियाँ इकट्ठी हो जाएँगी, उनकी अदा-यगी के लिए तीसरी योजना की अवधि में लगभग ४२० करोड़ ६० देने पड़ेगे। इसके अतिरिक्त तीसरी योजना की अवधि में जो ऋण लिए जाएँगे, उनमें से भी कुछ चुकाने योग्य हो जाएँगे। पूँजी खाते हुए अन्य व्यवहारों का विचार करने के बाद, इस खाते की देय राशियों का संवयोग ५०० करोड़ ६० माना जा सकता है। ये व्यवहार अधिकतर निजी हिस्सों में ही हुए हैं और होंगे।

निर्यात और अदृश्य प्राप्तिवो द्वारा की हुई कमाई में से, पिछले पैराग्राफ में निर्दिष्ट देनदारियाँ घटा देने के बाद, आयात का मूल्य चुकाने के लिए शेष राशि ₹,०७० करोड़ ६० की बच जाती है। इसके मुकाबले में, अनिवार्य आवश्यकताएँ मगाए जाने वाले कच्चे मालों, अथवा सामान, सामान्य व्यापार के हिस्सा में आए हुए खाद्यान्नों और पुरानी मशीनों को बदलने के लिए मगाई हुई नई मशीनों, आदि का मूल्य ₹,५७० करोड़ ६० होगा।

इसका अर्थ यह है कि ५०० करोड़ ६० का घाटा रह जाता है, जो चुकाने-योग्य हो जानेवाले ऋणों की राशि के लगभग बराबर है। इसे योजना की आवश्यकताओं की चिन्ता करने से पहले पूरा करना पड़ेगा। यह कमी आरम्भ के वर्षों में और भी बड़ी रहने की सम्भावना है, क्योंकि अधिकतर पुराने ऋण इन्हीं वर्षों में देय होंगे। इन वर्षों के बाद, ज्यों ज्यों लोहे व इस्पात, मशीन निर्माण और दवाओं तथा रसायनों, आदि की परिभोजनाओं से माल अधिकाधिक मात्रा में तैयार होने लगेगा, त्यों त्यों यह कमी घटती चली जाएगी। इसके साथ ही यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में उत्पादन की मात्रा बढ़ने के कारण विदेशों से आयात कम अथवा बन्द करके जो वचत की जाएगी, उसे अर्थ-व्यवस्था में विकास के कारण उत्पन्न हुई नई नई आवश्यकताएँ खा जाएँगी।

योजना के सरकारी और निजी क्षेत्रों के पूँजी-विनियोग में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कितनी होगी, यह योजना की विभिन्न परियोजनाओं के सोपानों में बँट-वारे पर निर्भर करेगा। अगले कुछ महीनों में इसके लिए बहुत काम करना होगा। यदि स्वदेश में निर्मित बुनियादी सामान तथा उपकरणों का यथासम्भव अधिक उपयोग किया जाए—और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आयात कम करनेवाली परियोजनाओं के लिए शुरू के वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा मिल जाती है—तो योजनाकाल में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता अन्दाजन १,६०० करोड़ ६० की पड़ेगी। इसके अतिरिक्त, स्वदेश में बुनियादी यन्त्रों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लगभग २०० करोड़ ६० के पुँज और सन्तुलनमूलक उपकरण भगाने पड़े गे। इस प्रकार के आयात का सीधा सम्बन्ध योजना में निहित परियोजनाओं के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। यह आयात कुछ ऐसे पुँजों और अघटने हिस्सों का है, जो अभी देश में नहीं बनते और बुनियादी यन्त्रों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जिनकी अत्यन्त आवश्यकता है।

३—प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन^१

(Comparative Study of the First, Second and the Third Five Year Plans)

इन तीनों आयोजनों के विषय में पूर्णरूप से तुलना करना अत्यन्त विशाल विषय होगा। इसलिए केवल मुख्य विषयों पर ही यह अध्ययन सीमित किया गया है। इन विषयों में निम्नलिखित मुख्य हैं

हमें पहली चीज़ें पहले लेनी होंगी और एक दिये सीमित समय में प्राथमिकताओं का निश्चय करना होगा, यद्यपि, जैसे वर्ष के बाद वर्ष बीतते जायेंगे, इन प्राथमिकताओं में फेर-बदल होता जायगा। जैसे जैसे आरम्भ में शुरू किये गये विकास-क्षेत्रों का काम आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे हम अन्य क्षेत्रों पर जोर देना होगा और अन्य क्षेत्रों के विकास के लिये पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी।

प्रथम योजना के पाँच वर्षों में सबसे ऊँची प्राथमिकता खेती बाड़ी को जिसके अन्तर्गत सिंचाई और बिजली आ जाते हैं, देनी होगी।* हम जिन योजनाओं को हाथ में ले चुके हैं उनकी पूर्ति पर जोर देना कुछ हद तक इसी बात की ओर संकेत करता है। लेकिन इसके अलावा भी यह जाहिर है कि अनाज और उद्योगों के लिए जरूरी कच्चे माल का उत्पादन काफी बढ़ाये बिना अन्य क्षेत्रों में विकास की रफ्तार को तेज रखना असम्भव होगा और अधिक विकास के लिये खाद्य और कच्चे माल

१. समस्त आँखें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं से हैं।

* प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत सरकार, अध्याय ७

का होना बहुत जरूरी है, इसीलिये इन वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भरता और बहुतायत की दशाओं का निर्माण होना बुनियादी बात है ।

खेती में मुधार बहुत हद तक सरकार द्वारा लगाई गई पूँजी पर निर्भर करेगा और क्योंकि खेती-बाड़ी के काम को सब से ऊँची प्राथमिकता दी गई है, इस लिए सरकार द्वारा उद्योगों में लगाई गई पूँजी अपेक्षाकृत सीमित रहेगी । वर्तमान अवस्था में इस क्षेत्र में उन्नति बहुत हद तक निजी प्रयत्न और पूँजी पर निर्भर करेगी । सरकार आरम्भिक अवस्था में बुनियादी सेवाओं और यातायात की व्यवस्था पर भी यथाशक्ति अपना ध्यान केन्द्रित करेगी । लेकिन कुछ केन्द्रीय उद्योगों, जैसे लोहा और इस्पात, भारी रासायनिक और भारी विजली-उद्योगों के प्रति उसकी विशेष जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आज की दुनिया में ये उद्योग औद्योगिक उन्नति के आधार हैं । इस प्रकार के उद्योगों के विकास के लिये आरम्भ में इतनी पूँजी लगती है, वह बहुत बड़ी होगी और निर्माण का समय काफी लम्बा होगा । इसीलिये इस दिशा में आरम्भ से ही काम शुरू करना होगा ।

जिस हद तक आरम्भिक रूप में पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया जायगा उसी हद तक अनिवार्यतः सामाजिक सेवाओं का विकास सीमित हो जायगा । लेकिन फिर भी यह साफ है कि कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक मानव-सम्पत्ति के सुधार के लिए पूँजी न लगाई जाय । उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से भी शिक्षा, टैक्नीकल शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का विस्तार विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकता है । इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष सामाजिक प्रयत्नों के लिये बहुत गुंजायश है । इसीलिये इस क्षेत्र के लिए जो विशेष आर्थिक व्यवस्था रखी गई है, इसके बाद भी अन्य साधनों के द्वारा बहुत अधिक काम किया जा सकता है । उदाहरणार्थ, देहाती क्षेत्रों में साक्षरता का प्रसार इच्छापूर्वक सामाजिक सेवा करने वालों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है । सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार प्रायः सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी आरम्भिक ज्ञान देकर किया जा सकता है । जहाँ तक टैक्नीकल शिक्षा का सवाल है, यह अत्यन्त आवश्यक है कि समुचित आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाय, क्योंकि यह न केवल विकास की प्रणाली के लिये आवश्यक है बल्कि वर्तमान समय में प्रचलित विगुड़ साहित्यिक शिक्षा के प्रति मुकाब को सही रास्ते पर जाने के लिये भी जरूरी है । इस प्रकार के मुकाब के कारण ही मध्यवर्गीय लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है ।

क्योंकि हमारे यहाँ जन शक्ति का बहुत बड़ा भाग अभी उपयोग में नहीं आ रहा है, इसीलिये स्थानीय विकास के लिये स्थानीय श्रम-शक्ति का उपयोग करने के प्रोग्राम की उच्च प्राथमिकता देनी होगी । जीवन यापन की दशाओं में सुधार करने के लिये उनका योगदान पहली दृष्टि में भले ही बहुत छोटा मालूम हो, लेकिन कुल मिला कर और सामूहिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के रूप में, आरम्भिक अवस्था को देखते

हुये, वह अनुपात में बहुत अधिक होगा। इस सिद्धान्त पर आधारित सामूहिक विकास के प्रोग्राम और भरपूर चहुमुखी विकास, जो कि चुने हुये क्षेत्रों में होगा, विशेष महत्त्व के सिद्ध होंगे।

ऊपर बताई गई प्राथमिकताओं की आम रूपरेखा के अन्तर्गत अधिक विस्तृत नक्शे हैं, जो देश के एक भाग से दूसरे भाग में बदलते जायेंगे। उदाहरण के लिये खेती-बाड़ी के क्षेत्र में कुछ जगहों में सिंचाई विशेष महत्त्वपूर्ण हो सकती है और कुछ दूसरी जगहों में रासायनिक खादों को विशेष महत्त्व मिल सकता है। कुछ क्षेत्रों में खेती के विकास के लिये सड़कों में सुधार एक आवश्यक घात हो सकती है। उद्योगों के क्षेत्र में राष्ट्रीय हित की दृष्टि में कुछ उद्योगों का विकास अन्य उद्योगों से अधिक जरूरी हो सकता है, भले ही उन उद्योगों का विकास निजी तौर पर उद्योगों का संचालन करने वालों को हमेशा अधिक आकर्षक और लाभदायक न प्रतीत हो। इन सब प्राथमिकताओं की दृष्टि में रखना इसलिये जरूरी है, जिससे कि जो कुछ भी अनावश्यक है, या आरम्भिक अवस्था में राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिये जो कुछ भी अपेक्षाकृत कम सहायक है उसमें साधनों का अपव्यय न हो जाय।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस ओर स्पष्ट संकेत किया गया है कि देश की साधारण जनता के जीवन-स्तर में सुधार और राष्ट्रीय आय में वृद्धि तीव्र गति से होनी चाहिये। किन्तु साथ ही साथ यह भी बताया गया था कि 'समाजवादी ढंग की समाज व्यवस्था' को प्राप्त करने के उद्देश्य से आर्थिक विषमता को कम से कम कर दिया जायेगा। इस विषय में द्वितीय योजना में प्राथमिकतायें कुछ अन्य रूप से निर्धारित की गई थी। जो निम्न प्रकार है ¹

हमारे समाज के मूल उद्देश्य क्या है, इसका सार इधर समाजवादी ढंग की समाज व्यवस्था के वाक्यांश द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मोटे तौर पर इसके माने यह है कि आगे बढ़ने का रास्ता चुनते समय हम सारे समाज के हित की बात सोचेंगे, किसी खास वर्ग या व्यक्ति के लाभ की नहीं, और विकास-पद्धति और सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धों का विधान कुछ इस तरह निर्धारित करेंगे कि न सिर्फ राष्ट्रीय आय और रोजगार के अवसर में वृद्धि हो बल्कि लोगों की आय और सम्पत्ति में विषमता घटती ही चली जाये, आर्थिक उन्नति से समाज के वर्ग विशेष रूप से लाभान्वित हों जो अपेक्षाकृत कम सम्पन्न हैं, कारों और सुख और शान्ति का साक्षात्कार हो और निम्न से निम्न आदमी को भी अपनी जिन्दगी सफल बनाने का पर्याप्त अवसर मिले।

ऐसी परिस्थितियों की स्थापना के लिये राज्य को अपने ऊपर भारी जिम्मे-दारियां लेनी पड़ती हैं। उद्योगों के सार्वजनिक क्षेत्र को तेजी से बढ़ाना होता है।

1 द्वितीय पंचवर्षीय योजना—भारत सरकार
(संक्षिप्त) अध्याय २—पृष्ठ १०

सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में पूँजी कहीं, नितनी और किस तरह लगे, इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी बहुत हद तक राज्य को अपनानी होती है, और विकास के ऐसे काम उठाने होते हैं जिन्हें निजी क्षेत्र या तो उठा नहीं सकता या उठाना नहीं चाहता। कुछ बड़े-बड़े नये उद्योग धन्धों की, जिनके लिये प्राधुनिक गिनत्यविधि का ज्ञान, बड़े पैमाने पर उत्पादन, और साधनों के आवंटन और नियंत्रण का एकाधिकार अपेक्षित हो, जिम्मेदारी मुख्यरूप से राज्य को ही उठानी होगी। ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ औद्योगिक कारणों से आर्थिक सत्ता और सम्पदा का संचयन एक विशेष व्यक्ति या वर्ग के हाथ में हो जाने की सम्भावना हो। प्राथमिक या पूर्णरूप से सार्वजनिक स्वामित्व और प्रबन्ध पर सार्वजनिक नियंत्रण या हिस्सेदारी खास तौर से प्रावश्यक हो जाती है। निजी क्षेत्र को भी बहुत काम करना होगा, लेकिन समूची योजना के दायरे में रह कर हम काफी तेजी से औद्योगीकरण करना है। लोहा और इस्पात, लोहेतर धातुएँ, कोयला, सीमेंट जैसे मूल उद्योगों और मशीन तैयार करने वाले उद्योगों का द्रुत विकास करना पड़ेगा। ग्रह उद्योगों और छोटे उद्योगों को भी उन्नत करना पड़ेगा।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में प्राथमिकताओं के विषय में बताया गया है कि कृषि और उद्योगों तथा निर्यात की आवश्यकताएँ पूरी कर देना तीसरी योजना का एक प्रधान लक्ष्य है। इसलिये कृषि के उत्पादन को यथासम्भव उच्चतम स्तर तक उठाना होगा ताकि ग्रामीण लोगों की आमदनी और रहन-सहन का स्तर भी अन्य क्षेत्रों के लोगों के साथ साथ ऊँचा उठे। इस योजना में कृषि और ग्रामीण मण्डल व्यवस्था के विकास के लिये पर्याप्त साधन मुहूर्त्या करने का प्रयत्न किया गया है। सोचा गया है कि यदि योजना के आगे बढ़ने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति और तेज करने के लिये, विशेषकर ग्रामीण जन शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करने के लिये, और साधनों की आवश्यकता पड़े, तो वे भी जुटा दिये जाएँ। योजना में उद्योग, बिजली और परिवहन के क्षेत्रों को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है। अर्थव्यवस्था को उच्चतर स्तर पर ले जाने और उसकी गति को तीव्र करने के लिये इन क्षेत्रों का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है।

पहली और दूसरी योजनाओं की कल्पना, देश के एक दीर्घकालीन सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रम की दो मजिला क रूप में की गई। पहली योजना में १९५०-५१ से १९८०-८१ तक के ३० वर्ष की आधिक उन्नति का चित्र प्रस्तुत करके अनुमान लगाया गया था कि देश की राष्ट्रीय आय १९७१-७२ तक और प्रति व्यक्ति आय १७७-७८ तक दुगुनी हो जाएगी। हम अनुमान का आधार में पूर्व कल्पनाएँ थी कि देश की आबादी किम रफ्तार से बढ़ेगी, विकास की हरेक मजिल में राष्ट्रीय आय की वृद्धि का कितना भाग फिर पूँजी-निर्निर्माण में लगेगा, और जो

पूँजी लगाई जाएगी, उससे अतिरिक्त उत्पादन के रूप में कितना लाभ होगा। दूसरी योजना के समय, इन पहले के अनुमानों और कल्पनाओं पर पहली योजना में प्राप्त अनुभवों से लाभ उठा कर, पुन विचार किया गया और यह मत व्यक्त किया गया कि १९५०-५१ की तुलना में, देश की राष्ट्रीय आय १९६७-६८ में और प्रति व्यक्ति आय १९७३-७४ में ही सम्भवतः दुगुनी हो पाएगी। उस समय एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य यह रखा गया था कि पाँचवी योजना के समाप्ति-काल तक खेती पर आश्रित रहने वालों का अनुपात आबादी के लगभग ६६ या ७० प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घट कर लगभग ६० प्रतिशत रह जाएगा।

दूसरी योजना में जिन लक्ष्यों की कल्पना की गई है, उनकी पूर्ति दो बातों पर निर्भर करेगी—पहली तो यह, कि आबादी में वृद्धि किस हिसाब से होती है, और दूसरी यह, कि अगली तीन योजनाओं में जो प्रयत्न किया जाएगा, उसका परिणाम और स्वरूप क्या होगा। दूसरी योजना प्रकाशित होने के बाद आबादी के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय परिवर्तन सामने आ चुका है। आगामी १५ वर्षों में आबादी की सम्भावित वृद्धि के विषय में विभिन्न कल्पनाओं के आधार पर जो अनुमान लगाए गए हैं, उनसे प्रतीत होता है कि आबादी बढ़ने की रफ्तार दूसरी योजना में दिखाई हुई रफ्तार से कहीं अधिक रहेगी। नीचे की तालिका में आबादी की वृद्धि के विषय में केन्द्रीय अक-सकलन-संगठन-द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के साथ दूसरी योजना की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुमानों की तुलना की गई है।

(ये आकड़े करोड़ में हैं)

	१९५१	१९५६	१९६१	१९६६	१९७१	१९७६
दूसरी योजना के अनुमान	३६ २	३८ ४	४० ८	४३ ४	४६ ५	५० ८
केन्द्रीय अक सकल						
लन संगठन के अनुमान	३६ २	३९ १	४३ १	४८ ०	५२ ८	५६ ८

केन्द्रीय अक सकलन संगठन के अनुमानों को तीसरी योजना तैयार करने के लिए किन्हाल मान लिया गया है। परन्तु ये अनुमान भी अस्थायी ही हैं और इन्हें जन्म, मृत्यु और जन वृद्धि में सम्बन्धित निम्नलिखित आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है।

(प्रति वर्ष प्रति हजार वृद्धि)

	१९५१-५६	१९५६-६१	१९६१-६६	१९६६-७१	१९७१-७६
जन्म-दर	४१ ७	४० ७	३९ ६	३२ ८	२७ ३
मृत्यु दर	२५ ६	२१ ६	१८ २	१३ ६	१२ ६
वृद्धि की दर	१५ ८	१९ १	२१ ४	१९ ८	१४ ७

इन अनुमानों के अनुसार, १९५१-७६ की अवधि में आवादी में कुल मिला कर २० * ६ करोड़ की वृद्धि होगी, जबकि दूसरी योजना में केवल १३ * ८ करोड़ की वृद्धि का ही अनुमान लगाया गया था। आवादी में वृद्धि के इस हिसाब से, थमिको की सख्या जो १९५१ में १४ * १ करोड़ थी, वह १९७६ में बढ़कर २२*२ करोड़ हो जाएगी। १९६१ से १९७६ तक के १५ वर्षों में, थमिक सख्या में कोई ६ करोड़ की वृद्धि होने की सम्भावना है।¹

प्रथम योजना² काट में पूँजी और उत्पादन की वृद्धि का अनुपात १ : १ होता है, दूसरी योजना काट में विनियोग के अनुमानों और उत्पादन की वृद्धि की आशा के आधार पर यह अनुपात २ : १ होने की आशा है। दूसरी योजना काट में बल अधिक औद्योगीकरण पर होगा और इसलिए यह आशा है कि पूँजी विनियोग पहली योजना की तुलना में कुछ अधिक बढ़-चढ़ कर होगा। वस्तुतः आगे आने वाली योजनाओं में जैसे जैसे विभिन्न दिशाओं में विकास की गति को केन्द्रित किया जाएगा वैसे ही अतिरिक्त उत्पादन के लिए आवश्यक पूँजी की राशि में भी वृद्धि होनी जाएगी। तीसरी, चौथी और पाँचवी योजनाओं के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि पूँजी उत्पादन क्रमशः २*६, ३*४ और ३*७ होंगे। ये अनुपात केवल दृष्टान्त रूप में हैं। ठीक-ठीक लेना-जोखा स्वाभाविक तभी हो सकता है जब विकास के सुनिश्चित कार्यक्रमों, उनकी जरूरतों और उनके परिणामों के प्रकाश में विचार किया जाए। यहाँ यह बात बता दी जाये कि सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए पूँजी-उत्पादन अनुपात विभिन्न क्षेत्रों में पूँजी की उत्पादकता का सचेतात्मक विवरणमात्र है। यह उत्पादकता न केवल विनियोजित पूँजी की राशि पर निर्भर करती है बल्कि कुछ अन्य बातों पर भी, जैसे पूँजी-निर्माण से सम्बन्धित प्रौद्योगिक उन्नति का स्तर, नई साज-सज्जा के संचालन की दक्षता और उत्पादन की विधियों से सम्बन्धित व्यवस्था और संगठन की कुशलता। विनियोग के रूप पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। विभिन्न देशों और विभिन्न समयों में पूँजी-उत्पादन अनुपात का अनुमान भी विभिन्न होते हैं। अनेक देशों के अनुपातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि पूँजी निर्माण अनुपात प्रायः ३ : १ और ४ : १ के बीच रहता है। यद्यपि कभी किसी देश में अनुपात इससे न्यूनार्थिक भी हो सकता है, फिर भी भारत और दूसरे देशों के अनुपात की तुलना करते हुए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पूँजी विनियोग का लेना-जोखा करते हुए मुद्देतर विनियोग को अलग कर दिया जाता है। यद्यपि एक ऐसे देश में जहाँ प्रधानतः ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था है, ऐसे विनियोग का महत्त्व बहुत होता है।

1. Ibid, pp. 4—5

2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना (संक्षिप्त), भारत सरकार, पृष्ठ ३-५

पहली योजना सम्बन्धी रिपोर्ट में यह मान लिया गया था कि १९५६-५७ से वचत की दर ५० प्रतिशत होगी। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि १९६८-६९ तक अर्थ व्यवस्था में विनियोग की दर राष्ट्रीय आय का २० प्रतिशत हो जाएगी और तत्पश्चात् उसी स्तर पर स्थिर हो जाएगी। अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि यह आशा बहुत बड़ी थी। जिस भविष्य की परिकल्पना अब की गई है, उसमें १९५५-५६ में विनियोग राष्ट्रीय आय का लगभग ७ प्रतिशत होगा, १९६०-६१ में ११ प्रतिशत, १९६५-६६ में १४ प्रतिशत और १९७०-७१ में १३ प्रतिशत। इसके बाद विनियोग की गति प्रायः स्थिर रहेगी, और १९७५-७६ तक १६ प्रतिशत हो जाएगी। राष्ट्रीय आय का १६ से १७ प्रतिशत तक वास्तविक विनियोग काफी ऊँचा है, यद्यपि उसे प्राप्त करना असम्भव नहीं है। पश्चिमी देशों में, जिन्होंने बहुत पहले से औद्योगीकरण का मार्ग पकड़ा, वास्तविक पूँजी निर्माण की गति १० से १५ प्रतिशत रही है। जापान में १९१३ और १९३९ के बीच की पूँजी विनियोग की गति १६ से २० प्रतिशत रही है। रूस में १५ से २० प्रतिशत ऊँची दर को लगातार कायम रखा गया है। समुचित विनियोग नीति और कार्यक्रमों के द्वारा नव विकसित देशों में विनियोग की गति को वर्तमान स्तर से अधिक ऊँचा उठाया जा सकता है। उपर्युक्त दिशाओं में विश्लेषण और अनुमान के फलस्वरूप यह कहा जा सकता है कि १९६७-६८ तक राष्ट्रीय आय और १९७३-७४ तक प्रति व्यक्ति आय दूनी हो सकेगी। पहली पंचवर्षीय योजना में जितनी आशा की गई थी उक्त योजना-काल में उससे अधिक वृद्धि राष्ट्रीय आय में हुई है। प्रथम दो योजनाओं के अन्त में राष्ट्रीय आय में ४७ प्रतिशत वृद्धि की आशा है, जब कि पहली योजना में २५ प्रतिशत वृद्धि की बात ही कही गई थी। नीचे दी हुई तालिका में बताया गया है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास की गति अनुमानित क्या होगी

आय और विनियोग की वृद्धि १९५१-७६
(१९५०-५३ के मूल्यों पर आधारित)

	पहली योजना (१९५१-५६)	दूसरी योजना (१९५६-६१)	तीनरी योजना (१९६१-६६)	चौथी योजना (१९६६-७१)	पाँचवी योजना (१९७१-७६)
१. समयावधि के अन्त में राष्ट्रीय आय (करोड़ रु०)	१०,८००	१३,४८०	१७,२६०	२१,६८०	२७,२७०
२. कुल वास्तविक विनियोग (करोड़ रु०)	२,१००	६,२००	६,६००	१,८००	२०,७००
३. समयावधि के अन्त में राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में विनियोग	७.३	१०.७	१३.७	१६.०	१.०

४. समयावधि के अन्त में आवादी (लाख)	३,८४०	४,०८०	४,३४०	४,६५०	५,०००
५. वृद्धिसूचक पूँजी विनियोग अनुपात	१.८१	२.३.१	२.६.१	३.४.१	३.७.१
६. समयावधि के अन्त में प्रति व्यक्ति आय (रुपये)	२८१	३३१	३६६	४६६	५४६

यह द्रष्टव्य है कि दूसरी और तीसरी योजनाओं की अवधि में विनियोग की वृद्धि बाढ़ की योजनाओं से अपेक्षाकृत अधिक है, अतः विकास के क्रम को निर्दिष्ट करने में इन दस वर्षों का सबसे अधिक महत्व है। यही वह समय है, जिसे लाँघते हुए बाहरी सहायता द्वारा घरेलू साधनों को मजबूत बनाना होगा क्योंकि यह समय ऐसा होगा जब कि जीवन-स्तर निम्न और बचत की संभावनाएँ अल्प होंगी।

विभिन्न मुख्य विकास मन्त्रों में योजना व्यय का वितरण¹

मन्त्र	प्रथम योजना		दूसरी योजना	
	कुल व्यय (करोड़ रु०)	%	कुल व्यय (करोड़ रु०)	%
१-कृषि और सामुदायिक विकास	३१७	१४.१	५३८	११.८
२-सिंचाई और बिजली	६६१	२८.१	६१३	१६.०
३-उद्योग और लान	१७६	७.६	८६०	१८.४
४-परिवहन और संचार	५५७	२३.६	१३८५	२८.६
५-सामाजिक सेवाएँ	५३३	२२.६	६४५	१६.७
६-शिक्षा	६६	३.०	६६	२.१
योग	२३५६	१००	४८००	१००

तीसरी योजना में प्रस्तावित व्यय और पूँजी-विनियोग¹

(करोड़ रुपये)

विकास का विभाग	सरकारी क्षेत्र			निजी क्षेत्र का पूँजी विनियोग	समस्त पूँजी विनियोग
	योजना का प्रस्ता- वित व्यय	चानू व्यय	पूँजी विनियोग		
१-कृषि, छोटी सिंचाई और सामुदायिक विकास	१,०२५	३५०	६७५	८००	१,४७५
२-बड़े और मध्यम सिंचाई कार्य	६१०	१०	६४०	—	६४०
३-विजली	६२५	—	६२५	५०	६७५
४-ग्रामीण और छोटे उद्योग	२५०	६०	१९०	२७५	४३५
५-उद्योग और खानें	१,५००	—	१,५००	१,०००	२,५००
६-परिवहन और संचार	१,४५०	—	१,४५०	२००	१,६५०
७-समाज सेवायें	१,२५०	६००	६५०	१०७५	१,७२५
८-इन्वेण्टरियाँ	२००	—	२००	६००	८००
सर्व योग	२५०	१०५०	६,२००	४,०००	१०,२००

पहली योजना के समय देश की अर्थ व्यवस्था में वार्षिक पूँजी-विनियोग लगभग ५०० करोड़ रु० में बढ़ते-बढ़ते कोई ८५० करोड़ रु० तक पहुँच गया था । दूसरी योजना के अन्त तक वार्षिक पूँजी विनियोग के १,४५० करोड़ रु० से १,५०० करोड़ रु० तक पहुँच जाने की आशा है । तीसरी योजना की समाप्ति पर वार्षिक पूँजी-विनियोग का विस्तार शायद २,५०० करोड़ रु० के आस पास पहुँच जायेगा । पहली योजना में सरकारी पूँजी विनियोग लगभग २०० करोड़ रु० प्रति वर्ष से आरम्भ होकर योजना समाप्ति तक ४५० करोड़ रु० होगया था । दूसरी योजना के अन्त तक इसके लगभग ८०० करोड़ रु० और तीसरी योजना के अन्त तक कोई १,५०० करोड़ रु० हो जाने की आशा है ।

उत्पादन और विकास : प्रगति और नए लक्ष्य*

वस्तु	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६०-६१ की अपेक्षा की अपेक्षा में हुई प्रति-शत वृद्धि
१	२	३	४	५	६	७
१. कृषि और सामुदायिक विकास						
(१) कृषि की उपज						
खाद्यान्न	लाख टन	५२२	६५८	७५०	१,०००-१,०५०	५४
कपास	लाख गांठे	२६	४०	४४	५४	८६
चीनी (गुड़)	लाख टन	५६	६०	७२	१०-६२	२४-२८
तिलहन	लाख टन	५१	५६	७२	६२-६४	२५-३२
पदसन्	लाख गांठे	३३	४२	५४	६५	१८
बाप (क)	लाख पौंड	६,१३०	६,७८०	७,२५०	८,२००	१८
तम्बाकू	हजार टन	२५७	२६८	३००	३२५	१७
मछली	लाख मीट्रिक टन	७	१०	१४	१८	५
दूध	लाख मन	४,६६०	४,२८०	६,०००	६,६००	१००
ऊन	लाख पौंड	६००	६५०	७२०	८००	२६
*मृत्वीय पंचवर्षीय योजना, रुपरेखा, पृष्ठ ३८-४५.						

[नियोजन : देश और विदेश में]

	लाख एकड़	५१५	५६२	७००	६००	३६	२६
(२) वृषि-सम्बन्धी सेवाएँ							
सिंचित क्षेत्र (विद्युत् योग)							
भूमि का उद्धार (अतिरिक्त क्षेत्र)		—	२७	१२	१०	—	—
भूमि-सुरक्षण (सामन्वित अति- रिक्त भूमि)		—	७	२०	१३०	—	—
नम्रजलवाले उर्वरक	लाख एकड़ हजार टन (नम्रजन)	५५	१०५	३६०	१,०००	५५५	१७८
फास्फेटवाले उर्वरक	हजार टन (फास्फेट)	७	१३	६७	४००-५००	८५७	४६७-६४६
बीजों के फार्म	महत्वा	—	—	४,०००	४,५००	—	१३
(३) सामुदायिक विकास							
खण्ड	संख्या	—	१,०६४	३,११२	५,२१७	—	६८
अन्तर्गत ग्राम गाँव	हजार	—	१५०	४००	५५०	—	३८
अन्तर्गत ग्राम- जनसंख्या	लाख	—	७८०	२,०००	३,७४०	—	८७
२. विजली							
सगे हुए कारखानों की क्षमता	लाख किलोवाट	२३	३४	५८	११८	१५२	१०३
उत्पादित विजली	करोड़ किलोवाट-घंटे	६५.७५	१,१००	२,०७०	४,२२५	२१५	१०४
कस्बों और गाँवों में विजली पहुँचाई गई	हजार	३७	७४	१६	३४	४१४	७६

५. खनिज पदार्थ
कच्चा लोहा
कोयला

लाख टन
लाख टन

३०
३२०

४७
३८०

१२०
५३०

३२०
८७०

३००
६६

१६७
८३

४. बड़े उद्योग

(१) धातु-शोधन-उद्योग

तैयार इस्पात
कच्चा लोहा (विक्री
के लिए)

लाख टन

१०

१३

२६

६६

१६०

१६५

ताँबा
प्रत्युत्पीनियम

लाख टन

३.५

३.८

६

१५

१५७

६७

हजार टन
हजार टन

३७

७.३

१७

७५

३४६

१३३

३४१

(२) मैकेनिकल और विजली इजीनियरी
सीमेंट की मशीनें

मूल्य लाख २० में

मूल्य लाख २० में

चीनी की मशीनें

मशीनी औजार

(वर्गोइल)

वाल और रोलर-

बियरिंग

डीजेल इंजिन

ट्रैक्टर

मूल्य लाख में

संख्या लाख २० में

हजार

संख्या

१

६

२४

१२०

२,३००

५००

१००

५००

—

१०

२,०००

१०,०००

—

५००

[नियोजन : देश और विदेश में]

विजली की मोटरें (२०० हार्सपावर या उससे नीचे की)	हजार हार्सपावर	१००	२७०	८००	२,५००	७००	२१३
विजली के ट्रान्सफार्मर (३३ किलोवाट और उससे नीचे के)	ऐम्पीयर	१७६	६२५	१,३५०	३,५००	६५५	१५६
विजली के तार (ए० सी० एस० ग्रार० कण्डक्टर)	हजार टन	१७	८७	१८	५५	६५६	१५८
(३) रेलों के इन्जिन भाप और डीजल तेल के सव्वा विजली के	प्रतिफलघ	—	५००	१,२५०	१,६०६	—	२६
(४) रसायन, उर्वरक नमून वाले (नमून के रूप में) फार्मेटवाले (फार्मेट के रूप में) गंधक का तेजाब सोडा ऐस कार्बोनाट सोडा सल्फा ड्रग डी०डी०टी०	हजार टन	६	७६	२१०	१,०००	२,२३३	३७६
	हजार टन	६	१२	७०	५००-५००	६७८	५७१-६१५
	हजार टन	६६	१६५	५००	१,२५०	३०५	२१३
	हजार टन	५५	८१	२५०	५५०	५३३	८८
	हजार टन	११	३५	१२५	३५०	१,०३६	१७२
	टन	—	८३	१५०	१,०००	—	५६७
	टन	—	२८५	२,८००	२,८००	—	—

६. परिवहन-सेवाएँ

(१) रेलें :

याधियों ने यात्रा की
माल ढोया गया
पक्की सड़कें राष्ट्रीय
मार्गों शामिल करके
जहाजरानी

(२) संचार-सेवाएँ

डाक-घर
तार-घर
टेलीफोनो की सख्या

लाख मील
लाख टन
हजार मील
लाख योस टन

हजार
हजार
हजार

६५०
६१०
६७०.५
४

५५
५.१
१६८

१,०६०
१,१४०
१२२
५

५५
५.१
२८०

१,२४०
१,६२०
१४४
६

७५
६.३
४७५

१,४३०
२,३५०
१६४
११

६५
८.३
६७५

३१
७८
४८
१२५

१०८
७५
१८३

१५
४५
१४
२२

२७
३२
४२

७. शिक्षा

(१) सामान्य शिक्षा

विद्यालयों में विद्यार्थियों की सख्या
लाख विद्यालय जाने वाले निम्नलिखित
प्राथमिकों के बच्चों का प्रतिशत

प्राथमिक ६ से ११ वर्ष
माध्यमिक ११ से १४ वर्ष
उच्चतर माध्यमिक १४ से १७ वर्ष

२३५

४३

३१५

५१

४११

६०

६४८

८०

७५

४३

५८

३०

७७

१४०

१५

१५

१५

संस्थाएँ

प्राथमिक शूनियर बुनियादी

विद्यालय

माध्यमिक शूनियर बुनियादी

विद्यालय

उच्च-उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय

बहुदेशीय विद्यालय

(२) तकनीकी शिक्षा

इजीनियरी और टेक्नोलॉजी

डिग्री देने वाली संस्थाओं

की बालिश की क्षमता

हजार

हजार

हजार

हजार

२०६.७

१३.६

७.३

—

२७८.१

२१.७

१०.८

०.४

३५४.६

३०

१४

१.६

५००

४५

१८

१.८

६६

१२१

६२

—

४१

५०

२६

१३

४,११६

५,८८८

१३,१५५

१८,५००

२२०

४१

डिप्लोमा देने वाली संस्थाओं

की बालिश की क्षमता

५,६०३

१०,४८४

२४,०२०

३४,०००

३०७

४२

कृषि-डिग्री (स्तर)

पशु-चिकित्सा (डिग्री स्तर)

संख्या

संख्या

१,०६०

१,६८६

४,५००

६,०००

३२५

३३

१६

[नियोजन : देश और विदेश में]

३६६]

६. स्वास्थ्य

(१) नस्थाए'

अस्पताल और
औषधालय
अस्पतालों में रोमी-
शायार्ण
प्राथमिक स्वास्थ्य
इकाइयाँ
परिवार-नियोजन-
केन्द्र

(२) कर्मचारी
मेडिकल कालेजों
की दायित्वों की
क्षमता

डाक्टर (रजिस्टर्ड)
नर्स (रजिस्टर्ड)
मिडवाइफें (रजि-
स्टर्ड)

नर्स-दाइया और
दाइया रजिस्टर्ड
हेल्थ असिस्टेंट और
सेनीटरी इन्स्पेक्टर

हजार	८.६	१०	१२.६	१४.६	४७	१६.१
हजार	११३	१२४	१६०	१६०	४२	१६
संख्या	—	७२४	२,८००	४,०००	—	७६
संख्या	—	१४७	१,७६७	८,१६७	—	३५६
संख्या	२,८५४	३,६५५	४,७६०	अनुपलब्ध	६८	—
हजार	५६	७०	८४	१०३	५२	२३
हजार	१७	२२	३२.५	५२.५	६१	६२
हजार	१८	२७	४०	७०	१२२	७५
हजार	२२	६८	१२	४२	४४५	२५०
हजार	३.५	४	७	१४	१००	१००

प्रमुख संगठित उद्योगों और खनिज पदार्थों का उत्पादन, प्रगति और लक्ष्य

उद्योग का नाम	इकाई	१९५०-५१ का उत्पादन		१९५१-५२ का उत्पादन		१९६०-६१ का लक्ष्य	
		(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
(घ) धातुकर्म-उद्योग							
१. लोहा और इस्पात							
(१) इस्पात की विलयिता दस लाख टन		१.४	१.७	६	३.५	१०.२	६.५
(२) तैयार इस्पात दस लाख टन		०.६८	१.३	४.५	२.६	७.५	६.६
(३) बिक्री के लिये कच्चा लोहा		०.३५	०.३८	०.६	०.६	—	१.५
(४) मिश्र धातु, भोजारो का और विदेश इस्पात (तैयार)		—	—	—	—	—	—
(५) धूमर कोहे की ठसार्ई हजार टन		—	—	४०	४०	२००	२००
(६) इस्पात की ठसार्ई दस लाख टन		—	—	०.१	०.०५	१.२	१.२
(७) इस्पात की गठार्ई हजार टन		—	—	६०	३५	०.२	०.२
२. लोह संगनीज		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	१५०	१००	२००	२००
३. लोह सिलिकन		—	—	५	५	४०	४०
४. अल्युमीनियम		३.६८	७.३	१७.५	१७	८२.५	७५
५. तांबा घाग मे घोधा हुआ और विद्युच्चिसेलित हजार टन		—	७.३	७.२	७.६	१८.४	१८.४

1. Ibid, p. 220 229

1. Ibid, p. 220 229

६. सीसा	हुजार टन	—	२.२	६	१.५	५.५	१.५
७. जस्ता	हुजार टन	—	—	—	—	—	—
(आ) यांत्रिक इजीनियरी उद्योग							
८. ओद्योगिक यंत्र							
(१) मूलो कपडा	बरोड रुपये	—	४	१०	२२	१२	२०
(२) सीमेंट	बरोड रुपये	—	०.३४	१.१	५.५	५.५	५.५
(३) चीनी	बरोड रुपये	—	०.१६	१०.५	५.५	११ से १२	१०
(४) कागज	करोड रुपये	—	—	०.७	—	५.५	६.५
(५) डेरी	बरोड रुपये	—	—	०.२५	—	२.५	२.५
(६) औद्योगिक बायलर	करोड रुपये	—	—	३.७	०.६	२.६	२.५
(७) फ़ैन्	हुजार टन	—	—	२.५	१.५	६०	६०
(८) मशीनी धोजार	करोड रुपये	—	०.७२	७	५.५	३०	३०
(९) भारी मशीन-निर्माण (इस्पात और रासायनिक यंत्र)	हुजार टन	—	—	—	—	५०	—
(१०) फोयला-खनन यंत्र	हुजार टन	—	—	—	—	५५	—
(११) भारी प्लेट और वेसल (प्रेसर-वेसल, ताप-विनि-भावक और दूसरे प्रकार के रासायनिक संयंत्र तथा उपकरण)	हुजार टन	—	—	—	—	—	३० से ४०

(४) सहायक वाहन
(जिसमें ट्रैक्टर भी
शामिल है)

(५) मोटर साइकिलें
और स्टूटर

१५. बाल और रीतार
वेयरिंग

१६. मिट्टी हटाने के उप-
करण

(१) रेंगनेवाले ट्रैक्टर
(२) डम्पर और छुरपा
(३) फावड़ा

१७. सड़क रोलर
१८. कुपि उपकरण और
यन्त्र

(१) बिजली चालित
(२) डीजेल-इंजन
(३) ट्रैक्टर

१९. वाइसिकिलें
२०. सिलाई-मशीनें

२१. वेल्डिंग इलेक्ट्रोड

हजार अदद

हजार अदद

दस लाख अदद

अदद

अदद

अदद

अदद

हजार अदद

हजार अदद

हजार अदद

दस लाख अदद

हजार अदद

दस लाख आर-
एफ-टी

अनुपलब्ध

१६

२४

—

—

—

३५०

८६

३३

२

१०५

३००

३५०

२५

४८ से ६०

८

६००

५००

१२५

८००

१८५

७२

१२

२०२

५००

१,०८०

२०५

५०

१२

५००

५००

१००

७००

१५०

६६

१०

२

५५०

६००

२२. जहाज-निर्माण
(हिन्दुस्तान शिल्प-
यादे, सूखी गोदी
और दूसरे शिपयादे
का विस्तार)

हजार जी-थार-टी

—

५०

२०

२० ५० से ६० ५० से ६०
(डी० डब्ल्यू० (डी० डब्ल्यू०
टी०) टी०)

(६) बिजली इंजीनियरी उद्योग

२३. बिजली ट्रांसफार्मर
(२३ किलोवाट से
नीचे)

दस लाख किलो-
वाट

०.१८

०.६३

२.२

१.३५

५

३.५

२४. बिजली के मोटर
(२० हार्स पावर
और उससे कम)

दस लाख हार्स-
पावर

०.१

०.२७

१.२५

०.८

३

२.५

२५. बिजली के केबल
और तार

(१) ए० सी० एल०

आर०

(२) बी० आई०

आर० और प्ला-

स्टिक की पतं

चढ़े हुए

हजार टन

१.७

८.७

२८

१८

५५

४४

दस लाख कोर
गज

३६.४

८६.६

५००

२५०

८००

६००

(३) रेपर इंसुलेटेड / मील

—

१,०००

७५०

४,५००

४,०००

(४) मूलो कोर के केवल मोल			५२५	५७०	४७०	२,०००	२,०००	२,०००
(५) कोविंसियल केवल मोल			—	३००	३००	३००	३००	३००
१६ बिजली के पक्षे	दस लाख भवद	० १६	० २६	२ २	० ६	२ ५	२ ५	२ ५
२७ हाउस-सर्विस मोटर	दस लाख भवद	—	० २५	० ६	० ५५	२ ५	२ ५	२ ५
(६) रासायनिक और सम्बन्ध उद्योग								
२८ उर्वरक								
(१) नत्रजनयुक्त (नत्रजन की मात्रा के अनुसार) हजार टन		६	७६	२३५	२३०	१,०००	१,०००	१,०००
(२) फास्फेटयुक्त (फास्फेट की मात्रा के अनुसार) हजार टन		६	१२	५२	७०	५००	५००	५००
२९ भारी रसायन								
(१) गंधक अम्ल (मरक-रिक एसिड) हजार टन		६६	१६५	५२६	४००	१,२५०	१,२५०	१,२५०
(२) सोडा ऐश हजार टन		५५	६६	३०५	२५०	५५०	५५०	५५०
(३) नाइट्रिक सोडा हजार टन		११	३५	१५०	१२५	५००	५००	५००
(४) कैल्शियम कारबाइड हजार टन		—	३	२६	२०	६७	६०	६०
(५) सोडियम हाइड्रोसल्फाइड हजार टन		—	—	५	३५	१२	१०	१०
(६) हाइड्रो पेरोक्साइड हजार टन		—	—	३	२	६५	—	—
३० विविध रासायनिक उत्पादन								
(१) कार्बन ब्लैक हजार टन		—	—	—	—	३०	३०	३०

तृतीय पंचवर्षीय योजना]

३५. कच्ची किलों सिने- माटोग्राफिक	—	—	—	—	१०	१०
३६. रबड़ की चीजें (१) मोटर, वर्ग रूह के टायर	—	०.६	१.७६	१.५	३.७	३
(२) वाइसिकिल के टायर	—	५.७८	१६.६	१५	३८.६	३१
३७ नकली रबड़	—	—	—	—	३०	३०
३८. (१) फायर घोर गता	११४	१८७	३६३	३२०	८२०	७००
(२) ब्रखवारी फायर	—	५.२	३०	२८	१२०	१२०
(३) लिक्विडिटी- कागज	—	—	—	—	१,५००	१,५००
३९. सीमेन्ट	२.७	५.६	१०	८.८	१५	१३
४०. रिफ्रैक्टारिया	—	०.२८	०.८७	०.६	२	१.६
४१. विद्युत-पोसिलेन (उच्च तनाव घोर निम्न तनाव के पृथक्कारी)	—	५.३	—	८.५	३०	२४
४२. काँच घोर काँच का सामान (जिसमें चरमो का काँच भी शामिल है)	६२	१२५	४५७	२४०	६१५	४४०
४३. पेट्रोलियम की चीजें	—	३.६	५.३	४.६	७.५	७.५

(कच्चा तेल)

(कच्चा तेल)

४४. मोटरों और उद्योगों में

व्यवहृत श्रमिकों का

४५. औद्योगिक गैस

(१) आक्सीजन

(२) एसिटिलीन

दस लाख गैलन

दस लाख घन फुट

दस लाख घन फुट

४६. कपास

(१) सूत

(२) कपड़ा (मिल)

४७. पटसन

४८. रेयन और रेयोबाला कपड़ा

(१) रेयन का तार

(२) रेयोबाला कपड़ा

(३) रासायनिक छुगदी

अथवा सामान

(१) ऊनी और बटा हुआ

तार

(२) ऊनी कपड़ा

(३) ऊनी टाप

दस लाख पीड

दस लाख गज

हजार टन

दस लाख पीड

दस लाख पीड

हजार टन

दस लाख पीड

दस लाख पीड

दस लाख गज

दस लाख पीड

दस लाख टन

दस लाख टन

५०. नमक

५१. चीनी

८.५

१५.६

४.५

२.५

६०

५०

४०६]

(च) कपड़ा-उद्योग

१,१७६

३,७२०

८६२

०.४

—

—

१८

—

—

—

(क) लाख-उद्योग

२.७

१.१२

१,६५०

५,१०२

१,१५०

१६

१५

—

—

२१.७

१.५

—

१,०००

१५६

१००

१००

२,१००

५,३००

१,२००

१,१००

५२.३

४८

—

—

६७

५८

१०

अनुपलब्ध

३.६

२.२८

३.५५

२.२५

२,३००

२५०

२५०

२,२५०

५,८००

१,२००

१५०

७५

६०

[नियोजन : देश और विदेश]

५२

३५

३१.५

५.५

३

६.५

३

५२. वनस्पति-तेल
(घ) खली का
विस्तारक-
तत्व निष्का-
सना

(घा) बिनीले
का तेल

५३. वनस्पति

हजार टन	—	—	६३६ (खली)	३६ (तेल)	२,००० (खली)	१६० (तेल)
हजार टन	—	—	४१५ (बीज)	३७ (तेल)	८५० (बीज)	१०० (तेल)
हजार टन	१५३	२७६	४३४	३५०	५५०	५००

(ए) खनिज पदार्थ

५४. कोयला	दस लाख टन	३२	३८	—	—	६७
५५. कच्चा लोहा	दस लाख टन	३	४.७	—	—	३२

४—तृतीय पंचवर्षीय योजना की विशेषताएँ

(Characteristics of the Third Five Year Plan)

तृतीय पंच वर्षीय योजना की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। यी तो प्रत्येक योजना में ही कुछ न कुछ विशेषताएँ होती हैं, जैसे, प्रथम योजना भारत के लिए आर्थिक विकास प्राप्त करने का सबसे पहला कदम था, द्वितीय योजना में उद्योगों के विकास पर विशेष महत्व प्रदान किया गया तथा, इसी योजना काल से 'समाजवादी अर्थ व्यवस्था' तथा 'समाजवादी ढंग के समाज' की स्थापना का लक्ष्य स्थिर किया गया। इसी प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे, इसके आकार का विशालत्व, Take off stage, सन्तुलित आर्थिक विकास, बेरोजगारी दूर करने के लिये 'अत्यधिक' रोजगार की सुविधाओं का निर्माण, ग्रामीण जनता के लिये रोजगार का निर्माण, आर्थिक विपन्नताओं को दूर करने का प्रयास एवं कीमतों को बढ़ने से रोकने की व्यवस्था। इनमें से कुछ विशेषताओं पर पहले ही विवेचना किया जा चुका है, और कुछ निम्न प्रकार हैं

विशाल-आकार (Large Size)—

तीसरी योजना में सब मिला कर १०,२०० करोड़ रु० पूँजी-विनियोग करने का विचार है। इसमें से ६,२०० करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र में और ४,००० करोड़ रु० निजी क्षेत्र में लगाए जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में अन्दाजत १,०५० करोड़ रु० का धातु व्यय होगा। उसे मिला कर इस क्षेत्र का समस्त व्यय ७,२५० करोड़ रु० हो जायगा। निजी क्षेत्र में पूँजी-विनियोग में २०० करोड़ रु० की वह राशि भी शामिल है, जो पूँजी-समूह प्रयोजन से सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में ले जाई जाएगी। नीचे की तालिका में तीसरी और दूसरी योजनाओं के व्यय और पूँजी-विनियोग की तुलना की गई है।

दूसरी और तीसरी योजनाओं का व्यय और पूँजी-विनियोग

(करोड़ रुपये)

	सरकारी क्षेत्र		निजी क्षेत्र		समस्त पूँजी-विनियोग
	योजना का व्यय	चालू व्यय	पूँजी-विनियोग		
दूसरी योजना	४,६००	६५०	३,६५०	३,१००	६,७५०
तीसरी योजना	७,२५०	१,०५०	६,२००	४,०००	१०,२००

इससे प्रकट है कि तीसरी योजना का समस्त पूँजी-विनियोग दूसरी योजना के पूँजी-विनियोग से लगभग ५१ प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, सरकारी क्षेत्र के पूँजी-विनियोग और प्रस्तावित व्यय में क्रमशः लगभग ७० प्रतिशत और ५८ प्रतिशत की, और निजी पूँजी-विनियोग में लगभग २६ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

पहली योजना के समय देश की ग्रथं-व्यवस्था में वार्षिक पूँजी-विनियोग लगभग ५०० करोड़ रु० से बढ़ते बढ़ते कोई ८५० करोड़ रु० तक पहुँच गया था। दूसरी योजना के अन्त तक वार्षिक पूँजी विनियोग के १,४५० करोड़ रु० से १,५०० करोड़ रु० तक पहुँच जाने की आशा है। तीसरी योजना की समाप्ति पर वार्षिक पूँजी-विनियोग का विस्तार शायद २,५०० करोड़ रु० के आसपास पहुँच जाएगा। पहली योजना में सरकारी पूँजी-विनियोग लगभग २०० करोड़ रु० प्रतिवर्ष से आरम्भ होकर योजना समाप्ति तक ४५० करोड़ रु० हो गया था। दूसरी योजना के अन्त तक इसके लगभग ६०० करोड़ रु० और तीसरी योजना के अन्त तक कोई १,५०० करोड़ रु० हो जाने की आशा है।

विपमता का निवारण^१

ग्राम और सम्पत्ति की विपमता का निवारण करने की समस्या, किसी ग्राम तक वर्तमान विपमताओं को दूर कर देने की समस्या है, परन्तु इसके अधिक महत्त्वपूर्ण पहलू का सम्बन्ध ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्न करने से है, जिनमें अधिक विकास क्षीप्त होने के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक असमानताओं में भी स्पष्टतः कमी आए। पहले भी कई क्षेत्रों में ऐसे कुछ उपाय किए जा चुके हैं, जिनका प्रत्यक्ष परिणाम आर्थिक और सामाजिक विपमताएँ घटने के रूप में प्रकट हुआ है। इनमें से कुछ को तीसरी योजना में और आगे बढ़ाया जाएगा। उदाहरणार्थ, ग्रामीण ग्रथं व्यवस्था में भूमि-सुधारों की प्रगति से विपमता कम करने में बड़ी सहायता मिली है। काश्त की सुरक्षा और लगान में कमी करने के काम तो काफी हद तक पूरे हो चुके हैं। अगले दो-तीन वर्षों में, आराजी की अधिकतम सीमा तय करने के कानूनों पर भी प्रमल हो जाएगा। तब बहुतेरे किसान अपनी जमीन के मालिक बन जाएँगे। सिंचाई का विस्तार होने से गाँवों के विद्योपकर उन इलाकों के, जो पानी की कमी से प्रताडित थे—बहुत से गरीब लोगों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाने में मदद मिलेगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों जैसे पिछड़े वर्गों के हितार्थ बनाए गए कार्यक्रमों का प्रयोजन ही जनता के उन वर्गों को लाभ पहुँचाना है, जो वर्तमान परिस्थितियों में विकास की सामान्य योजनाओं से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। आरम्भिक शिक्षा का विस्तार (इसे तीसरी योजना में ६ से ११ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया जाएगा), छानवृत्तियों की सहायता में वृद्धि और अन्य प्रकार की सहायता, आरम्भिक स्वास्थ्य-केन्द्रों की स्थापना आदि सभी गाँवों में बने के बालों की व्यवस्था, गलेरिया-जैसे रोगों का उन्मूलन, और स्वयंसेवा-संगठनों का—सास कर स्त्रियों और बालकों के सेवा-संगठनों का—विस्तार, ऐसे काम हैं जिनसे जनता को समान अवसर मिलने के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होने में बड़ी सहायता मिल सकती है। सामुदायिक विकास-आन्दोलन का काम करने वालों से भी बार-बार तकाबा किया जा रहा है कि वे लोगों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाने और निम्न वर्गों को रोजगार दिलाने के उपायों पर अधिक ध्यान

इस क्षेत्र में वित्तीय कार्रवाइयों की भी एक प्रमुख भूमिका है। अतः उनका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि आय और सम्पत्ति की विपमता कम करने में वे सहायक सिद्ध हों। पूर्ववर्णित उद्देश्यों की सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि कम्पनी-कानून का पालन कराने वाली, कारखानों को लाइसेन्स देने वाली, नई कम्पनी खोलने के लिए पूँजी एकत्र करने की इजाजत देने वाली और विदेशों से आयात का नियन्त्रण करने वाली, आदि-जैसी शासन की विभिन्न शाखाएँ अपना-अपना काम अधिक समन्वयपूर्वक करें। कम्पनियों का नियमन करते समय कम्पनियों द्वारा कई कम्पनियों में पूँजी लगाए जाने और कई-कई कम्पनियों के एक ही डाइरेक्टर होने जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए कानून मौजूद हैं, परन्तु ये कानून अमल में कहीं तक आ रहे हैं, यह देखने की जरूरत है। देखने की एक और बात यह है कि निजी पूँजी संचालन की लिए करो की जो रियायत दी जाती है अथवा बढ़ावा देने के लिए इसी प्रकार की अन्य कार्रवाइयों की जाती हैं, उन पर किस प्रकार अमल होता है। इन रियायतों और कार्रवाइयों का निश्चय ही महत्त्व है, परन्तु देखना यह है कि अमल में इनका नतीजा, योजना में शामिल विभिन्न उद्योगों के विकास-कार्यक्रमों की पूर्ति के रूप में निकलता है, या नहीं। आय और सम्पत्ति की विपमता कम करने और आर्थिक क्षमता का केन्द्रीयकरण रोकने की समस्याएँ बड़ी पेचीदा हैं और द्रुत प्रगति की समस्याओं के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है।

स्वयं स्फूर्ति विकास अवस्था (The Take off Stage)—

नियोजन द्वारा जहाँ भी आर्थिक उन्नति का प्रयास किया जाता है वहाँ इस बात की चेष्टा की जाती है कि नियोजन को एक दीर्घकालीन तत्त्व मान कर चला जाये। इसका खास कारण यह होता है कि जब तक 'दीर्घकाल' की दृष्टिकोण में रख कर नियोजन पद्धति को प्रपनाई नहीं जाती, तब तक वह अपूर्ण समझा जाता है। हमारे नियोजनों ने भी स्पष्ट वाक्यों में कहा है

“हमारे विकास में जो परिस्थितियाँ बाधक मिट रही हैं और जिन पर योजना-निर्माताओं को ध्यान देना है, वे ये हैं लोगों की कम ग्रामदानी और रहन-सहन का नीचा स्तर, अधिकांश लोगों का खेती में लगा होना, बड़े पैमाने पर अर्द्ध-रोजगारी, उपकरणों और तकनीकी जानकारी के लिए अधिक उन्नत देशों पर निर्भर करना और आर्थिक उन्नति की धीमी चाल। इन सब आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की जड़ें बड़ी गहरी हैं और इन्हें हल करने के लिए विकास की एक दीर्घकालीन योजना बनानी पड़ेगी। जो राष्ट्र गरीबी से निवृत्त कर उन्नति के मार्ग पर प्रगसर होना चाहे, उसे बहुत समय तक और लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। यही कारण है कि पहली योजना में विकास की समस्या को २५ या ३० वर्ष-व्यापी कार्य की दृष्टि से देखा गया था, और प्रारम्भिक पाँच वर्षों के लिए उसी हिसाब से कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे।”

यद्यपि कतिपय कारणवश विकास का कार्य अपेक्षाकृत छोटे भागों में बांट कर करने में आसानो होती है, तथापि वस्तुतः वह एक ही सम्बन्धी और निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया होगी है, और उसमें प्रत्येक भाग के लक्ष्य और प्राथमिकताएँ एक दूसरे के साथ एक बड़े उद्देश्य द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसी कारण, पहली और दूसरी योजनाओं की कल्पना, देश के एक दीर्घकालीन सामाजिक और आर्थिक विकास-कार्यक्रम की दो मजिलों के रूप में की गई। पहली योजना में १९५०-५१ से १९८०-८१ तक के ३० वर्ष की आर्थिक उन्नति का चित्र प्रस्तुत करके अनुमान लगाया था कि देश की राष्ट्रीय आय १९७१-७२ तक और प्रति व्यक्ति आय १९७७-७८ तक दुगुनी हो जाएगी। इस अनुमान का आधार ये पूर्व-कल्पनाएँ थी कि देश की प्रावादी वृद्धि रफ्तार से बढ़ेगी, विकास की हरेक मजिल में राष्ट्रीय आय की वृद्धि का कितना भाग फिर पूँजी-विविनियोग में लगेगा, और जो पूँजी लगाई जाएगी, उससे अतिरिक्त उत्पादन के रूप में कितना लाभ होगा। दूसरी योजना के समय, इन पहले के अनुमानों और कल्पनाओं पर पहली योजना में प्राप्त अनुभवों से लाभ उठा कर, पुनः विचार किया गया और यह मत व्यक्त किया गया कि १९५०-५१ की तुलना में, देश की राष्ट्रीय आय १९६७-६८ में और प्रति व्यक्ति आय १९७३-७४ में ही सम्भवतः दुगुनी हो जाएगी। उस समय एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य यह रखा गया था कि पाचवी योजना के सम्पत्ति-काल तक खेती पर आधारित रहने वालों का अनुपात प्रावादी के लगभग ६६ या ७० प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घट कर लगभग ६० प्रतिशत रह जाएगा। दूसरी योजना में त्रिन लक्ष्यों की कल्पना की गई है, जिनकी पूर्ति हो वातों पर निर्भर करेगी—पहली तो यह, कि प्रावादी में वृद्धि किस हिसाब से होती है, और दूसरी यह कि अगली तीन योजनाओं में जो प्रयत्न किया जाएगा, उसका परिणाम और स्वरूप क्या होगा ?

केवल भारतीय नियोजन में ही नहीं, बल्कि संसार के उन सभी राष्ट्रों में, जिन्होंने निर्वाजन द्वारा आर्थिक विकास को प्राप्त करने का प्रयास किया है अथवा कर रहे हैं, नियोजन को एक दीर्घकालीन विकास का तत्त्व समझा है। इस प्रकार, नियोजन द्वारा एक सुनिश्चित, सुव्यवस्थित और सन्तुलित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिये नियोजन पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित पाँच भागों में बाँटा जाता है।

१—परम्परागत समाज (The Traditional Society),

२—स्वयं स्फूर्ति अवस्था के पूर्व की आर्थिक स्थिति (Pre-Take off Economic Stage) ;

३—स्वयं स्फूर्त आर्थिक अवस्था (The Take-off stage or The Self-sustained Growth Stage) ;

४—आर्थिक 'परिपक्वता' की ओर अग्रसर की स्थिति (Drive to Economic Maturity), एवं

५—अधिक उपभोग की अवस्था (Stage of extensive mass consumption)

प्रथम पंचवर्षीय योजना का जब भारत में निर्माण किया गया था तो उससे पहले देश की दशा अत्यन्त दयनीय थी। सैकड़ों वर्षों के विदेशी शासन के कारण, द्वितीय महायुद्ध के कारण, देश में किमी प्रकार के सन्तुलित या सुव्यवस्थित आर्थिक या व्यापारिक नीति के अभाव से, देश में फैली हुई बेकारी तथा अत्यधिक जनसंख्या के दबाव के कारण देश का आर्थिक स्तर दिन-प्रति-दिन अवनति की ओर जा रहा था। यही कारण था कि स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् जब देश में योजना को अपनाने के विषय में विचार विमर्श हुआ, और अन्त में, प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया तो इस बात की चेष्टा की गई कि इस योजना काल में इस बात का पूरा प्रयास किया जाए कि इस काल में भविष्य नियोजनों के लिए एक सुदृढ़ पृष्ठ भूमि तैयार की जा सके। इसी के साथ-साथ, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, इस बात की चेष्टा की गई कि इस काल में कृषि उत्पाति में अत्यधिक विकास सम्भव हो सके। साथ ही साथ कृषि से सम्बन्धित अन्य विषयों पर भी समान महत्त्व दिया गया था। नियोजन की प्रथम सोपान (परम्परागत मजमा) की विशेषताओं के आधार पर ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया था। प्रथम योजना में इस बात की पूरी चेष्टा की गई थी कि 'विकसमान' आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के अन्तर्गत ही योजना कार्य चले।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जब निर्माण किया गया था तब तक 'सफल नियोजन' बनाने योग्य पृष्ठ भूमि देश में उत्पन्न हो चुकी थी। यही कारण था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 'विकसमान' आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के अन्तर्गत ही नियोजन नहीं किया गया था। राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त, समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना का मिद्धान्त, तीव्रगति से औद्योगिक विकास के सिद्धान्तों का अपनाना इस बात की पुष्टि करता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 'स्वय-स्फूर्ति आर्थिक अवस्था के पूर्व की आर्थिक स्थिति' की प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया था। इसी उद्देश्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। उद्योगों के तीव्र विकास और 'सम्पूर्ण रोजगार' का उद्देश्य इमांनिये रखा गया था कि इस काल में प्रत्येक नागरिक की दार्थिक और वास्तविक आमदनी में अत्यन्त वृद्धि हो सके। क्योंकि जब तक देश के समस्त नागरिकों के प्रतिवर्ष आमदनी में वृद्धि न हो, तब तक देश में वचत, विनियोग और पूँजीगत उत्पादन की मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकती। स्वय-स्फूर्ति आर्थिक स्थिति की भिन्नि (Foundations) इसी पर निर्भर होनी है कि देश की तीव्र आर्थिक विकास के लिये वचत, विनियोग और

पूँजीगत उत्पादन में इतनी वृद्धि हो जाये कि भविष्य में आर्थिक विकास के लिये किसी का सहारा लेना न पड़े। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, बचत, विनियोग एवं पूँजीगत उत्पादन की वृद्धि के लिये पर्याप्त प्रयास हुए, एवं इस ओर कुछ भ्रष्टताएँ भी प्राप्त हुई।

स्वय-स्फूर्त स्थिति (Take off Stage) के विषय में यह बताया जाता है कि स्वय-स्फूर्त आर्थिक अवस्था की प्राप्ति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय का कम से कम १०% भाग का विनियोग हो। इसी के साथ साथ यह भी आवश्यक समझा जाता है कि कृषि, उद्योग और अन्य 'क्षेत्रों' का सन्तुलित विकास हो। इस विषय में एक बात ध्यान रखना आवश्यक है, वह यह कि अधिकसित या घट-विकसित देशों के लिये यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय का १०% से अधिक भाग का विनियोजन राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिये प्रयत्न हो। इस स्थिति को प्राप्त करने के विषय में यह भी कहा जाता है कि देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए जिससे 'विदेशी विनिमय' पर देश को सम्पूर्ण रूप से आश्रित न रहना पड़े। विदेशी व्यापार में अनुकूल स्थिति को प्राप्त करने से भी यह स्थिति काफी हद तक दूर हो जाती है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण स्वय-स्फूर्त आर्थिक स्थिति में अनुसार की गई है। इसी कारण योजना में इस बात का पूरा प्रयास किया गया है कि कृषि और उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों का द्रुत किन्तु सन्तुलित विकास हो। इस बात की भी चेष्टा की गई है कि इस बात की ओर दृष्टि रखी जाय कि विदेशी विनिमय के कारण योजना कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। साथ ही साथ योजना में इस ओर भी संकेत किया गया है कि इस योजना का लक्ष्य विनियोजन दर में वृद्धि करना है जिससे योजना काल में ही भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाये कि हम उसे स्वय-स्फूर्त आर्थिक स्थिति मान सकें।

तीसरी योजना के उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों का निश्चय करते समय इन बातों को ध्यान में रखा गया है पूर्ववर्णित सामाजिक आदर्श, योजना-काल में अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएँ, दीर्घकालीन विकास का वह रूप, जिसके साथ योजना जुड़ी है, और गत दो योजनाओं की अवधि में हुई वास्तविक प्रगति। आशा है कि पहली दो योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय में लगभग ४२ प्रतिशत की वृद्धि हो चुकेगी। तीसरी योजना का लक्ष्य, राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष लगभग ५ प्रतिशत वृद्धि करना है। इस प्रकार, १९५१ से १९६६ तक के पन्द्रह वर्षों में, राष्ट्रीय आय में समस्त वृद्धि लगभग ८० प्रतिशत हो सकेगी। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि पूँजी विनियोग की दर, जो दूसरी योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय का लगभग ११ प्रतिशत होगी, तीसरी योजना के अन्त तक लगभग १४ प्रतिशत हो जाय।

तीसरी योजना का एक मुख्य लक्ष्य यह है कि देश आत्मचालित ढंग से प्रगति करने के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ जाए। मूलतः प्रगति को आत्मचालित बनाने का अभिप्राय यह है कि राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में वचत और पूँजी-विनियोग की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि राष्ट्र की आय में निरन्तर और अधिकाधिक वृद्धि होती चली जाए। इस समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू देश में पूँजीगत तथा अन्य सामग्रियाँ स्वयं बना सकने की इतनी क्षमता उत्पन्न करना है कि जितनी मात्रा में पूँजी लगाने की बात सोची जा रही है, वह सार्थक सिद्ध हो जाए। साथ ही, उन यन्त्रों के डिजाइन बनाने और उन्हें चला सकने की योग्यता का सम्पादन करना भी आवश्यक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, एक अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में, निर्यात के द्वारा अल्पकाल में इतनी वचत कर लेना बहुत कठिन होता है कि विदेशों से मंगाए गए अपनी आवश्यकता के सभी उपकरणों का मूल्य उसी से चुकाया जा सके। इसलिए अपनी निर्यात की कमाई को बढ़ाने का अधिकतम प्रयत्न करना होगा—विदेशों के साथ लेन-देन का हिसाब बराबर करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। फिर भी, भुगतान-सन्तुलन के एक बड़े भाग की पूर्ति, पूँजीगत सामान विदेशों से मगाने के स्थान पर उसका बड़े परिमाण में स्वदेश में निर्माण करके ही करनी होगी। इसीलिए, तीसरी योजना में पूँजी-विनियोग के स्वरूप और परिमाण का निश्चय करते समय विदेशों के हिसाब को दस वर्ष की अवधि में बराबर तथा स्थिर कर देने के लक्ष्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

५—तृतीय पंचवर्षीय योजना की आलोचना

(Criticism of the Third Five Year Plan)

तृतीय पंचवर्षीय योजना की अभी केवल रूपरेखा ही प्रकाशित हुई है। इस कारण इसकी पूर्णरूप से आलोचना करना या समर्थन करना अभी सरल नहीं है। वास्तव में, प्रारम्भिक रूपरेखा और वास्तविक 'योजना' में काफी प्रभेद रहता है। फिर भी, रूपरेखा में जो विशेष कमियाँ दिखाई देती हैं, उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं

तृतीय पंचवर्षीय योजना का आकार अत्यन्त विशाल रखा गया है। १०,२०० करोड़ रुपया भारतवर्ष जैसे अविकसित देश के लिए एक विशाल रकम है। द्वितीय योजना में इस राशि के मुकाबले काफी कम रुपया नियोजन कार्य के लिए उल्लेख किया गया था, किन्तु उस रकम की व्यवस्था भी पूरी तरह से न हो पाई थी। यही कारण था कि द्वितीय योजना काल में (Plan outlay) को पुनः निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। भारत की जनता के जीवन स्तर में कोई विशेष उन्नति द्वितीय काल में सम्भव न हो सकी। फिर भी यह आशा करना कि तृतीय योजना काल में १०,२०० करोड़ रु० की व्यवस्था सम्भव हो सकेगी एक 'कल्पना'

मात्र है। (अब तो इस बात की आशा व्यक्त की जा रही है कि यह रकम बढ़ कर १२,००० करोड़ रु० होने जा रहा है।) योजनाधिकारियों की यह एक बड़ी भूल है, जिसमें विशेष सुधार की आवश्यकता है। यह कहा गया है कि इस में जब प्रारम्भिक रूप से नियोजन का कार्य शुरू किया गया था तो Plan outlay इस रकम से बड़े गुनी अधिक थी जब कि आज के भारत से उस समय के रूम की आर्थिक स्थिति अधिक दयनीय थी। किन्तु हमारे नियोजक इस बात को भूल जाते हैं कि इस समय भारत में जितनी मुद्रा प्रसार एवं ऊँची कीमतें हैं, वैसी स्थिति इस के प्रारम्भिक नियोजन काल में नहीं थी। वास्तविक सत्यता तो इस बात की है कि चाहे किसी भी रूप में हम देखें, यह तत्त्व सत्य है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो Plan outlay है वह अत्यन्त विशाल है, एवं उसकी पूर्ति की सम्भावनाएँ अत्यन्त कम हैं।

यद्यपि नियोजन कार्य को प्रारम्भ हुए भारतवर्ष में प्रायः १० वर्ष हो गये, तथापि भारत सरकार अभी जनता में यह विश्वास उत्पन्न न कर सकी कि नियोजन का कार्य जनता की भलाई के लिये ही है। समस्त जनता—विशेषतः से ग्रामीण जनता—यह सोचती है कि नियोजन में उन्हें किसी भी रूप से लाभ न है और न रहेगा। उनका मत है कि नियोजन का केवल उद्देश्य 'सरकारी फायदे' है। सरकार की ओर से योजनाओं को सफल कर देने के लिये जितना प्रचार होना आवश्यक था उतना प्रचार नहीं हो पाया। इसका परिणाम यह रहा कि ग्रामीण एवं साधारण जनता अभी योजना का अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता, स्वरूप, प्रकार एवं लाभ आदि के विषय में अनजान है। उन्हें ठीक तरह से समझाने की व्यवस्था करनी चाहिए कि 'नियोजन उन्हीं के लिये, उन्हीं की भलाई के लिए है' कोरी 'सरकारी योजना' नहीं है। देशी तथा विदेशी प्रेक्षकों ने यह सही ही कहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना में जो विकास कार्यक्रम तैयार किए गए, वे लोगों के मन में योजनाओं के प्रति थका और उल्लास उत्पन्न करने में असमर्थ रहे हैं। योजना आयोग के 'मूल्यांकन कार्यक्रम समूह' ने अप्रैल सन् १९६० में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि लोग हर एक विकास कार्यक्रम को 'सरकारी फायदे' की स्कीम समझते हैं। यही कारण है कि अधिकांश व्यापारियों में सब साधारण का रवैया विकास कार्यक्रम की सफलता के पक्ष में नहीं है इसमें अधिकांश दोष अधिकारियों का है। साथ ही राज्य-विधानसभाओं और समद में जनता के प्रतिनिधियों का भी दोष है। उन्हें विज्ञान के कार्यों में जनता का नेतृत्व करना चाहिए। इसके साथ ही बहुत कुछ दोष उन राज्य सरकारों का है, जो शासन के विकेन्द्रीकरण के लिए तत्पर नहीं। प्रजातन्त्र में विकास योजनाओं के प्रति जनता में विश्वास पैदा करने के लिए विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। केवल आध्र और राजस्थान में ही इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। यद्यपि वहाँ पर कुछ दिक्कत आई है किन्तु इस बात के बिना दृष्टिगोचर हुए हैं कि लोगों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने जिला-

परिषद् और क्षेत्र समिति बिल के द्वारा जिला परिषदों और क्षेत्रीय समितियों को कुछ अधिकार देने जा रही है, पर शासन का तत्व अपने पास ही रखेगी—इसका नाम जनतंत्रीय विकेन्द्रीकरण होगा। यह सभी बात अभी केवल 'योजना स्तर' पर ही है। इनमें हमारी सरकार को कितनी सफलता मिलेगी इसको शायद कोई नहीं जानता (१)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programmes)—सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारम्भ किए ६ वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा देहाती क्षेत्रों के लिये विकास एवं कल्याण कार्यों के हेतु बनायी गई थी—और आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखा गया था। इस बात की आशा की गई थी कि यह ग्रामों में आर्थिक क्रान्ति लाने में सफल होगा और इस प्रकार सारा देश लाभान्वित होगा। इस बात की आशा की गई थी कि एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने से ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बेरोजगारी तथा अर्ध-बेरोजगारी के कारण जो अपार मानव शक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है उसका उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकेगा। इससे आर्थिक क्रान्ति का सूत्रपात होगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। किन्तु वह उद्देश्य सफल न हो सका।

यह आशा व्यक्त की जा रही है कि तीसरी योजना के अन्त तक लगभग २१०० खण्ड अपने पहले सोपान में होंगे, लगभग २,००० खण्ड दूसरे सोपान में होंगे और १,००० से अधिक खण्ड अपने विकास-कार्यक्रम के दस वर्ष पूरे कर चुकेंगे। सामुदायिक विकास और सहकारिता के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों पर तीसरी योजना में कुल मिलाकर ४०० करोड़ रुपये की व्यय की व्यवस्था है।

परन्तु, हमें देखना तो यह है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक सम्भव हो पाती है? प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सामुदायिक विकास, सहकारिता आदि के लक्ष्य तीसरी योजना के मुकाबले में कम था, परन्तु उनकी पूर्ति भी सम्भव नहीं हो पाई थी। उस रूप में यह आशा करना कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव होगी, शायद 'आशा' से भी अधिक होगी।

भारतीय नियोजन की सफलता का सबसे बड़ा बाधक प्रबन्ध और प्रशासन की त्रुटियाँ हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से सभी वर्गों द्वारा इस आर सकेत किया जा रहा है कि हमारे प्रशासन व्यवस्था में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। किन्तु खेद का विषय है कि अब तक प्रशासन भ्रष्टाचारी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जब कि विनियोजन कम मात्रा में हुआ था, प्रशासन की अक्षमता के कारण बहुत से प्रयासों में कोई

विशेष सुविधा प्राप्त न हो सकी। उसी सदर्थ में यह कहा जा सकता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जब Total Outlay इतना विशाल है, एवं जब सभी कार्य विशाल रूप से करने की आवश्यकता होगी, हमारे प्रबन्धक एवं प्रशासन सम्बन्धी कार्यकर्ता समय एवं आवश्यकतानुसार कार्य नहीं कर सकेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि नियोजन के सभी उद्देश्य तथा लक्ष्य अधूरे रह जायेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो प्रशासन सम्बन्धी सभी विषयों में गुरुत्वपूर्ण सुधार करने पड़ेंगे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी, प्रथम और द्वितीय योजनाओं की तरह सामाजिक सेवाओं के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यह अत्यन्त दुःख है। सच तो यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सामाजिक सेवाएँ ऐसे हैं जिन पर अधिकतम महत्त्व प्रदान करना चाहिए। इसका कारण यह है कि लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र ठीक प्रकार से सभी कार्य कर सकता है कि जबकि देश के सभी नागरिक शिक्षित, बुद्धिमान एवं स्वस्थ हों, इनके अभाव में देश का आर्थिक विकास ठीक प्रकार से एवं सन्तुलित रूप से नहीं हो पाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में यह आशा प्रगट की गई थी कि इसमें सामाजिक सेवाओं पर अधिक दल दिया जायेगा। किन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा ने इस आशा को ममूल नष्ट कर दिया है।

देश से-आवास (housing) सम्बन्धी कठिनाइयाँ अत्यन्त विशाल रूप में विद्यमान हैं। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में आवास सम्बन्धी कठिनाइयों के विषय में सभी ज्ञात है। किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि हमारे नियोजकों ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण में इस और कोई ध्यान नहीं दिया। आवास सम्बन्धी कठिनाइयाँ जब तक पूर्ण रूप से दूर नहीं हो जाती तब तक देश के समस्त नागरिकों के जीवन-स्तर एवं 'जीवन सुख' की मात्रा में वृद्धि एक कल्पना मात्र रह जायेगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सरकार को इस बात का भरसक प्रयास करना चाहिए कि विभिन्न स्तर और क्षेत्रों के नागरिकों की आवास सम्बन्धी समस्त कठिनाइयाँ पूरी तरह से दूर कर सकें।

“विदेशी विनिमय की कठिनाई भी एक बड़ी समस्या है किन्तु इससे भी अधिक विकट समस्या आंतरिक वित्त (internal finance) की है। जब तक देश में द्रव्य के आन्तरिक साधनों की उपलब्धि न होगी, तब तक बड़ी मात्रा में मिलने वाली विदेशी विनिमय को धनराशि किसी काम की नहीं होगी। जब हम किसी कारखाने में १ करोड़ रुपये का विनियोग करते हैं तो उसका ५० प्रतिशत देश के आन्तरिक साधनों पर व्यय करना पड़ता है और बाकी का ५० प्रतिशत बाहरी मशीनरी तथा अन्य कल-पुर्जों में व्यय करते हैं जिसके लिए हमें पूर्ण रूप से देश के बाह्य द्रव्य की सहायता नहीं मिलती, जबकि किसी भी नये उत्पादन कार्य को शुरू

करने के लिये हमें ६० प्रतिशत से लेकर ६५ प्रतिशत तक आंतरिक पूँजी व द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब तक देश के आंतरिक साधनों का विकास नहीं किया जायेगा, तब तक हमारे लिये योजना में निर्धारित, निजी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लक्ष्यों को, पूरा करना कठिन होगा। और जब निजी क्षेत्र योजना के लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो सार्वजनिक क्षेत्र के लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की आय का मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र ही है।”

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण कार्य करती है ; लेकिन धन सम्बन्धी जरूरतों की अन्तिम पूर्ति वचन द्वारा होनी है। कर की वृद्धि के कारण निजी बचत का क्षेत्र एकदम सहाय्य हो गया है। द्रव्यपूर्ति का दूसरा साधन सामूहिक बचन (Corporate Saving) है, किन्तु सरकारी गलत कदमों के फलस्वरूप यह स्रोत समाप्त हो रहा है। सन् १९६० के बजट पर बोलते हुए वित्तमन्त्री ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया था।

“विदेशी विनियोग के द्वारा भी द्रव्य की पूर्ति में सहायता मिलती है, लेकिन विदेशी पूँजी तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कि देश के अन्दर उसके लिए उपयुक्त वातावरण न बनाया जाय। जिन लोगों ने चीन का भ्रमण किया है वे जानते हैं कि योजनाओं की सफलता के लिए चीन में विदेशी पूँजी किस तरह प्राप्त करते हैं। वहाँ पर ७०% पूँजी की आवश्यकता को दीर्घकालीन आधार पर पूँजीगत वस्तुओं के रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों में हम इस तरह का सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते। जब तक हमारे देश में विदेशी पूँजी को आकर्षित तथा प्रोत्साहित करने के लिए उचित वातावरण पैदा नहीं किया जाएगा तब तक विदेशी पूँजी से प्राप्त सहायता की धनराशि में कमी होती जायगी।”

“ऐसा सुझाव दिया गया है कि द्रव्य बाजार को सरल बनाने के लिए मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाय। कभी-कभी लोगों की क्रयशक्ति पर रोक लगाने और द्रव्य पर आवश्यक नियन्त्रण करने का भी सुझाव दिया गया है, जिसके फलस्वरूप उपभोग में कमी हो और कृत्रिम रूप से वस्तुओं की पूर्ति बढ जाय। किन्तु ये कार्य योजना के उद्देश्य के विपरीत हैं। सब कुछ होते हुए हमारे नियोजन का उद्देश्य रोजगार की अधिक से अधिक सुविधाएँ उत्पन्न करना तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। हम कीमतों को कम करने की कोशिश करते हैं, जिनसे बेरोजगारी फैलती है और लोगों का जीवन स्तर गिरता है। इतने सब कार्यों के होते हुए भी, हम देखते हैं कि कृषि पदार्थों की कीमतें बढ़ती है। इस प्रकार एक ओर तो औद्योगिक उत्पादन की वस्तुओं जैसे, बपड़े की कीमतें गिरती हैं, मित्तों के पाम स्टॉक समाप्त हो जाता है, उपभोग कम होता जाता है, और दूसरी ओर कृषि उत्पादन की वस्तुओं की कीमतें ऊँची दर पर स्थिर हो जाती है। इसलिए यह

स्पष्ट है कि मुद्रा-सकुचन अथवा साख नियन्त्रण का कृषि वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इन वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि को रोकने के लिए सर्वोत्तम ढंग यह है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाय ।”

“सरकार विभिन्न स्थानों द्वारा ‘द्रव्य-बाजार’ से द्रव्य को वापस ले लेती है— उत्पादन कर के रूप में, कर्ज के द्वारा तथा ‘अतिरिक्त बजट’ (Surplus budgets) के द्वारा । इस तरह से इकट्ठा किया हुआ धन बैंकों के पास शीघ्र नहीं लौटता । ग्रन्थ देशों में एक रुपये के नोट ६ बार बाजार में चलने को आते हैं जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता । अधिकतर सरकारी व्यय या तो विदेशों से मास खरीदने में व्यय किया जाता है या देहाती क्षेत्र के उन लोगों पर व्यय किया जाता है जो बैंकों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते अथवा जिनमें दिनियोग करने की प्रवृत्ति नहीं होती । हमारी वैकिक व्यवस्था भी इतनी संगठित नहीं है कि वह देहाती क्षेत्र से धन आकर्षित कर सके ।”¹

तृतीय पंचवर्षीय योजना की एक और बड़ी कमी यह है कि इसमें ‘पूँजीगत उत्पादन’ की उत्पत्ति में उतनी प्रमुखता प्रदान नहीं की गई है जितनी कि आशा की जाती थी । किन्ती भी देश की नियोजन व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि जैसे-जैसे दिन गुजरते जाय, वैसे ही वैसे देश में भारी उद्योग की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए, देश में ‘उत्पादन वस्तुयें’ और ‘उपभोग की वस्तुयें’ अधिकतम मात्रा में उत्पन्न होनी चाहिए, ताकि कुछ वर्षों के पश्चात् देश सभी प्रकार की वस्तुओं, मशीनों, यन्त्रों और भारी मशीन आदि के विषय में आत्म-निर्भर हो सके । द्वितीय योजना में भी ‘उपभोग की वस्तुओं’ के निर्माण पर अधिक बल प्रदान किया गया था, जिससे देश के प्रौद्योगीकरण में बाधाएँ उत्पन्न हो गई थी । तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात, सीमेंट, लोहा, मशीन, यन्त्र आदि के निर्माण में जितना अधिक बल प्रदान करना चाहिए था, उतना बल प्रदान नहीं किया गया है । इस ओर सरकार तथा योजना आयोग को अधिक ध्यान देना चाहिए ।

कृषि और वाद्यान्न के विषय में भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है जो वास्तव में दुःख की बात है । कृषि-प्रधान देश होने के कारण प्रायः ७० प्रतिशत जनता कृषि-आय पर ही आशरित है । उस परिस्थिति में कृषि में उन्नति न होने का या राख पदार्थ के विषय में आत्म-निर्भर न होने का एक सहज परिणाम यह है कि देश अभी तक दरिद्र बना हुआ है । भारत के पास इतना अधिक प्राकृतिक सम्पत्ति के होते हुए भी भारतीय जनता दरिद्र है, क्या यह दुःख और लज्जा की बात नहीं है ? योजना आयोग को अब से कई वर्ष पहले ही यह देख लेना चाहिए था कि कृषि पद्धति में, भूमि सस्करण में और कृषि उपज के मामले में देश सम्पूर्ण रूप से आत्म-

¹ L N Birla's speech in the Annual Meeting (1957) of Indian Chamber of Commerce and Industry.

निर्भर हो पाया है। अब तक प्रतिवर्ष लाखों रुपये का अनाज और कृषि उपज विदेशों से मँगाना पड़ता है; फिर भी देश की जनता को अधिक दाम देकर जीवन-रक्षक वस्तुओं को प्राप्त करना पड़ना है।

“बेरोजगारी फैलाने के लिये नियोजन करो” एक कहावत सी हो गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण से पहले देश में जितनी बेरोजगारी थी, प्रथम योजना की समाप्ति पर उससे अधिक बेरोजगारी देश में फैल गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने यह दावा किया था कि इस नियोजन काल में (१९५६-६१) देश से बेरोजगारी समाप्त हो जायेगी। परन्तु, फल इसका विपरीत ही रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण काल में देश में जितनी बेरोजगारी थी उससे अधिक इस समय देश में बेरोजगारी विद्यमान है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के विषय में यह आशा करना कि इस काल में देश की बेरोजगारी की अवस्था में किसी प्रकार का सुधार होगा, सम्पूर्ण रूप से अभास्यक होगा। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि हमारे नियोजक देश से बेरोजगारी दूर करने में पूर्णतः असमर्थ रहे हैं। उन्हें इस बात के लिये पूरी तरह से प्रयास करना चाहिये कि देश से बेरोजगारी सम्पूर्ण रूप से दूर हो जाये।

नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के जीवन-स्तर और उपभोग के स्तर में वृद्धि करना, विपन्नता का निवारण और राष्ट्रीय आय में द्रुत वृद्धि करना होता है। यह सभी सम्भव हो सकता है जबकि नियोजन सन्तुलित एवं सुव्यवस्थित हो। नियोजन को भारत में प्रारम्भ हुए १० वर्ष हो गये हैं, किन्तु जनता के वास्तविक आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पाई है। बेरोजगारी अभी विद्यमान है। मनुष्यों के जीवन स्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है। प्रायः सभी वस्तुओं के कीमतों में अत्यन्त वृद्धि हो गई है। आवास की कठिनाई, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, आय में वृद्धि न होना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हमारे नियोजक उद्देश्यों की प्राप्ति में अग्रफल रहे हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वित होना काफी हद तक देश के आन्तरिक वृद्धि और विनियोग एवं विदेशी सहायता पर निर्भर है। यह एक जटिल समस्या है। आन्तरिक वृद्धि की मात्रा में वृद्धि न होने का कारण यह है कि नागरिकों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि नहीं हो पाई है, वेतन में वृद्धि नहीं हो पाई है, बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि हो गई है। इनके साथ देश की औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं व्यवसाय सम्बन्धी नीति दोषपूर्ण है। इन सब बातों का प्रभाव यह है कि आन्तरिक वृद्धि एवं विनियोग उस स्तर पर पहुँच नहीं पायेगा जिसकी आशा व्यक्त की गई है। साथ ही साथ विदेशी सहायता के विषय में भी दृढ़ता से यह कहना कि वह ठीक समय पर प्राप्त हो सकेगा सम्भव नहीं है क्योंकि वह बहुत सी बातों पर—जिनमें राजनैतिक वातावरण भी है—पर निर्भर करता है। इस प्रकार, इस

बात का पूरा डर है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिन "साधनों" का उल्लेख किया गया है, वह उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, एव उसी कारण, नियोजन भी सफल न हो पायेगा।

कीमतों में वृद्धि औद्योगिक नीति की त्रुटियाँ, मुद्रा प्रसार आदि कुछ और कारण हैं जिनके फलस्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना के सफल होने की आशा कम है। यद्यपि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि 'कीमतों की वृद्धि' एव 'मुद्रा-प्रसार' पर नियन्त्रण किया जायेगा, किन्तु उनकी सफलता के विषय में हमें सन्देह है। इस 'विशाल' योजना को कार्यान्वित करने के लिये मुद्रा प्रसार की अत्यन्त आवश्यकता पड़ेगी एव इसका प्रत्यक्ष परिणाम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगा। इससे देश के नागरिकों का जीवन तथा उपभोग का स्तर ऊँचा न हो पायेगा, बचत नहीं हो पायेगी, बचत के अभाव में विनियोग नहीं हो पायेगा। इस प्रकार, योजना के लक्ष्य प्राप्त न हो सकेंगे। औद्योगिक एव व्यवसायिक नीति में त्रुटि के कारण तथा 'राष्ट्रीयकरण' के भय से निजी क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार आशानुसार न हो पायेगा।

केन्द्रीय नियोजन और राज्यों के नियोजनों में कोई सामंजस्य रखने की चेष्टा नहीं की गई है। समस्त देश में नियोजन का लक्ष्य, उद्देश्य, तरीके, प्राथमिकताएँ आदि एकसी होनी चाहिये। किन्तु भारत में जो योजनाएँ निर्माण की गई हैं उनमें यह बात नहीं पाई जाती। प्रत्येक राज्य ने अपनी इच्छानुसार, आवश्यकतानुसार एव जनता के 'दबाव' के अनुसार अपने अपने राज्य के लिये नियोजन तैयार किये हैं। उनके आदर्शों एव लक्ष्यों में एव केन्द्रीय नियोजन में अत्यन्त असामंजस्य है। हमका परिणाम यह होगा कि न तो समस्त राष्ट्र में और न विभिन्न राज्यों में ठीक तरह से आर्थिक विकास हो पायेगा। हमारे निोजकों को इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिये कि केन्द्रीय नियोजन और राज्यों के नियोजनों में सामंजस्य बनाये रखें, क्योंकि उभी रूप में नियोजन के पूरे लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के विषय में यह कहा गया है कि यह Take off Stage है। यह भी, वास्तविक परिभाषा के अनुसार, गलत है। इसका कारण यह है कि नियोजन की Take off stage होने के लिये यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय का कम से कम १०% भाग विनियोजित हो। भारत जैसे अवििकसित देश के लिये तो यह प्रतिशत और अधिक होना चाहिये। परन्तु भारत में अभी राष्ट्रीय आय का १०% भाग भी विनियोजित नहीं होता है। यह सब कुछ कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण तृतीय योजना के सफल होने में सन्देह है।

तृतीय भाग

विदेशों में नियोजन एवं आर्थिक व्यवस्था

अमेरीका का पूँजीवाद^१ (American Capitalism)

१—प्रारम्भिक तथ्य (Preliminary Concepts)

जिस प्रकार सोवियत रूस केन्द्रीय नियोजन का आदर्श है, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था का। संयुक्तराज्य में आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक उत्थिति का होना इस बात का स्वयं प्रमाण है कि यह सोचना कि देश की आर्थिक उत्थिति केवल केन्द्रीय नियोजन द्वारा ही हो सकता है, गलत है। आर्थिक उत्थान के लिए, प्राकृतिक साधनों की प्राप्ति के साथ साथ सबसे अधिक आवश्यक यह है कि जनता एवं सरकार दोनों ही अग्रसर होने को इच्छुक हों। सरकार तो इस प्रयास में जनता की सहायता ही कर सकती है। यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक नीति के विषय में सत्य है। स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था अपनाने के उपरान्त भी अमेरिका सब ओर से खुशहाल है।

"संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य जनता का सम्पन्न होना सर्व विदित है।^२ यह सत्य है कि ससार की छ प्रतिशत जनता तथा ७ प्रतिशत भूखण्ड से हम ससार

1 (Courtesy: The U S Embassy and U S I S in New Delhi) This chapter is based on the Literature, mentioned at relevant places, kindly sent by the Director of Information, U S I S, New Delhi. He also very kindly granted permission to reprint.

2 'The general prosperity of the United States is well known. The fact that with six per cent of the world's people and seven per cent of the world's land area we produce one-third of the world's goods like other similar statistics about our economy are common knowledge. They need no elaboration here.'

Life in America—A Progressive Economy—W G Brown, Charge d' Affairs, American Embassy, New Delhi, at the Inauguration of Life in America, A Progressive Economy' Exhibition, Delhi 'Varsity, Sept 1959.

की एक तिहाई वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं। यह हमारे अर्थव्यवस्था सम्बन्धी अन्य आँकड़ों की तरह से सामान्य ज्ञान की बात है। उन पर यहाँ अधिक मात्रात्मक आँकड़ों की आवश्यकता नहीं।”

श्री रिचर्ड्स ने अपनी सोवियत संघ की यात्रा करते समय कहा था, “संसार में अमरीका संसार का सबसे बड़ा पूँजीपति देश है। घन वितरण के आधार बिन्दु को लेकर वर्ग-विहीन समाज की भावना के निकट है एवं सर्व साधारण के कल्याण तथा वैभव की भावना का महत्त्व समझने लगा है।”¹

संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले जो घन की अधिक विषमता (आर्थिक विषमता तथा निर्धनता) पाई जाती थी, वह बहुत अधिक मात्रा में मालिक अथवा प्रबन्धक को अपने कर्मचारियों के ऊपर एकाधिकार जो अतीत में शोषण के लिए अवसर प्रदान करता था अब पूर्णतया समाप्त हो गया है। बेकारी एवं वृद्धावस्था की प्रपणता (Distitution in old age) की तीव्रता से जड़ काट डाली गई है। एकाधिकार अथवा बाजार पर नियंत्रण होने से उत्पन्न अवयुक्तों की गैर कानूनी ठहरा दिया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सम्पन्नता का निर्माण, स्वतन्त्र मनुष्य का स्वतन्त्र प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करने के परिणाम स्वरूप हुआ है, इसके साथ ही साथ एक साथ कार्य करने एवं स्पर्धा के कारण, अपनी इच्छानुसार सरकार को चुनने (बनाने) के कारण ताकि उच्च स्तर के सिद्धान्तों का निर्माण हो सकने तथा इन सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्रयोग में लाकर और जहाँ व्यक्ति अथवा समूह के लिए अधिक कार्य है वहाँ सरकार योग देकर देश को सम्पन्न बनाने में सफल हुई है।

अमेरिका की इस प्रणाली ने बड़े-बड़े उद्योगों को ही जन्म नहीं दिया है—जिन्हें बहुत से व्यक्ति अमरीकी उद्योगों के नाम से पुकारते हैं, बल्कि असह्य छोटे-छोटे उद्योगों को भी उत्पन्न किया है। अमेरिका के सम्पूर्ण कर्मचारियों का ६५ प्रतिशत भाग व्यापारिक उद्योगों में लगा हुआ है फिर भी प्रत्येक उद्योग में कर्मचारियों की संख्या ५० से कम ही है। इस प्रकार के ४ मिलियन सधु उद्योग धन्धे हैं जो कि अमेरिका द्वारा निर्मित माल का एक तिहाई भाग उत्पन्न करते हैं जो अमेरिका के थोक विजय तथा फुटकर विजय का आधा एवं सेवा उद्योगों का तीन चौथाई भाग है।

1 “The United States is the world's largest Capitalist country ; has, from the stand point of the distribution of wealth, come closest to the idea of prosperity for all in a classless society.”
Vice President, Nixon (U. S. A)

इन सधु उद्योगों का बहुत अधिक भाग व्यक्तिगत अथवा साभेदारी के अधिकार में है। इसके विपरीत, बड़े उद्योगों के स्वामित्व में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है।

गत शताब्दी के पिछले भाग में, बड़े उद्योगों के स्वामी अधिकांश परिवार अथवा व्यक्तियों के छोटे समूह थे। अब हजारों साभेदार, अपने बहुत से कर्मचारियों सहित बहुत सी औद्योगिक संस्थाओं के स्वामी हैं। उनका प्रबन्ध अब परिवारों के हाथों से छिन कर उन व्यक्तियों के हाथों में आ गया है जो प्रबन्ध का कार्य करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत से आर्थिक विकासों में से प्रबन्ध के व्यवसाय को अल्पकाल में ही विकसित होना एक महत्वपूर्ण घटना है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रान्ति भी हो चुकी है जो वास्तव में एक शान्तिपूर्ण क्रान्ति थी। तब से धनी और निर्धन की विशाल विषमता लुप्त सी हो गई है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिन वस्तुओं का उपभोग प्रारम्भ में केवल धनी लोग करते थे अब उनका अधिकतर भाग कर्मचारियों द्वारा उपभोग किया जाता है।

आर्थिक दृष्टि से कर्मचारी वर्ग बहुत आगे बढ़ चुका है। पिछली शताब्दी में समाप्त होने से ही औसत कर्मचारी के वेतन में—द्रव्य की क्रय शक्ति और बढ़ते हुए मूल्य को ध्यान में रखते हुए—२२५ प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। कुछ विशेष उद्योगों में इससे भी अधिक वृद्धि हुई है।

सप्ताह में कार्य करने के समय का औसत केवल ४० घण्टे ही रह गया है। फिर भी अमरीकी कर्मचारी इन्हीं ४० घण्टों में अपने पूर्वजों के डेढ़ सप्ताह की उत्पत्ति से तिगुना उत्पन्न करता है। इन प्रगतियों के फलस्वरूप अमेरिका के कर्मचारियों के अवकाश के समय में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अर्थव्यवस्था तीव्रगति से आगे बढ़ रही है (U. S. Economy Continues Upward Momentum)¹। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार विभाग के वयनानुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उन्नति कर रही है। उस विभाग के बड़े बड़े निदेशकों से ज्ञात हुआ है कि, आय, उत्पादन एवं रोजगार में सन् १९५६ के द्वितीय खण्ड में वृद्धि हुई है। मई में रोजगार में जो सराहनीय प्रगति हुई थी उससे प्रतीत होता है कि टिकाऊ माल की माँगों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय, जिसका वार्षिक दर ३७६,००० मिलियन डालर था, मई में ७ प्रतिशत अधिक हो गई जबकि फुटकर विप्रेय तथा विस्तार पर व्यय में भी वृद्धि हुई। मोटरकारों की बिक्री अप्रैल एवं मई में गतवर्ष के मूल्य से १६० प्रतिशत अधिक थी।

1 Major facts in American Economic Growth, Carl, F. Occhiale (American Economy, U. S. I. S., New Delhi, July 16, 1959, pp. 6-7)

व्यक्तिगत भवन-निर्माण के लिए व्यय इस वर्ष के प्रथम ६ माह में ही १७५०० मिलियन डालर तक पहुँच गया। इसका मुख्य कारण यह है कि रहने के मकानों में ३२ प्रतिशत वृद्धि हुई। पिछले वर्ष भी लगभग इतने ही समय में १०,२०० मिलियन डालर व्यय हुआ। सार्वजनिक निर्माण का ६ माह का व्यय ७,४०० मिलियन डालर या जो गतवर्ष के उतने ही समय के व्यय से १४ प्रतिशत अधिक था।

उन महीनों में सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन पूर्ण तीव्रता से तथा पहले से अधिक हुआ। मई १९५६ में यह सूच १९४७-४९ की औसत का १५ प्रतिशत हो गया। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्र के कारखाने तथा खाने इस समय, गतवर्ष की अपेक्षा, २० प्रतिशत अधिक उत्पन्न कर रहे हैं तथा गत दो वर्षों के उत्पादन क्षेत्र में उद्योग दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति कर रहे हैं। बहुतों ने अपनी उच्चतम सीमा को पार कर भी लिया है, दूसरे उसके निकट हैं। ये सभी टिकाऊ माल की सूची (Index) में दी गई मात्रा जोड़ते हैं।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोमल वस्तुओं (Soft goods) के उद्योग पिछड़ रहे हैं। वे भी उन्नति कर रहे हैं, लेकिन १९५७-५८ में उनकी उन्नति अपेक्षाकृत कम थी। अतः १९५८ की गर्मियों के प्रारम्भ में ही उन्होंने क्षीयता से, पहली कमी को पूरा कर लिया तथा और प्रगति करने लगे। इसलिये उनका वर्तमान लाभ इतना चमत्कार पूर्ण प्रतीत नहीं होता है जितना कि टिकाऊ उद्योगों का। कुछ उद्योगों का, सभी प्रकार के उत्पादन का प्रयत्न, इस दृष्टि से भ्रमात्मक है कि वे उद्योग चल सम्पत्ति की सूची बनाने का प्रयत्न करके विक्रय के स्तर से उत्पादन को अधिक करना चाहते हैं। किन्तु चल सम्पत्ति की सूची बनाना (Inventory) आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। १९५७-५८ से चल वस्तुओं की सूचियों (Inventories) का ८,००० डालर प्रतिवर्ष के हिसाब से भुगतान किया जा रहा था। अब वे लगभग उसी दर पर एकत्र की जा रही हैं। व्यापार विभाग का कथन है कि "वास्तव में देखा जाय तो अमेरिका के व्यापारी 'परम्परागत सूची बनाने की स्थिति' (Conservative) के आदी हो गये हैं।"

२—अमेरिका का पूँजीवाद योरुप

के पूँजीवाद के समान नहीं है^१

(American Capitalism is not the same as European Capitalism)

स्वतन्त्र विचार द्वारा अधिक स्वतन्त्रता पर बल देती है। (Liberalism stresses Economic freedom)—स्वतन्त्र विचार द्वारा के अनुयायी (Liberals)

1. *American Capitalism*—Massimo Salvadori, American Reporter Book Supp., Feb. 27, 1957, (Ch. II, pp. 5-15).

ने १६ वीं सदी में तथा स्वतन्त्र विचारधारा के अग्रदूतों ने (fore-runners of liberalism) ने १७ वीं और १८ वीं सदी में, आर्थिक स्वतन्त्रता को राजनैतिक तथा आर्थिक (Economic) आधार पर न्यायसंगत ठहराया। वे कहते थे कि (क) सम्पत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व अच्छी बात है तथा प्राचीन युगों की वैयक्तिक एवं साध्वनिक सग्रहवादी प्रवृत्ति में हुए निश्चित सुधारों का प्रतिनिधित्व करती है। (ख) वे नागरिक जो साहमी हैं या अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से मालिक के प्रतिनिधि हैं उन पर उनके संचालन का अधिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। (ग) यदि स्वतन्त्र बाजार में—जहाँ तक स्वतन्त्र बाजार सम्भव हो—आर्थिक शक्तियाँ प्रचलित होनी हैं तो सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। उनकी सुसंचालित कार्य पद्धति, साध्वनिक और व्यक्तिगत एकाधिकारों के विपरीत तथा नियमों और व्यवसायों के उस जाल के विपरीत जो कि आर्थिक प्रयास करने में जनता का गला घोटते थे—सफल सिद्ध हुई। उन सीमाओं के अन्तर्गत जो राज्य अथवा सच ने निर्धारित नहीं की अपितु बाजार की परिस्थितियों ने निर्धारित की है, नागरिक उत्पत्ति के साधनों तथा श्रम की गतिशीलता का एक पूँजी अथवा वस्तुओं और सेवाओं का जो उन्होंने उत्पन्न की—स्वतन्त्र उपभोग कर सके तथा एक समुचित सीमा तक स्वतन्त्र हो गये।

स्वतन्त्र विचारधारा के बहुत से अनुयायियों ने, कई पीढ़ियों तक अनिच्छा पूर्वक उन परिस्थितियों के विनाश करने की भूल की जो जनता के बहुत बड़े भाग को सम्पत्ति का स्वामी होने से वंचित करती है। सन् १६८८ से पूर्व इंग्लैंड में तथा १७८६ में पू्व महाद्वीप में, सम्पत्ति एक विशेषाधिकार (Privilege) के रूप में रही है। विशेषाधिकार होने के कारण यह स्वतन्त्रता से पूर्णतः भिन्न था। लेकिन उसने समयको की शक्तिशाली बनाया तथा इसने बहुत सी स्वतन्त्र संस्थाओं को जन्म दिया और सम्पत्ति के स्वामी होने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया।

उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्यों तथा कनाडा दोनों में ही—एक भिन्न परिस्थिति रही, पूँजीवाद विशेषाधिकार के रूप में कम से कम रह गया तथा लाभ में से हिस्सा बटाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। सर्वहारी वर्ग (Proleterian class) की वृद्धि को रोक दिया गया है तथा यह वर्ग समाप्त हो रहा है।

कुछ विभिन्नताएँ (Some differences)—वास्तव में समय के कारण बड़ा अन्तर हो जाता है। उदाहरणार्थ यह कहना न्याय सभत होगा कि सन् १८८६ ई० में अमेरिका तथा योरोप की आर्थिक प्रणालियाँ लगभग समान थीं। आज के योरोप का पूँजीवाद ७० वर्ष पूर्व के योरोप के पूँजीवाद से बिल्कुल भिन्न है। अमेरिका के पूँजीवाद के विषय में भी यही बात बिल्कुल सत्य है। यही नहीं, इन दोनों ने ऐसी विभिन्न पद्धतियों में उन्नति की है कि इनमें सन् १९१६ ई० में बिल्कुल समानता नहीं थी। अमेरिका का 'आर्थिक मिथुन का मिद्वान्त' अंग्रेजों, जर्मनों अथवा फ्रांसीसियों के सिद्धान्त से भिन्न है। वहाँ ऐसे नियेवात्मक (Restrictive) एकाधिकृत

(Monopolistic) पूँजीवाद का अभाव रहा है जिसे २० वर्ष पहले अर्थशास्त्रियों ने नई संज्ञा (Oligopoly) के नाम से विभूषित किया, उन्होंने यह सोचा था कि पूँजीवादी प्रतिस्पर्धा का अन्त हो जायगा, लेकिन फिर भी एकाधिकार (Monopoly) नहीं हो सका, कर्मचारी (Employees) व्यापार (enterprise) के शत्रु नहीं हैं अथवा हैं, मजदूर संघों (Labour unions) ने व्यापार से सख्त (Attitude) एवं कला (Technique) उधार ली है; समाजवादी आन्दोलन (Socialist movement) नगण्य है तथा लाभ की अपेक्षा इसे हानि हुई है, स्वदेशी समूहवाद (Indigenous Collectivist) के प्रोत्साहन को मुख्य तत्त्व मानकर निरंकुश परिस्थितियों (Dictatorial tendencies) को बढ़ावा देना, (यदि समूहवाद (Collectivism) का बोलबाला होता है तो साम्यवाद (Communism), यदि समूहवादी विरोधी तत्त्वों का बोलबाला होता है तो Fascism का प्रादुर्भाव होता है) इन बातों का कनाडा के जीवन को अपेक्षा अमेरिका के जीवन में प्रभाव है ।

अमेरिका एवं योरोप के पूँजीवाद का अन्तर बहुत सीमा तक आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारधारा से भी उत्पन्न होता है । योरोप में, आर्थिक स्वतन्त्रता में कानून (Legislation) का अभाव रहा है; हस्तक्षेप न करने की रीति (Laissez faire) अपने सही अर्थ में प्रचलित रही है तथा उसने जयत व्यापार सिद्धान्त बनने की विशेषतायें प्राप्त करती हैं । हायक (Hayek) के शब्दों में^१ "स्वतन्त्र विचारधारा के लिए किसी ने भी इतनी हानि नहीं पहुँचाई है जितनी कि कुछ स्वतन्त्र विचारकों के अशिष्ट सिद्धान्तों ने । इसके द्वारा सबसे अधिक हानि हस्तक्षेप न करने वाले सिद्धान्त को पहुँची । बीसवीं सदी में समूहवादी तथा सघनवादियों (Collectivist and Corporatist) ने सरकारी कानूनों (Governmental legislation) के साथ पूँजीवाद के 'शुण' की स्वीकार किया, अथवा आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप करने के सिद्धान्त को माना ।"

अमेरिका की आर्थिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का निर्धारण पुस्तकों की अपेक्षा अनुभव के आधार पर अधिक सही रूप में किया जा सकता है, क्योंकि उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया अथवा लिखा गया है, वहाँ उससे अधिक कार्य हुआ है । यह साधारण बात है ।

आर्थिक स्वतन्त्रता राजनैतिक स्वतन्त्रता से भिन्न नहीं है, यह कानूनों का परिणाम है जिनका कि लक्ष्य आर्थिक स्वतन्त्रता को स्थापित करना, उसे बनाये

1. "Nothing has done so much harm to the liberal cause as the wooden insistence of some liberals on certain rough rules of thumb, above all, on the Principles of Laissez faire," Hayek.

रखना, अथवा शक्तिशाली बनाना है।”¹ योरूप की आर्थिक स्वतन्त्रता में इच्छा (Will) का अभाव रहता है, जबकि अमेरिका की आर्थिक स्वतन्त्रता इच्छा को कार्यान्वित करती है।

३—प्रणाली²

(The System)

प्राकृतिक साधन ही पर्याप्त नहीं हैं (Natural resources only are not enough)—यह सामान्य मत है—(केवल विदेशियों में ही नहीं) कि अमेरिका की वर्तमान आर्थिक प्रणाली की सम्पन्नता दूसरे देशों की प्रणालियों से पूरुणतया नहीं तो मुख्यतया वहाँ की जनसंख्या की तुलना में प्राकृतिक साधनों का बाहुल्य होने के कारण है। विशेषकर संयुक्त राज्य के विषय में यह कहा जा सकता है कि अमेरिका की सम्पन्नता केवल मिट्टी तथा मिट्टियों के प्रकार तथा मनुष्यों के परिणाम स्वरूप नहीं है, परन्तु मुख्यतया राष्ट्रीय जाशुति की आकांक्षाओं (aspirations) तथा उसके महत्त्व की गहरी जड़ों के कारण है, एवं उस ढंग के कारण है जिस पर अमेरिकावासियों ने अपने आर्थिक प्रयत्नों का संगठन किया है।

स्वतन्त्र साहस (Free enterprise)—अमेरिका के स्वतन्त्र साहस की मुख्य विशेषताय, जो पिछले ७० वर्षों में विकसित हुई है, निम्नलिखित है —

(१) उत्पत्ति के साधनों का स्वामी कई मिलियन व्यक्ति कृषि स्तर पूँजी (Non-agricultural Capital) के स्वामी, मिलियन-मिलियन भूमिधर कृषक तथा शारीरिक श्रम एवं मानसिक कुशलता रखने वाले जैसे ठीक समझ अपनी सम्पत्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिये उन्हें कानून से द्वारा जो सीमा निर्धारित की है उसके अन्तर्गत व्यापक क्षेत्र प्राप्त है।

(२) स्पर्धा ही आर्थिक क्रिया का सिद्धान्त है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हर स्थान पर हर समय स्पर्धा होती है। स्पर्धा सीमित है। ‘अथ व्यवस्था’ के विस्तृत क्षेत्र है जो स्थिर हैं लेकिन यदि सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली को लिया जाय तो प्रणाली में स्वयं की गतिशील बनाने के लिए तथा मौलिक कार्य करने के लिए पर्याप्त स्पर्धा है।

(३) कांग्रेस का लक्ष्य, आर्थिक एवं प्रमाथिक बहुत से वर्गों की इच्छा को रक्षित हुए, आर्थिक कानूनों का निर्धारण करते हुए स्वतन्त्र साहस को बनाये रखना है। तथा जैसा कि अन्य आर्थिक प्रणालियों में व्याप्त है, पूँजीवाद भी उन प्रवृत्तियों को रोक्ता है जिनका कि विकास आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए घातक है। मनुष्यकृत नियम अग्रणी है। वे स्वतन्त्र रहने की इच्छा के प्रगट रूप हैं।

1 “Economic freedom is not different from political freedom, it is the outcome of laws the aim of which is to establish, maintain or strengthen Economic freedom”

2 Ibid, Ch III, pp 16—44

(४) योएष के किसी भी बड़े राष्ट्र में बहुमत का पूँजीवाद के पक्ष में होना सन्देहजनक है। कई देशों में कई बार पूँजीवाद को स्वीकार तो कर लिया जाता है लेकिन उसे पसन्द नहीं किया जाता। अमेरिका वाले दूसरी तरह सोचते हैं। हर वर्ग, कृषक, श्रमिक, व्यापारी तथा उपभोक्तागण के पास आलोचनायुक्त कुछ होता है किन्तु यह कहने वाले बहुत थोड़े हैं कि “स्वतन्त्र साहस बुरा है, हमें कोई दूसरी प्रणाली ग्रहण करनी चाहिए।”

लगभग सभी अमेरिकी अपनी प्रणाली को जिससे उन्हें निम्नलिखित चार लाभ प्राप्त हैं, छोड़ने की बात पर काँपते हैं :

(१) यह सभी को रहन-सहन का उच्च स्तर प्रदान करती है। (२) यह कुशल है। (३) यह व्यक्ति को तथा उसके परिवार को अपनी इच्छानुसार जीवन यापन करने की क्षमता प्रदान करती है। (४) यह अनवरत सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति के पक्ष में है।

सम्पत्ति (Property)—समाजवादी विद्वान आर्थिक अथवा नैतिकता के आधार पर, सम्पत्ति पर निजी अधिकार रखने की प्रणाली की जो कटु प्रानोचना करते हैं उसका आजकल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है।

अमेरिका के प्रत्येक नागरिक का यह विश्वास है कि सम्पत्ति अच्छी वस्तु है। यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वतन्त्रता तथा आर्थिक सुरक्षा दोनों ही प्रदान करती है। सम्पत्ति हर जगह सम्मान प्रदान करती है, जहाँ तक हमें ज्ञात है सोवियत रूस में भी ऐसा ही है परन्तु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह विशेष सम्मान प्रदान करती है यदि वह व्यक्ति ने निजी प्रयत्नों तथा श्रम का परिणाम हो। सन् १९५० ई० के निरीक्षण के अनुसार लगभग १० मिलियन पारिवारिक इकाइयों में से ८ प्रतिशत ही ऐसी थी जिन पर ‘वास्तविक सम्पत्ति’ औद्योगिक सामग्री (Industrial stock) अथवा अन्य रूप में नहीं थी। ‘संयुक्त राज्य में जनता का पूँजीवाद’ (Peoples' Capitalism in U. S. A.) नामक पुस्तक जो फरवरी १९५६ में प्रकाशित हुई थी, उसके हिसाब से ७० मिलियन अमेरिकी वचत का हिसाब रखते हैं, ११५ मिलियन व्यक्तियों ने बीमा करा रखा है, ७ मिलियन के पास काफी ‘वचत का भण्डार’ है। सम्पत्ति-हीन परिवारों की प्रतिशत कई दशकियों (Decades) से धीरे-धीरे घटती जा रही है।

सभी के लिए पूँजीवाद (Capitalism for all)—यह सत्य है कि बहुत से मामलों में, विशेषकर एक दर्जन बड़े उद्योगों में, उत्पादन के साधनों का प्रबन्ध का अत्यधिक कन्द्रीयकरण है। फिर उन्हीं साधनों का स्वामित्व बहुत कंटा हुआ है, यद्यपि सत्वाओं में मिश्रता है, फिर भी सम्भवतया ७ मिलियन से भी अधिक व्यक्ति आधे मिलियन से अधिक सघों पर स्वामित्व किये हुए हैं। आजकल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ३३ मिलियन असंगठित फर्म में असम्बन्ध व्यापार होता है जो एक अथवा अधिक व्यक्तियों से सम्बन्धित है। ४ मिलियन किसान (सभी किसानों का ६८

प्रतिशत) अपनी जोतने वाली भूमि के स्वामी है। आधे मिलियन से अधिक स्वतन्त्र कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जिनके उत्पादन के साधन केवल दक्षता तथा प्रशिक्षण हैं।

पूँजी तथा श्रम का विस्तृत मेल (Integration of Capital and Labour)

Lincoln ने एक बार लिखा था, “जनता की एक बहुत बड़ी मछली अपने निजी श्रम को पूँजी से संयुक्त करती है।”¹ यह आज भी सत्य है क्योंकि अधिकांश अमरीकी पूँजी के स्वामी भी हैं तथा साथ ही कार्य भी करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिम यारूप की भाँति पूँजीवादी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है। कमचारी पूँजी के स्वामी हैं तथा पूँजीपति स्वयं कार्य करते हैं। स्वामित्व की विस्तृत व्यापकता ने फर्म से असम्बद्ध कार्यों को पूरी तौर से प्रभावित किया है। बहुत सीमा तक, स्वामित्व तथा प्रबन्ध दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गये हैं। यह कहने में अतिशयोक्ति न होगी कि अमरीका के उद्योगों में प्रबन्ध ने एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है, जो अन्यत्र अज्ञात है, जहाँ कि सम्पत्ति का निजी अधिकार माय्य है। अमेरिका की आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

‘फॉरच्यून’ (Fortune) के सम्पादक ने लिखा था “Main Street का प्रभाव Wall Street के नियन्त्रण की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।”² उसने आगे लिखा था, “प्रबन्ध माहुरी के कार्यों को इस ढंग से संचालित करे जिससे माहुरियों, उपभोक्ताओं एवं जनता में बहुत ही साम्य तथा कार्य करने का मन्तुलन बना रहे।”³

स्पर्धा (Competition) —

स्पर्धा, अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था (Economy) का सबसे अधिक आलोचित एवं बहुचर्चित विषय है। अमेरिका वाते इस बात पर महमत प्रतीत करते हैं कि स्पर्धा महत्वपूर्ण है। फिर भी इसका बहुत बड़ा भाग अमेरिका की अर्थ व्यवस्था में नहीं है। और यह भव तो अतीत की अपेक्षा कम है। बहुत से तो इसके अन्त का आभास पाकर निराश हो रहे हैं। इसका भविष्य इङ्ग्लैण्ड तथा जर्मनी के पूँजीवाद

1 ‘A considerable number of persons mingle their own labour with Capital,’ Lincoln

2 ‘The influence of Main Street has become vastly more important than the control of Wall Street’

3 ‘Management must conduct the affairs of the enterprise in such a way as to maintain on equitable and working balance, among stock holders, customers and the public at large’

से भिन्न नहीं है जो शताब्दी के समाप्त होते ही एकाधिकार की प्रणाली (monopolistic) का हो गया था। इसलिए वे वणिक्वाद के विरोधी तत्त्वों (Neo-mercantilism) एवं संघवाद (Corporation) को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। यदि कोई अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था की पूरक इकाइयों को अकेले सोचता है, तो वह अच्छी तरह इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि वहाँ स्पर्धा बहुत कम है अथवा है ही नहीं।

मादारण तथ्य यह है कि यह प्रणाली अपनी इकाइयों का केवल जोड़ ही नहीं है, परन्तु इकाइयों और उनके सम्बन्ध का जोड़ है। स्पर्धा किसी भी दी हुई इकाई में परम्परानुसार (Inherent) नहीं प्राप्त की जा सकती है किन्तु सम्बन्ध की प्रणाली से अनुभव की जाती है।

Prof. Galbraith ने अपनी पुस्तक 'American Capitalism, The Concept of Countervailing Power' के प्रथम पृष्ठ पर लिखा है, 'अमेरिका की अर्थ व्यवस्था का वर्तमान संगठन तथा प्रबन्ध नियमों के विरुद्ध है। तथा न यह कार्य करता है'¹ सम्पूर्ण प्रणाली में स्पर्धा को बिना मुख्य अंग समझे, व्यापार की सर्वमान्यता बहुत ही कम हो जायेगी।

नियोजन (Planning) —

बहुत प्रकार के नियोजकों, जैसे समूहवाद (Collectivism), संघवाद (Corporatism), वणिक्वाद (Mercantilism) इत्यादि के उपासकों का कहना है कि अमेरिका की अर्थ व्यवस्था की बुराइयों नियोजन के अभाव के कारण हैं। यही कमी समुक्त राज्य का निर्माण करनी है तथा अस्थिर आर्थिक अस्थिरता ससार की स्थिरता के लिए खतरा बन जाता है। इस आलोचना के उत्तर में दो बातें कही जा सकती हैं। यदि नियोजन का राष्ट्रीय स्तर पर यह अर्थ समझ कि यह कानून के माध्यम से एक निश्चित नक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए एक निश्चित अर्थ व्यवस्था की दिशा प्रशस्त करता है तो स्पष्ट है कि अमेरिका की अर्थ व्यवस्था तथा अन्य आर्थिक प्रणालियों का अन्तर नियोजन के अभाव के कारण नहीं है। बल्कि विभिन्न प्रकार के नियोजनों का ग्रहण करने के कारण है।

आर्थिक स्वतन्त्रता का नियोजन उतनी ही बुद्धिमत्ता, विचारशीलता एवं दूरदर्शिता चाहता है जितना कि वणिक्वादियों की हितकारी अर्थ व्यवस्था का नियोजन समूहवाद अथवा संघवाद चाहता है। आर्थिक स्वतन्त्रता के नियोजन का अर्थ है आर्थिक प्रणाली को एक गति देना जो प्रत्येक इकाई को अपना स्थान निर्धारण करने में सहायता करता है। आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic freedom) के नियो-

1 "The present organisation and management of the American Economy are in defiance of the Rules nevertheless in works"

जन का अर्थ है कि प्रत्येक इकाई का स्थान सरकार निर्धारित करे। टर्गोट (Turgot) तथा एडमस्मिथ (Adam Smith) की भाँति अमेरिका निवासी भी इस विचार से सहमत हैं कि, 'सर्वोत्तम परिणाम उस प्रणाली द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जो प्रत्येक इकाई को अपना स्थान निर्धारित करने में सहायता करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कमचारियों के साथ-साथ भूस्वामियों एवं पूँजीपतियों से भी अपने प्रयत्न के बदले अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की आशा की जाती है।' विद्वाना एवं अन्य राष्ट्रीय मंचों में किसी ने भी टर्गोट तथा स्मिथ एवं अमरीकियों का गलत ठहराने के लिए पूरा सनापजनक प्रमाण उपस्थित नहीं किए हैं।

समुक्त राज्य में भी, जहाँ आर्थिक क्रियाएँ होती हैं, वहाँ नियोजन पर पूर्ण बल दिया जाता है। प्रबन्धन वगैरह का मुख्य कार्य नियोजन को अगले दिन, अगले सप्ताह, अगले माह अथवा आगामी पाँच वर्षों में कार्यान्वित करना है। आगामी वर्ष के नियोजन के लिए प्रति वर्ष व्यापारियों द्वारा काफ़ी समय, शक्ति एवं विचार किया जाता है। ध्यान पूर्वक योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। सम्भवतया अन्य प्रणाली की अपेक्षा सोवियत रूस को भी मिलाकर अधिक ध्यान पूर्वक तैयार की जाती है। अमरीकियों का विश्वास है कि समग्रतः राज्य नियोजन (State Planning) आर्थिक प्रारम्भ को अपेक्षित बनाती है, लेकिन वहीं नियोजन प्रत्येक दूकान अथवा कारखाने का मुख्य लक्ष्य है। अमरीका का आर्थिक प्रणाली सीमित महात्मक (Limited Federal Planning) के आधार पर कार्य करती है जो मुख्यतया वित्तीय ढाँचे (Financial Trade work) को प्रभावित करता है तथा स्वतन्त्र नागरिकों की उन असह्य यात्रनामाओं को प्रभावित करता है जो उनके द्वारा निर्मित हुई हैं तथा कार्यान्वित की गई हैं। सावधानी से योजना निर्माण करने के लिए अधिक अधिक प्रशिक्षण आवश्यक होता है। अतः आज व्यापार जगत् में शिक्षा का महत्त्व बढ़ गया है। प्रबन्धक के लिए विदेश विद्यालय अथवा महा विद्यालय का प्रमाण-पत्र (Degree) का होना अधिक से अधिक आवश्यक होगा है। जो उद्योग (Firm) बहल कर सकते हैं वे प्रशिक्षित अथवा शास्त्री, आंकड़ों के विशेषज्ञ (Statisticians) तथा अन्य सामाजिक विज्ञान विशेषज्ञों की सहायता का उपयोग करते हैं जिनकी कि समुक्त राज्य अमरीका में निजी उद्योग, सरकारी सहायता से वहाँ अधिक सुविधाएँ प्रदान करती हैं।

श्रमिक संघ (Labour Unions)

व्यापारियों की एक प्रभावशाली संगठन के अस्तित्व ने जो उस स्तर तक पहुँच गया है जहाँ वे स्वतन्त्र अथवा व्यवस्था की प्रकृति का जानते हैं—नया अर्थव्यवस्था (Non-Economic elements) से इनके सम्बन्ध में, अमरीकी स्वयं (Free enterprise) की वृद्धि में योग दिया है। अमरीका के श्रमिकों का दृष्टिकोण यहाँ के श्रमिकों के दृष्टिकोण से उतना ही भिन्न है जितना सम्भवतः Atlantic महासागर का दोनों ओर के व्यापार के दृष्टिकोण में भिन्न है। समुक्त राज्य में संगठित श्रम का

योग उतना ही मौलिक है जितना कि योक्ष में बहुत समय तक रह चुका है। इस समय देश में लगभग १२ मिलियन संगठित कर्मचारी हैं। श्रमिक सघ शक्ति तथा प्रभाव (Power and influence) में N. A. M. के औद्योगिकों (Industrialists) बैंक वालों (Bankers) तथा किसानों के व्यापार सघ (Chambers) से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ग्रन्थक्ष मीने (Meany) ने तीन बातों पर दल दिया था जिन्हें केवल कुछ ही योक्षियन नेता (यदि कोई स्वीकार कर मवेगा तो) स्वीकार करेंगे। (क) श्रमिक तथा प्रबन्धक का हित एक दूसरे पर निर्भर है। (ख) स्वतन्त्र श्रम, स्वतन्त्र माहस के रूप में केवल स्वतन्त्र सरकार में ही विद्यमान रह सकता है। (ग) अमरीकी श्रम, सरकारी नियन्त्रण के विस्तार का समर्थन नहीं करता है, बल्कि केवल सामूहिक लेन देन (bargaining) द्वारा ही अपने सक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रयास करता है।

राज्य का कार्य (Role of The State)

समुक्त राज्य अमरीका में व्यापार एवं श्रम योक्षीय व्यापार एवं श्रम से भिन्न प्रकार के हैं। ऐसा ही सरकार के कर्तव्य के बारे में है, ऐसा ही आर्थिक प्रणाली के क्षेत्र में है। आर्थिक स्वतन्त्रता, इच्छा का कार्य था इसके अस्तित्व के पुनर्स्थापना की ही आवश्यकता नहीं थी, बल्कि व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यों—जो इस प्रणाली की कुंजी है—के माध्यम से पुनः व्यापार की आवश्यकता थी। सर्वे प्रथम, सरकार का कार्य बाह्य आर्थिक दबाव के विरुद्ध अमरीका के बाजार की रक्षा करनी थी। दूसरे, सरकार का कार्य आन्तरिक एकाधिकारों के विरुद्ध सघर्ष से सम्बन्धित था। समुक्त राज्य में एकाधिकारों के विरुद्ध लड़ने का कार्य, व्यवस्थापिका के विरोधी तत्वों, जनता के उपयोगों के नियमों एवं बैंकों के माध्यम से, Wagner Act के उपायों के माध्यम से समान शक्ति के विकास के लिए सुविधा प्रदान करके तथा अनुपातिक प्राय एवं मृत्युकर द्वारा जो कुछ व्यक्तियों के हाथ में प्रत्यधिक सम्पत्ति एकत्र होने को रोकते हैं, प्रोफेसर गैलब्रथ के अनुसार, समानता प्राप्त हो सकती है।

श्रमिक एवं प्रबन्धक, उत्पादक एवं उपभोक्ता विनियोगिता एवं उधार लेने बाने, कृषि तथा उद्योग ये सभी आर्थिक प्रणाली के तत्व हैं। इनमें से किसी एक के साथ अनुचित पक्षपात करने से ग्रन्थ व्यवस्था में असन्तुलन उत्पन्न होता है। अतः आर्थिक प्रणाली को गतिशील रखने के लिए अधिकारात्मक उपायों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। अमरीकी कांग्रेस व्यवस्थापन द्वारा विभिन्न तत्वों में सन्तुलन के सिद्धान्त को अपनाती है। इस कार्य में, अमेरिका की कांग्रेस, सम्भवतः योक्षीय अर्थ-व्यवस्था (पूँजीवादी दृष्टि में) किसी भी योक्षीय मसद से अधिक सफल हुई है। यदि गैलब्रथ की 'टुबल लेन-देन की स्थिति को आश्रय देना' उदार आर्थिक नीति की कसौटी है तो अमरीकी सरकार, सदैव समाजवादी तत्वों के घोर विरोधी होने के साथ साथ परम्परावादियों की अपेक्षा अधिक उदार है।

४—क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक प्रणाली में 'आमदनी स्तरों में' विशाल अन्तर नहीं है ?

(Does not the Economic system of the United States Lead to the concentration of wealth at one Pole of Society while Poverty grows at the other Pole ?¹)

(क) इस विवाद के भ्रम की पुष्टि गत तीन दशकों में हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था के विकास द्वारा सिद्ध होती है ।

धनिकों का भाग (जनसंख्या का सर्वोच्च पाँच प्रतिशत), कुल व्यय करने योग्य आय में गिरता जा रहा है

प्रतिव्यक्ति की कुल व्यय करने का (Percentage of total Disposal Income of Individuals) प्रतिशत

१९२८	२६ १
१९३६	२४ ८
१९४८	१७ ६

(ख) कम आय वाले वर्गों के भाग में वृद्धि इस प्रकार हुई है —

आय की दृष्टि से गृह प्रबंध का क्रम (Households Arrayed by income)	राष्ट्रीय आय का प्रतिशत वितरण (Percentage Distribution of National income)		औसत आय (Average income)	औसत आय में प्रतिशत वृद्धि (Percentage Increase in Average)	
	१९३५-३६	१९४८	१९३५-३६	१९४८	
सबसे निम्न पाँचवाँ (Lowest fifth)	४०	४२	५३४	८६३	६७
द्वितीय पाँचवाँ (Second fifth)	८७	१०५	१,१५६	२,२३२	६३
तृतीय पाँचवाँ (Third fifth)	१३६	१६१	१,८१०	३,४०	८८
चतुर्थ पाँचवाँ (Fourth fifth)	२०५	२२३	२,७३४	४,७११	७२

1 Questions and Answers about the American Economic System - W S and E S Woytinsky, 'American Economy', U. S I S, New Delhi Aug 23, 19७7

सर्वोच्च पाँचवाँ

(Highest fifth) ५३'२ ४६'६ ९,०८३ ६,६११ ४०

(ग) हाल ही के वर्षों में द्रव्य आय (Money income) के वितरण में प्रगतिशील आयकर ने अधिक समानता लाने में योग दिया है :

द्रव्य आय की दृष्टि से गृह-प्रवन्ध का सम (Households Arranged by Money Income)	द्रव्य आय का प्रतिशत वितरण (Percentage distribution of Money Income)	करों से पूर्व (Before Taxes)	करों के पश्चात् (After Taxes)
		१९४७	१९५४
निम्नतम पाँचवाँ (Lowest fifth)		४	५
द्वितीय पाँचवाँ (Second fifth)		१०	११
तृतीय पाँचवाँ (Third fifth)		१६	१७
चतुर्थ पाँचवाँ (Fourth fifth)		२२	२४
सर्वोच्च पाँचवाँ (Highest fifth)		४८	४९

(घ) सबसे अधिक सम्पन्न तथा अपेक्षाकृत निचले भौगोलिक प्रदेशों एक राज्यो के आय के स्तर में जो अन्तर है उसमें ह्रास हुआ है :

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita income)	१९५४ सन् १९२६ के प्रतिशत रूप में
धनी राज्य (Rich States)	१९२६
न्यूयार्क (New York)	\$१,१५६ \$२,१६३ १८७
कनेक्टिकट (Connecticut)	१,०२६ २,३६१ २३०
डीलेवेर (Delaware)	१,०१७ २,३७२ २३३
कैलीफोर्निया (California)	६६५ २,१६२ २१७
इलीनोइस (Illinois)	६५७ २,१५५ २६५
निचले राज्य (Poor States)	
उत्तरी कैरोलिना (North Carolina)	३३४ १,१६० ३५६
अलाबामा (Alabama)	३३४ १,०६१ ३३७
अरकानसास (Arkansas)	३०५ ६७६ ३२१
मिसिसिपी (Mississippi)	२८५ ८७२ ३०६
दक्षिणी कैरोलिना (South Carolina)	२७० १,०६३ ३८०

सन् १९२६ में पांच धनी राज्यों का अमाशित (Unweighed) घनत्व पाँच निचले राज्यों के औसत में ३.४ गुना था। सन् १९५४ में २.२ का अनुपात था। दोनों वर्गों का अन्तर भाषा कर दिया गया है।

(ड) श्वेत (White) तथा अश्वेत (Non white) कर्मचारियों की आय के भेद को मिटाने का एक लक्ष्य रहा है :—

	Median Annual Earnings	1954 as Percentage of 1939
	१९३९	१९५४
श्वेत पुरुष (Male White) डॉलर	१११२	डॉलर ३७५४
श्वेत स्त्रियाँ (Female White)	६७६	२०४६
अश्वेत पुरुष (Male Non-White)	४६०	२१३१
अश्वेत स्त्रियाँ (Female Non-White)	२४६	६१४

सन् १९३९ में श्वेत पुरुषों का औसत वेतन अश्वेत पुरुषों के औसत वेतन से १४२ प्रतिशत अधिक था। १९५४ में ७६ प्रतिशत का अन्तर था। स्त्रियों के वेतन में सन् १९२९ में १७५ प्रतिशत का अन्तर था तथा सन् १९५४ में १२४ प्रतिशत का।

सामाजिक कल्याण तथा हितकारी कार्यक्रम के विषय में स० राज्य अमेरिका में क्या प्रबन्ध है ?

(What About Social Security and Welfare Programmes in the United States ?)

(क) संयुक्त राज्य सामान्यतः लगभग ३०,००० मिलियन डॉलर (कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति का लगभग ८ प्रतिशत) सामाजिक कल्याण पर व्यय करता है। सन् १९५४ में ये व्यय इस प्रकार थे :—

योग	डालरो की संख्या हजार मिलियनों में (Thousand Millions of Dollars)
सामाजिक बीमा	८.२
जनता की सहायता	२.८
स्वास्थ्य एवं औषधि सम्बन्धी सेवाएँ	२.९
अन्य कल्याण के कार्य	०.७
शिक्षा	६.६
अनुभवी एवं वृद्धों की सहायता (Veterans' aid)	४.१

मघारमक व्ययों (Federal expenditures) ने कुल का ४० प्रतिशत सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक कार्यक्रमों एवं लगभग ८० प्रतिशत राज्य एवं स्थानीय कार्यक्रमों को प्रदान किया।

(ख) सघात्मक व्ययों में वृद्धावस्था एवं उत्तरजीवी बीमा (Old age and Survivors), राज्य की वित्तीय (Financial) तथा अन्य आवश्यकता वाले कार्यों के लिए, अन्य एवं बच्चों के लिए, रेल के कर्मचारियों की सुरक्षा एवं युद्ध से अवकाश प्राप्त वृद्ध लोगों की मदद के लिए सहायता में स्वीकृति देना, सम्मिलित है।

राज्य मुख्यतया, रोजगार की सुरक्षा, कर्मचारियों का मुआवजा, आवश्यकता वालों को सरकारी सहायता, स्वास्थ्य एवं औपधि सम्बन्धी सेवाओं (अवकाश प्राप्त वृद्ध कर्मचारियों के अतिरिक्त) एवं शिक्षा के लिए उत्तरदायी है।

(ग) अवकाश के कार्यक्रम (Retirement Programmes), सभी घसैनिक वेतनों (Wages and Salaries) के ६४.४ प्रतिशत, बेरोजगारों का बीमा ७६.१ प्रतिशत, कर्मचारियों का मुआवजा ७८.३ प्रतिशत, को सम्मिलित कर लेते हैं।

(घ) सन् १९५४ में ५.४ मिलियन व्यक्तियों को अवकाश की सुविधायें (Retirement benefits) प्रदान किया गया था :

वृद्धावस्था में अवकाश (Old age retirement)	४.६ मिलियन
रेल कर्मचारियों का अवकाश	०.३ " "
सघात्मक राज्य एवं स्थानीय अवकाश प्राप्त वृद्धों सहित (Federal, State and local retirement including Veterans) अवकाश की सुविधायें	०.५ " "

इसके अतिरिक्त, उत्तरजीवियों (Survivors) का मासिक लाभ (Benefits) लगभग ३१ लाख व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें वृद्ध विधवायें अथवा बीमा वाले मृतक कर्मचारियों के भाँ बाप, उनके १८ वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे तथा किसी भी उम्र के ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाली विधवायें हैं, असमर्थता की सुविधायें (Disability benefits) लगभग ३.१ मिलियन व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें युद्ध के अवकाश प्राप्त व्यक्ति सम्मिलित हैं। बेरोजगार का मुआवजा प्राप्त करने वालों की संख्या का औसत प्रति वर्ष १.५ मिलियन के लगभग है।

लगभग ५.५ मिलियन व्यक्तियों ने (राज्य के सघात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत) दिसम्बर १९५४ में तथा दिसम्बर १९५५ में सहकारी सहायता प्राप्त की।

सबको मिलाकर, सघात्मक एवं राज्य के सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत (Under all Federal and State Programmes) सन् १९१४ ई० में १७ तथा १८ मिलियन व्यक्तियों को सुविधायें (Benefits) दी गईं।

(ङ) सघात्मक वृद्धावस्था के कार्यक्रम (Federal old age Programmes) के अनुसार मनुष्य के लिए अवकाश (Retirement) प्राप्त करने की अवस्था ५५ वर्ष एवं स्त्रियों के लिए ५२ से ५५ वर्ष है। ७२ वर्ष की अवस्था में अथवा उसके

पश्चात्, कार्यक्रम के अन्तर्गत बीमा किए हुए पुरुष सुविधाओं (Benefits) के अधिकारी हो जाते हैं चाहे ये अवकाश ग्रहण कर चुके हो अथवा नहीं ।

अव्युत्थल कर्मचारी की मासिक आय ८१-५० डॉलर है । उद्योग के एक औसत कर्मचारी की प्रति सप्ताह आय ८० डॉलर है । कुशल कर्मचारी साधारण रूप से प्रति सप्ताह १०७-५० डॉलर प्राप्त करता है । एक प्रशिक्षित कर्मचारी की पत्नी इस सुविधा का आधा भाग प्राप्त करती है जबकि विधवा इसका तीन चौथाई भाग ।

(च) राज्य में बेरोजगार की परिस्थितियों के बीमा का विधान हर राज्य में भिन्न-भिन्न प्रकार का है । औद्योगिक राज्यों में साप्ताहिक सुविधाएँ साधारण साप्ताहिक आय का ४५-५० प्रतिशत के लगभग हैं, जो कि लगभग ४५ या ५० डॉलर हैं । अधिकतर राज्यों में सुविधाओं का समय २० से २५ सप्ताह रखा गया है ।

बहुत सी निजी व्यापारिक संस्थाओं ने भी अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश के पश्चात् पेंशन देने का सिद्धान्त बना लिया है । ये सघातक वृद्धावस्था कार्यक्रम (Federal old age Programme) द्वारा प्रदत्त वेतन के अतिरिक्त कुछ सुविधायें भी प्रदान करते हैं । सन् १९५६ के अन्त में लगभग २३ हजार अमरीकी फर्मों ने पेंशन की योजनाएँ बनाईं जिनसे १४ लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए । इन योजनाओं के अन्तर्गत, सन् १९५५ में लगभग ५२५ मिलियन डॉलर सुविधाओं, ६२००० वार्षिक वेतन पाने वाले को भुगतान किया गया जिनमें से अधिकतर राष्ट्रीय-सामाजिक-बीमा प्रणाली के अन्तर्गत अवकाश प्राप्त करने की पेशन भी प्राप्त कर रहे थे । व्यक्तिगत पेशनों की योजनाओं को विशेष व्यवस्थापन द्वारा, विशेष स्तर की पूर्ति करने वाले उद्योगों की पूर्ति के लिए कर-ऋण स्वीकृत करके प्रोत्साहित किया ।

क्या समुक्त राज्य अमरीका की 'सम्पन्नता' बनाबटो नहीं है ?

(Is not 'Prosperity' in the U S. due to an artificial boom ?)

(क) इन हाल ही के वर्षों में समुक्त अमरीका में कोई विशेष व्यापारिक तेजी नहीं हुई है ।

विस्तार (Boom) की विशेषता अर्थव्यवस्था का तीव्र तथा असमान विस्तार होना, एवं सम्बन्धी श्रेणी वाली स्थितियों का अतिक्रमण करते हुए विकास की एक सूची है । समुक्त राष्ट्र अमेरिका में आर्थिक-विकास ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् सामान्य गति से धीरे-धीरे विक्रम वाली विशेषता को ग्रहण कर लिया है ।

सन् १९५५ की कीमतों के आधार पर व्यक्तिगत आय का विवरण
(Disposable Personal Income at 1955 Prices)

वर्ष	डोलर हजार मिलियनो में	प्रतिशत वृद्धि	प्रति व्यक्ति आय डालरों में	प्रतिशत वृद्धि
१९४७	२०२.६		१,४०६	...
१९४८	२०८.६	३.१	१,४२४	१.३
१९४९	२११.७	१.४	१,४१८	-०.४
१९५०	२२६.५	८.०	१,५१३	७.०
१९५१	२३३.३	१.८	१,५१२	-०.१
१९५२	२३८.८	२.४	१,५२२	०.७
१९५३	२५०.७	५.०	१,५७०	३.१
१९५४	२५४.८	१.३	१,५६४	-०.४
१९५५	२६६.४	५.७	१,६३०	४.१

जनसंख्या की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कहा जा सकता है कि वार्षिक प्रणाली के विस्तार के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय लगभग २ प्रतिशत वार्षिक औसत की दर से बढ़ रही है। राष्ट्र में तीव्र विकास की भावना सन् १९४७ में यानी इस समय के प्रारम्भ में, खुशहाली के बहुत ऊँचे स्तर पर लाभों (gains) की एकत्र करके, बनाए रखी है।

(ख) सन् १९५१ की द्रुत वृद्धि के अतिरिक्त (कोरिया की लड़ाई) कीमतों में इस समय तक बड़े सुन्दर ढग से स्थायित्व (stable) बना रहा है।

वार्षिक औसत औद्योगिक उत्पादन थोक कीमतों का जीवन-निर्वाह-व्यय
का सूचकांक 'कीमत सूचकांक' (cost of living)

१९४७	१००	६६.४	६५.८
१९४८	१०४	१०४.४	१०२.८
१९४९	९७	९६.२	१०१.८
१९५०	११२	१०३.१	१०२.८
१९५१	१२०	११४.८	१११.०
१९५२	१२४	१११.६	११३.५
१९५३	१३४	११०.१	११४.४
१९५४	१२५	११०.३	११४.८
१९५५	१३६	११०.७	११४.५
१९५६	१४३	११४.३	११६.२
१९५७	१४६ (फरवरी)	११०.४ (जून)	१२०.२ (जून)

(ग) औद्योगिक उत्पादन (Industrial Production)

अमेरिका औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में सामान्य गति से, छोटे-छोटे सुधारों

एव आवश्यकतानुसार परिवर्तनों के साथ अग्रसर हो रहा है । ऊपर की तालिका के द्वितीय column से ज्ञात होता है कि औद्योगिक उत्पादन में निरन्तर उन्नति हो रही है । सन् १९४७-४८ से ६ वर्ष की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में ४३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वृत्ति कि जनसंख्या में उसी समय में १७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में २२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस प्रकार, वार्षिक लाभ का औसत २ प्रतिशत से तनिक अधिक ठहराया गया है ।

लाभ को विभिन्न उद्योगों में और आय के रूपों में कर दिया गया है (कर्म-चारियों का मुद्रावजा, व्यवसायो, लघु व्यापार, सघो) । केवल कृषि ही पिछड़ी हुई है । किसानों की आय में सन् १९५१ से ह्रास हो रहा है तथा यह परिस्थिति सन् १९५६ ई० तक बिपरीत नहीं हुई थी । यह सिद्धान्त कुछ-कुछ इस तथ्य के कारण कम हो गया था कि कृषि में ह्रास उसके पश्चात् आरम्भ हुआ था जब कि वह आर्थिक प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी थी ।

मक्षेप में कह सकते हैं कि १९४० से ५६ तक का आर्थिक विस्तार प्रदर्शन की कार्य प्रणाली से लिंकुस भिन्न है वल्कि यह सुसन्तुलित विकास को सिद्ध करता है ।

क्या समुक्त राज्य में सन्तुलनता विदेशों के शोषण पर निर्भर नहीं है ?

(Does Not Prosperity in the United States depend on the exploitation of Foreign Countries ?)

समुक्त राज्य अमेरिका अन्य देशों से वस्तुएँ विनिमय (exchange) करने में बहुत ही दिलचस्पी लेता है, क्योंकि यह मुख्यतया बहुत से आवश्यक सामानों तथा कच्चे माल जैसे कौकी, कोको, चीनी, दक्षिणी गोलाद्धं व फल, लकड़ी, गुग्गी (Pulp) ऊन, बच्चा लोहा (ore), बिना लोहे की धातुएँ (Non-ferrous metals), कुछ रसायनिक पदार्थ (chemicals) को उत्पन्न नहीं करता है । लकड़ी की सीमित पूर्ति के कारण समुक्तराज्य समाचार छपने वाले कागज के लिए आयात पर निर्भर रहता है । यह सभी प्रकार धागे वाली वस्तुओं, जो ऊँची बिस्म की होती हैं, का आयात इङ्ग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, स्विटजरलैण्ड तथा अन्य औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों से करता है । जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसने आयात की पर-तन्त्रता सम्भवतः बढ़ती जा रही है । नए कच्चे माल के स्रोतों की खोज, समुक्त राज्य अमेरिका को विदेशों में विनियोग करने के लिए निर्देशित करती है ।

विदेशी बाजार, घरेलू उपयोग के उत्पादन (Domestic Products) के निर्माण एव पूँजी के विनियोग (capital investment) के लिए मार्ग प्रस्तुत करते हैं जो अमेरिका के लिए गौण है (कृषि के आधिक्य तथा कुछ अन्य वस्तुओं को छोड़ कर ।)

संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात (exports) का मूल्य कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति (Gross National Product) का ४ प्रतिशत है, जब कि ६६ प्रतिशत उत्पन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग घर ही कर लिया जाता है। यह निर्यात अनुपात ससार में सबसे कम है। आधुनिकतम विकसित देश इंग्लैण्ड, फ्रांस, बेल्जियम, नोर्वे, डेनमार्क, स्विटजरलैण्ड, आस्ट्रिया, कनाडा, आर्जेन्टिना, न्यूजीलैण्ड तथा अन्य, अपने उत्पन्न किए हुए माल को २० से लेकर ३० प्रतिशत तक निर्यात करते हैं। भारत तथा यूथोपिया भी, संयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा अधिक निर्यात करते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति (G. N. P.) की तुलना में निर्यात एवं आयात (हजार मिलियन डॉलरों में)।

(United States exports and imports as compared with G. N. P.
(Thousand Millions of Dollars)

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति (G.N.P.)
१९२६	४४	५२-	१०४४
१९३५	२०	२३	७२५
१९४०	२६	४०	१००६
१९४५	४२	६८	२१३६
१९५०	८६	१०३	२८५१
१९५१	११०	१५०	३२८२
१९५२	१०७	१५२	२४५४
१९५३	१०६	१५८	३६३०
१९५४	१०२	१५१	३६१२
१९५५	११४	१५५	३८१७
१९५६	१२५	१८८	४१४७

संयुक्त राज्य अमेरिका आयात की अपेक्षा निर्यात में कम दिलचस्पी लेता है। क्योंकि यह विदेशी बाजारों को जीतने की कोई इच्छा नहीं रखता है। इसका (प्रथम) मुख्य कारण यह है कि उसके स्वयं का घरेलू बाजार विस्तृत है, तथा (द्वितीय) उसके आयात किये हुए माल को उठा लेने की सामर्थ्य सीमित है।

ऋण लेने वाले एवं ऋण देने वाले के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति, जैसी कि संयुक्त राज्य की पूंजी विदेशों में लगी हुई (Invested) एवं विदेशों की पूंजी संयुक्त राज्य में लगी हुई है, जो उसके अन्तर्गत निर्धारित हुई है—बदल रही है। द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक, संयुक्त राज्य अमेरिका पर विदेशों का ऋण उसके विदेशों में लगी हुई सम्पत्ति से अधिक था। इन वर्षों में, संयुक्त राज्य का अन्य देशों को ऋण देने के परिणामस्वरूप, विदेशों को ऋण चुकाने के उत्तरदायित्व बढ़ गये हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग की स्थिति डॉलर हजार मिलियन में

	१९४०	१९४५	१९५०	१९५४
संयुक्त राज्य का विदेशों में विनियोग				(Prel.)
योग	१२.३	१९.८	३२.८	४२.४
निजी क्षेत्र	१२.२	१४.७	१९.०	२६.६
सरकारी	०.१	२.१	१३.८	१५.८
सं० राज्य में विदेशी सम्पत्ति तथा विनियोग				
योग	१३.५	१७.६	१९.५	२६.८
निजी क्षेत्र	१३.२	१३.३	१४.३	१९.५
सरकारी	०.३	४.३	५.२	७.३

कुल मिला कर ऋणी (Debtor) (—) अथवा ऋणदाता (Creditor) (+) की स्थिति :

—१.२ —०.८ +१३.४ +१५.५

महायुद्ध के पश्चात् संयुक्त राज्य ने विदेशों को व्यापारिक विनियोग की अपेक्षा विदेशी सहायता के रूप में ही ऋण दिया है। जब ये ऋण विदेशों में लगी हुई सम्पत्ति अथवा भुगतान करने वाली सम्पत्ति (Assets) एवं हिसाब के उत्तरदायित्व (Liability accounts) से अलग कर लिये जाते हैं तो प्रतीत होता है कि विदेशों को भुगतान करने वाली सम्पत्ति (Assets) उसके उत्तरदायित्वों (Liabilities) के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में (Balance) में रह जाती है।

संयुक्त राज्य में विदेशों के विनियोगों की महत्वहीन आय की तुलना में राष्ट्रीय आय के आँकड़े निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किये जाते हैं :

डॉलर हजार मिलियन में

	१९४०	१९४५	१९५०	१९५५
विदेशों के विनियोग से संयुक्त				
राज्य की आय (+)	+०.६	+०.६	+१.६	+२.५
संयुक्त राज्य का विदेशी विनियोगी				
पर भुगतान करना (—)	—०.२	—०.२	—०.४	—०.५
कुल लाभ (+) अथवा हानि (—)	+०.४	+०.४	+१.२	+२.०
अन्ततः संयुक्त राज्य में होने वाले				
हस्तान्तरण की तुलना	+०.२	—०.६	—५.५	—०.५
घन की सरकारी स्वीकृति, मैनिक				
एवं आर्थिक सहायता इत्यादि	—०.१	—१.०	—४.१	—४.१

समग्रतः, संयुक्त राज्य की विदेशों को सहायता एवं अमरीकियों का विदेशों में रहने वाले सम्बन्धियों को दिया हुआ ऋण उनके विदेशी विनियोग की आय से अधिक होता है।

५—परिणाम

(The Results)¹

(क) पूँजीवाद के अपने निजी बहुत से अवयुग होते हुए भी, अमेरिका में बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। (ख) प्रतीत तथा वर्तमान के अनुभवों में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी भिन्न प्रकार की प्रणाली ■ इससे अधिक अच्छे परिणाम निकल सके। (ग) एक उच्च विकसित ग्रह व्यवस्था वाले मयुक्त राज्य अमरीका का क्षेत्रफल समार की भूमि का ६३ प्रतिशत है। अमरीकियों की जनसंख्या समार की जनसंख्या का लगभग ६६ प्रतिशत है। मयुक्त राज्य की 'वार्षिक पुस्तक' में वर्णित राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका की राष्ट्रीय आय सम्पूर्ण मानव जाति की प्राचीन आय का प्रतिनिधित्व करती है—सन् १९५५ में कुल ८००-९०० बिलियन डॉलर में से ८०० डॉलर थी (इन आंकड़ों में राष्ट्रीय आय के गुप्त विषयों को सम्मिलित नहीं किया गया है जोकि अमेरिका के योग में कम से कम १० प्रतिशत की और वृद्धि करेंगे, तथा समार के योग में पाँचवे भाग की वृद्धि करेंगे)। अमरीकी जनता समार की वस्तुओं एवं सेवाओं का $\frac{2}{3}$ भाग उत्पन्न करती है, तथा सम्पूर्ण उत्पादित वस्तुओं का $\frac{1}{3}$ और $\frac{2}{3}$ भाग के बीच में उत्पादन करते हैं।

उपभोग्य शक्ति का परिमाण तथा फौलाद औद्योगिक विकास के लिय सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैं। मयुक्त राज्य में सब साधनों में उपभोग की हुई शक्ति सन् १९५१ में, जो कोयले के टनों में परिवर्तित कर दी गई थी, १.२ बिलियन टन थी। सन् १९५३ में मयुक्त राज्य अमेरिका ने १०० मिलियन टन से अधिक इस्पात उत्पन्न की। सन् १९५५ में इस्पात का उत्पादन ११५ मिलियन टन तक पहुँच गया।

अनाज की उत्पाति कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। सन् १९५२ में, मयुक्त राज्य अमेरिका ने, समार की अनाज की पांच मुख्य फसलों का २६ प्रतिशत भाग पैदा किया था।

मयुक्त राज्य की सड़क यातायात के विषय में सभी भली प्रकार से जानते हैं। अमेरिका के मोटर गाड़ी उत्पन्न करने के उद्योग आवासीय कुछ वर्षों में, ३० मिलियन यात्री गाड़ियों की और वृद्धि करेंगे, जोकि आजकल प्रायः ५० मिलियन हैं। सन् १९५५ में, मयुक्त राज्य अमेरिका का वायुयान यातायात समार के समस्त वायुयान यातायात का आधे से अधिक था।

यात्रियों के लिए प्रयुक्त होने वाले सम्पूर्ण समार के ८० प्रतिशत वायुयानों का निर्माण अमेरिका में हुआ। मयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापारिक उद्देश्यों में

1 *American Capitalism*—Massimo Salvadori. (American Reporter Book Supplement, Feb 27, 1957, Ch IV, pp. 45—56)

प्रयुक्त होने वाले वायुयानों की संख्या १२,००० है तथा इनकी संख्या में बड़ी द्रुत गति से वृद्धि हो रही है। ससार के लगभग $\frac{1}{3}$ व्यापारिक जलयानों (Merchant shipping) का निर्माण अमेरिका के व्यापारिक जहाजों बेड़े (Fleet) में निर्माण हुआ है।

(ख) परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था (Dynamic Economy), जो जॉर्ज सोल (George Soule) के अनुसार, "वास्तविक कुल राष्ट्रीय उत्पाति में सन् १९४१-१९५० के दशक में एव १८९१-१९०० के दशक की अपेक्षा पांच गुने से भी अधिक वृद्धि हुई जबकि जनसंख्या केवल दूनी ही हुई पचगुने उत्पादन में बवल ८१ प्रतिशत श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी।...प्रति व्यक्ति की घण्टे का उत्पादन १९४१-१९५० में सन् १८९१-१९०० में १८१ प्रतिशत अधिक था, क्योंकि १९५० से पूर्व ८० वर्ष तक मध्यम राज्य के प्रति व्यक्ति की आय में १.९ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई। प्रति परिवार की औसत आय १,००० डॉलर से लेकर ४,००० डॉलर प्रतिवर्ष बढ़ी। (समान क्रम शक्ति के डॉलर में)।

कृषि उत्पादन में, युद्ध से पूर्व के औसत एव १९५२-५३ के औसत में, ३८ प्रतिशत की वृद्धि हुई (संयुक्त राज्य की 'आंकड़े सम्बन्धी वार्षिक पुस्तक' के आधार पर निकाला हुआ प्रतिशत) आज कल अमेरिका की अर्थव्यवस्था ४ से ६ प्रतिशत वार्षिक दर से विस्तृत हो रही है। १७ प्रतिशत १९५५ में विस्तृत हुई थी)।

(ग) रहन-सहन का स्तर (Standard of Living)

संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग ५० मिलियन पारिवारिक इकाइयाँ हैं। ४० मिलियन से अधिक परिवारों में २ या अधिक व्यक्ति हैं। शेष में मुख्यतया वे व्यक्ति हैं जो बहुत ही छोटे अथवा वृद्ध हैं। अमेरिका के आधे से अधिक परिवार अपने निजी मकानों में रहते हैं। वहाँ एक मकान में अधिक व्यक्ति नहीं रहते। ८३ प्रतिशत घरों में परिवार के हर सदस्य के लिए एक कमरा है, और कहीं कहीं इससे भी अधिक हैं। जनसंख्या की तुलना में, सन् १९५३ में अमरीकियों ने अंग्रेजों में ६० प्रतिशत एव रूसियों से १२० प्रतिशत अधिक गृह घरों का निर्माण किया। अमरीकी परिवारों के पास ५० मिलियन से अधिक मोटर, ३० मिलियन टेलिविजन सेट, १२५ मिलियन रेडियो सेट हैं। देश में ५० मिलियन से भी अधिक टेलीफोन हैं। गोश्त, रोटी, मक्खन, आलू तथा चीनी का एक एक किलो (kilo) खरीदने के लिये सन् १९५१ की सदियों में, संयुक्त राज्य में, औसत औद्योगिक मजदूरी के अनुसार, कार्य करने का समय २ घण्टा ४० मिनट था; जबकि दूरी के लिये ब्रिटेन में ३ घण्टा कार्य करना आवश्यक था एव मोबिलिटी संघ में इनकी प्राप्ति के लिये २० घण्टा कार्य करना आवश्यक था। एक सूनी पोशाक, एक मर्दाना सूट, एक जोड़ी जूता खरीदने के लिये संयुक्त राज्य में, औसत मजदूरी (या वेतन) के अनुसार, कार्य करने का समय ५० घण्टा, ब्रिटेन में ६६ घण्टा तथा

सोवियत संघ में २५८ घन्टा था। किन्तु, इतना होने पर भी, अमरीकी यह नहीं सोचते हैं कि वे जीवन-स्तर के “आदर्श” तक पहुँच पाये हैं। वे जीवन-स्तर में और उन्नति प्राप्त करने के लिये ज़रूरी से कार्य करते चले जा रहे हैं।

(घ) आय (Income)

सन् १९३५ में अमरीकियों की व्यक्तिगत आय ३०० बिलियन (Billion) डॉलर थी। उनमें से ८० प्रतिशत धर्मिकों के मुआवजे की प्रकट करना है। केवल वेतन इत्यादि ही इस मद के अन्दर अक्सर रखे जाते हैं, जैसे किसान की आय खेत की जोतकर होनी है, छोटे छोटे व्यापारियों की आय अपनी दुकान से, जिसमें वह कार्य करता है, होती है, व्यवसायी व्यक्ति अपनी कुशलता से, धर्मिकों या इसमें भ्रष्टाचार सम्मिलित नहीं है। सन् १९३० में, जबकि कुल व्यक्तिगत आय २२३ बिलियन डॉलर थी १४३ बिलियन (सार्वजनिक बोम एव उपहारों को निकालकर) वेतनों एव दावों से पैदा किया जाता था, जो ३,२०० डॉलर वार्षिक औसत की दर से प्राप्त करते थे। ३३ बिलियन अपने स्वयं के कार्य द्वारा पैदा किया जाता था (किसानों, व्यापारियों तथा व्यवसायी लोगों द्वारा) जो ४,००० डॉलर औसत के अनन्त प्रति व्यक्ति के वार्षिक हिसाब से प्राप्त करते थे। ‘भूमि-मूँजी’ में किराये भुगतान तथा बितरित लाभों के रूप में) २२ बिलियन अथवा कुल योग का दसवा भाग आय थी, जो लगभग १३ बिलियन व्यक्तियों के बीच विभाजित की जाती थी (१५०० डॉलर प्रति व्यक्ति की औसत से) जो कि अधिकांश में व्यवसाय में तथा दुष्प्रभाव स्वयं व्यवसाय वाले थे। १४३,३५ तथा २२ बिलियन और २२३ बिलियन के मध्यमान हिसाब मुख्यतया हस्त-श्रम भुगतान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

(ii) समूहवादी (Collectivists) अमेरिका के व्यापार के लाभ से भयभीत हो गये हैं। वे एक और कुछ सँकड़े अथवा हवार भ्रष्ट पूँजीपतियों को अधिक मात्रा में लेकर कार चलाते हुए तथा बड़ा आलसपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए देखते हैं जवनि दूसरी ओर ‘लाखों कर्मचारी भूखों मरते हैं।’ इस विचारधारा को ठीक करने के लिए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि (१) पूँजीपति कुछ भी अथवा हवार नहीं है बल्कि कई मिलियन है। (२) पूँजीपति के धन का परिमाण अमेरिका में बहुत विशाल है। सन् १९५० में अमरीकी व्यापार को ४३ बिलियन डॉलर का लाभ हुआ, उनमें से २२ बिलियन करो के रूप में दे दिया गया, १२ बिलियन का फिर से विनियोग किया गया एव व्यक्तिगत आय के रूप में उत्पादकों को केवल ९ बिलियन डॉलर ही प्राप्त हुआ।

(iii) अमेरिका की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग, जो कि अर्द्ध-कुशल एव औद्योगिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, लगभग ६५ मिलियन है— वह समस्त धर्मिकों का प्रायः ३ भाग है। अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों के अधिकतर

परिवारों की वर्तमान आय ४,५००—५,००० डालर वार्षिक है ; कुशल कर्म-चारियों के अधिकतर परिवारों की आय ५,०००—६००० डालर तक वार्षिक है ।

(iv) सन् १९५३ में, लगभग $\frac{1}{3}$ जनसंख्या की आय २,००० डालर अथवा उससे कम थी, जो एक औसत अमरीकी की दृष्टि में, उपयुक्त एवं उचित आय से पर्याप्त कम थी ।

आर्थिक श्रेणियाँ (Economic Classes) :

संयुक्त राज्य में आय के भेद का स्तर गिरता जा रहा है । जनसंख्या के उच्चतम ५ प्रतिशत भाग ने, सन् १९२८ में, कुल आय का ३४ प्रतिशत तथा सन् १९४८ में १८ प्रतिशत से भी कम प्राप्त किया । अमेरिका की जनसंख्या का सबसे कम वेतन पाने वाला वर्ग, अकुशल श्रमिकों तथा कर्मचारियों का है, जो सन् १९३० में सम्पूर्ण श्रम शक्ति के $\frac{1}{3}$ का प्रतिनिधित्व करता था तथा सन् १९५० में केवल $\frac{1}{4}$ का प्रतिनिधित्व करता था । आय के नीचे गिरने का उदाहरण, अक्टूबर, १९५५ के 'न्यूयार्क टाइम्स' (New York Times) में प्रकाशित आकड़ों की सख्या से प्राप्त होता है जो सन् १९०४ एवं सन् १९५४ के पाँच विभिन्न वर्गों (सभी कर्मचारी जो उद्योगों में काम कर रहे हैं, मोटर गाड़ियों के कर्मचारी, रेलवे के इन्जीनियर्स, महाविद्यालयों के अध्यापक, रेलवे सभ के कार्यकर्ता) से सम्बन्ध रखता है । निर्माण करने वाले सभी उद्योगों के कर्मचारियों की आय को १ मान लिया जाय तो, १९०५ में अन्य वर्गों की आय १.२, २.७, ४.२, ५.८ या सन् १९५४ में १.२, १.६, १.३, २.६ थी । दो अत्यधिक भेद रखने वाले वर्गों के मध्य का अन्तर आधा हो गया है ।

यह देखने के लिए कि अमरीका की आर्थिक प्रणाली का क्या स्थान है, यह सबसे अच्छा होगा कि इसकी सोवियत रूप के समूहवाद से तुलना की जाय । प्रत्येक व्यक्ति दोनों राष्ट्रों में तीन मुख्य आर्थिक वर्गों को स्पष्ट देखेगा (१) सोवियत सभ के किसान एवं संयुक्त राज्य के किसान (२) उद्योग कर्मचारी तथा श्रम जातियों के व्यवसायों में अपेक्षाकृत थोड़े व्यक्ति (३) प्रबन्धक वर्ग ।

(घ) आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) :

रूजवेल्ट के सामाजिक सुरक्षा कानून (Social Security Act) में सुधार होने के परिणाम स्वरूप जो सन् १९५० तथा १९५४ में कार्य रूप में परिणत किये गये थे, लगभग सभी लाभ पर प्रयुक्त कर्मचारी (Gainfully employed) तथा आत्म-नियुक्त (Self-Employed), सघातक वृद्धावस्था एवं उत्तरजीवी बीमा (Federal old age and Survivors' Insurance) द्वारा लाभान्वित होते हैं । जो व्यक्ति ३५० डॉलर मासिक अथवा इससे अधिक का अर्जन करते हैं, वे ६५ वर्ष की आयु में यदि मरेंगे तो, १०८.५० डॉलर मासिक प्राप्त करते हैं, यदि विवाहित हैं तो १६२.८० डॉलर मिलता है । विधवा अथवा मृतक कर्मचारी पर आश्रित एक प्राणी—जिस कर्मचारी की मासिक आय ३५० डॉलर थी—८१.४० डॉलर मासिक

प्राप्त करते हैं और दो आश्रित प्राणी १६२.०० डॉलर प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति के लिए अवकाश लाभ (Retirement Benefits) और उत्तरजीवी लाभ २० डॉलर मासिक में कम नहीं हो सकता।

संगठित कर्मचारियों की सभी थ्येणियो में सघात्मक बीमा (Federal Insurance) के अतिरिक्त पेंशन की भी योजनाएँ हैं। खाने, फीलाद, मोटर, तेल, वस्त्र-उद्योग—केवल कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों का ही उल्लेख किया गया है—मपने सभी थ्येणियों के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को १०० डॉलर से १२० डॉलर मासिक पेंशन देते हैं। अध्यापक, चिकित्सक तथा अन्य व्यावसायिक व्यक्ति अपनी स्वयं की पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं। अस्वस्थता एवं दुर्घटना के लाभ (Sickness and accident benefits) अधिकतर उद्योगों द्वारा भुगतान किये जाते हैं। सन् १९५५ तक सघात्मक मजदूरी कम से कम ७५ सेंट (cents) प्रति घण्टा थी। उस साल वह एक डॉलर तक हो गई।

बेरोजगार कर्मचारी (हाल की ३-४% श्रम-शक्ति) भी वेतन प्राप्त करते हैं जो हर राज्य में भिन्न-भिन्न है, अधिक सम्पन्न राज्यों में साधारण पैदा का आधे के लगभग भुगतान किया जाता है। सन् १९५५ में अमरीकी परिवारों की वचत २०० बिलियन डॉलर के लगभग थी। वचत में ४ प्रतिशत सालाना से भी अधिक की दर से वृद्धि हुई। बिना वचत वाले परिवारों की संख्या घट रही है।

ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ¹

(Economy of Great Britain)

१—राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (National Economy)²

ग्रेट ब्रिटेन का संसार के देशों में, आकार की दृष्टि से लगभग ७५ वाँ स्थान है, संसार की भूमि का लगभग ०.१८ प्रतिशत है। जन-संख्या में इसका नवाँ स्थान है, जहाँ संसार के २ प्रतिशत निवासी हैं तथा जनसंख्या के घनत्व में इसका चौथा स्थान है, मुख्य देशों में केवल जापान, बेल्जियम तथा नीदरलैंड्स ही अधिक घन हैं, ग्रेट ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रति वर्ग मील ११ गुना व्यक्ति रहते हैं। संसार के व्यापार में इसका दूसरा स्थान है, जिसका योग, कुल योग का १० प्रतिशत से भी अधिक है। निमित्त माल का निर्यात करने में, संसार के निर्यात में, इसका पाँचवाँ स्थान है।

ग्रेट ब्रिटेन, अपनी स्वयम् की भूमि से, अपनी आवश्यकता का आधा ही साधन पदार्थ उत्पन्न कर पाता है, तथा कोयले एवं निम्न श्रेणी के कच्चे लोहे को छोड़कर इसके प्राकृतिक साधन बहुत कम हैं। इस प्रकार यह संसार की ऐसी वस्तुओं जैसे, गेहूँ, गोشت, मक्खन, चारा, अनाज, फल, चाय, तम्बाकू, ऊन तथा कड़ी इमारती लकड़ी का सर्वाधिक आयात करने वाला देश है। इसके बदले में यह संसार का एक बड़ा समुद्री जहाज, हवाई जहाज, रेल् के इंजन, मोटर गाड़ियाँ, बिजली का सामान, रसायन, सूती वस्त्र तथा सब प्रकार की मशीनों का निर्यात करने वाला देश है।

1. Courtesy : U. K. High Commission in India, New Delhi, and British Information Services, New Delhi.

2. 'Britain, an Official Handbook, 1959, Ch. VIII, pp. 226—236 (Courtesy): The Director of British Information Services, New Delhi.

२—उद्योग (Industry¹)

इङ्ग्लैण्ड में सर्व प्रथम सर्वाधिक औद्योगीकरण किया गया। एक आदमी कृषि का कार्य करता है तो ११ आदमी खानो तथा कारखानों में काम करते हैं। जन-संख्या के प्रतिशत की दृष्टि में, निर्मित भान का निर्यात करने में इङ्ग्लैण्ड सगार में सबसे प्रमुख देश है। औद्योगिक उत्पादन के विस्तार के कारण यह सगार की अद्वितीय कर्मशाला (Workshop of the World) की स्थिति को प्रकट करता है।

उद्योग का स्वरूप (Structure of industry) :

यहां स्वामित्व की प्रणाली (The pattern of ownership) तथा उद्योग का संगठन कई प्रकार का है। निजी, सघ, सहकारी तथा सार्वजनिक जोखिम प्रादि बहुत सी भिन्न प्रकार की प्रणालियाँ हैं, तथा अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण हैं। औद्योगिक जोखिम, बहुत सी छोटी कर्मशालाओं (Small workshops) से लेकर बड़े संगठन, जैसे राष्ट्रीय कोयला परिषद (Coal Board), एक सरकारी सस्था, जिसमें ७००,००० कर्मचारी कार्य करते हैं, इम्पीरियल कैमिकल इन्डस्ट्री (Imperial Chemical Industries Ltd.), एक सीमित उत्तरदायित्व सस्था (a limited liability company) जो अपने सहायकों सहित ११५,००० व्यक्तियों को रोजगार देती है, तथा सीमित सहकारी थोक विक्रेता समिति (Co-operative Wholesale Society Ltd.), एक सहकारी समिति जिसमें लगभग ५०,००० कर्मचारी कार्य करते हैं, तक इससे भिन्न हैं।

सार्वजनिक जोखिम का सहयोग (Role of the public enterprise) :

बीसवी सदी के पूर्वार्द्ध में, सामाजिक सेवाओं की उन्नति, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास ने, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र को धीरे-धीरे अधिक प्रभावित किया। उत्पादक आर्थिक क्रियाओं में राज्य ने प्रत्यक्ष रूप से अधिक भाग लिया, विशेष रूप से, १९४०—५० के दशक में। सन् १९५१ से कोलाद उद्योग का अधिकांश तथा ब्रिटिश यातायात आयोग (British Transport Commission) की सेवाएँ सार्वजनिक स्वामित्व से व्यक्तिगत स्वामित्व में आ गई हैं। राज्य का हस्तक्षेप, विशेष व्यवस्था से स्थापित की हुई सस्थाओं—जो किसी विशेष कार्य को सुलभाने के लिए स्थापित की जाती हैं—के माध्यम से प्रभावित करता है। ऐसी सथायें, यद्यपि किसी सरकारी विभाग का अंग नहीं होती हैं और पर्याप्त सीमा तक सरकारी नियन्त्रण में होती हैं, फिर भी सरकारी नियन्त्रण से भिन्न होती हैं। इस व्यवस्था से स्थापित की हुई सस्थाओं में सर्व प्रमुख सार्वजनिक निगम

(Public Corporations) हैं जो जनता के हित में बड़े उद्योगों और सेवाओं का संचालन करते हैं ।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् राष्ट्रीयकरण कानून के अन्तर्गत सार्वजनिक निगमों का कुछ बड़े उद्योगों, सेवाओं, कोयले की खानों, आन्तरिक यातायात, गैस की पूर्ति, विद्युत बनाने एवं उसकी पूर्ति करने तथा नागरिक वायु यातायात (Civil Air Transport) का संचालन करने के हेतु निर्माण हुआ ।

उत्पत्ति एवं उत्पादनक्षमता ((Production and Productivity) :

औद्योगिक उत्पत्ति—इसमें युद्ध के बाद तीव्र वृद्धि हुई, क्योंकि उद्योगों में युद्ध की सामग्री का उत्पादन न होकर अन्य जीवनोपयोगी पदार्थ बनने लग गये थे तथा मानव शक्ति सेना से छुटकारा पाकर निर्माण कार्य में लग गई थी । सन् १९४६ तक युद्ध से पूर्व के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया गया तथा सन् १९४८ में यह निर्माण १५ प्रतिशत अधिक हो गया । सन् १९४८ से १९५६ तक की उत्पत्ति, रोजगार तथा उत्पादन क्षमता को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया जा रहा है

वर्ष	औद्योगिक उत्पत्ति	उद्योग में रोजगार	उद्योग में प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उत्पादन
१९४८	१००	१००	१००
१९४९	१०६	१०२	१०५
१९५०	११४	१०३	११०
१९५१	११७	१०६	१११
१९५२	११४	१०५	१०८
१९५३	१२१	१०६	११४
१९५४	१२०	१०८	१२०
१९५५	१३७	१११	१२३
१९५६	१३६	११२	१२२
१९५७	१३८	११२	१२४

सन् १९४८ से १९५७ तक औद्योगिक उत्पत्ति ३८ प्रतिशत बढ़ गई । उद्योग में लगे हुए कमचारियों की सराया केवल १२ प्रतिशत ही बढ़ी, जिससे कि प्रति व्यक्ति के उत्पादन में २४ प्रतिशत की वृद्धि हुई । उत्पत्ति की यह वृद्धि, उन्नत पद्धतियों की कुशलतापूर्वक अपनाने के परिणामस्वरूप हुई । सन् १९५४-५८ में उत्पत्ति में बहुत थोड़ा अन्तर प्रकट हुआ है । इसका मुख्य कारण मुद्रा प्रसार की प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण करना था ।

युद्ध के पश्चात् सबसे अधिक वृद्धि सन् १९४८-५७ की वृद्धि सहित-इंजीनियरिंग, जहाज बनाने और विद्युत के सामान के वर्ग, मोटरगाड़ियों के वर्ग,

रासायनिक वर्ग ; कागज तथा छपाई के वर्ग ; और गैस, विद्युत एवं जल के कार्यों में क्रमशः ५५% ; ६५% ; ६२% ; ६६% तथा ६३% वृद्धि हुई। सन् १९४८-५७ में कारखानों तथा अन्य औद्योगिक संस्थाओं में विद्युत शक्ति का उपयोग दूना हो गया।

प्रबंध (Management) .

ब्रिटिश उद्योग में उत्पादन क्षमता की वृद्धि में योग देने वाला प्रमुख साधन प्रबंध की नवीन पद्धतियों के विकास का होना रहा है। वर्तमान सदी में, विशेषकर द्वितीय युद्ध में तथा युद्ध के पश्चात् में ब्रिटेन में—अन्य देशों के समान ही—प्रबंध के महत्व की बढ़ती हुई जायति में, विशेष कुशलता तथा ज्ञान का विषय अत्यन्त समझा जाने लगा।

यह कुछ सीमा तक संचार के बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उत्पत्ति को बढ़ाने की आवश्यकता द्वारा प्रोत्साहित किया गया है तथा आशिश रूप से यह पूर्ण रोजगार की परिस्थितियों तथा मुख्य वस्तुओं, जैसे फौलाड़ की पूर्ति के दबाव से प्रोत्साहित किया गया है। समग्रतः सन्तुष्ट के सबसे प्रभावशाली रोजगार, सामान तथा मशीनरी के संगठन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, उद्योग में मानवीय सम्बन्धों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है तथा प्रबंध और श्रम के मध्य की बातचीत को अधिक महत्व दिया जा रहा है। बहुत ही विशेष प्रबंध वाली संस्थायें अस्तित्व में आ गई हैं, जो सहायता के लिए शैक्षणिक तथा अन्य गुणों की मांग करती हैं। प्रथम युद्ध के समय से व्यवसायिक एवं इंजीनियरिंग संस्थाओं ने अपनी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में औद्योगिक प्रशासन (Industrial Administration) को भी जोड़ लिया है।

कुल उत्पादन (Net output) के रूप में, विभिन्न वर्गों के तुलनात्मक महत्व का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है, जो सन् १९५४ की उत्पत्ति की गणना के परिणामों एवं सन् १९५६ की निर्धारित सुविधाओं पर आधारित है।

उद्योग वर्गों का सन् १९५४ एवं १९५६ का कुल उत्पादन
(Net Output of Industry groups in 1954 and 1956)

	१९५४ पौण्ड दस लाखों में	१९५६* पौण्ड दस लाखों में	योग का प्रतिशत
धातु सम्बन्धी निर्माण (Metal Manufacture)	५१९.४	६५५.१	६१

जहाज निर्माण, इंजीनियरिंग तथा विद्युत का सामान (Ship building, Engi- neering and Electrical goods)	१४६७.७	१,७३७ £	२४ २
मोटर गाड़िया (Vehicles)	७०७ ७	८०४ ७	११ २
विभिन्न धातुओं सम्बन्धी उत्पत्ति (Miscellaneous Metal Products)	३३७.३	४०५ ७	५ ७
रासायनिक एवं अन्य सहायक व्यापार (Chemical and allied Trades)	५२८ ६	६१२ ५	८.५
सूत एवं कपड़े का कार्य (Textile and Clothing)	६१५ ७	६३५ ४	१३.०
भोजन, पेय तथा तम्बाकू (Food, Drink and Tobacco)	५६४ ४	६६८ ८	६ ४
अन्य निर्माण करने वाले उद्योग (Other Manufacturing Industries)	१२०५ १	१,३५१ १	१८ ६
योग	६२७६ २	७,१७१ २	१००

Source Board to Trade Journal

३—कृषि (Agriculture)¹

यद्यपि ग्रेट ब्रिटेन सघन वसा हुआ है तथा औद्योगिक देश है, जो अपने प्राये
खाद्य-पदार्थ की पूर्ति आयात करके करता है, फिर भी कृषि वहाँ का सबसे बड़ा एवं
महत्वपूर्ण उद्योग है। इसमें लगभग १० लाख व्यक्ति कार्य करते हैं अथवा नागरिक-
रोजगार (Civil Employment) के ४ प्रतिशत सलग्न हैं। राष्ट्र की कुल उत्पत्ति
का ४ प्रतिशत प्रदान करना है, जिसमें ६०० लाख एकड़ भूमि में से ४८० लाख
एकड़ भूमि का प्रयोग किया जाता है।

(१) खेन सङ्ख्या एवं स्वामित्व (Farms Numbers & ownership) :

सम्पूर्ण वजर चरागाहों को छोड़ कर ब्रिटेन में लगभग ५२३,००० कृषि चक
(Agricultural holdings) हैं। ३१६,००० इंग्लैण्ड में, ५५,००० वेल्स में, ७१,
००० स्कॉटलैंड में तथा ८१,००० उत्तरी आयरलैंड में हैं। कुल योग का ३/५ चक
आकार में ५० एकड़ से भी कम है। जो दस लाख व्यक्ति कृषि में कार्य करते हैं
उनमें से १/३ किसान हैं, शेष वेतन पाने वाले कर्मचारी अथवा किसानों के परिवारों
के सदस्य हैं। बहुत से किसानों के पास स्वतन्त्र रूप से अपने खेत हैं, लेकिन अधिक-

तर प्रचलित प्रबन्ध में किरायेदार (Tenant) हैं जिससे वे अपनी खेती कर सकें तथा पशुओं, फसल एवं घत सामग्री को अपने स्वामित्व में रख सकें जबकि जमींदार जमीन, मकान तथा अचल सामग्री के स्वामी होते हैं तथा उनकी सुरक्षा एवं उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। सन् १९५० में संयुक्त राज्य के खाद्य एवं कृषि संगठन के लिए की गई गणना के अङ्कों से ज्ञात हुआ था कि इंग्लैण्ड तथा वेल्स के ३६ प्रतिशत चको के स्वामी वे ही लोग थे जिनके कि वे अधिकार में थे, ४६ प्रतिशत पूर्णरूप से किराये पर उठाये जाते थे, १५ प्रतिशत का कुछ अंश स्वामित्व में था तथा कुछ अंश किराये पर डराया जाता था।

कृषि के प्रकार (Types of farming)

इंग्लैण्ड और वेल्स की कुल कृषि योग्य भूमि जो २६६ मिलियन एकड़ है, में से २४५ मिलियन एकड़ भूमि फसल तथा घास के लिए है। अधिकतर खेत मिश्रित खेत हैं, लेकिन मामान्य रूप से इंग्लैण्ड का पूर्व का प्रायः भाग विशेषरूप से जोतने बोलने के लिए है, तथा पश्चिमी पक्ष प्रायः वेल्स सहित डेरी फार्मिंग के लिए सुरक्षित है। कृषि योग्य भूमि के ३७ प्रतिशत चरागाह है, २२ प्रतिशत जोतने एवं बोलने योग्य भूमि तथा २६ प्रतिशत मिश्रित है। शेष अवर्गीकृत (unclassified) है अथवा कृषि की दृष्टि से बहुत कम महत्व की है। मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, घास, चुकन्दर तथा चारा हैं। स्कॉटलैण्ड में कुल १५० लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि में से ४०^१ लाख एकड़ फसलों तथा घास के लिए हैं तथा शेष पहाड़ी चरागाह है।

सन् १९३७-५७ (जून) में ब्रिटन में पशु समुदाय (दम लाखों में)

	१९३६	१९४४	१९५३	१९५४	१९५५	१९५६	१९५७
दुग्धशाला के पशु	३६	४४	४५	४६	४५	४७	४७
अन्य पशु	५०	५१	५६	६२	६२	६२	६२
भेड़	२६६	२०१	२२५	२२६	२२६	२३६	२४८
सुअर	४४	१६	५२	६३	५८	५५	६०
मुर्गी	७४४	४५१	६२१	८३६	८६६	६२५	६४६

Source Monthly Digest of Statistics

३. उत्पत्ति (Production)

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व ब्रिटन ने खाद्य पदार्थों की पूर्ति का लगभग ३१ प्रतिशत मनुष्य के उपभोग के लिए कैंतोरीज के रूप में उत्पन्न किया। यह सन् १९५७ तक ४० प्रतिशत के लगभग हो गया।

४. वातायात एवं संचार प्रोत्साहन (Transport and Communication, Propulsion)

* श्रेण्टे (coal fired) का परिमाण इन्हीं कुछ वर्षों में १० लाख टन से भी P 309) १। भाप द्वारा चालित जहाजों में कोयले का स्थान तेल ने ले लिया है

जबकि भाप ने अपना स्थान डीजल इंजन को दे दिया है। सन् १९५७ में लगभग, सभी टनेज (Tonnage) का ४५ प्रतिशत कार्य डीजल से लिया गया। हाल ही में, जहाजों में, भाप से चलने वाले यन्त्रों (gas turbines) का उपयोग करने के प्रयोग किये गये हैं।

ग्रेट ब्रिटेन के व्यापारिक जहाजों (Merchant fleet) का
सन् १९५७ के आकार का वितरण

टनेज वर्ग (Tonnage group)	सभी जहाज		ब्रिटेन के जहाज	
	जहाजों की संख्या	ग्रास टन	जहाजों की संख्या	ग्रास टन
१०० तथा ५०० ग्रास टन से कम	१,८५२	४,६२,७७६	१६६	४३,५४४
५०० " २,००० " "	१,६६८	१२,२५,३६६	८०	७७,६७७
२,००० " ६,००० " "	६८२	२,७६२,६०६	४०	१२७,४११
६,००० " १०,००० " "	११६७	८,६४६,६४३	२४६	१६,६६,०४५
१०,००० " १५,००० " "	३४८	३६,०६,६११	२१३	२४,३४,६६८
१५,००० " २५,००० " "	६४	१८,२२,३४४	४६	८७,८३,१५
२५,००० " ३०,००० " "	१८	४,६०,०५६	१	२५,०००
३०,००० ग्रास टन तथा अधिक	४	२,३४,७५६		
	५४२७	१६८५७४६१	७६२	५५८५८६०

सन् १९५२ का ब्रिटिश घरेलू माल यातायात (British Domestic freight Transport, 1952)

(Source : Lloyd's Register of Shipping)

	टन carried लाखों में	दस टन माईलेज हजार मिलियन में	टन carried का प्रतिशत	टन माईलेज का प्रतिशत
रेल	३०० ^१	२२	२४	४३
सड़कें	६००	१६	७२	३७
समुद्र तटवर्ती जहाज	४०	१० ^२	३	२०
अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग	१०	०.२	१	
योग	१२५०	५१२	१००	१००

Source Paper by K.F Glover and D N Milles, Read before the Royal Statistics Society, 28 th April, 1954.

1. Tons originating, Including, Free hauled traffic,
2. The 'Inland' Equivalent, that is ton milage by inland transport that would result of the coastwise traffic passed by inland means of carriage.

५—श्रम (Labour)

जून १९५२ के अन्त में ग्रेट ब्रिटेन की काम करने वाली कुल जनसंख्या के २४० लाख थी, जो कुल जनसंख्या की ४२ प्रतिशत के लगभग थी, तथा सामान्य रूप से काम करने वाले उम्र के लोगों की जनसंख्या लगभग ७३ प्रतिशत थी (स्त्रियों के लिए १५ वर्ष से ५६ वर्ष तक तथा पुरुषों की १५ से ६४ वर्ष)। वास्तव में, काम करने की उम्र के ६६ प्रतिशत अंग्रेज आजकल लाभ के कार्य करते हैं अथवा खोज में रहते हैं। सेप ४ प्रतिशत में मुख्यतः वे लोग हैं जो अपनी शिक्षा को जारी रखते हैं, अथवा संबंधी काम के अयोग्य हैं तथा कुछ व्यक्ति अपना व्यक्तिगत व्यापार करते हैं। काम करने की उम्र वाली स्त्रियों का लाभ के काम की खोज करने का अनुपात बहुत कम है, ४६ प्रतिशत घर की स्त्रियों की इच्छा घर से बाहर जाने की होती ही नहीं है, और यदि वे ऐसा करना चाहती हैं तो घरेलू कार्य उनके पैरों में जकड़ डाल देता है। सामान्य रूप से काम के उपयुक्त आय के व्यक्तियों के प्रतिरिक्त दस लाख बृद्ध पुरुष एवं स्त्रियाँ अब भी काम करती हैं। काम करने वाली जनसंख्या का अधिकांश मजदूरी या वेतन के लिए काम करता है, लेकिन १५ तथा १७ लाख नियोजता (Employers) तथा आत्म नियुक्त (Self-Employed) हैं।

ग्रेट ब्रिटेन में सामान्य मानव शक्ति की स्थिति (हजार में)

	जून १९४८ के अंत में	जून १९५७ के अंत में	जून १९५८ के अंत में
कुल कार्य योग्य जन संख्या ¹			
पुरुष	११,६५७	१६,२२५	१६,१६६
स्त्रियाँ	७,१२३	७,६६३	७,६०४
योग	२२,७८०	२४,१८८	२४,०७०
H M शक्तियाँ स्त्रियों की सेवाओं सहित			
पुरुष	२०७	६८७	६००
स्त्रियाँ	३६	१५	१४
योग	२४३	७०२	६१४

रोजगार के दफ्तरो में लिखित बेरोजगार (Registered Unemployed)¹

	जून १९४२ के अन्त में	जून १९५७ के अन्त में	जून १९५२ के अन्त में
पूर्ण रूप से बेरोजगार	२७३	२३५	३७०
अस्थायी रूप से कार्य में मलग्न ²	६	१५	६२

(Source Ministry of Labour and National Employment)

नागरिक रोजगार वालों की सख्या	जून १९४८ के अन्त में	जून १९५७ के अन्त में	जून १९५८ के अन्त में
पुरुष	१४,५४६	१५,३६७	१५,२६५
स्त्रियाँ	७,०२०	७,८७८	७,७८६
योग	२१,५६६	२३,२४५	२३,०५१

Source * Ministry of Labour and National Service

श्रम का रोजगार (Employment of Labour)

नागरिक रोजगार (Civil employment) की विस्तृत औद्योगिक वर्ग द्वारा की गई कुल सख्या की व्याख्या निम्न तालिका में दी जा रही है। तब १९५८ के मध्य के आंकड़े (Figures) सामयिक (Provisional) हैं :

1 The total working population represents the estimated total number of persons aged 15 and over who work for pay or gain, or register themselves as available for such work. The total comprises the armed forces, men and women on release leave not yet in employment, all persons, employers and workers on their own account as well as employees in civil employment (including persons temporarily laid off but still on the employers' list, and wholly unemployed persons registered for employment). Part-time workers are counted as full units. Owing to the small numbers now involved (6,000 at end-June, 1953) men and women on release leave are not shown separately in the lower half of the table.

2 The unemployment figures are end-month estimates.

3 The figures for the temporarily unemployed have been calculated from the computation of the total working population as they are already included in civil employment.

ब्रिटेन में नागरिक रोजगार की व्याख्या (हजार में)

Analysis of Civil Employment in Great Britain (Thousands)

उद्योग अथवा सेवा	जून १९४८ के अन्त में	जून १९४७ के अन्त में	जून १९४८ के अन्त में
कृषि एवं मत्स्य विभाग रानें	१,१७८ ८७८	१,०२५ ८६२	१,००२ ८५४
उत्पादन करने वाले उद्योग, रासायनिक एवं सहायक व्यापार	४४१	५३४	४२६
धातुएँ, इजीनियरिंग एवं मशीनरी	३,६४४	४,६१८	४,५८४
सूत बुनने का काम	६३१	६३४	८६४
कपड़ों का काम	६४६	६७८	६४८
खाद्य, पेय एवं तम्बाकू	७५०	६१६	६२६
अन्य उत्पादन	१,४२२	१,५६१	१,५६५
उत्पादन करने वाले उद्योगों का योग	८,१३७	९,२७१	९,११६
मकान बनाने एवं ठेके का काम	१,४५०	१,५१६	१,४६५
गैस, विद्युत एवं जल	३२१	३७६	३७८
धातुयात एवं सव्वाहन	१,७८७	१,७०३	१,७१५
वितरित किए हुए व्यापार	२,४८४	२,६४५	२,६७६
ध्वाकसायिक, वित्तीय तथा विभिन्न सेवाएँ	३,६५४	४,२१७	४,२४७
केन्द्रीय सरकार की सेवाएँ	६२२	५४३	५३०
स्थानीय निकायों की सेवाएँ	७००	७५५	७६१
नागरिक रोजगार का कुल योग	२१,५६६	२३,२४५	२३,०८०

व्यावहारिक काम करने की परिस्थितियाँ (उपार्जन)

Working Conditions & Practical (Earnings) :

ग्रामज मजदूरों के लिए कम से कम अथवा आदर्श कार्य करने के घंटों की दरें, जैसी कि स्वीकार पत्रों (Agreements) अथवा वेतन के क्रमों (Wages orders) द्वारा निर्धारित हुई हैं, पुरुषों के लिए १ घण्टे में ३^s एवं ४^s 1d के बीच में तथा स्त्रियों के लिए २^s एवं २^s ११ d के मध्य में है। साधारणतः वास्तविक अर्जन (Earnings) बहुत अधिक हैं।

ग्रैंट ब्रिटेन में श्रम एवं राष्ट्रीय सेवा मन्त्रालय (Ministry of Labour and National Service) धर्मिकों की भाग्य एवं काम करने के घंटों का उत्पादक उद्योगों एवं कुछ अन्य उद्योगों में छ माही निरीक्षण करते हैं।

अक्टूबर सन् १९५७ में किए हुए निरीक्षण से ७० लाख कर्मचारी प्रभावित हुए तथा सभी उद्योगों के प्रति घंटे की औसत आय निम्न प्रकार है :

पुरुष २१ वर्ष तथा अधिक आय के	५ s. २ d.
युवक एवं २१ वर्ष से कम आय के लड़के	२ s. ५ d.
स्त्रियाँ १८ वर्ष की तथा अधिक आय की	३ s. १ d.
१८ वर्ष से कम आय की लड़कियाँ	२ s. ० d.
सभी कर्मचारी	४ s. ६ d.

औसत साप्ताहिक आय (Average weekly earnings) इस प्रकार थी :

नव-युवक	१०२ s. ४ d.
स्त्रियाँ	१२६ s. ६ d.
लड़कियाँ	८५ s. २ d.
सभी कर्मचारी	११२ s. ५ d.

६—सामाजिक कल्याण¹ (Social Welfare)

राज्य एवं स्वेच्छा से की गई सेवाएँ ब्रिटेन में अब राज्य, केन्द्रिय अथवा स्थानीय सरकारी अधिकारियों के माध्यम से या साधारण जनता द्वारा होता है। वृद्ध अथवा अपंगों की देखभाल रखने के लिए, माताओं एवं बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए, बीमारी, जल्बा और औद्योगिक दुर्घटना-अस्ती को सुविधा प्रदान करने के लिए, विधवाओं अथवा अवकाश प्राप्त व्यक्तियों की पेंशन तथा पारिवारिक भत्तों के लिए ये संस्थाएँ प्रयत्नशील होती हैं। ब्रिटेन में सार्वजनिक कल्याण के लिए प्रतिवर्ष ३० हजार मिलियन पाउंड से अधिक खर्च होता है, अर्थात् प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति के लिए इस पर प्रायः ५० पाउंड खर्च होता है।

स्वेच्छा से बने हुए संगठन, विशेषकर गिर्जाघर लगभग सभी सामाजिक सेवाओं का नेतृत्व करने वाले थे। सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण की व्यवस्था करने से पूर्व वे स्कूल, विभिन्न प्रकार के चिकित्सालयों तथा मनोरंजनात्मक संस्थाओं का प्रबन्ध करते थे, उन्होंने स्वयम् विधियों को दूर किया, इससे पूर्व सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता था कि सम्पूर्ण समाज ही अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लिए उत्तरदायी है। जहाँ पर इनकी सेवाएँ एवं प्रदत्त सुविधायें समुचित एवं उपयुक्त थी वहाँ उन्हें भविष्य में भी क्रियाशील रहने को प्रोत्साहित किया गया है। आजकल ब्रिटेन में इन स्वेच्छा से की गई सेवाओं का पूरक (Supplementary) राज्य है।

स्वेच्छा से की गई बहुत-सी सामाजिक सेवाएँ राज्य की कल्याणकारी सेवाओं का कार्य करती हैं एवं उनकी पूरा करती हैं। यह दोनों—स्वेच्छा से बने संगठन एवं राज्य-पारस्परिक सहयोग से सामाजिक कल्याण का कार्य करते हैं।

७—गृह निर्माण समस्या एवं नियोजन¹ (The Housing Problem and Planning)

ग्रेट ब्रिटेन में कुल मिलाकर १५५ लाख घर हैं, जिनमें से १३५ लाख England एवं वेल्स में, १५ लाख Scotland में तथा लगभग ५ लाख उत्तरी आयरलैण्ड में हैं। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् सन् १९४५ में गृह निर्माण कार्य पुन प्रारम्भ हुआ। सन् १९५८ तक मध्य तक, ब्रिटेन में, ३० लाख नवीन एवं स्थायी गृहों का निर्माण हो चुका था। इसके अतिरिक्त लगभग १६०,००० अस्थायी घरों का निर्माण भी हुआ था (जिनमें से कुछ अब बदल दिये गये हैं)। सन् १९५६ तथा सन् १९५७ में, १००,००० से अधिक निवास-स्थानों, जो रहने के योग्य न थे, नष्ट कर दिये गये अथवा नष्ट करने के लिये छोड़ दिये गये। सन् १९५६ के अन्त में उत्तरी आयरलैण्ड में इसी प्रकार का एक आन्दोलन आरम्भ किया गया।

ब्रिटेन में नियोजन (Planning in Great Britain)

सन् १९४७ का नगर तथा देहात का नियोजन कानून एवं स्काटलैण्ड का सन् १९४७ का नगर एवं देहात नियोजन कानून व्यापक एवं महत्वपूर्ण प्रयास है, जो सम्पूर्ण बर्तमानिया की भूमि के प्रयोग के लिये रचनात्मक कार्य अथवा प्रणाली प्रदान करता है। उनके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं—

- १—विकास योजनाओं के माध्यम से सम्पूर्ण बर्तमानिया में नियोजन का एकीकरण, जिसमें कि भविष्य के विकास के बारे में पूरी तरह से विचार किया जा सके।
- २—स्थानीय नियोजनाधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से तथा उनके नियन्त्रण में, छुट्ट अथवाओं के साथ, विकास करना।
- ३—नियोजन कार्य को सफल बनाने के लिये, भूमि प्राप्त करने के लिये तथा भूमि का विकास करने के लिये और केन्द्रीय धन राशि से स्थानीय अधिकारियों को भूमि की प्राप्ति एवं भूमि का साफ करने के लिये अनुदान की दर तथा क्षेत्र को विस्तृत करने के लिये, सावजनिक अधिकारियों के अधिकारों का विस्तार करना है।
- ४—इस अतिरिक्त इस के अनुसार जंगल, पुरातत्त्व विभाग, भूमि की सुरक्षा आदि के विषय में सुधार करना है।

सन् १९४७ के कानूनों में, भुआवजा को बहुततर बनाने की समस्या—जिसने पहले प्रभावशाली नियोजन में बाधा डाली थी—को हल करने के लिये बहुत से वित्तीय साधन बनाये गये, लेकिन इसके लिये अपनाई गई प्रणाली व्यवहार में सन्तोषजनक सिद्ध नहीं हुई।

चीनी जनवादी जनतन्त्र में नियोजित आर्थिक विकास¹ (Planned Economic Growth In People's Republic of China)

१—सन् १९५६ में आर्थिक स्थिति²

चीन में, सन् १९५८ की तीव्रगति के आधार पर, सन् १९५६ के प्रथम अर्द्ध-भाग में, द्रुत विकास हुआ।

उद्योग

इस वर्ष के प्रथम अर्द्ध-भाग में उद्योगों के उत्पादन का कुल मूल्य ७२६०० मिलियन Yuan था। यह गत वर्ष के प्रथम अर्द्ध-भाग के ४४३०० मिलियन Yuan से ६५ प्रतिशत अधिक था। इस वर्ष के प्रथम अर्द्ध-भाग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादन, पिछली साल के प्रथम अर्द्ध-भाग के उत्पादनों की तुलना में, इस प्रकार है लोहा (आधुनिक यन्त्रों द्वारा उत्पन्न किया हुआ) ६.५ मि० टन, १६० प्रतिशत, इस्पात (आधुनिक यन्त्रों द्वारा उत्पन्न किया हुआ) ५.३ मिलियन टन, ६६ प्रतिशत, कोयला १७४ मिलियन टन, १०० प्रतिशत से अधिक, विद्युत शक्ति १८४०० मिलियन Kilowatt-hours, ५५ प्रतिशत, घातु काटने वाली मशीन के उपकरण ४५,००० यूनिट, १०० प्रतिशत से अधिक, सूती कपड़ा ४,१४७,००० Bales, ४६ प्रतिशत तथा चीनी ७८०,००० टन, ४३ प्रतिशत। अन्य सभी उत्पादनों का परिमाण पिछली साल की तुलना में अधिक हो गया। उनमें से बहुत कम में २० प्रतिशत में कम वृद्धि हुई।

1 Courtesy Embassy of People's Republic of China in India, New Delhi

2. Chou En-Lai Report on adjusting the major targets of the 1959. National Economic Plan and further developing the campaign for increasing production and practising Economy. (Courtesy: Director of Information, Embassy of the People's Republic of China in India, New Delhi).

कृषि (Agriculture) :

यद्यपि ग्रीष्म ऋतु की फसल के लिए बोया हुआ क्षेत्रफल कम हो गया था एवं इस वर्ष की बसन्त ऋतु में कुछ प्राकृतिक प्रकोप भी हुए, फिर भी कृषकों के विस्तृत जन समूह के सहस्र एवं सरकारी प्रयत्नों के कारण काफी प्रगति हुई ।

गेहूँ, मोटे अनाज एवं चावल का कुल उत्पादन १३६,००० मिलियन catties¹ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष के १३६,५०० मिलियन catties उत्पादन से—जो ग्रीष्म ऋतु की फसल के विशेष रूप से अच्छे होने के कारण था—२,५०० मिलियन catties अधिक था ।

यातायात .

इस वर्ष के प्रथम अर्द्ध भाग में रेलों द्वारा ढोये गये माल का परिमाण २४७ मिलियन टन था, गत वर्ष के इसी समय की तुलना में ४६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । जहाजों एवं नावों द्वारा ढोये गये माल का परिमाण ५५ मिलियन टन था अर्थात् ७५ प्रतिशत की वृद्धि की, मोटरों द्वारा ढोये गये माल का परिमाण १४० मिलियन टन था अर्थात् ६४ प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

पूँजी निर्माण :

इस वर्ष के प्रथम अर्द्ध भाग में कुल विनियोग १०,७०० मिलियन yuan था, जो गत वर्ष के इसी समय के विनियोग से १४ प्रतिशत अधिक था । पूँजी के इस निर्माण के फलस्वरूप कई योजनाओं में—पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से उत्पादन आरम्भ होगये तथा उद्योगों की उत्पादन-क्षमता में बहुत वृद्धि हुई ।

ध्यापार :

इस वर्ष के प्रथम अर्द्ध भाग में फुटकर विक्रय कुल २६,६०० मिलियन yuan का हुआ जो गत वर्ष से—इसी समय के विक्रय से—२३ प्रतिशत अधिक हुआ ।

उपरोक्त तथ्यों से यह देखा जा सकता है कि इस वर्ष के प्रथम अर्द्ध भाग में उद्योग, कृषि, यातायात, पूँजी-निर्माण तथा ध्यापार सबसे बड़ी द्रुत गति से विकास हुआ । सबको मिलाकर चीन की आर्थिक दशा ठीक है, उपलब्धियाँ अधिक रही हैं तथा सम्पूर्ण प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की प्रकट करता है । अधिकांश जनता इस प्रकार के कार्यों से सन्तुष्ट है तथा उन्हें अपने उज्ज्वल भविष्य का पूर्ण विश्वास है । लेकिन जनता के बहुत अधिक बहुमत—जिस अपनी शक्ति पर विश्वास है—के विपरीत जनता की एक बहुत थोड़ी संख्या ऐसी है, जो देश के समाजवादी निर्माण की बड़ी उपलब्धियों के प्रति उदासीन है । वे वर्तमान आर्थिक स्थिति के विषय में बड़े निराशावादी हैं तथा वे अपने आतिशूलक विचारों को फैलाने का दुस्तर प्रयास करते हैं ।

1. Catty—0.5 kg or 1.1023 Lb.

२—लोहा एवं फौलाद बनाने में जनता का प्रयत्न (The Mass Campaign to make iron and steel)

सन् १९५८ में चीन में १३३९ मिलियन टन कच्चा लोहा उत्पन्न किया (या ५ मिलियन टन कोयले को निकाल कर जो इस्पात बनाने योग्य नहीं था, बल्कि कृषि के साधारण यन्त्र एवं उपकरण बनाने के लिए ठीक था) जो १९५७ में उत्पन्न किये हुये कोयले से दो या तीन गुना अधिक था तथा ११०८ मिलियन टन इस्पात उत्पन्न किया, जो मन् १९५७ से दुगुना था। ... इस्पात के उद्योग की उन्नति होने से अन्य उद्योगों में काफी प्रगति हुई। बहुत से महत्त्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादन होने लगे या कई गुने हो गये। कुल औद्योगिक उत्पादन में, सन् १९५७ ई० की अपेक्षा सन् १९५८ में ६६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुछ भी सही, लोहे एवं इस्पात बनाने के लिए जनता के प्रयत्न में लोहे एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिये पथ प्रदर्शन किया। जहाँ तक स्वदेशी लोहा पिघलाने की भट्टी एवं अन्य सम्बन्धित भट्टियों का प्रश्न है उनका भी विकास किया गया है, तथा उनके द्वारा कच्चे लोहे के उत्पादन एवं गुण में वृद्धि हुई है। Small Blast furnaces की कुल क्षमता, (प्रत्येक में ६५ एवं १०० Cubic Meters के मध्य में) जो आजकल चालू हैं, उसमें ४३,००० Cubic Meters तक उत्पादन होने लगा है। कुल (Large Blast Furnaces) जो कि देश में हैं लगभग दूनी हो गई। वे दस मिलियन टन कच्चे लोहे को शुद्ध करने के योग्य होंगी हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में, ये small blast furnaces लगभग ५५ मिलियन टन कच्चे लोहे को शुद्ध करेंगी। सन् १९६३ से आरम्भ होकर ये १५ मिलियन टन लोहा प्रति वर्ष शुद्ध किया करेंगी।

Small blast furnaces द्वारा उत्पन्न कोयले की किस्म एवं कोयले के उपभोग की दर में, पिछले कुछ महीनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जुलाई तक कच्चे लोहे का अनुपात ७५ प्रतिशत बढ़ गया। प्रति टन कच्चे लोहे पर कोयले के उपभोग की दर ४ टन के लगभग रह गई तथा प्रतिदिन कच्चे लोहे का उत्पादन भट्टी के प्रति Cubic Meters के प्रयोग की क्षमता से ०.७ टन तक पहुँच गया। यह आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य में इससे अधिक उन्नति होगी एवं उत्पत्ति के गुण तथा मात्रा में वृद्धि होगी तथा कोयले के उपभोग की दर कम हो जायगी।

तथ्यों से सिद्ध होता है कि बृहत्, सघु तथा मध्यम श्रेणी के औद्योगिक साहस का, तथा आधुनिक एवं स्वदेशी पद्धतियों के प्रयोग से निम्नलिखित लाभ हैं

साहस विस्तृत रूप से वितरित कर दिया जाता है, यह उनके निर्माण में कम समय लेता है, वे कच्चे एवं अन्य आयुक्त मालों की कम माँग करते हैं, तथा उनकी पूति करना बहुत आसान है। यह स्रोतों के विस्तृत परीक्षण में, उत्पत्ति के साधनों की अधिक उपयुक्त ढंग से प्रयोग करने में, उनका समुचित रूप से पूर्ण प्रयोग करने में, पर्याप्त सहायता देगा। कुछ भी हो, स्वदेशी पद्धतियों का प्रयोग

करने में अथवा आधुनिक एवं स्वदेशी पद्धतियों को मिलाकर, लघु उद्योगों के निर्माण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए 'दोनों ही पंरों से चलना चाहिए' केवल एक टांग में ही नहीं ।

३—बाजार का प्रश्न

इन वर्षों के (१९५६) प्रथम अर्द्ध-भाग में बहुत आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति गत वर्ष की—इसी समय की—तुलना में पर्याप्त बढ़ गई । आंकड़ों से ज्ञात होता है कि अनाज, कोयला, सिंक, धाराब तथा दियासलाई की पूर्ति में १० से ३० प्रतिशत वृद्धि हुई, सूती कपड़ा, नमक, साबुन, साइकिल तथा सिगरेटों में ३० से ५० प्रतिशत वृद्धि हुई, बुने हुये वस्त्र, बुनने की ऊन, ऊनी वस्तुओं, रबड़ के छूते तथा फाउन्टेनपैन में ५० से लेकर १०० प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई, खाद्य तैलों, कागज, मिट्टी का तेल, तथा चाय में १० प्रतिशत से भी कम वृद्धि हुई । १९५६ के प्रथम अर्द्ध-भाग में, केवल एक दर्जन वस्तुओं की पूर्ति गिर गई, इसमें मूँगर का गोश्त, गाय का गोश्त, भेड़ का गोश्त, मण्डे की वस्तुओं, जल-जीवों से बनी हुई वस्तुओं, चीनी, घरेलू उपयोग के लिए सूती कपड़े, चमड़े के छूते, बिजली के बल्ब तथा हाथ की घड़ियाँ सम्मिलित हैं ।

इन वस्तुओं की पूर्ति में कमी होने का कारण उत्पत्ति का गिरना नहीं है । गोश्त, मण्डे से उत्पन्न वस्तुयें, जल जीवों से बनी हुई वस्तुओं, घरेलू उपयोग के लिए सूती कपड़ों जैसी वस्तुओं की पूर्ति इसलिये कम हो गई कि इन वस्तुओं का उपभोग देहाती क्षेत्रों में—जहाँ ये उत्पन्न होती थीं—बहुत बढ़ गया ।

सबको मिलाकर, वस्त्रों, दैनिक प्रयोग की वस्तुओं, अन्य खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं रही । दैनिक प्रयोग की वस्तुओं की पूर्ति में, अन्य वस्तुओं की तुलना में, कुछ कमी अनुभव की गई । कुछ भी हो, इस वर्ष के (१९५६) प्रथम अर्द्ध-भाग में, बहुत सी दैनिक प्रयोग की वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों की पूर्ति में जो कमी थी वह जून तथा जुलाई में सुवरने लगी । कुछ लोगों का कथन है कि बाजार में सब छोटे से खींचतान थी । लेकिन यह कहना जानबूझकर सच्चे का भुड़लाना है । कुछ लोगो ने फिर भी कहा कि 'मुक्ति से पूर्व' व्यक्ति को हर वस्तु बाजार में मिल सकती थी, लेकिन अब कुछ भी प्राप्य नहीं । सभी जानते हैं कि इसमें तनिक भी सत्य नहीं है । कर्मचारियों के लिए, जो देश की जनसंख्या का ८० या ९० प्रतिशत है, ये बातें विस्मृत विरोधी हैं । कर्मचारी मुक्ति से पूर्व जो वस्तु चाहते थे, नहीं प्राप्त कर पाते थे, परन्तु अब हर आवश्यक वस्तु प्राप्य है । जो ऐसी बातें कहते हैं वे या तो इसको देख नहीं पाते हैं अथवा कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर को ऊँचा देखकर सन्तुष्ट नहीं हैं । वे अब भी फिज़ूल खर्ची, तथा प्राचीन समाज के सड़े हुए जीवन—जो बहुत थोड़े लोग जैसे रईस, उच्च नौकरी वाले, जमींदार, धनिक एवं पूँजीपति

आदि व्यतीत करते थे—की अभिलाषा करते हैं। क्या इससे यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं ?

अन्य व्यवसायों को छोड़कर आए हुए व्यक्तियों के अतिरिक्त, १९५८ के नये कमचारियों तथा स्टाफ के प्रवेश से, इस वर्ष प्रतिमास ४०० मिलियन yuan से भी अधिक क्रय शक्ति में वृद्धि हुई। इस प्रकार, १९५९ के प्रथम अर्द्ध-भाग में सामूहिक क्रय शक्ति को मिलाकर नगरों की क्रय शक्ति का मूल्य १४३०० मिलियन yuan था जो गत वर्ष के इसी समय की ११०० मिलियन yuan की तुलना में ३० प्रतिशत अधिक था।

कुछ लोगों का सन्देह है कि कुछ वस्तुओं की पूर्ति में अभाव आने का कारण निर्यात में अत्यधिक वृद्धि होना था। यह अब भी तथ्यों के अनुरूप नहीं है। १९५९ के निर्यात का कुल परिमाण गत वर्ष के कुल निर्यात के परिमाण से १७ ८ प्रतिशत अधिक था। इसके अनतिरिक्त, गत वर्ष की तुलना में अनाज तथा बहुत सी अबाध पदार्थों—जिनकी कि घर पर आवश्यकता थी—में तनिक भी वृद्धि नहीं हुई प्रथम ही वर्षों में तो बहुत कम हुई। उदाहरणार्थ, इस वर्ष १५ अगस्त तक, चावल के निर्यात का कुल योग केवल ७६२,००० टन था जबकि सूअर के गोشت का निर्यात केवल १४००,००० सूअरों के बराबर था, यह १९५८ के चावल के उत्पादन तथा इसी तरह जीवित सूअरों की कुल संख्या का—वर्ष के अन्त में—१ प्रतिशत से भी कम था। समाजवादी निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि कृषि उत्पादन से देश को आवश्यक सामग्री का विनिमय किया जाय। यह उद्योग के विकास के हित में ही नहीं है, बल्कि कृषि के विकास के हित में भी है।

४—प्रथम पंचवर्षीय योजना की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ¹

एव सन् १९५८ की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष :

सन् १९५४ में, जबकि जनता की राष्ट्रीय सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ, समाजवादी क्षेत्र ने चीन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पहले से ही अग्रगण्य स्थान प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी पूँजीवादी उद्योग तथा व्यापार व्यक्तिगत कृषि एवं दस्तकारी बड़े परिमाण में बनी रही। अन्त में पारस्परिक सहायता का आदोलन देहाती क्षेत्रों में व्यापक रूप से विकसित हुआ, ५० प्रतिशत से लगभग कृषक गृहस्थों ने, 'कृषि अन्तःपारस्परिक सहायता की टोलियों' में भाग लिया, लेकिन दो प्रतिशत कृषक-गृहस्थों ने तब भी 'कृषि उत्पादकों की सहकार समितियों' की स्थापना की। उस समय तक चीन ने पुनः आर्थिक स्थापना के समय के, कार्य को पूरा कर लिया था, तथा

1 Chou-En lai—Report on the work of the Govt. Delivered at the First Session of the Second National People's Congress on April 18, 1959 (Foreign Language Press, Peking, Govt. of China).

बड़े स्तर पर नियोजित आर्थिक निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया, लेकिन यह सोचना सैप रह गया था कि इतने बड़े देश में—जिसकी कि आबादी ६०० मिलियन है—इतने थोड़े समय में समाजवादी औद्योगीकरण की नींव डालने के योग्य हो सकेंगे कि नहीं। अब वहाँ की क्या दशा है? यह स्पष्टतया देखा जा सकता है कि ठीक चार वर्ष में, चीन के साम्यवादी दल तथा माओत्सेतंग के नेतृत्व में समाजवादी क्रान्ति तथा समाजवादी निर्माण में बड़ी सफल उपलब्धियाँ मिली।

सन् १९५५ तथा १९५६ में चीन ने पूँजी प्रधान उद्योग एवं व्यापार, कृषि एवं वस्तुकारी और इस प्रकार से समाजवादी आन्दोलन के मुख्य लक्ष्य, उत्पत्ति के साधनों के स्वामित्व को प्राप्त किया। अब कुछ राष्ट्रीय अल्प सत्यको के सिवाय, चीन में उत्पत्ति के साधनों पर मुख्यतया दो प्रकार का स्वामित्व है, प्रथम, समाजवादी स्वामित्व जो पूर्णतया जनता का है, द्वितीय, सामूहिक समाजवादी स्वामित्व।

चीन में समाजवादी निर्माण एवं समाजवादी क्रान्ति एक दूसरे का उत्थान करते हुए साथ-साथ चलते रहते हैं। सन् १९५३ से १९५७ तक चीन ने राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना को पूरा किया। लेकिन वास्तविक बात यह है कि उन्होंने १९५७ में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना को पूरा किया तथा उसी के आधार पर सन् १९५८ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अधिक गौरव से प्रारम्भ किया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के परिणाम स्वरूप सन् १९५७ में औद्योगिक एवं कृषि सम्बन्धी उत्पादन का कुल मूल्य १२८,७४० मिलियन Yuan तक पहुँच गया, यानी १९५२ की तुलना में—जब ८२,७१० मिलियन Yuan था—६८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन का कुल मूल्य ६५,०२० मिलियन Yuan तक पहुँच गया, १९५२ की तुलना में—जब २७,०१० मिलियन Yuan था—१४१ प्रतिशत बढ़ गया, वस्तुकारी की उत्पत्ति १३,३७० मिलियन Yuan तक पहुँच गई; सन १९५२ की तुलना में—जब ७,३१० मिलियन Yuan था—१३ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई और कृषि का मूल्य ६०,२५० मिलियन Yuan तक पहुँच गया, यानी १९५२ की तुलना में—जब यह ४८,३६० मिलियन Yuan था—२५ प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में, राज्य द्वारा नियुक्त विनियोग का योग ४६,३०० मिलियन Yuan था, यानी नियोजित व्ययों से, जो कि ४२,७४० मिलियन Yuan थे, १५ प्रतिशत अधिक था। पाँच वर्षों के देश-रेख के निर्माण कार्य में १००० से अधिक औद्योगिक एवं खनिज सम्बन्धी कार्य-क्रम प्रारम्भ हुए जिनमें से ६२१ असाधारण (above norm) थे। २२७ से अधिक पर योजना में विचार हुआ। सन् १९५७ के अन्त तक ५३७ 'असाधारण' औद्योगिक कार्य-क्रम पूरे किये जा चुके थे अथवा आंशिक रूप से पूरे हो चुके थे तथा वे उत्पत्ति करने लगे थे।

सन् १९५७ में सम्पूर्ण देश के उद्योगों ने, १७५,००० अभियन्ताओं (Engineers) तथा प्रावधिक कर्मचारियों (Technicians) को रोजगार दिया, यानी १९५२ की तुलना में—जबकि इनकी संख्या ५८,००० थी—तिगुने लोगों को रोजगार दिया, उद्योगों तथा पूँजी-निर्माण कार्य-क्रमों ने १०,१६०,००० कर्मचारियों को, सन् १९५२ की तुलना में—जब यह संख्या ६,११०,००० थी—६६ प्रतिशत अधिक लोगों को रोजगार दिया। औद्योगिक उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन की विविधता, दोनों ही की वृद्धि के परिणाम स्वरूप, औद्योगिक भात्म-निर्भरता (वस्तु एवं यांत्रिक उपकरण दोनों ही में) बढ़ गई। उदाहरणार्थ, इस्पात के उत्पादन में ८६ प्रतिशत तथा कलो एवं यांत्रिक उपकरणों में ६० प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई।

साथ ही साथ उद्योग एवं कृषि के अनुपात तथा भारी एवं हल्के उद्योगों के अनुपात में भी परिवर्तन हुआ। उद्योग एवं दस्तकारी के, सन् १९५२ के उद्योग एवं कृषि के उत्पादन मूल्य में ४१.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई; जबकि १९५७ में उनके मूल्य में ५६.७ प्रतिशत वृद्धि हुई। सन् १९५२ में, पूँजी प्रधान वस्तुयें, उद्योग के उत्पादन-मूल्य में ३६.७ प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि सन् १९५७ में यह अनुपात ५२.८ तक पहुँच गया। सन् १९५८ में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में, चीन की ग्रन्थ-व्यवस्था में, चीन के इतिहास की एक अद्वितीय घटना घटी—वह थी अत्यधिक प्रगति। जब उद्योग एवं कृषि के उत्पादन का मूल्य २०५,००० मिलियन Yuan हुआ तो यह सन् १९५७ के १२४,१०० मिलियन Yuan से ६५ प्रतिशत अधिक था।

उद्योग एवं दस्तकारी के उत्पादन का कुल मूल्य ११७,००० मिलियन Yuan तक हो गया, यानी सन् १९५७ के ७०,४०० मिलियन Yuan से ६६ प्रतिशत अधिक हो गया। सन् १९५७ में, पहले की तुलना में कच्चे लोहे, इस्पात, कोयला, शक्ति उत्पन्न करने वाले औजार, रेलवे इंजिन, मोटर गाड़ियाँ तथा इंजन आदि के उत्पादन में दुगुनी वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन का कुल मूल्य ८८,००० मिलियन Yuan हो गया, यानी सन् १९५७ के ५३,७०० मिलियन Yuan से ६६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अनाज, रुई, तथा तम्बाकू के उत्पादन में भी दुगुने से अधिक वृद्धि हुई। पूँजी विनियोग भी राज्य के बजट के माध्यम से २१,४०० मिलियन Yuan तक हो गया, यानी सन् १९५७ के १२,६०० मिलियन Yuan से ७० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वहुत से औद्योगिक तथा कृषि-उत्पादनों में, अकेले सन् १९५८ में ही इतनी वृद्धि हुई कि सन् १९५७ एवं १९५८ दोनों के ही उत्पादनों को भात दे दी। उदाहरणार्थ, सन् १९५२ की तुलना में सन् १९५७ में इस्पात के उत्पादन में ४ मिलियन टन, कोयला में ६४ मिलियन टन, कल तथा औजारों में १४,३०० की, अनाज की फसलों में ६१,२०० मिलियन Cattles तथा रुई में ६.७३ मिलियन टन की वृद्धि हुई। सन् १९५७ की तुलना में, सन् १९५८ में इस्पात के उत्पादन में १.७३ मिलियन टन

की, कोयले के उत्पादन में १४६ मिलियन टन की, कल एवं औजारों में २२,००० की, अनाज की फसलों में ३८०,००० Cattles तथा रुई में ३३'५८ मिलियन टन की वृद्धि हुई। उद्योग एवं कृषि की उन्नति के साथ-साथ, यातायात, डाक तथा संचालन, व्यापार तथा संस्कृति एवं शिक्षा सभी में विशेष प्रगति हुई।

चीन ने औद्योगिक क्षेत्र में इस्पात की मुख्य कड़ी मान कर तथा भारी उद्योगों और बड़े इजिनो की प्राथमिकता देकर, सर्वतोमुखी विकास किया। औद्योगिक उत्पत्ति तथा पूंजी-निर्माण के लिए आधुनिक युग में इस्पात बहुत ही आवश्यक धातु है, इसका अपर्याप्त उत्पादन सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास में बाधक है। इसलिए सन् १९५८ में, समूचे राष्ट्र को लोहा एवं इस्पात का उत्पादन बढ़ाने में लगा दिया तथा परिणामस्वरूप सन् १९५७ के इस्पात के ५,३५०,००० टन उत्पादन से सन् १९५८ में ११,०८०,००० टन हो गया। इस्पात के उत्पादन से कोयले के उद्योग के साथ-साथ कल निर्माण तथा अन्य उद्योगों में भी विशेष उन्नति हुई।

सन् १९५८ में कृषि-क्षेत्र की बड़ी उपलब्धियों में भी, समाजवाद के निर्माण की शक्ति की परीक्षा की, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उद्योग एवं कृषि को साथ-साथ विकास करना चाहिए तथा यह विकास साथ-साथ किया भी जा सकता है, कृषि तथा उद्योग द्रुत गति से विकास कर सकते हैं। वास्तव में, उद्योग एवं कृषि की प्रगति देर से, सन् १९५८ में प्रारम्भ हुई। चीनी कृषि के लिए कलो एवं रासायनिक खादों का उत्पादन अब भी बहुत कम है लेकिन एक बार किसानों के प्रारम्भिक प्रयत्न को चरम सीमा तक पहुँचाया है। क्षेत्र की प्रति इकाई के हिसाब से कृषि-उत्पादन अब भी तीव्र गति से बढ़ाया जा सकता है। कृषि के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य-क्रम से जो कि १९५७ में संशोधित हुआ था, स्पष्ट है कि देश के तीन प्रदेशों में—जिनमें कि देश विभक्त है—सन् १९५७ में प्रति Mov¹ अनाज की उत्पत्ति क्रमशः ४००; ५०० तथा ८०० Cattles तक होनी थी तथा रुई क्रमशः ६०, ८० एवं १०० Cattles होनी थी। वास्तव में, सन् १९५८ तक सम्पूर्ण देश की Counties एवं Municipalities ने अनाज के उत्पादन के लक्ष्य को, जो कि उनके लिए राष्ट्रीय कार्य-क्रम में कृषि के विकास के लिए निर्धारित किये थे, प्राप्त कर लिया, जबकि अधिकतर देश के कई उत्पादन करने वाले क्षेत्रों ने भी रुई के उत्पादन में कार्य-क्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त किया।

1. A 'Mov' is equivalent to 0.06 hectare or 0.1647 Acre.

५—सन् १९५६ में—द्वितीय पंचवर्षीय योजना^१ की द्वितीय वर्ष में—चीन का आर्थिक क्षेत्र में कार्य

सन् १९५६ द्वितीय वर्ष है जिसमें चीनी समाजवाद के निर्माण के लिए अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पूरा कर रहे हैं। चीनी साम्यवादी दल की आठवीं केन्द्रीय समिति के छठवें पूर्ण अधिवेशन में, जो नवम्बर सन् १९५८ में हुआ था, सन् १९५६ में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को विकसित करने के मुख्य कार्य एवं नीतियों पर विवाद हुआ तथा चार लक्ष्य रखे १८ मिलियन टन इस्पात, ३८० मिलियन टन कोयला, १,०५०,००० मिलियन Cattles अनाज तथा १०० मिलियन टन रुई। इन उद्देश्यों एवं उत्पत्ति तथा निर्माण की परिस्थितियों के आधार पर सन् १९५६ की प्रथम तिमाही अप्रैल सन् १९५६ में—चीनी साम्यवादी दल की आठवीं केन्द्रीय समिति के सातवें मुख्य अधिवेशन में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए सन् १९५६ की 'प्राक्प योजना' को ग्रहण किया।

सन् १९५६ की राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की विकास योजना, महान् उन्नति के प्रयास को अनवरत रखने को बल देती है। जैसा कि प्राक्प योजना से विदित है कि सन् १९५६ में औद्योगिक एवं कृषि के उत्पादन का कुल मूल्य ४० प्रतिशत बढ़ जायगा अर्थात् १९५८ में जो २०५,००० मिलियन yuan या २८७,००० मिलियन yuan हो जायगा, इस परिमाण में से १६५,००० मिलियन yuan उद्योग तथा दस्तकारी का होगा। ३२ में से १७ मुख्य उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होगी। कच्चा लोहा, इस्पात, मिट्टी का तेल, सल्फ्यूरिक एसिड, रासायनिक खाद, एन्टीबायोटिक शक्ति उत्पन्न करने वाले यन्त्र, रेल के इंजिन, माल ढोने वाले वाहन, ट्रेक्टर आदि कुछ अपवादों के अतिरिक्त, अन्य मुख्य औद्योगिक उत्पादनों में ३० प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि होगी। अन्य कुछ उत्पादनों में हूनी तथा किन्हीं में कई गुनी वृद्धि होगी।

बड़े एवं छोटे उद्योगों की साथ साथ विकास की आवश्यकतानुसार, सन् १९५६ में 'पूँजीगत वस्तुओं' के उत्पादन में ४६ प्रतिशत तथा उपभोक्ता की वस्तुओं के उत्पादन में ३४ प्रतिशत वृद्धि होने का आयोजन है। कुछ औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में, जो कि जनता के दैनिक जीवन के प्रयोग की वस्तुएँ हैं—विशेषकर वे वस्तुएँ जो पहले पर्याप्त सख्या में उत्पन्न नहीं की गई हैं—उनके उत्पादन की वृद्धि के लिए योजना में स्थान दिया गया है। योजना में उद्योग एवं कृषि के साथ-साथ विकास की आवश्यकतानुसार, सन् १९५६ में, औद्योगिक एवं दस्तकारी के उत्पादन का मूल्य सन् १९५८ के उत्पादन मूल्य से ४१ प्रतिशत बढ़ जायगा जबकि कृषि के उत्पादन का मूल्य सन् १९५८ के कुल उत्पादन मूल्य से ३६ प्रतिशत बढ़ जायगा। छोटे उद्योगों के विकास एवं लोगों के उच्च रहन-सहन के स्तर के साथ,

कृषि तथा पशुओं सम्बन्धी उत्पादन में वृद्धि करने, अच्छे कपड़े के उत्पादन, गन्ना, सूअर तथा धोडो की वृद्धि की दर, रुई एवं अनाज के उत्पादन मे लगातार वृद्धि की जायगी । कृषि के लिए औद्योगिक सहायता, अधिक सिंचाई तथा सिंचाई की बत्ते, ट्रैक्टर, अनाज एवं कृषि सम्बन्धी अन्य यन्त्र, रबड़ के टायरों वाली दो पहियों की ठेला गाड़ी, रासायनिक खाद एवं कृषि के घातक कीटाणुओं को मारने वाली औषध प्रदान करके उत्पादन बढ़ाया जायगा ।

सन् १९५७ एवं १९५८ की तुलना मे, बहुत से उत्पादनों मे सन् १९५६ की योजना मे वृद्धि होगी । यह औद्योगिक उत्पत्तियों, शक्ति, सत्त्व्यूरिक एसिड, रासायनिक खाद, माल ढोने की गाड़ी, रुई कातने की कले, कपड़ा बुनने का तारा, सूती कपड़ा, कागज, वनस्पति तेलो एवं गन्ना, जूट, अन्य पशु तथा सूअर आदि के विषय मे सत्य है ।

औद्योगिक भर्त्से पर विशेषकर केन्द्रित नेतृत्व को शक्तिशाली बनाना आवश्यक है, जिससे कि स्थानीय अधिकारियों एवं जन समूह के साथ राज्य के साधनों को केन्द्रीय अधिकारियों के साधनों के साथ पूर्ण रूप से मिला दिया जाय तथा देश की एकीकृत योजना को दृष्टि मे रख कर, सभी क्षेत्रों मे पूर्ण प्रबन्ध किया जाय । इसमें मुख्य निर्माण का कार्य-क्रम पहले पूरा होना चाहिए, तथा सभी क्षेत्रों के कार्यों की पूर्ति का आश्वासन देना चाहिए ।

योजना लक्ष्यात्मक सम्भावनाओं पर आधारित होनी चाहिए । जब उनकी भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय शक्ति के साधन कुछ निश्चित मुख्य योजनाओं की पूर्ति करते हैं तो ये अन्य कार्य-क्रमों की आवश्यकताओं को उसने सन्तोषप्रद ढंग से पूरा नहीं कर सकते । इस विरोध को दूर करने के लिए छोटे भागों के लाभ को सम्पूर्ण त्याग देना चाहिए, तथा मुख्य योजनाओं की पूर्ति के आश्वासन का प्रथम स्थान होना चाहिए । इस सिद्धान्त के अनुसार, सन् १९५६ की औद्योगिक उत्पत्ति एवं निर्माण योजना की रचना हुई थी । उत्पत्ति एवं पूँजी-निर्माण, वितरण तथा महत्त्वपूर्ण कच्चे माल एवं औजार पर प्रशासकीय कर्मचारियों की वृद्धि करके एवं स्थानान्तरण करके तथा जोरिम के कार्यों पर कर्मचारी बढ़ा कर तथा स्थानान्तरण करके, थम एवं बेतन की प्रणालियों मे परिवर्तन करके, प्राविधिक शक्तियों के कार्यों मे पुन सुधार होना चाहिए तथा इनको केन्द्रीय अधिकारियों, राज्य के अधिकारियों, नगर पालिका तथा प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रदेशों के अधिकारियों की पूर्ण आधीनता मे रख देना चाहिए । विशेष उत्पत्ति एवं निर्माण कार्यों की प्राथमिकता की सूची की रचना ऊँचे से लेकर नीचे वर्ग के महत्त्व, आवश्यकता तथा कच्चे माल एवं औजारों की प्राप्ति को दृष्टि मे रख कर होनी चाहिए ।

संगठनात्मक कार्य मे भी नेतृत्व को शक्तिशाली बनाना एवं उत्पत्ति तथा निर्माण के बहुत से सम्बन्धों को लगातार नियन्त्रित रखना आवश्यक है, जिससे सन् १९५६ मे पूरा होने वाला महान् कार्य, औद्योगिक उत्पत्ति तथा पूँजी निर्माण,

निश्चित नियमों के अनुसार पूरा होगा तथा सभी सत्यात्मक तथा गुणात्मक आवश्यकताओं को सन्तुष्ट किया जायेगा और अधिक महत्वपूर्ण उत्पादन तथा निर्माण कार्य-क्रमों के लिए यह आवश्यक है कि १० दिन का मासिक अवकाश तिमाही 'दाइम टेबिल' बनाना चाहिए तथा केन्द्र एवं प्रान्तों के अधीन जो अंग हैं ग्राम नगरपालिकाओं या प्रमुसत्ता सम्पन्न प्रदेशों को अपने निरीक्षक कर्मशालाओं तथा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुण का निरीक्षण करने निजी दौरे भेजने चाहिए तथा इस प्रकार नियोजित लक्ष्यों की समुचित पूर्ति का आश्वासन दिलाना चाहिए ।

१९५८ की कृषि की प्रगति से, उत्पत्ति बढ़ाने के आठ प्राविधिक सिद्धान्तों से सम्बन्धित चीनियों को जो अनुभव हुए वे इस प्रकार हैं :— मिट्टी की उपनि, खाद का प्रयोग, सिंचाई की सुविधा, बीज का चुनाव, घने पौधे लगाना, पौधों की सुरक्षा, खेत का प्रबन्ध, तथा कृषि के औजारों का सुधार । इस अनुभव ने चीनियों को बोध करा दिया कि विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों एवं फसलों के अनुसार विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए तथा इन पद्धतियों का अविवेक पूर्वक उपयोग नहीं करना चाहिए तथा विभिन्न पद्धतियाँ जो एक दूसरे से सम्बन्धित तथा एक दूसरे पर निर्भर हैं उन्हें प्रकले तथा बहुतों को एक साथ प्रयुक्त नहीं करना चाहिए ।

देहात में मानव शक्ति की कमी का अन्त करने के ये मौलिक उपाय हैं— कृषि में श्रम के उत्पादन को बढ़ाना, तथा कृषि में प्राविधिक नवीन पद्धति एवं प्राविधिक क्रान्ति लाना, कृषि धीरे-धीरे अर्द्ध यंत्रवत् एवं पूर्ण यंत्रवत् कृषि के औजारों का प्रयोग करना, क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए । कृषि औजारों में मूधार आन्दोलन जो सन् १९५८ में प्रारम्भ हुआ उसे जारी रखना चाहिए तथा उन स्वीकृत औजारों को जो व्यवहार में उपयोगी सिद्ध हो चुके हैं आवेश से तथा शक्ति से उनको उन्नत तथा सर्व प्रिय बनाया जाय ।

यातायात के क्षेत्र में सन् १९५६ की योजना का अनुभव करने में सर्व प्रथम हमें रेल यातायात को देखना चाहिए, हमें सगठनात्मक कार्य को सत्तिशाली बनाना चाहिए, प्रचलित यातायात की सुविधाओं को पूरी तरह में प्रोत्साहन देना चाहिए तथा यात्रानुसार पूँजी-निर्माण के कार्य को पूरा करना चाहिए । यातायात विभागों को अपने कार्य की बहुरंग योजनाएँ बनानी चाहिए, माल सादने तथा उतारने के समय में कमी करनी चाहिए, मालगाड़ियों तथा जहाजों की गति बढ़ानी चाहिए तथा ईंधन के उपभोग में मितव्ययिता होनी चाहिए, जिससे वर्तमान सुविधाओं में अधिक माल ले जाया जा सके । यातायात में माल के महत्त्व तथा आवश्यकतानुसार उसे ले जाने का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए, जिससे पहिले ऐसी महत्त्वपूर्ण वस्तुओं जैसे 'पूँजी गत वस्तुओं—लोहा, इस्पात, कोयला, तथा उपभोक्ता वस्तुओं—अनाज आदि का समय से पहुँचाने का प्रबन्ध होना चाहिए । अधिक दूरी तथा कम दूरी के यातायात के मिश्रित करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए । कम दूरी के यातायात को सहारा देने, उन्हें गाड़ियों के प्रयोग तथा देहाती साधनों के यातायात में जहाजों

का प्रयोग करने का प्रबन्ध करना चाहिए। सभी और के औद्योगिक एवं व्यापारिक विभागों के यातायात के कार्य को नियंत्रित करने, कम करने तथा सम्भव हो सके तो ऐसे अनुचित कार्यों जैसे, उसी माल को विपरीत दशा में जहाज द्वारा भेजना, अत्यन्त दूरी पर माल को जहाज द्वारा भेजना अथवा उनके लक्ष्यों में बाधाओं की स्थितियों को, दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का आश्वासन देने तथा बाजार के स्वामित्व को जारी रखने के लिए व्यापार विभागों को एक निश्चय समस्या का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि पहिले कहा था कि सन् १९५६ में वस्तुओं का कुल फुटकर विक्रय ६५, ००० मिलियन yuan तक हो जायगा तथा सन् १९५८ से १९ प्रतिशत अधिक हो जायगा। यह वृद्धि यानी सन् १९५० का कुल फुटकर विक्रय १७,००० मिलियन yuan से तीन गुनी अधिक है। सन् १९५३ की यानी प्रथम योजना की प्रथम वर्ष के ३४,८०० मिलियन yuan की तुलना में यह ८७ प्रतिशत अधिक है। चीन देश की जनसंख्या बहुत होने के कारण प्रति व्यक्ति के उपभोग में थोड़ी सी वृद्धि का अर्थ होता है, अतिरिक्त उपभोग के योग में एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि। इस स्थिति में जहाँ कि उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन भोग के साथ नहीं चल सकता है तो वहाँ जहाँ कि एक वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं की पूर्ति अस्थायी रूप से कम है, वहाँ इस स्थिति की अग्रहेलना करना कठिन हो जाता है। आखिरी व्यापार विभागों का महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि देश भर में बाजार का सुप्रबन्ध किया जाय तथा अपनी क्षमतानुसार उपभोक्ता की वस्तुओं की पूर्ति का काम किया जाय तथा यदि सम्भव हो सके भोग एवं पूर्ति के बीच के अन्तर को दूर करने का प्रयास किया जाय।

व्यापार विभागों को कई स्तर पर, कृषि के उत्पादन के क्रम कार्य को उत्पन्न करने तथा देहाती सहकारिता एवं दैनिक उपभोग की औद्योगिक वस्तुओं को उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। उनको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कच्चे माल की तरह प्रयोग से अवशिष्ट माल का क्रय ठीक प्रकार से होता है या नहीं। साथ ही साथ कृषि उत्पत्ति तथा सहायक व्यवसायों को उत्पन्न किया जाय तथा नगरी एवं देहाती के मध्य क्रय एवं बाजार की ठेके देने की वस्तुओं की पारस्परिक गति को विस्तृत किया जाय, निर्यात व्यापार के प्रशासन को उत्पन्न किया जाय जिससे कि राज्य निर्यात योजना—संख्या एवं गुण को दृष्टि में रखकर—समय पर पूरी हो सके।

औद्योगिक, कृषि, यातायात अथवा व्यापार कोई भी क्षेत्र बगैर न हो, उन आन्दोलन का केन्द्रीय लक्ष्य, सदैव धर्म की उत्पत्ति, उत्पत्ति की वृद्धि, मिलव्यमिता तथा वर्धादी का विरोध होना चाहिए। सन् १९५६ की राष्ट्रीय आर्थिक योजना का क्षेत्र विस्तृत है तथा होने वाले कार्य कठिन है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें प्रोत्साहन देने की कोई सम्भावना नहीं है अथवा उनकी योजना के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सकते। उत्पत्ति तथा निर्माण दोनों में ही नई 'प्रावधिक पद्धतियों' एवं प्राविधिक आन्दोलन की सम्भावनाएँ असंमित हैं। आगारों तथा वस्तुओं की उत्पत्ति

उन्नत-वस्तुओं का उपभोग, उत्पत्ति के तथा योजनाओं के उद्देश्यों में उन्नति, इमारतों के सिद्धान्तों का अस्तित्व में आना, मानव शक्ति, कच्चे माल तथा अन्य वस्तुओं में मितव्ययिता, बहुत सी स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग, उत्पत्ति एवं कार्यक्रमों के गुण में उन्नत करना—ये सभी मिद्धान्त श्रम की उत्पत्ति को बढ़ाने तथा कीमत में कमी करने में सहायता करेंगे । जब तक वे नीतियाँ निर्धारित करने में सामर्थ्यवान हैं, वगैरे तथा जन समूह की राजनैतिक चेतना को उन्नति करना चाहिए तथा जनता को सन् १९५६ की योजना के बड़े राजनैतिक महत्त्व का अनुभव करना चाहिए और उन समस्याओं से अवगत कराना चाहिए जो आये आने वाली हैं, तथा जनता को चरम सीमा तक प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें नवीन पद्धतियों तथा साधनों का अनुसंधान करना चाहिए, जिससे कि उत्पत्ति बढ़ेगी तथा मितव्ययिता में भी वृद्धि होगी । सदाह-एयर्, देश भर की सभी खानों में कोयले का औसत दैनिक उत्पादन, सन् १९५६ की जनवरी तथा फरवरी में ६६०,००० टन था लेकिन नवीन प्रावधिक पद्धतियों पर केन्द्रीत प्रतिस्पर्धा तथा प्रावधिक क्रान्ति—जो कर्मचारियों में भाव में प्रारम्भ हुई—के फलस्वरूप इस महीने में औसत दैनिक उत्पादन १,१३०,००० टन तक पहुँच गया । इस प्रकार इस वर्ष की प्रथम तिमाही का जो कार्य निर्धारित हुआ था वह पूरा हो गया । इसी प्रकार का जन आन्दोलन कोयला तथा अन्य उद्योगों, कृषि तथा यातायात में भी प्रारम्भ हो रहा है । अब वे वर्ष की दूसरी तिमाही के प्रारम्भिक भाग में है जो कि वार्षिक योजना की पूर्ति का निश्चित समय है । उन्हें आदर्श एवं राजनैतिक दोनों ही दृष्टियों से हर कर्मचारी, कृषक, बुद्धिजीवी व देश भक्त नागरिकों की शक्ति को, देश के प्रत्येक भाग में, तुरन्त देश व्यापी आन्दोलन शुरू करने के लिए तथा मितव्ययिता को व्यवहार में लाने के लिए, प्रोत्साहित करना चाहिए । उन्हें विश्वास है कि यदि वे ऐसा आन्दोलन छेड़ते हैं तथा उसे अन्त तक जारी रखते हैं तो वे निश्चय ही सन् १९५६ की योजना को, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का विकास करने के लिए, सामर्थ्यवान हो सकेंगे ।

आदर्श नियोजन : सोवियत संघ।

(Planning Model : U. S. S. R.)

१—रूस की सप्तवर्षीय योजना की मौलिक विशेषतायें^१

(Basic Features of the Soviet Seven Year Plan)

समाजवादी निर्माण के प्रत्येक पहलू पर, सोवियत संघ के प्रभावशाली विकास, सोवियत राज्यों का एकीकरण (Consolidation of Soviet State) का कार्य एवं उसकी अर्थव्यवस्था सदैव सफलतापूर्वक सुलझाई गई है, क्योंकि साम्यवादी दल समाज के विकास के लिए मार्क्सवाद, लेनिनवाद के सिद्धान्तों को मौलिक सिद्धान्त मानता है, जिससे कर्मचारियों के बृहत समूह के रचनात्मक कार्यों एवं प्रारम्भिक (Initiative) कार्यों में सहायता मिलती है तथा राजकीय आर्थिक योजनाओं में, समाजवादी तथा साम्यवादी निर्माण के मुख्य प्रश्न एवं उन्हें हल करने के उपाय तथा साधनों का ठीक तरह से निर्धारित करना है।

सोवियत संघ के समाजवादी निर्माण ने यह निश्चयपूर्वक सिद्ध कर दिया है कि समाजवादी पद्धतियों पर आधारित अर्थव्यवस्था को सफल बनाने के लिए दीर्घकालीन तथा संगठित राजकीय योजनाओं की आवश्यकता है। लेनिन ने—जिसकी, प्रतिभा ने समाजवादी अर्थव्यवस्था के नियोजन के विचारों को जन्म दिया था, जिसने समाजवादी नियोजन के मौलिक सिद्धान्तों को छूट निकासता तथा आर्थिक विकास के लिए प्रथम दीर्घ श्रेणी वाली योजना (Long Range Plan) को प्रेरित एवं संगठित किया—अम्मीरता पूर्वक वैज्ञानिक ढंग से रूस के विद्युतीकरण (Electri-

१ [Courtesy the Embassy of the U S S R in India, and the Information Department of U S S R in India, New Delhi]

२ New Soviet Seven Year Plan Thesis of N S Khrushchov's Report to 21st C P S V Congress Published by the Information Dept of U S S R Embassy in India, New Delhi

fication) के लिए प्रसिद्ध (GOERO) योजना को समर्थित किया। लेनिन द्वारा ही प्रसिद्ध सहकारी योजना के अन्तर्गत कृषि का समाजवादी रूप में परिवर्तन किया गया। साम्यवादी दल ने लेनिन के आर्थिक नियोजन के विचारों को पंचवर्षीय योजनाओं की आधारशिला माना। उनकी सफल अनुभूति ने आर्थिक प्रगति में द्रुत गति से बढ़ने का आश्वासन दिया एवं रूस को शक्तिशाली समाजवादी औद्योगिक देश बना दिया, तथा उसे सामूहिक कृषि-शक्ति में परिवर्तित कर दिया। सोवियत संघ के द्रुत आर्थिक उत्थान के बहुमूल्य अनुभव ने—जो राजकीय योजनाओं पर आधारित है—अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति एवं मान्यता प्राप्त कर ली है।

वर्तमान परिस्थितियों में, जब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एक नवीन विकास के शिखर पर पहुँची, तो साम्यवादी दल ने अपने २० वें अधिवेशन में दीर्घ श्रेणी (Long Range) की योजनाओं की अवधि को और बढ़ाने के लिए बल दिया।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य एवं विचारधारा सोवियत संघ की उच्च सोवियत (Supreme Soviet) के अधिवेशन में निर्धारित किये गये थे, जो कि प्रक्टूबर की समाजवादी क्रांति (Great October Socialist Revolution) की ४० वीं वर्षगांठ को समर्पित किये गये।

यह अनुमान किया जाता है कि सोवियत संघ के आर्थिक विकास के आगामी १५ वर्षों में देश के उद्योग धन्धे दूने हो जायेंगे तथा उत्पादन तिगुना हो जायेगा। इसके प्रतिरिक्त सन १९५७ ई० की तुलना में खनिज लोहे (Iron ore) का उत्पादन ३.५ गुना, तेल का चार गुना, गैस का १३ से १५ गुना तक, कच्चे लोहे एवं फौलाद (Pig Iron & steel) का २.३ गुना, विद्युत का ४.३ गुना तथा सीमेंट आदि का ४ गुने से भी अधिक, बढ़ जायेगा। कृषि के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास का आश्वासन दिया गया है ताकि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सके, एवं सोवियत संघ के लोगों की आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्णरूपेण सन्तुष्ट किया जा सके। आगामी १५ वर्षों में आर्थिक विकास का कार्यक्रम सोवियत संघ में साम्यवाद के निर्माण का आर्थिक कार्यक्रम है।

१९५६-६५ आर्थिक विकास के उद्देश्य जो इस दीर्घकालीन योजना के धर्ममय भाग हैं सोवियत संघ के साम्यवादी दल (C.P.S.U.) के २१ वें अधिवेशन में उसके समक्ष रखे जा रहे हैं। कार्यक्रम का एक बड़ा भाग, जो १५ वर्षों के कार्यक्रम में आता है, सन् १९५६ से १९६६ तक के समय में ही कर लिया जायगा।

आगामी ७ वर्षों की मुख्य समस्या, आर्थिक प्रगति को समाजवाद तथा पूँजीवाद के बीच दान्तिपूर्ण आर्थिक प्रतियोगिता में अधिक से अधिक प्राप्ति करके साम्यवाद की ओर जोड़ना है अर्थात् पूँजीवाद पर विजय प्राप्त करके पूरा साम्यवाद का प्रसार करना है।

विकास के कार्यों मे समाजवादी अर्थव्यवस्था को सर्वे उच्च स्थान दिया गया है और दिया जाता है। जब सन् १९१३ के औद्योगिक उत्पादन के स्तर को पुनः प्राप्त करके अर्थव्यवस्था के पुनः निर्माण के भौतिक तत्वों की ओर अग्रसर हुए, तथा उनको पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रारम्भ किया तो सोवियत संघ समार^१ के अत्यधिक विकसित पूँजीवादी देशों से ५० से १०० वर्ष तक पीछे था। १० से १२ वर्षों मे इस अपने एक सदी पिछड़ेपन को दूर कर, अग्रिम बढ़ गया तथा एक महान् समाजवादी शक्ति बन गया और अपनी महान् उपलब्धियों, स्वतन्त्रता एवं आत्मनिर्भरता की रक्षा करने के योग्य हो गया।

द्वितीय विश्व-युद्ध मे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को महाद् क्षति पहुँचने के पश्चात् भी—'देशभक्ति के युद्ध' के समाप्त होने के २ या २॥ वर्ष पश्चात्—सोवियत संघ के औद्योगिक उत्पादन का स्तर फिर १९४० अर्थात् युद्ध के पूर्व के स्तर पर आ गया, तथा अगले दस वर्षों मे चार गुने से भी अधिक बढ़ गया।

अगले ७ वर्षों मे, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तथा उसके सभी अंग, मुख्य रूप से, भारी उद्योग जारी रहेगे, ताकि अमेरिका सहित सभी पूँजीवादी देशों के समान बहुमुखी आर्थिक विकास हो सके। उनका ध्येय, समाजवाद के वर्तमान स्तर से भी श्रेष्ठ समाजवाद का निर्माण करके उसकी प्रगति को साम्यवाद की ओर अग्रसर करने तथा अन्त मे सोवियत संघ की जनता के हित के लिए आर्थिक शक्तियों मे वृद्धि करना है।

सप्तवर्षीय योजना, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों मे अत्यधिक परिवर्तन लाने पर आधारित है। यह केवल आर्थिक उत्थान को पहले से तीव्र गति देने का ही आश्वासन नहीं देती है, बल्कि सबसे अधिक विकसित पूँजीवादी देशों की तुलना मे, उत्पादन—जो उद्योगों की कुँजी है—के परिमाण एवं कृषि मे बहुत वृद्धि का परिचायक है। उत्पत्ति की शक्तियों के सात वर्ष के द्रुत विकास का ही यह परिणाम है कि देशवासियों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने वाली समस्या का कार्य पर्याप्त सीमा तक हल हो जायेगा तथा वह आवश्यक भौतिक सुविधाओं की उत्पन्न करने मे सफल हो सकेगा—“तथा जो समाज के सभी सदस्यों के सर्वतोन्मुखी विकास एवं सभी दृष्टियों से समृद्ध होने का आश्वासन देगी।”^१

आगामी १५ वर्षों मे सोवियत संघ सम्पूर्ण उत्पत्ति की मात्रा मे ही नहीं, अपितु प्रति व्यक्ति आय मे भी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा तथा वहाँ साम्यवाद के भौतिक एवं प्रावधिक आधार भी स्थापित हो चुके होंगे।

1 For ensuring the full well being and free all round development of all members of Society VI Lenin, Collected Works, Vol. VI, p 37.

२—समाजवादो उद्योग का विकास (Development of Socialist Industry)

कुल औद्योगिक उत्पादन—सन् १९५८ की तुलना में १९६५ ई० में लगभग ८० प्रतिशत बढ़ेगा। इस वृद्धि में यह उत्पादन भी सम्मिलित है

(क) उत्पत्ति के साधनों का उत्पादन ८५ से ८८ प्रतिशत बढ़ेगा तथा,

(ख) उपभोक्ता की वस्तुओं का उत्पादन ६२ से ६५ प्रतिशत तक बढ़ेगा। सन् १९५१-६५ में सम्पूर्ण उद्योग के कुल उत्पादन की वार्षिक औसत वृद्धि ८६ प्रतिशत के लगभग होगी, जबकि पहले की सात वर्षों में वृद्धि केवल ६०,००० मिलियन रूबल्स ही हुई।

(क) भारी उद्योग

(१) लोहा एवं इस्पात उद्योग—योजना में यह कहा गया है कि सन् १९६५ में ६५७० मिलियन टन कच्चा कोयला उत्पन्न किया जायेगा, अर्थात् १९५८ से ६५७७ प्रतिशत अधिक, इस्पात ८६६१ मिलियन टन, यानी ५६६५ प्रतिशत अधिक, घातु ६५७० मिलियन टन अथवा १९५८ से ५२६४ प्रतिशत अधिक, खनिज लोहा (Dressed iron ore) १५०-१६० मिलियन टन (२३०-२४५ मिलियन टन अचुद्ध खनिज लोहा) सन् १९५६-६५ में वार्षिक औसत वृद्धि, कच्चे लोहे (Pig iron) में, सन् १९५२-१९५८ के २५ मिलियन टन के स्थान पर ३६४४ मिलियन टन होगी, इस्पात में १९५२-५८ की ३४ मिलियन टन वृद्धि के स्थान पर ४४५१ मिलियन टन होगी, Rolled Metals की १९५२-५८ की २७ मिलियन टन वृद्धि के स्थान पर ३२-३६ मिलियन टन वृद्धि हुई, तथा खनिज लोहे की वृद्धि १९५२-५८ की ६२ मिलियन टन की वृद्धि के स्थान पर ६-१०३ मिलियन टन हुई। 'विद्युत स्पात' का उत्पादन १७० गुना अधिक हो जायेगा, चदर का स्पात लगभग दुगुना हो जायेगा।

ऐसा विचार है कि सन् १९५६-६५ में १९५१-१९५८ के १६१ मिलियन अधिकार दिये हुए कच्चे लोहे के उत्पादन के स्थान पर २४३० मिलियन टन कच्चा लोहा उत्पन्न करने की आशा दे दी जायेगी, इस्पात सन् १९५२-५८ के १२४ मिलियन टन की अपेक्षा २८३६ मिलियन टन, Rolled Metal सन् १९५२-५८ के ६६ मिलियन टन के स्थान पर २२-२६ मिलियन टन उत्पन्न होगा।

२—लोहेतर धातुओं का उद्योग (Non-ferrous Metals Industry)

सन् १९५८ की तुलना में, लव्याङ्क इस प्रकार हैं, एलमोनियम के उत्पादन में २८ गुनी वृद्धि, शुद्ध ताँबे के उत्पादन में १६ गुनी वृद्धि तथा कलई, मैग्नेशियम, टिटैनियम, जर्मेनियम और सिलीकन के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। लोहेतर (Non ferrous) सम्बन्धी, विशेषकर अन्य धातुओं में भी औरो की तरह वृद्धि होगी। एलमोनियम के उद्योग में बड़ी तेजी से विकास होगा।

अन्य खुले साधनों द्वारा लोहेतर (Non-ferrous) खनिज धातुओं का उत्पादन, सात वर्षों में २८ गुने से अधिक बढ़ जायगा तथा १९६५ में कुल खनिज धातु का उत्पादन ६५ प्रतिशत होगा। सोवियत संघ में हीरो का उत्पादन, सन् १९६५ में १९५८ की अपेक्षा, लगभग १४ गुने से भी अधिक बढ़ जायेगा।

(३) रासायनिक उद्योग (Chemical Industry) रसायनों का उत्पादन लगभग ३ गुना बढ़ जायगा। मिलावट (Synthetic) की वस्तुओं की उत्पत्ति में भी वृद्धि होनी है, रासायनिक तन्तुओं की उत्पत्ति में ३८-४ गुनी वृद्धि होगी। मिलावट के मूल्यवान तन्तुओं को मिलाकर १२-१४ गुनी वृद्धि होनी है, प्लास्टिक तथा मिलावट की रेजिन्स (Synthetic resins) में ६७ गुनी वृद्धि होगी।

(४) ईंधन उद्योग (Fuel Industry)

सन् १९६५ में तेल एवं गैस का भाग, कुल ईंधन के उत्पादन में, वर्तमान उत्पादन के ३१ प्रतिशत भाग के स्थान पर ५१ प्रतिशत हो जायगा, तथा कोयले का भाग ५९ प्रतिशत रह जायेगा। तेल के उद्योग में योजनानुसार सन् १९६५ में २२००-२४० मिलियन टन, अर्थात् १९५८ की अपेक्षा दूने से भी अधिक हो जायगा। तेल की वार्षिक औसत वृद्धि में सन् १९५१-५५ के ६६ मिलियन टन तथा सन् १९५६-५८ के १४२ मिलियन टन के स्थान पर १६७ मिलियन टन एवं १७८ मिलियन टन की क्षमता वृद्धि होगी। तेल को शुद्ध करने की क्षमता में सन् १९५६-१९६५ में २१-२२ गुनी वृद्धि होगी। गैस उद्योग में गैस का उत्पादन सन् १९५८ के ३०,००० मिलियन क्यूबिक मीटर के स्थान पर सन् १९६५ में १५०,००० मिलियन क्यूबिक मीटर हो जायगा अथवा ५ गुने के लगभग हो जायगा। कोयला उद्योग में सन् १९६५ में, सन् १९५८ की अपेक्षा २०-२३ प्रतिशत यानी ५९६-६०९ मिलियन टन तक वृद्धि हो जायगी तथा सबसे अधिक, 'कम खर्च होने वाले कोयले' के उत्पादन में, (यूराल को छोड़कर) देश के पूर्वी भागों में ४२-४५ प्रतिशत की वृद्धि होगी, 'खाना बनाने वाले कोयले' के उत्पादन में ६० से ६६ प्रतिशत वृद्धि होनी है अर्थात् १९६५ में १५०-१५६ मिलियन टन हो जायेगा।

(५) विद्युतीकरण (Electrification) :

सन् १९६५ में, विद्युत शक्ति का उत्पादन देश में ५००,००० मिलियन किलोवाट यानी दुगुना हो जायगा तथा विद्युत शक्ति के 'प्लाट्स' की क्षमता में दुगुनी वृद्धि होगी। गर्मल टर्बाइन की क्षमता में, सप्तावर्षीय योजना काल के अन्त तक, २३-२४ गुनी वृद्धि हो जायगी। विद्युत ग्रिड्स के विस्तार को भी लगभग ३५५०० किलोवाट टेंशन यानी २५-३ गुना बढ़ाने का विचार किया गया है।

(६) कलों का निर्माण (Machine Building) :

बड़ी कलों और औजारों (Major type of Machines and Instruments) की योजना निम्न प्रकार है

	१९६५ मे वृद्धि	१९५८ की तुलना मे
धातु काटने की रत व औजार (हजारो मे)	१६० २००	१ ४-१ ५ गुना
विशेष प्रकार के तथा कुल कल औजारो का योग (हजारो मे)	३८	२ गुना
दवाने एवं छापने की कल (हजारो मे)	३६ २	१ ५ गुना
स्वतः तथा अर्द्ध-स्वत चलने वाली कलो का पूरा सेट	२५०-२७१	१ ६ २ १ गुना
सूक्ष्म औजार (मिलियन रुबल)	१८,५००-१९,२००	२ ५-२ ६ गुना
गणना करने वाली एवं अंकित करने वाली कलें (मिलियन रुबल)	२०,०००-२,१००	४ ५-४ ७ गुना
वायु चालित यन मिलियन किलोवाट)	१८७ २० ४	२ ८-३ गुना
वायु चालित यनो के उत्पन्न करने वाले यन (मिलियन किलोवाट मे)	१७ ५-१८ ४	३-३ २ गुना
वर्तमान विद्युत यनो के बदलने के यन (मिलियन किलो- वाट मे)	३२-३४	२ २-२ ४ गुना
कारखानों के घूमने वाले औजार (हजार टन मे)	३,५००-३,७००	३ ३-३ ५ गुना
रासायनिक औजार (मिलियन रुबल)	२,५००	२ २ गुना
लाघ, एवं लाघ कारखानो के उद्योगो के प्रावधिक औजार (मिलियन रुबल)	३,८००-४ १००	२ १ २ ३ गुना
मोटर गाडियाँ (हजारो मे)	७५० ८५६	१ ५ १ ७ गुना
ट्रेक, लाइन, तथा डोजर के कारखान की इकाइयाँ (मिलियन अरबवाकित)	२,१००-२,७०० ८ ४-९ ०	२ ३-२ ५ गुना २ ८ ३ गुना

सीमेन्ट उद्योग के लिए प्रावधिक

श्रीजार (हजारों में)

१८०-२२०

२'१-२'६ गुना

ढलाई करने के उत्पादन के लिए

प्रावधिक श्रीजार (मिलियन

रूबल्स)

३६०-४१०

२'३ गुना

(७) टिम्बर, कागज एवं लकड़ी का उद्योग .

छोटे उत्पादकों को न गिनते हुए, कुल लकड़ी (Timber) का चीरना सन् १९५८ की तुलना में १९६५ में ३२२ मिलियन क्यूबिक मीटर से ३७२-३७८ मिलियन क्यूबिक मीटर हो जायगा ।

व्यापारिक लकड़ी का चीरना सन् १९६५ में २७५-२८० मिलियन क्यूबिक मीटर हो जायगा ।

कारखानों में चिरी हुई लकड़ी की उत्पत्ति, सन् १९५८ को ६८६ मिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़ कर सन् १९६५ में ६२'६५ मिलियन क्यूबिक मीटर हो जायगी । उत्तर एव साइबेरिया के सड़की वाले क्षेत्र में लकड़ी का चीरना १'८ गुना अधिक हो जायगा । सन् १९६५ में फर्नीचर का निर्माण १८,००० मिलियन रूबल्स हो जायगा अथवा सन् १९५८ की अपेक्षा २४ गुना अधिक हो जायगा । ऐसी योजना बनाई गई है कि सन् १९६५ में संत्यूनीज की उत्पत्ति लगभग ४८ मिलियन टन होगी अथवा सन् १९६२ की उत्पत्ति से २'३ गुनी अधिक होगी, बनावटी रेशे (Artificial fabrics) की उत्पत्ति में, उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति का आश्वासन दिलाने के लिए विस्कोस संत्यूनीज की उत्पत्ति, सन् १९६५ में ५८०,००० टन करनी पड़ेगी यानी सन् १९५८ से ४५ गुनी अधिक हो जायगी । सन् १९६५ में कागज की उत्पत्ति ३'५ मिलियन टन होगी यानी सन् १९५८ की अपेक्षा १'६ गुनी अधिक, काडंबोड लगभग २'८ मि० टन उत्पन्न किया जायगा अर्थात् सन् १९५८ की अपेक्षा ४ गुना अधिक उत्पादन होगा । वांधने के लिए प्रयोग में आने वाले काडंबोड का उत्पादन सन् १९५८ के ७०,००० टन के स्थान पर १९६५ में १,५००,००० टन हो जायगा । अलवारी कागज की उत्पत्ति सन् १९५८ से १८ गुनी अधिक हो जायगी ।

उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पत्ति

(८) हल्के उद्योग—हल्के उद्योग का कुल उत्पादन ७ वर्षों में लगभग १'५ गुना अधिक हो जायगा । हल्के उद्योग की प्रमुख वस्तुओं की उत्पत्ति की योजना निम्न प्रकार बनाई गई है :

		१९५८	१९६५	१९६५ १९५८ के प्रतिशत में
	प्रत्याशित पूर्ति			
सूती कपड़ा (मिलियन मीटर)	५,८००	७,७००-८,०००	१३३-१३८	
ऊनी कपड़ा (मिलियन मीटर)	३००	५००	१६७	
लिनन कपड़ा (मिलियन मीटर)	४८०	६३५	१३२	
रेशमी कपड़ा (मिलियन मीटर)	८१४	१,४८५	१८२	
बनियान व मोड़े आदि (मिलियन मीटर)	८८२	१,२५०	१४२	
बिना हुए झण्डरबोझर (मिलियन)	३६२	७८०	१६६	
बिना हुए वस्त्र (मिलियन)	६५	१६०	१६८	
घमड़े के जूते (मिलियन जोड़े)	३५५	५१५	१४५	

(६) खाद्य-उद्योग—सदयाच्च, खाद्य उद्योग की प्रमुख पैदावार के निम्न-

लिखित उत्पादन को प्रकट करते हैं .

	१९५८	१९६५	१९६५, १९५८ के प्रतिशत में
	प्रत्याशित पूर्ति		
गोदत, राज्य के कच्चे माल के स्रोतों की प्रथम कौटि की सहायक उत्पत्ति सहित (हजार टन) ।	२,८३०	६,१३०	२१७
मक्खन, राज्य के कच्चे माल के स्रोतों में (हजार टन) ।	६२७	१,००६	१६०
दूध के रूप में डेरी-उत्पादन (हजार टन) ।	६,०१७	१३,५४६	२२५
चुन्दर से उत्पन्न दानदार चीनी (हजार टन) ।	५,१५०	६,२५०-१०,०००	१८०-१६४
वनस्पति तेल, राज्य के कच्चे माल के स्रोतों से (हजार टन) ।	१,२२१	१,६७५	१६२
मछली पकड़ना (हजार टन) ।	२,८५०	४,६२६	१६२
द्विपाईल एल्कोहल (मिलियन डिक्लीटर्स) ।	१५८८	२०२८	१२८
खाने योग्य पदार्थों सहित कच्चे माल से उत्पन्न मादक पदार्थ (मिलियन डिक्लीटर्स) ।	१११७	१००	६०

(१०) घरेलू वस्तुओं की उत्पत्ति—घरेलू वस्तुओं तथा मशीनों एवं औजारों का उत्पादन, जो गृहस्थों के कार्य को हल्का करेगा, दूना हो जायगा तथा सन् १९६५ में ८८,००० मिलियन रूबल्स हो जायगा । फर्नीचर के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी, सिलाई की मशीनें, रेफ्रिजरेटर, कपड़े धोने की मशीनें, डिश वाशर्स, रेडियो, तथा बेनार के तार, घड़ियों, साइकिलों, मोटर साइकिलों, टैलीविजन तथा

मोटरो, स्कुटरों एवं बिजली के घरेलू मीनारों, इन सभी के उत्पादन में समुचित रूप से वृद्धि होगी ।

३—समाजवादी कृषि का विकास (Development of Socialist Agriculture)

सोवियत संघ की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के सन् १९५६-१९६५ के लक्ष्य-द्वार का प्रारूप निम्नलिखित बिषयों पर प्रकाश डालता है—

अनाज के उत्पादन को और अधिक विस्तृत करना, जिससे सात वर्षों के अन्त तक अनाज की फसल १०,००० मिलियन पीण्ड प्रति वर्ष तक हो सके ।

सन् १९६५ में प्रमुख औद्योगिक फसल की उत्पत्ति में निम्न प्रकार से वृद्धि की जा सके—रई ५.७ से ६.७ मिलियन टन अथवा सन् १९५७ से ३५-४५ प्रतिशत अधिक, तेल प्रदान करने वाले बीज लगभग ५.५ मिलियन टन अथवा ७० प्रतिशत अधिक, चुकन्दर ७०-७५ मिलियन टन अथवा सन् १९५७ से १.५ या २ गुना अधिक, सन् की वस्तुएं ५००,००० टन यानी सन् १९५७ से ३२ प्रतिशत अधिक ।

सन् १९६५ में आलू की कुल फसल में सन् १९५७ के लगभग ८८ मिलियन टन के स्थान पर १.४७ मिलियन टन तथा सब्जियों की उत्पादित मात्रा में जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वृद्धि होगी ।

फलों तथा कन्दमूल फल इत्यादि की उत्पत्ति में ७ वर्ष में कम से कम दुगुनी वृद्धि, घास में कम से कम चार गुनी वृद्धि होगी ।

सन् १९५८ की तुलना में, सन् १९६५ में मुख्य पशु-उत्पत्ति के उत्पादन में वृद्धि इस प्रकार होगी गोशत (कटे हुए की तौल) ६,०००,००० टन अथवा सन् १९५८ का दुगुना, दूध १००-१०५ मिलियन टन यानी सन् १९५८ का १.७-१.८ गुना, उन लगभग ५५०,००० टन अथवा १.७ गुना तथा अण्डे ३७००० मिलियन अथवा सन् १९५८ का १.६ गुना है ।

सन् १९६५ में, कृषि का कुल उत्पादन सन् १९५८ की तुलना में—जैसा कि निम्नलिखित अंकों में प्रदर्शित किया गया है—१.७ गुना अधिक हो जाएगा ।

खेतों के प्रति सौ हेक्टरों (Hectors)

(Mean Centners)

	सोवियत संघ सन् १९६५	संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी सन् १९५७
अनाज	३२६-३६०	२८०
आलू	२६४	१६
चीनी	१८.५-२०	४१
गोशत (कटे हुए की वजन)	३२	२६

दूध	२००-२१०	१०१
ऊत	१-१	०.२

(२) फसलों की उत्पत्ति—आगामी सात वर्षों के समय में फसल की उत्पत्ति का द्रुत गति से विस्तार करना है। आगामी वर्षों में भी फसल की उत्पत्ति के विकास के लिए, अनाज के उत्पादन को सबसे अधिक बढ़ाना, कृषि उत्पत्ति का मुख्य आधार होगा। सोवियत संघ की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के लक्ष्यांक, कृषि के लिए खाद की पूर्ति सन् १९५८ की १०.३ मिलियन टन के स्थान पर सन् १९६५ में ३१,०००,००० टन प्रकट करते हैं।

(३) पशु-पालन—आगामी सात वर्षों में पशु-पालन द्वारा गोشت, दूध, घण्डे तथा ऊत में वृद्धि करनी है। सन् १९५२-१९५८ में गोشت की उत्पत्ति के वार्षिक औसत का परिमाण लगभग ५००,००० टन (कट हुए गोश्त का वजन) था। सन् १९५९ से ६५ में यह १,१००,००० टन से भी अधिक हो जायगा, दूध ३,१००,००० से ५,९००,०००-६,६००,००० टन एवं ऊत १८,००० टन से ३३,००० टन हो जायगी। सामूहिक कृषि में प्रति गाय के दूध में कम से कम २,६०० किलोग्राम की वृद्धि होनी है। सन् १९५२-१९५८ की पशुओं की औसत वार्षिक वृद्धि की अपेक्षा सन् १९५९-६५ में ३.२ गुनी हो जायगी जिसमें बायो की ३.२ गुनी तथा भेड़ों की लगभग दुगुनी वृद्धि सम्मिलित है।

अनाज की उत्पत्ति की नियोजित वृद्धि के फलस्वरूप सन् १९६५ में, पशुओं के लिए ८५-९० मिलियन टन चारा प्राप्त हो सकेगा। साथ ही साथ घास की उत्पत्ति में भी कम से कम दुगुनी वृद्धि तथा साइलेज (Silage) में कम से कम चार गुनी वृद्धि होनी चाहिए और आधुनिक उत्पादन में सन् १९५७ की अपेक्षा लगभग दुगुनी वृद्धि होनी चाहिए।

(४) कृषि की पैदावार की प्राप्ति (Procurement of Agricultural products)

लक्ष्यांक प्रदर्शित करते हैं कि मौलिक कृषि की पैदावार की प्राप्ति में सन् १९६५ में निम्न प्रकार से वृद्धि होगी

	१९६५ (हजार टनो में)	१९६५ १९५७ का प्रतिशत
रई	५,७००-६,१००	१३५-१४५
चुकन्दर	७०,०००-७८,०००	१८०-२००
तेल वाले बीज	३,५६०	१८०
आलू	११,७२०	१४८
सन की वस्तुयें	५३०	१३७
गोश्त	११,०१०	२.२

दूध	४०,६१०	२ गुना
ऊन	५४०	१.६ गुना
अण्डे (मिलियन)	१०,०००	२.३ गुना

(५) राजकीय कृषि का विकास (Development of State farms)—

अगले सात वर्षों में राजकीय कृषि क्षेत्रों, विशेषकर बंजर भूमि के विकास क्षेत्रों में, गृह निर्माण तथा फार्मों से लगे हुए घर बनवाने की योजना बनाई गई है। सन् १९६५ में सन् १९५७ की तुलना में, अनाज उत्पन्न करने की कीमत को कम से कम ३० प्रतिशत, तथा गोश्त में १६ प्रतिशत, दूध में २३ प्रतिशत, ऊन में ८ प्रतिशत, रूई में २० प्रतिशत कीमत घटायी जाय। राजकीय कृषि का विकास करने तथा राजकीय कृषि में उच्च लाभ का आश्वासन देने के लिए ऐसी योजना बनाई गई है कि मशीनों की पूर्ति तथा उनके सामान एवं खाद सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में समुचित रूप से वृद्धि की जा सके। राजकीय कृषि में विशेष अनुसन्धान, कुछ निम्नित पैदावारों को प्रभावित करेगा।

(६) कृषि का यन्त्रीकरण तथा विद्युतीकरण (Mechanisation and Electrification of Agriculture)—उत्पत्ति के विस्तार के लिए अधिकतम यन्त्रीकरण एवं विद्युतीकरण, सामूहिक कृषि का आधुनिकतम उपकरण का प्रवन्ध, सन् १९५६-६५ के कृषि के विकास की पूर्ति के लिए निर्णायक परिस्थिति है।

सात वर्षों में कृषि के लिए एक मिलियन ट्रैक्टर, लगभग ४००,००० अनाज की मिश्रित फसल काटने वाली मशीन तथा अन्य कल एवं उपकरण और देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त किये जाने वाले कृषि के मिश्रित यन्त्रों की बड़ी संख्या में उपलब्ध करने की योजना बनाई है।

कृषि के विद्युतीकरण के लिए सन् १९५६-१९६५ में विस्तृत क्षेत्र होगा। सात वर्ष के अन्त तक देश के सभी सामूहिक कृषि क्षेत्रों में विद्युतीकरण की व्यवस्था पूरा करने की कल्पना की गई है जबकि राजकीय कृषि क्षेत्रों का विद्युतीकरण, मरम्मत एवं प्रावधिक सेवा केन्द्रों की व्यवस्था की पूर्ति और शीघ्र हो जायगी। सामूहिक कृषि क्षेत्रों में विद्युतीकरण की व्यवस्था करने से कार्य का परिमाण सन् १९५२-५८ के कार्य से इन सात वर्षों में यानी १९६५ में २५ गुना अधिक होगा। सात वर्षों में कृषि क्षेत्रों में विद्युतशक्ति का उपभोग लगभग ४ गुना बढ़ जायेगा। राजकीय कृषि क्षेत्रों तथा सामूहिक कृषि क्षेत्रों को राजकीय विद्युत शक्ति प्रणाली एवं विद्युत केन्द्रों से बिजली देने का प्रवन्ध किया गया है। सामूहिक कृषि क्षेत्र तथा राजकीय कृषि क्षेत्र, उत्पत्ति में, विद्युत शक्ति का प्रयोग अधिक विस्तृत रूप से करेंगे।

(७) वन (Forests)—इमारती लकड़ी के सोनो को इस प्रकार प्रयोग करने की योजना बनाई गई है कि वह केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ही पूर्णतः सम्पुष्ट नहीं करें, बल्कि बचत हो एव वन प्रदेशों को पुनः सुगन्धित किया जा सके ।

४—यातायात तथा सवादवाहन का विकास

आगामी सात वर्षों में, प्रमुख यातायात, विशेषकर रेल गाड़ी तथा वायुयान यातायात के प्राबधिक क्षेत्र में मौलिक सुधार होंगे ।

(१) आगामी सात वर्षों के समय में, १८००—१८५० हजार मिलियन टन किलोमीटर अथवा ४० से ४५ प्रतिशत माल गाड़ियों में वृद्धि होगी । सन् १९६५ में, माल गाड़ियाँ ८५ तथा ८७ प्रतिशत के बीच में बिजली एव डीजल इंजन में बंटा करेगी जबकि सन् १९५८ में केवल २६ प्रतिशत ही बिजली तथा इंजन से चलती थी । बिजली तथा डीजल से चलने वाले इंजन लगभग १००,००० किलोमीटर की दूरी तक चलेगे । मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के मध्य यातायात एव संचार की ६,००० किलोमीटर लम्बी लाइनें बिछाने एव द्वितीय श्रेणी के मार्गों में ८,००० किलोमीटर लम्बी प्रधान लाइन बिछाने की योजना बनाई गई है ।

(१) आगामी ७ वर्षों में, रेल यातायात, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की क्षमता के वर्तमान स्तर को मात करने के लिए, ३४—३७ प्रतिशत बढ़ जायगा । रेल से माल ढोने के भाड़े में, ७ वर्षों में, लगभग २२ प्रतिशत की कमी हो जायगी ।

(२) आगामी ७ वर्षों में, सामुद्रिक यातायात में, जहाज से भाड़ा-निर्यात एव आयात के द्वारा—लगभग दूना हो जायगा एव सोवियत संघ के व्यापारियों के लिए समुद्री जहाजों में समुचित वृद्धि होगी । बन्दरगाहों के प्रबन्ध की क्षमता में ७ वर्षों तक ६० से ७० प्रतिशत तक की वृद्धि होगी । कुल घटाने-जतारने के कार्य में ७५ प्रतिशत दम्नीकरण सम्मिलित है ।

(३) नदी-यातायात —अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में नदी यातायात का बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग होगा । सात वर्षों में, इससे प्राप्त होने वाला भाड़ा लगभग १.६ गुना अधिक हो जायगा ।

(४) आगामी सात वर्षों में, 'ट्रक पाइप लाइन' की लम्बाई लगभग तिगुनी हो जायगी, जबकि 'पाइप लाइन' द्वारा किये गये यातायात के परिमाण में लगभग ५.६ गुनी वृद्धि होगी ।

(५) आगामी सात वर्षों में, मोटर यातायात के भाड़े में अनुमानत १.६ गुनी वृद्धि होगी जबकि मोटरों द्वारा ले जाये गये यात्रियों की संख्या तिगुनी से भी अधिक हो जायगी । मोटरों की सम्पूर्ण क्षमता में ४० प्रतिशत वृद्धि होगी तथा नई तरह की मोटर गाड़ियों के साथ मोटर सेवा में वृद्धि भी जायगी । बसों की गति शीलता में ४.४ गुनी वृद्धि होगी । इन सात वर्षों का प्रधान कार्य, मोटर यातायात

के लिए सड़को का बृहत् निर्माण होगा। गत सात वर्षों से १९५६-६५ में राज्य-व्यापी महत्त्व की सड़को का २८ गुना अधिक निर्माण करने की योजना बनाई गई है।

(६) द्रुत एवं बड़े टर्बो जेट तथा टर्बो-प्रोप जहाजों के बनने से, सवारी-यातायात की श्रेणियों में, वायु-यातायात एक प्रधान अंग होगया। इन सात वर्षों में, वायुयान द्वारा यात्रियों का आवागमन लगभग ६ गुना बढ़ जायगा। परिवहन का विकास कार्य मविप्य में भी जारी रहेगा।

५—अर्थ-व्यवस्था में पूँजी-विनियोग तथा पूँजी-निर्माण

आगामी ३ वर्षों में सम्पूर्ण देश में, विशेषकर पूर्वी भागों में, अद्वितीय ढंग से निर्माण कार्य होगा। सन् १९५६-६५ में, पिछले सात वर्षों की तुलना में, राज्य द्वारा किया गया, पूँजी-विनियोग १८ गुना अधिक होगा तथा अर्थ-व्यवस्था में पूँजी विनियोग की लगभग कुल मात्रा—जो सोवियत संघ में अब तक विद्यमान रही है—के बराबर होगी।

निम्न तालिका पूँजी विनियोग के परिमाण की विशेषताएँ स्पष्ट करती है—

(हजार मिलियन रूबल में और कीमती की तुलना में)

	१९५२-५८	१९५६-६५	प्रतिशत में वृद्धि
अर्थ-व्यवस्था के लिए योग	१ ०७२	१,६४०-१,६७०	१८१-१८४
औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण	८२१	१,४८८-१,५१३	१८१-१८४
सकातों तथा जनता की सुविधा के लिए निर्माण	२०८	३७५-३८०	१८०-१८३
शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा की वस्तुओं का निर्माण	४३	७७	१७६

जब सन् १९५६-६५ में राज्य द्वारा किया गया सामान्य पूँजी-विनियोग, अर्थ-व्यवस्था में, १०८ गुना होगा, तो उद्योगों में किया गया पूँजी-विनियोग, गत ७ वर्षों के पूँजी विनियोग की अपेक्षा दुगुना होगा। लोहा एवं हस्पात उद्योग के लिए लगभग १००,००० मिलियन रूबल निश्चित किया गया है। रसायन उद्योग के विकास के लिए १००,०००-१०५,००० मिलियन रूबल रखा गया है। तेल तथा गैस के उद्योग में १७०,०००-१७३,००० मिलियन रूबल का विनियोग किया जायगा। कोयला-उद्योग के विकास के लिए ७५,०००-६८,००० मिलियन रूबल निश्चित किया गया है। विद्युत शक्ति के 'प्लाण्ट्स', विद्युत ग्रिड्स तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए १२५,०००-१२६,००० मिलियन रूबल निश्चित किया गया है। इमारती लकड़ी, कागज तथा लकड़ी के उद्योगों में कुल ५८,०००-६०,०००

मिलियन रूबल का विनियोग होना है एवं ८०,०००-८५ मिलियन रूबल के एवं खाद्य-उद्योगों में विनियोग होना है। मकान एवं जनता की सुविधाओं के लिए ३७५,०००-३८०,००० मिलियन रूबल व्यय होना है। शिक्षा संस्थाओं, विशेषकर छात्रावास एवं शिशु हितकारी संस्थाओं तथा अन्य सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में वृहत् धन राशि व्यय होनी है। राज्य के पूँजी विनियोग का लगभग १५०,००० मिलियन रूबल कृषि पर व्यय होना है।

प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार सामूहिक कृषि-क्षेत्र, सन् १९५६-६५ में, २५०,००० मिलियन रूबल, मकानों की निर्माण सुविधाओं, सामूहिक तथा सामान्य विकास एवं देहात के विकास पर व्यय करने योग्य हो जायेंगे तथा सम्बन्धित उपकरणों के क्रय में ६५,००० मिलियन रूबल व्यय होगा। इस प्रकार कृषि में कुल पूँजी विनियोग, सन् १९५६-६५ में—राज्य द्वारा एवं सामूहिक कृषि क्षेत्रों द्वारा—लगभग ५००,००० मि० रूबल होगा। रेल यातायात के विकास के लिए ११०,०००—१५०,००० मि० रूबल व्यय करने का अनुमान लगाया गया है।

निर्माण-उद्योग एवं निर्माण सामग्री-उद्योग के विकास पर ११०,०००—११२,००० मिलियन रूबल पूँजी का विनियोग होना है।

निर्माण के इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए निर्माण-सामग्री-उद्योग का विकास करना होगा। इन उद्देश्यों के लिए अधियों का प्रारूप (Draft), सन् १९६५ में ७५-८१ मिलियन टन सीमेन्ट की उत्पत्ति की वृद्धि की ओर संकेत करता है यानी सन् १९५८ के उत्पादन से २२-२४ गुना अधिक होगा।

६—सोवियत संघ के लोगों की समृद्धि में वृद्धि

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के लक्ष्यांक, सोवियत संघ की जनसंख्या की भौतिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक-स्तर की द्रुत वृद्धि को प्रकट करते हैं, सोवियत संघ की जनता के हित के लिए, सोवियत सरकार एवं साम्यवादी दल के अथक परिश्रम तथा सेवा कार्य का स्पष्टीकरण करते हैं।

१—राष्ट्रीय आय

सन् १९५८-६५ में राष्ट्रीय आय में ६२-६५ प्रतिशत की वृद्धि होगी, तथा इसकी वृद्धि में सार्वजनिक उपभोग पर भी प्रभाव पड़ेगा। सात वर्षों में उपभोग की धनराशि में ६०-६३ प्रतिशत की वृद्धि होगी।

२—कारखानों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की सभी शाखाओं में ११५ मिलियन व्यक्तियों की अथवा २१ प्रतिशत की वृद्धि होगी। सात वर्षों के अन्त में कारखानों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों की कुल संख्या, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में, ६६० मिलियन व्यक्ति तक पहुँच जायेगी।

३—कारखानों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों की वास्तविक आय

कर्मचारियों की मजदूरी, पेन्शन में वृद्धि, अनुदान एवं श्रविक में कीमतों में कमी होने के परिणाम स्वरूप, ७ वर्षों में, उनको औसतन ४० प्रतिशत का लाभ होगा।

कृषि-उत्पत्ति में वृद्धि एवं उच्च थ्रम की उत्पत्ति के आधार पर, कृषकों की सामूहिक आय में भी, सात वर्षों में, कम से कम ४० प्रतिशत वृद्धि होगी। यह, विशेषकर सामूहिक कृषि क्षेत्रों में, सामान्य रूप में विकास होने के कारण होगा।

४—मजदूरी सम्बन्धी विषय

आगामी सात वर्षों में, उद्योग एवं कार्यालयों के कर्मचारियों की मजदूरी के नियमों में सुधार-कार्य, राष्ट्रीय सर्व-व्यवस्था की सभी शाखाओं में, उद्योग एवं कार्यालय कर्मचारियों की मजदूरी में सामान्य वृद्धि के साथ साथ, पूरा होना चाहिये। उद्योग एवं कार्यालय के कम मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों की मजदूरी में सात वर्षों में, २७०-३२० रुबल से ५००-६०० रुबल प्रति मास हो जायगी।

सन् १९२६-२७ में तक्याकु में प्रदर्शित मापदण्ड कार्य की जनत-स्थिति का, भौतिक स्वच्छता एवं सुरक्षा का, थ्रम की परिस्थितियों को आधारित स्तर पर लाने में नवीनतम वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग सम्बन्धी उपलब्धियों के प्रयोग के माध्यम से जोखिम तथा निर्माण-कार्य के कार्यक्रमों का, आश्वासन देते हैं। महिलाओं एवं लड़कों के कार्य की परिस्थितियों में पर्याप्त उन्नति की जायगी।

५—सिखा एवं ग्रन्थ सुविधाओं का विस्तार करने के लिए, समुचित धन राशि निश्चित करने का आयोजन किया गया है। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य का व्यय, सन् १९२८ के २१५,००० मिलियन रुबल की प्रपेक्षा सन् १९६५ में ३४५,००० मिलियन रुबल के लगभग होगा।

६—लक्याकु, पेन्शन प्रणाली को भी और उन्नत करने की पूर्ण कल्पना को प्रकट करते हैं। सन् १९६३ तक, कम से कम वेतन को ४००-५०० रुबल प्रतिमास तक बढ़ा देने के साथ ही साथ पन्शन में वृद्धि करने की आवश्यकता भी उठ खड़ी होती है। सन् १९६३ तक वृद्धावस्था की कम से कम पेन्शन नगरी में ३०० रुबल से बढ़कर ४०० रुबल मासिक हो जायगी तथा देहाती क्षेत्रों में २५५ से ३४० रुबल प्रतिमास हो जायगी।

७—सोवियत-संघ के साम्यवादी दल के वीसवें अधिवेशन के निर्णयों को दृष्टि में रखकर, सन् १९६० तक, कारखानों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों का दैनिक कार्य करने का समय ७ घण्टे तथा कोयला एवं खानों के महत्वपूर्ण उद्योगों के कर्मचारियों का—जो थ्रम के गर्म में कार्य करते हैं—दैनिक कार्य करने का समय ६ घण्टे कर दिया जायगा। सन् १९६२ तक, कारखानों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों का कार्य करने का समय ७ घण्टे प्रतिदिन से घटाकर ४० घण्टे साप्ताहिक कर दिया जायगा। इस प्रकार सोवियत संघ में बहुमुखी उन्नति प्राप्त होगी।

Appendix I

Percentage Distribution, by Sector, of Planned Public Expenditures in Selected ECARE Countries¹

Country	Duration of the Plan	Agriculture and Irrigation	Transport and Communication	Power	Industry and Mining	Social Services	Others
Burma	1952-60	10.8	42.4	23.0	8.2	15.5	—
Ceylon	1954/55-1959/60	36.5	33.1 ^a	—	4.4	16.0	10.0 ^b
China : Taiwan	1955-56	47.3	8.7	10.4	27.5	—	—
Mainland	1955-57	8.0	11.7	2.8	40.9	18.6	18.0
India	1956/54-1960/61	21.0 ^b	29.0	9.0	19.0	20.0	2.0
Nepal	1956-60	22.0	30.0	14.0	8.0	4.0	22.0 ^b
Pakistan	1956-60	11.1 ^c	20.5	52.5 ^d	13.4	23.8	1.7

¹ Figures shown for different Countries are not fully comparable because of differences in definition

(a) Public utilities including power

(b) Includes Community development

(c) Excludes expenditures on irrigation

(d) Includes expenditures on irrigation.

[Source *Economic Development and Planning in Asia and the Far East* (United Nations Publication), Nov 1956]

Re-quoted from : *New Horizons in Planning*—A Ghosh, p 194]

Appendix II

सरकारी क्षेत्र में उद्योग और खनिज पदार्थ-सम्बन्धी परियोजनाएँ
 अ. वे परियोजनाएँ जिन पर अमल हो रहा है और जो दूसरी योजना की अवधि से
 आगे लाई गई हैं :

(१) उद्योग

- तीनों इस्पात-सयंत्रों (भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर) को पूरा करना ।
- राउरकेला का उर्वरक-कारखाना ।
- हुतिया, रांची में भारी मशीनों का कारखाना ।
- हुतिया, रांची में डलाई और गड्डाई की उद्योगशाला ।
- दुर्गापुर में खनन-मशीनों का कारखाना ।
- भोपाल में भारी बिजली-उपकरण-परियोजना ।
- श्रीपथ परियोजनाएँ सन्ततनगर में साइक्लिक श्रीपथ सयन, ऋषिकेष्ट के पास ऐंटीवायोटिक्स का कारखाना, केरल में फाइटो-केमिकल्स, गिरी के निकट शल्य-क्रिया के औजारों का कारखाना ।
- पानवल के निकट कार्बनिक अन्तराधिक-सयंत्र ।
- हिन्दुस्तान एंटीवायोटिक्स का विस्तार ।
- द्राम्बे उर्वरक परियोजना ।
- नहरकटिया उर्वरक-परियोजना ।
- कोठामुडियम के पास आन्ध्र उर्वरक परियोजना ।

(२) कोयला

- राष्ट्रीय कोयला-विक्रम निगम के कोयला-कार्यक्रम ।
- भोजपूरी और पाथरडीह में कोयला खानों के केन्द्र ।

(३) खनिज पदार्थ

नक्षेत्री लिग्नाइट परियोजना

(अ) उर्वरक-सयन ।

(आ) त्रिकेष्टि और कार्बनीकरण सयंत्र ।

(इ) तापीय बिजली सयन ।

किरिबुल्ल खनिज लोहा परियोजना

(४) तेल :

आयल इंडिया—बिना साफ किए तेल के पाइप बिछाना ।

नूनमती और बरोनी के तेल-शोधक कारखाने

भा. नई परियोजनाएँ जिनके लिए विदेशी ऋण का वचन मिल चुका है :

भारी मशीनों के सयंत्र का विस्तार ।

खनन-मशीनों के सयंत्र का विस्तार ।

दूसरी और तीसरी भारी बिजली-उपकरण-परियोजनाएँ ।

हस्तिना में ढलाई-गढ़ाई उद्योगशाखा का विस्तार ।

भिलाई इस्पात-कारखाने का विस्तार ।

भारी मशीनी औजार-परियोजना ।

सूक्ष्म औजार-परियोजना ।

बहमे के कांच की परियोजना ।

कच्ची फिल्म-परियोजना, नीलगिरि ।

घड़ियाँ बनाने की परियोजना ।

इ. योजना में शामिल नई परियोजनाएँ जिनके लिए अभी तक विदेशों से ऋण का प्रबन्ध नहीं हुआ है .

(१) इस्पात :

(अ) राउरकेला इस्पात-सयंत्र का विस्तार ।

(आ) दुर्गपुर इस्पात सयंत्र का विस्तार ।

(इ) मिथ्रघानु और औजारों के इस्पात का सयंत्र ।

(ई) बोकारो इस्पात सयंत्र ।

(उ) ऊपर (ई) से सम्बन्धित आनुपंगिक सुविधाएँ (कोयला, हमरे खनिज पदार्थ, बिजली और परिवहन) ।

(२) दूसरे उद्योग

भारी ढाँचा-विषयक परियोजना ।

हैवी प्लेट एण्ड वेमेल वर्क्स ।

हिन्दुस्तान मशीन टूलज, जलाहाबाद का विस्तार ।

भोपाल की भारी बिजली-उपकरण-परियोजना का विस्तार—दूसरा और तीसरा सोपान ।

विदासपत्तनम के शिपयार्ड का विस्तार और सूखी गोदी का निर्माण ।

होमगावाड में सिविलरिटी पेपर मिल ।

हिन्दुस्तान केबल्स, रूपनारायणपुर का विस्तार ।

कोचीन में दूसरा शिपयार्ड ।

(३) कोयला :

राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के नए कार्यक्रम ।
 सिमरेनी कोयला-खानों का विस्तार ।
 मरम्मत और सरक्षण के लिए केन्द्रीय वर्कशॉप ।
 केन्द्रीय रोपवे-योजनाएँ ।
 क्रोकिंग कोयले घोलने की अतिरिक्त क्षमता ।
 मइवेली-खान के उत्पादन का विस्तार ।

(४) दूसरे खनिज पदार्थ .

पाइराइट से गन्धक प्राप्त करने की परियोजना ।
 ब्रैलाडिला खनिज लोहा परियोजना ।
 सिक्किम में ताम्र के भाडारों का उपयोग ।
 केतरी और दरीशे के ताम्र के भाडारों का उपयोग ।
 पन्ना के हीरो का उपयोग ।
 कच्चे मैंगनीज के उपयोग के कार्यक्रम ।
 भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्थान का विस्तार ।
 भारतीय खनिज प्रतिष्ठान का विस्तार ।

(५) तेल :

तेल के प्रन्नेपण और वितरण के कार्यक्रम ।

(६) दूसरे कार्यक्रम .

राज्य सरकारों की परियोजनाएँ—जैसे, मंसूर माथरन एण्ड स्टील वर्क्स,
 प्राग टूल्ज, नेपा मिल्स, दुर्गापुर कोक मोबन्स का विस्तार तथा कोलार
 गोल्ड मार्शनिंग अण्डरटेकिंग का विस्तार ।
 बागान-उद्योगों को ऋण के रूप में सहायता ।
 दार्शनिक प्रणाली की शुरूआत ।
 राष्ट्रीय उद्योग-विकास-निगम, राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् तथा भारतीय
 मानक-संस्थान के कार्यक्रम ।
 पूर्वी-विनियोग-निगमों के रूप में काम करने वाली संस्थाओं को ऋण ।
 औद्योगिक वस्तियाँ ।

ई. ऐसी परियोजनाएँ, जिन पर आरम्भिक काम चलते रहना चाहिए, ताकि यथा-
 समय निरूपित किए जा सकें :

(२) उद्योग :

भारी कम्प्रेसर और पम्प-परियोजना ।
 बुनियादी उपमसह-परियोजना ।

वाल और रास्टर-वेयरिंग की परियोजना ।
 मशीनी भोजारो की अतिरिक्त क्षमता ।
 दूसरी भारी ढाँचा-परियोजना ।
 दूसरा प्लेट ऐण्ड वेसेल वर्क्स ।
 समुद्री डीजेल इंजिन-परियोजना ।

(२) खनिज पदार्थ .

खनिज तेलों के लिए पाइप लाइनों ।
 स्नहक तेल-परियोजना ।
 गैर-कोकिंग कोयला घोने के केन्द्र ।
 पत्थर के कोयले के लिए कम ताप के कार्बनीकरण-सयंत्र ।
 नहवेली लिग्नाइट उच्चताप-कार्बनीकरण-सयंत्र तथा कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए सम्बद्ध सुविधाएँ ।

उ. ऐसी परियोजनाएँ, जिनका स्वरूप आनुषंगिक है :

नए खोजे गए तेल के लिए नया शोधन-केन्द्र ।
 बिना साफ किए हुए तेल के पाइप-लाइन ।
 तेल-अन्वयण की भारत-स्टैनलेक-परियोजना में तथा तेल-उत्पादन के बढ़ाने के लिए आयल इण्डिया के कार्यक्रम में सरकारी योगदान ।
 नहरबंदिया की प्राकृतिक गैस के लिए पाइप बिछाना ।¹

1. तृतीय पञ्चवर्षीय योजना (रूपरेखा), भारत सरकार ।

APPENDIX III

भारत में राज्य-उद्योगों की अनुसूची

(A) Banks

- (i) The Reserve Bank of India (ii) The State Bank of India

(B) Statutory Corporations

- (a) The Life Insurance Corporation (b) Damodar Valley Corporation (c) Central Warehousing Corporation (d) Industrial Finance Corporation (e) Rehabilitation Finance Corporation. (f) Indian Airlines Corporation (g) Air India International

(C) Control Boards

- (i) Bhakra Nangal Project (ii) Chambal Valley Project (iii) Nagarjun Sagar Project

(D) Commodity Boards

- (a) Coffee Board (b) Tea Board (c) Coir Board (d) Central Silk Board (e) Rubber Board

(E) Boards with Commercial Functions

- (i) All India Handicrafts Board (ii) All India Handloom Board

(F) Limited Companies (Private)

I Central Government Undertakings

- (1) Ashoka Hotels Ltd (2) Bharat Electronics (P) Ltd. (3) Eastern Shipping Corporation Ltd (4) Export Risk Insurance Corporation (P) Ltd (5) Govt Telephones Board (P) Ltd (6) Heavy Electricals (P) Ltd (7) Hindustan Aircraft (P) Ltd (8) Hindustan Anti Biotics (P) Ltd (9) Hindustan Cables (P) Ltd (10) Hindustan Housing Factory (P) Ltd (11) Hindustan Insecticides (P) Ltd (12) Hindustan Machine Tools (P) Ltd

(13) Hindustan Shipyard (P) Ltd (14) Hindustan Steel (P) Ltd
 (15) Indian Handicraft Development Corporation (16) Indian Refine-
 ries (17) Indian Telephone Industries (P) Ltd (18) Nahan
 Foundry (P) Ltd (19) Nangal Fertilisers and Chemicals (P) Ltd
 (20) National Coal Development Corporation (P) Ltd (21) Na-
 tional Industrial Development Corporation (P) Ltd (22) National
 Instruments (P) Ltd (23) National Research Development Cor-
 poration (24) National Small Industries Corporation (P) Ltd
 (25) Neyveli Lignite Corporation (P) Ltd (26) Rehabilitation
 Housing Corporation Ltd (27) Sindri Fertiliser and Chemicals (P)
 Ltd (28) State Trading Corporation of India (P) Ltd (29) Sulta-
 na Cotton Manufacturing Co (30) Western Shipping Corporation
 (P) Ltd

II Combined Undertakings (Centre & States)

- | | |
|---|--|
| (a) Indian Rare Earths (P) Ltd | Centre & Kerala |
| (b) Kulu Valley Transport (P) Ltd | Centre & Punjab |
| (c) National Projects Construction
Corporation (P) Ltd | Centre M P Rajasthan,
Bihar, J & K, Kerala. |
| (d) Orissa Mining Corporation
(P) Ltd | Centre & Orissa |
| (e) Travancore Minerals (P) Ltd | Centre & Kerala |
-

tion appears in the table as an output or sale and simultaneously as an input or purchase, and when factor incomes are included as inputs, then the sum of the outputs from each industry is observed to balance, in an accounting sense, with the sum of inputs "

"For ease of presentation the outputs are set out in rows, the inputs in columns, so that each industry has attributed to it a row and n column making a balanced account " (p 442)

"To 'elevate' the plan view of the economy's structure into a model, the following working assumptions have usually been made:

- (a) "that there are constant returns to scale and,
- (b) 'that the combination of inputs, observed accounting wise in input output table will remain in constant proportions whatever the level of output, i.e., there can be no substitution between different materials or fuels, and no technological progress within the context of any single table' (p 443)

"There are two types of model. In the earlier 'closed' version, the proportional relationships just mentioned were assumed to extend beyond the purely industrial sectors of the economy so that what we normally term final consumption, by households, by government or by foreign countries became inputs to those sectors, giving rise to labour services, administration' and imports in a proportionally related manner. These 'outputs' then became in their turn 'inputs' to industrial sectors, giving the system a completely circular and independent structure of input output relationships "

"Since each output, in this version, is made by of an unique combination of inputs then the only dimension that is free to alter is the scale or level of activity at which the system is to be in equilibrium. Some writers have pointed the analogy between this feature of the Leontief model and the possibility of equilibrium at levels below full employment which is so distinctive a part of the Keynesian theory

"If we represent Leontief model in symbolic but familiar terms, then the matrix of coefficients usually denoted by A and the Column Vector of n total outputs y , are related by the equation

$$y = Ay$$

every industry's output, in this system, being the sum of its inputs into all the other 'industries'. It follows that

$$\begin{aligned} y - Ay &= 0 \\ (I - A)y &= 0 \end{aligned}$$

or
which is soluble when A and any single element in the vector, y , are known "

"The version which is used in this exercise is much less rigid and naive in form, and consequently offers more hope of becoming useful practice"

"Instead of regarding the activities of households, government, capital formation and foreign trade as 'processes' for which there are proportionally related inputs and outputs, these expenditures are regarded as taking place outside the system, while labour and other factor incomes are looked upon as 'primary' or original inputs in common with goods and services imported from outside the system. The model is thus 'open ended' "

"If the final demands—i.e., private and public current consumption, export and additions to capital—are calculated or estimated in advance, then the theory of production permits the estimation of output levels necessary to satisfy all the demands, final and intermediate. In algebraic language, if the set of final demands, x , and the matrix A are given, then

$$Ay + x = y$$

Therefore, the vector of outputs

$$\begin{aligned} y &= (1 - A)^{-1} x \\ &= (1 + A + A^2 + A^3 + \dots) x \end{aligned}$$

and so, by means of this inversion or expansion, we can obtain industry by industry the outputs which will satisfy the assumed or estimated demands from outside the system and, simultaneously, the indirect or intermediate requirements arising within the interdependent set of industries' (p 444)

"In our equations y , the output by industries is shown as a function of x the final demands. In more familiar Keynesian terms this is showing O as a function of $C + I$, but with this difference that O is expanded, as it were, to show the inter industry transactions which are hidden from view in the consolidation of aggregative national income analysis. It is in fact from these intermediate sales and purchases between industrial sectors that the input output coefficients are derived

"If one is interested in predicting future levels of output then it is important to remember that the successful use of an open ended input-output model puts a special premium on being able to prepare consistent and accurate estimates of final demands' (p 444)

The study of input output analysis is of great importance as it represents a true picture of interdependence. Economic dynamism depends on various factor's interdependence. Say, the volume of output will depend, besides other things, on the volume

of raw material taxable capacity depends on income and the possibility of saving, introduction of new railway presupposes the possibility of their economic operation. Unless the Planning Authority makes detailed study of all these interdependence it can never achieve the desired result in matters of the fixation of targets, adjustments of priorities, calculations of allotments and allocations.

In our First Five Year Plan too much emphasis was laid on agriculture and irrigation. Basic idea behind it was besides increasing the food supply to arrange for a rapid and steady flow of raw materials to the industry. That was based on a study of inter industry interdependence. Hence we can easily mention that the application of this planning technique was made in our First Five Year Plan. This adjustment between raw material and the requirement of finished good is not always final. Though the main reason of planning is to have balanced economic growth and the removal of waste but due to miscalculations the results are sometimes ineffective in planned attempt also.

Prof J R Hicks has defined Input as something which is bought for the enterprise and an Output as something which is sold by it. This taken in its raw form may be said that input is the flow of raw materials into the factory and output is the outflow of finished goods of the same factory. Their volumes (not value) must be equal—leaving aside the proportion of 'factory consumption'. This however is not the case with their values—there is a tremendous difference between the values of inputs and outputs.

For a Planning Authority the study of this interdependence is not important from the point of view of production alone. They are important in other spheres as well say in the fields of Capital Formation, Income Expenditure Ratio, Capital Output Ratio, Employment Living Standard Ratio, Savings Capital Ratio etc. To a considerable extent this study of interdependence has been made by the drafters of our Second and Third Five Year Plans in almost all fields. It is expected that with the availability of more accurate and reliable statistical data in the country this study of interdependence will be more in common use. They will be easy to calculate and apply in our forthcoming economic plans.

The basis of an Input Output analysis is the system which is technically called a Matrix. Matrix may be defined as A system of $m \times n$ numbers arranged in the form of an ordered set of m rows each row consisting of an ordered set of n numbers is called an $m \times n$ matrix—to be read as m by n matrix * Prof

* Matrices by Shanti Narayan 1963 Ch I p 12

Shanti Narayan has further indicated the mathematical use of this linear programme as follows

"To locate any particular element of a matrix, we have to employ two suffixes which will respectively specify the row and the column in which it appears. Numbering the rows from top to bottom and columns from left to right the element in the i th row and the j th column will usually be referred to as the (i, j) th element so that of the two suffixes i and j the first one, i , to the left will always denote the number of rows and the second one, j , the number of columns. For an $m \times n$ matrix which, of course, has m rows and n columns suffixes i and j respectively range from 1 to m and 1 to n .

"Also it will be usual to denote a matrix by a capital letter such as A, B, P etc and then the (i, j) th element will be denoted by a_{ij}, b_{ij}, p_{ij} etc. Thus we shall usually write.

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1j} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2j} & a_{2n} \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{ij} & a_{in} \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{mj} & a_{mn} \end{vmatrix} = [a_{ij}]$$

'The first suffix is invariant for each row and the second is invariant for each column

An $m \times n$ matrix is said to be a Type $m \times n$. In relation to matrices the numbers are usually called *scalars* †

Others have represented this Matrix system in other ways as well. A rectangular arrangement of numbers or symbols, showing in the best possible manner, the transactions of an economy can be called a matrix. A set of rows and columns of figures make up a particular matrix. The receipts of one sector of the economy or the receipts by a class of transactors are indicated in each row of the matrix and each column contains the payments of one sector to the another ‡. This type of matrix may be simple as well as of complex model. Simple model consists of single line columns and rows. Complex models on the contrary consists of multiple lines columns and rows. In U.K. and U.S.A. matrices consisting of over 500 rows and columns have been calculated out. Here, we are producing a model of simplest type of matrix

† (1) Ibid pp 13-14 (2) Please also read for an advanced mathematical interpretation Introduction to Linear Algebra and the Theory of Matrices by Hans Schwerdtfeger

‡ New Horizons in Planning—Atal Ghosh 1966 p 6

Model of 'Simplest Type' Matrix

Receipts→	Firms	Households	Total
Payments↓			
Firms		500	500
Households	500		500
Total	500	500	1000

Mostly, as has already been indicated, these Matrices models are used in the study of interdependence. In the above example, if we replace 'firms' and 'households' by 'raw materials and finished goods' or by 'agricultural' and 'manufacturing', our study will be somewhat correct of the system of interdependence. Complicated and complex matrices are usually used in this type of study because the present day economic structure is, itself complex †

Matrix system, again according to its nature, is divided into two categories dynamic and static models. For a detailed analysis, these two models of 'flow coefficient' and 'capital coefficient' is to be studied. In the Planning process the Planning Authority is faced with the problem of applying these models in preparing the Plan frame. Both these systems can be applied, in both 'advance' and 'backward' economies provided sufficient and accurate statistical data are available in the country, particularly of those directly or indirectly connected with industry, trade, commerce, manufacture agriculture etc. Drafters of our First, Second and Third Five Year Plans experienced acute difficulty in fixing targets, priorities etc. due to the non availability of required statistical material in the country. It is expected that all these advanced techniques will be utilised, in more details, in our forthcoming plans—while sufficient reliable statistical data will be available in the country.

† For details please read the sources quoted in the first paragraph above. Alak Ghosh has made a good study of it in his book 'New Horizons in Planning'.